उपकार

सामान्य अध्ययन

आधुनिक भारत का इतिहास

संघ एवं राज्य लोक सेवा तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी

डॉ. के. के शर्मा

उपकार

सामान्य अध्ययन

आधुनिक भारत का इतिहास

संघ एवं राज्य लोक सेवा तथा
अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी

लेखक
डॉ. के. के. शर्मा

उपकार प्रकाशन, आगरा-2

Introducing Direct Shopping

Now you can purchase from our vast range of books and magazines at your convenience :

- Pay by Credit Card/Debit Card or Net Banking facility on our website *www.upkar.in* *OR*
- Send Money Order/Demand Draft of the print price of the book favouring 'Upkar Prakashan' payable at Agra. In case you do not know the price of the book, please send Money Order/Demand Draft of ₹ 100/- and we will send the books by VPP (Cash on delivery).

(Postage charges FREE for purchases above ₹ 100/-. For orders below ₹ 100/-, ₹ 20/- will be charged extra as postage)

© प्रकाशक

प्रकाशक

उपकार प्रकाशन

(An ISO 9001 : 2000 Company)

2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर (शाह सिनेमा के सामने), **आगरा–**282 002

फोन : 4053333, 2530966, 2531101; **फैक्स** : (0562) 4053330, 4031570

E-mail : care@upkar.in, **Website :** www.upkar.in

ब्रांच ऑफिस :

4845, अन्सारी रोड, दरियागंज,
नई दिल्ली–110 002
फोन : 011–23251844/66

पीरमोहनी चौक, कदमकुआँ,
पटना–800 003
फोन : 0612–2673340

1-8-1/B, आर. आर. कॉम्प्लेक्स (सुन्दरैया पार्क के पास, मनसा एन्क्लेव गेट के बगल में),
बाग लिंगमपल्ली, हैदराबाद–500 044 (आ. प्र.)
फोन : 040–66753330

28, चौधरी लेन, श्याम बाजार,
मेट्रो स्टेशन के निकट, गेट नं. 4
कोलकाता–700004 (W.B.)
फोन : 033–25551510

B-33, ब्लंट स्क्वायर, कानपुर
टैक्सी स्टैण्ड लेन, मवइंया,
लखनऊ–226 004 (U.P.)
फोन : 0522–4109080

- *इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी त्रुटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा.*
- *इस पुस्तक को अथवा इसके किसी अंश को बिना प्रकाशक की लिखित अनुमति के, किसी भी रूप–फोटोग्राफी, विद्युत-ग्राफिक, यान्त्रिकी अथवा अन्य रूप में किसी भी प्रकार से उपयोग के लिए नहीं छापा जा सकता है.*
- *किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल आगरा ही होगा.*

ISBN : 978-93-5013-614-0

मूल्य : ₹ 215·00 मात्र
(Rs. Two Hundred Fifteen Only)

Code No. 2340

मुद्रक : उपकार प्रकाशन (प्रिंटिंग यूनिट) बाई-पास, आगरा

विषय-सूची

1. भारत में ब्रिटिश विस्तार 3–32

[कर्नाटक युद्ध, बंगाल विजय, मैसूर राज्य एवं इसके द्वारा अंग्रेजों के राज्य विस्तार के प्रयास का विरोध, तीन आंग्ल मराठा युद्ध, भारत में ब्रिटिश राज्य की आरम्भिक संरचना : रेग्यूलेटिंग एवं पिट का इण्डिया एक्ट]

2. ब्रिटिश राज्य के आर्थिक प्रभाव 33–53

[सम्पत्ति का अपवाह (ड्रेन ऑफ वेल्थ) कर व्यवस्था, भू-राजस्व बंदोबस्ती (जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी), उद्योगों का विनाश, कृषि का वाणिज्यीकरण एवं रेलवे, भूमिहीन श्रमिकों की वृद्धि]

3. सांस्कृतिक समागम एवं सामाजिक परिवर्तन 54–81

[पश्चिमी शिक्षा एवं आधुनिक विचारों की भूमिका, भारतीय पुनर्जागरण, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलन, भारतीय मध्यम वर्गों की वृद्धि, छापाखाना एवं इसका प्रभाव, भारतीय भाषाओं में आधुनिक साहित्य का उदय, सन् 1857 से पहले सामाजिक सुधार के उपाय]

4. ब्रिटिश शासन का विरोध 82–96

[प्रारम्भिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह–कारण, प्रकृति, अवधि एवं परिणाम)

5. भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम 97–149

[भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम–प्रथम चरण : राष्ट्रीय संचेतना का विकास, संघों का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा इसका नरमपंथी चरण, आर्थिक राष्ट्रीयता : स्वदेशी आन्दोलन : उग्रवाद में वृद्धि तथा कांग्रेस में 1907 ई. का विभाजन, 1909 ई. का अधिनियम–'फूट डालो और शासन करो' की नीति; कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच 1916 का समझौता]

6. गांधीजी एवं उनकी विचारधारा 150–171

[जन-जुटाव के लिए गांधीजी द्वारा अपनाया गया तरीका, खिलाफत एवं असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं भारत छोड़ो आन्दोलन, राष्ट्रीय आन्दोलन में अन्य विचारधाराएँ–क्रान्तिकारी आन्दोलन, वामपंथ, सुभाषचन्द्र बोस तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना]

7. भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति में अलगाववादी प्रवृत्तियाँ 172–193

[मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा, 1945 ई. के बाद की स्थिति, साम्प्रदायिक हिंसा, देश का विभाजन एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति]

8. भारत : स्वतन्त्रता प्राप्ति से 1964 तक 194–225

[भारत स्वतन्त्रता से 1964 ई. तक संसदीय पंथ-निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य (1950 ई. का संविधान), जवाहरलाल नेहरू का विकासवादी समाजवादी दर्शन, योजना व्यवस्था एवं राज्य नियन्त्रित औद्योगीकरण, कृषिक सुधार, गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त पर आधारित विदेशी नीति, चीन के साथ सीमा संघर्ष]

9. आधुनिक भारत के महान् व्यक्तित्व 226–259

10. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन : सिंहावलोकन [1885 से 1964 तक] 260–284

- प्रश्नकोश 285–309
- परिशिष्ट 310–336

आधुनिक भारत

1

भारत में ब्रिटिश विस्तार
(British Expansion in India)

[कर्नाटक युद्ध, बंगाल विजय, मैसूर राज्य एवं इसके द्वारा अंग्रेजों के राज्य विस्तार के प्रयास का विरोध, तीन आंग्ल-मराठा युद्ध, भारत में ब्रिटिश राज्य की आरम्भिक संरचना : रेग्यूलेटिंग एवं पिट का इण्डिया-एक्ट (The Carnatic wars, Conquest of Bengal, Mysore & its resistance to British expansion, The three Anglo-Maratha wars, Early structure of British raj : Regulating & Pitt's India-Act)]

ब्रिटिश विस्तार

आधुनिक भारत का इतिहास (1757-1947 ई.) आर्थिक संक्रमण, सामाजिक बदलाव तथा राजनीतिक परिवर्तनों एवं संघर्षों का लेखा-जोखा कहा जा सकता है. इस काल में हुए विविध परिवर्तन किसी एक घटना विशेष के परिणाम नहीं थे, अपितु एक लम्बे समय में भारतीय समाज, यहाँ की राजनीति तथा साम्राज्यवादी शक्ति के परस्पर दबाव तथा तात्कालिक शासकों की अतिमहत्वाकांक्षा तथा उनके स्वार्थों की परिणति थे, जिनकी शुरूआत मुगल साम्राज्य के पतन के साथ हुई.

हालांकि 15वीं शताब्दी की शुरूआत में ही हिन्दुस्तान में यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों की स्थापना का क्रम प्रारम्भ हो चुका था. यहाँ पर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के भरसक प्रयास किए और समय तथा मौका पाकर इन कम्पनियों ने राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया.

जब 1707 ई. में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था. देश में अराजकता तथा अशांति का वातावरण पनपने लगा. इस असंतोष के पनपने का मुख्य कारण यह था कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी इतने अयोग्य तथा निर्बल थे कि वे विशाल मुगल साम्राज्य को एकता के एक सूत्र की कड़ी में आबद्ध न कर सके. मुगलों की शासन व्यवस्था में साम्राज्य का आधार केन्द्र होता था तथा सम्राट् प्रशासनिक व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु. सम्राट् सेना का प्रधान सेनापति तथा न्याय व्यवस्था का भी मुख्य स्रोत होता था. उसके जितने भी मंत्री थे वे सब शासन नीति के निर्माता न होकर केवल सलाहकार की ही भूमिका निभाते थे. औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को 20 प्रांतों में बाँट रखा था, जिन्हें 'सूबा' कहा जाता था. इन प्रांतों के 'सूबेदार' तथा दीवान शीर्षस्थ अधिकारी होते थे. करों की वसूली, कृषि विकास के कार्य तथा राजकोष का लेखा-जोखा रखना दीवानों का कार्य था, तो सूबेदार शांति व्यवस्था, न्यायिक कार्य तथा सेना पर नियंत्रण रखने का कार्य सँभालता था. चूँकि मुगलकाल में सेना का संगठन मनसबदारी प्रथा पर आधारित था. अतः मनसबदार के अधिकार में जितनी भी सेना होती थी उसका वेतन उसके मुखिया को एक बार में ही दे दिया जाता था, इसका परिणाम यह हुआ कि सम्राट् की सेवा में रहने वाले सिपाही केवल उन्हीं सरदारों से परिचित थे जिनसे उनको वेतन मिलता था. शुरूआत में मनसबदारों को नकद वेतन दिया जाता था, लेकिन बाद में उन्हें नकद वेतन के स्थान पर जागीरें प्रदान की जाने लगीं. ये जागीरें धीरे-धीरे पैतृक सम्पत्ति बन गईं और यह पद भी पैतृक हो गया, योग्यता का कोई मापदण्ड नहीं रहा. इस प्रकार की व्यवस्था से सम्राट् के नियंत्रण में सुदृढ़ सेना का अभाव हो गया और मनसबदार ही सामंतों की हैसियत में आ गए. यह सामंती व्यवस्था ही तात्कालिक अव्यवस्था, अराजकता तथा विघटन का मूल कारण थी. सामंतों ने भी बड़े-बड़े सम्राटों की तरह अपने-अपने दरबार, न्यायालय तथा सेनाओं की स्थापना कर ली थी. इस प्रकार की क्रियाविधि से विशाल मुगल साम्राज्य

छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों में विभाजित हो गया. सामंत लोग निजी स्वार्थों तथा दलबंदियों में इस प्रकार फँस चुके थे कि उन्होंने राज्य की मूल शक्ति पर ही कुठाराघात करना शुरू कर दिया था. वजीर तथा अन्य अधिकारी एक-दूसरे को नीचा दिखाने लगे.

इरविन के अनुसार मुगल सामंत चार गुटों में विभक्त हो गए, जो कि निम्नलिखित थे–

1. तूरानी
2. ईरानी
3. अफगानी
4. हिन्दुस्तानी

प्रथम तीन सामंतों का मुगल दरबार में प्रभुत्व था और ये मूलतः विदेशी थे, चौथा दल हिन्दुस्तानी इस कारण से कहलाया, क्योंकि इनमें अधिकतर वे मुसलमान सामंत शामिल थे जो कई पीढ़ियों से भारत में रह रहे थे.

इस प्रकार की विघटित व्यवस्था को देखकर, मुगलों की कमजोरी का लाभ उठाकर अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने क्रमशः बंगाल तथा कर्नाटक में अपनी-अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली. इन दोनों शक्तियों में भारत में सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेजों को विजयश्री मिली.

भारत में अंग्रेजों का प्रवेश–16वीं सदी के अन्त में यूरोप के अन्य देशों की तरह ब्रिटेन के लोगों की भी विश्व व्यापार में रुचि बढ़ी. अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने समुद्री रास्तों के जरिये नवीन व्यापारिक देशों की खोज आरम्भ कर दी. फ्रांसिस ड्रेक 1578 ई. में प्रशांत महासागर को पार करके मलक्का (द्वीप समूह) पहुँचा तथा आशा अंतरीप का चक्कर लगाकर 1580 ई. में इंग्लैण्ड लौट गया. 1588 ई. में स्पेनिश आर्मेडा की पराजय से इंग्लैण्ड की समुद्री मार्ग की बाधाएँ दूर हो गईं. महारानी एलिजाबेथ ने अपनी व्यापारिक नीतियों का पुनरीक्षण करके 1599 ई. में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' बनाने की अनुमति प्रदान की. इस कम्पनी की शुरूआत लगभग 217 हिस्सेदारों ने 30133 पौण्ड की राशि लगाकर की. महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसम्बर, 1600 ई. को इस कम्पनी को पन्द्रह वर्षों के लिए व्यापार करने के उद्देश्य से एकाधिकार का आज्ञापत्र प्रदान किया.

इस आज्ञापत्र में उल्लेख किया गया कि जहाँ स्पेन एवं पुर्तगाल का किला न हो व्यापार किया जाए. इस आज्ञापत्र के द्वारा युद्ध एवं संधि करने, कानून बनाने तथा अपने एकाधिकार पर आघात करने वालों को दण्ड देने की भी व्यवस्था तय की गई. इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के सभी राज्यों के मध्य 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक वाणिज्यिक युद्ध चलता रहा. अंग्रेज समुद्री कप्तानों ने उन समुद्रों में अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया जिन पर पुर्तगाली तथा स्पेनवासी अपना दावा जताते थे. अंग्रेजों द्वारा धन-सम्पत्ति तथा माल से भरे जहाजों को लूटकर अपने कब्जे में कर लिया जाता था.

अंग्रेजों का पहला जहाजी बेड़ा 1608 ई. में भारत में प्रविष्ट हुआ. इस बेड़े का कप्तान हॉकिन्स था. 1610 ई. में हॉकिन्स ने आगरा में मुगल सम्राट् जहाँगीर से मुलाकात की. कम्पनी की शक्ति से प्रभावित होकर सर टॉमस रो के अनुरोध पर सम्राट् ने सन् 1613 ई. में पश्चिमी क्षेत्र में उन्हें बस्तियाँ बसाने की अनुमति दे दी. सर टामस रो को मुगल दरबार में राजदूत नियुक्त किया गया, जो 1615 से 1618 ई. तक मुगल दरबार में रहा. उसके राजदूत होने का व्यापक प्रभाव यह पड़ा कि आगरा, अहमदाबाद, सूरत तथा भड़ौंच में अंग्रेजों ने अपनी कम्पनियाँ स्थापित कर लीं. इन्हें व्यापारिक कोठियाँ कहा जाता था. मुख्य बात यह है कि इन फैक्ट्रियों में माल का उत्पादन नहीं किया जाता था. अलग-अलग स्थानों से क्रय किया गया माल इन केन्द्रों पर इकट्ठा किया जाता था. अपनी साम्राज्य शक्ति को बढ़ाते-बढ़ाते अंग्रेजों ने 1668 ई. में बम्बई पर अधिकार कर लिया था. यह माना जाता है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने बेंग्राजा की इनफान्टा कैथेरिन के विवाह में दहेज के रूप में बम्बई मिली थी. 1688 ई. में चार्ल्स द्वितीय ने कम्पनी के लिए बम्बई को दस पौण्ड वार्षिक किराये पर दे दिया था. कालांतर में बम्बई सूरत से अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन गया था.

अंग्रेजों ने जब यह देखा कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर मुगलों तथा मराठों का प्रभाव अधिक है, तो उन्होंने अपनी रणनीति के तहत भारत के पूर्वी समुद्र तट पर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की. चूँकि पूर्वी प्रदेशों में छोटे-छोटे राज्य थे, किसी बड़ी शक्ति का आधिपत्य नहीं था. अतः अंग्रेजों को यहाँ ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी. फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरि के शासक से जोकि विघटित विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधि था, मद्रास को पट्टे पर ले लिया तथा किलेबंदी करवाकर सेंट जॉर्ज का किला बनवाया. दक्षिणी-पूर्वी समुद्र तट पर 1611 ई. में ही मछलीपट्टम (मसूलीपट्टनम) पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया. मद्रास में अंग्रेजों का चूँकि व्यापार अच्छा चला जिसको देखकर कोरोमण्डल तट को प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बनाया गया. 1633 ई. में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर तथा बालासोर (उड़ीसा) में नए केन्द्र स्थापित किए गए. 1651 ई. में हुगली में व्यापारिक कोठी तथा बाद में पटना तथा कासिमबाजार में भी व्यापारिक अड्डों की स्थापना की गई. 1658 ई. में कोरोमण्डल तट एवं बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सभी बस्तियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नियन्त्रण में दे दिया गया.

इसी दौरान बंगाल में मुगल सम्राट् शाहजहाँ के पुत्र शुजा ने तीन हजार रुपए वार्षिक कर का प्रावधान रखकर कम्पनी को व्यापारिक मामले में कुछ अधिकार दे दिए थे. एक अन्य आदेशानुसार 1656 ई. में अंग्रेजों को आयात-निर्यात कर में भी छूट मिल गई.

कम्पनी की नीतियाँ–अपनी स्थापना वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक यानी कि (1600 से 1700 ई. तक) यह कम्पनी व्यापारिक संस्थान के रूप में कार्य करती रही. इस समय इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना था. 1600 ई. में कम्पनी की हिस्सा पूँजी जो 30133 पौण्ड थी, बढ़कर 1722 ई. में 6 करोड़ पौण्ड हो गई. कम्पनी का शेयर मूल्य 12 से 45 प्रतिशत तक बढ़ चुका था. उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि 1614 ई. में 25,000 पाउण्ड वजन की काली मिर्च 26042 पौण्ड में खरीदी जाती थी तथा यह इंग्लैण्ड में 208333 पौण्ड में बेची जाती थी. जो रेशमी वस्त्र हिन्दुस्तान में 37499 पौण्ड में क्रय किया जाता था, यूरोप में उसका विक्रय मूल्य 107140 पौण्ड होता था. इस प्रकार के व्यापारिक लाभ से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई. अपनी आर्थिक वृद्धि के फलस्वरूप कम्पनी का यह प्रयास होने लगा कि भारत के अधिकाधिक भाग पर अपना प्रभुत्व जमाकर एक उपनिवेश का निर्माण किया जाए. इस निर्माण के साथ ही साथ कम्पनी ने सैन्य विस्तार की भी योजना बनाई और इस योजना की क्रियान्वति करने के लिए उसने देश में व्याप्त दुर्व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया. अंग्रेजों के प्रमुख अधिकारी जेराल्ड औंगियर, जो सूरत का प्रेसीडेंट और बम्बई का गवर्नर था, उसने कम्पनी की संचालक समिति को पत्र लिखा "अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबन्ध करें." कुछ ही वर्षों में कम्पनी ने यह सलाह स्वीकार कर ली तथा दिसम्बर 1687 ई. में मद्रास के प्रधान को पत्र लिखकर यह आदेश दिया गया कि "आप असैनिक और सैनिक शक्ति का ऐसा शासन कायम कीजिए तथा दोनों की प्राप्ति के लिए इतनी आय पैदा कीजिए तथा बनाए रखिए, जो सदैव के लिए भारत में एक विशाल सुगठित, सुरक्षित अंग्रेजी राज्य की नींव बन सके. इस नई नीति का प्रतिपादक जोशुआ चाइल्ड था. कैप्टेन निकल्सन पुर्तगालियों से सालसेट तथा चटगांव हथियाना चाहता था, परन्तु वह सफल नहीं हो सका. जब वह हुगली पहुँचा तो 1686 ई. में बंगाल के सूबेदार शाइस्तखाँ ने अंग्रेजों को मार भगाया. इसकी प्रतिक्रियास्वरूप जॉन चाइल्ड ने बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बन्दरगाहों को घेरकर मुगल जहाजों को पकड़ लिया तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को पकड़ने के लिए कप्तान को लालसागर की ओर भेजा, परन्तु वहाँ भी उसे मुँह की खानी पड़ी. अंततः जॉन चाइल्ड को हर्जाने के रूप में डेढ़ लाख रुपए अदा करने पड़े. इस प्रकार कम्पनी की राज्य विस्तार की पहली योजना धूल-धूसरित हो गई. इसका प्रभाव यह हुआ कि कम्पनी को अपना ध्यान राज्य विस्तार से हटाकर पचास वर्ष तक व्यापार पर ही केन्द्रित करना पड़ा.

कम्पनी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1715 ई. में मुगल दरबार में एक दूत मण्डल भेजे जाने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मुगल बादशाह से व्यापार के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करना था तथा साथ ही कलकत्ता के आसपास कुछ भू-भाग प्राप्त करने का भी इरादा था. दूत मण्डल में जॉन सुर्मन, एडवर्ड स्टीफेंसन तथा एक सर्जन हैमिल्टन भी था. बादशाह फर्रुखसियर गम्भीर बीमारी से पीड़ित था, जिसको सर्जन ने ठीक कर दिया जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने कई सुविधाएँ प्रदान कर दीं, जिनमें मुख्य सुविधाएँ निम्नलिखित थीं–

1. कम्पनी को तीस हजार रुपए की निश्चित वार्षिक राशि के भुगतान पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया.

2. दस हजार की राशि का भुगतान करने पर सूरत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई.

3. कम्पनी कलकत्ता के पास अतिरिक्त भूमि किराये पर ले सकती थी.

4. जो किराया राशि कम्पनी ने पूर्व में ही दे रखी थी उसी में मद्रास तथा हैदराबाद में भी व्यापार करने का अधिकार पत्र मिल गया.

5. कम्पनी के सिक्कों को मुगल साम्राज्य में प्रचलन की आज्ञा मिल गई.

इस प्रकार के व्यापारिक अधिकारों के मिलने के बाद कम्पनी की तीसरी महत्वपूर्ण नीति थी सामाजिक उद्देश्य के लिए टिकी यूरोपीय शक्तियों का उन्मूलन. भारत में फ्रांसीसियों का आगमन सबसे अंत में हुआ था. फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार 18वीं सदी के दूसरे दशक में अधिक हुआ जब मालाबार के समुद्री तट पर माही एवं कोरोमण्डल तट पर कराइकेल बन्दरगाह उनके कब्जे में आ गए. इसी समय मॉरीशस द्वीप भी उनके अधिकार में आ गया था, जिससे यूरोप को जाने वाले समुद्री मार्ग पर सफलतापूर्वक नियन्त्रण स्थापित करना सम्भव हो गया. फ्रांसीसियों के आगमन से अंग्रेजों के लिए एक नई समस्या पैदा हो गई. दोनों शक्तियों का उद्देश्य एक ही था–भारत में अपना प्रभुत्व जमाना. भारत की तात्कालिक दुर्बल राज्य शक्ति को देखकर दोनों के मध्य टकराहट होना स्वाभाविक था, दोनों में एकाधिकार प्रवृत्ति भी बढ़ी. दोनों कम्पनियाँ यह चाहती थीं कि भारतीय व्यापार पर उनका आधिपत्य हो.

कर्नाटक युद्ध–अंग्रेज तथा फ्रांसीसी कम्पनियों का प्रथम युद्ध कर्नाटक में हुआ, जिसकी राजधानी अर्काट थी. तथा-

कथित कर्नाटक राज्य वर्तमान कर्नाटक प्रांत में स्थित न होकर पूर्वी समुद्री तट पर मद्रास एवं पांडिचेरी के पश्चिम-मध्य में स्थित राज्य था, जिसे उस समय कर्नाटक कहा गया. 1740 ई. के पश्चात् कर्नाटक में प्रशासनिक अस्थिरता के कारण यह क्षेत्र आंग्ल-फ्रांसीसी संघर्ष का केन्द्र बना गया.

कर्नाटक का प्रथम युद्ध–कर्नाटक के प्रथम युद्ध की भूमिका में बाह्य कारण निहित थे, जिनसे दोनों शक्तियों के मध्य टकराव पैदा हुआ. यूरोप में 1740 ई. में ब्रिटेन और फ्रांस एक-दूसरे के विरुद्ध हो गए थे आस्ट्रिया के उत्तराधिकार के क्षेत्र को लेकर. इस प्रतिक्रिया का असर यह हुआ कि भारत में रह रहे ब्रिटेनी तथा फ्रांसीसियों के मध्य भी विरोधाभास शुरू हो गया. यूरोप में युद्ध शुरू होने के बाद अंग्रेजों की सहायता करने के लिए एक जहाजी बेड़ा भारत आया तथा दूसरी ओर फ्रांसीसियों की सहायतार्थ ला-बूर्डोने के नेतृत्व में मॉरीशस से दो हजार सैनिक भारत में आए. 1742 ई. में डूप्ले फ्रांसीसी कम्पनी का गवर्नर बना था. 1744 ई. में युद्ध हुआ जिसका कारण प्रमुख रूप से यह भी था अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया था. इस समस्या से निजात पाने के लिए डूप्ले ने मॉरीशस के गवर्नर ला-बूर्डोने से सहयोग माँगा. मद्रास से कलकत्ता की ओर जाते समय अंग्रेजी बेड़े की अनुपस्थिति में फ्रांसीसी सेनापति ने मद्रास पर हमला कर उसे अपने अधिकार में ले लिया. इसी बीच एक घटना यह भी घटी कि डूप्ले तथा ला-बूर्डोने में मतभेद हो गया. मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा होने के बाद अंग्रेजों ने कर्नाटक के तात्कालिक नवाब अनवरुद्दीन से सहयोग की पेशकश की. अनवरुद्दीन को अपनी भूमि पर दो विदेशियों का युद्ध होना अच्छा नहीं लगा फलतः उसने डूप्ले से मद्रास को छोड़ने का आग्रह किया तथा मद्रास पर कब्जा करने का भी प्रयास किया, परन्तु उसे वांछित परिणाम नहीं मिला. अडियार नदी के तट पर हुए इस युद्ध में डूप्ले को मिली सफलता ने डूप्ले तथा ला-बूर्डोने के मध्य और भी अधिक कड़वाहट पैदा कर दी. उसी समय प्राकृतिक प्रकोप ऐसा हुआ कि भीषण आँधी और तूफान से फ्रांसीसी बेड़े को अत्यधिक क्षति पहुँची तथा ला-बूर्डोने को मॉरीशस लौटना पड़ा.

1748 ई. में एक्सलाशेपेल की संधि के परिणामस्वरूप युद्ध बंद हो गया. संधि का परिणाम यह हुआ कि दोनों कम्पनियों का अपने-अपने केन्द्रों पर पूर्ववत् आधिपत्य हो गया. इस युद्ध का मुख्य परिणाम या निष्कर्ष यह निकला कि यूरोपीय कम्पनियों को भारतीय राजाओं के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का रास्ता साफ हो गया.

प्रथम युद्ध का महत्व–इस युद्ध का सबसे अधिक प्रभाव भारत के ऊपर यह पड़ा कि भारतीय राजनीति का खोखलापन तथा यहाँ की सैनिक दुर्बलताएँ यूरोपीय शक्तियों के समक्ष उजागर हो गईं. कर्नाटक का नवाब एक व्यापारिक कम्पनी को युद्ध करने से नहीं रोक पाया तथा नवाब की सेना फ्रांसीसियों की सेना से परास्त हो गई. नवाब की हार के कारण ही फ्रांसीसियों के हौसले बुलन्द हो गये. इस सम्बन्ध में मैसलिन का कहना है कि "अधीनस्थ की स्थिति से फ्रांसीसी लोग छलांग मारकर प्रायः प्रभु की स्थिति में पहुँच चुके थे". इसी क्रम में प्रो. डॉडवेल ने अपने विचार रखते हुए कहा है कि "इसने डूप्ले के प्रयोग और क्लाइव की कृतियों के लिए एक रंगमंच खड़ा कर दिया".

कर्नाटक का द्वितीय युद्ध–1748 ई. में हैदराबाद के सूबेदार निजाम आसफजोह की मृत्यु के साथ ही साथ कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का श्रीगणेश हो चुका था. निजाम आसफजोह का पुत्र नासिरजंग हैदराबाद का निजाम बना. ऐसा करने के कारण निजाम आसफजोह की पुत्री का लड़का मुजफ्फरजंग नासिरजंग का विरोधी बन गया और उसने हैदराबाद का सिंहासन पाने के लिए फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त किया. दूसरी तरफ कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के विरोधी स्व. नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब को नवाब बनाने की कोशिश में थे. इस प्रकार अनिश्चय की स्थिति का फायदा उठाकर डूप्ले अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करना चाहता था, उसने तत्काल प्रभाव से इसका लाभ उठाने के लिए योजना बनाई.

अपनी रणनीति के तहत उसने मुजफ्फरजंग तथा चंदा साहब को समर्थन देना तय किया तथा साथ ही दोनों से समझौता भी कर लिया. समझौते के अनुसार मुजफ्फरजंग तथा चंदा साहब को सैनिक सहायता देने का वचन दिया तथा एक फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी भेजी. इस सेना की मदद से हैदराबाद में अनवरुद्दीन को हराकर मुजफ्फरजंग एवं कर्नाटक में नासिरजंग को हराकर चंदा साहब वहाँ की गद्दी पर आसीन हुए. इस सफलता के मिलने के बाद दोनों ने फ्रांसीसी कम्पनियों को काफी धन दिया. इसके साथ ही मुजफ्फरजंग ने डूप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया. उत्तरी सरकारों के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए. मुजफ्फरजंग के अनुरोध पर फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी डूप्ले ने कप्तान बुस्सी के अधीन हैदराबाद में तैनात कर दी. इस सारे क्रियाकलाप का मुख्य प्रभाव यह हुआ कि कर्नाटक पर फ्रांसीसियों का सीधा नियन्त्रण कायम हो गया. कर्नाटक तथा हैदराबाद पर डूप्ले की शक्ति में भी आशातीत वृद्धि हुई. फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज आशंकित हो उठे. वे उस मौके की तलाश में रहते जिससे फ्रांसीसियों पर अंकुश लगाया जा सके. संयोग से उन्हें एक मौका हाथ भी लग गया. उसी दौरान स्व. नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र मुहम्मद अली चंदा साहब के डर से भागकर त्रिचनापल्ली चला गया. उसको वहाँ अंग्रेजों से कुछ

सहायता मिलने की अपेक्षा थी. अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाकर मुहम्मद अली को अपने संरक्षण में लेकर फ्रांसीसियों से मुकावला करने की तैयारी कर ली.

फ्रांसीसियों ने काफी कोशिश की कि त्रिचनापल्ली का दुर्ग उनके कब्जे में आ जाए, परन्तु वे इसमें सफल नहीं हो पाए. इस समय की विषम परिस्थिति में अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने की नौवत आ चुकी थी, परन्तु क्लाइव ने दूरदर्शिता का उदाहरण देते हुए फ्रांसीसियों का ध्यान त्रिचनापल्ली से हटाने के लिए चंदा साहब की राजधानी आर्काट पर घेरा डाल दिया. चंदा साहब को मजबूरन अपनी सेना आर्काट भेजनी पड़ी. यह सेना अंग्रेजों से आर्काट को मुक्त नहीं करा सकी. इस प्रकार डूप्ले तथा फ्रांसीसियों की यह अंग्रेजों के हाथों प्रथम पराजय थी. इस पराजय ने डूप्ले की महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर दिया. इसी बीच त्रिचनापल्ली पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया. इसी समय चंदा साहव भागकर तंजौर पहुँचा जहाँ उसकी हत्या कर दी गई. इस मौके का फायदा उठाकर मुहम्मद अली, जोकि अंग्रेजों का हिमायती भी था कर्नाटक का नवाव वन वैठा. डूप्ले ने अपनी शक्ति तथा प्रभाव को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, परन्तु वह सफल नहीं हो सका. इस प्रकार उससे अप्रसन्न होकर 1754 ई. में फ्रांस की सरकार ने उसको वापस बुला लिया. उसके स्थान पर गोडेहू को भेजा गया, जिसने अंग्रेजों से संधि करके द्वितीय कर्नाटक युद्ध के रंगमंच का पटाक्षेप कर दिया.

कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का महत्त्व—यदि परिणामों की दृष्टि से देखा जाए तो यह निष्कर्ष सामने आता है कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध प्रथम युद्ध की अपेक्षा कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण रहा. इस युद्ध के परिणामस्वरूप डूप्ले तथा फ्रांसीसियों की समस्त आकांक्षाएँ चूर-चूर हो गईं. अंग्रेजों की स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ हो गई. इस युद्ध ने विदेशियों के समक्ष भारत के देशी राजाओं की कलई खोलकर रख दी.

कर्नाटक का तृतीय युद्ध—भले ही कर्नाटक के दूसरे युद्ध में अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों को अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, परन्तु उनके मनोवल में कहीं कोई कमी नहीं आई थी तथा वे इसका वदला लेने की दृष्टि से मौके की तलाश में भी थे. 1756 ई. में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के शुरू होने के साथ ही साथ दोनों शक्तियों का एक वार फिर जवर्दस्त टकराव हुआ. इस समय अर्थात् 1758 ई. तक वंगाल पर अंग्रेजों की विजय (प्लासी का युद्ध) ने उनकी स्थिति और सुदृढ़ कर दी. दूसरी ओर भारत में फ्रांसीसी प्रतिष्ठा को फिर से कायम करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने 1757 ई. में काउंट लैली को भारत भेजा. वह 1758 ई. में भारत पहुँचा. यह सही है कि वह वीर, साहसी तथा कुशल सेनापति था, परन्तु उसके अन्दर एक कमी थी कि वह जिद्दी था और बिना सोचे-विचारे निर्णय लेता था. इसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा.

उसने आते ही सेंट डेविड के किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया तत्पश्चात् उसने तंजौर के शासक के पास अपनी सेना भेजी. उस पर फ्रांसीसी कम्पनी के करीव 60-70 लाख रुपये बकाया थे, जिन्हें वह वसूलना चाहता था. अपने मकसद में सिद्धि पाने के लिहाज से उसने तंजौर पर आक्रमण कर दिया, परन्तु अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण उसका मिशन पूरा नहीं हो सका. इस पराजय से क्षुब्ध होकर उसने अंग्रेजों के गढ़ मद्रास पर आक्रमण करने की योजना वनाई. अपनी सहायता के लिए उसने हैदरावाद से वुसी को भी वुला लिया. अपनी योजना के अनुसार 1758 ई. में फ्रांसीसी सेना ने मद्रास को घेर लिया. इस स्थिति का मुकावला करने के लिए क्लाइव ने कर्नल फोर्ड को मद्रास भेजा जिसने मछलीपट्टम (मसूलीपट्टनम) पर अपना अधिकार कर लिया.

उधर अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम से मिलकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली तथा इसी समय के मध्य एक और जहाजी बेड़ा अंग्रेजों की सहायता के लिए आ गया जिसका परिणाम यह हुआ कि लैली को उल्टे पैर लौटना पड़ा. इस स्थिति से लैली के मन में निराशा घर कर गई. उसकी हालत कमजोर हो गई, क्योंकि न तो उसके पास पर्याप्त साधन ही थे और न ही गृह सरकार से उसे पर्याप्त सहायता मिल सकी थी. फिर भी वह अंग्रेजों के विरुद्ध छुटपुट युद्ध करता रहा. इन युद्धों के चलते 1760 ई. में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसे वांडीवाश के युद्ध के नाम से जाना जाता था, जिसमें अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसियों को वुरी तरह पराजित करके बुसी को गिरफ्तार कर लिया. लैली ने हताश होकर मैसूर के शासक हैदरअली से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता करने की गुहार की, परन्तु हैदरअली वादा करके ऐन वक्त पर मुकर गया. अंग्रेजों ने मद्रास का वदला लेने की गरज से पांडिचेरी पर घेरा डाल दिया. हालांकि लैली ने अंग्रेजों का डटकर मुकावला तो किया, परन्तु अन्त में उसे हथियार डालने पड़े और उसने 1761 ई. में समर्पण कर दिया. परिणाम यह हुआ कि पांडिचेरी पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया. इसके बाद उन्होंने माही तथा जिंजी पर भी अधिकार कर लिया.

तृतीय युद्ध के परिणाम—तीसरा युद्ध फ्रांसीसियों की सत्ता समूल नष्ट करने के रूप में जाना जाता है. चूँकि लैली अपनी क्रियाविधि से कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं कर सका था. अतः फ्रांसीसी सरकार ने उसे वापस बुलाकर 1763 ई. में मृत्युदंड की सजा दे दी. इस युद्ध के कारण भारत में अंग्रेज सर्वोच्च शासक के रूप में प्रतिष्ठित हुए. सप्तवर्षीय युद्ध की

समाप्ति पर दोनों पक्षों में संधि हो गई जिसके अनुसार फ्रांसीसियों को पांडिचेरी पुनः मिल गया (पेरिस की संधि के अनुसार); परन्तु उन्हें इसकी किलेबंदी का अधिकार नहीं दिया गया था. बंगाल से भी फ्रांसीसियों का पत्ता साफ हो गया. कहने का तात्पर्य यह है कि अब अंग्रेज ही सर्वोच्च तथा सर्वाधिक सत्तासीन माने गए.

अंग्रेजों की सफलता के कारण

अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध में अंग्रेजों को ही विजयश्री मिली, जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे–

फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीति में उलझना–यूरोप की राजनीति में उलझे रहना फ्रांसीसियों की हार का मुख्य कारण था. फ्रांस की सरकार इटली-जर्मनी आदि क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास में लगी रहती थी, जिसके फलस्वरूप वह भारत की ओर व्यवस्थाएँ बनाने में अपना समुचित ध्यान नहीं दे पाती थी. ठीक इसके विपरीत अंग्रेजों का एक ही लक्ष्य था भारत में अपना प्रभुत्व जमाना और उन्होंने अपने षड्यंत्रों के अनुसार अपनी पूरी ताकत भारत की ओर लगाई जिससे उन्हें अपने कार्य में वांछित परिणामों की प्राप्ति हुई.

फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों की व्यवस्थाओं में अन्तर–फ्रांसीसी सरकार में तानाशाही तथा स्वेच्छाचारिता की भावना थी. इस भावना ने पन्द्रहवें लुई शासक के शासनकाल में और भी विकराल रूप धारण कर लिया था. इसका परिणाम यह हुआ कि देश में भ्रष्टाचार, अपव्यय तथा अराजकता का माहौल आवश्यकता से अधिक व्याप्त हो गया और फ्रांसीसी सरकार अपने हितों की रक्षा सही ढंग से नहीं कर सकी. इस कारण जब-जब फ्रांसीसियों को भारत में अंग्रेजों से लड़ते समय सहायता की आवश्यकता पड़ी, उन्हें सहायता नहीं मिल पाई. फ्रांसीसियों के भ्रष्ट तथा गैरजिम्मेदारानापूर्ण क्रियाकलापों की वजह से फ्रांसीसी युद्ध में हारते रहे.

फ्रांसीसी सरकार की उपनिवेशों में कम रुचि–फ्रांसीसी सरकार अपने आंतरिक विद्रोह तथा आपसी झगड़ों में इतनी व्यस्त थी कि वह भारत में अपनी सरकार जमाने के प्रति पर्याप्त दिलचस्पी नहीं दिखा पाई. इसलिए वह यथोचित ध्यान नहीं दे सकी, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजों ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए हरसम्भव प्रयास किए.

फ्रांसीसी नौसेना का अशक्य होना–अंग्रेजों के पास शक्तिशाली नौसेना थी. भारत की तात्कालिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की थीं कि जिस देश के पास पर्याप्त नौसना होती वही सही मायने में भारत पर अपना अधिकार कर सकता था. उस समय भारत में व्यापारिक तथा सैनिक सफलता की दो ही मुख्य शर्तें थीं कि भारतीय तट पर दृढ़ आधार स्थापित किया जाए तथा सामुद्रिक शक्ति पर्याप्त हो. इन दोनों ही प्रकार की व्यवस्था में फ्रांसीसियों की अपेक्षा अंग्रेज अधिक कुशल सिद्ध हुए, परिणामतया उन्हें अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने में आसानी रही.

अंग्रेजों की कुशल सैन्य नीति–अंग्रेजों के बजाय फ्रांसीसियों के पास भौगोलिक महत्व के स्थानों की कमी थी. उनके पास सामुद्रिक किनारों का अभाव था. उनकी शक्ति का प्रमुख केन्द्र पांडिचेरी था जहाँ पर मद्रास की अपेक्षा कम सुविधाएँ थीं, जिसके कारण अंग्रेजों ने अपनी धाक सरलता से जमा ली.

दोनों कम्पनियों के पदाधिकारियों में अन्तर–फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी कम्पनियों के पदाधिकारियों के नेतृत्व में जमीन-आसमान का अन्तर था. अंग्रेजी कम्पनी को क्लाइव, लॉरेंस तथा फोर्ड जैसे कुशल नेतृत्व करने वाले मिले थे. वे धैर्यवान, कुशल तथा साथ ही व्यवहारकुशल भी थे, जबकि फ्रांसीसी कम्पनी के नेतृत्वकारियों की हठधर्मिता, जल्दबाजी, अयोग्यता तथा अदूरदर्शिता के कारण उन्हें पराजय का मुँह देखना पड़ा.

फ्रांसीसियों की धार्मिक नीति–अनुदार धार्मिक नीति के कारण भी फ्रांसीसी अपने ध्येय की प्राप्ति में असफल रहे थे. अंग्रेजों की धार्मिक नीति ज्यादा उदार तथा सहिष्णु थी, जो अंग्रेजों के लिए सहायक सिद्ध हुई. भारतीयों का उन्हें पर्याप्त सहयोग एवं समर्थन मिला.

डूप्ले की भ्रांतिपूर्ण नीतियाँ–फ्रांसीसियों के पतन में मुख्य रूप से फ्रांसीसी कम्पनी के नेतृत्वकारी डूप्ले की भ्रांतिपूर्ण नीतियों का प्रमुख हाथ रहा. उसने भारत में व्यापार करने की अपेक्षा राजनीति करने की ओर अपना रुख रखा. वह राजनीतिक षड्यंत्रों में इतना अधिक उलझ चुका था कि वह चाहते हुए भी व्यापार की सफलता की तरफ उचित ध्यान नहीं दे सका.

उपर्युक्त कारणों की वजह से तथा अन्य कई कारणों से भी भारत में अंग्रेजों के हाथों फ्रांसीसियों को धूल चाटनी पड़ी और अंग्रेज अपनी विजय पताका फहराने में कामयाब हुए.

बंगाल विजय–अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर 18वीं शताब्दी में बंगाल पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया. बंगाल में आशातीत सफलता मिलने से अंग्रेजों का सम्पूर्ण भारत पर एकाधिकार हो गया. बंगाल में अंग्रेजी सत्ता दो महत्वपूर्ण युद्धों का परिणाम थी. ये दोनों युद्ध थे प्लासी तथा बक्सर का युद्ध. बंगाल विजय का परिणाम यह हुआ कि जो अंग्रेज भारत में व्यापारी की हैसियत से आए वे यहाँ के शासक बन बैठे.

बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार–बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की शक्ति के विस्तार में प्लासी का युद्ध महत्त्वपूर्ण माना जाता है जो 1757 ई. में हुआ. उस समय मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर अलीवर्दी खाँ 1740 ई. में वहाँ का नवाब बन गया, लेकिन वह शासन व्यवस्था

को सँभाल नहीं सका. 1756 ई. में उसकी मृत्योपरांत बंगाल की स्थिति ज्यादा दयनीय हो गई. जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया.

प्लासी का युद्ध–प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में एकछत्र राज्य करने का अवसर प्रदान किया. यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कम्पनी के आपसी संघर्ष की परिणति थी.

प्लासी युद्ध के कारण और महत्व–अंग्रेजों की स्वार्थपरता तथा बंगाल की तात्कालिक परिस्थिति ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया. जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद बिहार के नायब-निजाम अलीवर्दी खाँ ने मौके का फायदा उठाकर स्वयं को बंगाल का स्वतन्त्र नवाब घोषित कर दिया. बंगाल का नवाब बनने से पहले उसने वहाँ के तत्कालीन नवाब सरफराज के साथ युद्धकर तथा उसे मार डाला. नवाब बनने के तुरन्त बाद अलीवर्दी खाँ ने मुगल सम्राट् मुहम्मदशाह को अपार धन का लालच देकर अपनी नवाबी की मान्यता को कानूनन पक्का कर लिया था. उसने कुशलता से शासन तो किया, परन्तु पूर्णतया सफल शासन नहीं कर सका.

जब 9 अप्रैल, 1756 ई. में उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी सबसे छोटी बेटी का लड़का सिराजुद्दौला राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ. सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खाँ ने अपने जीवनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था. सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही बंगाल में उपद्रव होने शुरू हो गए. उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसका पुत्र शौकत जंग, जोकि उस समय पूर्णिया का शासक था तथा उसका दीवान राजवल्लभ सिराजुद्दौला के प्रमुख विरोधी थे. इन लोगों ने सेनापति मीरजाफर, कलकत्ता के एक व्यापारी अमीचंद तथा जगत सेठ को भी अपने खेमे में मिला रखा था. ये लोग सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारकर अपना मनचाहा व्यक्ति गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन सिराजुद्दौला ने चालाकी से घसीटी बेगम को कैद कर उसकी सारी सम्पत्ति हड़प ली तथा अपने पुत्र को 16 अक्टूबर, 1756 ई. में मनीहारी के युद्ध में परास्त करके मार डाला.

इतने समयांतराल में अंग्रेजों ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी. उनके हौसले काफी बढ़ चुके थे तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो चुकी थी. उनके क्रिया-कलापों से सिराजुद्दौला सशंकित रहने लगा था और कुछ अधिक ही सावधानी भी बरतने लगा.

सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य युद्ध के कारण–अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध होने के कई प्रमुख कारण थे, जिनमें से कुछ पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है–

जब सिरजुद्दौला नवाब बना था तो उस समय की परम्परा के अनुसार अंग्रेजों ने उसे नजराना नहीं भेजा, जिसके कारण उसने स्वयं को अपमानित महसूस किया. अंग्रेज उसके अधिकारियों से ही सारा काम निकलवा लेते थे तथा उसकी अवहेलना भी करते थे. एक बार तो उन्होंने खुद नवाब को ही कासिम बाजार की कोठी में ही आने से रोक दिया. इसके अलावा अंग्रेजों ने उसके मना करने पर भी कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर किलेबंदी करना चालू रखा तथा सिराजुद्दौला के विरोधियों से उनकी साँठ-गाँठ थी. वे उन्हें अपने यहाँ शरण देते और उनसे राज की बातें भी मालूम करते थे. ऐसी स्थिति में दोनों में टकराव होना स्वाभाविक था. जब सिराजुद्दौला ने यह देखा कि फ्रांसीसियों ने तो चंद्रनगर की किलेबंदी करना उसके कहने से बंद कर दिया था, परन्तु अंग्रेजों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया. वह अंग्रेजों को एक शासक के रूप में नहीं, अपितु एक व्यापारी के रूप में ही देखना चाहता था. उधर अंग्रेज भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण सदैव उसकी अवहेलना करके उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण सिराजुद्दौला के मन में अंग्रेजों के प्रति विष की बेल दिन प्रतिदिन पनपती हुई आगे बढ़ गई.

संघर्ष का प्रथम चरण–सिराजुद्दौला की ओर से अंग्रेजों के लिए यह आदेश भेजा गया कि वे फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट कर दें, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी इस माँग को ठुकरा दिया. इसके एवज में उसने मई, 1756 ई. में कासिमबाजार पर हमला करके उसे अपने अधिकार में ले लिया. इसके बाद उसने कलकत्ता पर आक्रमण किया तथा 20 जून, 1756 ई. को फोर्ट विलियम किले को जीत लिया. इस विजय के कारण ही अंग्रेज गवर्नर ड्रेक को फुल्टा द्वीप में जाकर शरण लेनी पड़ी. इस विजय के पश्चात् उसने अंग्रेजों को बंदी बनाया और मानिकचंद के हाथ में कलकत्ता का राज्यभार सौंप दिया और स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया.

काली कोठरी की दुर्घटना–काली कोठरी की दुर्घटना ने अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के सम्बन्धों में और भी अधिक कड़वाहट पैदा कर दी. घटना यह थी नवाब के अधिकारियों ने फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद 146 अंग्रेज कैदियों को, जिनमें स्त्रियाँ और बच्चे भी थे, एक छोटे अँधेरे कमरे में जो 18 × 14·10 फुट का था बंद कर दिया. जून के महीने में अगली सुबह उन कैदियों में से 23 व्यक्ति ही जिन्दा बचे थे. बचने वालों में हॉलवेल भी था, जिसने इस घटना का प्रचार किया था.

अंग्रेजों की प्रतिक्रिया–जब इस घटना की खबर मद्रास पहुँची तो अंग्रेजों का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था. बदला लेने के उद्देश्य से क्लाइव तथा वाटसन सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े. उन्होंने नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर

अपने पक्ष में कर लिया. परिणामस्वरूप मानिकचंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया, कलकत्ता के बाद अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया. ऐसी विषम परिस्थितियों में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा. एक संधि जो 9 फरवरी, 1757 ई. को दोनों के मध्य हुई उसके अनुसार अंग्रेजों को पूर्व में प्रदत्त सारी सुविधाएँ वापस मिलनी थीं. यह संधि अलीनगर की संधि के नाम से जानी जाती है. इसके अनुसार अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी कर सकते थे तथा अपना सिक्का चला सकते थे. नवाब को अंग्रेजों के लिए जब्त फैक्ट्रियाँ, सम्पत्ति तथा आदमियों को लौटाने का वचन देना पड़ा. नवाब की ओर से कम्पनी को हर्जाना भी दिया जाना था. हालांकि यह संधि नवाब की शान के खिलाफ थी, परन्तु इसके अलावा उसके पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं बचा था.

अंग्रेजी षड्यंत्र और प्लासी युद्ध का आरम्भ–अंग्रेजों की नीति कुछ और ही थी, वे इस संधि से भी प्रसन्न नहीं थे. वे किसी ऐसे व्यक्ति को शासक बनाना चाहते थे जो उनके कार्य में बाधा न डाले. क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरोधियों से मिलकर मीरजाफर से एक गुप्त संधि कर ली जिसके अनुसार उसे नवाब बनाने का लोभ दिया. इसके प्रतिफल के रूप में उसने कासिम बाजार, ढाका तथा कलकत्ता की किलेबंदी करने, कम्पनी के लिए एक करोड़ रुपया देने तथा उसकी सहायता के लिए भेजी गई सेना का खर्च वहन करने का अंग्रेजों को आश्वासन दिया.

अपनी षड्यंत्र नीति के तहत क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया. इस समय उसकी हालत अत्यन्त दयनीय थी. दरबारीजनों के षड्यंत्र तथा अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण के खतरे ने उसको और भ्रमित कर दिया. नवाब ने मीरजाफर को अपनी ओर मिलाने की कोशिश भी की, परन्तु वह सफल नहीं हो सका. अंग्रेज इसी मौके की तलाश में थे. अपने प्रयासों में असफल रहने पर नवाब आगे बढ़ा. 23 जून, 1757 ई. को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना-सामना हुआ, परन्तु सिराजुद्दौला के थोड़े ही सैनिकों ने भाग लिया. आन्तरिक विद्रोह के कारण उसे हारना पड़ा. वह जान बचाकर भागा, परन्तु मुर्शिदाबाद में मीरजाफर के पुत्र ने (मीरन ने) उसे पकड़कर मरवा डाला.

युद्ध का महत्व व परिणाम–भारतीय इतिहास में प्लासी के युद्ध का अत्यन्त ही व्यापक तथा स्थायी परिणाम निकला. क्लाइव ने मीरजाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जिसके बदले में उसने अंग्रेजों को बेशुमार धन-सम्पदा और ढेरों सुविधाएँ प्रदान कीं. मीरजाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था, अंग्रेज उससे मनचाहा काम करवा सकते थे. प्लासी के युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेज बंगाल की राजनीति पर नियन्त्रण करने में कामयाब हो गए. अब वे व्यापारी के स्थान पर राजशक्ति के स्रोत बन गए. आर्थिक दृष्टि से भी अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण करना प्रारम्भ कर दिया. इसी युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजी सत्ता-स्थापना की प्रक्रिया की नींव रखी गई. बंगाल से प्राप्त किए गए धन से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर निर्णायक विजय प्राप्त की. नवीन चन्द्र सेन ने इस बारे में कहा है कि "प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि आरम्भ हो गई."

ताराचंद के अनुसार, "प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लम्बी प्रक्रिया आरम्भ की, जिसने भारत का स्वरूप ही बदल दिया. सदियों से प्रचलित आर्थिक तथा शासकीय व्यवस्था बदल गई."

बक्सर का युद्ध–इस युद्ध को दूसरा चरण कहा जाता है और प्लासी के युद्ध की अपेक्षा इस युद्ध के अधिक प्रभावी तथा स्थायी परिणाम निकले. सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह रही कि इस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की पूर्णरूपेण स्थापना कर दी.

बक्सर युद्ध के कारण और महत्व–जब प्लासी के युद्ध के बाद मीरजाफर नवाब बना तो अंग्रेजी कम्पनी की पौ-बारह हो गई, क्योंकि जैसा कम्पनी चाहती वैसा ही होता. वह कम्पनी के हाथ की कठपुतली बन चुका था. सारी शक्ति क्लाइव के हाथों में निहित हो गई. मीरजाफर ने ढेरों वादों को पूरा किया तथा कम्पनी के लिए पर्याप्त धन भी दिया, परन्तु कम्पनी की माँग दिन पर दिन बढ़ती गई. परिणाम यह हुआ कि मीरजाफर की प्रशासनिक व्यवस्था लड़खड़ाने लगी. मिदनापुर, ढाका, पटना, पूर्णिया आदि स्थानों पर विद्रोह होने शुरू हो गए. मीरजाफर ने कम्पनी की सहायता से विद्रोहों पर अंकुश लगाना चाहा पर उसे सफलता नहीं मिली. कम्पनी की मनमानी के कारण एक मोटे तौर पर मीरजाफर पर 1760 ई. तक कम्पनी का करीब 25 लाख रुपए बकाया हो गए. इसी समय बंगाल में डचों का हस्तक्षेप भी शुरू हो चुका था. 1759 ई. में अलीगौहर ने बंगाल पर हमला बोल दिया तथा स्थिति मीरजाफर के नियन्त्रण से बाहर होती जा रही थी. जब तक क्लाइव का हाथ रहा कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, परन्तु 1760 ई. में जब वह चला गया तो मीरजाफर स्वयं को असहाय महसूस करने लगा. अब क्लाइव के स्थान पर हॉलवेल और वैन्सिर्टाट ने गवर्नर के रूप में सत्ता सँभाली. इन लोगों का भी मीरजाफर के ऊपर दबाव बना रहा, परन्तु स्थिति नियंत्रण में न होने के कारण मीरजाफर असहाय था. परिणामतया अंग्रेजों ने उसे गद्दी से हटाने की योजना बना ली. योजना के तहत अंग्रेजों ने उसके दामाद मीरकासिम से एक गुप्त समझौता करके कम्पनी के लिए धन की माँग पूरी करने का वचन ले लिया. 14 अक्टूबर, 1760 ई. को मीरजाफर को घेर लिया गया, उसे गद्दी छोड़नी पड़ी. वह

मुर्शिदाबाद छोड़कर कलकत्ता चला गया. उसके लिए 15 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाने लगी. मीरकासिम नवाब बन चुका था.

हालांकि मीरकासिम भी षड्यंत्र के तहत ही नवाब बना था, परन्तु वह मीरजाफर से कहीं अधिक योग्य तथा कुशल था. उसने बिगड़ती हुई प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए विद्रोही जमींदारों को दबाया, भ्रष्ट कर्मचारियों से राजकीय धन वसूलना शुरू किया, अतिरिक्त कर लगाए तथा सेना को प्रशिक्षित करके अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति पाने के लिहाज से अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया. सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई.

संघर्ष की शुरूआत–मीरकासिम के इस प्रकार के व्यवहार से कम्पनी कुछ शंका करने लगी, क्योंकि वह तो ऐसा शासक चाहती थी जो कि उसकी अनुपालना करे, परन्तु मीरकासिम उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा. अतः अंग्रेजों के द्वारा उसे गद्दी से हटाए जाने के प्रयास किए जाने लगे. स्वयं के कर्मचारियों की अंतर्कलह, उपेक्षा तथा अंग्रेजों की लूट-खसोट से परेशान होकर उसने देशी व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी. इस निर्णय से अंग्रेजों को "दस्तक" का दुरुपयोग करके धन कमाने की सुविधा खत्म हो गई. इस पर क्रुद्ध होकर अंग्रेजों ने सैनिक कार्यवाही की योजना बनाकर 25 मई, 1763 ई. को **ऐमायट** तथा **हे मुंगेर** ने कम्पनी की ओर से नवाब के समक्ष 11 सूत्रीय माँगें रख दीं जिनको उसने ठुकरा दिया. इसी बीच पटना के अंग्रेज अफसर एलिस को कलकत्ता कौंसिल ने नगर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया. एलिस ने 24 जून, 1763 ई. को पटना पर अधिकार कर लिया. जब मीरकासिम को यह पता चला, तो उसने पटना पर आक्रमण करके पुनः अपना अधिकार कर लिया.

पटना की घटना–दूसरी तरफ मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक सेना ने मुर्शिदाबाद की ओर कूच किया. मुंगेर से मीरकासिम ने भी रवानगी ली. रास्ते में अनेक स्थानों जैसे–कटवा, गिरिया तथा सुती में अंग्रेजों की सेना ने मीर की सेना को परास्त कर दिया. सबसे प्रमुख युद्ध उदयनाला के पास हुआ जिसमें मीरकासिम बुरी तरह परास्त हुआ. पराजय से विक्षुब्ध मीरकासिम ने पटना में गिरफ्तार करीब 148 अंग्रेज सैनिकों की हत्या करवा दी, जिनमें एलिस भी शामिल था. अंग्रेजों ने मौका पाकर पुनः मीरजाफर को नवाब बनवा दिया. मीरकासिम के अधिकारियों की गद्दारी के कारण पटना और मुंगेर उसके हाथ से निकल गए. उसे 1763 ई. में अपना राज्य छोड़कर अवध में शरण लेनी पड़ी.

बक्सर का युद्ध–जब मीरकासिम भागकर अवध पहुँचा तो उस समय वहाँ का नवाब शुजाउद्दौला था. उस समय मुगल सम्राट् शाहआलम भी वहीं मौजूद था. उसने नवाब वजीर को सैनिक खर्च देने का वादा किया. अतः वह मीरकासिम का साथ देने को तैयार हो गया. तीनों की सम्मिलित शक्ति से डरकर अंग्रेजों ने अवध नरेश को अपने में मिलाने का असफल प्रयास किया. तीनों ने मिलकर बिहार की तरफ प्रस्थान किया. 23 अक्टूबर, 1764 ई. को बक्सर के पास युद्ध हुआ. मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जमकर युद्ध किया. इस युद्ध में अंग्रेजों की ही विजय हुई. मीरकासिम युद्ध क्षेत्र से भाग गया और 1777 ई. में दिल्ली के निकट उसकी मृत्यु हो गई. कुछ समय तक तो नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेजों का विरोध करता रहा, परन्तु कारा के युद्ध में पराजित होने के बाद उसने भी 1765 ई. में अंग्रेजों के समक्ष अपने हथियार डाल दिए. शाहआलम ने बाद में अंग्रेजों से सन्धि कर ली.

बक्सर युद्ध के परिणाम–बक्सर युद्ध के परिणाम प्लासी युद्ध के परिणामों से कहीं अधिक स्थायी एवं प्रभावी थे. बक्सर युद्ध ने प्लासी युद्ध के निर्णयों पर मुहर लगा दी. इस युद्ध के अंजाम स्वरूप बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया. बंगाल में ऐसा नवाब प्रतिष्ठित हुआ जो कि अंग्रेजों की कठपुतली मात्र ही था. अवध नवाब और मुगल सम्राट् की पराजय से अंग्रेज उत्तरी भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए. 1765 ई. में हुई इलाहाबाद की संधि के अनुसार शुजाउद्दौला ने शाहआलम को इलाहाबाद तथा कारा के जिले दिए और कम्पनी को हर्जाने के रूप में 50 लाख देने स्वीकार किए तथा साथ ही अंग्रेजी सेना का खर्च भी. शाहआलम ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कम्पनी को दे दी. बक्सर के युद्ध के परिणामस्वरूप ही अंग्रेजी कम्पनी की सीमाएँ गंगा पार बनारस तथा इलाहाबाद तक पहुँच गईं. इसके कारण ही बंगाल के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों से जो उनका सम्बन्ध हुआ उससे पहली बार वे एक नवीन, उन्नत तथा प्रभुत्वमय सम्बन्ध स्थापित कर सके. मैलिसन ने इस युद्ध के बारे में यहाँ तक लिखा है कि "बक्सर विजय से अंग्रेजों को न केवल बंगाल ही मिला, न केवल अंग्रेजों की सीमाएँ इलाहाबाद तक पहुँची, अपितु इससे अवध के शासक विजयी शक्ति के कृतज्ञतापूर्ण निर्भरता तथा विश्वास के बन्धनों से बँध गए, जिसने आने वाले 94 वर्षों तक उनको मित्रों का मित्र तथा शत्रुओं का शत्रु बनाए रखा." यह कम्पनी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी.

इतिहासकार ताराचंद ने बक्सर युद्ध के बारे में अपना मत देते हुए कहा है कि "प्लासी युद्ध ने सत्ता का हस्तान्तरण किया और बक्सर युद्ध ने अधिकारों का सृजन किया. कम्पनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हुआ तथा राजनीतिक सत्ता के अन्तर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार युग का आरम्भ हुआ.

अंग्रेजों ने 1763 ई. में मीरकासिम को गद्दी पर से हटाकर मीरजाफर को दोबारा नवाब बना दिया, परन्तु वह नाममात्र का शासक था. अंग्रेजों ने मीरजाफर के दीवान राजा नंदकुमार को पदच्युत कर बंगाल के प्रशासन पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी. मीरजाफर यह सब देखता रहा, परन्तु वह अंग्रेजों के सामने निरीह था. अंग्रेजों ने उसे जी भरकर लूटा. 1765 ई. में जब मीरजाफर की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र नजमुद्दौला गद्दी पर बैठा. उसने भी अंग्रेजों के साथ एक संधि की जिसके आधार पर सुरक्षा, वित्त, सेना तथा बाह्य सम्बन्धों पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया. राजा नंदकुमार पर आरोप लगाकर मृत्युदण्ड दिया गया. अंग्रेजों की मनमानी शुरू हो गई. चारों तरफ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई. परिस्थिति को सुधारने के उद्देश्य से क्लाइव को गवर्नर बनाकर पुनः बंगाल भेजा गया. उसने अपनी कूटनीतियों से बंगाल पर अंग्रेजों का स्थायी प्रभुत्व कायम किया. क्लाइव के आगमन तक बंगाल के प्रशासन पर कम्पनी का पूर्ण आधिपत्य कायम हो चुका था. अगस्त, 1765 ई. में कम्पनी को स्थायी रूप से बंगाल की दीवानी भी मिल गई जिससे कम्पनी का कार्यभार बहुत बढ़ गया. यदि क्लाइव चाहता तो बंगाल के नवाब पद को खत्म कर सकता था, परन्तु उसने अपनी कूटनीति के तहत ऐसा नहीं किया तथा बंगाल की व्यवस्था नए शुरूआत के साथ की.

बंगाल की व्यवस्था–हालांकि कम्पनी ने मीरजाफर के पुत्र को बंगाल की गद्दी पर तो बैठाया, परन्तु उसके साथ यह शर्तें लगा दीं कि वह निजामत सम्बन्धी कार्य अर्थात् विदेशी मामले तथा सैनिक संरक्षण और फौजदारी के मामले कम्पनी के हाथों में सौंप दे. नजमुद्दौला ने कम्पनी की शर्तों के अनुसार दीवानी सम्बन्धी मामलों को एक डिप्टी सूबेदार के हाथों सौंप दिया जोकि कम्पनी द्वारा बहाल किया गया था. क्लाइव ने जो अपनी नई कूटनीति चलाई उनसे वहाँ का शासक मात्र एक नाम का ही शासक रह गया था. सारी शक्ति कम्पनी के हाथों में आ गई थी.

बंगाल में द्वैध शासन–द्वैध शासन का अर्थ है दोहरी नीति अथवा दोहरा शासन बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक क्लाइव ही था. उसने द्वैध व्यवस्था के अनुसार, यह योजना बनाई कि विदेश व्यापार-नीति और विदेशी व्यापार का प्रबन्ध तो कम्पनी अपने हाथ में ले ले तथा लगान वसूलने एवं न्याय के लिए भारतीय अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाए. इस चालाकी भरे कदम से यह हुआ कि दीवानी सम्बन्धी कामों का जिम्मा कम्पनी के नियन्त्रण में चला गया. लगान वसूल करने के लिए मुहम्मद रजा खाँ को बंगाल का तथा सिताब राय को बिहार का नाजिम बनाया गया. इनके केन्द्रीय दफ्तर क्रमशः मुर्शिदाबाद और पटना में

मुगल सम्राट् को तथा 53 लाख रुपए नवाब को मिलने थे. नवाब को नियन्त्रण में रखने के लिहाज से मुहम्मद रजा खाँ को ही दीवान नियुक्त किया गया जोकि अंग्रेजों का विश्वास-पात्र था. इस प्रकार, बंगाल में दोहरी व्यवस्था लागू की गई–कम्पनी एवं नवाब की. इस व्यवस्था का परिणाम यह रहा कि कम्पनी का धन पर पूरा अधिकार हो गया और प्रजा के प्रति उसका कोई कर्त्तव्य नहीं रहा. दूसरी तरफ, प्रजा का उत्तर-दायित्व नवाब पर डाला गया, परन्तु उसके पास न तो धन ही था और न ही सेना. इसी तरह इस व्यवस्था का प्रक्रम 1772 ई. तक वारेन हस्टिंग्स के आने तक चलता रहा.

द्वैध शासन से लाभ तथा हानि–क्लाइव द्वारा लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली से अंग्रेजों के लिए लाभ ज्यादा रहा. इसके द्वारा वास्तविक शक्ति की मालिक कम्पनी ही बन गई. अंग्रेज लोग अब व्यापारी नहीं, बल्कि यहाँ के शासक बन चुके थे. जो विदेशी कम्पनियाँ भारत में व्यापार करती थीं उनसे भी उन्हें आय होने लगी थी. चूँकि कम्पनी के पास योग्य पदाधिकारियों की कमी थी. अतः उसने बंगाल की लगान व्यवस्था सँभालने के लिए भारतीय पदाधिकारियों की सेवा लेनी शुरू कर दी. इस व्यवस्था से कम्पनी के खर्च में कमी आई तथा उसे पर्याप्त मात्रा में आर्थिक लाभ हुआ.

हालांकि इस दोहरी व्यवस्था से जहाँ कम्पनी शुरूआत में लाभ में रही और वहीं अंत में यह व्यवस्था कम्पनी के लिए दुष्कर सिद्ध हुई. 1767 ई. में जब क्लाइव लौटा तो इस व्यवस्था के दोष पूरी तरह उजागर हुए. कम्पनियों के कर्मचारियों की मनमानियाँ बढ़ गईं, उद्योग-धन्धे नष्ट हो गए, प्रशासनिक ढाँचा लड़खड़ा गया तथा कम्पनी को व्यापार में भी काफी घाटा उठाना पड़ा. मुख्य रूप से निम्नलिखित दुष्परिणाम सामने आए.

प्रशासनिक अव्यवस्था–सम्पूर्ण बंगाल में सरकार नाममात्र के लिए रह गई. सर्वत्र अराजकता, भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्था का आलम हो गया. कम्पनी तथा नवाब दोनों के कर्मचारी पथभ्रष्ट होकर प्रजा पर अत्याचार करने लगे. अनुशासन-हीनता का बोलबाला था.

अधिकारों व उत्तरदायित्वों का पृथक्करण–क्लाइव के द्वारा चलाई गई इस द्वैध शासन प्रणाली से नवाब के अधिकार कुछ भी नहीं रहे. सारे कार्यों के लिए उसे कम्पनी पर ही आश्रित होना पड़ता था. नवाब के हाथ में न धन रहा, न शक्ति. नवाब साधनों के अभाव में, चाहते हुए भी जनता को राहत नहीं पहुँचा सकता था. परिणामस्वरूप उसने शासन में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया. जनता की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया.

आर्थिक व्यवस्था-अस्त-व्यवस्था–द्वैध शासन प्रणाली से कम्पनी के भू-राजस्व में वृद्धि हुई. जहाँ बंगाल में दीवानी

होता था, वहीं 1766-67 ई. में यह रकम 22 लाख रुपए हो गई. लगान व्यवस्था जनता के लिए कष्टप्रद हो गई थी. अब लगान वसूली का कार्य उन लोगों को दिया जाने लगा जो अधिक-से-अधिक कर वसूल कर सकें. उपज बढ़ाने के प्रयास प्रायः नष्ट ही हो गए थे. परिणामस्वरूप बहुत से किसानों ने खेती करना छोड़ दिया. लगान इतनी कड़ाई से वसूला जाता था कि अनेक किसानों ने अपने बच्चों को बेचकर लगान चुकाया. खेती कम होने से कम्पनी की आय भी गिरने लगी थी.

उद्योग-धन्धे नष्ट–द्वैध शासन प्रणाली लागू होने से पूर्व रेशमी तथा सूती वस्त्र, चीनी, नील, नमक तथा शोरे का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था. 1765 ई. के बाद इनके उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई. इंग्लैण्ड के वस्त्र व्यापार को भारत में अच्छा बाजार मिल सके, इसलिए भारतीय वस्त्र उद्योग को कम्पनी ने जानबूझकर नष्ट कर दिया. कम्पनी का उत्पीड़न इतना बढ़ गया कि अनेक जुलाहों ने अपने अँगूठे तक कटवा दिये, ताकि उन्हें कम्पनी के लिए वस्त्र तैयार नहीं करना पड़े. यह स्थिति इसलिए आई, क्योंकि जो काम वे कम्पनी के लिए करते थे, उससे उनकी आजीविका भी नहीं चल पाती थी.

वाणिज्य व्यापार का ग्राफ कम–पैदावार कम होने, कृषि की व्यवस्था चौपट होने तथा किसानों का खेती के प्रति रुझान कम होने से व्यापार-वाणिज्य भी बुरी तरह प्रभावित हुआ. सन् 1717 ई. के शाही फरमान द्वारा प्राप्त आज्ञा के अनुसार कम्पनी बंगाल में बिना किसी प्रतिबन्ध के व्यापार करने के लिए अनुबन्धित थी. व्यापार पर कम्पनी का ही एकाधिकार था. इसे बनाए रखने के लिए कम्पनी कर्मचारी कम मूल्य पर सामान बेचते थे, जिससे देशी व्यापारियों को भारी आर्थिक घाटा उठाना पड़ा. साथ ही साथ कम्पनी की स्थिति भी डांवाडोल हो गई और उसे भी आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी.

मैसूर राज्य और अंग्रेजी शासन विस्तार का विरोध–जैसे-जैसे अंग्रेजी सत्ता का क्षेत्र बढ़ता गया वैसे-वैसे अंग्रेजों का रुझान भारतीय राजनीति में और बढ़ता गया. परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास की ओर अपना रुख बनाया. दक्षिण में अंग्रेजों को मैसूर के शासकों, हैदराबाद के निजाम तथा मराठों की शक्ति को देखकर अपने कदम रखने पड़ते थे. फ्रांसीसियों के साथ इनका तालमेल अंग्रेजों के लिए कष्टकारी सिद्ध हुआ. मराठा अपनी शक्ति बढ़ाकर मुगल सम्राट् को भी अपने कब्जे में करना चाहते थे. मुख्य रूप से हैदरअली तथा टीपू सुल्तान अंग्रेजों की शक्ति कम करने को प्रयासरत थे. मौके के अनुसार रोहिला सरदार, अवध का नवाब, जाट तथा सिख भी अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे थे. अंग्रेजों को दक्षिण में अपने पैर मजबूत करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे इन समस्त शक्तियों से लोहा लें. यह कार्य इतना आसान नहीं था, परन्तु अंग्रेजों ने साम-दाम-दण्ड-भेद की नीति का सहारा लेकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ही ली. 1857 ई. तक अंग्रेज सम्पूर्ण भारत में अपना वर्चस्व कायम रखने में सफल हो गए.

आंग्ल-मैसूर संघर्ष–हैदर की फ्रांसीसियों से मैत्री को मैसूर युद्ध का एक कारण माना जाता है. इसके समर्थन में कहा जाता है कि 1756-57 ई. में अंग्रेज-फ्रांसीसी युद्ध में हैदरअली ने फ्रांसीसियों को समर्थन दिया था. संघर्ष विवाद का एक महत्वपूर्ण कारण मद्रास सरकार और कर्नाटक नवाब के साथ मैसूर का सीमा विवाद था.

हैदरअली का जीवन-परिचय–1721 ई. में बुडीकोटा के एक साधारण परिवार में हैदरअली का जन्म हुआ. उसका पिता फतह मुहम्मद मैसूर राज्य में एक साधारण नौकरी करता था. वह अपनी योग्यता के आधार पर सेना में फौजदार बन गया. अशिक्षित होते हुए भी हैदरअली में वीरोचित गुण, सैनिक प्रतिभा तथा कूटनीति के भाव कूट-कूट कर भरे हुए थे. मैसूर के राजा चिक्क कृष्णराज के दो प्रमुख मंत्री थे. प्रथम नंजराज और दूसरा देवराज. नंजराज ने हैदरअली की प्रतिभा देखकर सेना में बहाल कर दिया तथा वह अपनी योग्यता के आधार पर डिंडिगल का फौजदार बन गया. 1761 ई. में उसने नंजराज को पदच्युत कर स्वयं को राजा का संरक्षक घोषित कर दिया. उसने शीघ्र ही अपनी कूटनीति से बेदनूर, सुंडा, कनारा, मालाबार, कोयंबटूर तथा बारामहल पर अपना अधिकार जमा लिया. वह कुछ ही दिनों में मैसूर का वास्तविक शासक बन गया. उसकी बढ़ती हुई प्रगति व शक्ति देखकर अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की.

प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध–अंग्रेजों के साथ-साथ मराठे तथा निजाम भी हैदरअली की शक्ति से परेशान थे. आर्काट के नवाब मुहम्मद अली को, जो हैदर का शत्रु था, अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी. इसलिए हैदर अंग्रेजों से नाराज था. उधर मालाबार का प्रदेश छिन जाने से अंग्रेज भी उससे नाराज थे. 1766 ई. में अंग्रेज, मराठे और निजाम का त्रिगुट कायम हुआ. हैदरअली ने सर्वप्रथम त्रिगुट को ही तोड़ना उचित समझा. जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो हैदर ने उन्हें 35 लाख रुपए देकर एक तरफ कर दिया. 1767 ई. में अंग्रेजी सेना तथा निजाम ने मिलकर हैदर पर आक्रमण कर दिया, परन्तु कर्नाटक ने नवाब मुहम्मद अली के भाई महफूज खाँ ने हैदर का साथ दिया. उसने चालाकी से निजाम को हैदर के पक्ष में कर दिया. अंग्रेजों को अकेले ही युद्ध करना पड़ा.

निजाम की सेना तथा हैदर और कर्नल स्मिथ के मध्य चंगमा, त्रिनोमाली, वेनियामबाड़ी आदि स्थानों पर युद्ध हुए

जिनमें हैदर ही परास्त हुआ. निजाम ने 22 मार्च, 1768 ई. को अंग्रेजों से संधि कर ली. उधर हैदर अपनी तैयारी में लगा रहा और नवम्बर, 1768 ई. में कावेरीपट्टनम् तथा अन्य किलों पर आधिपत्य कर लिया. इसी क्रम में उसने तंजौर पर हमला करके वहाँ के शासक से 4 लाख रुपए वसूल किए. मंगलौर भी अब उसके कब्जे में आ गया. उसने मार्च 1769 ई. में मद्रास पर आक्रमण कर दिया. हैदरअली के प्रभाव को देखते हुए मद्रास कौंसिल ने 4 अप्रैल, 1769 ई. को उससे संधि कर ली. इस संधि के रूप में प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई. इस युद्ध का भारतीय इतिहास में अपना प्रमुख स्थान है.

युद्ध का महत्व–प्रथम आंग्ल युद्ध अंग्रेजों के लिए अत्यधिक महँगा साबित हुआ. इस युद्ध में जो संधि की गई थी उसके अनुसार दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के जीते गए प्रदेशों को वापस लौटा दिया गया. अंग्रेजों को एक भारी रकम हर्जाने के रूप में चुकानी पड़ी. अंग्रेजों का मैसूर पर कब्जा करने का सपना सच नहीं हो सका और उनकी प्रतिष्ठा को भी आघात पहुँचा.

द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध–अंग्रेज तथा हैदरअली के मध्य 1780 ई. में पुनः युद्ध शुरू हो गया. इसके कई कारण थे. मद्रास कौंसिल की ओर से 1769 ई. में हुई संधि की अवहेलना की जा रही थी. जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, तो अंग्रेजों ने हैदर की सहायता नहीं की, फलतः वह अंग्रेजों से नाराज हो गया. इसी समय अमेरिकी स्वातंत्र्य संग्राम के चलते यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य युद्ध छिड़ गया, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा. अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार करके माही-विजय की योजना क्रियान्वित किया. चूँकि माही क्षेत्र हैदर के अधिकार में आता था. अतः माही विजय की योजना उसे फूटी आँख भी नहीं सुहाई. हैदर ने निजाम तथा मराठों की सहायता से अंग्रेजों को खदेड़कर कर्नाटक पर हमला करके 1780 ई. में आर्काट को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया. जब अंग्रेजों की हार की खबर कलकत्ता पहुँची तो वारेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकूट को मद्रास भेजा. अपनी कूटनीति के आधार पर हेस्टिंग्स ने निजाम, बरार के राजा तथा महादजी सिंधिया को अपने खेमे में मिला लिया. हैदर ने अकेले ही लोहा लिया, परन्तु वह 1781 ई. में पोर्टोनोवो के युद्ध में पराजित हो गया. 1782 ई. में उसकी मृत्यु हो गई. उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया. हालांकि उसने अंग्रेजों को पराजित तो किया, परन्तु दोनों ही पक्ष कोई निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सके. 1784, (7 मार्च) को मंगलौर संधि के रूप में द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई.

तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध–मंगलौर संधि के बाद भी दोनों पक्ष एक-दूसरे पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं थे. टीपू चूँकि अंग्रेजों की नीति को जानता था, अतः वह सतर्क रहा. 1787 ई. में उसने अपने एक दूत को फ्रांस में भेजा तथा अपने पक्ष में शामिल होने का संदेशा भिजवाया. टीपू को कुस्तुन्तुनिया की ओर से भी सहायता का आश्वासन मिला. टीपू ने गुंटूर के निजाम पर हमला करके उसको पराजित कर गुंटूर को हथिया लिया. टीपू के इस प्रकार बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेजों का भयभीत होना स्वाभाविक ही था. अंग्रेजों के गवर्नर जनरल कार्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध निजाम को सहायता देने का वचन दिया. परिणाम यह हुआ कि दोनों पक्षों में विरोध पैदा हो गया. टीपू ने दिसम्बर, 1789 ई. में ट्रावणकोर राज्य पर हमला कर दिया और उधर कार्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया. उसने एक संधि के तहत मराठों तथा निजाम को अपने पक्ष में कर लिया. जनरल मीडोज मैसूर पर अधिकार करने की दृष्टि से आया, परन्तु टीपू के समक्ष उसकी दाल नहीं गली. इस पराजय के बाद कार्नवालिस ने मार्च, 1791 ई. में बंगलौर को अपने अधीन कर लिया और साथ ही साथ 1791 ई. में ही टीपू ने भी कर्नाटक पर विजय प्राप्त की. दोनों के मध्य अंतिम तथा निर्णायक युद्ध टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टम के निकट हुआ. हालांकि टीपू ने डटकर मुकाबला किया, परन्तु अपनी पराजय को देखते हुए उसने 1792 ई. में संधि कर ली.

इस संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य कम्पनी के हवाले कर दिया. इस राज्य को अंग्रेजों, मराठों तथा निजाम ने आपस में बँट लिया. डिंडिगल, कुर्ग, मालाबार, पहाड़ीघाट तथा बारामहल का क्षेत्र अंग्रेजों ने, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के मध्य का भाग मराठों ने तथा कृष्णा नदी का मध्यवर्ती इलाका निजाम ने लिया. करीब 30 लाख पौंड की रकम भी टीपू को अंग्रेजों को देनी पड़ी तथा जमानत के रूप में अपने दो पुत्रों को भी कार्नवालिस के हवाले कर दिया. इस संधि से टीपू की प्रतिष्ठा घटी, जबकि अंग्रेजों की बढ़ी. इसी संधि को ध्यान में रखते हुए कार्नवालिस ने कहा– "बिना अपने मित्रों को अत्यन्त शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया है." तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध का एक विशेष परिणाम यह रहा कि इस युद्ध से टीपू की शक्ति नष्ट हो गई और अंग्रेजों की शक्ति का लोहा माना जाने लगा.

चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध–भले ही तीसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध ने टीपू को पराजित कर दिया था, परन्तु वह निराश नहीं हुआ. उसने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को पुनः संगठित किया. अपने राजदूतों के माध्यम से उसने फ्रांसीसियों से सहायता पाने का आश्वासन ले लिया था. जब 1798 ई. में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया तो उसने अंग्रेजी सत्ता की जड़ों को स्थायी रूप से जमाने की

कोशिश की. उसने टीपू पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर 20 फरवरी, 1799 ई. में युद्ध शुरू कर दिया. वेलेस्ली ने निजाम तथा मराठों को अपने पक्ष में करके, मैसूर पर हमला कर श्रीरंगपट्टम् का घेरा डाल दिया. युद्ध में 4 मई, 1799 ई. को टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ.

युद्ध का महत्व–भारत की तात्कालिक राजनीति पर चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध का व्यापक प्रभाव पड़ा. सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को यह हुआ कि उनके दो प्रमुख शत्रुओं टीपू तथा फ्रांसीसियों का प्रभुत्व खत्म हो गया. वेलेस्ली ने पुराने राजवंश के अल्पवयस्क राजकुमार को मैसूर के शेष भाग का राजा घोषित कर दिया और उसके साथ संधि भी कर ली. इस प्रकार मैसूर पर भी अंग्रेजी शासन का कब्जा हो गया. डीन हटन के शब्दों में, "सैनिक, आर्थिक और शांति स्थापना की दृष्टि से मैसूर की विजय क्लाइव के समय के पश्चात् अंग्रेजी शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी."

आंग्ल-मराठा सम्बन्ध–शिवाजी मराठा शक्ति के संस्थापक थे. उनके काल से ही मुगल तथा मराठों के युद्ध चलते आ रहे थे. मराठा शक्ति को और सुदृढ़ बनाने में तीन पेशवाओं–बालाजी विश्वनाथ (1713-20), बाजीराव प्रथम (1720-40) और बालाजी बाजीराव अथवा नाना साहब (1740-61) ने महती भूमिका अदा की. 14 जनवरी, 1761 ई. को पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार से उनकी शक्ति को गहरा आघात पहुँचा. आपस की फूट के कारण अंग्रेज मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने में सक्षम हो सके. 1761 ई. में माधवराव पेशवा बना. उसने मात्र 11 वर्ष में ही मराठों की शक्ति को पुनः शिखर पर पहुँचा दिया, जिससे अंग्रेज भयभीत रहने लगे. 1722 ई. में माधवराव की मृत्यु होते ही मराठों में गृह-कलह उत्पन्न हो गया. राजगद्दी को लेकर खींचतान होती रही. माधवराव का छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, परन्तु 1773 ई. में उसकी हत्या करवाकर उसका चाचा रघुनाथ पेशवा बन गया. नाना फड़नवीस का दल रघुनाथ का विरोधी था, वह माधवराव को पेशवा बनाना चाहता था. रघुनाथ इस स्थिति को भांपकर अंग्रेजों के यहाँ शरण ली और अंग्रेजों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका हाथ लग गया.

आंग्ल-मराठा प्रथम युद्ध–बम्बई सरकार राघोबा को अपने अधिकार में लेकर पूना पर अधिकार करना चाहती थी. इसलिए उसने कलकत्ता कौंसिल की अनुमति लिए बिना राघोबा के साथ 7 मार्च, 1775 ई. को सूरत की संधि की. इस संधि के अनुसार बम्बई की सरकार ने राघोबा को पेशवा बनाने तथा सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया. उसे सालसेट, बेसीन, भड़ौच तथा सूरत से प्राप्त लगान का एक भाग कम्पनी को देना था. वह इस बात पर भी सहमत हुआ कि संधि के पश्चात् मराठे बंगाल तथा कर्नाटक पर हमले करना बंद कर देंगे. उसने यह वचन भी दिया था कि अगर वह पूना दरबार से कोई संधि करेगा तो उसमें अंग्रेजों को भी सम्मिलित करेगा और अंग्रेजों के शत्रुओं से मैत्री नहीं करेगा. सैनिक सहायता के बदले राघोबा ने कम्पनी को धन देने का वचन दिया. संधि के अनुसार राघोबा की सहायता के लिए कर्नल कीटिंग के अधीन एक सेना भेजी गई. अरास के युद्ध में अंग्रेजी सेना तथा फड़नवीस के मध्य युद्ध हुआ, परन्तु कोई विशेष परिणाम नहीं निकला.

पुरंदर की संधि–कलकत्ता की सरकार सूरत की संधि को अनुचित मानती थी. अतः उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया. इसी के तहत कर्नल अप्टन को मराठा-मण्डल के नेताओं से बातचीत करने के लिए पूना भेजा गया. मराठा मण्डल तथा कर्नल के मध्य 1 मार्च, 1776 ई. को एक नई संधि की गई जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है. संधि के अनुसार युद्ध बंद कर दिया गया. पूना दरबार की ओर से अंग्रेजों के लिए 12 लाख रुपए तथा सालसेट का इलाका दिया गया.

चूँकि बम्बई की सरकार पुरंदर संधि को अनुचित मानती थी. अतः उसने सूरत की संधि को ही मान्यता दिया. अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी एक-दूसरे के दुश्मन बन गए थे. अतः फ्रांसीसियों का फड़नवीस से सम्बन्ध अंग्रेजों के लिए घातक हो सकता था, इसलिए बम्बई की कौंसिल ने पूना की ओर एक सेना भेजी, जिसे मराठों ने तलगांव के युद्ध (1778 ई.) में हरा दिया. बड़गांव में भी अंग्रेजी सेना को मात खानी पड़ी. और अंततः 1779 ई. में एक संधि की जिसे बड़गांव की संधि के नाम से जाना जाता है. संधि के अनुसार अंग्रेजों ने विजित मराठा प्रदेशों को लौटा दिया. यह कार्य अंग्रेजों के लिए अपमानजनक था. अतः वारेन हेस्टिंग्स ने मराठों से युद्ध जारी रखने का फैसला किया. हेस्टिंग्स ने सेना की दो टुकड़ियों को क्रमशः जनरल गोडर्ड और पोफम के नेतृत्व में भेजा. गोडर्ड ने अनेक स्थानों पर मराठों को पराजित करके 1780 ई. में हैदराबाद पर अधिकार कर लिया. पोफम ने भी ग्वालियर पर अपना आधिपत्य जमा लिया.

सालबाई की संधि–कई दफा पराजित होने से मराठा बौखला उठे. महादजी सिंधिया के प्रयासों से 17 मई, 1782 ई. को मराठों तथा अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई, जो सालबाई की संधि के नाम से विख्यात है. इस संधि की बदौलत ही प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध की समाप्ति हुई. संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने विजित क्षेत्रों से अपना-अपना अधिकार वापस ले लिया. सालसेट तथा ऐलीफेंटा को अंग्रेजों के पास ही छोड़ दिया गया. अंग्रेजों ने रघुनाथ का पक्ष लेना छोड़ माधवराव को पेशवा मान लिया. पेशवा की ओर से रघुनाथ को पेंशन मिलने लगी तथा यमुना नदी के पश्चिम के क्षेत्र पर

सिंधिया का फिर से अधिकार हो गया. प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध से दोनों पक्षों को समान रूप से लाभ हुआ. दोनों पक्षों को अपार क्षति उठानी पड़ी तथा दोनों ही पक्षों की कठिनाइयों में इजाफा हुआ.

आंग्ल-मराठा द्वितीय युद्ध—नाना फड़नवीस की मृत्यु के पश्चात् विभिन्न मराठा सरदारों में राजगद्दी पाने के लिए संघर्ष छिड़ गया. 1802 ई. में होल्कर ने पेशवा और सिंधिया की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया. पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों की शरण ली. अंग्रेज तो ऐसे ही मौके की तलाश में थे, उन्होंने उसे तत्काल संरक्षण दिया. 31 दिसम्बर, 1802 ई. में बेसीन की संधि हुई. कम्पनी ने उसकी रक्षा का आश्वासन देकर उसे पुनः पूना में सिंहासन पर बैठाया. पेशवा ने संधि की शर्तों के आधार पर सूरत अंग्रेजों को दे दिया. पेशवा की सहायता के लिए एक सहायक सेना तैयार की गई. पेशवा ने सेना के खर्च के लिए 26 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी वाले क्षेत्र कम्पनी को दे दिया. पेशवा ने भी यह वचन दिया कि वह किसी भी यूरोपीय को (अंग्रेजों को छोड़कर) अपने राज्य में नहीं रहने देगा. अंग्रेजों की अनुमति के बिना वह किसी राज्य से समझौता अथवा संधि नहीं करेगा. इस प्रकार वादा करने से पेशवा की स्वतन्त्रता खत्म हो गई. वह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया. मराठा सरदार इस बात से क्षुब्ध थे कि पेशवा की स्वतन्त्रता पर अंकुश लग गया. अतः शीघ्र ही अंग्रेजों से दोबारा युद्ध शुरू हो गया. हालांकि पेशवा अंग्रेजों की सहायता से ही गद्दी पर बैठा था, परन्तु वह संतुष्ट नहीं था. उसने गुप्त रूप से मराठों को एक करने की योजना भी बनाई, परन्तु वह असफल रहा. जब बेसीन की संधि हुई थी तब सिंधिया तथा भोंसले नर्मदा नदी के दक्षिणी प्रदेशों में थे. वेलस्ली को यह खतरा था कि कहीं वे निजाम पर आक्रमण न कर दें, इसलिए उसने उनको नागपुर लौट जाने के लिए कहा. 1803 ई. में वेलेस्ली ने द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध को प्रारम्भ कर दिया. सितम्बर, 1803 ई. में सिंधिया और भोंसले की सेना असई के युद्ध में पराजित हुई. लेक की अध्यक्षता वाली सेना ने उत्तर में लासवाड़ी में सिंधिया की सेना को बुरी तरह पराजित किया. इस पराजय से विक्षुब्ध होकर भोंसले और सिंधिया ने क्रमशः देवगांव (17 दिसम्बर, 1803 ई.) तथा सुर्जी अर्जुन गांव की संधियाँ (30 दिसम्बर, 1803 ई.) कम्पनी के साथ कर लीं. दोनों ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया. दोनों ने ही अपने राज्य का एक बड़ा भाग कम्पनी को दे दिया. इसी के साथ-साथ दोनों ने अपने-अपने दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया तथा बिना अंग्रेजों की अनुमति से किसी भी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी नहीं देना स्वीकार किया. संधि का परिणाम यह हुआ कि उड़ीसा का समुद्री इलाका, गंगा-यमुना का मध्यवर्ती क्षेत्र तथा पेशवा पूर्णरूपेण अंग्रेजों के नियन्त्रण में आ गया. महाराष्ट्र से फ्रांसीसियों का प्रभाव भी समाप्त हो गया.

होल्कर के साथ संघर्ष—होल्कर ने जाटों की सहायता से अंग्रेजों के साथ युद्ध किया. वह कई बार पराजित भी हुआ, परन्तु उसने हार नहीं मानी. जब इन्दौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो वह भागकर अपने मित्र भरतपुर राजा के पास चला गया और वहीं से युद्ध करता रहा. जनरल ने कई बार भरतपुर दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास किया. इस समय लॉर्ड वेलेस्ली की कुछ गलत नीतियों के कारण कम्पनी का खर्च बढ़ता ही जा रहा था. अतः कम्पनी के संचालकों ने उसे वापस बुला लिया और जॉर्ज बार्लो को अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में भेजा. जॉर्ज बार्लो ने जनवरी, 1806 ई. में होल्कर के साथ राजघाट की संधि करके द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया.

द्वितीय युद्ध में मराठों की काफी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, परन्तु वे पूर्णतः पराजित नहीं हुए थे. कम्पनी को तुरन्त ही उनके साथ तृतीय युद्ध लड़ना पड़ा जिसमें वे अन्तिम रूप से पराजित हुए.

तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध—तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध की शुरूआत पेशवा तथा गायकवाड़ के मध्य झगड़े से हुई. गायकवाड़ ने 1814 ई. में गुजरात की भूमि पर चल रहे झगड़े के निपटारे के लिए अपने दूत गंगाधर शास्त्री को पूना भेजा. पेशवा के प्रधानमंत्री त्र्यंबक ने इसकी हत्या करवा दी. क्रुद्ध होकर अंग्रेज रेजीडेंट एलफिंसटन ने पेशवा से त्र्यंबकजी की माँग की जिसे पेशवा ने काफी मान-मनुहार के पश्चात् स्वीकार किया, परन्तु त्र्यंबक कैद से भागने में सफल रहा. हेस्टिंग्स ने पुनः पेशवा पर इस बात का दबाव डाला कि वह त्र्यंबक को लौटा दे और रामगढ़, सिंहगढ़ तथा पुरंदर के दुर्ग भी जमानत के रूप में देने को कहा गया. पेशवा अभी तक कोई निर्णय भी नहीं कर पाया था कि कर्नल स्मिथ ने पूना को घेर लिया. उसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा 13 जून, 1817 ई. को पेशवा के साथ नई संधि की. इसके द्वारा मराठा संघ (पूना संधि) भंग कर दिया गया. फलतः पेशवा का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया. पेशवा को बुंदेलखंड, मालवा तथा अहमद नगर का दुर्ग कम्पनी को देना पड़ा. अंग्रेजी सेना को पूना में रखने की अनुमति भी उसे देनी पड़ी. इस प्रकार के अधिकार मिल जाने के बाद अंग्रेजों ने अन्य मराठा सरदारों को भी संधि करने के लिए बाध्य किया. 6 नवम्बर को गायकवाड़ को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार गायकवाड़ ने अपनी सेना कम कर दी, सहायक सेना बढ़ा दी गई और उसके खर्च के लिए गायकवाड़ ने कुछ इलाके कम्पनी को दे दिए. इस प्रकार आपसी मनमुटाव की स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने अप्पा साहब से संधि की जो कि नागपुर की संधि के नाम से जानी

जाती है. इस संधि से भोंसले और अन्य मराठों की शक्ति क्षीण हो गई. 5 नवम्बर, 1817 ई. को दौलतराव को ग्वालियर की संधि करनी पड़ी. उसने पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद करने का वचन दिया और चम्बल नदी के बाएँ तट के सभी राजपूत राज्यों पर से अपना अधिकार वापस ले लिया. उपर्युक्त संधियों ने मराठों को पंगु बना दिया. वे अंग्रेजों से बदला लेने की फिराक में रहते थे. सबसे पहले पेशवा ने शुरूआत की. उसने पूना की अंग्रेज रेजीडेंसी में आग लगवा दी. उसने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया, परन्तु वह 1817 ई. के किर्की के युद्ध में परास्त हो गया. पूना पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया. पेशवा ने युद्ध जारी रखा, परन्तु गौरगांव (जनवरी, 1818 ई.) तथा अष्टि के युद्ध में (फरवरी 1818 ई.) पराजित होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा. बाजीराव द्वितीय (पेशवा) को गद्दी से उतार दिया गया. बाजीराव को 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में रहने के लिए कहा गया. उसके राज्य का एक भाग शिवाजी के वंशज को देकर सतारा में प्रतिस्थापित किया गया. अधिकांश भाग की मालिक कम्पनी ही बनी रही. इस प्रकार अन्य मराठा सरदारों ने भी अंग्रेजों से मुक्त होने का प्रयास किया. होल्कर भी युद्ध की तैयारी में व्यस्त हो गया. नवम्बर, 1817 ई. में सीताबल्दी (सीतावर्डी) के युद्ध में भोंसला सरदार अप्पाजी को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया. उन्होंने उसके राज्य पर अधिकार करके कुछ हिस्सा राघोजी के पौत्र को दे दिया, लेकिन महीदपुर के युद्ध में दिसम्बर, 1817 ई. में होल्कर को परास्त होकर जनवरी 1817 ई. में मंदसौर की संधि करनी पड़ी. इस संधि की शर्तों के अनुसार होल्कर को खानदेश सहित नर्मदा नदी के पार का समस्त क्षेत्र कम्पनी को देना पड़ा.

इस प्रकार अंग्रेजों ने गृहकलह की स्थिति का भरपूर फायदा उठाकर मराठों को निशक्त बनाकर अपना साम्राज्य बढ़ाने में सफलता पाई.

मराठों के पतन के कारण–मराठों ने भारत में मुगल साम्राज्य को समाप्त करके अपनी प्रभुता जमाने के प्रयास किए थे और किसी सीमा तक वे इसमें सफल भी हुए, परन्तु पानीपत के तृतीय युद्ध में हुई हार के कारण उनके मंसूबों पर पानी फिर गया, परन्तु फिर भी उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा था. अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को रोकने में वे सफल नहीं हो सके मराठों की असफलता के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित थे–

मराठों में मनमुटाव का होना–एकता का अभाव और आपसी फूट के कारण ही मराठा अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए थे. प्रत्येक मराठा सरदार चाहे वह होल्कर, सिंधिया, भोंसले अथवा गायकवाड़ था. मराठा साम्राज्य को बढ़ाने को उद्यत था, परन्तु उसमें भी वे व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने के अधिक पक्षधर थे. फलस्वरूप टकराहट गति पकड़ती गई और उसका जमकर फायदा उठाया अंग्रेजों ने.

प्रशासनिक अव्यवस्था–हालांकि शिवाजी ने सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का बीजारोपण किया था, परन्तु उसके उत्तराधिकारी उस व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम हुए. उनका अधिकांश समय लूटपाट और युद्ध में बीतता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे शासन व्यवस्था को सही दिशा नहीं दे सके.

कुशल नेतृत्व का अभाव–पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कोई योग्य शासक उभरकर सामने नहीं आया, कुशल मार्गदर्शन के अभाव में मराठों की शक्ति विध्वंश की ओर जाने लगी. आपसी फूट के कारण उन्होंने अपने दुश्मनों से भी मदद के लिए हाथ फैलाने शुरू कर दिए थे. यह स्थिति उनके पतन का प्रमुख कारण बनी.

उच्च आदर्शों का त्याग–शिवाजी ने जो ध्येय तथा लक्ष्य रखे थे उन्हें उनके उत्तराधिकारियों ने विस्मृत कर दिया. वे भोग-विलास, षड्यंत्र तथा आराम पाने की ओर झुक गए. प्रशासनिक व्यवस्था ढीली पड़ गई, जिससे जनता को परेशानी होने लगी. जनता समस्याओं का समाधान न होने के कारण शासक को वांछित सहयोग नहीं दे सकी. परिणामस्वरूप जनसमर्थन के अभाव में मराठा शक्ति क्षीण हो गई.

देशी ताकतों के सहयोग की कमी–मराठों की कुछ नीतियाँ ऐसी थीं जिनके कारण उन्हें तत्कालीन देशी रियासतों की ओर से समर्थन नहीं मिला. मराठों ने मैसूर के शासकों हैदरअली व टीपू को आवश्यकता पड़ने पर सहयोग नहीं किया तथा हैदराबाद के निजाम को भी उन्होंने बुरे वक्त में पीठ दिखा दी, जोकि उनकी एक भयंकर भूल थी. इसका परिणाम यह हुआ कि आवश्यकता के समय उन शासकों ने भी मराठों का कोई सहयोग नहीं किया.

मराठों ने तत्कालीन राजपूत शासकों से भी चौथ वसूली शुरू कर दी थी, जिससे वे उनसे अप्रसन्न रहने लगे थे. मौका पाकर उन्होंने भी मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों की ही सहायता की.

दुर्बल सैन्य शक्ति–मराठों ने अपनी छापामार रणनीति को छोड़कर यूरोपीय पद्धति अपनाई, परन्तु स्वयं को उसके अनुरूप नहीं ढाल पाए. फलतः उनकी युद्ध नीति कमजोर पड़ गई और खामियाजे के रूप में उन्हें पराजय का मुँह देखना पड़ा.

गुप्तचर व्यवस्था का अभाव–अंग्रेजों के पास साम-दाम-दंड-भेद की चारों नीतियाँ थीं, जबकि मराठों के पास गुप्तचरों का अभाव था. कहाँ पर क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है इसकी उन्हें भनक तक नहीं लग पाती थी और विरोधी गुट अपने मंसूबों में सफल हो जाता था.

आर्थिक स्थिति कमजोर होना–लूटपाट तथा भागा-दौड़ी में ही मराठों का अधिकांश समय बीता जिससे वे न तो प्रशासनिक व्यवस्था को ही संभाल सके और न ही आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए सोच सके. धन की कमी उनके लक्ष्य प्राप्ति के इरादों में आड़े आई.

अन्य कारण–उन्हें भौगोलिक स्थिति का पर्याप्त आभास नहीं था, जबकि अंग्रेज लोग इससे पूर्णतया परिचित थे, जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया. मराठों की असफलता के लिए यह कारण भी मुख्य सहयोगी रहा.

रेग्यूलेटिंग एक्ट–लॉर्ड क्लाइव के समय से ही कर्मचारियों में लूट-खसूट तथा व्यक्तिगत व्यापार द्वारा धन कमाने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी. भारत आने वाले प्रत्येक अंग्रेज कर्मचारी का प्रमुख लक्ष्य धनी बनना तथा धन अर्जित करके वापस इंगलैंड लौट जाना हो गया था. उपहार लेने की प्रथा भी समाप्त नहीं हुई थी. इस प्रकार की नीति पर अंकुश लगाने तथा भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप करना आवश्यक समझा. कम्पनी ने अपना लाभांश 1766 ई. में 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया तथा 1767 ई. में 12·5 करना चाहा, परन्तु संसद के हस्तक्षेप से ऐसा नहीं हो सका. एक तरफ कम्पनी लाभांश बढ़ाना चाहती थी, तो दूसरी ओर सरकार से भी कर्ज की माँग करती थी. सरकार द्वारा पूर्व में भी कर्ज दिया गया था, किन्तु अधिक कर्ज की माँग को लेकर कम्पनी पर नियन्त्रण लगाना आवश्यक हो गया. कम्पनी को 4 लाख पौण्ड ब्रिटिश राजकोष में राजस्व रूप में जमा कराए जाने की शर्त पर भारत से लगान वसूल करने का अधिकार 1767 ई. में मिल गया जिसे 1772 ई. तक बढ़ाया जाता रहा. कम्पनी ने न तो लाभांश का ही भुगतान किया और न ही 4 लाख पौण्ड जमा कराए. 1772 ई. में लॉर्ड नार्थ ने कम्पनी की हालत देखकर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट को बताया कि यदि कम्पनी को 10 लाख पौण्ड का कर्ज नहीं दिया गया तो उसका व्यापार नष्ट हो सकता है. ब्रिटिश सांसदों ने तात्कालिक स्थिति के मद्देनजर इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि कम्पनी की भारतीय सम्पत्ति पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार होना चाहिए. संसद की ओर से नियुक्त प्रवर एवं गुप्त समिति ने भी इस बात का समर्थन किया. कम्पनी को दीवानी या राजनीतिक राज्य के संपादन के योग्य बनाने के लिए भी रेग्यूलेटिंग एक्ट का एक उद्देश्य था.

इस अधिनियम के द्वारा दी गई शक्तियों से ही कम्पनी भारत में भू-राजस्व वसूल करने तथा न्यायिक कार्य सम्पादन के लिए अधिकार सम्पन्न हो गई. उपर्युक्त सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने 1773 ई. में रेग्यूलेटिंग एक्ट पारित किया जो 1774 ई. में लागू किया गया.

अधिनियम के उपबंध–1. कम्पनी संचालकों के चुनाव में मतदान का अधिकार 1000 पौण्ड के एक वर्ष या इससे अधिक समय के हिस्से धारक का रखा गया. पूर्व में 500 पौण्ड के हिस्सेदार को संचालकों के चुनाव में मताधिकार का अधिकार था. संचालकों का कार्यकाल एक वर्ष के स्थान पर चार वर्ष के लिए तय किया गया, किन्तु कुल सदस्यों के एक चौथाई (6 सदस्य) का चुनाव प्रतिवर्ष किया जाना था. एक सदस्य के दुबारा चुने जाने के लिए एक वर्ष का अंतराल आवश्यक था. अपने हिस्से के अनुपात में मत देने का अधिकार दिया गया जैसे–3, 6 और 10 हजार पौण्ड के हिस्सेदारों को क्रमशः 2, 3 एवं 4 मत देने का अधिकार था. इस अधिनियम के तहत यह भी तय किया गया कि डाइरेक्टरों को राजस्व विभाग के सामने भारत से आने वाला राजस्व सम्बन्धी सारा पत्र व्यवहार रख देना चाहिए तथा राज्य सचिव के सामने असैनिक या सैनिक शासन सम्बन्धी प्रत्येक तथ्य रख देना चाहिए. इस प्रकार कम्पनी के मामलों पर पार्लियामेन्ट का नियन्त्रण रखने की पहली निश्चित कार्यवाही की गई. 1781 ई. में एक परिपूरक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार सभी सरकारी पत्रों को, जो भारत भेजे जाने थे, एक राज्य सचिव को दिखलाना पड़ता था.

2. गवर्नर जनरल तथा उसकी कौंसिल को अधिकृत किया गया कि वह युद्ध एवं शांति के मामलों में मद्रास एवं प्रेसीडेंसियों पर नियन्त्रण रखे, किन्तु संचालक समिति प्रांतीय सरकारों को सीधे भी निर्देशित कर सकती थी.

3. बंगाल के लिए जो फोर्ट विलियम प्रशासक नियुक्त किया गया, उसे समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया. गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए चार सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसमें विचाराधीन मामलों में बहुमत से निर्णय लिए जाने की व्यवस्था थी. मतों की बराबरी की हालत में अध्यक्ष को एक अधिक मत प्राप्त था. प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और चार परिषद सदस्यों–क्लेवरिंग, मौनसन, बारवेल एवं फिलिप फ्रांसिस के नाम कानून में उल्लिखित थे. वे पाँच वर्षों के लिए नियुक्त किए गए (हालांकि यह अवधि परिपूरक कानूनों द्वारा और भी बढ़ा दी गई). उनके उत्तराधिकारी कम्पनी द्वारा नियुक्त होते थे.

4. कानून द्वारा क्राउन (सरकार) को अधिकृत किया गया कि राजकीय आदेश द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस) स्थापित करे, जिसमें एक प्रधान न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश हों. बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की समस्त प्रजा पूरी तरह इस न्यायालय के अधीन होगी. सर ऐलीजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए.

5. गवर्नर जनरल एवं कौंसिल भारत के लिए कानून बना सकता था तथा अध्यादेश जारी कर सकता था, किन्तु इन्हें लागू करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकृत एवं प्रकाशित किया जाना अपेक्षित था.

6. कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा व्यक्तिगत व्यापार निषिद्ध कर दिया गया. इसके अतिरिक्त उपहार एवं जागीर आदि वर्जित कर दी गई. गवर्नर जनरल को 25,000 पौण्ड एवं कौंसिल के अन्य सदस्य को 10,000 तथा सर्वोच्च न्यायाधीश को 8000 पौण्ड वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया. कम्पनी के लिए 14 लाख पौण्ड का ऋण भी 4 प्रतिशत ब्याज पर स्वीकृत किया गया.

7. एक सैक्रेट्री ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई और कम्पनी का सैनिक तथा नागरिक शासन इसके अधीन कर दिया गया. कम्पनी को प्रशासन एवं सेना सम्बन्धी कार्य इसके परामर्श से करने थे.

अधिनियम के दोष–रेंगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1784 तक प्रभावित रहा. इसके कुछ दोष भी थे, जिन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर शृंखलाबद्ध किया जा सकता है–

1. संचालकों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की संख्या घटा दी गई तथा बड़े हिस्सेदारों को एक से अधिक मत का आधार प्रदान किया गया और इस अधिकार को पूँजी वाले लोगों तक सीमित कर दिया गया.

2. संचालक समिति अब व्यावहारिक रूप से 30 सदस्यों की हो गई जिनमें से 6 को प्रतिवर्ष पदमुक्त कर दिया जाता था. इस प्रावधान से 1246 सदस्य मतदान के अधिकारी नहीं रहे. ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि कम्पनी के छोटे कार्मिक भी कुछ समय भारत में नौकरी करने के बाद 500 पौण्ड के हिस्से क्रय कर संचालकों के मतदान का अधिकार प्राप्त कर लेते थे और संचालकों पर अनाधिकृत दबाव बनाए रखते थे. अतः इससे बचने के लिए 1000 पौण्ड वाले हिस्सेदार को मताधिकार दिया गया, परन्तु इस व्यवस्था से वांछित सुधार नहीं हुआ. इस व्यवस्था से सुधार की अपेक्षा प्रजातांत्रिक अधिकारों का ही हनन हुआ.

3. बम्बई तथा मद्रास की सरकारों पर गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल का पूरा नियन्त्रण नहीं था. केवल युद्ध अथवा संधि के मामलों में ही गवर्नर जनरल एवं कौंसिल हस्तक्षेप कर सकती थी. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था प्रान्तीय सरकारों को संचालक सीधे ही निर्देश जारी कर सकते थे. परिणामतया मद्रास एवं बम्बई प्रेसीडेंसियाँ प्रायः स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करती रहीं. इन प्रावधानों ने सब शक्तियों को एक-दूसरे का शत्रु बना दिया.

4. गवर्नर जनरल को समस्त निर्णयों के लिए कौंसिल में बहुमत प्राप्त करना होता था. अतः उसमें तथा उसकी कौंसिल में निरन्तर संघर्ष चलता रहा. गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को रद्द करने के लिए कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था.

5. इंग्लैण्ड में भी अनेक मामलों में डाइरेक्टरों के कार्यों पर मंत्रिमण्डल का नियन्त्रण भ्राँतिपूर्ण ही सिद्ध हुआ. 1774 से 1783 ई. के मध्य अधिनियम की अस्पष्टता के कारण अनेक व्यावहारिक दोष प्रकट हुए. बहुमत के आधार पर कौंसिल में निर्णय करवा पाना गवर्नर जनरल के लिए अत्यन्त कठिन हो गया. नवीन शासनकाल की शुरूआत 26 अक्टूबर, 1774 ई. को हुई. वारेन हेस्टिंग्स पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाया गया.

6. सुप्रीम कोर्ट एवं गवर्नर जनरल और कौंसिल के अधिकार क्षेत्र के विवाद को डंडास द्वारा रखे गए 1781 ई. के नियम से दूर किया गया.

पिट्स इण्डिया एक्ट–रेग्यूलेटिंग एक्ट में व्याप्त खामियों को सुधारने की दृष्टि से पिट्स इंडिया एक्ट का निर्माण किया गया. 1782 ई. में पार्लियामेंट की एक सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट में कम्पनी की नीतियों पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया. कई प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के बाद प्रधानमंत्री पिट (छोटे पिट) द्वारा रखा गया अधिनियम अगस्त 1784 ई. में पारित हुआ. पिट्स इण्डिया एक्ट कम्पनी एवं क्राउन की दोहरी सरकार थी, जो 1858 ई. तक आंशिक परिवर्तन के साथ चलती रही. इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्न थे–

1. **नियन्त्रण मण्डल**–भारत के मामले में छः कमिश्नरों का एक बोर्ड नियुक्त किया गया, जिसमें सरकार के राज्य सचिव और वित्त सचिव एवं चार प्रिवी कौंसिल के सदस्य थे. इन्हीं कमिश्नरों में से तीन की एक गुप्त समिति बनाई गई और इसका अध्यक्ष राज्य सचिव को बनाया गया. बोर्ड के गुप्त आदेश इस समिति के मार्फत ही भेजे जा सकते थे. सेना, लगान एवं सुधार सम्बन्धी मामलों में सीधा नियन्त्रण बोर्ड को दिया गया. संचालकों द्वारा बोर्ड के आदेशों की अवहेलना किए जाने पर बोर्ड अपनी ओर से आदेश प्रसारित कर सकता था, जिसे 14 दिन में संचालकों को स्वीकार करना होता था. इस प्रकार अधिनियम से संचालक मण्डल की ताकत घट गई अर्थात् संचालकों के पास व्यापार एवं संरक्षण छोड़ दिया गया, किन्तु बोर्ड के काम में हस्तक्षेप का अवसर नहीं रहा. गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या तीन कर दी गई. कौंसिल में बराबर मतों की स्थिति में एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार दिया गया. गवर्नर जनरल की नियुक्ति संचालक करते थे.

2. मद्रास तथा बम्बई में गवर्नर की कौंसिल में भी सेनापति को सदस्य बनाया गया. बम्बई तथा मद्रास को बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया. यह व्यवस्था भी की गई कि युद्धकाल में गवर्नर जनरल अन्य प्रदेशों का शासन व लगान वसूली का कार्य अपने नियन्त्रण में ले सकेगा. गवर्नर जनरल के आदेशों की अवहेलना करने पर गवर्नर को गवर्नर जनरल निलम्बित कर सकता था.

3. गवर्नर जनरल संचालकों की पूर्व स्वीकृति के बिना युद्ध नहीं कर सकता था. किसी भारतीय शासक के साथ युद्ध प्रारम्भ करने अथवा किसी राज्य को अन्य राज्यों के आक्रमण के विरुद्ध सहायता का आश्वासन दिए जाने का अधिकार उसे नहीं था.

4. यह भी निर्देशित किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भू-राजस्व व्यवस्था की जाँच कर जमींदारों, राजा या अन्य भूमि के स्वामी जिनके साथ अन्याय हो रहा है, स्थायी बन्दोबस्त करें.

अधिनियम का महत्व–इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन पर इंगलैण्ड सरकार का निश्चित अधिकार स्थापित हो गया. बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष मंत्रिमण्डल का सदस्य था, इस प्रकार वह प्रणाली स्थापित हुई जो बहुत ही थोड़े से परिवर्तन से 1947 ई. तक चलती रही. कम्पनी के अधिकारों को समाप्त करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को ही भारत का सचिव बनाया गया.

इस अधिनियम की यह भी एक विशेषता थी कि इसने पदों पर नियुक्ति का अधिकार संचालकों के ऊपर छोड़ दिया. बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वास्तविक कार्य सरकार के दो ही सदस्यों द्वारा होता था. गवर्नर जनरल की शक्ति में बेतहाशा वृद्धि हो गई. 1786 ई. में परिपूरक विधेयक पास हुआ. कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 के बजाय तीन कर दी गई. इस अधिनियम द्वारा गृह सरकार भारतीय राजनीति पर प्रभावी नियन्त्रण चाहती थी और ऐसा करने में पिट सफल रहा. पिट की योजनापूर्ण बुद्धि और डंडास की व्यावहारिक व्यवस्था, फाक्स के भाषण व एडमंड बर्क द्वारा प्रचारित आदर्शवाद को प्रभावशाली बनाने में अधिक सफल रही.

स्मरणीय तथ्य

- आधुनिक भारत के इतिहास का काल 1757 से लेकर 1947 ई. तक का माना गया है.
- मुगल सम्राट् औरंगजेब की 1707 ई. में मृत्यु होने के बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया.
- औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को 20 प्रांतों में बाँटा हुआ था.
- मुगल सामंत चार गुटों में विभक्त थे–
  1. तूरानी 2. ईरानी
  3. अफगानी 4. हिन्दुस्तानी
- महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया.
- अंग्रेजों का पहला जहाजी बेड़ा 1608 ई. में भारत में प्रविष्ट हुआ.
- सर टामस रो 1615 से 1618 ई. तक जहाँगीर के दरबार में राजदूत रहा.
- ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के समय उसका मूल उद्देश्य व्यापार करना था.
- कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1744 ई. में हुआ जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए.
- कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 ई. में हुआ.
- यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ई. में शुरू हुआ.
- प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में एकछत्र राज्य करने का अवसर प्रदान किया.
- काली कोठरी की घटना में 146 व्यक्तियों को बन्द किया गया.
- इतिहासकार ताराचंद ने बक्सर के युद्ध के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि प्लासी के युद्ध ने सत्ता का हस्तान्तरण कर दिया.
- द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव था.
- 1721 ई. में बुडीकोटा के एक साधारण परिवार में हैदरअली का जन्म हुआ.
- द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध जो कि अंग्रेज तथा हैदरअली के मध्य हुआ वह 1780 ई. में शुरू हुआ.
- पुरंदर की संधि मराठा मण्डल तथा कर्नल अप्टन के मध्य हुई.
- ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 ई. में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया.
- मुगल साम्राज्य में सम्राट् सेना का मुख्य सेनापति होता था.
- मुगल साम्राज्य के प्रांतों को सूबा कहा जाता था.
- सामंती व्यवस्था के कारण ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ.
- लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनाने की अनुमति 1599 ई. में मिली.
- सर टामस रो जहाँगीर के दरबार में राजदूत नियुक्त हुआ जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद, सूरत तथा भड़ौच में अपनी कम्पनियाँ स्थापित कर ली.
- दक्षिणी-पूर्वी समुद्र तट पर 1611 ई. में मछलीपट्टनम (मसूलीपट्टनम्) पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया.
- फ्रांस की सरकार ने डूप्ले की क्रियान्वित एवं गतिविधियों से अप्रसन्न होकर उसे 1754 ई. में भारत से वापस बुला लिया.
- डूप्ले के बाद भारत में अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से फ्रांस सरकार ने काउंट लैली को 1757 ई. में भेजा.
- लैली भी अपने उद्देश्यों में असफल रहा. फलतः फ्रांसीसी सरकार ने उसे भी वापस बुला लिया और 1763 ई. में उसे मृत्युदण्ड दे दिया.

- फ्रांसीसियों के बजाय अंग्रेजों की नीतियाँ उदारवादी थीं, जिनके कारण वे अपने पैर भारत में आसानी से जमा सके.
- बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना प्लासी तथा बक्सर युद्ध का परिणाम थी.
- प्रसिद्ध इतिहासकार नवीनचंद सेन के मतानुसार, "प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अनंत अंधकार वाली रात्रि शुरू हो गई".
- अंग्रेज अधिकारी एलिस ने 25 जून, 1763 ई. को पटना पर अपना अधिकार जमा लिया.
- अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में मीरकासिम परास्त हुआ था. पराजय से दुखी होकर वह युद्ध क्षेत्र से भाग गया और 1777 ई. में दिल्ली के पास उसकी मृत्यु हो गई.
- लॉर्ड क्लाइव की द्वैध नीति के कारण विदेश व्यापार नीति और विदेशी व्यापार प्रवन्ध कम्पनी के हाथ में था और लगान वसूली के लिए भारतीय अधिकारी नियुक्त किए गए.
- अंग्रेज साम-दाम-दण्ड-भेद की नीति अपनाकर 1857 ई. तक पूर्ण रूप से भारत के क्षेत्रों पर छा गए.
- मैसूर युद्ध का एक प्रमुख कारण हैदरअली तथा फ्रांसीसियों की मित्रता भी था.
- अंग्रेजों ने हैदरअली के शत्रु मुहम्मदअली, जोकि आर्काट का नवाब था, उसको शरण दे रखी थी, जिसके कारण हैदर अंग्रेजों के खिलाफ रहता था.
- भारत की तात्कालिक राजनीति पर चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध का व्यापक असर पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों के दो प्रमुख शत्रु हैदर तथा टीपू की शक्ति नष्ट प्रायः हो गई.
- मराठों तथा अंग्रेजों के मध्य 1779 ई. में एक संधि हुई जिसे बड़गाँव की संधि कहा जाता है.
- 17 मई, 1782 ई. की संधि (मराठा-अंग्रेज) सालबाई के नाम से जानी जाती है.
- अंग्रेजी कर्मचारियों की लूट-खसोट की प्रवृत्ति पर तथा उनकी मनमानी पर रोक लगाने के उद्देश्य से रेग्यूलेटिंग एक्ट की रचना की गई.
- रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 से 1784 ई. तक प्रभावित रहा.
- 1500 ई. में पड्रो अलबरे क्रेबल 13 जहाजों के बेड़े के साथ भारत में व्यापार करने एवं पूर्वी सागर पर आधिपत्य स्थापत्य करने के उद्देश्य से भारत आया था. उसने कोचीन में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी.
- डी नोवा नामक पुर्तगाली ने कालीकट में अरब जहाजों की लूटमार कर अरब सागर पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया था.
- 1505 ई. में डी. अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं सन् 1509 ई. में अलफासों डि अलबुकर्क दूसरा पुर्तगाली वायसराय भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आये थे.
- "मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इन लोगों से अच्छा व्यवहार तभी किया जा सकता है, जब एक हाथ में तलवार तथा एक में कलम हो.", यह कथन सर टामस रो का था.
- मसूलीपट्टम (मसूलीपट्टनम्) में **1611** ई. में अंग्रेजी **कप्तान हिपन** ने एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी.
- फोर्ड सेण्ट जॉर्ज एक व्यापारिक किलाबन्द कोठी थी, जिसे 1639 ई. में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने स्थापित किया था.
- भारत में पहली **फ्रेंच बस्ती** की स्थापना **सूरत** में हुई थी.

विशिष्ट स्मरणीय तथ्य

1. प्रमुख आंग्ल-मराठा, आंग्ल-मैसूर तथा आंग्ल-सिख युद्ध

क्र. सं.	युद्ध	समय	तत्कालीन गवर्नर जनरल
1.	प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध	1775-82 ई.	वारेन हेस्टिंग्स
2.	द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध	1803-06 ई.	लॉर्ड वेलेजली
3.	तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध	1817-18 ई.	लॉर्ड हेस्टिंग्स
4.	प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध	1767-69 ई.	लॉर्ड क्लाइव
5.	द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध	1780-84 ई.	वारेन हेस्टिंग्स
6.	तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध	1790-92 ई.	लॉर्ड कार्नवालिस
7.	चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध	1799 ई.	लॉर्ड वेलेजली
8.	प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध	1845-46 ई.	लॉर्ड हार्डिंग
9.	द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध	1848-49 ई.	लॉर्ड डलहौजी

2. नये स्वायत्त राज्य एवं उनके संस्थापक

क्र. सं.	स्वायत्त राज्य	संस्थापक
1.	हैदराबाद	चिनकिसिच खाँ
2.	मैसूर	हैदर अली
3.	कर्नाटक	सादुतुल्ला खाँ
4.	अवध	सआदत खाँ/बुररानुल मुल्क
5.	बंगाल	मुर्शीद कुली खाँ
6.	भरतपुर	बदनसिंह एवं चूरामन
7.	रुहेलखण्ड	अली मुहम्मद खाँ बंगश

3. बंगाल के स्वतन्त्र नवाब एवं शासनावधि

क्र. सं.	नवाब	शासनावधि
1.	मुर्शिद कुली खाँ	1713-1727 ई.
2.	शुजाउद्दीन खाँ	1727-1739 ई.
3.	सरफराज खाँ	1739-1740 ई.
4.	अलीवर्दी खाँ	1740-1756 ई.
5.	सिराजुद्दौला	1756-1757 ई.
6.	मीर कासिम	1760-1764 ई.
7.	मीर जाफर	1764-1765 ई.
8.	नजमुद्दौला	1765-1767 ई.

विगत वर्षों में आई.ए.एस. (प्री.) में पूछे गये प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन यूरोप की यांत्रिक घड़ी दक्षिण भारत में लाए थे तथा यह कब लाई गई थी ?
   (A) सत्रहवीं शताब्दी में फ्रांसीसी
   (B) सोलहवीं शताब्दी में पुर्तगाली
   (C) अठारहवीं शताब्दी में डच
   (D) पंद्रहवीं शताब्दी में अंग्रेज

2. निम्नलिखित में से मराठों से सम्बन्धित कौनसा एक कथन सही नहीं है ?
   (A) मराठा आन्दोलन ने शाहजी द्वारा उड़ीसा में एक वास्तविक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना का आरम्भ किया
   (B) पेशवा के पद पर बाजीराव 1720 में आरूढ़ हुआ
   (C) मराठों द्वारा राजस्थान, दोआब के कुछ भाग एवं पंजाब पर आधिपत्य का प्रयत्न 1741 में किया गया
   (D) मराठा आन्दोलन मराठा सरदारों के नेतृत्व में होने वाला एक आन्दोलन था

3. 1909 के इण्डियन कौंसिल एक्ट में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल से सम्बन्धित उपबन्धों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. एक्ट ने सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार में बढ़ोतरी की.
   2. एक्ट द्वारा पृथक् बजट मदों पर मतदान की अनुमति दी गई.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/ हैं ?
   (A) केवल 1 (B) केवल 2
   (C) 1 और 2 दोनों (D) न ही 1 और न ही 2

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेजों को उत्तरी सरकार (का क्षेत्र) प्रदान किया, क्योंकि मद्रास शासन ने उसकी फ्रांसीसियों व मराठों के विरुद्ध सहायता करने की सहमति दे दी.
   2. अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक बना.
   3. तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू सुल्तान द्वारा पश्चिमी तट पर अपना नियन्त्रण दृढ़ करने का प्रयास था.

   उपर्युक्त में से कौनसे कथन सही हैं ?
   (A) 1, 2 तथा 3 (B) केवल 1 तथा 2
   (C) केवल 2 तथा 3 (D) केवल 1 तथा 3

5. निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के साथ सेरिंग पट्टम की संधि सम्पादित की ?
   (A) हेस्टिंग्ज (B) कॉर्नवालिस
   (C) वेलेज़ली (D) डलहौजी

6. आंग्ल-मराठा युद्धों के दौरान निम्नलिखित में से कौनसी संधि सबसे अन्त में सम्पादित हुई थी ?
   (A) सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि
   (B) होलकर के साथ मंदसौर की संधि
   (C) बाजीराव-द्वितीय के साथ पूना की संधि
   (D) सिंधिया के साथ सूरजी-अर्जनगाँव की संधि

7. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?
   (A) 1793 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर-जनरल को मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेंसी में भी उसी प्राधिकार के प्रयोग में सक्षम बनाया जो वह बंगाल पर प्रयुक्त करता था.
   (B) 1813 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अभिगृहीत क्षेत्रों पर सम्राट् की निस्संदेह प्रभुसत्ता स्थापित कर दी.
   (C) 1833 के चार्टर एक्ट ने अधीनस्थ प्रेसीडेंसियों से कानून बनाने के समस्त अधिकार वापस ले लिए
   (D) 1853 के चार्टर एक्ट ने प्रादेशिक स्तर के कौंसलरों की नियुक्ति में सम्राट् की अनुमति को अनावश्यक बना दिया

8. 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. कौंसिल के सदस्यों की सदस्यता अवधि गवर्नर जनरल के प्रसादपर्यंत थी.
   2. गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त थी.
   3. गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को नागरिक व सैन्य शक्तियाँ दी गई थीं.

   उपर्युक्त में से कौनसे कथन सही हैं ?
   (A) 1, 2 तथा 3 (B) केवल 1 तथा 2
   (C) केवल 2 तथा 3 (D) केवल 1 तथा 3

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान के एक आधारभूत ढाँचे की अनुशंसा की.
   2. कैबिनेट मिशन ने संविधान की रचना करने वाले समूह के लिए कार्यप्रणाली तैयार की.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/ हैं ?

(A) केवल 1 (B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों (D) न ही 1 और न ही 2

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. जब वारेन हेस्टिंग्ज गवर्नर जनरल बना तब उसने कोषागार को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया.

2. 1780 में नमक का उत्पादन सरकार ने सीधे अपने हाथों में ले लिया.

3. भू-राजस्व का दसवर्षीय बन्दोबस्त 1790 में स्थायी घोषित कर दिया गया.

उपर्युक्त में से कौनसा/से सही है / हैं ?

(A) केवल 1 (B) केवल 1 तथा 2

(C) केवल 2 तथा 3 (D) 1, 2 तथा 3

11. लॉर्ड डलहौजी के प्रशासनकाल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ ?

(A) द्वितीय आंग्ल-वर्मा युद्ध

(B) कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का बिछाया जाना

(C) बम्बई से थाणे तक रेलवे का खोला जाना

(D) दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना

12. निम्नलिखित में से कौनसे भारत में कम्पनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे ?

1. भू-राजस्व

2. नमक और अफीम व्यापार का एकाधिकार

3. मालभाड़ा

4. रूपान्तरण ऋणपत्र

5. साइट (सीमा शुल्क, पथकर, उत्पादन शुल्क इत्यादि)

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) 1, 2 एवं 3 (B) 1, 2 एवं 5

(C) 2, 3, एवं 4 (D) 1, 3 एवं 5

13. निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था ?

(A) प्रथम कर्नाटक युद्ध (B) बक्सर का युद्ध

(C) प्लासी का युद्ध (D) वाण्डिवाष का युद्ध

14. मराठा शासन के प्रारम्भिक दशकों में भू-राजस्व माप की सर्वाधिक लोकप्रिय इकाई थी–

(A) गज (B) काठी

(C) जरीब (D) जंजीर

15. मराठा राज्यसंघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था ?

(A) वॉरेन हेस्टिंग्स (B) लॉर्ड वेलेजली

(C) लॉर्ड हेस्टिंग्स (D) लॉर्ड मिन्टो

16. भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंगलिश फैक्ट्री थी ?

(A) कोचीन (B) तेल्ली चेरी

(C) कन्ननूर (D) कालीकट

17. मीर कासिम द्वारा ईस्ट इण्डिया को प्रदत्त जमींदारी में निम्नलिखित जिलों में से कौन एक सम्मिलित नहीं था ?

(A) बर्द्धवान (B) मुजफ्फरपुर

(C) मिदनापुर (D) चिटगाँव

18. निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य एवं चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया था ?

(A) 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट

(B) पिट का इण्डिया एक्ट

(C) 1813 का चार्टर एक्ट

(D) 1833 का चार्टर एक्ट

19. 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का निम्नलिखित में से कौनसा कारण था ?

(A) उत्पादन की गुणवत्ता में ह्रास

(B) कच्चे माल की अनुपलब्धता

(C) ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर का ऊँचा होना

(D) कारीगरों की अनुपलब्धता

20. निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन एक सही है ?

(A) कार्नवालिस द्वारा सन् 1793 ई. में परिभाषित बंगाल के स्थायी बन्दोबस्त ने अभिजात्य जमींदारों के एक वर्ग को जमीन में स्वामित्व अधिकार प्रदान किए.

(B) स्थायी बन्दोबस्त कार्यवाही से जमींदारों की स्थिति कमजोर हो गई.

(C) टॉमस मुनरो ने बन्दोबस्त की एक व्यवस्था का विकास किया, जिसके अन्तर्गत सरकार भू-स्वामी काश्तकारों के साथ सीधे कोई संव्यवहार नहीं करती थी.

(D) भूमि नीति एवं बन्दोबस्तों से भूमि पर नियन्त्रण तथा भूमि कर्षण से जुड़े वर्गों के मध्य सम्बन्धों में संरचनात्मक सुधार नहीं हुए.

21. नीचे चार उद्योग दिए गए हैं, जो भारत में अंग्रेजी शासन की अवधि में विकसित हुए–

1. जूट उद्योग 2. लौह एवं इस्पात उद्योग

3. वस्त्र उद्योग 4. चीनी उद्योग

निम्नलिखित में से कौन एक, उद्योगों के विकास के सही कालक्रम को प्रकट करता है ?

(A) 1, 2, 3, 4 (B) 3, 1, 2, 4

(C) 1, 3, 2, 4 (D) 4, 1, 2, 3

22. बंगाल में स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने हेतु 1717 में इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को फरमान देने वाला मुगल बादशाह था–
   (A) बहादुरशाह (B) शाहआलम
   (C) फर्रुखशियर (D) जहाँदारशाह

23. सदर निजामत अदालत को वारेन हेस्टिंग्ज ने कहाँ स्थापित किया था ?
   (A) कलकत्ता (B) ढाका
   (C) पटना (D) मुर्शिदाबाद

24. बंगाल का वह नवाब कौन था, जो इजरदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रैयतों से सीधे राजस्व एकत्र करता था ?
   (A) अलीवर्दी खाँ (B) मुर्शीद कुली खाँ
   (C) शुजाउद्दीन (D) सरफराज खाँ

25. मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1863 में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी–
   (A) कलकत्ता में (B) अलीगढ़ में
   (C) दिल्ली में (D) कराची में

26. निम्नलिखित योरोपीय व्यापारिक वर्गों में से किसने सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की ?
   (A) पुर्तगाली (B) डच
   (C) अंग्रेज (D) फ्रांसीसी

27. सिराजुद्दौला द्वारा सन् 1756 ई. में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया था ?
   (A) मुर्शिदाबाद (B) फान्टा
   (C) कलकत्ता (D) कासिम बाजार

28. कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की ?
   (A) अर्काट (B) बुडिकोटा
   (C) डिंडिगुल (D) देवनहल्ली

29. रणजीत सिंह किस सिख मिशन के थे ?
   (A) कन्हैया (B) सुकरचकिया
   (C) अहलुवालिया (D) भँगी

30. बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे उसके सम्बन्ध बिगड़ गये ?
   (A) अलीवर्दी (B) सिराजुद्दौला
   (C) मीरजाफर (D) मीरकासिम

31. इलाहाबाद की सन्धि किन ने निष्पादित की थी ?
   (A) रॉबर्ट क्लाइव, मीरजाफर एवं राजा बलवन्त सिंह
   (B) रॉबर्ट क्लाइव, नज्मउद्दौला एवं शुजाउद्दौला
   (C) रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला एवं मीरकासिम
   (D) शाहआलम, मीरजाफर एवं शुजाउद्दौला

32. यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य था–
   (A) गोलकुण्डा (B) मैसूर
   (C) अवध (D) कश्मीर

33. मंगलौर, परम्बक्कम एवं पोर्टोनोवो स्थानों पर निम्नांकित किस युद्ध के दौरान प्रमुख लड़ाइयाँ हुईं ?
   (A) प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध
   (B) द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध
   (C) तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध
   (D) चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध

34. फ्रांसीसियों ने निम्नांकित किस सन्धि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया ?
   (A) अस्ला-श्लेज की सन्धि (1749)
   (B) पाण्डिचेरी की सन्धि (1754)
   (C) सलबाई की सन्धि (1782)
   (D) मंगलौर की सन्धि (1784)

35. सत्रहवीं शताब्दी में भारत और क्यूबा के बीच के व्यापार पर प्रभुत्व था–
   (A) पुर्तगालियों का (B) डचों का
   (C) अंग्रेजों का (D) फ्रांसीसियों का

36. बंगाल में मुर्शीद कुली खाँ के राजस्व सुधारों के परिणाम-स्वरूप वहाँ का वार्षिक राजस्व लगभग–
   (A) 80,00,000 रुपये हो गया
   (B) 1,50,000 रुपये हो गया
   (C) 1,00,00,000 रुपये हो गया
   (D) 2,00,00,000 रुपये हो गया

37. निम्नलिखित में से कौनसा क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल सम्राट् शाहजहाँ II को वापस किया था ?
   (A) 24 परगना (B) कड़ा और इलाहाबाद
   (C) बिहार और उड़ीसा (D) अवध और उड़ीसा

38. निम्नलिखित में से कौनसा एक कथन 'हिन्दू पद-पादशाही' शब्द को सही प्रकार परिभाषित करता है ?
   (A) मराठा साम्राज्य (B) मुगल साम्राज्य
   (C) मराठा साम्राज्यवाद (D) हिन्दू स्वराज्य

39. रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के संघर्ष में किसने सत्ता हड़प ली थी ?
   (A) ध्यान सिंह ने (B) नौनिहाल सिंह ने
   (C) शेरसिंह ने (D) खड़ग सिंह ने

40. मीर कासिम और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था ?
   (A) मुगल सम्राट् और अवध के नवाब के साथ मीर कासिम का गठजोड़
   (B) अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग
   (C) मीर कासिम का फ्रांसीसियों के साथ षड्यन्त्र
   (D) मीर जाफर का ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ षड्यन्त्र

41. निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया ?
   (A) 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट ने
   (B) 1813 के चार्टर एक्ट ने
   (C) 1833 के चार्टर एक्ट ने
   (D) 1853 के चार्टर एक्ट ने

42. फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी–
   (A) विदनूर में (B) सेरा में
   (C) सुंडा में (D) डिंडीगुल में

43. श्री रंगपत्तनम् में 'स्वतन्त्रता का वृक्ष' किसने लगाया ?
   (A) हैदर अली ने (B) चिक्का कृष्णराज ने
   (C) टीपू सुल्तान ने (D) देवराज ने

44. मराठों की वह महिला सरदार कौन थी, जिसने राजाराम की मृत्यु के बाद ईस्वी सन् 1700 के बाद भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था ?
   (A) अहिल्याबाई (B) मुक्ताबाई
   (C) ताराबाई (D) रुक्मिणीबाई

45. जिस मराठे ने 1719 में फर्रुखसियर का तख्ता उलटने में सैय्यद बन्धुओं की मदद की थी, वह था–
   (A) शिवाजी II (B) साहू जी
   (C) बालाजी विश्वनाथ (D) बाजीराव I

46. बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है ?
   1. सुजाउद्दीन 2. मुर्शीद कुली खान
   3. सरफराज खान 4. अलीवर्दी खान
   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–
   (A) 2, 1, 3, 4 (B) 1, 2, 4, 3
   (C) 2, 1, 4, 3 (D) 1, 2, 3, 4

47. कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी–
   (A) 1773 के नार्थ्स रेग्यूलेटिंग एक्ट के द्वारा
   (B) 1784 के पिट्स इण्डिया एक्ट के द्वारा
   (C) 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा
   (D) 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा

48. निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए–
   1. सूरजमल 2. चरहटसिंह
   3. बुधसिंह 4. बदनसिंह
   इनमें से जो भरतपुर के राज्य से जुड़े हुए थे, वे थे–
   (A) 1 और 2 (B) 2 और 3
   (C) 3 और 4 (D) 1 और 4

49. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए–
   1. कार्नवालिस कोड
   2. नॉर्थ का रेगूलेटिंग एक्ट
   3. पिट्स इण्डिया एक्ट
   इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है–
   (A) 3, 2, 1 (B) 2, 3, 1
   (C) 1, 2, 3 (D) 2, 1, 3

50. घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजवल्लभ और यार लतीफ खान जानी दुश्मन थे–
   (A) नवाब अलीवर्दी खान के (B) नन्द कुमार के
   (C) सिराजुद्दौला के (D) शुजाउद्दौला के

51. निम्नलिखित शक्ति गुटों में से कौनसे एक में ब्रिटिश विरोधी मोर्चा (1780) था ?
   (A) निजाम, मैसूर, बरार, मारवाड़
   (B) निजाम, बरार, रुहिल्ले तथा मराठे
   (C) मराठे, मैसूर, बरार तथा निजाम
   (D) मैसूर, मराठे, रुहिल्ले तथा बरार

52. सूची-I (विदेश यात्री) को सूची-II (भारत में आने का वर्ष) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची-I	सूची-II
(a) हॉकिन्स	(1) 1615
(b) सर टॉमस रो	(2) 1608
(c) मनूची	(3) 1585
(d) राल्फ फिच	(4) 1658

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	1	4	3
(B)	1	2	4	3
(C)	2	1	3	4
(D)	1	2	3	4

53. भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई–
   (A) बम्बई में (B) हुगली में
   (C) सूरत में (D) कलकत्ता में

54. भारत के साथ समुद्री व्यापार आरम्भ करने में निम्नलिखित में कौन अग्रणी थे ?
    (A) डच (B) अंग्रेज
    (C) पुर्तगाली (D) फ्रांसीसी

55. तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध मण्डल बनाने वालों में शामिल थे ?
    (A) निजाम, कर्नाटक के नवाब एवं अंग्रेज
    (B) मराठा, अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब
    (C) अंग्रेज, मराठा और निजाम
    (D) त्रावणकोर का राजा, मराठा और अंग्रेज

56. बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौनसी एक, डचों द्वारा स्थापित की गई थी ?
    (A) बांदेल (B) हुगली
    (C) चिनसूरा (D) श्रीरामपुर

57. ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेग्युलेटिंग एक्ट पारित किया, वर्ष–
    (A) 1773 में (B) 1775 में
    (C) 1853 में (D) 1855 में

58. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए–
    1. उदयपुर का अधिग्रहण 2. झाँसी का अधिग्रहण
    3. पंजाब का अधिग्रहण 4. अवध का अधिग्रहण
    इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है–
    (A) 3, 4, 2, 1 (B) 2, 1, 3, 4
    (C) 2, 4, 3, 1 (D) 3, 1, 2, 4

59. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    प्रथम विश्व युद्ध के अन्तिम चरणों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनकर्ताओं की घोर निराशा का कारण था–
    1. साम्राज्यिक सम्मेलन तथा शान्ति सम्मेलन में केवल थोड़े से भारतीय नरेशों की भागीदारी.
    2. विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत में शान्ति की जगह दमन का प्रयोग.
    3. 1919 में गांधी के दिल्ली गमन पर सरकार द्वारा रोक.
    4. 1919 में रॉलट कानून का पारित होना.
    इनमें से कौनसे कथन सही हैं?
    (A) 1 व 3 (B) 1 व 4
    (C) 2 व 4 (D) 2 व 3

60. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1826 की यांदबू सन्धि ने रास्ता साफ किया.
    1. अंग्रेज व्यापारियों के लिए आश्वासनपूर्ण संरक्षण का.
    2. अंग्रेजों के लिए एक करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का.
    3. बर्मा के लोगों तथा अंग्रेजों के बीच घोर लड़ाइयों का.
    4. चाय के लिए असम के अधिग्रहण का.
    इनमें से कौनसे कथन सही हैं?
    (A) 1 व 2 (B) 2 व 3
    (C) 3 व 4 (D) 2 व 4

61. निम्न में से कौनसा नवाब 1856 में अवध के ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजों द्वारा विलय किए जाने के समय पदच्युत किया गया था?
    (A) सआदत खाँ बुरहान-उल-मुल्क
    (B) सफदर जंग
    (C) वाजिद अलीशाह
    (D) बिरजीस कदर

62. ब्रितानवी (ब्रिटिश) शासन को समाप्त करने के लिए कूका आन्दोलन संघटित हुआ?
    (A) उत्तर प्रदेश में (B) बिहार में
    (C) पंजाब में (D) मुम्बई में

निर्देश–आगामी प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है. इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए–

कूट :
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(B) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है.
(C) A सही है, परन्तु R गलत है.
(D) A गलत है, परन्तु R सही है.

63. **कथन (A)** : बंगाल में अंग्रेजों के विरुद्ध संन्यासियों तथा फकीरों ने विद्रोह कर दिया था.
    कारण (R) : संन्यासी तथा फकीर अंग्रेजों द्वारा भारत की धार्मिक परम्परा में हस्तक्षेप के विरोधी थे.

64. निम्नलिखित प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध 1779–82 से सम्बन्धित हैं–
    1. बडगाँव सम्मेलन 2. पुरन्दर की सन्धि
    3. सूरत की सन्धि 4. सालबाई की सन्धि
    इनका सही कालानुक्रम है–
    (A) 3, 2, 1, 4 (B) 2, 1, 3, 4
    (C) 4, 2, 1, 3 (D) 1, 4, 3, 2

65. निम्न में से किसके मध्य 1731 ई. में वर्णा सन्धि हुई थी?
    (A) सतारा के शाहू छत्रपति तथा हैदराबाद के निजाम

(B) कोल्हापुर के सम्भाजी छत्रपति तथा सतारा के शाहू छत्रपति

(C) कोल्हापुर के सम्भाजी तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी

(D) बाजीराव प्रथम तथा भोपाल के नवाब

66. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में भारत में अपराधिक मुकदमों की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय था–

(A) सर्किट न्यायालय

(B) प्रॉविंशियल न्यायालय

(C) सदर दीवानी अदालत

(D) सदर निजामत अदालत

67. सूची-I (युद्ध) को सूची-II (सन्धियाँ) से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–

सूची–I (युद्ध)

(a) द्वितीय कर्नाटक युद्ध

(b) द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध

(c) तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध

(d) प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध

सूची–II (सन्धियाँ)

1. सालबाई 2. बसीन

3. पाण्डिचेरी 4. श्रीरंगपट्टनम

5. मंगलौर

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	1	2	5
(B)	3	5	4	1
(C)	4	5	2	1
(D)	3	1	4	5

68. निम्न में से किस अधिनियम ने 'संवैधानिक निरंकुशता' के सिद्धान्त का अनुमोदन किया?

(A) 1909 का इण्डियन कौंसिल अधिनियम

(B) 1919 का गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया अधिनियम

(C) 1935 का अधिनियम

(D) 1947 का भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम

69. सूची-I (घटना) को सूची-II (स्थान) से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–

सूची–I (घटना)	सूची–II (स्थान)
(a) चम्पारण सत्याग्रह	1. केरल
(b) पटना किसान आन्दोलन	2. पूर्वी बंगाल
(c) मोपला (मोपिला) विद्रोह	3. बिहार
(d) दक्खन उपद्रव	4. अहमदनगर

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	1	2	4
(B)	4	2	1	3
(C)	3	2	1	4
(D)	4	1	2	3

70. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची-I	सूची-II
(a) डच	(1) गोआ
(b) इंग्लिश	(2) पुलीकाट
(c) पोर्तगीज	(3) हुगली
(d) फ्रेंच	(4) चिनसूरा

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	4	1	2
(B)	1	3	2	4
(C)	2	3	1	4
(D)	2	1	4	3

उत्तरमाला

1. (B)	2. (A)	3. (A)	4. (C)	5. (B)
6. (B)	7. (D)	8. (C)	9. (C)	10. (B)
11. (D)	12. (B)	13. (D)	14. (B)	15. (C)
16. (C)	17. (B)	18. (D)	19. (C)	20. (A)
21. (B)	22. (C)	23. (D)	24. (B)	25. (A)
26. (A)	27. (C)	28. (C)	29. (B)	30. (D)
31. (B)	32. (B)	33. (B)	34. (A)	35. (B)
36. (B)	37. (B)	38. (D)	39. (D)	40. (B)
41. (C)	42. (D)	43. (C)	44. (C)	45. (C)
46. (A)	47. (A)	48. (D)	49. (B)	50. (C)
51. (C)	52. (B)	53. (C)	54. (C)	55. (C)
56. (C)	57. (A)	58. (D)	59. (C)	60. (A)
61. (C)	62. (C)	63. (A)	64. (A)	65. (B)
66. (D)	67. (B)	68. (C)	69. (C)	70. (C)

संकेत

3. बजट पर मतदान का अधिकार 1919 के एक्ट से मिला.

10. 1793 में इसे स्थाई घोषित कर दिया गया.

58. उदयपुर – 1852
झाँसी – 1853
पंजाब – 1849
अवध – 1856

61. अवध का अधिग्रहण कुशासन के आरोप में किया गया था.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. आधुनिक भारत के इतिहास का काल है–
   (A) 1757-1947 (B) 1757-1857
   (C) 1947-1957 (D) 1758-1958
2. औरंगजेब की मृत्यु हुई–
   (A) 1657 में (B) 1707 में
   (C) 1727 में (D) 1772 में
3. मुगल साम्राज्य के समय साम्राज्य का आधार विन्दु केन्द्र होता था–
   (A) शासन व्यवस्था का (B) लगान वसूली का
   (C) चौथ वसूली का (D) गुप्तचर विभाग का
4. सेना का प्रधान सेनापति तथा न्याय व्यवस्था का मुख्य स्रोत होता था–
   (A) मनसवदार (B) मुख्यमंत्री
   (C) सम्राट् (D) मुख्य सलाहकार
5. औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को बाँटा हुआ था–
   (A) 25 प्रांतों में (B) 30 प्रांतों में
   (C) 35 प्रांतों में (D) 20 प्रांतों में
6. इन बाँटे गए प्रांतों को कहा जाता था–
   (A) सूबा (B) परगना
   (C) जिला (D) रियासत
7. इन सूबों के शीर्षस्थ अधिकारी कहलाते थे–
   (A) मनसवदार (B) सूबेदार
   (C) सेनापति (D) मुख्यमंत्री
8. मुगल साम्राज्य में अव्यवस्था, अराजकता, विघटन पनपने का मूल कारण था–
   (A) सामंती व्यवस्था (B) राजदूत व्यवस्था
   (C) सलाहकार व्यवस्था (D) परामर्शदाता व्यवस्था
9. लॉर्ड इरविन के अनुसार मुगल सामंत कितने गुटों में विभक्त थे ?
   (A) 5 (B) 10
   (C) 3 (D) 4
10. महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनाने की अनुमति दी–
    (A) 1600 ई. में (B) 1700 ई. में
    (C) 1599 ई. में (D) 1499 ई. में
11. ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शुरूआत कितने हिस्सेदारों ने मिलकर की ?
    (A) 217 ने (B) 218 ने
    (C) 317 ने (D) 518 ने
12. इस कम्पनी को शुरू में कितने वर्ष तक के लिए व्यापार एकाधिकार पत्र मिला ?
    (A) 20 वर्ष (B) 15 वर्ष
    (C) 12 वर्ष (D) 14 वर्ष
13. यह अधिकार कम्पनी को कब मिला ?
    (A) 31 दिसम्बर, 1600 ई. को
    (B) 31 मई, 1600 ई. को
    (C) 31 जुलाई, 1600 ई. को
    (D) 31 अक्टूबर, 1600 ई. को
14. अंग्रेजों का प्रथम जहाजी बेड़ा भारत में आया–
    (A) 1612 ई. (B) 1610 ई.
    (C) 1608 ई. (D) 1607 ई.
15. इस प्रथम बेड़े का कप्तान कौन था ?
    (A) वारेन हेस्टिंग्स (B) हॉकिन्स
    (C) सर टॉमस रो (D) क्लाइव
16. मुगल सम्राट् जहाँगीर के दरबार में राजदूत था–
    (A) सर टॉमस रो (B) क्लाइव
    (C) हॉकिन्स (D) हेटिंग्स
17. जहाँगीर के दरबार में जो राजदूत नियुक्त हुआ, उसका कार्यकाल रहा–
    (A) 1618-1620 (B) 1617-1619
    (C) 1615-1618 (D) 1619-1620
18. अंग्रेजों को आयात-निर्यात कर में छूट मिली–
    (A) 1656 में (B) 1756 में
    (C) 1655 में (D) 1755 में
19. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शुरूआती दौर (1600) में हिस्सा पूँजी थी–
    (A) 50133 पौंड (B) 30133 पौंड
    (C) 33103 पौंड (D) 53103 पौंड
20. यह हिस्सा पूँजी 1722 ई. में बढ़कर हो गई–
    (A) 6 करोड़ पौंड (B) 7 करोड़ पौंड
    (C) 8 करोड़ पौंड (D) 10 करोड़ पौंड
21. "अब समय का तकाजा है आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबन्ध करें." यह कथन किस अंग्रेज शासक का है ?
    (A) विलियम (B) क्लाइव
    (C) जेराल्ड औंगियर (D) टॉमस रो
22. "आप असैनिक और सैनिक शक्ति का ऐसा शासन कायम कीजिए तथा दोनों की प्राप्ति के लिए इतनी आय पैदा कीजिए तथा बनाए रखिए"........."जो सदैव के

लिए भारत में एक विशाल, सुगठित तथा सुरक्षित अंग्रेजी राज्य की नींव बन सके." यह कथन है–

(A) मैकाले का (B) जोशुआ चाइल्ड का
(C) हेस्टिंग्स का (D) निकल्सन का

23. अंग्रेज तथा फ्रांसीसी कम्पनियों के मध्य प्रथम युद्ध कहाँ हुआ ?
(A) कलकत्ता में (B) गुजरात में
(C) बंगाल में (D) कर्नाटक में

24. डूप्ले फ्रांसीसी कम्पनी का गवर्नर बना–
(A) 1742 ई. में (B) 1743 ई. में
(C) 1744 ई. में (D) 1745 ई. में

25. प्रथम कर्नाटक युद्ध बन्द हुआ–
(A) क्लाइव की संधि के परिणामस्वरूप
(B) मैकाले की संधि के परिणामस्वरूप
(C) एलाशेपल की संधि के परिणामस्वरूप
(D) लॉर्ड मिन्टो की संधि के परिणामस्वरूप

26. कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का श्रीगणेश हुआ–
(A) 1552 ई. में (B) 1750 ई. में
(C) 1748 ई. में (D) 1749 ई. में

27. कर्नाटक में द्वितीय युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया–
(A) लॉर्ड हेस्टिंग्स ने (B) लॉर्ड क्लाइव ने
(C) लॉर्ड मिंटो ने (D) लॉर्ड हॉकिन्स ने

28. यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरूआत कब हुई ?
(A) 1756 में (B) 1757 में
(C) 1758 में (D) 1759 में

29. कर्नाटक युद्ध के तीसरे चरण में मुख्य बात क्या रही ?
(A) फ्रांसीसियों की शक्ति लगभग खत्म हो गई
(B) फ्रांसीसियों को अधिकार और मिल गए
(C) फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मात दी
(D) अंग्रेजों पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा

30. अंग्रेज सर्वशक्तिशाली शासक के रूप में सिद्ध हुए–
(A) कर्नाटक की प्रथम विजय से
(B) कर्नाटक के द्वितीय युद्ध से
(C) कर्नाटक के तृतीय युद्ध से
(D) इनमें से कोई नहीं

31. अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर बंगाल पर अपना कब्जा किया–
(A) 18वीं शताब्दी में (B) 16वीं शताब्दी में
(C) 17वीं शताब्दी में (D) 19वीं शताब्दी में

32. प्लासी का युद्ध हुआ–
(A) 1756 में (B) 1758 में
(C) 1559 में (D) 1757 में

33. सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले को कब जीता ?
(A) 20 जून, 1756 (B) 21 जून, 1756
(C) 22 जून, 1756 (D) 23 जून, 1756

34. काली कोठरी की दुर्घटना के समय कितने अंग्रेज कैदी बंदी बनाए गए ?
(A) 123 (B) 230
(C) 146 (D) 142

35. इन कैदियों में से कितने जिन्दा शेष रहे ?
(A) 23 (B) 32
(C) 37 (D) 30

36. प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ ?
(A) अंग्रेज तथा मीरजाफर
(B) अंग्रेज तथा अहमदशाह अब्दाली
(C) अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला
(D) अंग्रेज तथा मीरकासिम

37. प्लासी युद्ध का मुख्य परिणाम क्या रहा ?
(A) अंग्रेज व्यापारी से शासक हो गए
(B) अंग्रेज शासक से व्यापारी हो गए
(C) फ्रांसीसी व्यापारी से शासक हो गए
(D) फ्रांसीसी शासक से व्यापारी हो गए

38. "प्लासी युद्ध के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि शुरू हो गई." यह कथन है–
(A) ताराचंद का (B) नवीनचंद्र सेन का
(C) गोकुलचंद का (D) मोहन कृष्ण का

39. "प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लम्बी प्रक्रिया आरम्भ कर दी, जिसने भारत का स्वरूप ही बदल दिया." यह कथन है–
(A) ताराचंद का (B) नवीनचंद्र सेन का
(C) गोकुलचंद का (D) मोहन कृष्ण का

40. 1760 ई. में क्लाइव के स्थान पर सत्ता सँभाली–
(A) लॉर्ड मिन्टो ने
(B) मैकाले ने
(C) हेस्टिंग्स ने
(D) हालवेल तथा वेन्सिर्टाट ने

41. मीरकासिम ने अवध में शरण ली–
(A) 1766 में (B) 1768 में
(C) 1763 में (D) 1765 में

42. मीरकासिम की मृत्यु हुई–
(A) 1777 में दिल्ली के पास
(B) 1778 में बम्बई के पास
(C) आगरा में
(D) पटना में

43. "प्लासी युद्ध ने सत्ता का हस्तान्तरण किया और बक्सर युद्ध ने अधिकारों का सृजन किया." यह कथन है–
(A) प्रेमचंद का (B) गोकुलभाई का
(C) ताराचंद का (D) मोहन कृष्ण का

44. मीरजाफर की मृत्यु हुई–
(A) 1765 में (B) 1766 में
(C) 1767 में (D) 1768 में

45. अंग्रेजी कम्पनी को स्थायी रूप से बंगाल की दीवानी कब मिली ?
(A) अगस्त 1765 में (B) सितम्बर 1765 में
(C) जुलाई 1765 में (D) अक्टूबर 1765 में

46. द्वैध शासन का संस्थापक माना जाता है–
(A) हेस्टिंग्स (B) कार्ल लुइस
(C) क्लाइव (D) टॉमस रो

47. द्वैध व्यवस्था का अर्थ है–
(A) दोहरी नीति (B) इकहरी नीति
(C) संधि नीति (D) समर्पण नीति

48. द्वैध व्यवस्था के अनुसार विदेश व्यापार नीति किसके पास थी ?
(A) फ्रांसीसियों के पास
(B) अंग्रेज कम्पनी के पास
(C) मुगल सम्राट् के पास
(D) इनमें से कोई नहीं

49. द्वैध शासन प्रणाली का मुख्य लाभ यह हुआ–
(A) वास्तविक मालिक कम्पनी हो गई
(B) वास्तविक मालिक मुगल सम्राट् हो गए
(C) वास्तविक मालिक फ्रांसीसी हो गए
(D) इनमें से कोई नहीं

50. द्वैध शासन प्रणाली से कम्पनी का भू-राजस्व 8 लाख से बढ़कर कितना हो गया ?
(A) 10 लाख रुपए (B) 20 लाख रुपए
(C) 50 लाख रुपए (D) 22 लाख रुपए

51. द्वैध शासन प्रणाली से भारतीय उद्योग–
(A) नष्ट प्रायः हो गए (B) फले-फूले
(C) जस के तस रहे (D) इनमें से कोई नहीं

52. हैदर अली का जन्म हुआ था–
(A) 1722 में (B) 1721 में
(C) 1723 में (D) 1724 में

53. मैसूर युद्ध का एक कारण यह भी था–
(A) हैदर-फ्रांसीसियों की मित्रता
(B) हैदर-अंग्रेजों की मित्रता
(C) टीपू-अंग्रेजों की मित्रता
(D) टीपू-फ्रांसीसियों की मित्रता

54. हैदर अली ने किसको पदच्युत किया ?
(A) कृष्णराज को (B) देवराज को
(C) नजराज को (D) रावराज को

55. हैदरअली डिंडिगल का संरक्षक कब बना ?
(A) 1558 में (B) 1658 में
(C) 1758 में (D) 1761 में

56. अंग्रेज, मराठे तथा निजाम का त्रिगुट कायम कब हुआ ?
(A) 1765 में (B) 1766 में
(C) 1767 में (D) 1768 में

57. 1769 में मद्रास कौंसिल ने किससे संधि की ?
(A) टीपू से (B) रंगनाथ से
(C) पेशवा से (D) हैदर से

58. 1768 में हैदर ने किस पर अपना अधिकार किया ?
(A) कावेरीपट्टम् पर (B) विशाखापट्टनम् पर
(C) मछलीपट्टम पर (D) इनमें से कोई नहीं

59. द्वितीय मैसूर युद्ध की शुरूआत कब हुई ?
(A) 1782 ई. में (B) 1780 ई. में
(C) 1784 ई. में (D) 1783 ई. में

60. हैदर अली की मृत्यु हुई–
(A) 1782 में (B) 1775 में
(C) 1783 में (D) 1784 में

61. टीपू और अंग्रेजों के मध्य 7 मार्च, 1784 को एक संधि हुई जिसे जाना जाता है–
(A) बंगलौर संधि (B) मंगलौर संधि
(C) बंगाल संधि (D) कर्नाटक संधि

62. टीपू ने अपना एक दूत अंग्रेजों के पास भेजा–
(A) 1788 में (B) 1789 में
(C) 1787 में (D) 1786 में

63. अंग्रेजों तथा टीपू के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ–
(A) विशाखापट्टनम के निकट

(B) रंगपट्टम् के निकट
(C) मछलीपट्टम् के निकट
(D) कर्नाटक के निकट

64. रंगपट्टम् के युद्ध के बाद अंग्रेज-टीपू की संधि के अनुसार टीपू को अंग्रेजों को नकद राशि कितनी देनी पड़ी ?
(A) 50 लाख पौंड (B) 30 लाख पौंड
(C) 26 लाख पौंड (D) 32 लाख पौंड

65. टीपू सुल्तान का अन्तिम युद्ध माना जाता है–
(A) 25 मार्च, 1798 का
(B) 20 मई, 1795 का
(C) 20 फरवरी, 1799 का
(D) 20 जनवरी, 1798 का

66. अंग्रेजों तथा मराठों का तृतीय युद्ध कहाँ हुआ ?
(A) पानीपत (B) सोनीपत
(C) करनाल (D) इनमें से कोई नहीं

67. टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ–
(A) 6 मई, 1799 (B) 4 मई, 1798
(C) 4 मई, 1799 (D) 6 मई, 1778

68. पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ ?
(A) 14 जनवरी, 1761 (B) 15 जनवरी, 1762
(C) 18 जनवरी, 1761 (D) 20 फरवरी, 1761

69. पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी विजय हुई ?
(A) टीपू की (B) हैदर की
(C) अंग्रेजों की (D) पेशवा की

70. माधवराव पेशवा कब बना ?
(A) 1761 में (B) 1764 में
(C) 1763 में (D) 1762 में

71. बम्बई सरकार व रघुनाथ के साथ सूरत की संधि कब हुई थी ?
(A) 7 मार्च, 1775 को (B) 8 मार्च, 1776 को
(C) 9 मार्च, 1775 को (D) 9 मार्च, 1776 को

72. मराठा मण्डल तथा कर्नल अप्टन के मध्य जो संधि हुई, वह कहलाती है–
(A) कलकत्ता संधि (B) बंगाल संधि
(C) पुरन्दर संधि (D) पटना संधि

73. पुरन्दर की संधि कब हुई ?
(A) 1 मार्च, 1776 (B) 2 मार्च, 1776
(C) 3 मार्च, 1777 (D) 4 मार्च, 1778

74. 17 मई, 1782 को जो संधि मराठा तथा अंग्रेजों के मध्य हुई, वह थी–
(A) बंगलौर संधि (B) पटना संधि
(C) कलकत्ता संधि (D) सालवाई की संधि

75. होल्कर ने पेशवा और सिंधिया की सम्मिलित सेना को हराया–
(A) 1803 में (B) 1802 में
(C) 1804 में (D) 1806 में

76. पेशवा बाजीराव तथा अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई, वह थी–
(A) विशाखापट्टनम् संधि
(B) मछलीपट्टम् संधि
(C) बेसीन संधि
(D) रंगपट्टम् संधि

77. बेसीन संधि के अनुसार पेशवा ने अंग्रेजों को कितने रुपए आमदनी वाले क्षेत्र दिए ?
(A) 25 लाख रुपए वार्षिक
(B) 26 लाख रुपए वार्षिक
(C) 27 लाख रुपए वार्षिक
(D) 30 लाख रुपए वार्षिक

78. द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध कब शुरू हुआ ?
(A) 1803 में (B) 1804 में
(C) 1805 में (D) 1806 में

79. होल्कर के साथ राजघाट की संधि किसने की ?
(A) लॉर्ड मैकाले ने (B) जॉर्ज वालों ने
(C) लॉर्ड मिंटो ने (D) क्लाइव ने

80. राजघाट की संधि कब हुई ?
(A) जनवरी 1806 में (B) फरवरी 1806 में
(C) मार्च 1807 में (D) अप्रैल 1808 में

81. तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध की शुरूआत हुई–
(A) गायकवाड़ तथा हैदर के झगड़े से
(B) टीपू व गायकवाड़ के झगड़े से
(C) हैदर व पेशवा के झगड़े से
(D) पेशवा व गायकवाड़ के झगड़े से

82. ग्वालियर की संधि कब हुई ?
(A) 5 नवम्बर, 1817 को
(B) 6 नवम्बर, 1817 को
(C) 16 नवम्बर, 1817 को
(D) 15 नवम्बर, 1817 को

83. भोंसले सरदार अप्पाजी को अंग्रेजों ने कब हराया ?
    (A) दिसम्बर 1817 में (B) नवम्बर 1817 में
    (C) जनवरी 1817 में (D) फरवरी 1817 में
84. मंदसौर की संधि कब हुई ?
    (A) जनवरी 1817 में (B) फरवरी 1817 में
    (C) मार्च 1817 में (D) अप्रैल 1817 में
85. अंग्रेजों की मंदसौर संधि किसके साथ हुई ?
    (A) पेशवा से (B) होल्कर से
    (C) रणजीत सिंह से (D) माधवराव से
86. अंग्रेज कर्मचारियों के द्वारा बढ़ती लूट-खसोट को रोकने के लिए जो एक्ट बना, वह था–
    (A) पिट्स एक्ट (B) कम्पनी एक्ट
    (C) रेग्यूलेटिंग एक्ट (D) रेवेन्यू एक्ट
87. 1766 में अंग्रेजी कम्पनी ने अपना लाभांश 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया ?
    (A) 10% (B) 12%
    (C) 8% (D) 9%
88. रेग्युलेटिंग एक्ट कब बना ?
    (A) 1772 में (B) 1773 में
    (C) 1774 में (D) 1775 में
89. रेग्युलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ ?
    (A) 1772 में (B) 1773 में
    (C) 1774 में (D) 1775 में
90. कम्पनी संचालकों के चुनाव में मताधिकार कितने पौंड के हिस्सेदार को दिया गया ?
    (A) 1000 पौंड (B) 1500 पौंड
    (C) 1200 पौंड (D) 1600 पौंड
91. सरकारी पत्र जो भारत भेजे जाने थे, किसे दिखलाने पड़ते थे ?
    (A) राज्यपाल को (B) राज्य सचिव को
    (C) मुख्य सलाहकार को (D) इनमें से कोई नहीं
92. बंगाल के लिए नियुक्त किए गए प्रशासक को कहा गया–
    (A) सूबेदार (B) मुख्य सलाहकार
    (C) राज्य सचिव (D) गवर्नर जनरल
93. गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए जो समिति बनाई गई, उसमें सदस्य थे–
    (A) चार (B) पाँच
    (C) सात (D) आठ
94. गवर्नर जनरलों के उत्तराधिकारी नियुक्त होते थे–
    (A) राज्य सचिव द्वारा (B) सलाहकार द्वारा
    (C) कम्पनी द्वारा (D) खुद के निर्णयानुसार
95. गवर्नर जनरल को वेतन मिलता था–
    (A) 25000 पौंड (B) 20000 पौंड
    (C) 28000 पौंड (D) 15000 पौंड
96. रेग्युलेटिंग एक्ट कब तक प्रभावी रहा ?
    (A) 1782 तक (B) 1783 तक
    (C) 1784 तक (D) 1785 तक
97. रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों में सुधार के लिए जो एक्ट बना, वह था–
    (A) पिट्स इण्डिया एक्ट (B) रोलेट एक्ट
    (C) रेवेन्यू एक्ट (D) कम्पनी एक्ट
98. पिट्स इण्डिया एक्ट कब पारित हुआ ?
    (A) जुलाई 1784 में (B) अगस्त 1784 में
    (C) सितम्बर 1782 में (D) सितम्बर 1784 में
99. जिस एक्ट के आधार पर भारतीय प्रशासन पर इंग्लैण्ड सरकार का अधिकार निश्चित हो गया, वह था–
    (A) रोलेट एक्ट (B) कम्पनी एक्ट
    (C) रेवेन्यू एक्ट (D) पिट्स इण्डिया एक्ट
100. कम्पनी के अधिकारों को समाप्त करके भारत का सचिव किसे बनाया गया ?
    (A) बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को
    (B) राज्य सचिव को
    (C) प्रमुख सलाहकार को
    (D) मुख्य प्रशासक को

उत्तरमाला

1. (A)	2. (B)	3. (A)	4. (C)	5. (D)
6. (A)	7. (B)	8. (A)	9. (D)	10. (C)
11. (A)	12. (B)	13. (A)	14. (C)	15. (B)
16. (A)	17. (C)	18. (A)	19. (B)	20. (A)
21. (C)	22. (B)	23. (D)	24. (A)	25. (C)
26. (C)	27. (B)	28. (A)	29. (A)	30. (C)
31. (A)	32. (D)	33. (A)	34. (C)	35. (A)
36. (C)	37. (A)	38. (B)	39. (A)	40. (D)
41. (C)	42. (A)	43. (C)	44. (A)	45. (A)
46. (C)	47. (A)	48. (B)	49. (A)	50. (D)
51. (A)	52. (B)	53. (A)	54. (C)	55. (D)
56. (B)	57. (D)	58. (A)	59. (B)	60. (A)
61. (B)	62. (C)	63. (B)	64. (B)	65. (C)
66. (A)	67. (C)	68. (A)	69. (C)	70. (A)
71. (A)	72. (C)	73. (A)	74. (D)	75. (B)
76. (C)	77. (B)	78. (A)	79. (B)	80. (A)
81. (D)	82. (A)	83. (B)	84. (A)	85. (B)
86. (B)	87. (A)	88. (B)	89. (C)	90. (A)
91. (B)	92. (D)	93. (A)	94. (C)	95. (A)
96. (C)	97. (A)	98. (B)	99. (D)	100. (A)

2

ब्रिटिश राज्य के आर्थिक प्रभाव
(Economic impact of Britishraj)

[सम्पत्ति का अपवाह (ड्रेन ऑफ वेल्थ) कर व्यवस्था, भू-राजस्व बंदोवस्ती (जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी), उद्योगों का विनाश, कृषि का वाणिज्यीकरण एवं रेलवे, भूमिहीन श्रमिकों की वृद्धि (Drain of Wealth (tribute); Land Revenue Settlements (Zamindari, Ryetwari, Mahalwari), De-industrialisation Railways & Commercialisation of Agriculture Growth of Landless Labour)]

ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव—अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद भारत के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुए. अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारत की सम्पदा का निष्पादन होने लगा, परम्परागत उद्योग-धन्धे विनाश की ओर अग्रसर होने लगे तथा नए उद्योग पनपने लगे.

भारतीय मूल के उद्योगों के नष्ट होने से यहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराने लगी और 'सोने की चिड़िया' कहा जाने वाला देश अभावग्रस्त देश में परिणित होने लगा. अंग्रेजों से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी. कई प्रमुख शहर, बन्दरगाह तथा उद्योग-धन्धे विकसित थे, परन्तु अधिकतर लोग कृषि तथा ग्रामीण उद्योग-धन्धों पर ही आश्रित थे. भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में पूर्णरूपेण सुदृढ़ थी. कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, धातुओं के बर्तन, कृषि-यंत्र तथा अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खपत गाँवों में अथवा आसपास के बाजारों में ही हो जाती थी. इसके अलावा भारत के प्रमुख शहरों में भी इनकी खपत पर्याप्त थी. इतना ही नहीं यहाँ के माल की माँग विदेशों में भी थी. व्यापार करने की दृष्टि से पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों ने अपने-अपने केन्द्र यहाँ पर स्थापित किए और अंग्रेजों ने अपनी योजना में आशातीत सफलता प्राप्त की.

भारत का आर्थिक शोषण किया जाने लगा. आर्थिक शोषण के सहारे अंग्रेजों ने पर्याप्त धन जुटा लिया. भारत के अधिकतर भाग के अधिकतर संसाधनों पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया. उनके इस एकाधिपत्य का सबसे बुरा प्रभाव बंगाल के बुनकरों पर पड़ा. जो श्रमिक वस्त्र उद्योग से जुड़े थे, उन्हें कम कीमत पर ही कम्पनी में काम करने को विवश किया जाने लगा. देशी उद्योगपतियों के यहाँ उन्हें काम करने से रोका जाने लगा, आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाने लगा. अंग्रेजों की शोषण की नीति का सबसे अधिक यह प्रभाव पड़ा कि "भारतीय सम्पदा का निष्कासन" होने लगा.

सम्पदा का अपवाह—भारत का धन विभिन्न प्रकार से विदेशों में भेजा जाने लगा, जिसे सम्पदा का अपवाह अथवा सम्पदा का निष्कासन कहा जाता है. 1757 ई. से पूर्व अंग्रेज तथा यूरोपीय व्यापारी विदेशों से धन भारत में लाते थे. इसकी वजह यह थी प्लासी विजय से पूर्व यूरोप में भारतीय सामान की माँग अत्यधिक थी, विशेषकर सूती तथा रेशमी वस्त्रों की. यूरोप के व्यापारी बाहर से धन लाकर इन वस्तुओं को खरीदते थे और विदेशी बाजारों में उच्च मुनाफे पर बेचते थे, परन्तु बंगाल में कम्पनी की स्थापना से स्थिति बदल गई, परिणामस्वरूप विदेशों से धन आने के बदले यहाँ से ही धन विदेशों में जाने लगा जिसे सम्पदा का अपवाह कहा गया.

धन निष्कासन या सम्पत्ति पलायन सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने किया. 2 मई, 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इण्डिया कम्पनी एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख "इंग्लैण्ड डैब्ट टू इण्डिया" (England debt to India) में इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की सम्पदा को उस देश से छीन रहा है. भारत में वसूल किए गए कुल

राजस्व का लगभग एक चौथाई भाग देश से बाहर चला जाता है. जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे ने भी धन सम्पदा निष्कासन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यह स्थिति भारत के हित में नहीं है और कटु शब्दों में उसकी आलोचना की. प्रसिद्ध लेखक आर. सी. दत्त ने कहा है कि इंग्लैण्ड को प्रतिवर्ष अपने स्वयं का धन चाहे वह आधा ही हो, यदि बाहर भेजना पड़े, तो इंग्लैण्ड में वर्षों पूर्व ही अकाल पड़ गया होता. वे कहते हैं कि अंग्रेजों को विश्व में अनेक प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए कई मिलियन पौण्ड खर्च करने पड़े, परन्तु भारत पर कब्जा करने के नाम पर उनका एक शिलिंग भी खर्च नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ भारतीय लोगों के मूल्य पर ही किया गया. भारत से आर्थिक साधनों का निष्कासन अंग्रेजों के लिए वरदान सिद्ध हुआ.

धन निष्कासन का स्वरूप–जो धन भारत से इंग्लैण्ड को भेजा जाता था और जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, उसे ही सम्पदा का निष्पादन कहा गया. प्राप्त होने वाले भारतीय धन से अंग्रेज व्यापारी माल खरीदते और इंग्लैण्ड तथा अन्य स्थानों पर बेचते थे. इस प्रकार अंग्रेज दोनों प्रकार से धन प्राप्त कर रहे थे. भारत से धन का निष्कासन 1757 ईस्वी में बंगाल से प्रारम्भ हुआ. एक अनुमान के आधार पर 1757-65 ई. के मध्य करीब 60 लाख पौण्ड की रकम इंग्लैण्ड ले जाई गई थी. कम्पनी को व्यापार के तहत प्राप्त मुनाफा इसके अतिरिक्त था. 1765 ई. में बंगाल की दीवानी प्राप्त होने से कम्पनी को अतिरिक्त धन प्राप्त करने का स्रोत हाथ लग गया. अंग्रेजों को जो धन बंगाल से प्राप्त होता था उसे अंग्रेज लोग निवेश पद्धति से इंग्लैण्ड भेज देते थे. निवेश पद्धति के अलावा अंग्रेजों के पास अन्य कई रास्ते भी थे, जिनके मार्फत माल इंग्लैण्ड भेजा जाता था. बंगाल के नवाबों, उनके अधिकारियों, जमींदारों, व्यापारियों, जनता से कर वसूली के रूप में, गृह-प्रभार, सार्वजनिक भारतीय ऋण का व्यय, सुरक्षा व्यवस्था पर सैनिकों पर किया गया खर्च आदि मदों के रूप में पर्याप्त मात्रा में अंग्रेज लोग धन वसूलते थे. इसके अलावा रेलों, बैंकों, उद्योगों के मार्फत भी भारत का धन इंग्लैण्ड में जाने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन कमजोर होती चली गई. इसके बारे में मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि "हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की भाँति है, जिसके जरिये गंगा तट से सारी अच्छी चीजों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे निचोड़ दिया जाता है. भारत से कितना धन इंग्लैण्ड पहुँचा इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना कठिन है. इस बारे में अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग विचार हैं. जॉर्ज विगनेर के अनुसार 1834-51 ई. के समयांतराल के मध्य प्रतिवर्ष 4221611 पौंड प्रतिवर्ष के हिसाब से धन इंग्लैण्ड भेजा जाता था. इसी क्रम में विद्वान् डिग्वी का मानना है कि 1757-1815 ई. तक करीब 10 करोड़ पौंड इंग्लैण्ड पहुँच चुके थे. आर. सी. दत्त के अनुसार 1833-92 ई. के मध्य यह राशि 359 करोड़ थी, जबकि अन्य एक अनुमान के आधार पर 1860-1900 के मध्य प्रतिवर्ष की दर से 40 करोड़ रुपए भेजे गए. कुल मिलाकर अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार धन निर्गमन से भारत की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा.

धन निर्गमन का दुष्प्रभाव–अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई इस धन निर्गमन प्रणाली से भारत का आर्थिक ढाँचा पूर्णरूपेण खोखला हो चुका था. लोगों का जीवनस्तर गिर चुका था. उद्योग धन्धे नष्ट प्रायः हो चुके थे. कई बार अकाल पड़े जिनमें लाखों व्यक्तियों की जान गई. अनेक विद्वानों की मान्यता है कि 19वीं शताब्दी के अन्तिम दौर में पड़े अकालों की संख्या पिछले सौ वर्षों में पड़े अकालों से भी चार गुना अधिक थी. लोगों की कृषि पर निर्भरता का अनुपात बढ़ता गया. भूमिहीन श्रमिकों की बाढ़-सी आ गई. बंगाल की लूट और तत्जनित अकाल का विवरण देते हुए रजनीपाम दत्त ने लिखा है कि लूट से होने वाली आय को दिनों-दिन तेजी के साथ बढ़ाने की माँग की जाती थी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों के पास बीज के लिए रखा गया अनाज और उनके बैलों को छीन लिया जाता था. किसान पर्याप्त मात्रा में अपने पशुओं के लिए चारा तक उपलब्ध नहीं करा पाते थे. वी. जी. काले के अनुसार अन्य देशों की तुलना में पशुओं की संख्या अत्यन्त कम होने के कारण यहाँ गरीबी बढ़ गई और इसका मुख्य कारण था "भू-राजस्व की अधिकता". दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन की प्रवृत्ति को, 'अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने' की संज्ञा दी.

भू-राजस्व व्यवस्था–अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ करने के लिए भू-राजस्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए. अधिक-से-अधिक राजस्व प्राप्त करना ही उनका मूल उद्देश्य था. इसलिए उन्होंने भू-राजस्व व्यवस्था में कई परिवर्तन किए. दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद कम्पनी ने अपने को बंगाल-बिहार का भू-स्वामी समझा तथापि लगान वसूल करने का कार्य बंगाल के डिप्टी दीवान के पास रहने दिया. अधिक-से-अधिक धन प्राप्ति के लिए अंग्रेजों ने जो भू-राजस्व व्यवस्था का निर्धारण किया था, उसको सही ढंग से चलाने तथा अधिकाधिक लाभ कमाने की दृष्टि से जो राजस्व प्राप्ति के साधन बनाए, वे निम्नलिखित थे–

सार्वजनिक ऋण–साम्राज्य विस्तार के लिए कम्पनी द्वारा किए गए युद्धों तथा अन्य व्यय के लिए इंग्लैण्ड सरकार से भारत द्वारा समय-समय पर लिए गए ऋणों पर बड़ी तादाद में ब्याज की राशि वसूल की. 1792 ई. में यह ऋण ब्याज के

साथ 70 लाख, 1799 में एक करोड़ तथा 1857 में बढ़कर 6·90 करोड़ हो गया. ऋण की राशि बढ़ते-बढ़ते 1900 में 22·40 करोड़ पौण्ड तथा 1913 तक 27·40 करोड़ पौंड तक पहुँच गई तथा 1939 तक यह ऋण राशि 88·42 करोड़ तक पहुँच गई थी.

1858 ई. के बाद कम्पनी सरकार के स्थान पर इंग्लैण्ड सरकार का आधिपत्य हो जाने पर कम्पनी पर चढ़ा हुआ ऋण भारत पर ऋण हो गया और कम्पनी की देनदारी भारत सरकार के नाम लिख दी गई. सेवामुक्त अंग्रेज अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन की अदायगी भी कम्पनी सरकार को करनी होती थी. हिस्सेदारों को दिया जाने वाला लाभांश एवं लंदन प्रतिष्ठान का समस्त व्यय भारत सरकार से वसूल किया जाता था. 1858 ई. के बाद कम्पनी के हिस्सेदारों को दिया जाने वाला मुआवजा भी नई सरकार पर मढ़ दिया गया.

स्थायी बन्दोबस्त—जब लॉर्ड क्लाइव को दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनने का मौका मिला तो उसने लगान वसूली का कार्य भारतीय पदाधिकारियों के जिम्मे छोड़ दिया, परन्तु वास्तविक नियन्त्रण कम्पनी का ही था. इस व्यवस्था से जहाँ कम्पनी की आमदनी बढ़ी, वहीं भारतीय किसानों तथा यहाँ की कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. नई व्यवस्था के तहत सबसे अधिक लगान देने वाले को जमीन ठेके पर देने की व्यवस्था की गई. यह व्यवस्था भी कोई खास कारगर सिद्ध नहीं हो पाई. इससे कम्पनी के राजस्व में कमी आई. 1786 ई. में कार्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया. उसने कम्पनी के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए एक योजना 1790 ई. में शुरू की, जिसे स्थायी बन्दोबस्त के नाम से जाना जाने लगा. इस योजना के अन्तर्गत यह प्रावधान था कि जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में स्वीकृत कर निश्चित अवधि के लिए, निश्चित लगान के बदले उन्हें जमीन दे दी जाए. इस व्यवस्था के मद्देनजर उसने बंगाल के जमींदारों के साथ 'दस साला' प्रबन्ध किया. 1793 ई. में इस व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया गया. नई व्यवस्था के कारण जमींदारों को भूमि पर मालिकाना हक मिला. इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि किसान मात्र रैयत के रूप में जमींदारों पर आश्रित हो गए. जमीन पर जमींदारों का पैतृक अधिकार हो गया. किसानों के भूमि सम्बन्धी तथा अन्य पैतृक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया. जमींदारों के लिए आवश्यक कर दिया गया कि वे निश्चित समय के अन्दर तय किए गए लगान का 10/11 हिस्सा कम्पनी के कोष में जमा कराएं तथा 1/11 भाग लगान वसूली में होने वाले खर्चे के लिए रख लें. यह सख्त आदेश थे कि फसल हो या नहीं निर्धारित हिस्सा अथवा राशि प्रतिवर्ष कम्पनी कोष में जमा करानी ही होगी.

स्थायी बन्दोबस्ती व्यवस्था कम्पनी तथा जमींदारों के लिए वरदान सिद्ध हुई, जबकि किसानों के लिए यह एक तरह से कहर ढाने वाली व्यवस्था थी. कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर यह व्यवस्था लागू की गई थी. पहले यह बंगाल तथा बिहार में लागू की गई, तत्पश्चात् उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिलों तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लागू किया गया.

स्थायी व्यवस्था से लाभ—मार्शमैन ने इस व्यवस्था को साहस, बहादुरी तथा बुद्धिमानी का कार्य बताया है. उसके कथनानुसार इस व्यवस्था के वृद्धिजनक प्रभाव के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई, कृषि का विस्तार हुआ, लोगों की आदतों में सुधार का गुण देखने में आया. कुछ अच्छे प्रभाव निम्नलिखित थे, जो इस बन्दोबस्ती व्यवस्था के फलस्वरूप दृष्टिगत हुए.

बंगाल की स्थिति में सुधार—बंगाल के किसानों को यह विश्वास हो गया कि एक निश्चित राशि जमा कराते रहने से भूमि पर उनका मालिकाना हक बना रहेगा, फलतः किसानों ने खेती पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया. कृषि उत्पादन अच्छा होने से आर्थिक सम्पन्नता आने लगी. बंगाल एक सम्पन्न प्रदेश बन गया. सम्पन्नता के कारण शिक्षा व साहित्य का आशातीत विकास हुआ.

कम्पनी को आर्थिक लाभ—बन्दोबस्ती की व्यवस्था से कम्पनी को सबसे अधिक लाभ हुआ. उसकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन मजबूत होती गई. उसके समक्ष आर्थिक अनिश्चिता की स्थिति खत्म हो गई. लगान वसूली की निश्चित व्यवस्था से लगान वसूल करने में होने वाला अपव्यय भी समाप्त हो गया. कम्पनी के वे कर्मचारी जो लगान वसूली में नियुक्त थे, उन्हें अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगाया गया, जिससे कम्पनी की कार्यशैली में और अधिक गतिशीलता आई.

नए जमींदार वर्ग का उदय—नए जमींदारों के वर्ग को पैदा करने में इस बन्दोबस्ती व्यवस्था का प्रमुख हाथ रहा. यह वर्ग नई भू-व्यवस्था पर आश्रित था. जो वर्ग सुविधा सम्पन्न था वह अंग्रेजों का सहयोगी बन गया. अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसने भारतीय जनता के मध्य 'प्रतिरोधक' की भूमिका निभाकर सदैव अंग्रेजों का समर्थन किया. इस वर्ग ने स्वाधीनता संग्राम में भी अंग्रेजी हितों की रक्षा की.

जमींदारों को लाभ—जमींदारों को इस व्यवस्था से सुदृढ़ लाभ प्राप्त हुआ. सबसे मुख्य बात तो यह रही कि अब जमीन पर उनका पैतृक स्वामित्व स्थापित हो गया. इससे उत्तरोत्तर उनकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती चली गई. लगान से वसूले जाने वाले धन का एक हिस्सा उन्हीं के अधिकार में चला गया.

कृषि का विकास–आवश्यक रूप से लगान देने की परम्परा ने किसानों में कृषि के प्रति और अधिक लगाव पैदा किया, फलतः वे कृषि की ओर ध्यान अधिक देने लगे. वे अधिक-से-अधिक पैदावार बढ़ाने के उपक्रम करने लगे. जितनी अधिक फसल होगी उतना ही लाभ होगा. इससे प्रभावित होकर उन्होंने बंजर भूमि को भी उपयोग में लाना शुरू कर दिया. अतः वर्ष प्रतिवर्ष फसल की बढ़ोत्तरी होने लगी.

स्थायी बन्दोबस्ती व्यवस्था के दोष–स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था से जहाँ कई लाभ हुए, वहीं कुछ पहलुओं को लेकर इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने में आए.

कम्पनी को आर्थिक घाटा–स्थायी प्रबन्ध द्वारा वित्तीय दृष्टिकोण से ब्रिटिश सरकार को दीर्घकालीन घाटा ही हुआ, क्योंकि लगान की राशि तय करते समय जमीन की सही नाप या जाँच-पड़ताल नहीं की गई थी. भूमि तथा उत्पादन के भावी मूल्य बढ़ने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया. अतः बाद में जमींदारों की आमदनी तो बढ़ी, परन्तु कम्पनी के लिए विशेष लाभ नहीं हुआ. उदाहरण के लिए 1901 ई. में जमींदार किसानों से जो ऋण वसूलता था, उसका सिर्फ 28% प्रतिशत सरकार को मिलता था, शेष पर जमींदार का अधिकार होता था.

जमींदारों पर प्रभाव–स्थायी बन्दोबस्त ने एक सुविधाभोगी वर्ग 'जमींदार' को जन्म दिया. भले ही इनका कृषि से कोई सम्बन्ध नहीं था, परन्तु फिर भी उन्हें भूमि का मालिक बना दिया गया. वे स्वयं तो 'सरकारी रैयत' बन गए और किसान जमींदारों के रैयत. उनका एकमात्र ध्येय किसानों का शोषण करना था. भोग-विलास की इच्छा से व सुविधाभोगी जीवन बिताने के उद्देश्य से बहुत से जमींदार शहरों की तरफ पलायन कर गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अनेक जमींदार अपनी जमींदारियों का उचित प्रबन्ध नहीं कर सके, लगान वसूली का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो सका. अतः अनेक जमीदारों की जमींदारियों को नीलाम कर दिया. अनेक बहुत से पुराने जमींदार समाप्त हो गए और नए जमींदारों को जमीन मिली.

किसानों पर दुष्प्रभाव–किसानों को जमीदारों के अत्याचारों को सहन करना पड़ता था. भूमि से उनका स्वामित्व हट गया. उनके परम्परागत अधिकार जैसे–सार्वजनिक चरागाह, जंगलात तथा मछली-पालन आदि छीन लिए गए. उन्हें जमींदारों के यहाँ नजराना तथा भेंट आदि पहुँचाना पड़ता था.

सामाजिक विभेद में बढ़ोत्तरी–इस व्यवस्था ने समाज में दो वर्गों को जन्म दिया. एक निम्न वर्ग एवं एक उच्च वर्ग. निम्न वर्ग में किसान आते थे और उच्च वर्ग में जमींदार आते थे. इससे सामाजिक विभेद की खाई बढ़ती गई. आपसी वैमनस्य भी बढ़ता गया. जमींदार वर्ग हमेशा ही अंग्रेजों का हिमायती बना रहा और स्वतन्त्रता आन्दोलन में बाधक बनता रहा.

स्थायी बन्दोबस्त की तरह ही देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न भू-राजस्व प्रणालियाँ लागू की गई थीं. जैसे–अवध तथा मध्य भारत के कुछ क्षेत्र में "अस्थायी जमींदारी बन्दोबस्ती" की व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ, वहीं दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भारत में "रैयतवाड़ी व्यवस्था" तथा गंगा घाटी, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों, मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों और पंजाब में "महालवाड़ी" व्यवस्था लागू की गई. एक अनुमान के आधार पर समस्त भारत की भूमि का 19% स्थायी बन्दोबस्त के अधीन, 30% महालवाड़ी और 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्तर्गत रखा गया.

रैयतवाड़ी व्यवस्था–"रैयत" का अर्थ प्रजा या सामान्य किसान से लगाया जाता है. वी. जी. काले के अनुसार जिसके पास दो बैल, हल और एक गाड़ी होती है और जिसे वह फालतू समय में किराये पर ढुलाई के काम में लेता है "रैयत" कहलाता है. किसानों के साथ जो समझौता लगान के सम्बन्ध में किया गया उसे "रैयतवाड़ी" कहा गया.

भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना 1812 ई. में हुई. रैयतवाड़ी के बारे में रजनीपामदत्त ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है–इस बन्दोवस्त की खास बात यह थी कि सरकार को किसानों के साथ सीधे-सीधे कोई बन्दोबस्त करना चाहिए जो स्थायी न हो अर्थात् जिसमें हमेशा कुछ वर्षों के बाद संशोधन किया जा सके. इस प्रकार लूट के धन को किसी बिचौलिए में बाँटने के बजाय स्वयं ही पूरा हड़प लिया जाए. सबसे पहले रैयतवाड़ी प्रथा की शुरूआत मद्रास में हुई. मद्रास में यह व्यवस्था 1820 ई. में तथा 1825 ई. में मुम्बई में लागू की गई. 1854 ई. में पहला भूमि संगठन कानून बनाया गया एवं 1867 तथा 1887 ई. के कानूनों के तहत पंजाबी किसानों को चिरस्थायी काश्तकारों के रूप में मान्यता दी गई. इसके आधार पर उन्हें अपनी भूमि बेचने, गिरवी रखने तथा उपपट्टे रखने का अधिकार था.

रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख उपबंध–(1) प्रत्येक रैयत बिना किसी पारस्परिक गारण्टी के व्यक्तिगत रूप से कर देने योग्य था.

(2) राजकीय अधिकारियों एवं लघु उत्पादकों के मध्य बिचौलिये की भूमिका खत्म हो गई अर्थात् सरकार ही सारा लगान वसूल करती थी.

(3) रैयतवाड़ी प्रथा का मुख्य बिन्दु यह था कि भूमि का पट्टेदार जब चाहे उचित समय नोटिस देकर जो भूमि उसके पट्टे पर थी, उसे या उसके किसी भाग को छोड़ सकता था और इस प्रकार सरकारी मालगुजारी अदा करने के दायित्व से बच जाता था.

(4) लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी.

(5) भू-राजस्व दरों की समय-समय पर (30 वर्षों के बाद) पुनर्समीक्षा होती थी.

(6) लगान भूमि के मूल्य के आधार पर तय किया जाए न कि उसमें पैदा होने वाली फसल के आधार पर.

रैयतवाड़ी व्यवस्था के परिणाम–यह प्रणाली भी किसानों के लिए घाटे का सौदा ही साबित हुई. बम्बई और मद्रास प्रेसीडेंसियों में, जहाँ यह लागू की गई, वहाँ भी इसके दुष्परिणाम ही सामने आए. लगान की राशि इतनी अधिक रखी गई थी किसानों को लगान चुकाने के लिए जमींदारों से ऋण लेना पड़ता था. या तो उनकी जमीन विक गई या उन्हें गिरवी रखनी पड़ गई. अतः उनकी जमीन उनके हाथ से सदा के लिए निकल गई. लगान वसूल करने वाले यातनाएँ देकर भी लगान वसूल करने में नहीं हिचकते थे. सबसे बड़ी बात तो यह थी सरकार के हाथों में यह अधिकार हमेशा सुरक्षित रहा कि वह अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लगान की दर बढ़ा दे, जिससे जमींदारों का वर्ग नहीं पनप सका. दूसरा लाभ यह भी हुआ कि जमीन से सम्बन्धित अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार हो गया. जमीन अब व्यक्तिगत सम्पत्ति बन गई तथा यह हस्तांतरित होने वाली वस्तु हो गई, जिसके फलस्वरूप सामाजिक गतिशीलता में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हो गई.

महालवाड़ी व्यवस्था–'महाल' शब्द से तात्पर्य है "जागीर अथवा गाँव" या गाँव का समूह. इस पद्धति में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक गाँव या गाँव के समूह के साथ स्थापित की गई. इस पद्धति के अनुसार कोई एक व्यक्ति पूरे गाँव का मालिक नहीं होता था और न ही वह सरकारी भू-राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी था. हालांकि सुविधा के लिए ग्रामीण भूमि के भागीदारों में से प्रमुख को लंबरदार बना दिया गया और गाँव की ओर से उसे हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर दिया. इस प्रथा में गाँव के भागीदारों में संयुक्त रूप से मालिकाना अधिकार निहित होते थे. गाँव की समस्त भूमि के अतिरिक्त मूल्य को अधिकार मान लिया जाता था. महालवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने कृषकों से सीधा सम्पर्क नहीं किया, बल्कि एक नए वर्ग को मुखिया बनाया. ऐसा करते समय सरकार ने एक कृषक को अपनी भूमि के अधिकार बेचने अथवा उसकी जमानत पर ऋण लेने के अधिकार प्रदान कर दिए. किसानों को भूमि विक्रय का अधिकार मिलने का परिणाम यह हुआ कि साहूकारों ने ऋण के बदले किसानों को जमीन क्रय करना शुरू कर दिया. अवध क्षेत्र में यह प्रथा 1801 ई. में तथा मराठों के अधिकृत प्रदेशों में 1803-04 ई. में लागू की गई. पंजाब में जो व्यवस्था लागू की गई थी उसे संशोधित महालवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया. अवध और अन्य क्षेत्रों में शुरू में यह व्यवस्था 3-4 वर्षों के लिए लागू की गई. इस अवधि में वसूल होने वाली राशि में 25% की बढ़ोत्तरी की गई. 1807 और 1818 ई. के मध्य इस राशि में दुबारा बढ़ोत्तरी की गई जो 50% थी. महालवाड़ी प्रथा में मार्टिन बर्ड ने कुछ सुधार किए थे, इस कारण इसे बर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है. लगान की राशि 2/3 निश्चित की गई. यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए रखी गई थी. इस व्यवस्था में लगान की राशि 66 प्रतिशत रखी गई जो पहले की तुलना में बहुत अधिक थी. अतः 1855 ई. में लॉर्ड डलहौजी ने सहारनपुर नियम के अनुसार लगान की राशि 50% कर दी.

ब्रिटिश भूमि नीति के परिणाम–अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई भू-राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारी, महालवाड़ी एवं रैयतवाड़ी प्रथा के कुछ प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं–

जमीन को हस्तांतरणीय बनाना–इस व्यवस्था का प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि जमीन अब लेन-देन वाली वस्तु हो गई. लोग एक-दूसरे को जमीन बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे. इस व्यवस्था के अभाव में अंग्रेजों को लगान वसूलना कठिन हो जाता. इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह रही कि इससे भारतीय समाज छिन्न-भिन्न हो गया, संयुक्त परिवार टूट गए और मुकद्दमेबाजी शुरू हो गई.

भूमि, पूँजी-विनिमय का साधन–जमीन पर सरकार की ओर से मालिकाना हक मिलने के कारण लोगों का रुझान जमीन की ओर बढ़ा. चूँकि कुटीर-उद्योग नष्ट प्रायः होने के कगार पर थे. इसलिए साहूकारों ने अपना पैसा जमीन में ही लगाना उचित समझा. ऋण चुकाने के लिए किसानों को वे पैसा देने लगे. जब किसान ऋण अदा नहीं कर पाता था, तो महाजन उसकी भूमि नीलाम कराकर उस पर अपना कब्जा कर लेता था.

किसानों पर कर्ज बढ़ा–अत्यधिक शोषण होने के कारण किसान के पास पैदावार का बहुत ही कम अंश बच पाता था. आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास इतना भी धन नहीं बचता था कि उसे बेचकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके. उसे या तो कर्ज लेना पड़ता था अथवा अपनी जमीन को गिरवी रखना पड़ता था.

पैदावार में कमी–हस्तांतरणीय व्यवस्था के कारण जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटती चली गई. पुराने साधनों से भी जमीन को खेती के योग्य नहीं बनाया जा सका, जिसके कारण लगातार उत्पादन में कमी आती गई.

जमींदार वर्ग का उदय–स्थायी भूमि व्यवस्था की बदौलत समाज में शक्तिशाली तथा साधन सम्पन्न वर्ग का आविर्भाव हुआ, जिसे जमींदार कहा जाता था. जमींदार लोग सरकार और किसानों के मध्य बिचौलिए की भूमिका निभाते थे. इनको सरकार तथा किसानों दोनों की ओर से सुविधाएँ मुहैया कराई जाती थीं. इसका परिणाम यह हुआ कि यह वर्ग किसानों का शोषक और सरकार का समर्थक बन गया.

कृषि उत्पादनों का निर्यात–इंग्लैण्ड में कच्चे माल और खाद्यान्न की आवश्यकता थी. अतः अंग्रेजों ने ऐसी फसलों का उत्पादन अनिवार्य कर दिया, जिसकी इंग्लैण्ड में आवश्यकता थी. उस पर मनमाना शुल्क वसूल कर उसका निर्यात किया जाने लगा. इसके परिणामस्वरूप भारतीय मूल का अधिकतर माल विदेशों में ही खपने लगा.

उद्योगों का विनाश–औपनिवेशक काल में भारतीय उद्योगों का जमकर शोषण हुआ, जिससे वे विनाश के कगार पर पहुँच गए. यहाँ के उद्योगों का विनाश इंग्लैण्ड के उद्योगों के विकास के साथ जुड़ा था. भारत के कृषि उत्पादनों एवं अन्य खनिजों से तैयार माल को दुबारा भारत के बाजारों में ही बिक्री के लिए लाया जाता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय उद्योग-धन्धे चौपट होने की स्थिति में आकर नष्ट हो गए. भारतीय माल की कीमतें विदेशी माल की तुलना में 50 से 60 प्रतिशत तक बनी रहीं. इसलिए अपने माल के अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए ब्रिटेन ने अपने विजित प्रतियोगियों के उत्पादनों का विनाश करने के विचार से अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया. भारतीय माल के आयात पर इतना अधिक शुल्क लगा दिया गया कि उसका आयात ही न हो सके. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय उत्पादकों पर अत्यधिक भार डाल दिया गया.

कृषि का वाणिज्यीकरण–भारत में कृषि ही सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का आधार थी. अधिकतर लोग गाँवों में ही निवास करते थे. सारा गाँव, जमीन का मालिक होता था. ग्राम पंचायत गाँव की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करती थी. जोत खण्डों के रूप में जमीन को किसान परिवारों में बाँट देती थी. परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से प्रत्येक खण्ड जोत में खेती होती थी. मार्क्स के शब्दों में "गाँव में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता था, उनका विनिमय गाँव की जनता तक ही सीमित था. किसान फसल उगाते थे, दूसरे कारीगर जैसे लुहार, बढ़ई, चमड़े का काम करने वाले, बुनकर आदि अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण करते थे. इस तरह गाँव के लगभग सम्पूर्ण उत्पादन का उपयोग गाँव की जनता ही करती थी. सभी एक-दूसरे के पूरक थे.

औपनिवेशक सरकार की कृषि नीति ही नहीं, अपितु औद्योगिक नीति भी कृषि की दुर्गति करने के लिए जिम्मेदार थी. 1813 ई. के बाद भारत में कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई. भारत ब्रिटिश सरकार के लिए एक अच्छा व्यापार मार्केट बन गया. साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के अनुरूप अंग्रेज सरकार भारतीय कृषकों को अधिकाधिक भूमि पर कृषि करने, अधिक उपज प्राप्त करने तथा विविध नकद फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित करती थी, जिससे कृषि द्वारा सरकार को समय-समय पर बढ़ाए जाने वाला भू-राजस्व प्राप्त होता रहे तथा नकद फसलों के निर्यात का लाभ मिलता रहे. दूसरी ओर किसान भी भारत में पूँजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ-साथ नए भूमि सम्बन्धों व लगान के कारण पूँजी की आवश्यकता रखते थे, इसलिए किसान भी अब उन फसलों को उगाने के लिए मजबूर होने लगा जिनका बाजार में क्रय-विक्रय हो सके. कृषि क्षेत्र में आए इस परिवर्तन को ही "कृषि का वाणिज्यीकरण" कहा जाता है. सरकार ने अनेक उपायों द्वारा भारतीय किसानों को कृषि के वाणिज्यीकरण की ओर अधिक-से-अधिक उन्मुख किया. अंग्रेज सरकार के द्वारा भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की स्थापना करके हस्तशिल्प का ह्रास किया गया. सरकार द्वारा अपनी समृद्धि के लिए शुरू की गई रैयतवाड़ी तथा महलावाड़ी प्रथा ने भी लोगों को कृषि के प्रति आकर्षित किया. जमींदारी प्रथा के द्वारा भी कृषि का वाणिज्यीकरण तेजी के साथ हुआ. भारत में आवागमन के साधनों का विकास, अधिक भू-राजस्व व्यवस्था तथा विदेशी माल के आयात के कारण भारतीयों का मन कृषि करने के प्रति पहले की अपेक्षा अधिक हुआ. हालांकि भारतीयों को इसे अपनाना मजबूरी था, क्योंकि भारतीय उद्योग-धन्धे विदेशी आयात नीति के कारण नष्ट प्रायः हो चुके थे और भारतीयों को कृषि की ओर ध्यान देने के अलावा अन्य कोई चारा भी नहीं था. अंग्रेजों की नीति ने भारतीयों के उद्योग-धन्धों को नष्ट करके उन्हें पंगु बना दिया. जब वे कृषि नीति पर पूर्णतः आश्रित हो गए तो उन्होंने कृषि व्यवस्था को भी अपनी नीतियों से पूर्णतः प्रभावित किया. इस प्रभाव से वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की प्रवृत्ति बढ़ी, क्योंकि भू-राजस्व का भुगतान तथा साहूकारों के ऋण की अदायगी अधिक पैदावार देने वाली तथा विक्रय करने पर अधिक लाभ देने वाली फसलों की पैदावार से ही सम्भव थी. 1895 से लेकर 1914 ई. तक समस्त औद्योगिक फसलों वाले बुवाई क्षेत्र में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कपास के क्षेत्र में 63%, जूट में 38%, अनाज के क्षेत्र में 37·4 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा, परिणामतया औद्योगिक फसलों में और विश्व व्यापार में उनके निर्यात में वृद्धि हुई. जहाँ पहले गेहूँ बोया जाता था, वहाँ अब कपास (पंजाब, बम्बई), जूट (बंगाल), नील (बंगाल), अफीम (बिहार), चाय (असम) में बोया गया. ऐसे क्षेत्र जहाँ अनाज की फसलें प्रमुख थीं, वहाँ गन्ना, तिलहन आदि पैदा होने लगा. वाणिज्यीकरण के कारण किसान धीरे-धीरे (मध्यस्थ) व्यापारियों पर निर्भर हो गए. अपनी बेहतर माली स्थिति के कारण व्यापारियों ने किसानों की गरीबी का पूरा फायदा उठाया.

भारत में रेलवे–ब्रिटिश शासकों के लिए यह आवश्यक था कि वे अपने संचार साधनों में अधिक-से-अधिक वृद्धि करें, तभी उनको व्यापार का पूरा फायदा मिलता. इस आवश्यकता के मद्देनजर डलहौजी ने सड़कों के निर्माण पर बल दिया.

इस दिशा में उसका प्रमुख कदम भारत में रेलवे की सुविधा शुरू करना था. उसने 1853 ई. में अपने रेलवे पत्र के माध्यम से रेलवे विकास की योजना बनाई. रेल बनाने तथा उन्हें चलाने की जिम्मेदारी निजी कम्पनियों को सौंपी गई, जिनकी पूँजी पर भारतीय सरकार ने कम-से-कम 5% लाभ देने की गारण्टी ली. डलहौजी की योजना चार मुख्य लाइन बनाकर सम्पूर्ण देश को एक-दूसरे भागों से जोड़ने एवं महत्वपूर्ण बन्दरगाहों से जोड़ने की थी. 1853 ई. में बम्बई से थाणे तक प्रथम रेलगाड़ी यातायात के लिए शुरू की गई. गारण्टी पद्धति पर शुरू की गई यह रेल लाइन बहुत खर्चीली सिद्ध हुई. भारत में रेल निर्माण पर औसत खर्चा 20-30 हजार पौंड प्रति मील था. यह खर्चा इंग्लैण्ड में केवल 9000 पौंड था. इसका कारण निजी कम्पनियों द्वारा लगाए गए धन पर उन्हें मुनाफे की गारण्टी थी, वे इस व्यवस्था का बिल्कुल अमानवीय तथा नाजायज लाभ उठाते थे. 1869 ई. तक भारत में 4000 मील लम्बी रेलवे बनाई गई.

1869 ई. को भारत सरकार की रेल निर्माण नीति में परिवर्तन किए गए. इस नीति का मुख्य मकसद खर्च में कमी लाना था. अतः रेलों का निर्माण राजकीय उद्योग के रूप में आरम्भ हुआ. इसके बाद भी रेलों का विकास तीव्र गति से नहीं हो पाया. इस कारण से ब्रितानी अधिकारी और व्यवसायी सरकारी नीतियों से असंतुष्ट थे. अतः 1880 ई. से पुनः इसका निर्माण और रखरखाव निजी कम्पनियों को सौंपा गया. रेल निर्माण सरकारी उद्योग के रूप में भी हुआ. वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना करके लॉर्ड कर्जन ने रेल विभाग को इन्हीं के सुपुर्द कर दिया. इसी समय रेलवे बोर्ड का गठन भी किया गया. इन प्रयासों के बाद 1905 ई. तक करीब 28,000 मील लम्बी रेल लाइन का निर्माण सम्भव हो सका. अनेक बन्दरगाह तथा व्यापारिक केन्द्र आपस में जुड़ चुके थे.

भूमिहीन श्रमिकों की वृद्धि–ऋणग्रस्तता का परिणाम अंततोगत्वा यह हुआ कि खेतिहर वर्ग ने अपनी जमीन का हस्तांतरण गैर खेतिहर सूदखोर के नाम कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसे भूमिहीन सर्वहारा (मजदूर) वर्ग का उदय हुआ जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर था. इस प्रकार की व्यवस्था से खेती के उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि सूदखोर महाजन इस जमीन को ऐसी दर पर शिकमी चढ़ा देता था कि किसान को अच्छी फसल पैदा करने का कोई लाभ दिखाई नहीं देता था. ब्रिटिश सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़े हुए लगान का खेतिहर द्वारा नियमित रूप से भुगतान नहीं किए जाने पर जमीन नीलाम करा दी जाती थी. भू-राजस्व की अदायगी के लिए साहूकारों से लिए ऋण का भुगतान न किए जाने की स्थिति में साहूकार भी भूमि को नीलाम करवा देता था. इसका नतीजा यह हुआ कि खेतिहर के लिए दूसरों की जमीन पर श्रम द्वारा आजीविका चलाने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं बचा. इस प्रकार भू-राजस्व की माँग या साहूकारी ऋण का बोझ कृषि श्रमिकों की वृद्धि का कारण बना. ए. आर. देसाई ने लिखा था कि भारतीय किसानों की बेहद गरीबी और तज्जन्य ऋणग्रस्तता, अनार्थिक जोतों और आदिम तकनीक पर आधारित कृषि की उर्वरकशीलता में क्रमिक ह्रास इन सबके बड़े कारण थे. भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था मूलतः औपनिवेशक थी. यह तथ्य देश के मुख्य विकास में बाधक था. यही किसानों की गरीबी का मुख्य कारण भी थी. बंगाल-बिहार में स्थायी बन्दोबस्त से किसान भूमि के स्वामी नहीं रहे, दूसरी ओर जमींदार जो कभी स्वामी नहीं थे, स्वामी बना दिए गए. ये लोग किसानों का शोषण करने लगे. रैयतवाड़ी प्रथा लागू करने से किसानों की फसल का अधिकांश भाग लगान में चला जाता था. इस व्यवस्था से किसानों की हालत दिन-प्रतिदिन पतली होती गई. बड़ी तादाद में जमीनें नीलाम होने लगीं और किसान खेतों पर मजदूरी करने को बाध्य हो गए.

इसके अलावा भारत का दस्तकारी उद्योग के नष्ट होने से किसान एकदम पंगु हो गए. इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिक किसानों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई. स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विनाश से गाँवों में खटने वाले विविध कामगर दूसरों की जमीनों पर दैनिक मजदूरी अथवा बटाई पर कार्य कर अपनी आजीविका चलाने लगे. ब्रिटिश पूँजी, जिसने भारत में आंतरिक पूँजी के संचय को तथा कस्बे में राष्ट्रीय औद्योगिक पूँजीवाद एवं ग्रामीण क्षेत्र में पूँजीवादी फर्मों के विकास को रोक रखा था, ताकि खुद लंदन के पूँजीवादी विकास के हितों की रक्षा हो सके. माल अर्थव्यवस्था की वृद्धि, कम्यून का विध्वंस और किसानों की बर्बादी इस सबका उपयोग किया. भारत की गुजारे लायक अर्थव्यवस्था के विध्वंस पर आधारित उत्पादित शक्तियों की तीव्र वृद्धि खुद भारत में नहीं, बल्कि ब्रिटेन में हुई.

भूमिहीन किसानों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी. 1875 ई. में 80 लाख, 1901 ई. में 350 लाख, 1911 ई. में 500 लाख और 1921 ई. में 370 लाख भूमिहीन श्रमिक किसान हो गए. विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कृषि श्रमिकों की स्थिति के विषय में काले ने लिखा था–औसतन 100 कृषक अपने यहाँ 25 श्रमिकों को काम पर लगाते थे, किन्तु यह संख्या प्रमुख प्रांतों में भिन्न-भिन्न रही. असम में 2, पंजाब में 10, बंगाल में 12, संयुक्त प्रांत में 16, बर्मा में 17, बिहार व उड़ीसा में 33, मद्रास में 40, बम्बई में 41 तथा मध्य प्रांत एवं बरार में 59. जहाँ एक ओर, कृषि श्रमिकों की वृद्धि हो रही थी, वहीं दूसरी ओर, गैर काश्तकार जमींदारों की संख्या भी बढ़ती गई. 50 वर्षों में परजीवी लगान लेने वालों की संख्या 10 गुना बढ़ी.

स्मरणीय तथ्य

- अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय सम्पदा का निष्क्रमण होने लगा.
- अंग्रेजों के आने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आश्रित थी.
- भारत की सम्पदा भारत से बाहर विदेशों में जाने की प्रक्रिया को ही सम्पदा का निष्क्रमण अथवा सम्पदा का निष्पादन कहा जाता है.
- सम्पदा का निष्कासन 1757 ई. में शुरू हुआ.
- भारतीय सम्पदा का निष्कासन बंगाल से शुरू हुआ था.
- मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष के अनुसार, "हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह है, जिसके जरिये गंगा तट की अच्छी चीजों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे निचोड़ दिया जाता है.
- किसानों का स्तर दिन-पर-दिन गिरने लगा था, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों का मुख्य उद्देश्य अपना आर्थिक विकास करना तो था ही, साथ ही भारतीय किसानों का शोषण भी था.
- 1913 ई. तक 27·40 करोड़ की राशि भारत से विदेशों में जा चुकी थी.
- 1786 ई. में कार्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया.
- कार्नवालिस ने कम्पनी की माली हालत सुधारने के लिए 1790 ई. में एक योजना शुरू की जिसको "स्थायी बन्दोबस्त" के नाम से जाना जाता है.
- स्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था को 1793 ई. में नया स्वरूप प्रदान किया गया.
- इसी व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि पर मालिकाना हक मिला.
- मार्शमैन ने इस व्यवस्था को साहस, बहादुरी तथा बुद्धिमानी का कार्य बताया.
- जनसंख्या वृद्धि में स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था का अहम् योगदान रहा.
- जमींदार वर्ग के उदय का कारण यही बन्दोबस्त व्यवस्था थी.
- अंग्रेजी सरकार से जमींदार वर्ग के स्वार्थ सिद्ध होते थे. अतः यह वर्ग किसानों का विरोधी और अंग्रेजों का शुभचिंतक था. जमींदार वर्ग ने किसानों तथा अंग्रेजी सरकार के मध्य प्रतिरोधक का कार्य किया.
- स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था लागू करने के समय किसानों से लगान प्राप्त करने के सम्बन्ध में भूमि की सही नाप-तौल नहीं की गई, जिससे कम्पनी को आर्थिक घाटा भी उठाना पड़ा.
- इस व्यवस्था के तहत अंग्रेज सरकार को लगान का 28% ही मिलता था.
- स्थायी बन्दोबस्ती से समाज दो वर्गों में बँट गया एक निम्न वर्ग तथा एक उच्च वर्ग.
- 1812 ई. में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरूआत हुई. रैयत का अर्थ सामान्य प्रजा अथवा किसान से लगाया जाता है, जिसके पास दो बैल, एक हल तथा गाड़ी होती है, जिसे वह फालतू समय में किराए पर चलाता है.
- 1854 ई. में पहला भूमि संगठन कानून बनाया गया.
- रैयतवाड़ी प्रथा का मुख्य बिन्दु यह था कि भूमि का पट्टेदार जब चाहे उचित समय नोटिस देकर भूमि के किसी भी भाग को छोड़ सकता था और इस प्रकार वह सरकारी मालगुजारी देने से बच जाता था.
- रैयतवाड़ी प्रथा ने भी किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर किया.
- 1801 ई. में महालवाड़ी प्रथा की शुरूआत हुई.
- "महाल" का तात्पर्य गाँव अथवा जागीर से लगाया जाता था.
- ब्रिटिश भूमि नीति के परिणामों से जमीन हस्तांतरित होने लगी थी.
- औपनिवेशक काल में भारतीय उद्योगों का जमकर शोषण हुआ.
- भारतीय किसान मूल खेती को छोड़कर अधिक पैसा देने वाली फसलों का उत्पादन अधिक करने लगे, जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा जाता था.
- वाणिज्यीकरण के कारण किसान व्यापारियों पर निर्भर हो गए.
- भारत में 1853 ई. में रेलवे पत्र के माध्यम से रेलवे के विकास की योजना बनाई गई.
- भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 ई. में बम्बई तथा थाणे के मध्य चली.
- भू-राजस्व की अनिर्वायता ने भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की.
- भूमिहीन कृषकों की संख्या 1911 ई. में 500 लाख थी.
- अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णरूपेण सुदृढ़ थी. यहाँ के कुटीर उद्योगों में निर्मित माल विदेशों तक में निर्यात होता था.

- अंग्रेजों के आधिपत्य का सबसे अधिक कुप्रभाव बंगाल के बुनकरों पर पड़ा. उनको कम कीमत पर अंग्रेजी कम्पनी में ही काम करने को राजी होना पड़ा.
- भारतीय सम्पदा का निष्कासन अंग्रेजों की शोषण नीति का ही परिणाम था.
- अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय धनराशि इंग्लैण्ड पहुँचाई जाती थी, उसके विभिन्न स्रोत थे, जैसे—लगान, बिक्री तथा वसूली. धन को भारत से बाहर जाने की यह प्रक्रिया धन का अपवाह कहा जाने लगा.
- धन निष्कासन के सिद्धान्त का प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने किया.
- प्रसिद्ध लेखक आर. सी. दत्ता का मानना है कि "अंग्रेजों को विश्व के अनेक देशों पर कब्जा करने के लिए कई मिलियन पौंड खर्च करने पड़े, परन्तु भारत पर कब्जा करने पर उनका एक शिलिंग भी नहीं खर्च हुआ."
- भारत से धन निष्कासन की प्रक्रिया 1757 ई. में शुरू हुई.
- जॉर्ज विगनेर के अनुसार 1834-51 ई. के मध्य प्रतिवर्ष 4221611 पौंड इंग्लैण्ड भेजे जाते थे.
- उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दौर में पड़े अकालों की संख्या पिछले सौ वर्षों में पड़े अकालों से भी चार गुना अधिक थी.
- भारत में गरीबी बढ़ाने के लिए भू-राजस्व व्यवस्था ही जिम्मेदार रही.
- दादाभाई नौरोजी ने "धन निष्कासन" की प्रवृत्ति को "खून चूसने" की संज्ञा दी थी.
- अंग्रेजी कम्पनी ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्था कायम की, जिसके आधार पर कम्पनी ने 1792 ई. में 70 लाख पौंड का ऋण ब्याज कमाया जोकि 1939 ई. तक बढ़ते-बढ़ते 88·42 करोड़ तक पहुँच चुकी थी.
- कम्पनी ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्था के साथ ही स्थायी बन्दोबस्त की भी व्यवस्था की जिसके तहत सबसे अधिक लगान देने वालों को ठेके पर जमीन देने की व्यवस्था की गई.
- स्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था 1790 ई. में कार्नवालिस द्वारा शुरू की गई.
- स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था में किसानों के लिए सख्त आदेश थे कि फसल हो या न हो प्रतिवर्ष निर्धारित राशि कम्पनी कोश में जमा करवानी होगी.
- स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था पहले बंगाल तथा बिहार में, तत्पश्चात् उड़ीसा, मद्रास तथा यू.पी. के बनारस जिले में लागू की गई.
- मार्श मैन के कथनानुसार इस व्यवस्था से जनसंख्या में वृद्धि, कृषि का विस्तार तथा लोगों की आदतों में सुधार आया.
- स्थायी बन्दोबस्ती से जमींदार वर्ग का उदय हुआ तथा उनका जमीन पर पैतृक अधिकार हो गया.
- किसानों का कृषि के प्रति अधिक झुकाव पैदा हुआ. समाज में विभेद की लकीर खिंच गई.
- एक अनुमान के आधार पर भारत की भूमि का 19% स्थाई बन्दोबस्त के अधीन, 30% महालवाड़ी व्यवस्था के अधीन और 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था के अधीन था.
- भारत में "रैयतवाड़ी" की स्थापना 1812 ई. में हुई.
- यह व्यवस्था मद्रास में 1820 ई. में तथा मुम्बई में 1825 ई. में शुरू की गई.
- 1887 ई. के कानूनों के तहत पंजाबी किसानों को चिरस्थायी काश्तकारों के रूप में मान्यता दी गई. इसके आधार पर उन्हें अपनी भूमि बेचने तथा गिरवी रखने का अधिकार था.
- भू-राजस्व दरों की समय-समय पर (30 वर्षों में) पुनर्समीक्षा होती थी.
- रैयतवाड़ी व्यवस्था से जमीन व्यक्तिगत सम्पत्ति बन गई तथा यह हस्तांतरित होने वाली वस्तु हो गई, जिसके फलस्वरूप सामाजिक गतिशीलता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई.
- महालवाड़ी प्रथा लागू करते समय सरकार ने कृषकों से सीधा सम्पर्क नहीं किया बल्कि एक नए वर्ग को मुखिया बनाया.
- अवध क्षेत्र में महालवाड़ी प्रथा 1801 ई. में लागू की गई.
- हस्तांतरणीय व्यवस्था से जमीन छोटे-छोटे भूखण्डों में परिवर्तित हो गई.
- भारतीय कृषि उत्पादनों एवं अन्य खनिजों से तैयार माल को दुबारा भारत में ही बिक्री के लिए लाया जाता था, जिससे यहाँ के उद्योग-धन्धे चौपट हो गए.
- 1813 ई. के बाद कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया.
- आवागमन के साधनों के विकास, अधिक भू-राजस्व व्यवस्था तथा विदेशी माल के आयात के कारण किसानों का कृषि के प्रति रुझान अधिक बढ़ा.
- 1869 ई. तक भारत में 4000 मील लम्बी रेल लाइन बनाई जा चुकी थी.

- 1869 ई. में इस रेल निर्माण नीति में परिवर्तन किए गए जिनका उद्देश्य खर्च में कमी लाना था.
- इस अवधि में रेलों का निर्माण राजकीय उद्योग के रूप में हुआ.
- 1880 ई. में रेलों के निर्माण की व्यवस्था पुनः कम्पनी के हाथों में सौंपी गई.
- 1905 ई. तक करीब 28,000 मील लम्बी रेल लाइन का निर्माण किया जा चुका था.
- भू-राजस्व की माँग तथा साहूकारी ऋण का बोझ भूमिहीन श्रमिकों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण रहा.
- 1875 ई. में जहाँ भूमिहीन श्रमिकों की संख्या 80 लाख थी, वह बढ़कर 1911 ई. में 500 लाख हो गई.

विशिष्ट स्मरणीय तथ्य

विभिन्न व्यापारिक कारखानों की स्थापना एवं वर्ष

क्र. सं.	स्थल	वर्ष
1.	मसूलीपट्टनम	1605 ई.
2.	पुलिकट	1610 ई.
3.	सूरत	1616 ई.
4.	विमलीपट्टम	1641 ई.
5.	कारिकल	1645 ई.
6.	चिनसूरा	1653 ई.
7.	कासिम बाजार, पटना नागपट्टम, बालासोर	1658 ई.
8.	कोचीन	1663 ई.
9.	पुलिकट	1890 ई.

अवध के नवाब एवं उनका कालचक्र

क्र. सं.	नवाब	कालचक्र
1.	सादात खाँ बुरहान मुल्क	1722-39 ई.
2.	सफदरजंग	1739-54 ई.
3.	शुजाउद्दौला	1754-75 ई.
4.	आसुफुद्दौला	1775-97 ई.
5.	वजीरअली	1797-98 ई.
6.	सआदत अली खान	1798-1814 ई.
7.	हैदर अली खान	1824-27 ई.
8.	नासिरउद्दीन	1827-37 ई.
9.	मुहम्मद अली	1837-42 ई.
10.	अमजद अली	1842-47 ई.
11.	वाजिद अली शाह	1847-50 ई.

प्रमुख युद्ध एवं उनका कालचक्र

क्र. सं.	युद्ध	कालचक्र
1.	घेरिया का युद्ध	10 अप्रैल, 1740 ई.
2.	शकूरखेड़ा का युद्ध	1724 ई.
3.	प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध	1845-46 ई.
4.	प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध	1767-69 ई.
5.	द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध	1780-84 ई.
6.	तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध	1790-92 ई.
7.	चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध	1799 ई.

सन् 1765 से 70 के दौरान प्राप्त भू-राजस्व

क्र.सं.	वर्ष	कुल राजस्व	भू-राजस्व
1.	1765-66	20073133 रु.	14946024 रु.
2.	1766-67	33829494 रु.	23467500 रु.
3.	1767-68	32071195 रु.	21352805 रु.
4.	1768-69	13664072 रु.	21352805 रु.
5.	1769-70	29706976 रु.	18572159 रु.

विभिन्न क्षेत्रों में भू-राजस्व व्यवस्था का प्रतिशत

क्र.सं.	क्षेत्र	भू-राजस्व प्रणाली	भूमिका %
1.	वाराणसी, बिहार, बंगाल, मद्रास के उत्तरी क्षेत्र	स्थायी बन्दोबस्त	19%
2.	मद्रास, बम्बई, सिन्ध, बरार, असम	रैयतवाड़ी बन्दोबस्त	56%
3.	पंजाब, मद्रास, भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रान्त	महालवाड़ी बन्दोबस्त	50%

1880 ई. में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में गठित 'स्ट्रेची अकाल आयोग' के प्रमुख सुझाव

1. अकाल की सम्भावना से पूर्व प्रभावित लोगों को रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएं.
2. गरीब एवं असमर्थ व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जाए. उनका सूचीकरण कर भोजन, अनाज और पैसा दिया जाए.
3. अनाज का संग्रह किया जाए और आवश्यकता के दौरान अनाज के निर्यात को रोका जाए.
4. अकाल के दौरान कर एवं लगान में छूट दी जाए.
5. अकाल राहत में होने वाले व्यय को प्रान्तीय सरकारें वहन करें एवं केन्द्रीय सरकार इसमें सहयोग प्रदान करे.
6. सूखाग्रस्त क्षेत्र से पशुओं को अन्यत्र ले जाने की व्यवस्था की जाए.

भू-राजस्व व्यवस्था एवं उनके प्रवर्तक

क्र. सं.	व्यवस्था	प्रवर्तक
1.	स्थायी बन्दोबस्त	लॉर्ड कार्नवालिस, 1793 ई.
2.	महालवाड़ी बन्दोबस्त	मार्टिन बर्ड, 1801 ई.
3.	रैयतवाड़ी बन्दोबस्त	सर टॉमस मुनरो, 1820 ई.

विगत वर्षों में आई.ए.एस. (प्री.) में पूछे गये प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   रैयतवारी (भू-राजस्व) प्रथा में,
   1. छोटे कृषकों के साथ बन्दोबस्त (Settlement) किया जाता था.
   2. कृषकों को भूमि पर सभी अधिकार उपलब्ध थे बशर्ते कि वे एक निश्चित राजस्व का भुगतान करें, जोकि राज्य के लिए ग्राम प्रमुख (Village headman) द्वारा एकत्र किया जाता था.
   3. बन्दोबस्त किया जाता था तथा उसका निश्चित समय के लिए नवीकरण किया जाता था जिस दौरान रैयत को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था.

   उपर्युक्त में से कौनसा/से सही है / हैं ?
   (A) केवल 1 (B) केवल 2 तथा 3
   (C) केवल 1 तथा 3 (D) 1, 2 तथा 3
2. ताराशंकर बंद्योपाध्याय के उपन्यास 'गणदेवता' में निम्नलिखित में से किस एक प्रथा का पतन प्रदर्शित किया गया है ?
   (A) जमींदारी प्रथा (B) रैयतवारी प्रथा
   (C) जजमानी प्रथा (D) महलवारी प्रथा
3. नील विद्रोह (Indigo revolt) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. हिन्दू व मुसलमान किसानों में पूर्ण एकता थी.
   2. विद्रोही रैयत का एक प्रमुख नेता हेमचन्द्र कर था.
   3. विद्रोही रैयत ने एक सुस्पष्ट संगठन तथा अनुशासन बनाए रखा था.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
   (A) 1, 2 तथा 3 (B) केवल 1 तथा 2
   (C) केवल 2 तथा 3 (D) केवल 1 तथा 3
4. निम्नलिखित में से किसने बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 'दि इकानामिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' प्रकाशित की ?
   (A) दादाभाई नौरोजी
   (B) गोपालकृष्ण गोखले
   (C) महादेव गोविन्द रानाडे
   (D) रोमेशचन्द्र दत्त
5. 1881 ई. का फैक्ट्री एक्ट निम्नांकित दृष्टि से पारित किया गया था–
   (A) किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना
   (B) श्रमिकों के मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना
   (C) औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियत करना
   (D) महिला कर्मियों की मजदूरी नियत करना
6. निम्नलिखित अधिनियमों का सही कालानुक्रम क्या है ?
   1. इण्डियन ट्रेड यूनियन्स एक्ट
   2. इण्डियन फैक्टरीज एक्ट
   3. द ट्रेड डिस्यूट्स एक्ट
   4. इण्डियन माइन्स एक्ट

   नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए–
   (A) 2, 4, 1, 3 (B) 3, 1, 4, 2
   (C) 1, 3, 2, 4 (D) 4, 2, 3, 1
7. निम्नलिखित में से कौन एक 17वीं शताब्दी में भारत में प्रवर्तित नई नकदी फसल थी ?
   (A) नील (B) लाल मिर्च
   (C) मूँगफली (D) तम्बाकू
8. परवर्ती 17वीं एवं प्रारम्भिक 18वीं शताब्दियों में इण्डोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था ?
   (A) गुजराती एवं मारवाड़ी व्यापारी वर्गों का
   (B) पुर्तगालियों का
   (C) डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी का
   (D) इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का
9. बंगाल में मुक्त व्यापार का मुगल फरमान अंग्रेजों को कब दिया गया था ?
   (A) 1717 (B) 1756
   (C) 1650 (D) 1696
10. निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य एवं चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया ?
    (A) 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट
    (B) पिट इण्डिया एक्ट
    (C) 1813 का चार्टर एक्ट
    (D) 1833 का चार्टर एक्ट
11. 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का निम्नलिखित में से कौनसा कारण था ?
    (A) उत्पादन की गुणवत्ता में ह्रास
    (B) कच्चे माल की अनुपलब्धता
    (C) ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर का ऊँचा होना
    (D) कारीगरों की अनुपलब्धता

12. निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन एक सही है ?
    (A) कार्नवालिस द्वारा 1793 में परिणमित बंगाल के स्थायी बन्दोबस्त ने अभिजात्य जमींदारों के एक वर्ग को जमीन में स्वामित्व अधिकार प्रदान किए
    (B) स्थायी बन्दोबस्त कार्यवाही से जमींदारों की स्थिति कमजोर हो गई
    (C) टॉमस मुनरो ने बन्दोबस्त की एक व्यवस्था का विकास किया, जिसके अन्तर्गत सरकार भूस्वामी काश्तकारों के साथ सीधे कोई संव्यवहार नहीं करती थी
    (D) भूमि नीति एवं बन्दोबस्तों से भूमि पर नियन्त्रण तथा भूमिकर्षण से जुड़े वर्गों के मध्य सम्बन्धों में संरचनात्मक सुधार नहीं हुए

13. नीचे चार उद्योग दिए गए हैं, जो भारत में अंग्रेजी शासन की अवधि में विकसित हुए–
    1. जूट उद्योग
    2. लौह एवं इस्पात उद्योग
    3. वस्त्र उद्योग
    4. चीनी उद्योग

    निम्नलिखित में से कौन एक उद्योगों के विकास के सही कालक्रम को प्रकट करता है ?
    (A) 1, 2, 3, 4 (B) 3, 1, 2, 4
    (C) 1, 3, 2, 4 (D) 4, 1, 2, 3

14. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है–

    कथन (A) : बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा पर अधिकार कर लेने के बाद, अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक तरीके अपनाए, जिसमें भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ.

    कारण (R) : अंग्रेजों ने विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था.

    उपर्युक्त दो वक्तव्यों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है ?
    (A) A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R है.
    (B) A और R दोनों सही हैं, किन्तु A की सही व्याख्या R नहीं है.
    (C) A सही है, किन्तु R गलत है.
    (D) A गलत है, किन्तु R सही है.

15. निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है ?
    (A) रैयतवाड़ी बन्दोबस्त – मद्रास
    (B) स्थायी बन्दोबस्त – बंगाल
    (C) महालवाड़ी बन्दोबस्त – उत्तर-पश्चिमी प्रान्त
    (D) तालुकदारी प्रथा – बम्बई

16. बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे उसके सम्बन्ध बिगड़ गये ?
    (A) अलीवर्दी (B) सिराजुद्दौला
    (C) मीर जाफर (D) मीर कासिम

17. ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने किस हेतु 'भारत में निवेश' (इन्वेस्टमेंट इन इण्डिया) शब्द का प्रयोग आरम्भ किया?
    (A) भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात
    (B) भारतीय वस्तुओं के क्रय हेतु बक्सर की लूट
    (C) निःशुल्क अन्तर्देशीय व्यापार से लाभ एवं दीवानी राजस्व का अधिशेष
    (D) भारत में खरीद के लिए भारतीय साहूकारों से उधार लिया हुआ धन

18. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए–

    सूची-I (कृषकों की राहत हेतु पारित अधिनियम)
    (a) पंजाब लैंड एलिअनेशन एक्ट
    (b) डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट
    (c) नार्थ वेस्ट प्रॉविंसेज एलिअनेशन एक्ट
    (d) सेन्ट्रल प्रॉविंसेज लैंड एलिअनेशन एक्ट

    सूची-II (पारित होने का वर्ष)
    (1) 1879 (2) 1904
    (3) 1916 (4) 1900

    कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	4	2	3
(B)	1	4	3	2
(C)	4	1	3	2
(D)	4	1	2	3

19. ईस्ट इण्डिया कम्पनी सरकार ने भारत से रकम भेजने की समस्या प्रारम्भ में कैसे सुलझायी ?
    (A) भारत से अनाज के अधिक निर्यात के विकास द्वारा
    (B) यूरोप को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में कपास एवं सिल्क की वस्तुओं के निर्यात द्वारा

(C) नील के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात द्वारा

(D) जूट के विकास एवं यूरोप को इसके निर्यात के प्रोत्साहन द्वारा

20. उत्तर सत्रहवीं शताब्दी में कृषि संकट के लिए निम्न-लिखित में से कौन उत्तरदायी थे ?

1. जागीर व्यवस्था की अंतर्निहित दुर्बलताएँ
2. मौद्रिक उतार-चढ़ाव
3. प्राकृतिक विपदाएँ
4. प्रशासनिक विफलता

नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–

कूट :

(A) 1 और 2 (B) 3 और 4
(C) 1, 2 और 3 (D) 2, 3 और 4

21. सत्रहवीं शताब्दी में भारत और क्यूबा के बीच के व्यापार पर प्रभुत्व था–

(A) पुर्तगालियों का (B) डचों का
(C) अंग्रेजों का (D) फ्रांसीसियों का

22. स्थायी बन्दोबस्त के अधीन जमा किए गए भू-राजस्व में जमींदारी का अंश था–

(A) 1/4 (B) 1/3
(C) 1/11 (D) 1/6

23. विदेशी पूँजीवादी भारतीय उद्योग की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए थे. निम्नलिखित में से कौनसा एक कारण उनमें से एक नहीं था ?

(A) श्रम बहुत सस्ता था

(B) कच्चा माल बहुत आसानी से और कम दामों में उपलब्ध था

(C) भारतीय पूँजीपति वर्ग काफी विकसित था, परन्तु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था

(D) बहुत से भारतीय उत्पादों की पूरे विश्व में काफी माँग थी

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. 1757 और 1857 के मध्य उत्तर भारत में आया महत्वपूर्ण आर्थिक विकास, कलकत्ता एवं गंगा नदी तन्त्र के माध्यम से महानगरीय अर्थव्यवस्था से जुड़ने के परिणामस्वरूप हुआ, जो नगरों के विकास में परिलक्षित हुआ.

2. भारतीय राजदरबारों के लुप्त होने से सुख-साधन वस्तु व्यापार से जुड़े दस्तकारों के रोजगार के अवसरों में ह्रास हुआ, यद्यपि इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ा.

3. पंजाब, कश्मीर और राजस्थान में गंगा घाटी की अपेक्षा परिवर्तन की गति धीमी और कम नाटकीय थी, जैसाकि नगरों के बहुत कम विकास से व्यक्त होता है.

उपर्युक्त कथनों में से कौन-कौनसे सही हैं ?

(A) 1 और 3 (B) 2 और 3
(C) 1 और 2 (D) 1, 2 और 3

25. ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी बंगाल में जमींदार हो गई थी–

(A) गोविन्दपुर, सुतानति तथा कोलीकाता ग्रामों के लगान की लेनदारी के बाद

(B) चन्द्रनगर, सुतानति तथा गोविन्दपुर ग्रामों के लगान की लेनदारी के बाद

(C) चन्द्रनगर, सुतानति तथा कोलीकाता ग्रामों के लगान की लेनदारी के बाद

(D) कोलीकाता, गोविन्दपुर तथा प्लासी ग्रामों के लगान की लेनदारी के बाद

26. निम्नलिखित युग्मों में से कौनसा एक सही सुमेलित नहीं है?

(A) रैयतवाड़ी बन्दोबस्त–मद्रास
(B) स्थायी बन्दोबस्त–बंगाल
(C) महालवाड़ी बन्दोबस्त–उत्तर-पश्चिमी प्रान्त
(D) ताल्लुकदारी बन्दोबस्त–बम्बई

27. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I

(a) दि इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन
(b) दि विक्टोरिया जुबली टैक्निल इन्स्टीट्यूट
(c) दि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी
(d) दि इण्डियन इन्डस्ट्रियल कमीशन

सूची-II

1. 1918 2. 1884
3. 1888 4. 1907

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	1	4
(B)	3	2	4	1
(C)	2	3	4	1
(D)	3	2	1	4

28. निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए–

1. दि इण्डियन करेंसी (Fowler) कमीशन
2. दि रॉयल कमीशन (Chamberlain) ऑन इण्डियन फाइनेंस एण्ड करेंसी
3. दि इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया
4. दि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

इन संस्थाओं की स्थापना का सही कालानुक्रम है–

(A) 2, 1, 3, 4 (B) 1, 2, 3, 4

(C) 1, 2, 4, 3 (D) 2, 1, 4, 3

29. निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए–

1. आर्थिक समृद्धि (Economic Prosperity).
2. अंग्रेजों के पास बंगाल के दीवानी अधिकार थे, जबकि नवाब निजामत के कार्य के लिए उत्तरदायी था.
3. अकाल (Famine) की लम्बी अवधि.
4. क्षेत्र में व्यापार की मात्रा में अकस्मात् वृद्धि.

इनमें से कौन-कौनसी बंगाल के द्वैधशासन प्रबन्ध (Dual government) की विशेषताएँ थीं?

(A) 1, 2 और 4 (B) 1, 3 और 4

(C) 2, 3 और 4 (D) 1, 2 और 3

30. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे–

(A) एस.ए. डांगे (B) लाला लाजपत राय

(C) जेड.ए. अहमद (D) एन. एम. जोशी

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

कार्नवालिस का बंगाल में स्थायी बन्दोवस्त ने

1. जमींदारों को उनकी भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया
2. रैयतों का जमींदारों की दया पर छोड़ दिया
3. कम्पनी के लिए स्थायी आय सुनिश्चित की
4. जमींदारों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी का समर्थक बनाया

इनमें से कौन सही है?

(A) 1 और 4 (B) 2, 3 और 4

(C) 1, 2 और 3 (D) 1 और 2

32. निम्नलिखित में से कौन एक, स्वातंत्र्योपरांत भारत में भूमि-सुधार के संदर्भ में सही नहीं है ?

(A) जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण

(B) भूमि को जोतने वाले को कृषक के अधिकार प्रदान करना

(C) भूमि की चकबन्दी

(D) बेनामी हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध

33. निम्नलिखित में से कौन बम्बई योजना की संरचना से सम्बद्ध नहीं था ?

(A) लाला श्रीराम (B) जी. डी. बिड़ला

(C) भूलाभाई देसाई (D) जे.आर.डी. टाटा

34. भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में पड़ने वाले पाँच दुर्भिक्षों का कारण था–

1. भारतीय उद्योग धन्धों में ह्रास.
2. कृषि मजदूरों में गतिहीनता.
3. मानसून की विफलता.
4. तैयार माल का आयात.

इनमें से कौनसे कथन सही हैं?

(A) 2 व 3 (B) 1 व 4

(C) 1, 2 व 3 (D) 2, 3 व 4

35. उन्नीसवीं शताब्दी में, जनसंख्या में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव पड़ने लगा था, क्योंकि–

(A) वाणिज्यिक फसलों के आगमन के कारण अधिक किसान कृषि की ओर आकर्षित होने लगे थे

(B) हस्तशिल्प तथा ग्रामीण उद्योगों के विनाश के कारण जनता कृषि की ओर उन्मुख होने लगी थी

(C) देशी सरकारों के पतन के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में कमी आ गई थी

(D) सुरक्षा कारणों से नगरों की आबादी का ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रव्रजन आरम्भ होने लगा था

36. 'दस्तक' शब्द से तात्पर्य है–

(A) निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क-मुक्त व्यापार

(B) उपद्रव

(C) हुगली के समीपवर्ती बन्दरगाह

(D) बाजार स्थल

37. निम्न में से कौनसे युद्ध के साथ ही अंग्रेजी आधिपत्य को फ्रांस की चुनौती समाप्त हो गई?

(A) वांडीवाश (B) बक्सर

(C) श्रीरंगपट्टनम (D) प्लासी

38. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

इंगलैण्ड के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य कि भारतीय सिविल सेवा में मौजूद ब्रिटिश तत्व प्रशासन के 'फौलादी ढाँचे' के समान है, जो भारत के लिए शाश्वत रूप से अपरिहार्य है, के परिणाम थे–

1. वेल्स के राजकुमार की यात्रा का बहिष्कार.
2. इंगलैण्ड की संसद की घोषित नीति के विपरीत भारतीयकरण की प्रक्रिया में मंदता.
3. कांग्रेस के विरुद्ध दमनकारी कदम.
4. सार्वजनिक सेवाओं के लिए बिठाए गए ली कमीशन द्वारा उदारवादी संस्तुतियाँ.

इनमें से कौनसा/से कथन सही हैं?

(A) 1, 2 व 3 (B) 1, 2 व 4

(C) 2 व 4 (D) केवल 4

निर्देश–आगामी प्रश्न में दो वक्तव्य हैं. एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है. इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए–

कूट :

(A) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है

(B) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है.

(C) A सही है, परन्तु R गलत है.

(D) A गलत है, परन्तु R सही है.

39. **कथन (A)** : आर. सी. दत्त द्वारा पुस्तक 'पॉवर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल' लिखी गई.

कारण (R) : वह भारत में बढ़ती हुई गरीबी का पर्दाफाश करना चाहते थे.

40. सूची-I (घटनाएं) को सूची-II (वायसराय) से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–

सूची-I (घटनाएं)

(a) स्थानीय स्वशासन

(b) 1892 का अधिनियम

(c) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

(d) शिमला शिष्टमण्डल

सूची-II (वायसराय)

1. लॉर्ड डफरिन
2. लॉर्ड मिण्टो
3. लॉर्ड रिपन
4. लॉर्ड मेयो
5. लॉर्ड लैन्सडाउन

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	2	4	5
(B)	3	5	1	2
(C)	1	5	4	2
(D)	3	2	1	5

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

भारतीय कृषि पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों का प्रभाव था–

1. एक नई बाजार अर्थव्यवस्था का निर्माण.
2. भू-स्वामियों एवं जोतने वाले कृषकों के बीच ध्रुवीकरण.
3. भूमिविहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि.
4. ग्रामीण शिल्पकारों में बेरोजगारी.

इनमें से कौनसे कथन सही हैं?

(A) 1, 2 व 3 (B) 2, 3 व 4

(C) 1 व 4 (D) 1, 2, 3 व 4

42. सूची-I (वर्ष) को सूची-II (अधिनियम) से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–

सूची–I (वर्ष)

(a) 1921 (b) 1926

(c) 1938 (d) 1939

सूची–II (अधिनियम)

1. बम्बई लघु सम्पत्ति धारक राहत अधिनियम
2. यू. पी. काश्तकारी अधिनियम
3. अवध किराया अधिनियम
4. आगरा काश्तकारी अधिनियम

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	4	1	3
(B)	3	4	1	2
(C)	2	1	4	3
(D)	3	1	4	2

43. ब्रिटिश राज्यकाल में महाजनी वर्ग के विकास का क्या प्रमुख कारण था ?

(A) प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की बर्बादी

(B) लोगों का खर्चीला स्वभाव

(C) किसानों से अधिक भू-राजस्व की माँग

(D) कृषि के लिए पूँजी की आवश्यकता

44. निम्नलिखित में से कौनसे भारत में कम्पनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे ?

(A) भू-राजस्व

(B) नमक और अफीम व्यापार का एकाधिकार

(C) मालभाड़ा

(D) रूपान्तरण ऋणपत्र

(E) इनमें से कोई नहीं

45. 1858 ई. से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियन्त्रण निम्नांकित में निहित था–

(A) भारत में सुप्रीम गवर्नमेंट

(B) ब्रिटिश पार्लियामेंट

(C) इंगलैण्ड से बोर्ड ऑफ कन्ट्रॉल

(D) काउंसिल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट

46. 1857 ई. के विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नांकित से की जाती थी–

(A) यू. पी. और बिहार के ब्राह्मण

(B) पूर्व के बंगाली के उड़िया
(C) उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी
(D) दक्षिण में मद्रास प्रेसीडेंसी और पश्चिम में मराठा

उत्तरमाला

1. (A)	2. (C)	3. (D)	4. (D)	5. (A)
6. (A)	7. (D)	8. (C)	9. (A)	10. (D)
11. (C)	12. (A)	13. (B)	14. (C)	15. (D)
16. (D)	17. (C)	18. (C)	19. (B)	20. (C)
21. (B)	22. (C)	23. (C)	24. (D)	25. (A)
26. (D)	27. (C)	28. (B)	29. (C)	30. (B)
31. (B)	32. (D)	33. (C)	34. (B)	35. (B)
36. (A)	37. (A)	38. (C)	39. (D)	40. (B)
41. (D)	42. (B)	43. (C)	44. (B)	45. (B)
46. (C)				

संकेत

3. नील आन्दोलन का नेतृत्व दिगम्बर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था.
36. दस्तक का दुरुपयोग प्लासी के युद्ध का एक प्रमुख कारण था.
39. पुस्तक के लेखक दादाभाई नौरोजी थे.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण निम्न प्रभाव हुए–
(A) सम्पदा निष्कासन
(B) उद्योग-धन्धे बढ़े
(C) भारतीय उद्योग धन्धे घटे
(D) उपर्युक्त सभी

2. अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था आधारित थी–
(A) ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर
(B) शहरी अर्थव्यवस्था पर
(C) नगरीय अर्थव्यवस्था पर
(D) सभी पर

3. अंग्रेजों के आधिपत्य का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा–
(A) शिल्पियों पर (B) बंगाल के बुनकरों पर
(C) जूट उत्पादकों पर (D) चाय उत्पादकों पर

4. भारत का धन विदेशों में जाने की क्रिया को कहा जाता था–
(A) सम्पदा का दोहन (B) सम्पदा का उदारीकरण
(C) सम्पदा का निष्क्रमण (D) इनमें से कोई नहीं

5. यह किसने कहा कि "ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की सम्पदा को छीन रहा है?"
(A) लोकमान्य तिलक ने (B) दादा भाई नौरोजी ने
(C) महात्मा गांधी ने (D) सरदार पटेल ने

6. "इंगलैण्ड को प्रतिवर्ष अपने स्वयं का धन बाहर भेजने को बाध्य होना पड़े, तो वहाँ वर्षों पूर्व ही अकाल पड़ गया होता." यह कथन किसका है ?
(A) आर. सी. दत्त (B) गोविन्द रानाडे
(C) प्रोफेसर उपाध्याय (D) मंसूर अली

7. भारत में धन का निष्कासन शुरू हुआ–
(A) 1758 ई. में (B) 1757 ई. में
(C) 1857 ई. में (D) 1858 ई. में

8. 1757-65 के मध्य कितनी राशि का निष्पादन हुआ ?
(A) 70 लाख पौंड (B) 50 लाख पौंड
(C) 60 लाख पौंड (D) 90 लाख पौंड

9. "हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की भाँति है, जिसके जरिए गंगा तट की सारी अच्छी चीजों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के तट पर निचोड़ दिया जाता है." यह कथन किसका है ?
(A) मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष का
(B) कम्पनी के गवर्नर का
(C) लॉर्ड डलहौजी का
(D) आर. पी. दत्ता का

10. कम्पनी को बंगाल की दीवानी कब मिली ?
(A) 1760 में (B) 1765 में
(C) 1770 में (D) 1772 में

11. 1834-51 ई. के मध्य प्रतिवर्ष कितना धन निष्पादन होता था ?
(A) 4221611 पौंड (B) 452153 पौंड
(C) 38120 पौंड (D) 596072 पौंड

12. 1757-1815 ई. तक कितने पौंड धन इंग्लैण्ड पहुँच चुका था ?
(A) 20 करोड़ (B) 10 करोड़
(C) 15 करोड़ (D) 18 करोड़

13. 1860-1900 ई. के मध्य प्रतिवर्ष कितना धन निष्क्रमण हुआ ?
(A) 15 करोड़ (B) 40 करोड़
(C) 18 करोड़ (D) 20 करोड़

14. 19वीं शताब्दी के अंत में पड़े अकालों की संख्या उससे पिछले सौ वर्षों में पड़े अकालों की संख्या का है–
(A) चार गुना (B) छः गुना
(C) आठ गुना (D) दस गुना

15. भारत में गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण था–
(A) भू-राजस्व की अधिकता
(B) अत्यधिक निष्क्रमण
(C) लगान व्यवस्था
(D) वसूली प्रथा

16. धन निष्कासन की प्रवृत्ति को "अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने" की संज्ञा किसने दी ?
(A) लाजपत राय ने (B) लोकमान्य तिलक ने
(C) दादाभाई नौरोजी ने (D) आर. पी. दत्ता ने

17. अंग्रेजों द्वारा भू-राजस्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का उद्देश्य था–
(A) अधिक-से-अधिक राजस्व प्राप्त करना
(B) किसानों को लाभ पहुँचाना
(C) जमींदारों को लाभ पहुँचाना
(D) इनमें से कोई नहीं

18. बंगाल-बिहार में दीवानी प्राप्त करने के बाद कम्पनी ने लगान वसूली का कार्य किसे सौंपा ?
(A) बंगाल के डिप्टी दीवान को
(B) कम्पनी के गवर्नर को
(C) कम्पनी के मैनेजर को
(D) क्लाइव को

19. कम्पनी द्वारा 1792 में 70 लाख पौंड ऋण वसूला गया, जोकि बढ़कर 1939 में कितना हो गया ?
(A) 40 करोड़ (B) 50 करोड़
(C) 88·42 करोड़ (D) 88·40 करोड़

20. लॉर्ड क्लाइव ने लगान वसूली का कार्य किसे सौंपा ?
(A) भारतीय पदाधिकारियों को
(B) गवर्नर को
(C) जमींदारों को
(D) सामंतों को

21. ठेके पर जमीन किसको दी जाती थी ?
(A) जो सबसे अधिक अंग्रेजों की सहायता करता
(B) जो सबसे अधिक लगान देता
(C) जो अंग्रेजों के साथ हाँ-में-हाँ मिलाता
(D) जो सबसे कम लगान देता

22. स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था कब शुरू की ?
(A) 1792 ई. में (B) 1793 ई. में
(C) 1791 ई. में (D) 1790 ई. में

23. स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की ?
(A) कार्नवालिस ने (B) लॉर्ड क्लाइव ने
(C) होमर ने (D) मैकाले ने

24. कार्नवालिस गवर्नर बनकर कब भारत में आया ?
(A) 1785 में (B) 1786 में
(C) 1787 में (D) 1788 में

25. स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था के तहत कार्नवालिस ने बंगाल के जमींदारों के साथ कितने साल तक अनुबन्ध किया ?
(A) 15 साल (B) 20 साल
(C) 18 साल (D) 10 साल

26. इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को खास उपलब्धि क्या हुई ?
(A) उन्हें जमीन पर मालिकाना हक मिला
(B) ऋण से मुक्ति मिली
(C) आर्थिक सहयोग मिला
(D) कुछ नहीं

27. स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था को स्थायी स्वरूप कब प्रदान किया गया ?
(A) 1796 ई. में (B) 1793 ई. में
(C) 1791 ई. में (D) 1794 ई. में

28. उपर्युक्त परिवर्तन का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा ?
(A) किसानों को ऋण मुक्ति मिली
(B) किसान भूमि के मालिक हो गए
(C) किसान जमींदारों पर आश्रित हो गए
(D) जमींदार को ऋण में रियायत मिली

29. स्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई ?
(A) उड़ीसा में (B) बंगाल व बिहार में
(C) बम्बई में (D) मद्रास में

30. स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था को साहस, बहादुरी तथा बुद्धिमानी का कार्य किसने बताया ?
(A) मार्शमैन ने (B) निकोलस ने
(C) डलहौजी ने (D) क्लाइव ने

31. स्थायी बन्दोबस्ती से जिस सम्पन्न वर्ग का उदय हुआ, वह था–
(A) सामंत वर्ग (B) जमींदार वर्ग
(C) कृषक वर्ग (D) कोई नहीं

32. स्थायी बन्दोबस्ती के तहत वित्तीय दृष्टिकोण से ब्रिटिश सरकार को दीर्घकालीन घाटा होने का कारण था–
(A) जमीन की सही नाप-तौल सही ढंग से न करना
(B) कम्पनी की व्यापार नीति
(C) कम्पनी की आर्थिक नीति
(D) लगान वसूली

33. जमींदार वर्ग किस व्यवस्था पर निर्भर था ?
    (A) भू-व्यवस्था (B) राजस्व व्यवस्था
    (C) कर व्यवस्था (D) लगान वसूली

34. जमींदार वर्ग ने जनता तथा अंग्रेज शासकों के मध्य कार्य किया–
    (A) सहायक का (B) प्रतिरोधक का
    (C) समन्वयक का (D) बिचौलिया का

35. स्थायी बन्दोवस्त के आधार पर जमींदारों को क्या मिला ?
    (A) ऋण मुक्ति
    (B) भूमि पर पैतृक अधिकार
    (C) लगान वसूली
    (D) कोई नहीं

36. स्थायी बन्दोवस्ती के कारण कृषि व्यवस्था में–
    (A) विस्तार हुआ
    (B) कमी आई
    (C) कोई प्रभाव नहीं हुआ
    (D) सामान्य असर हुआ

37. जमींदार किसानों से जो ऋण वसूलता था, उसका कितना प्रतिशत कम्पनी को दिया जाता था ?
    (A) 25% (B) 28%
    (C) 30% (D) 35%

38. जमींदारों को कहा जाता था–
    (A) रैयत (B) किसानी रैयत
    (C) सरकारी रैयत (D) दीवानी रैयत

39. जमींदारों का एकमात्र उद्देश्य था–
    (A) लगान वसूल करना
    (B) अंग्रेजों का हित चाहना
    (C) किसानों का भला
    (D) अधिक-से-अधिक ऋण वसूली

40. स्थायी बन्दोवस्त से किसानों पर यह प्रभाव पड़ा कि–
    (A) उनका भू-स्वामित्व हट गया
    (B) परम्परागत अधिकार चले गए
    (C) शोषण अधिक होने लगा
    (D) उपर्युक्त सभी

41. स्थायी बन्दोवस्ती से समाज कितने वर्गों में बँटा ?
    (A) एक (B) दो
    (C) तीन (D) चार

42. रैयतवाड़ी प्रथा शुरू हुई थी–
    (A) दक्षिण-पश्चिम भारत में
    (B) उत्तरी भारत में
    (C) पूर्वी भारत में
    (D) पश्चिमी भारत में

43. भारत में समस्त भूमि का कितने प्रतिशत भाग स्थायी बन्दोवस्त के अधीन था ?
    (A) 20% (B) 10%
    (C) 15% (D) 19%

44. महालवाड़ी प्रथा के अधीन कितने प्रतिशत भूमि थी ?
    (A) 30% (B) 20%
    (C) 25% (D) 35%

45. रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्तर्गत कितने प्रतिशत भूमि थी–
    (A) 45% (B) 50%
    (C) 51% (D) 55%

46. रैयत का सामान्य अर्थ है–
    (A) प्रजा का सामान्य जन
    (B) सामन्त वर्ग
    (C) जमींदार वर्ग
    (D) सैनिक वर्ग

47. किसानों के साथ जो समझौता लगान के सम्बन्ध में किया गया, वह कहलाया–
    (A) महालवाड़ी (B) रैयतवाड़ी
    (C) स्थायी बन्दोवस्त (D) कोई नहीं

48. रैयतवाड़ी की स्थापना कब हुई ?
    (A) 1872 ई. में (B) 1812 ई. में
    (C) 1852 ई. में (D) 1854 ई. में

49. रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई ?
    (A) बम्बई में (B) कलकत्ता में
    (C) मद्रास में (D) बंगाल में

50. पहला भूमि संगठन कब बनाया गया ?
    (A) 1856 में (B) 1852 में
    (C) 1854 में (D) 1865 में

51. पंजाबी किसानों को चिरस्थायी काश्तकारों के रूप में मान्यता मिली–
    (A) 1867 व 1887 के कानूनों के तहत
    (B) 1854 के कानूनों के तहत
    (C) 1852 के तहत
    (D) कोई नहीं

52. इस कानून से किसानों को अधिकार मिला–
    (A) भूमि वेचने का (B) भूमि गिरवी रखने का
    (C) पट्टे लिखने का (D) उपर्युक्त सभी

53. 1825 ई. में रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई ?
(A) बम्बई में (B) मद्रास में
(C) कलकत्ता में (D) बंगाल में

54. भू-राजस्व दरों की पुनर्समीक्षा कितने वर्षों बाद होती थी ?
(A) 20 वर्ष (B) 25 वर्ष
(C) 30 वर्ष (D) 35 वर्ष

55. किस व्यवस्था के तहत जमीन को व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जाने लगा ?
(A) महालवाड़ी (B) रैयतवाड़ी
(C) बन्दोबस्त (D) सामंतवादी व्यवस्था

56. 'महाल' शब्द का तात्पर्य है–
(A) गाँव का समूह या गाँव
(B) नगर अथवा गाँव
(C) शहर अथवा गाँव
(D) कस्बा अथवा गाँव

57. वह व्यवस्था जिसके अनुसार एक व्यक्ति गाँव का मालिक नहीं होता–
(A) रैयतवाड़ी (B) सामंतवादी
(C) महालवाड़ी (D) बन्दोबस्ती

58. अवध क्षेत्र में महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई ?
(A) 1801 में (B) 1802 में
(C) 1803 में (D) 1804 में

59. पंजाब में जो व्यवस्था लागू की गई, उसको कहा जाता था–
(A) संशोधित रैयतवाड़ी (B) संशोधित महालवाड़ी
(C) संशोधित सामंतवादी (D) संशोधित बन्दोबस्ती

60. भारत में कम्पनी का व्यापारिक अधिकार कब खत्म हुआ ?
(A) 1814 ई. (B) 1813 ई.
(C) 1815 ई. (D) 1816 ई.

61. कृषकों ने मूल खाद्यान्नों को छोड़कर अधिक आमदनी वाली फसलें उगाना शुरू कर दिया. इसको नाम दिया गया–
(A) व्यापारिक व्यवस्था (B) उदारीकरण
(C) वाणिज्यीकरण (D) आर्थिक नियोजन

62. विदेश आयात नीति के कारण भारतीय मूल के उद्योग धन्धे–
(A) नष्ट प्रायः हो गए (B) खूब फले-फूले
(C) अप्रभावी रहे (D) समानुपात में बढ़े

63. कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण कपास उत्पादन के कितने क्षेत्र में वृद्धि हुई ?
(A) 72% (B) 73%
(C) 63% (D) 62%

64. जूट के कितने उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की गई ?
(A) 50% (B) 30%
(C) 88% (D) 38%

65. भारत में सड़कों के निर्माण पर अत्यधिक बल किसने दिया ?
(A) डलहौजी ने (B) क्लाइव ने
(C) होमर ने (D) डूप्ले ने

66. डलहौजी ने रेलवे विकास की योजना कब बनाई ?
(A) 1854 ई. में (B) 1853 ई. में
(C) 1855 ई. में (D) 1856 ई. में

67. भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली ?
(A) बम्बई-पुणे (B) बम्बई-थाणे
(C) बम्बई-बंगाल (D) विशाखापट्टनम-बम्बई

68. भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरूआत कब हुई ?
(A) 1855 ई. में (B) 1854 ई. में
(C) 1888 ई. में (D) 1853 ई. में

69. रेल निर्माण के उस दौर में प्रति मील कितना खर्च आया ?
(A) 20-30 हजार पौंड (B) 20-25 हजार पौंड
(C) 25-40 हजार पौंड (D) 40-42 हजार पौंड

70. भारत में 1869 ई. तक कितने मील लम्बी रेल लाइन का निर्माण हो चुका था ?
(A) 4200 मील (B) 4000 मील
(C) 5000 मील (D) 5200 मील

71. 1869 ई. में रेल निर्माण नीति में परिवर्तन लाने का मुख्य ध्येय था–
(A) सुनियोजित विस्तार (B) अधिक आमदनी
(C) खर्चे में कमी (D) इनमें से कोई नहीं

72. रेलवे का निर्माण दोबारा से निजी कम्पनियों को कब दिया गया ?
(A) 1880 ई. से (B) 1780 ई. से
(C) 1882 ई. से (D) 1784 ई. से

73. ऋणग्रस्तता का एक दुष्परिणाम प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया, वह था–
(A) कृषक वर्ग का जन्म (B) सर्वहारा वर्ग का उदय
(C) जमींदारों का उदय (D) इनमें से कोई नहीं

74. भारतीय कृषि तथा अर्थव्यवस्था मूलतः कैसी थी ?
    (A) औपनिवेशक
    (B) भारतीय सिद्धांतानुसार
    (C) जमींदारों के मनमाफिक
    (D) उपर्युक्त सभी

75. भारत में 1875 में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या 80 लाख थी. यह बढ़ते-बढ़ते 1911 ई. तक कितनी हो गई ?
    (A) 400 लाख (B) 300 लाख
    (C) 500 लाख (D) 270 लाख

76. 1891 से 1901 तक की अल्पावधि में कितने भारतीय कामगारों को कृषि की ओर मुड़ना पड़ा ?
    (A) 75% (B) 50%
    (C) 25% (D) 35%

77. कृषि के वाणिज्यीकरण में मुख्य रुकावट क्या थी ?
    (A) स्वावलम्वी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
    (B) आर्थिक व्यवस्था
    (C) सामन्ती व्यवस्था
    (D) इनमें से कोई नहीं

78. लगान वसूली की ठेकेदारी से अवध में किस वर्ग का उदय हुआ ?
    (A) खोत (B) जमींदार
    (C) ताल्लुकेदार (D) सामंत

79. लगान वसूली की ठेकेदारी से बम्बई में किस वर्ग का उदय हुआ ?
    (A) ताल्लुकेदार (B) जमींदार
    (C) खोत (D) सामंत

80. ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत खत्म हुआ ?
    (A) रेग्यूलेटिंग एक्ट (B) चार्टर एक्ट
    (C) रोलिंग एक्ट (D) कोई नहीं

81. "ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और भारत के साथ उसके आर्थिक सम्बन्धों को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया." यह कथन किसका है ?
    (A) विपिन चन्द्र पाल का
    (B) लोकमान्य तिलक का
    (C) सर टॉमस रो का
    (D) डूप्ले का

82. अंग्रेजों द्वारा चालू की गई रेलवे व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ उन्हें कब हुआ ?
    (A) 1852 ई. में (B) 1853 ई. में
    (C) 1856 ई. में (D) 1857 ई. में

83. रेल निर्माण का काम व उनको चलाने की जिम्मेदारी निजी कम्पनियों को सौंपी गई, जिनकी पूँजी पर भारत सरकार ने कम-से-कम कितना प्रतिशत लाभ देने की गारण्टी दी ?
    (A) 5% (B) 7%
    (C) 10% (D) 15%

84. राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ ?
    (A) 1981 ई. में (B) 1891 ई. में
    (C) 1781 ई. में (D) 1117 ई. में

85. अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण कितने प्रतिशत किसान साहूकारों के ऋणी हो गए ?
    (A) 70% (B) 80%
    (C) 85% (D) 90%

86. रेलवे निर्माण पर जो खर्च भारत में 20-30 हजार प्रति मील था. वह इंग्लैण्ड में कितना था ?
    (A) 8000 रुपए (B) 10000 रुपए
    (C) 9000 रुपए (D) 15000 रुपए

87. लॉर्ड डलहौजी ने सहारनपुर नियम कब बनाया ?
    (A) 1860 ई. में (B) 1855 ई. में
    (C) 1862 ई. में (D) 1870 ई. में

88. महाजनी व्यवसाय मंदा पड़ जाने पर क्या करना श्रेयस्कर समझा ?
    (A) धन जमीन की खरीद फरोख्त में लगाने लगे
    (B) बैंक में जमा कराने लगे
    (C) लगान वसूली करने लगे
    (D) इनमें से कोई नहीं

89. ब्रिटिश साम्राज्यवादी औपनिवेशक आर्थिक नीतियों को कितने भागों में बाँटा गया है ?
    (A) तीन (B) चार
    (C) पाँच (D) सात

90. बन्दोबस्ती व्यवस्था के लिए 10 वर्षीय प्रवन्ध कब बनाया गया ?
    (A) 1793 ई. में (B) 1794 ई. में
    (C) 1795 ई. में (D) 1796 ई. में

91. बिना जुते क्षेत्र, घास के मैदास, चरागाह एवं जंगलों को राजकीय सम्पत्ति कब माना गया ?
    (A) 1838 ई. में (B) 1832 ई. में
    (C) 1828 ई. में (D) 1817 ई. में

92. "राजनीतिक दृष्टि से जमींदार एवं भू-सम्पत्ति धारक ब्रिटिश राज के इतने समर्थक बन गए कि बंगाल 1857

के सैनिक विद्रोह और विप्लव से पूर्णतया अलग रहा." यह कथन था–

(A) मुखर्जी का (B) देसाई का
(C) मार्क्स टेलर का (D) होमर का

93. स्थायी व्यवस्था के कारण भूमि के मूल्य में–
(A) कमी आई
(B) वृद्धि हुई
(C) भाव अपरिवर्तित रहे
(D) इनमें से कोई नहीं

94. उप जमींदार प्रणाली से किसानों की स्थिति में–
(A) उत्तरोत्तर कमी आई
(B) उत्तरोत्तर वृद्धि हुई
(C) कोई प्रभाव नहीं पड़ा
(D) इनमें से कोई नहीं

95. "केवल जमींदारों के साथ समझौता करके और किसानों की सर्वथा उपेक्षा करके एक बहुत बड़ी भूल की गई." यह कथन किसका था ?
(A) विलियम हुक का (B) रॉबर्टस् का
(C) क्लाइव का (D) होमर का

96. किसानों की समस्याओं के प्रति रुचि न होने से क्या प्रभाव पड़ा ?
(A) भू-स्वामी तथा किसानों में संघर्ष होने लगे
(B) दोनों में मित्रता हो गई
(C) स्थिति जस की तस रही
(D) इनमें से कोई नहीं

97. अंग्रेजी प्रशासन ने नीलामी व्यवस्था (मद्रास में) कब लागू की ?
(A) 1807 ई. में (B) 1800 ई. में
(C) 1808 ई. में (D) 1810 ई. में

98. बम्बई के भू-प्रबन्ध पत्रादि में अधिगृहिता नाम किसे दिया गया ?
(A) महालवाड़ी को (B) बन्दोबस्ती को
(C) रैयतों को (D) इनमें से कोई नहीं

99. रैयतवाड़ी के तहत कृषकों से सारा लगान कौन वसूलता था ?
(A) जमींदार (B) ताल्लुकेदार
(C) सामंत (D) सरकार

उत्तरमाला

1. (D)	2. (A)	3. (B)	4. (C)	5. (B)
6. (A)	7. (B)	8. (C)	9. (A)	10. (B)
11. (A)	12. (B)	13. (B)	14. (A)	15. (A)
16. (C)	17. (A)	18. (A)	19. (C)	20. (A)
21. (B)	22. (B)	23. (A)	24. (B)	25. (D)
26. (A)	27. (B)	28. (C)	29. (B)	30. (A)
31. (A)	32. (A)	33. (A)	34. (B)	35. (B)
36. (A)	37. (B)	38. (C)	39. (D)	40. (D)
41. (B)	42. (A)	43. (D)	44. (A)	45. (C)
46. (A)	47. (B)	48. (B)	49. (C)	50. (C)
51. (A)	52. (D)	53. (A)	54. (C)	55. (B)
56. (A)	57. (C)	58. (A)	59. (B)	60. (B)
61. (C)	62. (A)	63. (C)	64. (D)	65. (A)
66. (B)	67. (B)	68. (C)	69. (A)	70. (B)
71. (C)	72. (A)	73. (B)	74. (A)	75. (C)
76. (B)	77. (A)	78. (C)	79. (C)	80. (B)
81. (A)	82. (D)	83. (A)	84. (B)	85. (B)
86. (C)	87. (B)	88. (A)	89. (A)	90. (A)
91. (C)	92. (B)	93. (B)	94. (B)	95. (B)
96. (A)	97. (B)	98. (C)	99. (D)	

3

सांस्कृतिक समागम एवं सामाजिक परिवर्तन
(Cultural Encounter & Social Changes)

[पश्चिमी शिक्षा एवं आधुनिक विचारों की भूमिका, भारतीय पुनर्जागरण, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलन, भारतीय मध्यम वर्गों की वृद्धि, छापाखाना एवं इसका प्रभाव, भारतीय भाषाओं में आधुनिक साहित्य का उदय, सन् 1857 से पहले सामाजिक सुधार के उपाय (Introduction of Western Educations & Modern Ideas, Indian Renaissance, Social & Religious Reform Movements, Growth of Indian Middle Class, The Press & its Impact, Rise of Modern Literature in Indian Languages, Social Reforms Measures before 1857)]

सांस्कृतिक समागम एवं सामाजिक परिवर्तन

पश्चिमी शिक्षा एवं आधुनिक विचारों की भूमिका—आधुनिक शिक्षा की शुरूआत करके अंग्रेज वैज्ञानिक और समाजशास्त्री ज्ञान के क्षेत्र में भारत को आधुनिक पाश्चात्य उपलब्धियों के सम्पर्क में ले आए. आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ यूरोपीय जातियों के आगमन से माना जाता है. भारत में आने वाले पुर्तगाली पादरियों में फ्रांसिस जेवियर मुख्य था, उसी ने यहाँ 1542 ई. में अनेक स्कूल खोले. बम्बई स्थित बांद्रा एवं गोआ आदि स्थानों पर कॉलेज प्रस्थापित किए गए, जिनमें ईसाई धर्म, पुर्तगाली व्याकरण, संगीत, तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी. रॉबर्ट डे नोबिली नामक पादरी ने भी अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की. हॉलैण्ड निवासी डचों ने बंगाल में चिनसुरा एवं हुगली में भी कुछ स्कूल खोले. फ्रांसीसियों के द्वारा भी चन्द्रनगर, माही, यनाम, कारोकल एवं पांडिचेरी में अनेक स्कूल खोले गए. कलकत्ता के समीप सेरामपुर तथा तन्जौर के निकट डेनमार्कवासियों ने मिशनरी स्कूल स्थापित किए जिनमें दो जर्मन : प्लासो एवं जिजेनबल ने शिक्षण कार्य किया. डॉ. कैरे, वार्ड व मार्शमैन ने सेरामपुर को शिक्षा प्रमुख केन्द्र बना दिया.

आधुनिक शिक्षा का आविर्भाव–ऐडम ने, जो 1823 ई. में अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत् था, सार्वजनिक शिक्षा के लिए 10 सदस्यों की एक सामान्य समिति नियुक्त की, जिसमें एच. टी. प्रिंसेस और एच. एच. विलसन प्रमुख थे और उनके हाथों में वार्षिक एक लाख रुपए और पूर्व में जमा की गई रकम सौंप दी. समिति के समक्ष दो समस्याएँ थीं. पहली यह तय करना कि शिक्षा का स्वरूप क्या हो और दूसरा यह कि शिक्षा किसको दी जाए ? समिति में प्राच्य विद्या के समर्थकों का बोलबाला था. 1834 ई. में गवर्नर जनरल की परिषद् के विधि सदस्य के रूप में मैकाले के आने से परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन आया. अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना से पूर्व भी ईसाई मिशनरियाँ आधुनिक शिक्षा के लिए प्रचार-प्रसार करने लग गई थीं. उनका यह विश्वास था कि भारतीयों के धर्मपरिवर्तन का उनका लक्ष्य वस्तुतः सभ्यता के प्रचार-प्रसार का लक्ष्य है. ये मिशनरी भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रथम प्रचारक थे. इन्होंने अपने स्कूलों में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तो दी ही, उसके साथ ही ईसाई धर्म की भी शिक्षा दी.

मूलतः धर्मनिरपेक्ष इन शिक्षण संस्थाओं में भारतीयों को एक साथ लाकर उनके बीच ईसाई धर्म का प्रचार करना एकमात्र उद्देश्य था, लेकिन ऐसा हुआ कि जो लड़के इन संस्थाओं में आए उनमें अधिकांश ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की, परन्तु बहुत कम लोग ही ईसाई हुए. इन मिशनरियों का लक्ष्य तो धार्मिक था, लेकिन भारतीयों के मध्य आधुनिक शिक्षा के प्रचार में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की. भारत में राजा राममोहन राय तथा जौहरी डेविड हेयर पश्चिमी

सभ्यता के प्रचार-प्रसार के सबसे तगड़े समर्थक थे. वे कलकत्ता में सिर्फ इसीलिए आकर बसे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वे अपना जीवन शिक्षा, समाज सुधार और उदार संस्थाओं में लगाएं. हेयर एवं मैकाले यह मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके नवयुवक ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे. मैकाले ने अपने पिता को लिखे एक पत्र में लिखा था कि "यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा योजना पर कार्य ढंग से किया गया, तो यह निश्चित है कि तीस वर्ष पश्चात् बंगाल के सम्मानित वर्गों में एक भी मूर्तिपूजक नहीं बचेगा."

कम्पनियों के अधीन आसानी से नौकरियाँ मिल जाने के कारण भी नवयुवक अंग्रेजी शिक्षा के प्रति बड़ी भारी तादाद में आकर्षित हुए. विलियम बैंटिक ने प्रशासन व्यय कम करने की दृष्टि से कुछ निम्न पदों पर भी भारतीयों को नियुक्त करना शुरू कर दिया. लॉर्ड हार्डिंग्स के समय 1844 ई. में निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त लोगों को नौकरी दी जाएगी. इस नीति से और अधिक संख्या में लोगों का अंग्रेजी शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ने लगा था. खासकर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ बड़े पैमाने पर हुआ. इस समय तक अधिकांश भारत के लोग अंग्रेजी शिक्षा की गिरफ्त में आ चुके थे.

अंग्रेजों के वृहद राजनीतिक प्रशासकीय तन्त्र को चलाने के लिए शिक्षित व्यक्तियों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता थी और यह भी सम्भव नहीं था कि इतने सारे लोग सीधे ब्रिटेन से आते, इसलिए प्रशासन की खातिर सुयोग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिहाज से भारत में स्कूल और कॉलेजों का खुलना आवश्यक हो गया था. पहले यह किया गया कि उच्च पदों पर अंग्रेजों की तथा उनके अधीनस्थों के रूप में भारतीय लोगों की नियुक्तियाँ की गईं. अंग्रेजों की ओर से संचालित उद्योग-धन्धों, कम्पनियों तथा विविध व्यवसायों में कार्य मिलने के कारण आधुनिक शिक्षा को भरपूर प्रोत्साहन मिला. चूँकि अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेने के कारण देशी राज्यों की शक्ति कमजोर हो चुकी थी जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षण संस्थाओं की सहायता बन्द हो गई. अंग्रेजों को प्रसन्न रखने के लिहाज से नवीन संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन दिया जाने लगा. यह भी एक मुख्य कारण था कि कुछ नौजवान जो बहुत सालों तक संस्कृत विद्यालयों में पढ़े उन्हें अपनी उन्नति का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था, फलतः उनको मजबूरन अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख होना पड़ा. स्कूल बुक सोसाइटी की ओर से प्रकाशित 31,000 अंग्रेजी पुस्तकें दो वर्ष के अन्दर ही बिक गईं और अरबी तथा संस्कृत की पुस्तकों की बिक्री का यह हाल था कि तीन वर्ष में इतनी ही पुस्तकें बिकीं, उन्हें रखने का दो महीने का किराया भी मुश्किल से वसूल हुआ, छपाई का खर्च निकलना तो बहुत दूर की बात थी. अनेक भारतीय नेता भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे. 1823 ई. में बंगाल में सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन हुआ और कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई. इसका सर्वाधिक विरोध राजा राममोहन राय ने किया. उन्होंने गवर्नर जनरल एमहर्स्ट के पास एक आवेदन-पत्र भेजा और उसमें लिखा कि संस्कृत विद्यालय में विद्यार्थी उसे ही प्राप्त करेंगे जो दो हजार वर्ष पहले ज्ञात था. यदि ब्रिटिश विधानमण्डल की यही नीति रही, तो संस्कृत शिक्षा इस देश को अंधकार में रखने वाली सबसे अधिक सहायक भाषा सिद्ध होगी, परन्तु फिर भी हेयर के प्रयासों से 1817 ई. में कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज की स्थापना हुई, जो आगे चलकर 1854 ई. में प्रेसीडेंसी महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ. हालांकि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, अग्रकार, मगनभाई करमचंद कर्वे, तिलक, गोखले, मालवीय, गांधी और अन्य लोग इस अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के कुछ पहलुओं को लेकर आलोचना करते थे, लेकिन बाद में इसके महत्व को समझकर और सामाजिक परिवर्तनों को देखकर उन्होंने भी इसका समर्थन करना शुरू किया. अंग्रेजों का एक मंतव्य यह था कि अंग्रेजी संस्कृति समूचे विश्व में श्रेष्ठ है. अतः वे यह चाहते थे कि इसका जितना अधिक-से-अधिक प्रचार होगा वह उतनी ही उनके लिए फायदेमंद होगी. उनका यह भी मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय ब्रिटिश राज्य के प्रबल समर्थक बन जाएंगे और जनता में ब्रिटिश पूँजीवाद की राजनीतिक आवश्यकता और ब्रिटिश संस्कृति की सर्वोच्चता की मान्यता ने भारत में आधुनिक शिक्षा की स्थापना में योगदान दिया.

मैकाले का यह मानना था कि देशी तथा भारतीय शिक्षा में साहित्यिकता व वैज्ञानिकता का पुट नहीं है. अतः उसने संस्कृत तथा अरबी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का पुरजोर विरोध किया. उसके विचार में यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक खाना भारत तथा अरब के सम्पूर्ण देशी साहित्य के बराबर था. मैकाले का मूल उद्देश्य भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था, जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो, किन्तु विचारों से अंग्रेज हो. 1834 ई. में मैकाले गवर्नर जनरल की कौंसिल में विधि कार्यकारी सदस्य बना, उसी समय बैंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में नीति निर्धारित करने का निश्चय किया.

अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भिक दौर–अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से प्रारम्भिक लाभ अधिकतर मध्यमवर्गीय हिन्दुओं ने उठाया. उच्चवर्गीय हिन्दू तथा मुस्लिम समाज शुरू में इससे अलग प्रायः ही रहा. कुछ समय के बाद ही अंग्रेजी शिक्षा का असर इस तरह होने लगा कि अधिकतर भारतीय के मन में इसके

प्रति अत्यधिक रुचि तथा सम्मान होने लगा था. जो विचार इंग्लैण्ड पर छा रहे थे, उसी की तर्ज पर यहाँ की विचारधारा बड़ी तीव्रगति से बदलने लगी. कैथोलिक मुक्ति कानून (1829), सुधार बिल (1832), दासता दूरीकरण (1833) और नवीन दरिद्र पोषक कानून (1834) जैसे महत्वपूर्ण कानूनों का बनना पश्चिमी शिक्षा का ही प्रभाव था. 1857 ई. से पूर्व का काल शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगों का काल कहा जाता है. अतः उपलब्धियों की अपेक्षा प्रयोगों की अधिकता रही. 1813 ई. के चार्टर अधिनियम में शिक्षा सम्बन्धी निर्देश पूरी तरह अस्पष्ट थे. अतः शिक्षा के लक्ष्य, माध्यम, शिक्षा प्रणाली एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्ध के विषय में विवाद होता रहता था. यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग देशी विद्यालयों को प्रोत्साहन देना चाहता था तो कुछ लोग मिशनरी प्रयासों के समर्थक थे. उत्तर-पश्चिमी प्रांत में थॉम्पसन ने देशी विद्यालयों के आधार पर सार्वजनिक शिक्षा पद्धति के निर्माण का प्रयास किया. दूसरी ओर बम्बई शिक्षा बोर्ड द्वारा देशी विद्यालयों के स्थान पर सरकारी विद्यालयों की स्थापना की जा रही थी. यहाँ मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने के प्रयास होने लगे थे, जबकि बंगाल में अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया. आगरा में नार्मल स्कूल खोला गया एवं 1852 ई. में सेंट जोंस कॉलेज स्थापित किया गया. 1853 ई. में बनारस कॉलेज की स्थापना थॉम्पसन के द्वारा की गई. अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1849 ई. में अमृतसर एवं लाहौर में स्कूल खोले गए. 1842 ई. में कलकत्ता के हिन्दू कॉलेज में कानून तथा 1844 ई. में इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू की गई. 1841 ई. में मद्रास में हाई स्कूल तथा 1852 ई. में कॉलेज की स्थापना की गई.

अंग्रेजी संसद की ओर से नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट पर 1854 ई. में शिक्षा व्यवस्था का घोषणा-पत्र जारी किया गया. उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड था. उसकी घोषणा पर 1859 ई. में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए. इस तरह भारतीय शिक्षा को वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ. वुड के घोषणा-पत्र को भारतीय शिक्षा का महान् आज्ञा-पत्र भी कहा जाता है.

1854-1885 के मध्य शिक्षा का विस्तार–वुड की ओर से जारी घोषणा-पत्र में जनसामान्य में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया. 1870 ई. के बाद वित्तीय विकेन्द्रीकरण द्वारा शिक्षा का प्रभार प्रांतों पर डाल दिया गया, लेकिन प्रान्तीय सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया. 1871 ई. से लेकर 1882 ई. तक के काल में शिक्षा के क्षेत्र में अवश्य प्रगति हुई. इस बात का प्रमाण यह है कि जहाँ 1870-72 ई. में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 16473 थी वहीं 1881-82 ई. में इनकी संख्या बढ़कर 82916 हो गई. निजी स्तर पर देश के विभिन्न भागों में अनेक विद्यालय खोले गए. कलकत्ता और मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज, लाहौर का यूनिवर्सिटी कॉलेज, इलाहाबाद का सेंट्रल कॉलेज, अजमेर का गवर्नमेंट कॉलेज आदि सरकार द्वारा खोले गए प्रमुख महाविद्यालय थे. निजी क्षेत्र में कलकत्ता के विद्यासागर एवं सीटी कॉलेज, आगरा के सेंट जोंस कॉलेज, अलीगढ़ का मोहम्मदन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज, लखनऊ का केनिंग कॉलेज, लाहौर का फौरमेन एवं एचिसन कॉलेज, अजमेर का मेयो कॉलेज, इन्दौर का डेली कॉलेज, मद्रास क्षेत्र का पच्चैयप्पा कॉलेज, विजगापट्टम तथा जयपुर का महाराजा कॉलेज (1873 ई. से कॉलेज स्तर में तब्दील) आदि प्रमुख थे.

1870 ई. के पश्चात् कुछ शिक्षा प्राप्त भारतीय आईसीएस की परीक्षा में सफल होने लगे. इसलिए एक ओर अंग्रेज सरकार ने जहाँ परीक्षाओं में बैठने की अधिकतम आयु कम कर दी, वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा की अपेक्षा प्रारम्भिक शिक्षा पर ही अधिक ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया.

स्त्री शिक्षा–हालांकि वुड ने अपने शिक्षा घोषणा-पत्र में इस बात की सिफारिश की थी कि स्त्री शिक्षा पर अधिक-से-अधिक ध्यान दिया जाए, परन्तु उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि इसका दायित्व स्वयं सरकार उठाये. इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्री शिक्षा की गति मन्द रही. इसके बावजूद बम्बई, मद्रास, बंगाल व उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में स्त्री शिक्षा के लिए अनेक स्कूल खोले गए. राजा राममोहन राय तथा आर्य समाज की ओर से स्त्री शिक्षा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया गया.

मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार–जैसे ही कम्पनी सरकार की स्थापना हुई मुसलमानों में अंग्रेजी विरोधी भावना विकसित होने लगी थी. अंग्रेजी पढ़ने से उन्हें अपना धर्म भ्रष्ट होने का खतरा था. आमतौर पर मुस्लिम समुदाय अंग्रेजी शिक्षा से वंचित ही रहा, परन्तु 1857 ई. के विरोध के पश्चात् उन्होंने इस पर ध्यान दिया. 7 अगस्त, 1871 ई. में लॉर्ड मेयो के आदेश पर भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मुसलमानों को भी अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई. जब मुसलमानों को यह लगा कि वे अंग्रेजी शिक्षा के अभाव में अन्य वर्ग की अपेक्षा पिछड़ते जा रहे हैं, तो उनको अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख करने वालों में सर सैयद अहमद खाँ प्रमुख थे. उन्होंने ही 1875 ई. में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की जो आगे जाकर मुस्लिम विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया.

पाश्चात्य शिक्षा व आधुनिक विचारों से लाभ-हानि–चूँकि नवीन शिक्षा पद्धति में किसी भी प्रकार का जाति अथवा धर्म का बन्धन नहीं था, वह सबके लिए सुलभ थी, अतः उसका तेजी से साथ विस्तार हुआ. दूसरे शब्दों में कहें तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की शुरूआत हुई. पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से लोगों

की मानसिकता में बदलाव आया. अंधविश्वासों से उनका विश्वास हटने लगा तथा भाग्यवाद की प्रबल विचारधारा क्षीण होने लगी.

भारतीय महिला विश्वविद्यालय, 1916 ई. में पुणे में प्रोफेसर कर्वे द्वारा शुरू किया गया था, जो रीति-रिवाज नारी की प्रगति में बाधक थे, वे तेजी से लुप्त होने लगे. नई शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह तथा अस्पृश्यता जैसी बुराइयों के विरुद्ध विचारधारा को जन्म दिया. पाश्चात्य ग्रंथों का अध्ययन करके भारतीयों का ज्ञान सम्वर्धन हुआ. पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत हुई. भारत के लोगों को पहली बार विश्व के अन्य देशों के बारे में जानकारी मिली. आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों को पाश्चात्य चिंतकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों से परिचित कराया और अपने स्वतन्त्र अस्तित्व के बारे में चेताया.

हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से जहाँ भारतीय समाज को बहुत कुछ नया सीखने को मिला, वहीं कुछ बुराइयाँ भी पनपीं. इसमें सबसे प्रमुख हानिकारक प्रभाव हिन्दू-मुसलमानों के मध्य आपसी वैमनस्यता का बढ़ना था. आपसी खाई दिन-पर-दिन और चौड़ी होती चली गई, जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन में बाधाएँ आईं.

संक्षेप रूप में कहें तो यह तथ्य सामने आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन आधुनिक शिक्षा पद्धति का प्रत्यक्ष व अनन्य परिणाम नहीं था. यह कहना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं ठहराया जा सकता कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में राष्ट्रीयता का आविर्भाव हुआ. यह बिल्कुल सत्य है कि यदि राष्ट्रीय आन्दोलन केवल अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों तक ही सीमित रहता तो वह कभी भी जनआन्दोलन नहीं बन सकता था. अंग्रेजी शिक्षा का योगदान तो केवल अप्रत्यक्ष रूप में ही था, क्योंकि इसने भारतीयों को पाश्चात्य राजनीतिक जीवन का महत्व समझाया और अपने अधिकारों के प्रति विरोध करने की शक्ति पैदा की.

भारतीय पुनर्जागरण–सामाजिक एवं धार्मिक आन्दोलनों की बदौलत भारतीय लोगों की मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन आया. उनके विचारों में एक नई क्रांति ने जन्म लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय धर्म, समाज, साहित्य, राजनीति एवं कला-कौशल बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई. इस विचारधारा को ही पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई. प्रत्येक क्षेत्र में सुधार तथा आवश्यक परिवर्तन हुए. इन परिवर्तनों से राष्ट्रीयता के विकास में मदद मिली. कुछ क्षेत्रों को बिन्दुवार इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है–

धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन–चूँकि प्राचीन समाज में रूढ़िवादियों का बोलबाला था, इसलिए भारतीयों के विचार एक निश्चित दायरे तक ही सीमित थे. हिन्दू समाज विशेष रूप से इसके चंगुल में था. पुनर्जागरण के प्रभाव से धर्म सुधारकों ने हिन्दू धर्म के उत्थान, उसको व्यापक एवं सर्वग्राही बनाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए. इन प्रयासों के तहत बलि, यज्ञ, अंधविश्वासों तथा पुरोहितों के महत्व को नकारना शुरू हुआ. सत्य, ज्ञान, चिंतन, मनन और वेद का सहारा लेकर भारतीय धर्म में पुनरुत्थान की भावना जाग्रत हुई. इस क्षेत्र में ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, आर्य समाज तथा रामकृष्ण मिशन ने अथक सहयोग प्रदान किया. इनके प्रयासों से भारतीयों की धार्मिक जड़ता समाप्त हुई. हिन्दुओं की देखादेखी मुसलमान, सिख, ईसाई तथा पारसियों में भी अपने-अपने धर्म के उत्थान करने के लिए जागृति आई.

सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन–भारतीय समाज धार्मिक क्षेत्र की तरह विभिन्न कुप्रथाओं से ग्रस्त था. जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा, बाल विवाह, बहुविवाह, शिशु वध, बलि प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का चहुंओर साम्राज्य व्याप्त था. हालात ये थे कि समाज में स्त्रियों व विधवाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी. धार्मिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन कुप्रथाओं को दूर करना टेढ़ी खीर था, परन्तु जब धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन को लेकर आवश्यक सुधार हुए तो उनका सकारात्मक प्रभाव इन कुप्रथाओं पर भी पड़ा. सभी धर्म सुधारकों की ओर से सामाजिक सुधारों को भी सहयोग मिला. कुछ उदारवादी अंग्रेजों ने इसके सुधार में अपना सहयोग प्रदान किया. फलस्वरूप भारतीय समाज से सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, अस्पृश्यता, शिशु वध, दास प्रथा और बहुविवाह जैसी कुरीतियों में कमी आई. पर्दा प्रथा को समाप्त करने एवं विदेश यात्रा पर से धार्मिक प्रतिबन्ध हटाने के प्रयास किए गए.

मानसिकता व विचारों में परिवर्तन–धार्मिक तथा समाज सुधार आन्दोलनों ने भारतीयों के मन व मस्तिष्क को स्वतन्त्र व उन्मुक्त बना दिया तथा नवीन चेतना का स्फुरण किया. लोग धार्मिक रूढ़ियों तथा अंधविश्वास को त्यागने लगे. आपसी तर्क-वितर्क व कसौटी के आधार पर प्रत्येक मंतव्य को परखा जाने लगा. बुद्धि के आधार पर मानवता का दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा. आस्था के स्थान पर बुद्धि के आधार पर निर्णय लिए जाने लगे. तात्कालिक समाज जगत् में होने वाली राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियों से परिचित होने लगा और घटना-प्रघटनाओं में रुचि लेने लगा. उनके दिलो-दिमाग में भी स्वदेश प्रेम, समानता तथा विश्व-बंधुत्व की भावना ने जन्म लिया. आत्म सम्मान और देशभक्ति की भावना का जन-जन के हृदय में संचार हुआ.

अतीत का उजागर होना–पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह रही कि प्राचीन भारत के विस्मृत इतिहास एवं गौरव को उजागर करने का मौका मिला. इसमें पाश्चात्य

विद्वानों के साथ-ही-साथ भारतीय धर्म सुधारकों तथा विद्वानों ने अपना-अपना सहयोग प्रदान किया. चूँकि पाश्चात्य विद्वान् अपने देशों की स्थिति से नाखुश थे, अतः उन्होंने अपनी भड़ास को भारतीय इतिहास एवं दर्शन में रुचि लेते हुए इस कार्य को किया. ठीक इसके विपरीत भारतीय समाज सुधारकों एवं विद्वानों ने अपने देश के प्रति गौरव की भावना एवं विदेशी सत्ता को खत्म करने के उद्देश्य से यह कार्य किया. इस प्रयास से भारतीय साहित्य तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति व दर्शन का रूप उजागर हुआ. विदेशी विद्वानों में जेम्स फर्ग्यूसन, हैवेल, ब्राउन, भंडारकर, स्मिथ मिल और एलिफिंसटन आदि ने अपने अनुसन्धानों तथा लेखों से प्राचीन भारत की स्थिति को "स्वर्णिम युग" के रूप में और मध्यकाल को "अवनति के युग" के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया.

साहित्य के क्षेत्र में प्रगति–पुनर्जागरण से साहित्य के क्षेत्र में भी आशातीत परिवर्तन हुए. अंग्रेजी शिक्षा के विकास ने अनेक भारतीय ग्रन्थों का अनुवाद अंग्रेजी में करवा दिया. लोगों को अपने अतीत के साहित्य से रू-ब-रू होने का मौका मिला. भारतीयों के साथ-ही-साथ अंग्रेजों को भी यहाँ के स्वर्णिम साहित्य को समझने एवं परखने का मौका मिला. भारतीयों के अलावा यूरोपीय भाषाओं में भी भारतीय दर्शन तथा साहित्य का अनुवाद हुआ, फलतः भारतीय दर्शन व संस्कृति दूर-दराज तक पहुँचने लगी. उदाहरण के लिए विलकिंस ने गीता, मैक्समूलर ने वेद, जोन्स ने मनुस्मृति तथा शकुन्तला और कोलब्रुक ने पाणिनि की व्याकरण व हितोपदेश का अपनी देश की भाषाओं में अनुवाद किया. संस्कृत साहित्य के प्रति लोगों की आस्था व रुचि बढ़ी और समूचा जगत् इससे परिचित हुआ, जिससे भारतीयों के गौरव में वृद्धि हुई.

प्रादेशिक भाषाओं का विकास–संस्कृत साहित्य का जितना विकास हुआ उसी के अनुसार भारतीय मूल की अनेक प्रादेशिक भाषाओं को भी फलने-फूलने का मौका मिला और इनके साहित्य में भी विकास की धारा बह निकली. हिन्दी, उर्दू, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलगू आदि भाषाओं में इन क्षेत्रों के साहित्य व इतिहास को प्रकाशन का अवसर मिला. इनके अलावा इन प्रादेशिक भाषाओं में नया साहित्य भी रचा गया जिसमें भारतीयता का पुट कूट-कूट कर भरा हुआ था. इस प्रकार नए साहित्य सृजन तथा प्राचीन साहित्य के परिचय के आधार पर लोगों में स्वाभिमान की भावना ने जन्म लिया तथा अंग्रेजी दासता के विरोध में स्वर मुखरित होने लगे.

कला व औद्योगिक विकास में प्रगति–भारतीय पुनर्जागरण ने कला एवं औद्योगिक विकास की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया. हैवेल तथा सिस्टर निवेदिता के प्रयासों से भारतीय चित्रकला ने सफलता के ऊँचे आयामों तक अपनी पताका फहराई. कला के विकास के लिए अनेक कला केन्द्रों की स्थापना की गई. इनके द्वारा संगीत, नृत्य, चित्र तथा वास्तुकला विकसित दशा में पहुँच सकी. कृषि पर आधारित उद्योगों को भी पुनः पनपने का सुअवसर मिला.

वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति–साहित्य और भाषा के विकास के साथ-साथ वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अनेक अनुसन्धान हुए. रामानुजम, जगदीश चन्द्र बसु, सी. वी. रमन, मेघनाद साहा, एस. चन्द्रशेखर जैसे विद्वान् तथा वैज्ञानिकों ने अपने अनुसन्धानों तथा अन्वेषणों द्वारा वैज्ञानिक जगत् में भारत की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया.

मध्यम वर्ग का उदय एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास–सुधार आन्दोलनों एवं पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार ने भारत में मध्यम वर्ग का उदय सम्भव कर दिया. अंग्रेजी पढ़े-लिखे व्यक्ति वकील, डॉक्टर, अध्यापक, राजकीय कर्मचारी आदि इस वर्ग में विशिष्ट स्थान रखते थे. हालांकि प्रारम्भ में यह वर्ग अंग्रेजों का अंधभक्त था, परन्तु अंग्रेजों की कूटनीति को समझने के बाद तथा राष्ट्रीय, समानता व स्वतन्त्रता के संघर्षों से प्रेरणा लेकर यह वर्ग धीरे-धीरे अंग्रेजी सत्ता का विरोधी बन गया और स्वतन्त्रता के आन्दोलन का नेतृत्व भी किया. इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीय समाज में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया.

सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलन

19वीं तथा 20वीं सदी में भारत में जहाँ राजनीतिक घटनाओं का प्रभुत्व रहा, वहीं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आन्दोलनों के कारण समाज को एक नई दिशा एवं गति मिली. छुआछूत, मूर्तिपूजा, बालविवाह, धार्मिक अंधविश्वासों व पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं से लोगों को छुटकारा मिला. जब अंग्रेजों ने यहाँ पदार्पण किया तो भी ये प्रथाएँ अस्तित्व में थीं, परन्तु उन्होंने इन्हें मिटाने के लिए कोई ठोस एवं कारगर कदम नहीं उठाए. इसकी वजह यह थी कि इन सामाजिक कुरीतियों के सहारे भारतीयों के जीवन की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर स्वयं की सत्ता को मजबूत करना चाहते थे, परन्तु कुछ कारण ऐसे थे कि भारतीयों के जनमानस में बदलाव आया और वे अपना लाभ-हानि सोचने लगे. इन कारणों में पाश्चात्य, शिक्षा तथा ज्ञान-विज्ञान का सम्पर्क अपने आप में महत्वपूर्ण कारण रहा. भारतीय समाज की बुराइयों एवं नए समाज के उदय की कल्पना ने तात्कालिक जनसमुदाय के मन में ऐसा जोश-खरोश पैदा किया कि युद्ध स्तर पर धार्मिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार के आन्दोलनों को बल मिला.

सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आन्दोलनों के कारक

पाश्चात्य सभ्यता से सम्पर्क–भारत देश का पाश्चात्य देशों से शुरू से ही सम्पर्क था तथा वहाँ की संस्कृति एवं वहाँ

के जीवन वृत्त से भी गहरा सम्बन्ध था. हालांकि मध्य और आधुनिक काल में भी यह सम्पर्क बना रहा था, परन्तु अंग्रेजों के शासन के प्रभाव के चलते सामान्य जनजीवन पर इसका बहुत कम असर पड़ा. यूरोपीय कम्पनियों तथा अंग्रेजों के आगमन के कारण भारतीयों का पुनः एक बार पश्चिमी जगत् और विचारों से सम्बद्ध हुआ. आपसी सम्पर्क और विचारों के आदान-प्रदान से ही प्रबुद्ध भारतीयों में अपने यहाँ व्याप्त बुराइयों को दूर करने की ललक पैदा हुई. इस ललक के साथ यह भी इच्छा हुई कि भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के समक्ष भारतीय सभ्यता और संस्कृति को और उत्कृष्ट रूप में परोसा जाए. यह सब करने के लिए आवश्यक था भारत में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर करना और रूढ़िवादिता को दूर किया जा सकता था सिर्फ जन-जागृति और जन-आन्दोलनों से.

अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव–हालांकि 19वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रेरित तथा बाध्य तो किया था, परन्तु वह सब कुछ था उनके निजी स्वार्थों के कारण, परन्तु उनका यह सोचना उनके स्वयं के लिए लाभदायक तो सिद्ध हुआ, परन्तु भारतीयों के लिए एक वरदान के रूप में सामने आया. अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग संकीर्ण विचारधारा से कुछ ऊपर उठकर सोच सकते थे. वे पश्चिमी-सभ्यता का अनुसरण करने लगे थे. जहाँ उन्हें यह आभास हो रहा था कि पश्चिमी जगत् सामंतवाद, धर्मांधता व अन्य रूढ़िवादियों से कहीं अधिक दूर तक की स्वच्छ सोच रखता था. कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने वहाँ की अच्छी व हितचिंतक बातों को भारत में भी फैलाना चाहा. इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण भारतीयों को एक नई दिशा दिखाई दी, जिसने भारतीयों के मन में उज्ज्वल भविष्य के सोच का संचार किया.

नए सामाजिक वर्ग (मध्यम वर्ग) का उदय–अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार व प्रचार तथा अंग्रेजी शासन की प्रशासकीय नीतियों ने नए सामाजिक वर्ग को जन्म दिया जिसे मध्यम वर्ग के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा. इस मध्यम वर्ग में वकील, डॉक्टर, अध्यापक तथा राजकीय कर्मचारी आते थे. हालांकि यह वर्ग शुरू में तो अंग्रेजी सत्ता का हिमायती था, परन्तु अंग्रेजों की दृष्टि में होते उत्तरोत्तर बदलाव के कारण इसके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया. इस वर्ग के सामाजिक संगठन ने भारतीय जनजीवन में व्याप्त कुरीतियों को स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर करनी शुरू कर दी. समाज में पनपी व्यावसायिकता के कारण जातीय प्रथा पर आधारित सामाजिक गठबन्धनों की पकड़ स्वतः ढीली होती गई. इस वर्ग का मानना था कि समाज को बुराइयों एवं कुरीतियों की जकड़न से मुक्त करके समानता, विवेकशील, मानवतावादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले रास्ते पर लाया जाए, जिससे समाज में एक नई सोच का जन्म हो सके. इस प्रकार की सोच को अंजाम देने तथा उसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस तथाकथित मध्यम वर्ग ने पाश्चात्य शिक्षा तथा वहाँ के तौर-तरीकों का अनुसरण करना शुरू कर दिया जिसका प्रतिफल यह हुआ कि यह वर्ग सुधार आन्दोलनों का जनक तथा प्रणेता कहा जाने लगा.

सामाजिक गतिशीलता में तीव्रता–अंग्रेजों की कुछ नीतियाँ इस प्रकार की थीं जिनसे सामाजिक गतिविधियों में तीव्रता आना स्वाभाविक था. सामाजिक मान्यताओं और आर्थिक व्यवस्था को परिस्थितिवश तिलांजलि देकर कृषकों, कारीगरों और मजदूरों को जीवनयापन करने के लिए नए साधनों की खोज के लिए विवश होना पड़ा. इस प्रकार वे देशी नरेश तथा सामंतों की कृपा पर निर्भर न रहकर अंग्रेजी सरकार की सेवा की तरफ ज्यादा आकृष्ट होने लगे. आवश्यकतानुसार नए नगरों व कस्बों का विकास होना शुरू हो गया. अतः वहाँ की जनता ने रूढ़िगत परम्पराओं को त्यागकर खुले विचारों को अपनाना शुरू कर दिया.

ईसाई मिशनरियों के कार्य–ईसाई मिशनरियों का भी सामाजिक सुधार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा. अंग्रेजों ने तथा ईसाई मिशनरियों ने भारतीय रूढ़िवादिताओं का विरोध करना शुरू कर दिया और भारतीय जनता को अपने में मिलाने के प्रयास शुरू कर दिए. इस प्रकार के कृत्यों को देखकर अपने धर्म तथा संस्कृति की रक्षार्थ धर्म सुधारकों को मजबूरन अपने विचारों में क्रांति की भावना लानी पड़ी और उन्होंने यह विचार कर लिया कि जब तक हिन्दू धर्म में आवश्यक परिवर्तन नहीं लाया जाता तब तक समाज के कमजोर वर्गों को एक सूत्र में बाँधकर नहीं रखा जा सकता.

प्रबुद्ध अंग्रेजों का योगदान–भारतीय सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलन को पैदा करने में कुछ अंग्रेजों ने भी माहौल बनाया. हालांकि उनके द्वारा दिया गया सहयोग उनके अपने स्वार्थों की खातिर था, परन्तु उसका परोक्ष प्रभाव भारतीय समाज पर ही पड़ा. एशियाटिक सोसायटी की स्थापना ने प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. अपनी संस्कृति तथा धर्म के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद उस समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने की हवा चल निकली.

समाचार-पत्रों व आवागमन के साधनों का विस्तार–समाचार-पत्रों तथा आवागमन के साधनों का विकास होने पर विचारों में श्रेष्ठ अभिव्यक्ति आना स्वाभाविक था. लोग एक-दूसरे की समस्याओं से परिचित होने लगे. उन्हें ऐसा लगने लगा कि आवागमन के साधनों से कम समय में अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सकता है. नई व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से आवागमन के साधन बहुत ही सहायक सिद्ध हुए.

राष्ट्रीयता की भावना का विकास–इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी समाज में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तेजी से हुआ. अंग्रेजी शासकीय नीतियों तथा शैक्षणिक प्रवृत्ति आदि कारणों से भारतीय समाज के मन में राष्ट्रीय भावना को और बलवती होने का मौका मिला. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह मानना था कि बिना सामाजिक-धार्मिक स्वतन्त्रता के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख पाना असम्भव है.

धर्म सुधारकों के प्रयास–19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अनेक ऐसे धर्म सुधारकों ने जन्म लिया, जिन्होंने समय-समय पर तात्कालिक सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का बीड़ा उठाया. इन सुधारकों में प्रमुख रूप से रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, गोपाल हरिदेशमुख, दादाभाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खाँ, स्वामी विवेकानन्द व प्रो. विपिन चन्द्र ने अपने क्रांतिकारी तथा परिवर्तनकारी विचारों से समूचे जनमानस को राष्ट्रीयता की सुरक्षा के मद्देनजर झकझोर कर रख दिया.

बंगाल में सुधार आन्दोलन–चूँकि अंग्रेजों की सत्ता की शुरूआत बंगाल से ही हुई थी. अतः सुधार आन्दोलन की पहली कड़ी के रूप में शुरूआत भी यहीं से हुई.

युवा बंगाल आन्दोलन–बंगाल में नवचेतना लाने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 'यंग बंगाल आन्दोलन' ने किया. यह संगठन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवाओं का समूह था, जिसने पुरातनपंथी विचारों को नकारने की शुरूआत की. इस आन्दोलन के नेता के रूप में एंग्लो इण्डियन युवक हेनरी विवियन डेरोजियो था. वह कलकत्ता के हिन्दू कॉलेज में अध्यापक था. उसने युवाओं में अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर दिखाने की भावना का संचार किया. सर्वप्रथम उसने नारी शिक्षा पर जोर देने के लिए संगठित युवाओं की आवाज बुलन्द की. अत्याचारों से पीड़ित जनता को राहत देने; उच्च सरकारी सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति इत्यादि के प्रश्न पर भारतीय जनमानस को उद्वेलित करने में उसका प्रमुख हाथ रहा. उसे इस प्रकार के आन्दोलन से जुड़ा होने के कारण अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा. भले ही यह आन्दोलन ज्यादा कुछ कारगर सिद्ध नहीं हुआ, परन्तु श्रीगणेश करने में इसका श्रेय सम्पूर्ण रूप से था. हेनरी की मृत्यु के बाद यह आन्दोलन शिथिल पड़ गया था, लेकिन तब तक भारतीय लोग अपनी धार्मिक व सामाजिक स्थिति की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे.

राजा राममोहन राय और उनके कार्य–वे 'यंग बंगाल' आन्दोलन द्वारा पैदा की गई तर्कपूर्ण जिज्ञासा के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे. उन्होंने रूढ़िगत परम्पराओं को तिरस्कृत करते हुए विवेकपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीय प्रतिष्ठा और सामाजिक समानता के सिद्धान्त पर बल दिया. उनका जन्म बंगाल के प्रतिष्ठित परिवार में 1774 ई. में हुआ था. वे संस्कृत, फारसी, अरबी, फ्रेंच, ग्रीक आदि भाषाओं के अच्छे जानकार थे. 1809 ई. में उन्होंने अपनी एक पुस्तक "एकेश्वरवादियों को उपहार" या "तोहफत-उल-मुहीद्दीन" फारसी भाषा में लिखी. 1805 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेवा करने लगे, परन्तु 1814 ई. में उन्होंने कम्पनी की नौकरी छोड़ दी और स्थायी रूप से कलकत्ता में निवास करने लगे. कलकत्ता में उनकी मुलाकात डेरोजिओ और उनके समर्थकों से हुई. उनसे प्रभावित होकर उन्होंने 1815 ई. में "आत्मीय सभा" की स्थापना की, जिसमें धार्मिक मुद्दों पर चर्चा-परिचर्चा होती थी. मूर्ति पूजा, जाति-प्रथा व छुआछूत जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने का अथक् श्रम किया. सती प्रथा को मिटाने में उनकी अहम भूमिका रही. अपने विचारों से अधिक-से-अधिक लोगों को परिचित कराने की दृष्टि से उन्होंने वेदों तथा प्रमुख उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया. 1820 ई. में उनकी प्रसिद्ध दूसरी पुस्तक "प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस" प्रकाशित हुई. उन्होंने "ब्रह्म सभा" को भी स्थापित किया जो आगे चलकर "ब्रह्म समाज" के नाम से प्रसिद्ध हुई. इस संस्था का मुख्य उद्देश्य हिन्दुओं में जन-जागृति लाना था.

ब्रह्म समाज की स्थापना–राजा राममोहन राय की धारणा थी कि ईश्वर की उपासना तथा धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए किसी माध्यम की नहीं, अपितु निष्ठा और भक्ति की आवश्यकता है. धार्मिक सुधारों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने 1829 ई. में ब्रह्म समाज की स्थापना की. ब्रह्म समाज ने विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया. प्रत्येक शनिवार की संध्या को समाज की बैठक होती जिसमें वेदों की ऋचाओं का सस्वर पाठ होता. इसमें करीब 50-60 लोग भाग लेते. 1830 ईस्वी में इस समाज के लिए अलग से एक भवन कलकत्ता में खरीदा गया. इस नए भवन का उपयोग केवल निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए ही किया जाता था.

सामाजिक सुधार–राजा राममोहन राय एक धर्म सुधारक की अपेक्षा समाज सुधारक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए. छुआछूत, बाल-विवाह, जात पाँत के बन्धन इतने कठोर हो चले थे कि हिन्दू ईसाई धर्म स्वीकारने लगे थे. अतः राजाराम मोहनराय ने सामाजिक दशा को सुधारने का शंखनाद किया. 1818 ई. से उन्होंने सती प्रथा का विरोध शुरू किया. शास्त्रों का सहारा लेकर उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की कि धर्मशास्त्रों में भी सती प्रथा का विरोध किया गया है. उनके प्रयासों से तथा विलियम बेंटिंक के सहयोग से 1829 ई. में सती प्रथा को एक कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया. उन्होंने बहुविवाह पर भी रोक लगाई तथा विधवा विवाह के

पक्ष में अपना मंतव्य प्रकट किया. किसी हद तक छुआछूत तथा जाति प्रथा पर भी अंकुश लगाया गया.

शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान–राजा राममोहन राय की यह मान्यता थी कि बिना कूपमंडूकता दूर किए यथार्थ रूप से सामाजिक प्रगति सम्भव नहीं है और यह तब तक सम्भव नहीं था तब तक कि उन्हें पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान के सम्पर्क में न लाया जाए. इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर बल दिया. उन्होंने डेविड हेयर को सहयोग देकर 1817 ई. में कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज की स्थापना कराई. अपने खर्चे से 1817 ई. में ही कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल भी खुलवाया. वे अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से व उसे आधार बनाकर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को भी उजागर करना चाहते थे. अतः उन्होंने 1825 ई. में कलकत्ता में एक वेदांत कॉलेज की भी स्थापना कराई, जहाँ पाश्चात्य दर्शन के साथ-साथ भारतीय दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी. अपने विचारों को तेजी के साथ जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका 'संवाद कौमुदी' का प्रकाशन भी आरम्भ किया.

राजनीतिक क्षेत्र में योगदान–राजा राममोहन राय ने सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने बंगाल के किसानों को भू-स्वामियों के अत्याचारों से मुक्त कराने, किसानों के लिए लगान की राशि तय करने, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने, भारतीय वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क कम करने, उच्च सेवाओं के भारतीयकरण, न्यायिक स्वतन्त्रता एवं समानता, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्कीकरण, मुकदमों की सुनवाई के लिए जूरी की व्यवस्था, प्रेस की स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और समानता जैसे मुद्दों को जनहित के सामने उठाकर सोए हुए समाज में जागृति लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया.

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के समर्थक–राजा राममोहन राय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रबल समर्थक थे. इसीलिए उन्होंने विश्व में होने वाले अनेक जगह स्वतन्त्रता, जनतंत्र और राष्ट्रीय आन्दोलनों को अपना समर्थन दिया. उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों की उनके अत्याचारों को लेकर भर्त्सना की. इतना ही नहीं उन्होंने यहाँ तक भी कहा–"अगर संसद रिफार्म बिल पास कराने में असफल रही तो वे ब्रिटिश साम्राज्य छोड़कर चले जाएंगे." अपने विचारों का प्रचार करने के मकसद से वे एक बार 1830 ई. में इंग्लैण्ड भी गए और भारत में सुधारों के समर्थन में जनमत तैयार किया. उनकी यह भी इच्छा थी कि एक 'अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस' की स्थापना हो.

देवेन्द्रनाथ ठाकुर का योगदान–राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की देखरेख का कार्य पंडित रामचंद्र विद्यावागीश के जिम्मे आया, परन्तु एक योग्य नेता के अभाव में इस समाज के सदस्यों की संख्या में कमी आती चली गई. इस संस्था को पुनर्जीवित करने का श्रेय रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर को जाता है. 1842-43 ई. में वे ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए. उन्होंने "तत्वबोधिनी सभा" की स्थापना की तथा 'तत्वबोधिनी पत्रिका' का प्रकाशन भी किया. उन्होंने ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आन्दोलन के रूप में आगे बढ़ाया. अब ब्रह्म समाज का आधार धर्मग्रंथ के स्थान पर "मानव हृदय के आत्म अनुभव से उत्पन्न आध्यात्मिक ज्ञान" बन गया. मूर्तिपूजा, कर्मकांड तथा बाहरी दिखावे के वे प्रबल विरोधी थे. 1856 ई. में देवेन्द्रनाथ ठाकुर समाज का भार केशवचंद्र सेन पर छोड़कर स्वयं अध्ययन-मनन के लिए चले गए.

केशवचंद्र सेन का योगदान–केशवचंद्र सेन ने इस संस्था के विस्तार में अपना भरपूर योगदान दिया. इनके समय में ब्रह्म समाज की शाखाएँ यू.पी., पंजाब और मद्रास में भी खुल गईं. चूँकि ये बहुत अधिक उदारवादी थे, इसलिए इनके समय में समाज में विघटन भी बहुत जल्दी हुआ. 1865 ई. में देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने इन्हें ब्रह्म समाज के आचार्य पद से हटा दिया. इसकी परिणति यह हुई कि ब्रह्म समाज दो वर्गों में बँट गया. प्रथम–भारतवर्षीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज. भारतीय ब्रह्म समाज सेन के समर्थकों का था, तो आदि ब्रह्म समाज ठाकुर के समर्थकों का. आचार्य पद से विमुख होने के बाद भी सेन अपने विचारों का प्रसार-प्रचार करते रहे. उनके प्रयासों से 1872 ई. में ब्रह्म मैरिज एक्ट तैयार हुआ, जिससे अंतर्जातीय तथा विधवा विवाह को मान्यता मिली. लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए विवाह के लिए आयु 18 वर्ष रखी गई. इसमें एक विरोधाभास यहाँ उत्पन्न हुआ कि 1818 ई. में उन्होंने अपनी लड़की का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही कूचविहार के 16 वर्षीय राजकुमार के साथ कर दिया, इसका नतीजा यह हुआ कि इससे दल में फूट पड़ गई और एक नया दल 'साधारण ब्रह्म समाज' का गठन हुआ.

स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण मिशन–ब्रह्म समाज के बाद नवजागरण लाने में सबसे श्रेष्ठ भूमिका निभाई रामकृष्ण मिशन ने और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकान्द. उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के एक मन्दिर (दक्षिणेश्वर) के पुजारी थे. उनके अनुसार भगवान को पाने के लिए निःस्वार्थ भक्ति का होना आवश्यक है.

विवेकानंद का असली नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था. उनका जन्म 1863 ई. में कलकत्ता में हुआ था. उन्होंने अपने गुरु के उपदेश को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो

तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो. उनका कहना था कि "हममें से अधिकतर न वेदांती हैं, न पुराणपंथी और न तांत्रिक ही". हम केवल "छुओ नहीं" कहने वाले हैं. हमारा धर्म रसोईघर में है. हमारा ईश्वर खाना पकाने के वर्तन में है और हमारा धर्म है "मुझे छुओमत", "मैं पवित्र हूँ". उनका कहना था कि "यदि ऐसी स्थिति एक शताब्दी तक चल गई तो हम सब पागलखाने में होंगे". वे दीन-दुखियों की सेवा को ही प्रभु सेवा मानते थे. 1893 ई. में कन्याकुमारी की यात्रा के दौरान उन्हें यह आभास हुआ कि भारत का विकास धार्मिक प्रचार से नहीं, अपितु भारतीयों की गरीबी दूर करके ही होगा. 1893 ई. में ही उन्होंने शिकागो (अमरीका) में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया तथा वेदांत पर अपना मंतव्य प्रस्तुत किया. वेदांत दर्शन के प्रचार के लिए वे 1896 ई. में न्यूयार्क गए और वहाँ 'वेदांत सोसाइटी' की स्थापना की. वापस आकर जनकल्याण की दृष्टि से 1896-97 ई. में 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की. इसका प्रमुख केन्द्र कलकत्ता के बेलूर मठ को बनाया गया. बाद में इसकी विभिन्न संस्थाएँ भारत के विभिन्न भागों में तथा विदेशों में भी खुलीं. इस संस्था के द्वारा कई स्कूलों की स्थापना की गई, अस्पताल खोले गए तथा अनाथालय वगैरह बनवाए गए. विवेकानंद ने सही मायने में भारतीयों के आध्यात्मिक, नैतिक और शारीरिक विकास पर बल दिया. उन्होंने भारतीय साहित्य तथा दर्शन को जिस आयाम तक पहुँचाया, उसकी बराबरी आज तक किसी ने नहीं की. जुलाई, 1902 ई. में स्वामीजी की मृत्यु हो गई. उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आज भी अपने उद्देश्यों को बखूबी अंजाम दे रहा है.

भारत के अन्य भागों में सुधार आन्दोलन–भारत में बंगाल के अलावा अन्य भी अनेक स्थानों पर सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन हुए. इन सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आन्दोलनों में उपर्युक्त वर्णित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं ने भी अपना महती योगदान दिया. जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं–

प्रार्थना सभा–बंगाल में हुए आन्दोलनों की तरह महाराष्ट्र में भी सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों की प्रक्रिया चल पड़ी. 1837 ई. में प्रकाशित एक पत्रिका द्वारा मराठा ब्राह्मणों का ध्यान विधवा विवाह की ओर आकृष्ट किया गया. 1849 ई. में परमहंस मंडली नामक एक आस्तिक समाज का गठन किया गया. इसी क्रम में छात्र साहित्यिक और वैज्ञानिक समिति जैसी संस्थाओं ने भी सामाजिक सुधार में अपना योगदान दिया. गोपाल हरिदेशमुख 'लोकहितवादी', ज्योतिबा फुले और दादाभाई नौरोजी जैसे सुधारकों ने भी इस प्रयास में अपना सहयोग प्रदान किया. दादाभाई नौरोजी ने अन्य लोगों के सहयोग से 1851 ई. में रहनुमाई माजदायासन अथवा धार्मिक सुधार परिषद् की स्थापना की.

महाराष्ट्र में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार लाने में "प्रार्थना समाज" का सबसे बड़ा हाथ रहा. इसकी स्थापना 1867 ई. में बम्बई में हुई थी. केशवचंद से प्रेरणा पाकर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने इस संस्था की स्थापना की. इस समाज का एक ही उद्देश्य था एकेश्वरवाद को प्रश्रय देना तथा धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को मिटाना. अस्पृश्यता, जातिप्रथा तथा छुआछूत का विरोध किया और विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, स्त्री शिक्षा, दलितों के उद्धार को इसने जायज ठहराया. इस समाज के प्रसार-प्रचार में आर. जी. भंडारकार, जस्टिस महादेव गोविन्द राणाडे तथा विरेशालिंगम इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. इनके बाद गोखले, तिलक तथा गणेश अगारकर जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति भी इसमें शामिल हो गए. इनके प्रयासों से 1884 ई. में "दक्कन एजुकेशन सोसायटी" तथा फर्ग्यूसन एवं वेलिंगडन जैसे कॉलेजों की स्थापना की गई. प्रार्थना समाज भले ही ब्रह्म समाज से प्रभावित रहा हो, परन्तु था इससे भिन्न. इसने न तो ईसाई मिशनरियों से सम्पर्क किया और न ही हिन्दू धर्म से. इसी का परिणाम था कि यह ब्रह्म समाज से कहीं अधिक सफल रहा अपने उद्देश्यों में.

श्रीमती ऐनीबेसेंट और थियोसोफिकल सोसाइटी–समाज सुधार तथा धार्मिक क्षेत्र में थियोसोफिकल सोसाइटी ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया. इसकी स्थापना 1875 ई. में न्यूयार्क में की गई. इसकी स्थापना का श्रेय एक रूसी महिला ब्लावेट्स्की तथा एक अमरीकन कर्नल एम. एस. ऑल्काट को है. भारत में इसकी शाखा सर्वप्रथम मद्रास के निकट अड्यार में 1886 ई. में खोली गई. भारत में इस संस्था को पुष्पित-पल्लवित करने का प्रयास श्रीमती ऐनीबेसेंट नामक एक आयरिश महिला ने किया. वे 1893 ई. में भारत में आईं और यहीं बस गईं. उन्होंने भारतीय तौर-तरीके, वस्त्र, भोजन आदि सभी कुछ अपना लिया और एक विशुद्ध हिन्दू बन गईं. ऐनीबेसेंट के प्रयासों से ही बनारस में सेन्ट्रल स्कूल खोला गया, जोकि आगे चलकर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ. 1916 ई. में होमरूल लीग की स्थापना करके राष्ट्रीय आन्दोलन को भी प्रभावित किया.

स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज–स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज ने विशेषरूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश में अपनी विशेष भूमिका अदा की. पाश्चात्य प्रभावों के बढ़ते प्रभावों की प्रतिक्रियास्वरूप आर्य समाज की स्थापना की गई थी. इनका बचपन का तथा मूल नाम मूलशंकर था. इनका जन्म 12 फरवरी, 1824 ई. में सौराष्ट्र में राजकोट के समीप मौरवी जनपद के टंकारा ग्राम में एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनके प्रारम्भिक जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव था. युवावस्था आने तक उनके विचारों में आमूलचूक परिवर्तन आया. वे घर छोड़कर

आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़े. 1859 ई. में उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से दीक्षा ग्रहण की. उन्होंने अपने गुरु के आदेशानुसार वैदिक धर्म का प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया. 1863 ई. में उन्होंने आगरा से 'पाखंड खंडिनी पताका' लहराई. 1875 ई. में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की. 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक ग्रंथ से उन्होंने अपने विचारों को जनता के समक्ष रखा तथा "वेदों की ओर चलो" का नारा बुलन्द किया. उनके सिद्धान्तों से प्रभावित होकर भारत के अनेक क्षेत्रों में आर्य समाज की शाखाएँ खुलीं. आगे चलकर लाहौर आर्य समाज का प्रमुख केन्द्र बन गया. व्यापारी वर्ग से इस समाज को व्यापक समर्थन मिला. 1891 ई. में जहाँ इसके सदस्यों की संख्या 40 हजार थी वहीं यह 1901 ई. में बढ़कर 92 हजार तक पहुँच गई. 1883 ई. में स्वामीजी की मृत्यु हो गई और आर्य समाज को अपूरणीय क्षति हुई. 1893 ई. में आर्य समाज दो दलों में बँट गया. इस फूट तथा दो दल बनने की वजह मांसाहारी व शाकाहारी भोजन तथा अंग्रेजी और संस्कृत शिक्षा का प्रश्न था.

आर्य समाज का दर्शन और कार्य–आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की सर्वोच्चता, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे. "वेदों के ऊपर बढ़ी हुई सभी शाखाओं को वे छाँट देना चाहते थे". पुराणों में उनकी आस्था नहीं थी. उनके मतानुसार, "पुराण स्वार्थी, अज्ञानी और दुष्ट व्यक्तियों की रचनाएँ हैं". उनका मानना था कि दुनिया का सम्पूर्ण ज्ञान वेदों में ही निहित है. धार्मिक कर्मकांडों, तीर्थयात्रा, बलि तथा हिन्दू संस्कारों के वे कतई खिलाफ थे. दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा को भी उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया. वे विधवा विवाह, नारी शिक्षा व विदेश यात्रा करने के समर्थक थे. उन्होंने सभी जातियों को वेद पढ़ने के लिए प्रेरित किया. किसी भी प्रकार का जातीय व वर्ण का बन्धन नहीं था. स्वामीजी के दस सिद्धान्त जगत् प्रसिद्ध हैं, जोकि निम्नलिखित हैं–

1. सभी सत्य विद्या का आदि मूल ईश्वर है.

2. ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक होने के साथ ही पवित्र है.

3. वेदों में ही सच्चा ज्ञान निहित है. अतः सभी को वेदों का अध्ययन करना चाहिए.

4. सत्य को ग्रहण करने तथा असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए.

5. सभी कार्य धर्मानुसार ही होने चाहिए.

6. आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य संसार का उपकार करना है.

7. सबसे प्रेमपूर्वक, धर्मानुसार व यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए.

8. अविद्या का नाश और विद्या का विकास करना चाहिए.

9. सबको सभी की उन्नति के लिए प्रयास करने चाहिए.

10. सभी मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी नियम का पालन करना चाहिए.

सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज की सबसे बड़ी देन यह है कि इसने जाति व्यवस्था की संकीर्णता को दूर करने का प्रयास किया. सभी वर्णों को समान अवसर प्रदान करने तथा स्त्रियों की दशा सुधारने के विशेष प्रयास किए गए. बाल-विवाह, बहु-विवाह, बलि प्रथा जैसी कुरीतियों को मिटाने के भरसक प्रयास किए गए. हिन्दू जाति के उत्थान व उसकी सुरक्षा के लिए इसे संगठित किया गया. आर्य समाज ने शिक्षा के प्रचार के लिए भी प्रयास किए. स्वामीजी की मृत्यु के बाद लाहौर में डी. ए. वी. कॉलेज की स्थापना की गई. इसकी स्थापना के बाद और भी स्कूल खुले. गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के लिए भी स्कूल खोले गए. इसका प्रमुख केन्द्र गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार था, जहाँ वैदिक शिक्षा एवं अनुशासन पर बल दिया गया. आर्य समाज ने विदेशी दासता का भी विरोध किया. हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में अथक सहयोग दिया. इस प्रकार, आर्य समाज ने "पुनरुत्थानवादी आन्दोलन" को जन्म दिया.

मुसलमानों में सुधार आन्दोलन–हिन्दू धर्म के साथ-साथ ही मुसलमान, सिख, पारसियों में भी सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलन हुए. इनमें प्रमुख निम्नलिखित थे–

अलीगढ़ आन्दोलन–वहाबी आन्दोलन राजनीति से ज्यादा प्रेरित था. इसने मुसलमानों की स्थिति सुधारने में कोई खास प्रयास नहीं किया, परन्तु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मौलवी चिराग अली ने मुस्लिम सम्प्रदाय में स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के प्रयास किए. शिक्षा में सुधार लाने की दृष्टि से 1863 ई. में कलकत्ता में 'मुहम्मडन लिटररी सोसाइटी' की स्थापना की गई. 1867 ई. में देवबंद में मदरसा की स्थापना की गई. सबसे बड़े मुस्लिम सुधारक सर सैयद अहमद खाँ थे. उनके साथ अल्ताफ हुसैन, नजीर अहमद, मौलाना शिब्ली नूमानी आदि भी थे. उन्होंने एक 'सुधारवादी आन्दोलन' चलाया, जिसका केन्द्र अलीगढ़ था, इसी वजह से इसे अलीगढ़ आन्दोलन भी कहते हैं.

सैयद अहमद खाँ का व्यक्तित्व व कृतित्व–सर सैयद अहमद खाँ का जन्म 1817 ई. में दिल्ली के एक सम्भ्रान्त एवं समृद्ध परिवार में हुआ था. वे सरकारी सेवा में थे. सरकारी सेवा में होने के नाते वे अंग्रेजी सरकार के हिमायती थे, परन्तु इसके बावजूद वे मुसलमानों की उन्नति के लिए प्रयासरत थे. उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार एवं मुसलमानों की स्थिति को ऊपर उठाने का पुरजोर समर्थन किया. वे मुसलमानों को

आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे. अपने विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए 1870 ई. में उन्होंने उर्दू पत्रिका 'तहजीव उल अखलाक' का प्रकाशन आरम्भ किया. मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के प्रचार के लिए 1875 ई. में मुहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की.

हालांकि वे मुसलमानों का उत्थान करना तो चाहते थे, परन्तु उनमें कुछ प्रतिक्रियावादी भावनाएँ विद्यमान थीं. वे पर्दा प्रथा तथा बहुविवाह को भी बुरा नहीं मानते थे. ईस्वी 1888 में उन्होंने 'यूनाइटेड इण्डिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन' की स्थापना की. उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस का विरोध करना था. उन्होंने मुसलमानों को एक अलग वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया और विशेष राजनीतिक सुविधाओं एवं आरक्षण की माँग की. इसके दूरगामी परिणाम अत्यन्त ही भयंकर निकले. इसने साम्प्रदायिकता और पृथकतावाद को जन्म दिया. इसके बावजूद मुस्लिम समाज को शिक्षित करना, उसे आधुनिक बनाना और अपने अधिकारों के प्रति जाग्रत करना उनकी सुधारों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी.

अहमदिया आन्दोलन–अलीगढ़ आन्दोलन के अतिरिक्त अहमदिया आन्दोलन ने भी मुसलमानों की स्थिति को सुधारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. इस आन्दोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी थे. इस आन्दोलन का केन्द्र पंजाब के गुरुदासपुर जिले का कादियां नगर था. उन्होंने अपने विचारों को अपनी पुस्तक बराहीन-ए-अहमदिया में प्रकाशित किया (1880 में).

इन आन्दोलनों के अलावा मुसलमानों के मध्य अंजुमन हिमायते-इस्लाम, नदवतुल-उलेमा, खुदाई खिदमतगार आन्दोलन एवं खाकसार आन्दोलनों का भी प्रादुर्भाव हुआ. मुसलमानों की तरह पारसियों के बीच 1851 ई. में स्थापित रहनुमाई माजदायासन सभा ने भी व्यापक समाज सुधार के कार्य किए.

मध्यम वर्गों का उदय–समाज को अनुप्रस्थ ढंग से विभाजित करने पर बनने वाला मध्यम वर्ग का वह मिश्रित तथा निचला भाग जिसमें कमोवेश एक ही रुतवे या ओहदे के लोग रहते हैं, मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता था. वैचारिक दृष्टिकोण से यह सामाजिक वर्ग बौद्धिक स्वतन्त्रता, सामाजिक गतिशीलता, उदारवादी, व्यक्तिवाद तथा राजनीतिक जनतंत्र में विश्वास रखता था. भारत में आधुनिक मध्यम वर्ग का उदय अंग्रेजी शासनकाल में हुआ. अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप ही सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ. भारत में मध्यम वर्ग का विकास यूरोपीय देशों में हुए मध्यम वर्ग के विकास से भिन्न था. पश्चिम में विशेषकर इंग्लैण्ड में मध्यम वर्ग का उदय मूलतः आर्थिक तथा तकनीकी कारणों से हुआ और इस वर्ग के सदस्य मूलतः व्यवसायों तथा उद्योगों से सम्बन्धित रहे.

मध्यम वर्ग के उपवर्ग–मध्यम वर्ग के चार उपवर्ग मुख्य हैं. भाषा की समस्या तथा हुकूमत के एजेंट के रूप में काम करने वाले एक वर्ग के रूप में अंग्रेजों ने नवीन भारतीय मध्यम वर्ग के उदय को एवं इसके विकास को प्रोत्साहित किया. ये निम्नलिखित थे–व्यावसायिक मध्यम वर्ग, औद्योगिक मध्यम वर्ग, भूमि से सम्बन्धित मध्यम वर्ग और शिक्षित मध्यम वर्ग.

व्यावसायिक वर्ग–इसके अन्दर व्यापार तथा व्यवसाय से सम्बन्धित लोग आते थे. जैसे–दुकानदार, आढ़ती, मैनेजर, गुमाश्त, मुनीम, सर्राफ आदि इसी के अन्तर्गत आते थे.

औद्योगिक वर्ग–इस वर्ग के अन्तर्गत साधारणतः ऐसे लोगों की गणना होती थी जो वर्गीय दृष्टि से मध्यम वर्ग के अन्तर्गत होते हुए भी विभिन्न उद्योग-धन्धों से जुड़े हुए थे. इसमें छोटे उद्योगों के मालिकों तथा उद्योगों में कार्यरत शिल्पियों, दक्ष कारीगरों, विशेषज्ञों, श्रमिकों के कल्याण, सुविधा, सुरक्षा के लिए कार्यरत विभिन्न अधिकारी, निरीक्षक तथा लिपिक वर्ग के व्यक्तियों को स्थान दिया जाता था.

भूमि से सम्बन्धित वर्ग–इस वर्ग में भूमि से सम्बन्धित मध्यम वर्ग का स्वरूप मध्यम वर्ग के अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक रूढ़ और अगतिशील होता है. इस वर्ग में गतिशीलता का समावेश तब हुआ जब अंग्रेज भारत में आए. जमींदारों, जागीरदारों और सम्पन्न किसानों के अतिरिक्त महाजन और बनिये भी भूमि से सम्बन्धित मध्यम वर्ग के रूप में उभरकर सामने आए.

शिक्षित वर्ग–इस वर्ग का उदय 1857 ई. के महान् विप्लव के पश्चात् माना जाता है. इस वर्ग के अन्तर्गत अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एवं नौकरी करने वाले व्यक्ति आते थे, जो अंग्रेजी अमलदारी या अन्य रूप में काम करते थे. इनमें प्रमुख रूप से वकील, जज, मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षक, मुख्तार तथा क्लर्क आदि को सम्मिलित किया जाता था.

मध्यम वर्ग का योगदान–भारतीय सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास में मध्यम वर्ग का अपना एक अलग योगदान रहा है. 19वीं शताब्दी में कम्पनी शासन की समाप्ति एवं ब्रिटिश ताज के शासन के वर्षों में भी वाणिज्य व्यवसाय के अतिरिक्त शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में इस वर्ग का योगदान अपने आप में एक मिसाल कहा जा सकता है. पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, राजाराम मोहनराय, केशवचंद्र सेन इत्यादि मध्यम वर्ग में ही आते थे. आधुनिक भारत के निर्माण में इनका बहुत योगदान रहा. राजाराम मोहनराय तो आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं. राष्ट्र निर्माण एवं समाज सुधार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं एवं भूमिकाओं में क्रियाशील एवं अवतरित होने

का श्रेय मध्यम वर्ग को ही जाता है. अनेक प्रगतिशील एवं समाज सुधारक संस्थाओं का जन्म इसी मध्यम वर्ग में हुआ. ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसायटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी आदि समाज सुधारक संस्थाएँ इसी मध्यम वर्ग की देन हैं, जिन्होंने समाज में एक नई दिशा एवं जनजागृति लाने में अहम भूमिका निभाई. पराधीनता की पृष्ठभूमि में मध्यम वर्ग, विशेषकर शिक्षित मध्यम वर्ग का मुख्य कार्य सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विरासत को विकसित एवं पुनः प्रतिष्ठित करना था. इस कार्य को इस वर्ग ने बखूबी अंजाम दिया. इस वर्ग की अंग्रेजी शासन के प्रति शुरू में अच्छी भावनाएँ थीं. अमूमन लोग इस बात में गौरव का अनुभव करते थे कि अंग्रेज उनके शासक हैं. इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण मध्यम वर्ग लम्बे समय तक अंग्रेजों का आधार स्तम्भ बना रहा. कालान्तर में यह वर्ग अंग्रेजी शासकों की आर्थिक नीतियों के चलते उनसे विमुख हो गया. अंग्रेजों की प्रजातीय भेदभाव की नीति, भारतीयों से गुलाम सदृश व्यवहार, सरकारी नौकरियों में पक्षपात, भारत को ब्रिटेन के आर्थिक उपनिवेश में परिवर्तित कर देने की अंग्रेजों की मंशा, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों एवं दर्शनों के प्रभाव में आकर यह वर्ग अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगा. कांग्रेस जैसी महान् राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था का जन्म मध्यम वर्ग के समर्थन के फलस्वरूप ही सम्भव हुआ. कांग्रेस की स्थापना के साथ भारत में जिस राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, उसमें भारतीय पूँजीपति, कुछ प्रगतिशील जमींदारों, नए उद्योगपतियों तथा धनी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अर्थात् उच्च मध्यम वर्ग के लोगों ने ही भाग लिया. भारत का जनसाधारण वर्ग अर्थात् किसान, मजदूर तथा निम्न मध्यम वर्ग प्रारम्भ में राष्ट्रीय आन्दोलन एवं कांग्रेस से अलग ही रहा, हालांकि बाद में वह भी इसमें सम्मिलित हो गया था.

इसी प्रकार मुस्लिम लीग में यद्यपि प्रारम्भ में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं रही, परन्तु बाद में यह वर्ग मुस्लिम राजनीति में प्रमुख बन गया. उग्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रीय आन्दोलनों में भी मध्यम वर्ग की ही भूमिका उभरकर सामने आई. खुदीराम बोस, चंद्रशेखर तथा सरदार भगतसिंह जैसे क्रांतिकारी मध्यम वर्ग से ही आए थे. इनके कार्यकर्ता और नेता मुख्यतः पढ़े-लिखे नौजवान, गरीब और बेरोजगार विद्यार्थी, कम वेतन पर काम करने वाले बुद्धिजीवी आदि थे. स्वदेशी आन्दोलन के प्रणेता तथा कार्यकर्त्ता भी मध्यम वर्ग के ही थे. होमरूल आन्दोलन के सूत्रधार भी मध्यम वर्ग के ही लोग थे. हालांकि असहयोग आन्दोलन को जन आन्दोलन कहा जाता था, परन्तु मुख्य रूप से इस आन्दोलन के प्रणेता मध्यम वर्ग से ही थे. असहयोग आन्दोलन से लेकर स्वतन्त्रता की प्राप्ति तक जितने भी राजनीतिक तथा रचनात्मक आन्दोलन हुए सभी में मध्यम वर्ग के लोगों की, मुख्य रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग की, भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण रही. मध्यम वर्ग ने न सिर्फ राष्ट्रीय आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि सक्रिय रूप से इसमें भाग भी लिया. मध्यम वर्ग के प्रयासों से ही जनसाधारण में राजनीतिक चेतना आई. इसी प्रकार सामाजिक कुप्रथाओं के उन्मूलन, शिक्षा के प्रसार, हरिजनोद्धार तथा नए भारत के निर्माण जैसे कार्यों में भी इस वर्ग की भूमिका सराहनीय रही है. 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही. भारत को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए जितने भी राष्ट्रीय आन्दोलन हुए सभी में मध्यम वर्ग का ही हाथ प्रमुख रूप से रहा.

प्रेस की स्थापना–आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारम्भ 1766 ई. में विलिप बोल्ट्स द्वारा एक समाचार-पत्र के प्रकाशन से हुआ, परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उनको इंग्लैण्ड भेज दिया. 1780 ई. में जे. के. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार-पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया. हिक्की को कम्पनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी, परन्तु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली. हिक्की के प्रेस को कम्पनी ने जब्त कर लिया और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हो गया. नवम्बर 1780 ई. में प्रकाशित इण्डिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था. 18वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल में कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर तथा ओरियंटल स्टार, बम्बई गजट तथा हेराल्ड और मद्रास में मद्रास कैरियर, मद्रास गजट आदि समाचार-पत्र प्रकाशित होने लगे थे. इन समाचार-पत्रों की विशेषता यह थी कि ये एक-दूसरे के पूरक थे. ये सभी समाचार-पत्र साप्ताहिक थे. अंग्रेजी समाचार-पत्रों में भारतीय हितों के पोषण तथा संरक्षण का अभाव था, परन्तु पाठकों के मनोरंजन का पूर्ण ध्यान रखा जाता था. भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार-पत्रों में अधिक स्थान उन विषयों पर दिया जाता था जिनके अध्ययन से भारतीय सार्वजनिक विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकें.

प्रेस की भूमिका एवं प्रभाव–राष्ट्रीय भावना के उदय एवं विकास में, तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रत्येक पहलू के विषय में, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक, प्रेस की भूमिका उल्लेखनीय रही है. प्रेस ने जनता को आवश्यक राजनीतिक शिक्षा दी. प्रेस के ही माध्यम से विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने अपने विचारों को आम जनता तक फैलाने में सफलता प्राप्त की. सरकार की वास्तविक नीति को, उसकी दोहरी चालों को, उसके द्वारा भारतीयों के शोषण को सबके समक्ष रखने वाला तथा सरकार की कटु आलोचना को जनता तक पहुँचाने वाला माध्यम प्रेस ही था. विभिन्न नेताओं द्वारा प्रेस की स्थापना तथा समाचार-पत्रों का सम्पादन इसका सूचक है कि प्रेस को

महत्वपूर्ण संस्था माना जाता था. जनता के बीच प्रेस की रचनात्मक भूमिका को समझते हुए उसे राष्ट्र का एक अभिन्न अंग बना लिया गया था. प्रेस ने सभी ज्वलन्त समस्याओं को समझते हुए प्रभावशाली रूप से उन्हें प्रकाशित किया. उस युग का मुख्य उद्देश्य जनजागरण था. इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रेस की भूमिका उल्लेखनीय रही. विदेशी सत्ता से त्रस्त जनता को सन्मार्ग दिखाने, साम्राज्यवाद के विरोध में निर्भीक स्वर उठाने का कार्य प्रेस के माध्यम से ही सम्भव हुआ.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले समाचार-पत्र देश में लोकमत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. पत्रकारिता के साथ अनेक प्रतिष्ठित देशभक्तों तथा जाने-माने नेताओं का नाम जुड़ा था. शिक्षित भारतीय पत्रकारिता को अपना बहुमूल्य समय देकर समाचार-पत्रों के माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना कर तथा विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर देशवासियों को सरकार के विभिन्न कार्यों तथा देश की समकालीन स्थिति से अवगत करवाते थे. देशभक्तों ने अपने लाभ या व्यावसायिक दृष्टि से पत्रकारिता को नहीं अपनाया. उन्होंने इसे देश सेवा का एक सशक्त माध्यम बनाया. भारतीय समाचार-पत्रों ने लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया था. काफी समाचार-पत्र सरकार की तीखी आलोचना करने लगे थे. कांग्रेस को एक सशक्त राजनीतिक संस्था बनाने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी. इन समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले लेखों में राष्ट्रीय भावना भरी होती थी. होने वाली आम सभाओं के विज्ञापन इन समाचार-पत्रों में धड़ल्ले से छपते थे. जनता को उत्साहित करने में तथा उसके विचारों में क्रांति लाने के लिए समाचार-पत्रों ने एक पुल का काम किया. इन समाचार-पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी सदैव जनसम्पर्क में बने रहते थे. पूरे वर्ष हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में कांग्रेस के अधिवेशनों में पेश किए गए प्रस्तावों तथा माँगों पर चर्चा होती रहती थी. इन माँगों को बार-बार दुहराकर सरकार तथा जनता को प्रेस प्रभावित करता रहता था. इससे राष्ट्रीय चेतना का प्रचार-प्रसार तेज गति से होने लगा था. नई शिक्षा के परिणामस्वरूप लोगों की विचारधारा अवश्य बदली, परन्तु जो असन्तोष जन-जीवन में व्याप्त था, उसको सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य प्रेस ने ही किया. अंग्रेजी शासकों का वास्तविक रूप पत्रकारों के माध्यम से ही जनता के समक्ष आ सका.

अंग्रेजों द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, उसके विरुद्ध प्रेस ने भी आवाज उठाई. 1904-05 ई. के रूसी-जापान युद्ध में एक एशियाई देश (जापान) की, जोकि रूस की तुलना में अत्यन्त छोटा था, रूस जैसे विशाल एवं शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध युद्ध में विजय ने भारतीय प्रेस तथा जनता को नया जीवन एवं आशा प्रदान की. रूस के मध्य एशिया में बढ़ते हुए प्रभाव का लाभ भारतीय समाचार-पत्रों ने खूब उठाया. इससे भारतवासियों को अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने का अच्छा अवसर मिला.

बढ़ते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन के हर चरण को, उसके प्रत्येक पहलू एवं राजनीतिक गतिविधियों को प्रेस ने प्रमुखता दी. देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा राष्ट्र निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही. राष्ट्रीय आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने, उसके प्रत्येक रूप को विकसित करने, जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं से अवगत कराने, सरकार की नीतियों की समीक्षा कर जनता को प्रभावित करने, जनमत निर्माण तथा विभिन्न दलों के विचारों से भारतीयों को परिचित कराने, देश के विभिन्न भागों में सामाजिक वर्गों के बीच व्यापक विचारों का आदान-प्रदान करने, प्रादेशिक लोगों के मध्य एक मानसिक सम्बन्ध स्थापित करने, राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों को सफल बनाने, प्रादेशिक संस्कृतियों तथा साहित्य का विकास करने, विभिन्न कुरीतियों को दूर करने, जनतांत्रिक पुनर्निमाण के कार्यक्रमों से लोगों को अवगत कराने, संसार में होने वाली घटनाओं से भारतवासियों को परिचित कराने, देश के विभिन्न भागों में सामाजिक वर्गों के मध्य व्यापारिक विचारों का आदान-प्रदान कराने, राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों को सफल बनाने, प्रादेशिक संस्कृतियों तथा साहित्य का विकास करने तथा संसार में होने वाली घटनाओं से भारतवासियों को परिचित कराने और उन पर अपनी विचारधारा निर्मित करने और जनता के विचारों से सरकार को अवगत कराने का महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्य उस काल के प्रेस ने अत्यन्त कुशलता तथा सफलता से पूरा किया. इसी प्रकार से भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का प्रेस पर तथा प्रेस के माध्यम से सम्पूर्ण देश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा. भारतीय भाषाई समाचार-पत्रों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया. एक ओर जहाँ समाचार-पत्रों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा था, वहीं दूसरी ओर इस अधिनियम का एक अत्यन्त लाभकारी प्रभाव भी पड़ा था, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी. इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों में एक नई चेतना का संचार हुआ.

लॉर्ड कर्जन की बंगाल विभाजन की योजना तथा बाद में बंगाल विभाजन ने भारतीय समाचार-पत्रों को नया जीवन दिया तथा सरकार की नीति की आलोचना को एक नया एवं महत्वपूर्ण मसाला तैयार कर दिया. सभी समाचार-पत्रों में बंगाल विभाजन की कटु आलोचना की गई. फिर भी विरोध एवं लोकमत की उपेक्षा करते हुए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करके सरकार तथा समाचार-पत्रों को स्पष्ट तथा खुले संघर्ष का अवसर प्रदान किया. कर्जन की नीति की प्रायः सभी समाचार-पत्रों ने कटु आलोचना की. 1911 ई. में हिन्दू प्रेस के साथ-साथ मुस्लिम प्रेस ने भी ईसाईयों के विरुद्ध

हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता लाने का जो प्रयास किया वह उल्लेखनीय था. निजाम-उल-मुल्क तथा अखबारे आम ने ईसाई सरकार के विरुद्ध एक संगठित जनमत बनाने का आह्वान किया. भारतीय भाषाओं के पत्रों की स्थापना एवं विकास के परिणामस्वरूप ही जनमत का निर्माण एवं विकास सम्भव हो सका था. जनमत को अत्यन्त प्रभावकारी रूप में प्रतिबिंबित भी वे ही पत्र करते थे.

इस प्रकार भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीयता के प्रचार-प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया. इसने भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोने, आपसी सहमति के क्षेत्र के विस्तार में, विभिन्न समुदायों के बीच के विरोध और वैमनस्य को दूर करने, विभिन्न राष्ट्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उपाय सुझाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई. यह जनमत का प्रबल उत्प्रेरक और साम्राज्य विरोधी भावना का मुखर वाहन बन गया. कानून के संकुचित दायरे और सरकारी दमन के बावजूद इसने अभिव्यक्ति के नए-नए मार्ग ढूँढ़कर लोगों में राजनीतिक चेतना फैलाई तथा अन्याय से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया. निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रेस हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का भारी स्तम्भ बन गया.

स्मरणीय तथ्य

- आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ यूरोपीय जातियों के आगमन से माना जाता है.
- भारत में आने वाले पुर्तगाली पादरियों में फ्रांसिस जेवियर मुख्य था, जिसने 1542 ई. में अनेक स्कूल खोले.
- 1823 ई. में ऐडम नामक एक अंग्रेज उच्चाधिकारी ने जो अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत था, सार्वजनिक शिक्षा के लिए दस सदस्यों की एक सामान्य समिति नियुक्त की.
- 1834 ई. में लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल के द्वारा तय की गई परिस्थितियों में आमूलचूक परिवर्तन किया.
- भारत में राजा राममोहन राय तथा जौहरी डेविड हेयर पश्चिमी सभ्यता के प्रचार-प्रसार के सबसे बड़े समर्थक माने जाते थे.
- मैकाले की यह मान्यता थी कि यदि उसकी शिक्षा योजना पर ढंग से कार्य किया गया तो यह निश्चित है कि तीस वर्ष पश्चात् बंगाल के सम्मानित वर्गों में एक भी मूर्तिपूजक नहीं बचेगा.
- अंग्रेजी कम्पनियों में आसानी से नौकरी मिल जाने के कारण नवयुवकों का अंग्रेजी शिक्षा के प्रति प्रेम हुआ.
- अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को ही नौकरी दी जाएगी यह निर्णय लॉर्ड हार्डिंग्स के समय 1844 ई. में लिया गया.
- आधुनिक शिक्षा का सर्वाधिक प्रसार-प्रचार लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ.
- संस्कृत तथा अन्य देशी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त युवकों को नौकरी पाना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण भी अंग्रेजी के प्रति मोह होना स्वाभाविक था.
- बंगाल में सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन 1823 ई. में हुआ.
- कलकत्ता में 1817 ई. में हिन्दू कॉलेज की स्थापना की गई, जो आगे चलकर 1854 ई. में प्रेसीडेंसी महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ.
- मैकाले का यह मानना था कि देशी तथा भारतीय शिक्षा में साहित्यकता व वैज्ञानिकता का पुट नहीं है. अतः उसने संस्कृत तथा अरबी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का विरोध करना आरम्भ कर दिया था.
- मैकाले का उद्देश्य भारत में एक ऐसे वर्ग को जन्म देना था, जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो, परन्तु विचारों से अंग्रेज हो.
- अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से प्रारम्भिक लाभ अधिकतर मध्यमवर्गीय हिन्दुओं ने उठाया.
- 1853 ई. में बनारस कॉलेज की स्थापना थॉम्पसन के द्वारा की गई.
- कलकत्ता के हिन्दू कॉलेज में कानून की शिक्षा 1842 ई. में तथा 1844 ई. में इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू की गई.
- अंग्रेजी संसद की ओर से नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट पर 1854 ई. में शिक्षा व्यवस्था का घोषणा-पत्र जारी किया गया.
- 1870-72 ई. में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 16473 थी, वहीं 1881-82 ई. में यह संख्या बढ़कर 82916 हो गई.
- जयपुर का महाराजा कॉलेज 1873 ई. में कॉलेज स्तर में तब्दील हुआ था. इससे पूर्व यह स्कूल स्तर तक ही सीमित था.
- 1875 ई. में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो आगे चलकर मुस्लिम विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया.
- पाश्चात्य शिक्षा में किसी प्रकार का जातीय बन्धन न होने के कारण ही उसका प्रसार-प्रचार तेजी से सम्भव हो सका.
- सामाजिक एवं धार्मिक आन्दोलनों की बदौलत भारतीय लोगों की धारणा में जो परिवर्तन आए, उन्हें ही पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई.

- पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि प्राचीन भारत का विस्मृत इतिहास एवं गौरव आम जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा सका.
- भले ही अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन-अध्यापन अपने हितों की दृष्टि से लागू किया था, परन्तु उसका वांछित प्रभाव भारतीय समाज पर ही पड़ा. उन्हें इस शिक्षा से नई सोच व अपने भले-बुरे का अहसास होने लगा था.
- अंग्रेजों की दोगली नीतियों के कारण ही उनका जगह-जगह पर विरोध किया जाने लगा था.
- हिन्दू समाज के पथ प्रदर्शक राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में 1774 ई. में हुआ था.
- ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ही थे, जिन्होंने अपने पथ से भटकते हिन्दू समाज को एक नया रास्ता दिखाकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया.
- इन्हीं के सहयोग से 1829 ई. में एक सरकारी कानून बनाया गया और सती प्रथा का पूर्णरूप से अंत कर दिया गया.
- राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात् ब्रह्म समाज की बागडोर कविवर गुरुदेव रबीन्द्रनाथ ठाकुर के पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने सँभाली.
- रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ई. में कलकत्ता में हुआ.
- आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के जिवपुर गाँव में 1824 ई. में हुआ था.
- मुस्लिम समाज के अग्रज कहे जाने वाले सर सैयद अहमद खाँ का जन्म 1817 ई. में दिल्ली में हुआ.
- आधुनिक भारतीय प्रेस की स्थापना 1766 ई. में हुई. सर्वप्रथम विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार-पत्र का प्रकाशन किया गया.
- प्रेस के क्षेत्र में सबसे पहला समाचार-पत्र बंगाल गजट था.
- अंग्रेजों के वृहद राजनीतिक प्रशासकीय तंत्र को चलाने के लिए शिक्षित व्यक्तियों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता थी और इतने सारे लोग सीधे ब्रिटेन से आने सम्भव नहीं थे, फलतः सुयोग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिहाज से भारत में स्कूल तथा कॉलेजों का प्रादुर्भाव हुआ.
- अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेने के कारण देशी राज्यों की शक्ति कमजोर हो चुकी थी जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षण संस्थाओं की सहायता बंद हो गई.
- अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार इतनी तेजी से हुआ कि दो वर्ष के अन्दर अंग्रेजी पुस्तकों की 31,000 प्रतियाँ बिक गईं.
- राजा राममोहन राय संस्कृत को इस देश को अंधकार में रखने वाली भाषा मानते थे.
- 1857 ई. से पूर्व का काल शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगों का काल कहा जाता है.
- अंग्रेजी संसद की ओर से नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट पर 1859 ई. में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई.
- सरकार की ओर से 7 अगस्त, 1871 ई. को पारित एक आदेशानुसार मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन आवश्यक कर दिया गया.
- 1916 ई. में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की शुरूआत की गई.
- पुनर्जागरण के प्रभाव से हिन्दू धर्म का उत्थान एवं उसको व्यापक तथा सर्वग्राही बनाया जा सका.
- धार्मिक सुधार आन्दोलनों से ही भारतीयों की धार्मिक जड़ता को समाप्त किया जा सका.
- प्राचीन भारतीय काल को 'स्वर्णिम युग' तथा मध्यकाल को 'अवनति के युग' के रूप में जाना जाता है.
- अंग्रेजी शिक्षा से जहाँ अंग्रेजों ने अपना हित तो साधा ही, उससे कहीं अधिक भारतीयों को लाभ हुआ. इस अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही नए-नए सामाजिक वर्गों ने जन्म लिया.
- बंगाल में नवचेतना लाने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 'यंग बंगाल आन्दोलन' ने किया. यह संगठन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों का समूह था.
- राजा राममोहन राय की प्रथम प्रकाशित कृति का नाम 'एकेश्वरवादियों को उपहार' है.
- 1818 ई. में राममोहन के द्वारा सती प्रथा का विरोध किया जाने लगा.
- राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही 1817 ई. में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल तथा हिन्दू कॉलेज की स्थापना सम्भव हो सकी.
- देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने 'तत्वबोधिनी सभा' की स्थापना की तथा 'तत्वबोधिनी पत्रिका' का प्रकाशन भी शुरू किया.
- आचार्य केशवचंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ई. में ब्रह्म मैरिज एक्ट तैयार किया गया, जिससे अंतर्जातीय तथा विधवा विवाहों की शुरूआत सम्भव हो सकी.
- स्वामी विवेकानंद ने 1896 ई. में न्यूयार्क में जाकर 'वेदांत सोसायटी' की स्थापना की. 1896-97 ई. में 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की.
- 1867 ई. में बम्बई में 'प्रार्थना समाज' की स्थापना की गई.

- डॉ. ऐनीबेसेंट द्वारा 1875 ई. में न्यूयार्क की थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना की गई.
- डॉ. ऐनीबेसेंट 1893 ई. में भारत में आईं और यहाँ के हिन्दू धर्म को अपना लिया और यहीं बस गईं.
- स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1863 ई. में आगरा से 'पाखण्ड खंडिनी पताका' लहराई तथा 1875 ई. में बम्बई जाकर आर्य समाज की स्थापना की.
- स्वामीजी की मृत्यु 1883 ई. में हुई.
- शिक्षा में सुधार लाने की दृष्टि से 1863 ई. में कलकत्ता में 'मुहम्मडन लिटररी सोसायटी' की स्थापना की गई.
- सर सैयद अहमद खाँ ने 1870 ई. में उर्दू पत्रिका 'तहजीब उल अखलाक' का प्रकाशन आरम्भ किया.
- भारत को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने में जितने भी राष्ट्रीय आन्दोलन हुए उनमें प्रमुख हाथ मध्यम वर्ग का ही था.
- प्रथम समाचार-पत्र बंगाल गजट का प्रथम प्रकाशन 1780 ई. में हुआ.
- प्रेस की स्वतन्त्रता तथा उसके विस्तार एवं प्रचार से ही भारतीय स्वतन्त्रता की गतिविधियों को ऊर्जा तथा प्रेरणा मिली.
- 1911 ई. में हिन्दू प्रेस के साथ-साथ मुस्लिम प्रेस ने भी ईसाईयों के विरुद्ध हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयास करना शुरू किया.

विशिष्ट स्मरणीय तथ्य

1. 1857 ई. से पूर्व के प्रमुख नागरिक विद्रोह स्थान एवं कालक्रम

क्र. सं.	नागरिक विद्रोह	स्थान	कालक्रम
1.	संन्यासी विद्रोह	बिहार, बंगाल	1763-1800 ई.
2.	चुआर विद्रोह	बिहार, बंगाल	1766-1772 ई.
3.	विजयनगरम् विद्रोह	दक्षिण भारत	1794 ई.
4.	पायरस्सी राजा का विद्रोह	केरल	1799-1805 ई.
5.	वजीर अली का विद्रोह	अवध	1799 ई.
6.	वेलूथम्पी का विद्रोह	त्रावणकोर	1808-1809 ई.
7.	कोलियों का विद्रोह	गुजरात	1824-1828 ई.
8.	कित्तुर विद्रोह	मैसूर	1824 ई.
9.	गदाधर सिंह का विद्रोह	असम	1828-1830 ई.
10.	नरसिंह रेड्डी का विद्रोह	आन्ध्र प्रदेश	1846-1847 ई.
11.	किलेदारों (पाउपकारों) का संग्राम	दक्षिण भारत	1801-1805 ई.

2. आदिवासी संघर्षों के प्रमुख नेता

क्र. सं.	आदिवासी संघर्ष	नेतृत्वकर्ता
1.	संथाल संघर्ष	सिद्धु तथा कान्हू
2.	महाराष्ट्र का भील संघर्ष	सेवरम्
3.	रामोसी विद्रोह	चित्तरसिंह
4.	नागा संघर्ष	सांबुदान
5.	कोड़ा डोरा संघर्ष	कोरा मल्लपा
6.	रम्पा संघर्ष	राजन अनंतनय्या
7.	मुण्डा उन्मूलन महाविद्रोह	बिरसा मुण्डा
8.	खासी संघर्ष	उत्तरीत सिंह
9.	अहोम संघर्ष	गोमधन कुँवर
10.	कोल संघर्ष	भुण्डु भगत

3. 1857 ई. से पूर्व की प्रमुख सामाजिक संस्थाएँ

क्र.सं.	सामाजिक संस्था	संस्थापक	वर्ष
1.	ब्रह्म समाज	राजा राममोहन राय	1828 ई.
2.	आत्मीय सभा	राजा राममोहन राय	1815 ई.
3.	वेदान्त कॉलेज	राजा राममोहन राय	1825 ई.
4.	तत्वबोधिनी सभा	देवेन्द्रनाथ टैगोर	1839 ई.
5.	आदि ब्रह्म समाज	देवेन्द्रनाथ टैगोर	1843 ई.
6.	मानव धर्मसभा	महताजी दुर्गाराम मंघाराम	1844 ई.
7.	रहनुमाई माजदायासन सभा	दादाभाई नौरोजी, एस. एस. बंगाली, फरदोन नौरोजी	1851 ई. 1851 ई.
8.	यंग बंगाल आन्दोलन	हेनरी विवियन डिरोजियो	1828 ई.

4. सन् 1857 से पूर्व के राजनीतिक संगठन

क्र. सं.	राजनीतिक संगठन	संस्थापक	स्थान	वर्ष
1.	लैण्ड होल्डर्स सोसायटी	द्वारिकानाथ टैगोर	कलकत्ता	1838 ई.
2.	ब्रिटिश इण्डिया सोसायटी	विलियम एडम	लन्दन	1839 ई.
3.	ब्रिटिश इण्डिया एसोसिएशन	देवेन्द्रनाथ टैगोर	कलकत्ता	1851 ई.
4.	बम्बई एसोसिएशन	जगन्नाथ शंकर सेठ	बम्बई	1852 ई.
5.	मद्रास नेटिव एसोसिएशन	–	मद्रास	1852 ई.
6.	बंगाल ब्रिटिश इण्डिया सोसायटी	–	कलकत्ता	1844 ई.

5. 1857 ई. से पूर्व के प्रमुख समाचार-पत्र

क्र. सं.	समाचार पत्र/पत्रिका	संस्थापक	भाषा	स्थान	प्रकाशन वर्ष
1.	बंगाल गजट	जे. के. हिक्की	अंग्रेजी	कलकत्ता	1780 ई.
2.	बंगाल गजट	गंगाधर भट्टाचार्य	अंग्रेजी	कलकत्ता	1816 ई.
3.	समाचार दर्पण	मार्श मैन	बंगाली	कलकत्ता	1818 ई.
4.	दिग्दर्शन	मार्श मैन	बंगाली	कलकत्ता	1821 ई.
5.	संवाद कौमुदी	राजा राममोहन राय	बंगाली	कलकत्ता	1821 ई.
6.	मिरातुल अखबार	राजा राममोहन राय	फारसी	कलकत्ता	1822 ई.
7.	बॉम्बे समाचार	फर्दुन जी	गुजराती	बम्बई	1822 ई.
8.	बंगदल	द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न टैगोर	बंगाली	कलकत्ता	1830 ई.
9.	जामे जमशेद	पी. एम. मोतीवाला	फारसी	बम्बई	1831 ई.
10.	रफ्त गोफ्तार	दादाभाई नौरोजी	गुजराती	बम्बई	1851 ई.
11.	सत्य प्रकाश	कर्नलदास मूलजी	गुजराती	अहमदाबाद	1852 ई.
12.	हिन्दू पेट्रियट	हरिशचन्द्र मुखर्जी, गिरीशचन्द्र घोष	अंग्रेजी	कलकत्ता	1853 ई.

6. 1857 ई. से पूर्व के हिन्दी भाषी समाचार-पत्र

क्र. सं.	समाचार-पत्र	संस्थापक	स्थान	वर्ष
1.	उदंत मार्तण्ड	जुगल किशोर शुक्ल	कलकत्ता	1826 ई.
2.	बंग दूत	राजा राममोहन राय	कलकत्ता	1829 ई.
3.	मालवा अखबार	–	इन्दौर	1849 ई.
4.	समाचार सुधावर्षण	श्यामसुन्दर सेन	कलकत्ता	1854 ई.

7. 1857 ई. से पूर्व के महत्वपूर्ण कानून एवं एक्ट

क्र. सं.	कानून/एक्ट	गवर्नर जनरल/वायसराय	वर्ष
1.	रेग्यूलेटिंग एक्ट	वारेन हेस्टिंग्स	1773 ई.
2.	पिट्स इण्डिया एक्ट	वारेन हेस्टिंग्स	1784 ई.
3.	चार्टर एक्ट	लॉर्ड मिन्टो	1813 ई.
4.	सती प्रथा निषेध कानून	विलियम बैंटिंक	1829 ई.
5.	चार्टर एक्ट	विलियम बैंटिंक	1833 ई.
6.	चार्टर एक्ट	लॉर्ड डलहौजी	1853 ई.
7.	हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम	लॉर्ड डलहौजी	1856 ई.

विगत वर्षों में आई.ए.एस. (प्री.) में पूछे गये प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. भारतीयों के एक समूह ने, जिसकी अगुवाई एम. एन. राय कर रहे थे, ताशकन्द में अक्टूबर 1920 में मिलकर कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया की स्थापना की.
   2. दिसम्बर 1925 में कलकत्ता में कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के नाम से एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की गई.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/ हैं ?

   (A) केवल 1 (B) केवल 2

   (C) 1 और 2 दोनों (D) न ही 1 और न ही 2

2. बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किस एक ने वैन्कूवर में 'स्वदेश सेवक होम' की स्थापना की ?

   (A) जी. डी. कुमार (B) मदनलाल धींगरा

   (C) वी. डी. सावरकर (D) तारकनाथ दास

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. थियोसोफिकल सोसायटी ने आरम्भ से ही स्वयं को हिन्दू पुनरुत्थान के साथ सम्बद्ध किया.
   2. थियोसोफिकल सोसायटी के क्रिया-कलाप केवल दक्षिण भारत तक सीमित थे.
   3. थियोसोफिकल सोसायटी ने गुह्य रहस्यवाद (Occult mysticism) में विश्वास को समर्थन दिया.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/ हैं ?

   (A) 1, 2 तथा 3 (B) केवल 1 तथा 2

   (C) केवल 2 तथा 3 (D) केवल 1 तथा 3

4. निम्नलिखित में से कौनसा एक कथन सही है ?

   (A) लॉर्ड लिटन ने ही सर्वप्रथम यह आदेश जारी किया था कि समाचार-पत्रों में उनके सम्पादकों तथा मालिकों के नाम प्रकाशित किए जाने चाहिए

(B) लॉर्ड वेलेज़ली के काल में बंगाल गज़ेट एक साप्ताहिक के रूप में आरम्भ हुआ था
(C) लॉर्ड हेस्टिंग्ज के काल में जे. एस. बकिंघम ने कलकत्ता जरनल आरम्भ किया था
(D) अखबार-ए-आम एक दैनिक समाचार-पत्र के रूप में कराची से आरम्भ हुआ था

5. निम्नलिखित में से किस एक ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ?
(A) देवन्द्रनाथ टैगोर (B) ईश्वरचन्द्र विद्यासागर
(C) केशवचन्द्र सेन (D) श्यामचन्द्र दास

6. 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित की ?
(A) बाल शास्त्री जांभेकर
(B) महादेव गोविंद रानाडे
(C) गणेश वसुदेव जोशी
(D) दादोबा पाण्डुरंग तारखेदकर

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
केशवचन्द्र सेन ने प्रोत्साहन दिया
1. विधवा (Widow) विवाह को
2. अंतर्जातीय (Inter caste) विवाह को
3. पर्दा प्रथा के उन्मूलन को
4. स्त्रियों के लिए उच्चतर विश्वविद्यालयीन शिक्षा को
उपर्युक्त कथनों में से कौनसे सही हैं ?
(A) केवल 1 तथा 2 (B) केवल 2, 3 तथा 4
(C) केवल 1 तथा 4 (D) 1, 2, 3 तथा 4

8. निम्नलिखित में से किसने 1890 में 'इण्डियन सोशल रिफॉर्मर' आरम्भ किया ?
(A) ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (B) के. वीरेशलिंगम
(C) के. एन. नटराजन (D) एम. जी. रानाडे

9. बिहार में 1857 ई. के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था ?
(A) खान बहादुर खान (B) मौलवी अहमदुल्लाह
(C) कुँवर सिंह (D) राव साहब

10. 1857 ई. के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है ?
1. एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतन्त्र राजधानी घोषित करना.
2. कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना.
3. तात्याँ टोपे को फाँसी.
4. सिपाहियों का दिल्ली को कूच और लाल किले में उनका प्रवेश.
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) 4, 1, 2, 3 (B) 4, 1, 3, 2
(C) 3, 4, 1, 2 (D) 2, 3, 4, 1

11. जियलाङ्गरांग आन्दोलन का आयोजन हुआ था–
(A) नगालैण्ड में (B) मणिपुर में
(C) त्रिपुरा में (D) मिजोरम में

12. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची-I	सूची-II
(a) बुद्धु भगत	1. संथाल विद्रोह (1855)
(b) सिद्धु एवं कान्हूँ	2. भूमिज विद्रोह (1833)
(c) टीटू मीर	3. फराजी आन्दोलन (1836-37)
(d) गंगा नारायण	4. कोल बगावत
(e) शरियत उल्ला	5. बरारात विद्रोह (1831)

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
(A)	4	5	2	1	3
(B)	5	1	3	2	4
(C)	4	1	5	2	3
(D)	3	2	5	4	1

13. थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करते थे ?
(A) हिन्दू धर्म, पारसी धर्म एवं बौद्ध धर्म
(B) हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म एवं इस्लाम धर्म
(C) हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म
(D) केवल हिन्दू धर्म एवं बौद्ध धर्म

14. निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था, जिसने भारत में मजदूर आन्दोलन संगठित किया था ?
(A) बी. पी. वॉर्डिया (B) लाला लाजपत राय
(C) एन. एम. लोखांडी (D) एन. जी. रंगा

15. बाबा रामचन्द्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया ?
(A) अवध में (B) बिहार में
(C) बंगाल में (D) आन्ध्र में

16. भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी–
(A) द इण्डियन रिव्यू
(B) द फ्री प्रेस ऑफ इण्डिया
(C) द हिन्दुस्तान रिव्यू
(D) द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इण्डिया

17. उल गुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के प्रति जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था ?
(A) कोरा मल्लम (B) रानाडे
(C) बिरसा मुण्डा (D) कोण्डा दीरा

18. ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए निम्नलिखित चार लोकप्रिय आन्दोलनों पर विचार कीजिए–
    1. भील विद्रोह
    2. धनंजय भंज की बगावत
    3. गूजर विद्रोह
    4. कोल्हापुर विद्रोह

    इन आन्दोलनों का सही कालक्रम है–

    (A) 1, 3, 4, 2 (B) 3, 1, 4, 2
    (C) 3, 1, 2, 4 (D) 1, 3, 2, 4

19. बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थ में निम्नलिखित में से किन कारणों ने भारत में मजदूर आन्दोलन को तीव्र किया ?
    1. ब्रिटिश मजदूर आन्दोलन का प्रभाव
    2. 1917 की रूस क्रान्ति
    3. निर्वाह व्यय में वृद्धि
    4. भारतीय मजदूरों के विरुद्ध ब्रिटिश के वैधानिक उपाय

    नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

    (A) 2 एवं 3 (B) 1 एवं 4
    (C) 2 एवं 4 (D) 1 एवं 3

20. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए–

    सूची-I

    (a) राजा राममोहन राय (b) केशवचन्द्र सेन
    (c) दयानन्द सरस्वती (d) रामकृष्ण परमहंस

    सूची-II

    1. यह अभिमत दिया गया था कि ब्रह्मवाद एक प्रकार विश्व धर्म बनना चाहिए.
    2. हिन्दू धर्म की पहचान वेदों में यथा संस्थापित धर्म से की.
    3. इस पर बल दिया कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हैं.
    4. यह उद्घोषणा की कि हिन्दू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में मिलता है.

    कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	4	2	3
(B)	1	4	3	2
(C)	4	1	3	2
(D)	4	1	2	3

21. बंगाल में क्रान्तिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया ?

    (A) माइकेल मधुसूदन
    (B) सखाराम गणेश देउस्कर
    (C) वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय
    (D) रवीन्द्रनाथ टैगोर

22. 1890 ई. की बोम्बे मिल हैण्ड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन (श्रमिक संघ) थी. इसकी स्थापना की थी–

    (A) सदिपद बनर्जी ने (B) एन. एम. लोखाण्डे ने
    (C) एम. एन. राय ने (D) एस. एम. जोशी ने

23. निम्न-जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों और प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया. इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया था–

    (A) एम. के. गांधी ने
    (B) वरनार्ड कोह ने
    (C) बी. आर. अम्बेडकर ने
    (D) एम. एन. श्रीनिवास ने

24. दयाल सिंह मजीठिया सम्बद्ध थे–

    1. समाचार-पत्र से 2. शिक्षा से
    3. बैंकिंग से 4. ब्रिटिश सेना से

    कूट :

    (A) 1, 2, 4 (B) 1, 2, 3
    (C) 2, 3, 4 (D) 1, 3, 4

25. त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह संघटित किया था–

    (A) 1800 ई. में (B) 1805 ई. में
    (C) 1809 ई. में (D) 1811 ई. में

26. निम्नलिखित में से कौनसा एक विद्रोह सिधो और कान्हो से सम्बद्ध है ?

    (A) संथाल विद्रोह, 1855 ई.
    (B) कोल विद्रोह, 1820-37 ई.
    (C) मुण्डा विद्रोह, 1899-1900 ई.
    (D) उड़ीसा जमींदारों का विद्रोह, 1804-1817 ई.

27. सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी–

    (A) ज्योतिबा फुले ने (B) श्रीनारायण गुरु ने
    (C) गोपाल बाबू वलोंग ने (D) भास्करराव यादव ने

28. उन्नीसवीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक थे–

    (A) रसिक कुमार मलिक
    (B) रामतनु लाहिडी
    (C) हेनरी विवियन डेरोजियो
    (D) पियरी चन्द्र मित्रा

29. विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमंडी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था–
(A) वीरेशलिंगम ने (B) के. टी. तेलंग ने
(C) वेहरामजी ने (D) गोपाला चारियार ने

30. लेखकों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
1. मुंशी प्रेमचन्द –सोज-ए-वतन
2. श्री श्रीधरालु –देशचरित्रलु
3. रवीन्द्रनाथ टैगोर –कालिन्दी
4. सी. वी. रमणपिल्लई –मार्तण्ड वर्मा
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-कौनसे सही सुमेलित हैं ?
(A) 1, 2, 3, 4 (B) 1, 2, 4
(C) 2, 3 (D) 1, 3, 4

31. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए–
1. गिरनी कामगार संघ (1928)
2. सुरमा घाटी का किसान आन्दोलन
3. तूतीकोरिन की हड़तालें (1908)
4. गुरुवायूर मन्दिर में प्रवेश हेतु जत्था (1931)
5. जैतो मोर्चा (1922)
इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है–
(A) 3, 5, 4, 2, 1 (B) 5, 3, 1, 4, 2
(C) 3, 5, 1, 4, 2 (D) 5, 3, 2, 4, 1

32. लेखकों और उनकी रचनाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
1. आनन्द कन्द–'विरहिणी'
2. बी.डी. सावरकर–'उत्तरक्रिया'
3. रवीन्द्रनाथ टैगोर–'गणदेवता'
4. मुहम्मद इकबाल–'बाल-ए-जिबरील'
उपर्युक्त में से कौन-कौनसे युग्म सही सुमेलित हैं?
(A) 1, 2 और 4 (B) 2 और 4
(C) 2 और 3 (D) 1 और 3

33. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–
सूची-I
(a) सुब्बरायुलू चेट्टी
(b) स्वामी नारायण गुरु
(c) रघुनाथय
(d) गजालु लक्ष्मणधरासु चेट्टी
सूची-II
1. वेद समाज 2. उपासना सभा
3. जाति मीमांसा 4. क्रिसेंट
कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	1	4
(B)	1	3	2	4
(C)	4	1	2	3
(D)	1	2	4	3

34. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–
सूची-I
(a) सरला देवी (b) पंडिता रमाबाई
(c) रामेश्वरी नेहरू (d) हुकुमो देवी
सूची-II
1. उच्च जाति की हिन्दू महिला
2. स्त्री दर्पण
3. कन्या हितकारिणी सभा
4. जिबनेर झरा पाता
कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	1	2	3
(B)	2	1	3	4
(C)	4	3	2	1
(D)	1	2	4	3

35. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेग्युलेटिंग एक्ट पारित किया, वर्ष–
(A) 1773 में (B) 1775 में
(C) 1853 में (D) 1855 में

36. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
भारत से इंग्लैण्ड को 'गृह प्रभार' (Home Charges) के अन्तर्गत 1858 तक होने वाले धन के अपवाह में शामिल था–
1. ईस्ट इंडिया कम्पनी के मालिकों को लाभांश का भुगतान उसके शेयरधारकों को भुगतान के लिए
2. सार्वजनिक ऋण पर ब्याज
3. रेलवे और सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए उधार ली गई पूँजी पर प्रत्याभूत ब्याज (Guaranteed Interest)
4. इंडिया ऑफिस के व्यय
उपर्युक्त में से कौन-कौनसे कथन सही हैं?
(A) 1, 2 और 3 (B) 2, 3 और 4
(C) 1, 3 और 4 (D) 1, 2, 3 और 4

29. विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमंडी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था–
(A) वीरेशलिंगम ने (B) के. टी. तेलंग ने
(C) वेहरामजी ने (D) गोपाला चारियार ने

30. लेखकों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
1. मुंशी प्रेमचन्द –सोज-ए-वतन
2. श्री श्रीधरालु –देशचरित्रलु
3. रवीन्द्रनाथ टैगोर –कालिन्दी
4. सी. वी. रमणपिल्लई –मार्तण्ड वर्मा
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-कौनसे सही सुमेलित हैं ?
(A) 1, 2, 3, 4 (B) 1, 2, 4
(C) 2, 3 (D) 1, 3, 4

31. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए–
1. गिरनी कामगार संघ (1928)
2. सुरमा घाटी का किसान आन्दोलन
3. तूतीकोरिन की हड़तालें (1908)
4. गुरुवायूर मन्दिर में प्रवेश हेतु जत्था (1931)
5. जैतो मोर्चा (1922)
इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है–
(A) 3, 5, 4, 2, 1 (B) 5, 3, 1, 4, 2
(C) 3, 5, 1, 4, 2 (D) 5, 3, 2, 4, 1

32. लेखकों और उनकी रचनाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
1. आनन्द कन्द–'विरहिणी'
2. बी.डी. सावरकर–'उत्तरक्रिया'
3. रवीन्द्रनाथ टैगोर–'गणदेवता'
4. मुहम्मद इकबाल–'बाल-ए-जिबरील'
उपर्युक्त में से कौन-कौनसे युग्म सही सुमेलित हैं?
(A) 1, 2 और 4 (B) 2 और 4
(C) 2 और 3 (D) 1 और 3

33. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I
(a) सुब्बरायुलू चेट्टी
(b) स्वामी नारायण गुरु
(c) रघुनाथय
(d) गजालु लक्ष्मणधरासु चेट्टी

सूची-II
1. वेद समाज 2. उपासना सभा
3. जाति मीमांसा 4. क्रिसेंट

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	1	4
(B)	1	3	2	4
(C)	4	1	2	3
(D)	1	2	4	3

34. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I
(a) सरला देवी (b) पंडिता रमाबाई
(c) रामेश्वरी नेहरू (d) हुकुमो देवी

सूची-II
1. उच्च जाति की हिन्दू महिला
2. स्त्री दर्पण
3. कन्या हितकारिणी सभा
4. जिबनेर झरा पाता

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	1	2	3
(B)	2	1	3	4
(C)	4	3	2	1
(D)	1	2	4	3

35. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेग्युलेटिंग एक्ट पारित किया, वर्ष–
(A) 1773 में (B) 1775 में
(C) 1853 में (D) 1855 में

36. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
भारत से इंग्लैण्ड को 'गृह प्रभार' (Home Charges) के अन्तर्गत 1858 तक होने वाले धन के अपवाह में शामिल था–
1. ईस्ट इंडिया कम्पनी के मालिकों को लाभांश का भुगतान उसके शेयरधारकों को भुगतान के लिए
2. सार्वजनिक ऋण पर ब्याज
3. रेलवे और सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए उधार ली गई पूँजी पर प्रत्याभूत ब्याज (Guaranteed Interest)
4. इंडिया ऑफिस के व्यय
उपर्युक्त में से कौन-कौनसे कथन सही हैं?
(A) 1, 2 और 3 (B) 2, 3 और 4
(C) 1, 3 और 4 (D) 1, 2, 3 और 4

37. ईस्ट इंडिया कम्पनी का चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार (Monopoly) समाप्त किया गया–
   (A) 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा
   (B) 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा
   (C) 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा
   (D) 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा

38. निम्नलिखित में से कौन-कौनसे युग्म सही सुमेलित हैं?
   1. स्ट्रैची कमीशन : अकाल (सूखा)
   2. हर्टांग कमेटी : शिक्षा
   3. फ्रेजर कमीशन : पुलिस सुधार
   (A) 1 और 2 (B) 1, 2 और 3
   (C) 2 और 3 (D) 1 और 3

39. सूची-I (लेखक) को सूची-II (पुस्तकें) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I

(a) दादा भाई नौरोजी (b) दयानन्द सरस्वती
(c) बाल गंगाधर तिलक (d) बंकिमचन्द्र चटर्जी

सूची-II

1. 'सत्यार्थ प्रकाश'
2. 'आनन्दमठ'
3. 'पॉवर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया'
4. 'गीता रहस्य'

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	4	1	2
(B)	2	1	3	4
(C)	1	3	4	2
(D)	3	1	4	2

40. सूची-I (फिल्म) को सूची-II (निर्देशक) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I

(a) 'अछूत कन्या' (b) 'अपना घर'
(c) 'धरती के लाल' (d) 'नीचा नगर'

सूची-II

1. देवकी बोस 2. हिमांशु राय
3. चेतन आनन्द 4. के.ए. अब्बास

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	1	4	3
(B)	1	2	4	3
(C)	2	4	3	1
(D)	3	1	4	2

41. भारत में संघीय कोर्ट का गठन हुआ–
   (A) 1891 के अधिनियम द्वारा
   (B) 1909 के अधिनियम द्वारा
   (C) 1919 के अधिनियम द्वारा
   (D) 1935 के अधिनियम द्वारा

42. भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ–
   (A) 1829 के अधिनियम द्वारा
   (B) 1833 के अधिनियम द्वारा
   (C) 1843 के अधिनियम द्वारा
   (D) 1858 के अधिनियम द्वारा

43. सर हरकोर्ट बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई थी–
   (A) ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय रियासतों के मध्य सम्बन्धों की जाँच हेतु
   (B) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु उचित प्रावधानों के सुझाव के लिए
   (C) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए
   (D) रियासतों के एकीकरण हेतु उपायों की खोज करने के लिए

44. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

भारत में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता का क्रमिक विकास कारण था–

1. भूमि जोत के विखण्डन का
2. कुटीर उद्योगों के पतन का
3. सिंचाई सुविधाओं के विकास के अभाव का
4. नगदी फसलों के चलन का

इनमें से कौन सही है?

   (A) 1, 2 और 3 (B) 2 और 4
   (C) 1, 3 और 4 (D) 1, 2, 3 और 4

45. निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह मण्डल की स्थापना की ?
   (A) बालगंगाधर तिलक ने
   (B) गोपाल कृष्ण गोखले ने
   (C) एम.जी. रानाडे ने
   (D) वी. डी. सावरकर ने

46. गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कौंसिल की पूर्ण सदस्यता विधि-सदस्य को प्रदान की गई थी–
   (A) 1892 के काउन्सिल्स अधिनियम द्वारा
   (B) 1861 के काउन्सिल्स अधिनियम द्वारा
   (C) 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा
   (D) 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा

47. महाजनी सभ्यता लिखी गई थी–
    (A) रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा
    (B) मुन्शी प्रेमचन्द द्वारा
    (C) सहजानन्द द्वारा
    (D) इन्दूलाल याज्ञनिक द्वारा

48. निम्नलिखित में से किसने कहा था, "मेरे लिए प्रत्येक छोटे-से-छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि वह मेरे लिए धर्मसम्मत है" ?
    (A) स्वामी विवेकानन्द (B) वी.डी. सावरकर
    (C) महात्मा गांधी (D) सुभाष चन्द्र बोस

49. नायर सर्विस सोसायटी की स्थापना की थी–
    (A) चन्द्र मेनन ने
    (B) टी.एम. माधवन ने
    (C) एम. पद्मनाभ पिल्लै ने
    (D) के. रामकृष्ण पिल्लै ने

50. मद्रास महाजन सभा अस्तित्व में आई–
    (A) 1882 में (B) 1883 में
    (C) 1884 में (D) 1885 में

51. **कथन (A)** : लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ कन्सेन्ट बिल का विरोध किया था.

    कारण (R) : लोकमान्य तिलक की मान्यता थी कि सरकार की बजाय समाज को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए कदम उठाने चाहिए.

    कूट :
    (A) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
    (B) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
    (C) A सही है, परन्तु R गलत है
    (D) A गलत है, परन्तु R सही है

52. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    18वीं शताब्दी में खालसा एक ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य था–
    1. सिखों के राष्ट्रमण्डल को केवल एक धार्मिक, सैन्य तथा राजनीतिक संगठन बनाना.
    2. खालसा तथा सिख-कुल के प्रशासन को एक जनतान्त्रिक स्वरूप देना.
    3. सभी व्यक्तिगत सदस्यों को समान राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक सुविधाएं देना.
    4. असमानता की छाया वाले प्रत्येक विचार को हतोत्साहित करना.

    इनमें से कौनसे कथन सही हैं?
    (A) 1 व 2 (B) 2 व 3
    (C) 3 व 4 (D) 1, 2, 3 व 4

53. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई?
    (A) वॉरेन हेस्टिंग्स (B) लॉर्ड वैलेजली
    (C) लॉर्ड कर्जन (D) विलियम बैंटिंक

54. किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राज योग नामक पुस्तकें लिखी गईं?
    (A) स्वामी विवेकानन्द (B) रानाडे
    (C) राजा राममोहन राय (D) रामकृष्ण परमहंस

55. यू. एस. ए. में ब्रह्मविद्या (थियोसॉफीकल) सोसायटी की स्थापना किसने की?
    (A) डॉ. एनी बेसेन्ट
    (B) ए. ओ. ह्यूम
    (C) तिलक तथा गोखले
    (D) मैडम ब्लावात्स्की तथा ऑल्कॉट

निर्देश–(प्रश्न 56-57) आगामी प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है. इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए–

कूट :
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(B) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है.
(C) A सही है, परन्तु R गलत है.
(D) A गलत है, परन्तु R सही है.

56. **कथन (A)** : अंग्रेजों ने विधिसम्मत शासन की आधुनिक धारणा को भारत में प्रारम्भ किया.

    कारण (R) : अंग्रेजों द्वारा भारत में उस समय प्रचलित वैयक्तिक सिविल कानून को मान्यता प्रदान नहीं की गई.

57. **कथन (A)** : 1916 में भारतीय औद्योगिक कमीशन नियुक्त किया गया.

    कारण (R) : ऐसा इस तथ्य के लाभस्वरूप हुआ था कि 1914 के युद्ध में टाटा लौह तथा इस्पात वर्क्स ने अंग्रेजों की बहुत सेवा की थी.

58. निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन एक 1816 ई. में आरम्भ हुआ और 1832 ई. तक चला ?
    (A) कोल विद्रोह (B) खासी विद्रोह
    (C) कच्छ विद्रोह (D) नयकड़ विद्रोह

59. निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है ?

व्यक्ति	प्रतिष्ठापित संस्थाएँ
(A) सी. आर. रेड्डी	प्रजामित्र मंडली
(B) ज्योतिबा फुले	सत्यशोधक समाज
(C) बी. आर. अम्बेडकर	ऑल इण्डिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन
(D) डॉ. आत्माराम पाण्डुरंग	प्रार्थना समाज

60. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची-I (विधान)

(a) हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
(b) सती निषेध
(c) सहवासवय-अधिनियम
(d) दास प्रथा का उन्मूलन

सूची-II (गवर्नर जनरल)

1. विलियम बेंटिक
2. लैंसडाउन
3. एलेनबरो
4. डलहौजी

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	4	2	1
(B)	4	2	1	3
(C)	4	1	2	3
(D)	2	1	3	4

उत्तरमाला

1. (A)	2. (A)	3. (D)	4. (C)	5. (C)
6. (D)	7. (A)	8. (C)	9. (C)	10. (A)
11. (B)	12. (C)	13. (A)	14. (A)	15. (A)
16. (D)	17. (C)	18. (D)	19. (C)	20. (C)
21. (C)	22. (B)	23. (D)	24. (B)	25. (B)
26. (A)	27. (A)	28. (C)	29. (A)	30. (B)
31. (C)	32. (B)	33. (B)	34. (A)	35. (A)
36. (A)	37. (C)	38. (B)	39. (D)	40. (A)
41. (D)	42. (B)	43. (A)	44. (A)	45. (C)
46. (C)	47. (B)	48. (C)	49. (C)	50. (C)
51. (A)	52. (D)	53. (C)	54. (A)	55. (D)
56. (C)	57. (C)	58. (A)	59. (C)	60. (C)

संकेत

1. सी. पी. आई की स्थापना कानपुर में हुई थी.

4. 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियन्त्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार-पत्रों पर नियन्त्रण लगाते हुए सम्पादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया.

7. केशवचन्द्र सेन के विचार क्रान्तिकारी थे. उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा की समाप्ति आदि का प्रचार किया.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ माना जाता है–
(A) यूरोपीय जातियों के आगमन से
(B) फ्रांसीसी जातियों के आगमन से
(C) भारतीयों के विदेश जाने से
(D) इनमें से कोई नहीं

2. पुर्तगाली पादरी फ्रांसिस जेवियर ने अनेक स्कूल खोले–
(A) 1545 ई. में (B) 1542 ई. में
(C) 1543 ई. में (D) 1546 ई. में

3. सार्वजनिक शिक्षा के लिए 10 सदस्यों की सामान्य समिति नियुक्त की गई–
(A) 1824 ई. में (B) 1825 ई. में
(C) 1823 ई. में (D) 1826 ई. में

4. उपर्युक्त समिति की स्थापना किसने की ?
(A) एडम ने (B) फ्रांसिस जेवियर ने
(C) क्लाइव ने (D) मॉण्टेग्यू ने

5. गवर्नर जनरल की परिषद् के विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले ने कब सदस्यता ग्रहण की ?
(A) 1836 ई. में (B) 1837 ई. में
(C) 1834 ई. में (D) 1840 ई. में

6. प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए किस शासक ने कुछ निम्न पदों पर भी भारतीयों की नियुक्ति शुरू की ?
(A) विलियम बैंटिक ने
(B) क्लाइव ने
(C) मैकाले ने
(D) इनमें से कोई नहीं

7. अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को ही सरकारी सेवा में लिया जाएगा, यह निर्णय किसके शासनकाल में लिया गया ?
(A) बैंटिक (B) रूजवेल्ट
(C) लॉर्ड हॉर्डिंग्स (D) मैकाले

8. उपर्युक्त निर्णय कब लिया गया ?
   (A) 1840 ई. में (B) 1841 ई. में
   (C) 1843 ई. में (D) 1844 ई. में

9. स्कूल बुक सोसायटी की ओर से प्रकाशित अंग्रेजी की पुस्तकें दो वर्ष में कितनी बिकी ?
   (A) 50,000 (B) 60,000
   (C) 31,000 (D) 41,000

10. सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन कब हुआ ?
   (A) 1826 ई. में (B) 1825 ई. में
   (C) 1827 ई. में (D) 1823 ई. में

11. उक्त समिति की स्थापना कहाँ हुई थी ?
   (A) बंगाल में (B) मद्रास में
   (C) कलकत्ता में (D) रंगून में

12. कलकत्ता में सार्वजनिक शिक्षा समिति की ओर से खोले जाने वाले संस्कृत कॉलेज का विरोध किसने किया ?
   (A) राजा राममोहन राय ने
   (B) सर सैयद अहमद खाँ ने
   (C) विवेकानंद ने
   (D) सरस्वती दयानंद ने

13. 1817 ई. में कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से सम्भव हुई ?
   (A) मेयर के द्वारा (B) हेयर के द्वारा
   (C) टॉल्सटाय द्वारा (D) इनमें से कोई नहीं

14. उपर्युक्त हिन्दू कॉलेज कालान्तर में जिस नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह है–
   (A) प्रेसीडेंसी महाविद्यालय
   (B) प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय
   (C) हिन्दुस्तान कॉलेज
   (D) हिन्दुस्तान विश्वविद्यालय

15. देशी तथा भारतीय शिक्षा में साहित्यकता व वैज्ञानिकता नहीं है, यह मानना है–
   (A) बैंटिंक का (B) मैकाले का
   (C) टॉल्सटाय का (D) रूजवेल्ट का

16. लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की कौंसिल में विधि कार्यकारी सदस्य बना–
   (A) 1835 ई. में (B) 1836 ई. में
   (C) 1834 ई. में (D) 1838 ई. में

17. अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से प्रारम्भिक लाभ अधिकतर किस वर्ग ने उठाया ?
   (A) मध्यमवर्गीय हिन्दुओं ने
   (C) निम्नवर्गीय हिन्दुओं ने
   (D) मुस्लिम समुदाय ने

18. कैथोलिक मुक्ति कानून की स्थापना की गई–
   (A) 1829 ई. में (B) 1830 ई. में
   (C) 1835 ई. में (D) 1836 ई. में

19. किससे पूर्व का काल शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगों का काल कहा जाता है ?
   (A) 1850 ई. से पूर्व का काल
   (B) 1849 ई. से पूर्व का काल
   (C) 1857 ई. से पूर्व का काल
   (D) 1858 ई. से पूर्व का काल

20. शिक्षा के लिए चार्टर अधिनियम बना–
   (A) 1813 ई. में (B) 1814 ई. में
   (C) 1815 ई. में (D) 1816 ई. में

21. देशी विद्यालयों के आधार पर सार्वजनिक शिक्षा पद्धति के निर्माण का प्रयास किया–
   (A) थॉमसन ने (B) रालसन ने
   (C) मैकाले ने (D) टाल्सटॉय ने

22. बनारस कॉलेज की स्थापना कब की गई ?
   (A) 1854 ई. में (B) 1853 ई. में
   (C) 1855 ई. में (D) 1856 ई. में

23. अमृतसर तथा लाहौर में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए कॉलेजों की स्थापना हुई–
   (A) 1850 ई. में (B) 1860 ई. में
   (C) 1842 ई. में (D) 1840 ई. में

24. अंग्रेजी संसद की ओर से नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट पर शिक्षा व्यवस्था का घोषणा-पत्र कब जारी किया गया ?
   (A) 1855 ई. में (B) 1854 ई. में
   (C) 1860 ई. में (D) 1853 ई. में

25. उपर्युक्त घोषणा-पत्र का संस्थापक कौन था ?
   (A) वुड (B) मैकाले
   (C) स्मिथ (D) रूजवेल्ट

26. 1870-72 ई. में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 16473 थी, जो 1881-82 में बढ़कर कितनी हो गई ?
   (A) 82916 (B) 82917
   (C) 82816 (D) 82817

27. जयपुर का महाराजा कॉलेज, कॉलेज स्तर में कब तब्दील हुआ ?
   (A) 1875 ई. में (B) 1874 ई. में

28. अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई ?
    (A) 1876 ई. में (B) 1872 ई. में
    (C) 1877 ई. में (D) 1875 ई. में

29. उपर्युक्त कॉलेज कालान्तर में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ ?
    (A) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
    (B) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
    (C) अंग्रेजी महाविद्यालय
    (D) दयानंद विश्वविद्यालय

30. लॉर्ड मेयो ने एक आदेश पारित किया, जिसमें यह आवश्यक था कि मुसलमानों को भी अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य है, वह बना–
    (A) 7 अगस्त, 1871 ई. में
    (B) 7 अगस्त, 1872 ई. में
    (C) 8 अगस्त, 1872 ई. में
    (D) 8 अगस्त, 1874 ई. में

31. किसी भी प्रकार के जातीय बंधन का न होना अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार-प्रसार में–
    (A) बाधक बना
    (B) साधक बना
    (C) कोई प्रभाव नहीं हुआ
    (D) थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा

32. भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई ?
    (A) पुणे में (B) बम्बई में
    (C) मद्रास में (D) बंगाल में

33. उपर्युक्त विश्वविद्यालय की शुरूआत किसने की ?
    (A) प्रोफेसर अब्दुल गनी ने
    (B) प्रोफेसर कर्वे ने
    (C) प्रोफेसर खान ने
    (D) इनमें से कोई नहीं

34. भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई ?
    (A) सन् 1917 ई. में (B) सन् 1918 ई. में
    (C) सन् 1916 ई. में (D) सन् 1912 ई. में

35. सामाजिक एवं धार्मिक आन्दोलनों की बदौलत भारतीयों के जनमानस के विचारों में हुए परिवर्तन को कहा जाता है–
    (A) जन-आन्दोलन (B) पुनर्जागरण
    (C) पुनरावलोकन (D) समग्र बदलाव

36. प्राचीन भारत की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है ?
    (A) स्वर्णिम युग (B) अवनति युग
    (C) उन्नति का युग (D) इनमें से कोई नहीं

37. भारत के मध्य काल को माना जाता है–
    (A) स्वर्णिम युग (B) अवनति युग
    (C) उन्नति का युग (D) इनमें से कोई नहीं

38. विलिकिंस ने किस भारतीय ग्रन्थ का अपनी भाषा में अनुवाद किया ?
    (A) गीता का (B) रामायण का
    (C) महाभारत का (D) वेदों का

39. वेदों का अपनी भाषा में किस विद्वान् ने अनुवाद किया ?
    (A) विलिकिंस ने (B) मैक्समूलर ने
    (C) जोन्स ने (D) कोलब्रुक ने

40. विलियम जोन्स के द्वारा अपनी भाषा में अनुदित भारतीय ग्रन्थ हैं–
    (A) मनुस्मृति तथा शकुन्तला
    (B) मनुस्मृति तथा रामायण
    (C) रामायण तथा महाभारत
    (D) महाभारत तथा मनुस्मृति

41. कोलब्रुक ने किस भारतीय ग्रन्थ का अपनी भाषा में अनुवाद किया ?
    (A) पाणिनी की व्याकरण (B) श्रीमद्भागवत
    (C) रामायण (D) वेद

42. सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों के लिए आन्दोलनों की शुरूआत हुई–
    (A) बिहार से (B) बंगाल से
    (C) कलकत्ता से (D) मद्रास से

43. बंगाल में नवचेतना लाने की दिशा में प्रथम प्रयास किस संस्था ने किया ?
    (A) प्रार्थना समाज ने
    (B) ब्रह्म समाज ने
    (C) यंग बंगाल आन्दोलन ने
    (D) कांग्रेस ने

44. "यंग बंगाल आन्दोलन" का प्रमुख नेता कौन था ?
    (A) हेनरी विलियम
    (B) हेनरी विवियन डेरिजिओ
    (C) हेनरी मस्कट
    (D) हेनरी माओत्से

45. उपर्युक्त हेनरी विवियन पेशे से कौन था ?
(A) अध्यापक (B) व्यापारी
(C) अंग्रेज अफसर (D) इनमें से कोई नहीं

46. अपने आन्दोलन में हेनरी ने किसको मुद्दा बनाया ?
(A) रूढ़िगत प्रथाओं को (B) नारी शिक्षा को
(C) बाल-विवाह को (D) बहु-विवाह को

47. राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था ?
(A) बंगाल में (B) कलकत्ता में
(C) मद्रास में (D) बिहार में

48. राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था ?
(A) 1778 ई. में (B) 1777 ई. में
(C) 1776 ई. में (D) 1774 ई. में

49. उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'एकेश्वरवादियों को उपहार' कब प्रकाशित हुई ?
(A) 1818 ई. में (B) 1809 ई. में
(C) 1810 ई. में (D) 1811 ई. में

50. राजा राममोहन राय के द्वारा लिखित पुस्तक 'तोहफत-उल-मुहीद्दीन' किस भाषा में लिखी गई है ?
(A) उर्दू (B) बांग्ला
(C) फारसी (D) अंग्रेजी

51. अंग्रेजी कम्पनी राजा राममोहन राय ने कब ज्वाइन की ?
(A) 1806 ई. में (B) 1805 ई. में
(C) 1807 ई. में (D) 1810 ई. में

52. राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी कम्पनी ईस्ट इण्डिया कम्पनी से त्यागपत्र कब दिया था ?
(A) 1815 ई. में (B) 1816 ई. में
(C) 1814 ई. में (D) 1818 ई. में

53. 'आत्मा सभा' की स्थापना कब की गई ?
(A) 1816 ई. में (B) 1815 ई. में
(C) 1817 ई. में (D) 1818 ई. में

54. सती प्रथा को मिटाने का श्रेय किसको जाता है ?
(A) राजा राममोहन राय को
(B) विवेकानंद को
(C) दयानंद सरस्वती को
(D) केशवचंद्र को

55. राजा राममोहन राय ने वेदों तथा उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया ?
(A) फारसी में (B) बांग्ला में
(C) उर्दू में (D) अंग्रेजी में

56. राजा राममोहन राय की दूसरी पुस्तक "प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस" कब प्रकाशित हुई ?
(A) 1820 ई. में (B) 1821 ई. में
(C) 1824 ई. में (D) 1825 ई. में

57. ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की ?
(A) स्वामी दयानंद सरस्वती ने
(B) विवेकानंद ने
(C) राजा राममोहन राय ने
(D) केशवचंद्र ने

58. ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई ?
(A) 1828 ई. में (B) 1829 ई. में
(C) 1830 ई. में (D) 1832 ई. में

59. राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध कब शुरू किया ?
(A) 1819 ई. में (B) 1818 ई. में
(C) 1825 ई. में (D) 1830 ई. में

60. सती प्रथा का अन्त कब हुआ ?
(A) 1829 ई. में (B) 1830 ई. में
(C) 1835 ई. में (D) 1838 ई. में

61. सती प्रथा निरोधक कानून बनाने में किसने सहयोग दिया ?
(A) विलियम बैंटिंक ने (B) टॉल्सटाय ने
(C) हेनरी ने (D) होमर ने

62. कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई ?
(A) 1826 ई. में (B) 1827 ई. में
(C) 1828 ई. में (D) 1825 ई. में

63. कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज की स्थापना कब हुई ?
(A) 1817 ई. में (B) 1825 ई. में
(C) 1818 ई. में (D) 1820 ई. में

64. राजा राममोहन राय ने किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया–
(A) संवाद कौमुदी (B) कुमुद कौमुदी
(C) भाष्य कौमुदी (D) दर्श कौमुदी

65. राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने सँभाली ?
(A) देवेन्द्रनाथ ठाकुर (B) केशवचंद्र ने
(C) विद्या वागीश ने (D) इनमें से कोई नहीं

66. तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया ?
(A) विद्या वागीश ने (B) केशवचंद्र ने
(C) देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने (D) इनमें से कोई नहीं

67. ब्रह्म समाज कितने भागों में विभाजित हुआ ?
(A) एक (B) दो
(C) तीन (D) चार

68. ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट का नाम रखा गया–
(A) आदि ब्रह्म समाज
(B) भारतीय ब्रह्म समाज
(C) आदि ब्रह्म भारतीय समाज
(D) इनमें से कोई नहीं

69. ब्रह्म मैरिज एक्ट कब तैयार हुआ ?
(A) 1873 ई. में (B) 1872 ई. में
(C) 1874 ई. में (D) 1875 ई. में

70. उपर्युक्त एक्ट का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला कि–
(A) विधवा तथा अन्तर्जातीय विवाह होने लगे
(B) सती प्रथा का अन्त हुआ
(C) बाल-विवाह बन्द हुए
(D) बहु-विवाह बंद हुआ

71. ब्रह्म समाज के अनुसार लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई ?
(A) 17 वर्ष (B) 18 वर्ष
(C) 20 वर्ष (D) 12 वर्ष

72. ब्रह्म समाज के अनुसार लड़की के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र थी–
(A) 12 वर्ष (B) 14 वर्ष
(C) 13 वर्ष (D) 15 वर्ष

73. रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे–
(A) राजा राममोहन राय (B) दयानंद सरस्वती
(C) विवेकानंद (D) इनमें से कोई नहीं

74. विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया ?
(A) 1893 ई. में (B) 1894 ई. में
(C) 1895 ई. में (D) 1896 ई. में

75. वेदांत सोसायटी की स्थापना किसने की ?
(A) दयानंद ने
(B) विवेकानंद ने
(C) राजा राममोहन राय ने
(D) केशवचंद्र ने

76. वेदांत सोसायटी की स्थापना कब हुई ?
(A) 1872 ई. में (B) 1876 ई. में
(C) 1893 ई. में (D) 1896 ई. में

77. रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई ?
(A) 1897-98 ई. में (B) 1899-1900 ई. में
(C) 1896-97 ई. में (D) 1995-96 ई. में

78. स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई ?
(A) 1901 ई. में (B) 1902 ई. में
(C) 1903 ई. में (D) 1904 ई. में

79. दक्कन एज्यूकेशन सोसायटी की स्थापना कब हुई ?
(A) 1885 ई. में (B) 1883 ई. में
(C) 1884 ई. में (D) 1890 ई. में

80. थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की ?
(A) राममनोहर ने (B) एनीबेसेंट ने
(C) कर्पूरचंद ने (D) गोविन्द रानाडे ने

81. थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई ?
(A) 1876 ई. में (B) 1872 ई. में
(C) 1874 ई. में (D) 1875 ई. में

82. एनीबेसेंट भारत में कब आईं ?
(A) 1872 ई. में (B) 1880 ई. में
(C) 1893 ई. में (D) 1895 ई. में

83. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का नाम प्रारम्भिक अवस्था में क्या था ?
(A) सेन्ट्रल स्कूल (B) सेन्ट्रल विद्यालय
(C) सेन्ट्रल कॉलेज (D) सेन्ट्रल महाविद्यालय

84. उपर्युक्त विद्यालय की स्थापना किसने की ?
(A) राजा राममोहन राय (B) दयानंद सरस्वती
(C) एनीबेसेंट (D) पुंडरीकाक्ष

85. थियोसोफिकल सोसायटी की भारत में सर्वप्रथम शाखा कहाँ खोली गई ?
(A) बम्बई में
(B) मद्रास में
(C) मद्रास के निकट अड्यार में
(D) बंगाल में

86. होमरूल लीग की स्थापना कब हुई ?
(A) 1916 ई. में (B) 1917 ई. में
(C) 1918 ई. में (D) 1920 ई. में

87. स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का मूल नाम क्या था ?
(A) दयाशंकर (B) मूलशंकर
(C) कृपाशंकर (D) करुणाशंकर

88. स्वामी दयानंद के गुरु का नाम था–
(A) विरजानंद (B) घनानंद
(C) स्वामीनंद (D) देवानंद

89. दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक का नाम है–
   (A) सत्यार्थ प्रकाश (B) रामायण
   (C) महाभारत (D) वेदांत

90. आर्य समाज की स्थापना कब हुई ?
   (A) 1876 ई. में (B) 1877 ई. में
   (C) 1875 ई. में (D) 1890 ई. में

91. आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंदजी की मृत्यु कब हुई ?
   (A) 1883 ई. में (B) 1882 ई. में
   (C) 1888 ई. में (D) 1889 ई. में

92. आर्य समाज का दो दलों में विघटन हुआ–
   (A) 1893 ई. में (B) 1892 ई. में
   (C) 1896 ई. में (D) 1899 ई. में

93. आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारम्भ कब हुआ ?
   (A) 1768 ई. में (B) 1766 ई. में
   (C) 1765 ई. में (D) 1770 ई. में

94. इसका प्रारम्भकर्ता कौन था ?
   (A) विलियम वोलस (B) विलियम थापर
   (C) विलियम थामस (D) इनमें से कोई नहीं

95. प्रथम भारतीय समाचार-पत्र था–
   (A) बंगाल गजट (B) पंजाब केशरी
   (C) पांचजन्य (D) शंखनाद

96. 1780 ई. में किस समाचार-पत्र की शुरूआत हुई ?
   (A) भारतीय गजट (B) इण्डिया गजट
   (C) शंखनाद (D) महामना हिन्दू

97. 1911 में हिन्दू प्रेस के साथ किस प्रेस ने ईसाइयों के विरुद्ध बिगुल बजाया ?
   (A) मुस्लिम प्रेस ने (B) निजाम-उल-मुल्क ने
   (C) अखबारे आम ने (D) इनमें से कोई नहीं

98. अहमदिया आन्दोलन के प्रवर्तक थे–
   (A) मिर्जा इस्माइल
   (B) सर सैयद अहमद खाँ
   (C) मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी
   (D) मौहम्मद उल हुक

99. मोहम्मद एंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई ?
   (A) 1878 ई. में (B) 1870 ई. में
   (C) 1890 ई. में (D) 1875 ई. में

100. उर्दू पत्रिका 'तहजीब उल अखलाक' का प्रकाशन किसने किया ?
   (A) सर सैयद अहमद खाँ ने
   (B) मोहम्मद उमर खाँ ने
   (C) बशीर अहमद ने
   (D) मोहम्मद असफाक ने

उत्तरमाला

1. (A)	2. (B)	3. (C)	4. (A)	5. (C)
6. (A)	7. (C)	8. (D)	9. (C)	10. (D)
11. (A)	12. (A)	13. (B)	14. (A)	15. (B)
16. (C)	17. (A)	18. (A)	19. (C)	20. (A)
21. (A)	22. (B)	23. (C)	24. (B)	25. (A)
26. (A)	27. (C)	28. (D)	29. (A)	30. (A)
31. (B)	32. (A)	33. (B)	34. (C)	35. (B)
36. (A)	37. (B)	38. (A)	39. (B)	40. (A)
41. (A)	42. (B)	43. (C)	44. (B)	45. (A)
46. (B)	47. (A)	48. (D)	49. (B)	50. (C)
51. (B)	52. (A)	53. (B)	54. (A)	55. (B)
56. (A)	57. (C)	58. (B)	59. (B)	60. (A)
61. (A)	62. (D)	63. (B)	64. (A)	65. (A)
66. (C)	67. (B)	68. (A)	69. (B)	70. (A)
71. (B)	72. (B)	73. (C)	74. (A)	75. (B)
76. (D)	77. (C)	78. (B)	79. (C)	80. (B)
81. (D)	82. (C)	83. (A)	84. (C)	85. (C)
86. (A)	87. (B)	88. (A)	89. (A)	90. (C)
91. (A)	92. (A)	93. (B)	94. (A)	95. (A)
96. (B)	97. (A)	98. (C)	99. (D)	100. (A)

4

ब्रिटिश शासन का विरोध
(Resistance to British Rule)

[प्रारम्भिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह–कारण, प्रकृति, अवधि एवं परिणाम
(Early uprisings; The 1857 Revolt-Causes, Nature, Course & Consequences)]

ब्रिटिश शासन का विरोध

प्रारम्भिक विद्रोह–अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के साथ ही भारत में उसका प्रतिरोध भी प्रारम्भ हो गया. कम्पनी सरकार की राजनीतिक, आर्थिक नीतियों के चलते समाज के विभिन्न वर्गों, विस्थापित शासकों, जमींदारों, धार्मिक नेताओं, फकीरों, संन्यासियों, सैनिकों, किसानों एवं जनजातीय लोगों ने अनेक वार विद्रोह एवं विरोध किया. भारत के विभिन्न भागों में ऐसे कई विरोध एवं विद्रोह हुए. हालांकि 1857 ई. का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण तथा बड़ा माना जाता है, परन्तु उससे पूर्व भी लगभग प्रत्येक वर्ष विद्रोहों की शृंखला चलती रही. इन विद्रोहों को चार भागों में बाँटा जा सकता है–

1. नागरिक विद्रोह
2. किसान आन्दोलन
3. जनजातीय आन्दोलन
4. सैनिक विद्रोह

नागरिक विद्रोह–कम्पनी के शासनकाल के 100 वर्षों के अन्दर विस्थापित जमींदारों, बड़े भूमिपतियों तथा विस्थापित शासकों के नेतृत्व में अनेक विद्रोह हुए. इन विद्रोहों का मुख्य कारण अंग्रेजों के द्वारा किया जाने वाला आर्थिक शोषण था. नागरिक विद्रोहों में निम्नलिखित विद्रोह प्रमुख थे–

संन्यासी विद्रोह–बंगाल में संन्यासी विद्रोह आरम्भिक विद्रोहों में अपनी अहम भूमिका रखता है. ये संन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे और विभिन्न सम्प्रदायों में वर्गीकृत थे. विद्रोही संन्यासियों का सम्बन्ध 'गिरि' सम्प्रदाय से था. अंग्रेजी शासन की शोषण प्रवृत्ति के ये खिलाफ थे. जब 1769-70 ई. में अकाल पड़ा तो पुराने जमींदारों, किसानों, कारीगरों तथा सैनिकों ने इन संन्यासियों का साथ दिया और अंग्रेजी कम्पनी के गोदामों तथा खेत में खड़ी फसलों को लूटना आरम्भ कर दिया. इन्होंने बहुत कठोरता से सरकार का मुकाबला किया, परन्तु उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए. वारेन हेस्टिंग्स ने इन संन्यासियों के विद्रोहों को बर्बरतापूर्वक दबा दिया.

अहोम विद्रोह–बंगाल के उत्तर-पूर्व में अहोमों का राज्य था. प्रथम बर्मा युद्ध के दौरान ईस्ट इण्डिया की सेना अहोम होकर भेजी गई थी. सरकार ने युद्ध की समाप्ति हो जाने पर सेना को भारत वापस लौटाने का आश्वासन दिया था, परन्तु उसने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया. इसके बजाय इस प्रदेश पर अधिकार करने की अटकलें लगाने लगा. इससे सरदारों ने रुष्ट होकर विद्रोह कर दिया. 1828 ई. में गोमधर कुँवर को राजा बनाया गया. विद्रोहियों ने रंगपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई, परन्तु सरकार ने इसे भी विफल कर दिया. गोमधर को कैद कर हिरासत में लिया गया. 1830 ई. में पुनः विद्रोह हुआ. रूपचंद कोनार के नेतृत्व में रंगपुर पर पुनः आक्रमण की तैयारी हुई, परन्तु यह विद्रोह भी असफल रहा. सरकार ने 1833 ई. में उत्तरी असम पुरंदरसिंह को दे दिया और राज्य का एक हिस्सा अहोम को प्रदान कर दिया गया.

खासी विद्रोह–ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने खासी पहाड़ी के कामरूप और सिलहट पर अनाधिकृत अधिकार कर लिया था. उनकी योजना असम तथा सिलहट के मध्य एक सैन्य मार्ग बनाने की थी. प्रारम्भ में बर्मा के राजा तीरत इसके लिए तैयार हो गए, परन्तु बाद में अंग्रेजों की इस क्षेत्र पर अधिकार की मंशा से तीरत ने इसका विरोध किया. 1829 ई. में उन्होंने सरकार के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया. सरकार ने इस विद्रोह को दबाकर तीरत सिंह को ढाका भेज दिया, जहाँ पर 1834 ई. में उसकी मृत्यु हो गई.

विजयनगर के राजा का विद्रोह–मद्रास में कम्पनी को जब उत्तरी सरकार की जमींदारी मिल गई, तो उसने विजयनगर के राजा से काफी बड़ी रकम की माँग की तथा उसकी सैन्य शक्ति को भंग करने के लिए भी कहा गया. उसके इनकार करने पर उसकी जमींदारी जब्त कर ली गई. सन् 1794 ई. के युद्ध में वह मारा गया.

किसान आन्दोलन–नागरिक विद्रोहों में सबसे अधिक किसानों के आन्दोलन ज्यादा रहे. किसानों को ही अंग्रेजी शोषण की सर्वाधिक मार झेलनी पड़ी थी. फलतः किसानों ने कई बार आक्रमण किए. इन आन्दोलनों में रंगपुर का विद्रोह तथा फौजी एवं वहाबी आन्दोलन प्रमुख रहे.

रंगपुर का विद्रोह–रंगपुर का विद्रोह 1783 ई. में हुआ. इस क्षेत्र में सरकार ने लगान में वृद्धि कर दी और इसे कड़ाई से वसूलने का प्रयास किया. इससे किसानों में अशांति फैल गई. हिन्दू और मुसलमान किसान एकजुट हो गए. लगान वसूलने वाला ठेकेदार देवीसिंह किसानों के क्रोध को शांत नहीं कर सका. किसानों को धीरज नारायण तथा नूरुलुद्दीन के नेतृत्व में अपना उपद्रव जारी रखना पड़ा. धीरज नारायण को इन लोगों ने अपनी स्वतन्त्र सरकार का नवाब और नूरुलुद्दीन को उसका बख्शी घोषित कर दिया. लगभग 10,000 किसानों ने कचहरी तथा थाने पर आक्रमण कर दिया. अनाज के गोदाम में आग लगा दी. कम्पनी की कूटनीतिक चाल से किसानों को माफी का आश्वासन मिल गया और किसानों से हथियार ले लिए. इससे विद्रोह कुछ धीमा पड़ गया, परन्तु जब कम्पनी ने इन विद्रोहियों को दण्डित करना शुरू किया तो विद्रोह पुनः भड़क उठा. कम्पनी ने कड़ाई के साथ विद्रोह को दबा दिया.

फरैजी आन्दोलन–बंगाल में किसानों के अन्य आन्दोलन भी हुए, जिसमें धार्मिक सम्प्रदाय के नेताओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निबाही. संन्यासियों की ही तरह बंगाल में मजनू शाह, चिरागअली शाह एवं पागलपंथी सम्प्रदाय के नेता टीपू ने किसानों की सहायता से कम्पनी और जमींदारों के विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया. इसी प्रकार धार्मिक नेता फरैजी के नेतृत्व में जो आन्दोलन चला, उसने सरकार के लिए अत्यधिक समस्या पैदा कर दी. फरैजी आन्दोलन को फरायजी आन्दोलन भी कहा जाता था.

वहाबी आन्दोलन–इस आन्दोलन को प्रारम्भ करने वाले सैयद अहमद बरेलवी (1786-1831 ई.) उत्तर प्रदेश के रायबरेली के निवासी थे. उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि अंग्रेजों ने भारत को दार-उल-हर्ब (दुश्मनों का देश) बना दिया था. उनका यह प्रयास था कि भारत को दार-उल-इस्लाम (इस्लाम का देश) बनाया जाए. सैय्यद अहमद ने समूचे उत्तर प्रदेश में अपने विचारों का प्रसार किया तथा "शिराज-ए-मुस्तकिन" नामक फारसी ग्रंथ में उनका संकलन किया. उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक परिषद् बनाई तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को जिहाद के श्रीगणेश के लिए चुना. सीमा क्षेत्र के कबीलाई इलाके में सिथाना को केन्द्र बनाया गया तथा विभिन्न स्थानों पर इसके कार्यालय खोले गए. बंगाल प्रेसीडेंसी के लिए पटना को मुख्य कार्यालय बनाया गया. 1826 ई. में इस संगठन ने हिजरत (दुश्मनों का देश से बाहर जाना) करना शुरू कर दिया. अपने समर्थकों के साथ वे 3000 मील की यात्रा करके करीब 10 महीने में पेशावर पहुँचे. पेशावर पर अधिकार करके एक स्वतन्त्र शासन की स्थापना की. बाद में इसका केन्द्र सिथाना में स्थापित किया गया. इस क्षेत्र में युद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर केन्द्र स्थापित किए गए. पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में सिखों से उनका कड़ा संघर्ष हुआ. 1831 ई. में सिखों से युद्ध करते समय वे शहीद हो गए. उनकी मृत्यु से वहाबी आन्दोलन कमजोर पड़ गया. इस आन्दोलन को पटना के विलायत अली तथा इनायत अली ने पुनर्जीवित किया. नए केन्द्र स्थापित किए गए. पटना को मुख्य केन्द्र बनाया गया. पंजाब तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में वहाबियों की अंग्रेजी सेना से कई मुठभेड़ें हुईं. एक अनुमान के अनुसार 1850-63 ई. के मध्य वहाबियों के विरुद्ध सरकार ने करीब 20 सैनिक अभियान चलाए. पटना केन्द्र के साथ सिथाना तथा मुल्का केन्द्र तहस-नहस कर दिए गए. कुछ विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ को काले पानी की सजा दी गई. इस प्रकार की दमनात्मक प्रक्रिया से वहाबी आन्दोलन 1871 ई. में ही खत्म हो गया.

आदिवासी आन्दोलन–किसानों के साथ-ही-साथ आदिवासी भी अंग्रेजी कार्यप्रणाली से त्रस्त थे. इन आदिवासियों का विरोध मुख्यतः जमीन की बेदखली, सामंती, महाजनी एवं सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों और सांस्कृतिक परम्पराओं पर हुए आघातों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण हुआ.

चुआर और हो विद्रोह–चुआर या भूमिज विद्रोह बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ. यह विद्रोह 1768 ई. से लेकर 1772 ई. तक तथा 1795 ई. से 1816 ई. तक चला. अकाल तथा बढ़े हुए भूमिकर एवं अन्य आर्थिक कठिनाइयों से पीड़ित होकर चुआरों के राजा जगन्नाथ ने 1768 ई. में विद्रोह कर दिया. 1832 ई. में गंगानारायण ने बगावत कर दी. सन् 1820-22 ई. एवं 1831 ई. में छोटा नागपुर एवं सिंहभूम के हो लोगों ने भी विद्रोह किया जिसे सरकार ने कुचल दिया.

कोल विद्रोह–किसानों के समान आदिवासियों का आन्दोलन भी एक जन-आन्दोलन था. इस आन्दोलन का आरम्भ 'दिकू' (परेशान करने वाले, आदिवासी क्षेत्रों में बाहर से आकर रहने वाले, भूमिपति, महाजन, कर्मचारी) आदि के विरुद्ध हुआ, परन्तु आगे चलकर यह राजविरोधी आन्दोलन

भी बन गया. अंग्रेजों की आर्थिक तथा राजनीतिक षड्यंत्रों के विरोधस्वरूप कोलों ने 1831 ई. में बगावत कर दी. इसका आरम्भ सिंहभूम के निकट सोनपुर परगना से हुआ था. इसका कारण कुछ आदिवासी महिलाओं का अपहरण करना था. लोगों ने विद्रोहस्वरूप **'दिक'** लोगों के विरोध में उनके पशु चुराना तथा फसल काटना आरम्भ कर दिया. धीरे-धीरे उन्होंने अपनी गतिविधियाँ तेज कर दीं. हत्या और आतंक का सहारा भी लिया जाने लगा. कोलों ने सरकारी खजाने को लूटा. थाने तथा कचहरियों में आग लगा दी.

कोल आन्दोलन के नेतृत्वकर्त्ताओं में बुद्धू भगत, जोआ भगत, केशो भगत, नरेन्द्रशाह मनकी तथा मदरा मेहतो प्रमुख रूप से थे. भले ही कोल विद्रोह ने अपने उद्देश्यों में कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी, परन्तु 1832 ई. तक इसे पूरी तरह दबा दिया गया.

संथाल विद्रोह–कोलों के विद्रोह के जो कारण थे लगभग वही कारण संथाल विद्रोह के थे. 1857 ई. के महाविद्रोह से दो वर्ष पूर्व ही संथालों ने सरकार के विरुद्ध बगावत कर दी. संथालों को चार भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने संगठित किया था. 30 जून, 1855 ई. को सिद्धू और कान्हू ने भगताडीह ग्राम में संथालों की एक आमसभा बुलाई. जिसमें लगभग 10 हजार संथालों ने भाग लिया था. इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की रणनीति तथा उद्देश्य तय किए गए थे. जुलाई 1855 ई. में संथालों का विद्रोह आरम्भ हुआ. प्रारम्भ में यह सरकार विरोधी नहीं था, लेकिन जब संथालों ने देखा कि सरकार जमींदार तथा महाजनों का ही पक्ष ले रही है, तो उनका विरोध सरकार के प्रति कड़ा हो गया. जगह-जगह सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों तथा महाजनों पर हमले किए गए. भागलपुर तथा राजमहल के बीच रेल, डाक तथा तार सेवाएँ बन्द कर दी गईं. संथालों ने अंग्रेजी शासन की समाप्ति की घोषणा करके अपना स्वतन्त्र शासन घोषित कर दिया.

सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से कलकत्ता से मेजर बर्रो के अधीन सेना की एक टुकड़ी संथालों के दमन के लिए भेजी पूर्णिया से भी सेना की टुकड़ियाँ भेजी गईं. सेना का मुकाबला संथाल नहीं कर पाए. संथालों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा करीब 15 हजार संथालों को मार डाला गया.

सैनिक विद्रोह–इन विद्रोहों तथा आन्दोलनों के अतिरिक्त कई छोटे-बड़े सैनिक विद्रोह भी हुए. 1778 ई. में जब वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस के राजा चेतसिंह पर अधिक धन के लिए दबाव डालना शुरू किया, तो सेना ने राजा की मदद की तथा अंग्रेजी सिपाहियों का विरोध किया. इसी प्रकार लॉर्ड वेलेजली ने जब अवध के नवाब वजीर अली को गद्दी से हटा दिया तब नवाब के सैनिकों ने ब्रिटिश सेना से युद्ध किया. इसी प्रकार बर्मा युद्ध के अवसर पर 47वीं भारतीय सेना ने बर्मा युद्ध में जाने से इनकार कर दिया. सरकार ने इस बटालियन के सैनिकों पर गोली चलाकर उन्हें खत्म कर दिया तथा शेष सैनिकों पर मुकदमा चलाकर अनेकों को फाँसी के फंदे पर चढ़ा दिया. 47वीं रेजीमेंट भंग कर दी गई. फलतः 1844 ई. में फिरोजपुर की 34वीं रेजीमेंट 7वीं बंगाल घुड़सवार सेना 14वीं रेजीमेंट और रावलपिंडी की 22वीं रेजीमेंटों ने विद्रोह कर दिया.

प्रारम्भिक विद्रोह का महत्व–1857 ई. के पूर्व के विद्रोह यद्यपि असफल हो गए थे, तथापि इन्होंने जनमानस में एक नई चेतना भरने का कार्य किया. किसानों और निम्नवर्गों की दयनीय स्थिति की ओर सबका ध्यान आकृष्ट हुआ. असंतोष की भावना ने समाज के अधिकांश वर्गों में विकराल रूप धारण कर लिया जिसकी परिणति 1857 ई. के प्रभावशाली विद्रोह में हुई.

1857 ई. का विद्रोह–1857 ई. का विद्रोह भारतीय इतिहास की प्रमुख ही नहीं अपितु सबसे प्रमुख घटना थी. कम्पनी सरकार की नीतियों के विरुद्ध जनता में विद्रोह की भावना भड़क उठी थी, फलतः यह महाविद्रोह हुआ.

विद्रोह के कारण–डलहौजी की नीतियाँ–अंग्रेजी कम्पनी अपने हितों को ध्यान में रखकर मनचाहे फैसले करती थी. डलहौजी की नीतियों ने आम जनता की भावनाओं को बहुत आहत किया. डलहौजी ने 'गोद निषेध नीति' के आधार पर सतारा, नागपुर, झाँसी, संभलपुर, जैतपुर तथा उदयपुर आदि को जबरदस्ती ब्रिटिश शासन में मिला लिया. इसी प्रकार की जबरदस्ती का शिकार हुआ 'अवध', जिसके कारण समस्त भारत में असंतोष व्याप्त हो गया.

अंग्रेज न तो लिखित और न ही मौखिक वादों को निभाते थे, फलतः विद्रोह का जन्म लेना स्वाभाविक था. डलहौजी ने पदों तथा पेंशनों को बंद कर भारत के एक बड़े वर्ग को असंतुष्ट कर दिया. उसने 1849 ई. में यह घोषणा कर दी कि बहादुरशाह के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी को लालकिला छोड़कर कुतुब के पास रहना होगा. लॉर्ड कैनिंग तो उससे भी आगे बढ़ गया. उसने 1856 ई. में यह घोषणा की कि बहादुरशाह की मृत्यु के बाद कोई भी शासक 'बादशाह' की उपाधि धारण नहीं कर सकेंगे. यह स्पष्टतया मुगल वंश के शासन को समाप्त करने की ही रणनीति थी. इस घोषणा से विद्रोह की भावना ने कठोर रुख अख्तियार कर लिया.

प्रशासनिक कारण–कम्पनी के गवर्नरों द्वारा किए जाने वाले सुधार कार्य ऊपर से तो लुभावने थे, परन्तु उनमें अंग्रेजी सरकार का ही हित विद्यमान होता था. किसानों पर ऋण का अत्यधिक भार था. प्रत्येक भू-राजस्व प्रणाली, चाहे वह रैयतवाड़ी या महालवाड़ी या स्थायी बन्दोबस्ती व्यवस्था

हो, का उद्देश्य एक ही था–अधिक-से-अधिक कर वसूलना. कम्पनी के कर्मचारी धन लोलुप थे, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था, न्याय केवल धनी लोगों को ही मिल पाता था.

सरकारी नौकरी देने के नाम पर पक्षपात का रवैया अपनाने के कारण भारतीय जनमानस का उद्वेलित होना स्वाभाविक था. ऊँची नौकरियाँ केवल अंग्रेजों तक ही सीमित थीं. देशी रियासतों के अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाने से अनेकों प्रतिष्ठित उच्च कुलीन वर्ग, मध्यमवर्गीय लोगों, कलाकारों, धार्मिक पेशेवालों व्यक्तियों के समक्ष बेकारी एवं भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई जिसके परिणामस्वरूप अपनी सुरक्षा के लिए मौलवियों तथा पंडितों ने जनमानस में आक्रोश एवं विद्रोह की भावना से लोगों को उद्वेलित करना प्रारम्भ कर दिया.

आर्थिक कारण–कम्पनी के द्वारा भारतीयों के प्रति होने वाला आर्थिक शोषण भी 1857 ई. की क्रांति के लिए प्रमुख कारण साबित हुआ. अंग्रेजों ने आते ही कुटीर धन्धों को समाप्त करना प्रारम्भ कर दिया. अंग्रेजों की 'मुक्त व्यापार नीति' के आधार पर भारतीय उद्योग धन्धे पूर्णतः नष्ट हो गए. भूमिपति दरिद्र हो गए. लोगों के सामने विपन्नता की स्थिति पैदा हो गई. अकेले बम्बई में ही इनाम कमीशन की ओर से बीस हजार जागीरें जब्त कर ली गईं. ताल्लुकेदारों की जमीनें छीन ली गईं जिनमें अवध के तालुकेदार अधिक थे. इस प्रकार आर्थिक शोषण की नीति ने विद्रोह की भावनाओं को भड़काने में अग्नि में घी का काम किया.

सामाजिक कारण–अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के प्रति उपेक्षा तथा तिरस्कृत भावना रखते थे. उनके प्रति अपमान-जनक व्यवहार करते थे. न्यायालयों में यह आलम था कि हमेशा भारतीयों को ही दोषी करार दिया जाता था. बाल विवाह, सती प्रथा, गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाने एवं विधवा विवाह को जायज करार देने के परिणामस्वरूप भारतीयों की मानसिकता का विकृत होना स्वाभाविक था. इस प्रकार सामाजिक जीवन में उपेक्षित जीवन से भारतीय त्रस्त हो चुके थे तथा वे विद्रोह के मौके की तलाश में रहने लगे थे.

धार्मिक कारण–1857 ई. के विद्रोह में धार्मिक कारणों की भी विशेष अहमियत रही. ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर विद्रोह की शुरूआत की भूमिका का सूत्रपात किया. धार्मिक कार्यों की आलोचना एवं उन्हें ढकोसला करार देना, भारतीय अपनी शान के खिलाफ समझते थे. बैंटिंक ने एक कानून के द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को पैतृक सम्पत्ति में भी हिस्सा दिलवाना शुरू कर दिया. यह हिन्दू धर्म पर खुला हमला था. विद्यार्थियों को हिन्दू धर्म के बजाय ईसाई धर्म की शिक्षा विस्तार से दी जाती थी, इससे यह सिद्ध हो गया कि अंग्रेज यहाँ की धार्मिक वृत्ति पर ईसाई धर्म को थोपना चाहते थे, यह भारतीयों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं था, परिणामतः विद्रोह होना स्वाभाविक था.

सैनिक कारण–इन असंतोषों के बाद भी अगर सैनिकों का सहयोग भारतीयों को नहीं मिलता तो क्रांति कभी नहीं होती. सैनिक भी अंग्रेजों से सन्तुष्ट नहीं थे. इस असंतोष के अनेक कारण थे. बंगाल की सेना में बहुत बड़ी संख्या अवध के सैनिकों की थी. ये सैनिक अपने नवाब के अपमान और राज्य छीने जाने के कारण क्रुद्ध थे. इसके अलावा भारतीय सेना के उच्च पद अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित थे. देशी सैनिकों को अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था. पूरी भारतीय सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या 1/6 भाग से भी कम थी, परन्तु उन पर खर्चा आधे से भी अधिक सैनिकों के बराबर किया जाता था. इस प्रकार की नीति से सैनिकों में विद्रोह फैलना स्वाभाविक था. लॉर्ड केनिंग के द्वारा बनाए गए एक्ट 'जेनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट' के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि बंगाल सेना को भारत के बाहर भी युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार रहना होगा, इस व्यवस्था से सैनिक असंतोष और अधिक बढ़ गया था. सन् 1854 ई. में बने 'डाकघर अधिनियम' के आधार पर सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा खत्म कर दी गई थी. इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण यह भी था कि कम्पनी सरकार ने पुरानी ब्राउन बैस बन्दूक की जगह जनवरी 1857 ई. से नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारम्भ किया था. इस राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे, उन्हें दाँतों से काटना पड़ता था. इस बात की अफवाह फैली हुई थी कि इनमें गाय तथा सूअरों की चर्बी भरी हुई है. इससे सैनिकों में भयंकर विद्रोह की भावना पनप उठी.

विद्रोह के परिणाम–यद्यपि 1857 ई. का विद्रोह असफल रहा तथापि इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुए. इससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश संसद तथा ताज का शासन आरम्भ हुआ. इस विद्रोह के परिणामों को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है.

मुगल शासन का अन्त–1707 ई. से ही मुगल सत्ता कमजोर पड़ने लग गई थी और विद्रोह शुरू होने तक वे केवल नाममात्र के ही शासक रह गए थे. मुगल शासक बहादुरशाह की रंगून में 1862 ई. में मृत्यु हो गई. उसकी मृत्यु के साथ ही भारत से मुगल शासन सदैव के लिए लुप्त हो गया.

कम्पनी के शासन का अन्त–1857 ई. के विद्रोह के कारण अव्यवस्था और अराजकता ने विकराल रूप धारण कर लिया और अंग्रेजी हितों की सुरक्षा खतरे में पड़ने लगी. यह देखकर ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी के शासन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया. 1 नवम्बर, 1858 ई. में ब्रिटिश संसद

ने "भारत सरकार अधिनियम 1858" पारित किया. सम्राज्ञी विक्टोरिया ने कम्पनी का शासन समाप्त करने की घोषणा कर दी. सरकार ने प्रशासनिक नियन्त्रण कम्पनी से छीनकर भारतीय राज्य सचिव को सौंप दिया. ब्रिटिश राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में अब वही भारत पर शासन को नियन्त्रित करने लगा. उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय 'इण्डिया कौंसिल' का गठन किया गया. इन सदस्यों में से 7 ईस्ट इण्डिया के भूतपूर्व संचालकों द्वारा एवं 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने थे. इस कौंसिल का कार्य राज्य सचिव को परामर्श देना था, परन्तु राज्य सचिव कौंसिल के बहुमत के निर्णय के विरुद्ध भी कोई निर्णय कर सकता था. इस प्रकार राज्य सचिव को अधिकाधिक अधिकार प्रदान किए गए तथा पूर्णतः कम्पनी के शासन का अन्त कर दिया गया.

गवर्नर जनरल की परिवर्तित स्थिति–1858 ई. के कम्पनी शासन समाप्त करने के निर्णय के आधार पर भारत के गवर्नर जनरल की स्थिति में भी व्यापक परिवर्तन हुआ. गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश शासन के वैयक्तिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा था. हालांकि उसके कार्य पहले जैसे ही रहे, परन्तु उसके पद को और अधिक गौरवशाली बना दिया गया था. उसको अब वायसराय कहा जाने लगा था. उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद् का गठन किया गया. प्रारम्भ में इसके सदस्यों की संख्या 5 रखी गई थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार कर दिया गया. परिषद् के सदस्यों के रूप में विभागीय प्रधानों एवं सेनाध्यक्षों को भी स्थान दिया गया था. ये सारे प्रशासनिक परिवर्तन औपचारिक रूप में ही किए गए थे. इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह पड़ा कि भारत पर शासन अब इंग्लैण्ड से होने लगा था. वहाँ के उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं बैंकरों ने सरकार पर अपना प्रभाव स्थापित कर अपने लाभ की योजनाएँ बनाना शुरू कर दिया था. फलतः शासन अधिक अनुदार और प्रतिक्रियावादी बनता चला गया. इसका एक लाभ यह हुआ कि सरकारी नीतियों के प्रतिक्रियास्वरूप भारत में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने लगी.

हितवादी सरकारी नीति का आविर्भाव–1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजी सत्ता में बेचैनी होने लगी. उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत की एकता को नष्ट करने तथा विद्रोह को कम करने के उपाय खोजने शुरू कर दिए. इसके परिणामस्वरूप उदारवादी नीतियों की घोषणा की गई. इस घोषणा-पत्र में प्रशासन के अधिग्रहण के अतिरिक्त यह बात स्पष्ट की गई कि सरकार भारत में विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति का पालन नहीं करेगी, बल्कि देशी राजाओं के अधिकारों, उनके सम्मान एवं गौरव की सुरक्षा करेगी. भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाया गया कि सरकार भारतीयों की प्राचीन परम्पराओं या रीतिरिवाजों की अवमानना नहीं करेगी तथा सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म आदि का भेदभाव किए बिना योग्यता के आधार पर सबको समान अवसर प्रदान करेगी.

ब्रिटिश सत्ता में रजवाड़ों एवं सामंतों का समावेश–सरकार ने इस घोषणा-पत्र के प्रथम भाग को ही महत्त्व देकर देशी राज्यों तथा सामंतों को अपने पक्ष में कर लिया. उन्हें गोद लेने का अधिकार वापस दे दिया गया. सभी राज्यों को अंग्रेजी अधिसत्ता के अन्तर्गत ले लिया गया. सभी नरेश ब्रिटिश ताज के अधीनस्थ शासक बन गए. 1876 ई. में महारानी विक्टोरिया द्वारा "कैसर-ए-हिन्द" की उपाधि धारण करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई. देशी राज्यों पर से वंशानुगत अधिकार समाप्त हो गया. इतने सबसे बाद भी सरकार को आवश्यकता के अनुसार देशी राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार बना रहा.

सरकारी नौकरियों में भारतीयों को स्थान–प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को भी स्थान देने के लिहाज से 1861 ई. में सरकार ने **'भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम'** बनाया. इन सेवाओं में प्रवेश करने वालों को लंदन में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना होता था. हालांकि भारतीय भी इसमें भाग ले सकते थे, परन्तु भारतीयों के लिए यह थोड़ा कठिन था, इसका परिणाम यह हुआ कि इन सेवाओं में अंग्रेजों का ही वर्चस्व बना रहा. इससे भारतीयों में असंतोष का पनपना स्वाभाविक ही था. इस असंतोष को बढ़ाने में प्रजातीय विभेद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की.

सेना का पुनर्गठन–1857 ई. की क्रांति में सेना के विद्रोह ने प्रमुख भूमिका निभाई. इस विद्रोह के पश्चात् सरकार ने इसके पुनर्गठन पर भी ध्यान दिया, ताकि विद्रोह को किसी हद तक कम किया जा सके. ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेना को अब सम्राट की सेना में परिवर्तित कर दिया गया. सैनिक पुनर्गठन के लिए "पील कमीशन" की नियुक्ति की गई. इसकी सिफारिशों के अनुसार सेना में भारतीयों की संख्या कम कर दी गई. सेना के महत्वपूर्ण पदों से भारतीयों को वंचित रखा गया और सुरक्षा का भार अंग्रेजी सेना को ही सौंप दिया गया. सैनिक वर्ग के लोग जिनमें सिख, गोरखा, पठान इत्यादि प्रमुख थे और जिन्होंने विद्रोह के दमन में कम्पनी की सहायता की थी, उन्हें सेना में प्रमुख स्थान दिया गया. रेजीमेंटों का गठन इस प्रकार किया गया ताकि वे आपस में संगठित न हो सकें. इस प्रकार से परिवर्तन करने का मूल उद्देश्य अपनी शक्ति को बढ़ावा देना ही था.

जातीय विभेद को बढ़ावा–अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने 1857 ई. के विद्रोह को मुस्लिम विद्रोह का स्वरूप प्रदान कर दिया. विद्रोह के पश्चात सरकार ने भारतीयों की एकता को नष्ट करने के लिए मुसलमानों को दण्डित करने के उद्देश्य से उनके

प्रति अनुदार रुख अपनाया. उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई. 1859 ई. से पूर्व मुसलमानों के दिल्ली लौटने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया. हिन्दुओं को अंग्रेज शासक अधिक महत्त्व देने लगे. इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों सम्प्रदायों में विभेद की खाई बढ़ती गई. इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया और यहीं से "दो राष्ट्र सिद्धान्त" तथा पाकिस्तान की माँग की पृष्ठभूमि तैयार हो गई.

साम्राज्यवादी विस्तार की नीति–1857 ई. के पश्चात् भारत में सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई, परन्तु विदेशों में साम्राज्यवादी विस्तार की नीति का पालन किया गया. भारत को केन्द्र बनाकर, इसकी सुरक्षा के उद्देश्य से भारतीय साम्राज्यवाद का विस्तार किया गया और इस विस्तारवादी योजना में भारतीय संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाने लगा.

भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन–उपर्युक्त परिणामों के अतिरिक्त कुछ अन्य परिणाम भी निकले. विद्रोह के परिणामस्वरूप भारतीय सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आया. भारतीयों की सामाजिक एकता प्रायः समाप्त हो गई. हिन्दू तथा मुसलमानों के मध्य आपसी वैमनस्यता को पनपने का मौका मिला. अंग्रेजों की दोगली नीति के कारण भारतीयों में आत्माभिमान एवं राष्ट्रीय चेतना जाग्रत होने लगी. विद्रोह के उपरान्त आपसी वर्गों में संघर्ष भी तीव्रतर होता गया. इस वर्ग संघर्ष का ग्रामीण परिवेश में प्रभाव अधिक पड़ा. सरकार ने रूढ़िग्रस्त सामाजिक व्यवस्था को ही बनाए रखने की कोशिश की, ताकि उसे तथा उसके हिमायतियों को अधिक-से-अधिक लाभ मिल सके. भारत में मध्यम वर्ग ने अपने आपको इस विद्रोह से प्रारम्भ में तो अलग रखा, परन्तु सरकार की नीतियों को समझने के बाद उसने भी विद्रोह का समर्थन करना शुरू कर दिया. सरकार ने अपने आर्थिक सुधारों को बनाए रखने के लिए भारत में रेलों का विस्तार, भाप का उपयोग तथा सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था शुरू की, जिससे उत्पादन और वितरण प्रणाली को स्थायित्व मिला. इसके साथ ही भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ी. भारत में उद्योगपतियों का एक नए वर्ग का उदय हुआ. उद्योगों के विकास के साथ-ही-साथ श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ.

भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म–1857 ई. के विद्रोह की असफलता ने भारतीयों को यह दिखा दिया कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर ही ब्रिटिश प्रशासन से मुक्ति नहीं मिल सकती. इसके लिए सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन तथा राष्ट्रीय भावना का होना आवश्यक है. इसको ध्यान में रखकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही इस दिशा में सार्थक प्रयास प्रारम्भ हो गए. विद्रोह के दौरान भी भारतीयों को अन्य देशों के उदार तत्वों से जो समर्थन मिला था जैसे–रूस, तुर्की, ईरान, ब्रिटेन के चार्टिस्ट आन्दोलन के नेताओं, चीन के ताइपिंग विद्रोहियों आदि, उससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरोध की इच्छा प्रबल होती गई. 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस विरोध को एक निश्चित दिशा मिल गई.

स्मरणीय तथ्य

- 1857 ई. के पूर्व के विद्रोहों को चार भागों में बाँटा जा सकता है–
  - (i) नागरिक विद्रोह
  - (ii) किसान विद्रोह
  - (iii) जनजातीय आन्दोलन
  - (iv) सैनिक विद्रोह
- नागरिक विद्रोह के नेतृत्व करने वाले विस्थापित जमींदार तथा विस्थापित शासक थे.
- बंगाल में संन्यासी विद्रोह करने वाले शंकराचार्य के अनुयायी थे.
- बंगाल के उत्तर-पश्चिम में अहोमों का राज्य था, जहाँ अहोमों का विद्रोह हुआ था.
- ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने खासी पहाड़ी के कामरूप और सिलहट पर अपना अधिकार कर लिया, जिसके कारण खासी विद्रोह का उदय हुआ था.
- मद्रास में राजा विजयनगर से कम्पनी ने एक बड़ी रकम की माँग की, जिसके कारण विजयनगर विद्रोह शुरू हुआ.
- नागरिक विद्रोहों में सबसे अधिक किसानों की भूमिका रही.
- किसान आन्दोलनों में रंगपुर विद्रोह तथा बहावी आन्दोलनों की प्रमुख भूमिका रही.
- रंगपुर का विद्रोह 1873 ई. में हुआ.
- रंगपुर के विद्रोह में करीब 10 हजार सैनिकों ने भाग लिया था.
- बहावी आन्दोलन के प्रणेता सैय्यद अहमद बरेलवी थे, जो कि रायबरेली (उत्तर-प्रदेश) के निवासी थे.
- बहावी आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य भारत को दार-उल-इस्लाम बनाने का था.
- सैय्यद अहमद की मृत्यु 1831 ई. में सिखों से युद्ध करते समय हुई.
- चुआर या भूमिज विद्रोह बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था.
- चुआर विद्रोह 1768 ई. से लेकर 1772 ई. तक तथा 1795 ई. से 1816 ई. तक चला.
- कोल विद्रोह की शुरूआत 'सिंहभूम' के निकट सोनपुर परगना से हुई.
- संथाल विद्रोह को संगठित करने वाले चार भाई थे–सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव.

- 'गोद निषेध नीति' का निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने किया.
- भारतीय उद्योग-धन्धों को चौपट करने में अंग्रेजों के द्वारा तैयार 'मुक्त व्यापार नीति' का प्रमुख हाथ रहा था.
- अंग्रेजों के समय पूरी भारतीय सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या कुल सेना का 1/6 भाग थी, परन्तु उन पर खर्चा आधे से अधिक सैनिकों के बराबर किया जाता था.

विशिष्ट स्मरणीय तथ्य

- 1857 ई. से पूर्व होने वाले विद्रोहों में अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक शोषण, उनकी राजनीतिक चाल तथा दोहरी नीति की प्रमुख भूमिका रही.
- नागरिक विद्रोहों के तहत संन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ.
- संन्यासियों के आन्दोलन को समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग्स था.
- विजयनगर का शासक अंग्रेजों के साथ 1794 ई. में हुए युद्ध में मारा गया.
- सरकार के द्वारा लगान में वृद्धि करना और उसे कड़ाई से वसूलने के फलस्वरूप रंगपुर का विद्रोह हुआ.
- रंगपुर का विद्रोह नूरुलुद्दीन के नेतृत्व में हुआ.
- धीरज नारायण को रंगपुर विद्रोह के अन्तर्गत नूरुलुद्दीन का बख्शी घोषित किया गया था.
- रंगपुर विद्रोह का एक परिणाम यह भी निकला कि हिन्दू तथा मुस्लिमों में एकता की भावना ने जोर पकड़ा.
- वहावी आन्दोलन के प्रणेता सैय्यद अहमद बरेलवी ने अपने विचारों को 'शिरात-ए-मुस्तकिन' नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था.
- वहावी आन्दोलन के तहत बंगाल प्रेसीडेंसी के लिए पटना में मुख्य कार्यालय की स्थापना की गई थी.
- वहावी आन्दोलन के तहत 1826 ई. में हिजरत प्रक्रिया शुरू की गई.
- सैय्यद अहमद की मृत्यु के बाद वहावी आन्दोलन की कमान विलायत अली तथा इनायत अली ने सँभाली थी.
- 1850-63 ई. के मध्य वहावियों के विरोध में अंग्रेज सरकार की ओर से 20 सैनिक अभियान चलाए गए.
- चुआर और हो विद्रोह का नेतृत्व राजा जगन्नाथ तथा गंगा नारायण ने किया.
- 1831 ई. में हुए कोल आन्दोलन का नेतृत्व बुद्धू भगत, जोआ भगत, केशो भगत तथा नरेन्द्रशाह मनकी ने किया.
- संथाल विद्रोह को और अधिक गति देने के उद्देश्य से 30 जून, 1855 को एक महासभा का आयोजन किया गया था.
- संथाल विद्रोह के तहत भागलपुर तथा राजमहल के मध्य रेल, डाक तथा तार सेवाएँ रद्द कर दी गई थीं.
- लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पदों में कटौती की गई तथा पेंशन देना बन्द कर दिया गया था.
- लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ई. में मुसलमानों के दिल्ली जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया.
- लॉर्ड केनिंग के आदेशानुसार 'बादशाह' की उपाधि को खत्म कर दिया गया था.
- भारत में ईसाई मिशनरियों का यह प्रयास था कि सम्पूर्ण भारत में हिन्दू धर्म के स्थान पर ईसाई धर्म का साम्राज्य स्थापित हो.
- लॉर्ड केनिंग के द्वारा बनाए गए जनरल सर्विस इन-लिस्टमेंट एक्ट के आधार पर बंगाल की सेना को भारत के बाहर भी युद्ध में जाने के लिए बाध्य किया गया था.
- 1707 ई. से मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी और वे नाममात्र के ही शासक रह गए थे.
- भारत सरकार अधिनियम की स्थापना नवम्बर 1858 ई. में की गई.
- इण्डिया कौंसिल में 15 सदस्यों को सम्मिलित किया गया था. जिनमें से 7 सदस्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भूतपूर्व संचालकों द्वारा तथा आठ ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे.
- 1858 ई. में गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन किया गया और उसकी सहायता के लिए एक कार्य-कारिणी परिषद् का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 5 थी.
- महारानी विक्टोरिया ने 1876 ई. में 'कैसर-ए-हिन्द' की उपाधि धारण की थी.
- प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को स्थान देने के उद्देश्य से 1861 ई. में 'भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम' बनाया गया था.
- अंग्रेज सरकार द्वारा सैनिक पुनर्गठन के लिए 'पील कमीशन' का गठन किया गया.

1857 के विद्रोह के स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न इतिहासकारों का मत

क्र. सं.	इतिहासकार	प्रस्तावित मत
1.	वी. डी. सावरकर	'सुनियोजित स्वतन्त्रता संग्राम'
2.	एल.ई.आर.रीज.	धर्मान्धों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध
3.	पी. राबर्ट्स	एक सैनिक विद्रोह
4.	डॉ. एस. एस. सेन	स्वतन्त्रता संग्राम
5.	अशोक मेहता	सुनियोजित संग्राम
6.	डॉ. के. के. शर्मा	'तत्कालीन अव्यवस्था के प्रति आक्रोश'
7.	बेन्जामिन डिजरेली	राष्ट्रीय विद्रोह
8.	जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू. टेलर	हिन्दू-मुस्लिम षड्यन्त्र
9.	टी. आर. होलम्स	बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य का युद्ध
10.	सर जॉन लॉरेंस	सैनिक विद्रोह
11.	डॉ. एस. बी. चौधरी	सामान्य जनता का विद्रोह

आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध

क्र.सं.	युद्ध	पक्ष/प्रतिपक्ष	वर्ष	विजय पक्ष
1.	खेड़ा का युद्ध	मराठा छत्रपति शाहू एवं चाची ताराबाई	1707 ई.	शाहू
2.	शंकर खेड़ा का युद्ध	निजामुल मुल्क एवं मुगल वायसराय मुबारिज खाँ	1724 ई.	निजाम
3.	भोपाल का युद्ध	बाजीराव I एवं मुगलों के मध्य	1737 ई.	बाजीराव I
4.	करनाल का युद्ध	नादिरशाह एवं मुगल सम्राट् मुहम्मद शाह	1739 ई.	नादिरशाह
5.	गिरिया का युद्ध	बंगाल नवाब सरफराज खाँ एवं बिहार के उपगवर्नर अलीवर्दी खाँ	1740 ई.	अलीवर्दी खाँ
6.	प्रथम कर्नाटक युद्ध	फ्रांसीसी (डूप्ले) एवं अंग्रेज	1744-48 ई.	फ्रांसीसी
7.	द्वितीय कर्नाटक युद्ध	डूप्ले एवं लॉर्ड क्लाइव	1750-54 ई.	क्लाइव
8.	तृतीय कर्नाटक युद्ध	फ्रांसीसी (लैली) एवं अंग्रेज	1757- 63 ई.	अंग्रेज
9.	प्लासी का युद्ध	क्लाइव एवं बंगाल नवाब सिराजुद्दौला	1757 ई.	अंग्रेज
10.	बेदारा का युद्ध	अंग्रेज एवं डच	1759 ई.	अंग्रेज
11.	वांडीवाश का युद्ध	अंग्रेज (आयरकूट) एवं फ्रांसीसी लैली	1760 ई.	अंग्रेज
12.	पानीपत का तृतीय युद्ध	अफगान अहमदशाह अब्दाली एवं मराठे	1761 ई.	अब्दाली
13.	बक्सर का युद्ध	अंग्रेज (हेक्टर मुनरो) एवं मीरकासिम, शिराउद्दौला एवं शाह आलम की सेना	1764 ई.	अंग्रेज
14.	प्रथम मैसूर युद्ध	अंग्रेज एवं हैदरअली	1766- 69 ई.	हैदरअली
15.	रुहेला युद्ध	लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं हाफिज खाँ	1774 ई.	अंग्रेज
16.	सिन्दरखेड़ा का युद्ध	निजाम एवं मराठे	1775 ई.	मराठे
17.	प्रथम मराठा युद्ध	वारेन हेस्टिंग्स एवं हाफिज खाँ	1775- 82 ई.	अनिर्णीत
18.	द्वितीय मैसूर युद्ध	लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, हैदर एवं टीपू सुल्तान	1780- 84 ई.	अनिर्णीत
19.	तृतीय मैसूर युद्ध	लॉर्ड कार्नवालिस एवं टीपू सुल्तान	1790-92 ई.	अंग्रेज
20.	चतुर्थ मैसूर युद्ध	लॉर्ड वेलेजली एवं टीपू सुल्तान	1799 ई.	अंग्रेज
21.	द्वितीय मराठा युद्ध	लॉर्ड वेलेजली एवं मराठा राज्य	1803-1806 ई.	अंग्रेज
22.	नेपाल युद्ध	लॉर्ड हेस्टिंग्स (सेनापति आक्टर सोनी) एवं गोरखे	1814-1816 ई.	अंग्रेज
23.	तृतीय मराठा युद्ध	लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं मराठा राज्य	1817-1819 ई.	अंग्रेज
24.	पिण्डारी युद्ध	कर्नल स्लीमेन एवं पिण्डारी लुटेरे	1817-1818 ई.	अंग्रेज
25.	किर्वी का युद्ध	अंग्रेज एवं पेशवा बाजीराव II	1817 ई.	अंग्रेज
26.	सीताबर्डी का युद्ध	अंग्रेज एवं भोंसले अप्पा जी	1817 ई.	अंग्रेज
27.	अष्टी का युद्ध	अंग्रेज एवं पेशवा बाजीराव II	1817 ई.	अंग्रेज
28.	प्रथम बर्मा युद्ध	अंग्रेज (एमर्हस्ट एवं बर्मा)	1824-1826 ई.	अंग्रेज
29.	प्रथम अफगान युद्ध	अंग्रेज गवर्नर जनरल आकलैण्ड एवं अफगान	1839-1842 ई.	अंग्रेज
30.	मियानी (सिन्ध का युद्ध)	अंग्रेज (ऐलनबरो) व सिंधी अमीर	1843 ई.	अंग्रेज
31.	प्रथम सिख युद्ध	अंग्रेज (हार्डिंग) एवं सिख	1845-1846 ई.	अंग्रेज
32.	द्वितीय सिख युद्ध	अंग्रेज (डलहौजी) एवं सिख	1848-1849 ई.	अंग्रेज
33.	चिलियाँवाला का युद्ध	अंग्रेज सेनापति ह्यूगफ एवं सिख सेनापति शेरसिंह	1849 ई.	सिख
34.	द्वितीय बर्मा युद्ध	अंग्रेज (डलहौजी) व बर्मी सेना	1852 ई.	अंग्रेज
35.	द्वितीय अफगान युद्ध	अंग्रेज (लिटन) एवं अफगान	1878-1880 ई.	अंग्रेज
36.	तृतीय बर्मा युद्ध	अंग्रेज (डफरिन) एवं बर्मी सेनी	1885 ई.	अंग्रेज
37.	तृतीय अफगान युद्ध	अंग्रेज (चेम्सफोर्ड) एवं अफगान	1919 ई.	अंग्रेज
38.	भारत-चीन युद्ध	चीन द्वारा भारत पर आक्रमण	1962 ई.	चीन
39.	भारत-पाक युद्ध	पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण	1965 ई.	भारत
40.	भारत-पाक युद्ध	भारत-पाक (बांग्लादेश की स्वतन्त्रता के कारण)	1971 ई.	भारत

1857 के विद्रोहों के प्रमुख केन्द्र, नेता एवं काल

क्र.सं.	विद्रोह केन्द्र	नेतृत्वकर्ता	अवधि (कालक्रम)
1.	दिल्ली	बहादुरशाह II	11 मई, 1857 से 20 सितम्बर, 1858 ई.
2.	लखनऊ	बेगम हजरतमहल	20 मई, 1857 से मार्च, 1858 ई.
3.	कानपुर	नाना साहब	4 जून, 1857 से 15 मार्च, 1858 ई.
4.	झाँसी	रानी लक्ष्मीबाई	5 जून, 1857 से 4 अप्रैल, 1858 ई.
5.	इलाहाबाद	लियाकत अली	20 जून, 1857 से 10 जून, 1858 ई.
6.	बनारस	आम जनता + सेना	20 जुलाई, 1857 से 15 जून, 1858 ई.
7.	बिहार	कुँवर सिंह	15 जुलाई, 1857 से 20 जून, 1858 ई.
8.	पंजाब	आम जनता + सेना	20 जुलाई, 1857 से 25 जून, 1858 ई.
9.	बरेली	बख्त खाँ	20 जुलाई, 1857 से 27 जून, 1858 ई.

विगत वर्षों में आई.ए.एस. (प्री.) में पूछे गये प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

   1. लॉर्ड डलहौजी की सरकार ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेण्ट एक्ट पारित किया जिसने सिपाहियों को सरकार की आवश्यकतानुसार किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए बाध्य किया.
   2. लॉर्ड कैनिंग की सरकार द्वारा पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट ने सिपाहियों को उपलब्ध मुफ्त डाक-सेवा की सुविधा वापस ले ली.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?

   (A) केवल 1 (B) केवल 2
   (C) 1 और 2 दोनों (D) न ही 1 और न ही 2

2. भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान हुए नागरिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिदो तथा कान्हु कौनसे समुदाय के थे ?

   (A) कोली (B) मुण्डा
   (C) संथाल (D) भील

3. 1857 के विद्रोह के उपरान्त इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिगृहीत किए जाने की घोषणा की ?

   (A) लॉर्ड ऑकलैण्ड (B) लॉर्ड कैनिंग
   (C) लॉर्ड डलहौजी (D) लॉर्ड हार्डिंग

4. अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था ?

   (A) वी. वी. गिरि (B) एस. ए. डाँगे
   (C) जवाहरलाल नेहरू (D) लाला लाजपत राय

5. निम्नलिखित में से कौनसा एक सही सुमेलित है ?

   (A) 1866 का उड़ीसा दुभिक्ष – सर जॉन लॉरेंस
   (B) पूसा का कृषि शोध संस्थान – लॉर्ड हार्डिंग
   (C) सिंचाई का विकास – लॉर्ड ऑकलैण्ड
   (D) 1943 का बंगाल दुर्भिक्ष – लॉर्ड इर्विन

6. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची-I (काल)	**सूची-II (भू-राजस्व व्यवस्था)**
(a) 1833	1. रैयतवाड़ी
(b) 1793	2. महालवाड़ी
(c) 1792	3. जमींदारी
(d) 1769	4. पंचसाला
	5. दससाला

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	2	3	4
(B)	2	3	1	4
(C)	2	3	5	4
(D)	3	2	1	5

7. मोपला (मोपिला) विद्रोह (1921) में कहाँ हुआ ?

   (A) तेलंगाना में (B) मालाबार में
   (C) मराठवाड़ा में (D) विदर्भ में

8. निम्नलिखित में से कौन भारत में मजदूर संघ आन्दोलन से जुड़े थे ?
   1. बी. पी. वाडिया 2. एन. एम. जोशी
   2. ढुंडिराज थेंगड़ी 4. के. कामराज
   5. विट्ठलभाई पटेल
   नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–
   (A) केवल 1 एवं 2 (B) 1, 2, 3
   (C) 1, 3 एवं 4 (D) 3, 4, 5
9. वह कौन लेखक था, जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध कहा ?
   (A) अशोक मेहता (B) आर. सी. मजूमदार
   (C) एस. एन. सेन (D) वी. डी. सावरकर
10. त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह संघटित किया था–
    (A) 1800 ई. में (B) 1805 ई. में
    (C) 1809 ई. में (D) 1811 ई. में
11. निम्नलिखित में से कौनसा एक विद्रोह सिन्धी और कान्हों से सम्बद्ध है ?
    (A) संथाल विद्रोह, 1853
    (B) कोल विद्रोह, 1820-37
    (C) मुण्डा विद्रोह, 1899-1900
    (D) उड़ीसा जमींदारों का विद्रोह, 1804-17
12. निम्नलिखित में से कौन 1929 में ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे ?
    (A) एम. एन. राय (B) एस. ए. डाँगे
    (C) जयप्रकाश नारायण (D) जवाहरलाल नेहरू
13. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I

(a) सैयद अहमद बरेलवी
(b) मुहम्मद कासिम नानौतवी
(c) मिर्जा गुलाम अहमद
(d) जका उल्लाह

सूची-II

1. 'दार-उल-उलुम देवबन्द'
2. 'बराहिम'
3. 'तरीका-ए-मुहम्मदिया'
4. 'दिल्ली उर्दू रिनेसां' (पुनर्जागरण)

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	3	4	2
(B)	3	1	2	4
(C)	1	3	2	4
(D)	3	1	4	2

14. निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए–
    1. सर अत्तर सिंह 2. भाई तेजा सिंह
    3. सोहन सिंह भकना 4. करतार सिंह झब्बर
    इनमें से कौन सिंह-सभा आन्दोलन के संगठनकर्त्ता (Organizer) नहीं थे?
    (A) 1 और 4 (B) 3 और 4
    (C) 2 और 3 (D) 1 और 2
15. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I	सूची-II
(a) रानी लक्ष्मीबाई	1. ग्वालियर
(b) मौलवी अहमदुल्लाह	2. कानपुर
(c) नाना साहेब	3. फैजाबाद
(d) कुँवर सिंह	4. जगदीशपुर

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	4	2	1
(B)	1	3	2	4
(C)	2	3	4	1
(D)	1	2	3	4

16. निम्नलिखित में से कौनसा एक, सही सुमेलित नहीं है?
    (A) भील विद्रोह : 1818–31
    (B) सतारा विद्रोह : 1814
    (C) किट्टूर विद्रोह : 1824
    (D) गडकरी विद्रोह : 1844
17. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I	सूची-II
(a) मैसूर कृषकों का विद्रोह	1. 1846-47
(b) विशाखापत्तम विद्रोह	2. 1830-31
(c) गन्जम विद्रोह	3. 1830–34
(d) कुरनूल विद्रोह	4. 1835

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	2	4	1
(B)	2	3	1	4
(C)	2	3	4	1
(D)	3	2	1	4

18. अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह (Khasi revolt) का नेतृत्व किया–
    (A) सुरेन्द्र साई ने (B) टीटू मीर ने
    (C) बिरसा मुन्डा ने (D) उतिरोत सिंह ने

19. निम्नलिखित में से किसने बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया ?
    (A) खान बहादुर खान (B) मौलवी अहमद उल्लाह
    (C) बख्त खान (D) अजीमउल्लाह खान

20. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए–
    1. होमरूल लीग का गठन
    2. राजद्रोह के आरोप में तिलक को छः वर्षों का निर्वासन
    3. सैनफांसिस्को में गदर पार्टी का गठन
    4. गांधीजी का चम्पारण सत्याग्रह

    उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है–
    (A) 2, 1, 4, 3 (B) 2, 3, 1, 4
    (C) 3, 2, 1, 4 (D) 2, 1, 3, 4

21. निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार-पत्र प्रकाशित किया ?
    (A) गंगाधर भट्टाचार्य (B) रवीन्द्रनाथ टैगोर
    (C) मृत्युंजय विद्यालंकार (D) राममोहन राय

22. 1857 के विद्रोह से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. विद्रोहियों का कोई स्पष्ट राजनैतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था.
    2. जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए सन्धि-वार्ता की.
    3. विद्रोहियों को मौलवी अहमदउल्लाह द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया.
    4. केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोही असफल हो गए.

    इनमें से कौनसे कथन सही हैं?
    (A) 1 व 4 (B) 2 व 4
    (C) 1, 2 व 3 (D) 1, 2 व 4

23. रिंग फेस का सम्बन्ध है–
    (A) हेनरी लॉरेंस से (B) डलहौजी से
    (C) वारेन हेस्टिंग्स से (D) लॉर्ड हेस्टिंग्स से

24. सन् 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसीडेन्ट थे–
    (A) एन. जी. रंगा (B) स्वामी सहजानन्द सरस्वती
    (C) विद्यानन्द (D) बाबा रामचन्द्र

25. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित है ?
    (A) उल्गुलान – दसपल्ले
    (B) वन सत्याग्रह – कडूपा
    (C) खोंड विप्लव – कुमायूँ
    (D) सफा हर आन्दोलन – बिरसा मुण्डा

उत्तरमाला

1. (B)	2. (C)	3. (B)	4. (D)	5. (A)
6. (C)	7. (B)	8. (A)	9. (D)	10. (B)
11. (A)	12. (D)	13. (B)	14. (A)	15. (B)
16. (B)	17. (C)	18. (D)	19. (C)	20. (B)
21. (A)	22. (C)	23. (C)	24. (B)	25. (B)

संकेत

1. जनरल सर्विस एनलिस्टमेण्ट एक्ट (1856)–लॉर्ड कैनिंग पोस्ट ऑफिस एक्ट (1854)– लॉर्ड डलहौजी.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. 1857 ई. के विद्रोहों को कितने भागों में बाँटा जा सकता है ?
   (A) 3 (B) 4
   (C) 57 (D) 8

2. 1857 ई. में जो विद्रोह हुए, उनका प्रमुख कारण था–
   (A) अंग्रेजों की दोगली नीति (B) आर्थिक शोषण
   (C) राजनीतिक कारण (D) उपर्युक्त सभी

3. संन्यासी आन्दोलन का शुभारम्भ हुआ–
   (A) बंगाल में (B) बिहार में
   (C) गुजरात में (D) कलकत्ता में

4. संन्यासी आन्दोलन के समर्थक किसके अनुयायी थे ?
   (A) कृपाचार्य (B) शंकराचार्य
   (C) माधवानंद (D) श्यामाचार्य

5. संन्यासी आन्दोलन के विद्रोहकर्ता किस सम्प्रदाय के थे ?
   (A) वैष्णव (B) गिरि
   (C) वल्लभ (D) इनमें से कोई नहीं

6. संन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया ?
   (A) वारेन हेस्टिंग्स ने (B) डलहौजी ने
   (C) होमर ने (D) मैकाले ने

7. बंगाल के उत्तर-पूर्व में किसका राज्य था ?
   (A) कुषाणों का (B) अहोमों का
   (C) मुस्लिमों का (D) इनमें से कोई नहीं

8. 1828 ई. में अहोमों का राजा किसे बनाया गया ?
   (A) कुँवर प्रजापति को (B) गोमधर कुँवर को
   (C) गिरधर कुँवर को (D) गिरधर नवरत्न को

9. किसके नेतृत्व में रंगपुर पर पुनः आक्रमण की तैयारी की गई ?
   (A) स्वरूप चंद कोनार (B) रूपचंद कोनार
   (C) कैलाश चंद (D) दयानंद

10. 1833 में उत्तरी असम किसको सौंपा गया ?
   (A) धुरंदर सिंह को (B) बलविंदर सिंह को
   (C) पुरंदर सिंह को (D) इनमें से कोई नहीं

11. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के खासी तथा सिलहट पर अधिकार करने के प्रयास से जो विद्रोह हुआ, वह था–
   (A) संन्यासी विद्रोह (B) नगा विद्रोह
   (C) बहावी विद्रोह (D) खासी विद्रोह

12. बर्मा के राजा तीरतसिंह की मृत्यु कब हुई ?
   (A) 1836 ई. में (B) 1833 ई. में
   (C) 1834 ई. में (D) 1840 ई. में

13. विजयनगर नरेश का देहावसान कब हुआ ?
   (A) 1794 ई. में (B) 1798 ई. में
   (C) 1799 ई. में (D) 1780 ई. में

14. रंगपुर विद्रोह कब हुआ ?
   (A) 1874 ई. में (B) 1872 ई. में
   (C) 1873 ई. में (D) 1875 ई. में

15. रंगपुर विद्रोह का प्रमुख कारण था–
   (A) अधिक कर लगाना
   (B) वैमनस्यता बरतना
   (C) सुविधाओं में कमी करना
   (D) इनमें से कोई नहीं

16. रंगपुर का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ ?
   (A) धीरज नारायण और नूरुलुद्दीन
   (B) अकेले धीरज नारायण के नेतृत्व
   (C) नूरुलुद्दीन के नेतृत्व में
   (D) अवध नारायण के नेतृत्व में

17. रंगपुर विद्रोह में कितने किसानों ने भाग लिया था ?
   (A) करीब 10 हजार (B) करीब 12 हजार
   (C) करीब 20 हजार (D) करीब 18 हजार

18. बहावी आन्दोलन के प्रणेता कौन थे ?
   (A) करीम बरेलवी
   (B) सैय्यद अहमद बरेलवी
   (C) अहमद हुसैन बरेलवी
   (D) मुहम्मद हुसैन बरेलवी

19. सैय्यद अहमद बरेलवी के विचार किस पुस्तक में निहित हैं ?
   (A) शिरात-ए-मुस्तकिन (B) गंगोत्री
   (C) चिराग (D) इनमें से कोई नहीं

20. बंगाल प्रेसीडेंसी के लिए मुख्य कार्यालय कहाँ बनाया गया ?
   (A) हिमाचल (B) कलकत्ता
   (C) पटना (D) मद्रास

21. बहावी आन्दोलनकर्त्ताओं ने हिजरत करना कब प्रारम्भ किया–
   (A) 1828 ई. में (B) 1827 ई. में
   (C) 1826 ई. में (D) 1825 ई. में

22. हिजरत का अर्थ होता है–
   (A) दुश्मनों को देश से बाहर निकालना
   (B) दुश्मनों को सुरक्षा देना
   (C) दुश्मनों के साथ साँठगाँठ करना
   (D) दुश्मनों के साथ शत्रुता बढ़ाने का प्रयास करना

23. भारत को दारुल-उल-इस्लाम कौन बनाना चाहता था ?
   (A) मुहम्मद अली
   (B) अहमद शाह
   (C) सैय्यद अहमद बरेलवी
   (D) मुहम्मद शाह बरेलवी

24. अंग्रेजों ने भारत को दारुल-उल-हर्ब बना दिया है. यह किसका मानना था ?
   (A) बसीर अहमद का
   (B) सैय्यद अहमद बरेलवी का
   (C) मुहम्मद अली का
   (D) अहमद शाह का

25. अहमद बरेलवी कब शहीद हुए ?
   (A) 1831 ई. में (B) 1854 ई. में
   (C) 1835 ई. में (D) 1828 ई. में

26. अहमद बरेलवी की मृत्यु किसके साथ हुए युद्ध में हुई ?
   (A) हिन्दू (B) सिख
   (C) ईसाई (D) पारसी

27. उनकी मृत्यु के बाद बहावी आन्दोलन को किसने सँभाला ?
   (A) विलायत अली ने
   (B) इनायत अली ने
   (C) (A) और (B) दोनों ने
   (D) इनमें से कोई नहीं

28. अंग्रेज सरकार ने वहावियों के विरुद्ध कितने सैनिक अभियान चलाए ?
(A) 25 (B) 20
(C) 19 (D) 18

29. वहावी आन्दोलन कब खत्म हुआ ?
(A) 1872 ई. में (B) 1873 ई. में
(C) 1870 ई. में (D) 1871 ई. में

30. चुआर या भूमिज विद्रोह बंगाल के किस जिले में हुआ ?
(A) समस्तीपुर (B) मेदिनीपुर
(C) दरभंगा (D) इनमें से कोई नहीं

31. चुआरों के राजा जगन्नाथ ने कब विद्रोह किया ?
(A) 1770 ई. में (B) 1769 ई. में
(C) 1670 ई. में (D) 1768 ई. में

32. अंग्रेजों के शासन के खिलाफ कोलों ने किस वर्ष में वगावत कर दी ?
(A) 1831 ई. में (B) 1832 ई. में
(C) 1836 ई. में (D) 1837 ई. में

33. कोल आन्दोलन के नेतृत्वकर्त्ताओं की संख्या कितनी थी ?
(A) एक (B) दो
(C) चार (D) पाँच

34. कोल आन्दोलन की समाप्ति कब हुई ?
(A) 1833 ई. में (B) 1832 ई. में
(C) 1836 ई. में (D) 1840 ई. में

35. संथाल विद्रोह को सफल वनाने के लिए संथालों ने एक आमसभा का आयोजन कब किया ?
(A) 30 जून, 1856 ई. (B) 30 जून, 1858 ई.
(C) 30 जून, 1855 ई. (D) 30 जून, 1840 ई.

36. राजमहल तथा भागलपुर के मध्य रेल-डाक-तार सेवा किस आन्दोलन के तहत बन्द हुई ?
(A) संथाल (B) संन्यासी
(C) वहावी (D) नागरिक

37. संथाल विद्रोह के तहत् अंग्रेज सेना की ओर से कितने संथालों को मार गिराया गया ?
(A) करीव 18 हजार (B) करीव 15 हजार
(C) करीव 20 हजार (D) करीव 28 हजार

38. वर्मा युद्ध के अवसर पर भारतीय सेना की किस वटालियन ने युद्ध का वहिष्कार किया ?
(A) 47वीं वटालियन (B) सिख वटालियन
(C) राजपूत वटालियन (D) जाट वटालियन

39. भारतीयों को 1857 ई. के विद्रोह में सबसे अधिक किसने उकसाया ?
(A) डलहौजी की नीतियों ने
(B) वेलेजली की नीतियों ने
(C) होमर की नीतियों ने
(D) हेस्टिंग्स की नीतियों ने

40. "गोद निषेध नीति" किसने शुरू की ?
(A) होमर (B) क्लाइव
(C) डलहौजी (D) वेलेजली

41. भारत में पेंशन व्यवस्था किस शासक ने बन्द की ?
(A) क्लाइव (B) डलहौजी
(C) होमर (D) वेलेजली

42. मुगल "बादशाह" की उपाधि धारण नहीं कर सकेंगे, यह घोषणा किसने की ?
(A) लॉर्ड क्लाइव (B) लॉर्ड वेलेजली
(C) लॉर्ड मिंटो (D) लॉर्ड केनिंग

43. उपर्युक्त घोषणा कब की गई ?
(A) 1856 ई. में (B) 1857 ई. में
(C) 1850 ई. में (D) 1851 ई. में

44. अंग्रेजों की किस नीति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई तथा यहाँ के उद्योग-धन्धे नष्ट हो गए ?
(A) मुक्त निर्यात व्यवस्था
(B) मुक्त आयात व्यवस्था
(C) मुक्त व्यापार व्यवस्था
(D) इनमें से कोई नहीं

45. ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा दिलाने वाला कानून किसने वनाया ?
(A) लॉर्ड बैंटिंक ने
(B) लॉर्ड मिंटो ने
(C) लॉर्ड क्लाइव ने
(D) लॉर्ड डलहौजी ने

46. तात्कालिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को हिन्दू धर्म के वजाय किस धर्म की शिक्षा अधिक दी जाती थी ?
(A) सिख (B) ईसाई
(C) जैन (D) बौद्ध

47. पूरी भारतीय सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या कितनी थी ?
(A) 1/8 भाग (B) 1/4 भाग
(C) 1/6 भाग (D) 1/3 भाग

48. 1/6 भाग अंग्रेजी सैनिकों पर कितना खर्च किया जाता था ?
 (A) आधे से अधिक (B) चौथाई हिस्से का
 (C) तिहाई हिस्से का (D) पाँचवें हिस्से का

49. जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट किस शासक ने बनाया ?
 (A) लॉर्ड क्लाइव (B) लॉर्ड मिंटो
 (C) लॉर्ड केनिंग (D) लॉर्ड बैंटिक

50. सैनिकों की डाक सेवा किस नियम के तहत बंद की गई?
 (A) डाकघर अधिनियम
 (B) डाकपाल अधिनियम
 (C) डाकसेवा अधिनियम
 (D) इनमें से कोई नहीं

51. डाकघर अधिनियम कब बनाया गया ?
 (A) 1855 ई. में (B) 1856 ई. में
 (C) 1853 ई. में (D) 1854 ई. में

52. कम्पनी सरकार ने पुरानी ब्राउन बैस बन्दूक की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब से शुरू किया ?
 (A) जनवरी 1857 ई. से
 (B) फरवरी 1857 ई. से
 (C) मार्च 1858 ई. से
 (D) मार्च 1857 ई. से

53. मुगल शासक बहादुरशाह की मृत्यु कहाँ हुई ?
 (A) रंगून में (B) जापान में
 (C) म्यामांर में (D) रूस में

54. ब्रिटिश सरकार ने "भारत सरकार अधिनियम" कब बनाया ?
 (A) 1860 ई. में (B) 1859 ई. में
 (C) 1862 ई. में (D) 1858 ई. में

55. महारानी विक्टोरिया ने कम्पनी साम्राज्य समाप्त करने की घोषणा कब की ?
 (A) 1588 ई. में (B) 1858 ई. में
 (C) 1857 ई. में (D) 1860 ई. में

56. भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित की गई ?
 (A) 16 (B) 17
 (C) 15 (D) 20

57. उपर्युक्त गठित समिति का नाम था–
 (A) इण्डिया कौंसिल (B) इण्डियन कौंसिल
 (C) भारत कौंसिल (D) इनमें से कोई नहीं

58. इण्डिया कौंसिल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भूतपूर्व संचालकों के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे ?
 (A) 7 (B) 5
 (C) 8 (D) 10

59. उपर्युक्त इण्डिया कौंसिल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कितने सदस्य तय किए जाते थे ?
 (A) अठारह (B) बीस
 (C) दस (D) आठ

60. इस कौंसिल का मुख्य कार्य था–
 (A) अध्यक्ष को परामर्श देना
 (B) सचिव को परामर्श देना
 (C) परिषद् को परामर्श देना
 (D) इनमें से कोई नहीं

61. गवर्नर जनरल की स्थिति में कब परिवर्तन हुआ ?
 (A) 1860 ई. में (B) 1859 ई. में
 (C) 1889 ई. में (D) 1858 ई. में

62. गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन के बाद गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा ?
 (A) लॉर्ड (B) वायसराय
 (C) चेयरमेन (D) सचिव

63. वायसराय की सहायता के लिए गठित कार्यकारिणी परिषद् में प्रारम्भ में कितने सदस्य मनोनीत किए गए ?
 (A) आठ (B) सात
 (C) पाँच (D) छः

64. महारानी विक्टोरिया ने "कैसर-ए-हिन्द" की उपाधि कब धारण की ?
 (A) 1870 ई. में (B) 1872 ई. में
 (C) 1876 ई. में (D) 1880 ई. में

65. भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम कब बनाया गया ?
 (A) 1861 ई. में (B) 1872 ई. में
 (C) 1870 ई. में (D) 1860 ई. में

66. सैनिक पुनर्गठन के लिए किस कमीशन की स्थापना की गई ?
 (A) पील कमीशन (B) होमरूल कमीशन
 (C) सैनिक आयोग (D) इनमें से कोई नहीं

67. भारत में सीमा विस्तार की नीति कब समाप्त की गई ?
 (A) 1860 ई. के बाद (B) 1862 ई. के बाद
 (C) 1872 ई. के बाद (D) 1857 ई. के बाद

68. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई ?
 (A) 1890 ई. में (B) 1887 ई. में
 (C) 1885 ई. में (D) 1886 ई. में

69. समाज का वह कौनसा वर्ग था जिसने प्रारम्भ में तो 1857 के विद्रोह से स्वयं को अलग रखा, परन्तु बाद में समर्थन दिया ?
   (A) मध्यम वर्ग
   (B) उच्च वर्ग
   (C) निम्न वर्ग
   (D) श्रमिक वर्ग

70. उद्योगों के विकास के साथ-ही-साथ भारत में किस वर्ग का उदय हुआ ?
   (A) पूँजीपति वर्ग
   (B) श्रमिक वर्ग
   (C) मध्यम वर्ग
   (D) इनमें से कोई नहीं

उत्तरमाला

1. (B)	2. (D)	3. (A)	4. (B)	5. (B)
6. (A)	7. (B)	8. (B)	9. (B)	10. (C)
11. (D)	12. (C)	13. (A)	14. (C)	15. (A)
16. (A)	17. (A)	18. (B)	19. (A)	20. (C)
21. (C)	22. (A)	23. (C)	24. (B)	25. (A)
26. (B)	27. (C)	28. (B)	29. (D)	30. (B)
31. (D)	32. (A)	33. (D)	34. (B)	35. (C)
36. (A)	37. (B)	38. (A)	39. (A)	40. (C)
41. (B)	42. (D)	43. (A)	44. (C)	45. (A)
46. (B)	47. (C)	48. (A)	49. (C)	50. (A)
51. (D)	52. (A)	53. (A)	54. (D)	55. (B)
56. (C)	57. (A)	58. (A)	59. (D)	60. (B)
61. (D)	62. (B)	63. (D)	64. (C)	65. (A)
66. (A)	67. (D)	68. (C)	69. (A)	70. (B)

5

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम
(Indian Freedom Struggle)

[भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम–प्रथम चरण : राष्ट्रीय संचेतना का विकास, संघों का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा इसका नरमपंथी चरण, आर्थिक राष्ट्रीयता; स्वदेशी आन्दोलन; उग्रवाद में वृद्धि तथा कांग्रेस में 1907 ई. का विभाजन, 1909 ई. का अधिनियम–'फूट डालो और शासन करो' की नीति; कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच 1916 का समझौता

(The First Phase :
Growth of National Consciousness; Formation of Associating; Establishment of Indian National Congress & its Moderate Phase; Economic Nationalism; Swadeshi Movement; The Growth of Extremism & the 1907 Split in Congress; The Act of 1909–the Policy of Divide & Rule, Congress—Muslim League Pact of 1916)]

राष्ट्रीय संचेतना का विकास–19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों एवं भारत के आर्थिक शोषण के विरुद्ध विरोधों की शुरूआत हुई. जिसके परिणामस्वरूप 1857 की महाक्रान्ति हुई. व्यापक रूप से राष्ट्रीय संचेतना का विकास हुआ एवं विभिन्न संस्थाओं का उदय हुआ. भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए लम्बे पैमाने पर एकजुट हो गए. इस उल्लेखनीय अनुष्ठान में विभिन्न संस्थाओं के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपना महती योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः 1947 ई. में भारत को आजादी प्राप्त हुई.

भारतीय राष्ट्रवाद

भारतीय राष्ट्रवाद के विस्तृत अध्ययन से पूर्व 'राष्ट्रवाद' क्या है ? उसका अर्थ क्या है, के सम्बन्ध में जान लेना उपयुक्त होगा. राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता का पर्याय है. "जब किसी राष्ट्र के नागरिक स्थान, वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन, भाषा-साहित्य मूल्य मान्यताओं, जाति समूह और धर्म आदि के अन्तर होते हुए भी सभी को एक समझते हैं और राष्ट्रहित के समक्ष अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों का परित्याग करते हैं, यही भावना राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता कहलाती है." प्रसिद्ध समाज विज्ञानी बुवेकर राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं–"साधारण रूप में राष्ट्रीयता देश-प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है. राष्ट्रीयता में स्थान के सम्बन्ध के साथ-साथ जाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परम्पराओं के सम्बन्ध भी प्रदर्शित होते हैं." सन् 1961 में आयोजित 'राष्ट्रीय एकता सम्मेलन' की रिपोर्ट में वर्णित राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता का स्वरूप इस तरह प्रदर्शित होता है–"राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोगों के हृदयों में एकता, संगठन, सन्निकटता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति एवं भावना का विकास किया जाता है."

इसी सन्दर्भ में पारम्परिक सद्‌भाव, विश्वास, भावना, उत्कृष्ट कर्त्तव्य एवं उन्नत जीवन-मूल्यों के निर्वहन के समवायत्व स्वरूप को राष्ट्रीयता मानते हुए कोठारी शिक्षा

आयोग (1964-86) अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रवाद को स्पष्ट करता है–"राष्ट्रीय एकता अपने में राष्ट्रीय भविष्य में विश्वास, उन्नत जीवन-मूल्यों एवं कर्त्तव्यों की भावना, स्वच्छ प्रशासन का विश्वास और पारम्परिक सद्भाव सम्मिलित किए हुए हैं."

डॉ. हुमायूँ कबीर राष्ट्रीयता को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं–"राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है."

इन सभी परिभाषाओं से राष्ट्रवाद का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना में देश-प्रेम के तत्व निहित होते हैं जो देश के विविध मतावलम्बी निवासियों को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयास करते हैं. सच्ची राष्ट्रीयता वही है जिसमें व्यक्ति देशहित व राष्ट्रहित के लिए सभी कुछ त्याग देने के लिए तत्पर रहता है. यदि यह कहा जाए कि किसी राष्ट्र के अस्तित्व का राष्ट्रीयता मूल अंग है, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी.

डॉ. राधाकृष्णन का कथन है–"राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है, जिसमें सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ सम्बन्ध है."

भारतीय राष्ट्रवाद का उदय

राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद भारत के लिए नया नहीं है. पौराणिक ग्रन्थों, उपनिषदों, वेदों में कई मन्त्र, ऋचाएँ, स्मृतियाँ सिर्फ राष्ट्र की अवधारणा को स्पष्ट करने मात्र के लिए हैं. "यजुर्वेद के एक मन्त्र में सारे देशवासियों के हितार्थ योगक्षेम की कामना की गई है." योगक्षेम से तात्पर्य है– भौतिक एवं आध्यात्मिक समन्वित समृद्ध जीवन यानि राष्ट्र के सभी वर्गों का अभ्युदय. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयता की अवधारणा के लिए समाहित तत्व–मातृभाषा, संस्कृति और मातृभूमि पूर्णतः भारत के लिए राष्ट्रीयता के पुरातनकालिक सम्बन्धों को उजागर करते हैं. इन सबके बावजूद राष्ट्रीयता तभी फलीभूत होती है जब राष्ट्र प्रभुता सम्पन्न और लोकतान्त्रिक हो. प्रभुता प्राप्ति के मूल में संघर्ष अत्यावश्यक होता है.

आधुनिक युग में भारतीय राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद का उदय सन् 1857 ई. की क्रान्ति के समय से माना जाता है. सन् 1857 ई. का व्यापक सैनिक विद्रोह अंग्रेजी राज के विरुद्ध भारतीयों का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम था. इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया. इस ऐतिहासिक संग्राम के विरुद्ध फिरंगियों ने कठोर नियम, कानून लागू किए. थॉमसन, गैरेट और मैलेसन द्वारा लिखित कुछ अंश अंग्रेजी दमन नीति को स्पष्ट करते हैं–"हर एक हिन्दुस्तानी जो अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ रहा था, उसे हत्यारा माना जाए. दिल्ली निवासियों का कत्ले आम किया जाए." इस सन्दर्भ में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नर जनरल की तत्कालीन दर्ज रिपोर्ट के अनुसार–"गाँव-गाँव में आग लगाकर लोगों को मार डाला गया. फाँसी देने वाले दल जिलों में गए. कुछ फाँसी देने वाले लोग शौकिया थे, जिन्होंने कलात्मक ढंग से लोगों को मारा. कई जान लेने के ढंग आविष्कृत किए गए. इसी दौरान वीर सावरकर की पुस्तक "स्वतन्त्रता संग्राम का पहला युद्ध" पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया. इससे सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीयता की धूम मच गई और जनक्रान्ति को अपेक्षाकृत अधिक बल मिला. अंग्रेजी शासकों ने क्रान्ति के बाद समय-समय पर शासन व्यवस्था में कुछ सुधार किए और शासन के कार्यों में थोड़ा-थोड़ा भारतीयों का सहयोग लोगों ने आरम्भ किया, लेकिन सुधारों की गति बहुत धीमी थी अतः राष्ट्रवाद की कोपलें तेजी से पल्लवित होने लगीं. कई स्वयंसेवी राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों का सूत्रपात हुआ. भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों की स्थापना में सबसे अहम् भूमिका इलबर्ट बिल की रही. इसके अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय अपराधियों को दण्ड देने का अधिकार दे दिया गया था. अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया. हेनरी कॉटन के अनुसार–यूरोपियनों द्वारा इस न्यायसंगत कानून का विरोध करने पर भारतीयों को राष्ट्रीय राजनीतिक सभा के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके माध्यम से वे अपनी आवाज सरकार तक पहुँचा सकें. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सन् 1876 ई. में इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना की. सन् 1883 ई. के अन्तिम माह में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें एक अखिल भारतीय संगठन को मूर्त रूप देने की अनुशंसा की गई. तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने भारतीयों की योजना का अनुमोदन किया. डफरिन के कथनों से आश्वस्त होकर सर ए. ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों एवं अन्य पचास शिक्षित नवयुवकों से स्वातन्त्र्य हितार्थ अपील की, जिसके फलस्वरूप 28 दिसम्बर, 1885 ई. को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी.

बाद में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास बन गया. राष्ट्रीय आन्दोलन के संघर्ष में राष्ट्र के समस्त वर्गों ने एकजुट होकर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक संघर्ष किया. राष्ट्रवाद की संकल्पना के विकास में स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द, गोखले, लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाषचन्द्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने महती भूमिका का निर्वहन किया. एक ओर राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता का संघर्ष व्यावहारिक रूप से लड़ा गया और दूसरी ओर राष्ट्रवाद का सैद्धान्तिक धरातल विकसित किया गया. इसके धार्मिक,

आध्यात्मिक समन्वयकारी, नरम, उग्र और मानवतावादी स्वरूप को मुखरित किया गया. कुछ साम्प्रदायिक शक्तियों ने राष्ट्रवाद का विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया जिसे विदेशी हुकूमत ने सहारा दिया और इसके फलस्वरूप 16 अक्टूबर, 1905 ई. को बंगाल विभाजन हुआ.

राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास

विदेशी शासकों ने भारत में प्रवेश के दौरान सम्पूर्ण भारत का राष्ट्रीय एकीकरण किया. देशवासियों में एकता की भावना जाग्रत की एवं भारत को अखण्ड एक इकाई बनाया. चूँकि भारत में एकता, राष्ट्रवाद की चेतना और संकल्पना का इतिहास, विश्व के इतिहास से भी अधिक प्राचीन है. एकता के स्वर दुनिया के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद के प्रणेता ऋषियों की वाणी में ही प्रस्फुटित हो चुके थे. इतना अवश्य था पुरातन काल में राष्ट्रवाद मात्र भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक ही सीमित था. राजनीतिक एकता का अस्तित्व प्राचीन भारत में नहीं था. अतैव आधुनिक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रवाद की संकल्पना अपूर्ण ही रह जाती है. सार्वभौमिक एवं नितान्त आधुनिक संकल्पना राष्ट्रवाद का अर्थ राजनीतिक एकता मानती है.

राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना के अनुसार 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता भारत में अस्तित्व में आई यानि राजनीतिक एकता का सूत्रपात 19वीं शताब्दी में ही हो पाया. विभिन्न आन्दोलनों, भारतीय विचारकों, साहित्यकारों और विभिन्न घटनाओं ने राष्ट्रीय चेतना की ज्वाला को अधिकाधिक भड़काया. भारत के राष्ट्रवाद की गति और शक्ति को समूल नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने साम्प्रदायिक झगड़े फैलाना शुरू किया एवं "फूट डालो, आपस में लड़ाओ और राज करो" की नीति अपनाई. इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयता की लहरें अनवरत बढ़ती रहीं और अन्ततः भारतीय राष्ट्रवाद के हाथ विजय पताका लग ही गई.

आधुनिक भारत के जनक एवं राष्ट्रवाद के अग्रदूत राजा राममोहन राय (1774-1833)

विश्व धर्म के अद्वितीय समर्थक–राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना के अर्थ में भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत एवं आधुनिक भारत के जनक राजा राममोहन राय थे. राजा राममोहन राय विश्व की अनेक भाषाओं के विद्वान् थे. अरबी, फारसी, संस्कृत में अत्यधिक योग्य एवं अंग्रेजी, फ्रेंच, हैब्रू और ग्रीक भाषाओं में पारंगत राजा राममोहन राय विश्व धर्म में गहरी शृद्धा रखते थे. सन् 1805 से 1824 ई. तक राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी शासकों के अधीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेवा करते हुए समय व्यतीत किया. उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद कलकत्ता बसकर लोगों की निःस्वार्थ सेवा करना प्रारम्भ किया. 1814 ई. में उन्होंने आत्मीय सभा प्रारम्भ की. सन् 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की. सन् 1831 में मुगल सम्राट् के किसी कार्यवश उन्हें इंग्लैण्ड जाना पड़ा और उसी दौरान मुगल सम्राट् ने उन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया. दुर्भाग्यवश 27 सितम्बर, 1833 ई. को ब्रिस्टल (इंग्लैण्ड में) उनका स्वर्गवास हो गया.

प्रबल राष्ट्रीय भक्त–राजा राममोहन राय एक प्रबल राष्ट्रीय भक्त थे. वे स्वतन्त्रता के आदर्शों में गहरी आस्था रखते थे. उनका कहना था–"स्वतन्त्रता मानव मात्र के लिए बहुमूल्य वस्तु है, जो राष्ट्र के लिए भी अत्यावश्यक है. स्वतन्त्रता की माँग विश्व के किसी भी कोने में हो उसमें सहयोग करना चाहिए, यह हमारा कर्त्तव्य है." उस दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सम्भव नहीं था अतः उन्होंने राजनीतिक जागृति के कार्य को जारी रखा.

पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के समर्थक–राजा राममोहन राय शिक्षा एवं विज्ञान के विकास में क्षेत्रीयता को दृष्टिगत नहीं रखते थे. पूर्वी क्षेत्र की समस्त भाषाओं के विद्वान् होने के बावजूद उन्हें अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था. उनका निश्चित और अटल विश्वास था कि पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान के समन्वय से भारत को उन्नति की राह प्राप्त होगी. तत्कालीन शैक्षणिक संस्था हिन्दू कॉलेज को मूर्त रूप देने का श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है.

स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के समर्थक–स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के समर्थक एवं समाचार-पत्रों के संस्थापक राजा राममोहन राय ने राष्ट्रीय प्रचार एवं समाज सुधार के लिए तीन समाचार-पत्र प्रकाशित किए. सन् 1821 में बंगला भाषा में संवाद कौमुदी, सन् 1822 में मिरात उल अखबार फारसी भाषा में तथा सन् 1829 में हिन्दी भाषा में बंगदूत नामक समाचार-पत्र निकालना प्रारम्भ किया. सन् 1823 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के त्यागपत्र के बाद जनवरी माह में सर जॉन एडम अंग्रेजी प्रदेशों के कार्यवाहक महाराज्यपाल बने. उन्होंने समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता के लिए आदेश जारी किया कि वही अखबार मालिक को समाचार-पत्रों का लाइसेंस दिया जाएगा, जो अंग्रेजी सरकार की आलोचना नहीं करेंगे. राष्ट्रवाद की प्रगति का अवरोधक परिणाम जानकर राजा राममोहन राय ने इस आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय तथा सम्राट् जॉर्ज चतुर्थ को एक याचिका भेजी. स्वतन्त्रता के महान् उपासक एवं प्रशासन की मनमानी के विरोधी राजा राममोहन राय संवैधानिक प्रशासन की स्थापना के समर्थक थे. राजा राममोहन राय के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हुए एक ईसाई

धर्म के प्रचारक विलियम लिखते हैं–"स्वतन्त्रता का प्रेम सम्भवतः उनकी आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा थी." 11 अगस्त, 1821 ई. को कलकत्ता पत्रिका के सम्पादक 'जेम्स सिल्क बकिंघम' को एक पत्र राजा राममोहन रायने लिखा– "स्वतन्त्रता के दुश्मन और प्रशासन में अपनी मर्जी के मालिक कभी सफल नहीं हुए और अन्ततोगत्वा असफल ही होंगे."

महान् समाज सुधारक एवं अन्याय विरोधी–राजा राममोहन राय एक समर्पित समाज सुधारक थे. सती प्रथा को अमानवीय संस्था करार देते हुए उन्होंने इसके विरुद्ध एक सघन आन्दोलन चलाया. अतिवादी एवं कट्टर लोगों ने उनका विरोध किया. उनके आग्रह को मानते हुए तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने 1829 ई. में सती प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया. सती प्रथा के समाप्त होने के साथ ही राजा राममोहन राय सुधारकों की अग्रिम पंक्ति में आ गए. राजा राममोहन राय अन्याय विरोधी थे. जूरी एक्ट 1827 ई. के अनुसार ईसाइयों के मुकदमे के दौरान कोई भी मुस्लिम या हिन्दू जूरी का सदस्य नहीं बन सकेगा, जबकि हिन्दू-मुस्लिमों के मुकदमे की सुनवाई के दौरान ईसाई जूरी के सदस्य बन सकते थे. इस कानून का राजा राममोहन राय ने सख्ती से विरोध किया एवं ब्रिटिश सरकार को इसके खिलाफ ज्ञापन भेजा. सेना के भारतीयकरण की माँग भी राजा राममोहन राय ने ब्रिटिश शासकों के समक्ष रखी.

धर्म सुधारक, विचारक एवं सत्यप्रिय व्यक्तित्व–राजा राममोहन राय, सर्वधर्म प्रिय एवं सत्यनिष्ठ विचारक थे. उन्होंने हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का गम्भीरता से अध्ययन एवं चिन्तन किया. अपने निष्कर्ष के अनुसार उन्होंने एकेश्वरवाद, पाप कर्मों से दूर रहने एवं सच्चे, शुद्ध जीवन पर बल दिया. ब्रह्म समाज में परमेश्वर की उपासना का ढंग सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए उपयुक्त था. जप, माला और आडम्बर रहित जीवन को अपनाना राजा राममोहन राय ने उत्कृष्ट जीवन बताया.

आधुनिक युग के प्रणेता–सच्चे रूपों में यदि राजा राममोहन राय के जीवन के सम्बन्ध में आकलन किया जाए, तो निश्चित रूप से राजा राममोहन राय आधुनिक युग प्रणेता के रूप में मुखरित होते हैं. महाकवि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर उनके स्वरूप को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं–"राजा राममोहन राय ने आधुनिक युग का सूत्रपात किया है. वे भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पिता और राष्ट्रवाद के अग्रदूत हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के द्वारा राजनीतिक जागृति के लिए मार्ग तैयार किया है." एक प्रसिद्ध विचारक शील के अनुसार–"राजा राममोहन राय विश्व मानवता के विचार के संदेशवाहक थे. वे मानवतावादी और विश्व मानवीयता के दिग्दर्शक सरल एवं स्पष्ट हृदय के व्यक्ति थे." संसार के पहले खोजकर्त्ता सिद्ध करते हुए पश्चिमी क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान् मोनियर विलियम्स कहते हैं– "राजा राममोहन राय विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक विश्लेषण का पहला विश्व भर में महान् अन्वेषक था." यद्यपि अंग्रेजी साम्राज्य को वे ईश्वरीय देन मानते थे, लेकिन उनका मानना था कि प्रशासन में भी भारतीयों को अधिक-से-अधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए. इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में उनके सिद्धान्तों का समन्वयीकरण का जिक्र करते हुए डॉक्टर डी. पामर लिखते हैं–"राष्ट्रवाद से बहुत पहले राजा राममोहन राय हुए फिर भी उनके सिद्धान्तों एवं शिक्षा से 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान मिल पाया."

भारतीय राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नवजागरण के प्रवर्तक

स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824-1883 ई.)

राजा राममोहन राय के बाद भारतीय राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक सांस्कृतिक महानता में विश्वास पैदा कर पुनर्जाग्रत करने वाले स्वामी दयानन्द सरस्वती थे. मूलशंकर के नाम से पहचाने जाने वाले इस प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्व का जन्म फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में संवत् 1881 को दशमी के दिन अर्थात् अंग्रेजी सन् के अनुसार 12 फरवरी, 1824 ई. को काठियावाड़ (सौराष्ट्र) के मौरवी जनपद के टंकारा ग्राम में हुआ. उन्होंने मानसिक परतन्त्रता से भारतीयों को मुक्त करने के लिए हिन्दी को राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाकर भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में दूरदर्शी और प्रेरणास्पद कदम उठाया. स्वयं स्वामी दयानन्द के शब्दों में– "जिस देश में एक भाषा, एक धर्म और एक वेशभूषा को महत्व नहीं मिलेगा, उसकी एक लड़खड़ाती रहेगी." स्वामीजी ने नारी, शूद्रों के सम्मान, हिन्दू धर्म और ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष जोर दिया. वेदों पर अटूट श्रद्धा एवं विश्वास रखने वाले स्वामीजी मूर्ति पूजा विरोधी थे. स्वामीजी वेदों के आदेशों पर चलते थे. वैदिक मंत्रों से नियमित संध्या एवं हवन करते थे. स्वामीजी के जीवन का लक्ष्य सर्वथा सत्य का प्रचार, एकता और समस्त भारतीयों को प्रेममय बनाना था. वे ऐसी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे कि जिससे संसार में कोई भी प्राणि जीवनपर्यन्त दुःखी न हो.

स्वामीजी स्वराज के समर्थक थे. उनका कहना था, "स्वराज्य से अच्छा सुराज कदापि नहीं हो सकता." वे स्वदेशी वस्तुओं और वेशभूषा के प्रबल समर्थक थे. वे अपने देशवासियों से कहते थे, "जब अंग्रेजों ने भारत आकर भी तुम्हारी वेशभूषा नहीं अपनायी, तो तुम्हें अपने देश में ही

अपनी वेशभूषा को छोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी है?" स्वामीजी का विचार था, "विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से पराधीनता एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग्रत होता है." उन्होंने वेदों का हिन्दी में भाष्य किया और शास्त्रार्थ से ईसाई धर्म का हिन्दू धर्म पर आक्रमण से रक्षा की. उनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश भी राष्ट्रवाद के लिए वरदान साबित हो सकी. स्वामी दयानन्द सरस्वती राष्ट्र प्रेमी थे. उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन नहीं किया था, अतः लेखन में कोई बनावट नहीं थी. सत्यार्थ प्रकाश में उनके द्वारा देश की पराधीनतावश हुई दुर्दशा से पाठक वर्णित लेखों को पढ़कर भावुक हो जाते थे. जीवनपर्यंत देशवासियों के हृदय में राष्ट्रवाद और स्वदेश की महानता का विश्वास जाग्रत करने वाले वे राजा राममोहन राय के बाद दूसरे व्यक्ति थे. 7 अप्रैल, 1875 ई. को मुम्बई में स्वामीजी ने आर्य समाज की स्थापना की, जिससे राष्ट्रवाद के नवजागरण में उल्लेखनीय दिशा मिली. 30 अक्टूबर, 1883 को भारत के इस महान् राष्ट्रवादी एवं आध्यात्मिक विचारक का निधन दूध में जहर पिलाने से हो गया.

निष्कर्ष—यदि हम स्वामी दयानन्द सरस्वती के कार्यों का मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकालें, तो वे ऊँचे कद के समाज सुधारक, धर्म प्रचारक एवं मानव कल्याण, विश्व बन्धुत्व का संदेश देने वाले महर्षि थे. फ्रेंच लेखक रोम्यां रोलां स्वामीजी को उत्कृष्ट सिद्ध करते हुए लिखते हैं, "ऋषि दयानन्द उच्चतम व्यक्तित्व के पुरुष थे. उन्होंने अछूत तथा अस्पृश्यता के अन्याय को कभी सहन नहीं किया और भारतीयों के छिने अधिकारों को पुनः दिलाने के लिए प्रयास किया. भारत में स्त्रियों की दयनीय हालत को बड़ी उदारता एवं साहस से स्वामीजी ने सुधारा. वह नव निर्माण और राष्ट्रीय संगठन के उत्साही अग्रदूत थे." स्वामी दयानन्द के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए मैक्समूलर लिखते हैं, "स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू धर्म के लिए सुधार का बड़ा कार्य किया. वे समाज सुधार कार्यों में बड़े उदार व्यक्ति थे. उनके विचार वेदों और ऋषियों की वाणी पर आधारित थे. उन्होंने वेदों पर बड़े-बड़े भाष्य किए, जिससे उनकी पूर्ण विद्वता परिलक्षित होती है." इसी सम्बन्ध में स्वामीजी का आकलन करते हुए एमर्सन लिखते हैं, "यह मानना पड़ेगा कि भारत के सांस्कृतिक व राष्ट्रीय नवजागरण में स्वामी दयानन्द का स्थान महत्वपूर्ण है. उनकी मान्यताओं और सिद्धान्तों ने हीन भावना से ग्रसित समस्त भारतीयों को अपूर्व उत्साह से भर दिया."

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद उनके सन्दर्भ में लिखते हैं, "महर्षि दयानन्द के उपदेशों ने करोड़ों लोगों को नवजीवन, नव चेतना तथा नया दृष्टिकोण दिया है." अपने शब्दों में सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन अपना मत अभिव्यक्त करते हैं, "स्वामी दयानन्द एक महान् सुधारक और प्रखर क्रान्तकारी थे. उनके हृदय में सामाजिक कुरीतियों को उखाड़ फेंकने की प्रचण्ड ज्वाला थी."

कांग्रेस के संस्थापक सर ए. ओ. ह्यूम स्वमीजी के लिए लिखते हैं, "किसी भी तरह स्वामीजी को देखा जाए, वस्तुतः वे राष्ट्र के गौरव थे. वे एक महान् और श्रेष्ठ पुरुष थे, उनकी मृत्यु से हमें अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा है." स्वामी दयानन्द सरस्वती के अवसान के बाद उनके अनुयायियों ने राष्ट्रवाद की उन्नति का क्रम अनवरत रखा. लाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द, सरदार भगतसिंह, लाला हरदयाल और परमानन्द आर्य समाज के कट्टर समर्थक थे. समाज सुधार के साथ-साथ राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भी आर्य समाज के कट्टर समर्थक थे. समाज सुधार के साथ-साथ राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भी आर्य समाज के समर्थकों ने उल्लेखनीय योगदान दिया.

रामकृष्ण मिशन एवं विवेकानन्द का राष्ट्रीयता वृद्धि में योगदान

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अवसान पर उनकी स्मृति में 1896 ई. में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई. काली देवी के उपासक रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों का आदर करते थे. उन्होंने धार्मिक एवं राष्ट्रीय उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि पाश्चात्य संस्कृति से भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति भौतिक है, जबकि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है. अज्ञेय और निर्गुण ईश्वर को मानने वाले रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों को सनातन धर्मों का अंश मानते थे. रामकृष्ण परमहंस के उपदेश इतने व्यापक थे कि चन्द्रसेन जैसे विद्वान् एवं नरेन्द्र जैसे नास्तिक भी ईश्वर के अनन्य भक्त बन गये. एक सन्त के शब्दों में, "आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसायटी की कमी रामकृष्ण परमहंस ने पूरी की. उन्होंने धर्म को व्यावहारिक बनाकर धार्मिक और सांस्कृतिक जागृति उत्पन्न की." उनका स्वर्गवास 15 अगस्त, 1886 ई. को हुआ.

उनके देहावसान के बाद एक तर्कशील एवं प्रखर बौद्धिक नवयुवक नरेन्द्र, जो विवेकानन्द बने, ने सन् 1896 ई. में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. रामकृष्ण मिशन की स्थापना के पीछे विवेकानन्द के उद्देश्य राष्ट्रवाद के उत्थान के साथ वेदान्त और व्यावहारिक धर्म का प्रचार देश-विदेश में करना था. विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन का मुख्य कार्यालय कलकत्ता के बैल्लोर में तथा बंगलौर व अल्मोड़ा में मठ स्थापित किए. रामकृष्ण मिशन की शाखाएँ म्यांमार, मलाया, अमरीका, श्रीलंका तथा यूरोप में भी स्थापित की गईं.

विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में–स्वामी विवेकानन्द ने सम्पूर्ण भारतवर्ष ई. में पैदल भ्रमण कर आध्यात्मिक उपदेश

दिये. सन् 1893 ई. में स्वामी विवेकानन्द विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए. निराकार, सर्वव्यापी एवं अज्ञेय ईश्वर के उपासक स्वामी विवेकानन्द ने समानता के नाते जब सम्मेलन में उपस्थित लोगों को भाई-बहिन कहकर सम्बोधित किया, तो सब लोग स्तम्भित हो गये. हिन्दुत्व को श्रेष्ठतम साबित करने वाले विवेकानन्द ने स्पष्ट किया कि भारत आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व गुरु है और रहेगा. उनकी पहुँच व अभ्यास अंग्रेजी भाषा में भी कम न था. उन्होंने उच्च स्वर में विश्व धर्म सम्मेलन में कहा, "जब तुम हिन्दू धर्म के बारे में नहीं जानते, तो हमारे धर्म के बारे में फैसला करने वाले आप कौन होते हो?" विवेकानन्द के तर्कपूर्ण भाषण ने सभी को निरुत्तर कर दिया. शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन की विज्ञान शाखा के तत्कालीन अध्यक्ष सर मार्विनमेरी स्नेल ने स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध में कहा था, "सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानन्द ने ईसाई धर्म अनुयायियों विशेषकर अमरीका-वासियों को यह सिखलाया कि ईसाई धर्म की अपेक्षा ठोस, स्वच्छन्द, शक्तिशाली, व्यापक एवं मानवीय मूल्यों से संयुक्त अन्य धर्म भी हैं." न्यूयॉर्क हैराल्ड ने इस सर्वधर्म सम्मेलन के लिए लिखा था, "विवेकानन्द निःसन्देह सबसे महानतम् व्यक्ति हैं. उनके भाषण सुनने के बाद अनुभव होता है कि उन सरीखे विद्वानों के देश में ईसाई पादरियों को भेजना भयंकर मूर्खता है." भगिनी निवेदिता विवेकानन्द के प्रसंगों को समाहित करते हुए लिखती हैं, "स्वामी विवेकानन्द भारत का नाम लेकर जीते थे. वे मातृभूमि के अनन्य भक्त थे." स्वामी विवेकानन्द ने भारत का आह्वान किया था–"गर्व से बोलो कि हम भारतवासी हैं, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरी जवानी की फुलवारी, मेरा पवित्र स्वर्ग और मेरे बुढ़ापे की काशी है. भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है."

निष्कर्ष—स्वामी विवेकानन्द सच्चे अर्थों में आस्तिकवादी दृष्टिकोण के आध्यात्मिक उत्कर्ष थे. उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों से सम्पूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का परचम लहरा दिया था. भारतीय राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान में जितने सुधारकों ने सहयोग किया उसमें एक नाम विवेकानन्द के कदमों पर चले स्वामी रामतीर्थ का भी है, उन्होंने अपनी सम्मोहक शब्द शैली से सम्पूर्ण भारतीयों के मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की उथल-पुथल मचा दी थी.–"मैं सारे शरीर सहित भारत हूँ. हिमालय मेरा सिर और कुमारी अन्तरीप मेरा पैर है. पूर्व और पश्चिम दोनों मेरी बाहें हैं, जिनको फैलाकार मैं स्वदेशवासियों को गले लगाता हूँ, मैं मूर्तिमान भारत हूँ, सच्ची देशभक्ति ही ईश्वर सेवा है. भारत में मूर्ति को क्यों पूजा जाता है? मातृभूमि देवी रूप है, तो फिर उसे क्यों नहीं पूजा जाता."

भारतीय राष्ट्रवाद का एक अध्याय : थियोसोफिकल सोसायटी एवं एनीबेसेन्ट

सन् 1875 में एक रूसी महिला मैडम ब्लेवेटस्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना की. वे दोनों दयानन्द सरस्वती के निमंत्रण पर भारत आये थे. उन्होंने हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध किया. यद्यपि आर्य समाज एवं स्वामी दयानन्द ने "स्वधर्मो मरणो श्रेय" पर बल दिया, परन्तु अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों ने उनके तर्कों को नहीं माना और उनकी क्षतिपूर्ति का कार्य थियोसोफिकल सोसायटी ने पूरा किया. राष्ट्रवाद पर जोर देने एवं पादरियों के बहकावे में न आने के लिए मैडम ब्लेवेटस्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने पुरजोर प्रयास किया. इसके पश्चात् मिसेज एनीबेसेन्ट इस सोसायटी की प्रमुख कार्यकर्ता बन गयीं.

मिसेज एनीबेसेन्ट—भारत को अपनी मातृभूमि एवं हिन्दू धर्म को अपना धर्म मानने वाली एनीबेसेन्ट मूलतः आयरलैण्ड की रहने वाली थीं. वे 1893 ई. में भारत में थियोसोफिकल सोसायटी की सदस्यता बनकर आई थीं. जो आगे चलकर सोसायटी की अध्यक्षा बन गईं. वेद व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एवं उपनिषदों में उनकी गहरी आस्था थी. उनके अनुसार हिन्दू संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ है. मिसेज एनीबेसेन्ट ने सेन्ट्रल हिन्दू हाई स्कूल एवं कॉलेज की वाराणसी में स्थापना की. उनका विश्वास पूर्तिपूजा में था एवं वे बाल विवाह, सती प्रथा के विरुद्ध थीं. इण्डियन होमरूल आन्दोलन को चलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है. इण्डियन नेशनल कांग्रेस में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही. सन् 1917 में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस में उन्हें अध्यक्षा चुना गया.

भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान

सन् 1757 ई. में बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों के विरुद्ध असंतोष अत्यन्त तीव्र होता चला गया. ईस्ट इण्डिया कम्पनी शासन के प्रसार होने के साथ-साथ जन-आक्रोश निरन्तर बढ़ता रहा. अंग्रेजी नीतियों से प्रभावित राजाओं, ताल्लुकेदारों में रोष एवं निराशा की भावना व्याप्त हो गई, जिसके फलस्वरूप 100 वर्षों की अवधि में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय स्तर पर अनेक विद्रोह हुए. प्रमुख विद्रोहों में संन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, विजयनगरम् के राजा का विद्रोह, उड़ीसा के जमींदारों का विद्रोह, पोलीगरों का विद्रोह, कोलियों का विद्रोह, गदकरियों का विद्रोह, जाटों, राजपूतों और बुन्देलों का विद्रोह तथा मोपला विद्रोह, संथाल विद्रोह एवं अन्य विद्रोह इत्यादि

उल्लेखनीय हैं. ये सभी स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे विद्रोह थे, जो स्थानीय समस्याओं से जुड़े हुए थे. इन विद्रोहों में सबसे बड़ा विद्रोह 1857 ई. का महासंग्राम था. यद्यपि इस विद्रोह को विभिन्न नामों से जाना गया तथापि इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य विदेशी शासन का अन्त करना था. इस विद्रोह को मुख्य रूप से 'राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का प्रथम संग्राम' एवं 'सैनिक विद्रोह' के नाम से जाना गया. डॉ. एस. बी. चौधरी ने 1857 के इस विद्रोह को 'सामान्य जनता का विद्रोह' कहा था. वी. डी. सावरकर के अनुसार यह सुनियोजित स्वतन्त्रता संग्राम था, यद्यपि 1857 का यह विद्रोह पूर्णतः सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद से भारतीय जनता अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध उद्वेलित हो गई. इससे यह अवश्य स्पष्ट हो गया कि शक्ति के बल पर अंग्रेजी शासन को हटाया जाना मुश्किल था. इसके लिए व्यापक जनसमर्थन की आवश्यकता थी. यह कहा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप ही राष्ट्रीयता का उदय हुआ. राष्ट्रीयता के विकास में अनेक कारक उत्तरदायी थे, उनमें मुख्य कारण निम्नलिखित थे–

भारत का राजनीतिक एकीकरण–अंग्रेजी आधिपत्य के फलस्वरूप समूचा भारत देश राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से एक सूत्र में बँध गया. यद्यपि यह कार्य अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के कारण किया था, लेकिन यही कारक अंग्रेजों के विनाश का कारक बना. जब भारत में अंग्रेज नहीं आये थे, उस दौरान भारत में सर्वत्र राजनीतिक एकता का अभाव था. राजनीतिक रूप से भारत अनेक खण्डों में बँटा हुआ था. अंग्रेजों ने भारत में आकर सारे देश में एकछत्र शासन स्थापित कर एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम की तथा सारे भारत का प्रशासनिक अध्यक्ष वायसराय को बनाया. इसके परिणामस्वरूप भारतवर्ष के सभी लोग एकजुट होकर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने में सक्षम हो गये. फलतः राष्ट्रीयता का आविर्भाव हुआ.

अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असन्तोष–अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों, शोषण के प्रति अचानक भारतीयों का आक्रोश बढ़ता गया. राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक शोषण ने भारतीयों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भारतीयों के हितों की रक्षा अंग्रेजी शासन के रहते हुए कभी नहीं हो सकती और परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता का आविर्भाव हुआ. अंग्रेजी शासन के दौरान केवल जमींदार, महाजन, ताल्लुकेदार और रजवाड़े ही प्रसन्न थे. वे अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीयों का शोषण करते थे. इसके अतिरिक्त किसान, मजदूर, शिल्पी, शिक्षित एवं मध्यम वर्ग अंग्रेजी शासन के शोषण से आहत हो चुके थे. पूँजीपति वर्ग भी अंग्रेजों के शोषण से प्रभावित था. समाज के कुछ स्वार्थी वर्गों को छोड़कर सभी ने एकजुट होकर अंग्रेजी शासन को उखाड़ने का निश्चय किया.

भारतीय राष्ट्रीयता की आर्थिक पृष्ठभूमि–स्वतन्त्रता संग्राम (1857) के प्रथम चरण में भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक एकता के साथ-साथ आर्थिक एकता का भी आविर्भाव हुआ. अंग्रेजों के शासन में व्यापार, संचार और परिवहन के साधनों का विकास हुआ. व्यापारिक एवं औद्योगिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि कार्य पूरी तरह ठप्प हो गया. सामान्य जनता, किसान, मजदूर, कारीगर पूरी तरह बेकार हो गये. इन सबके चलते मूल्य-वृद्धि, अकाल, महामारी, देशी उद्योगों के विनाश एवं धन के निष्कासन का ताण्डव शुरू हो गया. जनता पर करों का भार बढ़ता गया, मजदूरी कम हो गयी और अनाज के मूल्य में वृद्धि हो गई. देहातों की गरीबी से बैंकर, व्यापारी और विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोग भी प्रभावित हुए. राष्ट्रीय आय भी न्यूनतम हो गई. इससे देहातियों एवं शहरी मध्यम वर्ग में आर्थिक असन्तोष व्याप्त हो गया. इस आर्थिक एकजुटता के फलस्वरूप सभी वर्ग समान रूप से अंग्रेजी शासन को नष्ट करने के लिए पूर्णतः एकजुट हो गये.

साहित्य एवं समाचार-पत्रों की भूमिका–भारतीय राष्ट्रीयता के आविर्भाव एवं राजनीतिक संचेतना के विकास में साहित्य एवं समाचार-पत्रों की भूमिका भी उल्लेखनीय रही. 1857 के विद्रोह से पूर्व भारत में समाचार-पत्रों की संख्या न के बराबर थी, लेकिन इस विद्रोह के उपरान्त इनकी संख्या तेजी से बढ़ गई. अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार-पत्रों का प्रकाशन होने लगा. इस दौरान के प्रमुख अंग्रेजी समाचार-पत्रों में स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इण्डिया, इंगलिशमैन, मद्रास मेल, सिविल एण्ड मिलीटरी गजट तथा फ्रैण्ड ऑफ इण्डिया इत्यादि थे. ये अंग्रेजी समाचार-पत्र ब्रिटिश सरकार के समर्थक तथा भारत विरोधी थे. इन समाचार-पत्रों में अंग्रेजी नीतियों की प्रशंसा में लेख लिखे जाते थे. कालान्तर में ऐसे समाचार-पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिन्होंने राष्ट्रीयता की जागृति में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया. ऐसे समाचार-पत्रों में–अमृतबाजार पत्रिका, हिन्दू पैट्रियट, इण्डियन मिरर, बंगाली, रस्ट गुफ्तूर नेटिव ओपीनियन, केसरी, मराठा, हिन्दुस्तानी, हिन्दू, आजाद, ट्रिब्यून प्रमुख थे. इन समाचार-पत्रों में अंग्रेजी सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती थी. इनके माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता का विकास किया जाता था. समाचार-पत्रों के अलावा तत्कालीन साहित्य भी इसका सर्वोत्तम उत्तरदायी कारक था. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का भारत दुर्दशा, बंकिमचन्द्र चटर्जी का आनन्द मठ, रवीन्द्रनाथ टैगोर का गोरा, मुंशी प्रेमचन्द का सोजे-वतन, केशवचन्द सेन का वामबोधिनी नामक उपन्यास जैसी कई साहित्यकारों की साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से भी राष्ट्रीयता का उदय एवं विकास हुआ.

सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलनों की भूमिका–1857 के विद्रोह के पूर्व एवं उपरान्त कई धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं का जन्म हुआ. इन संस्थाओं के माध्यम

से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारत में राष्ट्रीयता तेजी से पल्लवित हुई. इस दौरान की प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएँ निम्नलिखित थीं–

क्र. सं.	संस्था	संस्थापक	स्थापना वर्ष	स्थान
1.	ब्रह्म समाज	राजा राममोहन राय	1828 ई.	बंगाल
2.	आत्मीय सभा	ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय	1815 ई.	बंगाल
3.	तत्त्वबोधिनी सभा	देवेन्द्रनाथ टैगोर	1826 ई.	बंगाल
4.	आदि ब्रह्म समाज	केशव चन्द्र सेन	1865 ई.	कलकत्ता
5.	प्रार्थना समाज	आत्माराम पाण्डुरंग, महादेव गोविन्द रानाडे	1867 ई.	महाराष्ट्र
6.	रहनुमाई माजदायन समाज	दादाभाई नौरोजी	1851 ई.	मुम्बई
7.	मानव धर्म सभा	मंचाराम	1844 ई.	प. भारत
8.	यंग बंगाल आन्दोलन	हेनरी विवियन डिरोजियो	1826 ई.	बंगाल
9.	राधास्वामी सत्संग	शिवदयाल साहेब	1861 ई.	आगरा
10.	हिन्दू कॉलेज	डेविड हेयर	1822-23 ई.	कलकत्ता
11.	स्वामी नारायण सम्प्रदाय	संत स्वामी नारायण (सहजानन्द)	1861 ई.	द. भारत
12.	आर्य समाज	स्वामी दयानन्द सरस्वती	1875 ई.	बम्बई
13.	लैण्ड होल्डर्स सोसाइटी	जमींदारों की संस्था नेता– प्रसन्न कुमार टाकुर, राजा राधाकान्त देव, द्वारका नाथ ठाकुर	1837 ई.	कलकत्ता
14.	पूना सार्वजनिक सभा	रानाडे एवं चिपलंकर	1870 ई.	पुणे
15.	लन्दन इण्डिया कमेटी	सी. पुरुषोत्तम मुदालियर	1862 ई.	लन्दन
16.	अहमदिया आन्दोलन	मिर्जा गुलाम अहमद	1889 ई.	गुरुदासपुर
17.	थियोसोफिकल सोसाइटी	कर्नल अकांट एवं मैडम ब्लाट्वस्की	1882 ई.	अड्यार
18.	राष्ट्रीय समाज सुधार समिति	एम. जी. रानाडे	1887 ई.	मुम्बई
19.	राजमुन्दरी सोशल रिफार्म एसोसिएशन	वीर सेलिंगम पंतुलू	1878 ई.	हैदराबाद
20.	एस. एन. डी. पी. योगम्	नारायण गुरु	1903 ई.	केरल

इन जैसी हजारों धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने भारत में स्वदेश प्रेम की भावनाओं को जागृत किया. जिसके परिणामस्वरूप भारतीयों में आत्मसम्मान, राष्ट्रीयता एवं आत्म-गौरव का प्रादुर्भाव हुआ.

अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार–अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारत में अंग्रेजी भाषा का व्यापक प्रसार हुआ. अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीयों की मानसिकता तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हो गई. अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप ही भारतीयों की समझ में समानता एवं स्वतन्त्रता जैसे शब्दों का अर्थ भी आने लगा. विश्व के दूसरे देशों की तुलनात्मक स्थिति, विभिन्न क्रान्तियों के बारे में भारतीयों को जानकारी मिली. समान शिक्षा प्रणाली के कारण भारत में शैक्षिक एकीकरण हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ.

भारत के उद्योग, व्यापार एवं कृषि का विनाश–सन् 1813 ई. के बाद भारत का आर्थिक ढाँचा पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया. भारतीय व्यापार को इंगलैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति ने पूरी तरह तबाह कर दिया. भारतीय अर्थव्यवस्था की इस दयनीय दशा का प्रभाव 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में प्रदर्शित हुआ. मार्क्स ने विवरण देते हुए इस दुर्दशा को स्पष्ट किया था, "सन् 1780 से 1850 के बीच भारत में ब्रिटेन से आये माल की कुल कीमत 386152 से बढ़कर 80,24,000 पौण्ड हो गयी. 1850 में ब्रिटेन का सूती कपड़ा उद्योग का जो माल विदेशों में निर्यात किया जाता था उसका चौथा हिस्सा अकेले भारत में पहुँचता था. उस समय ब्रिटेन की जनसंख्या का आठवाँ हिस्सा इस उद्योग में लगा हुआ था और इस उद्योग से ब्रिटेन की कुल आय का बारहवाँ हिस्सा मिलता था." सन् 1818 से 1836 के बीच ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को धागे का निर्यात किया उसकी अनुपात में वृद्धि 1 : 5200 थी. 1824 में ब्रिटेन ने भारत को मुश्किल से 60,00,000 गज मलमल भेजा था, लेकिन 1836 में 6,40,00,000 गज मलमल निर्यात किया था. साथ ही मलमल के प्रसिद्ध ढाका की आबादी 1,50,000 से घटकर 20,000 हो गई. इसके साथ ही एशिया में अभूतपूर्व क्रान्ति हुई, जिससे भारतीय समाज की धुरी के रूप में पहचाने जाने वाले करघा और चरखे का अस्तित्व समाप्त प्रायः हो गया. गाँवों के आर्थिक जीवन को असंतुलित एवं औद्योगिक नगरों को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया. कृषि पर अत्यधिक लगान लिया गया और विस्तार के लिए असहयोग का रुख अपनाया गया, जिससे कृषि के क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया. उल्लेखनीय तथ्यों के अनुसार कर से प्राप्त होने वाली राशि का 0·8 प्रतिशत या न्यूनतम धन सार्वजनिक निर्माण पर व्यय किया गया.

यातायात के आधुनिक साधन–अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों के विकास, भारत के प्रशासन पर अपना नियन्त्रण मजबूत करने एवं भारत से अधिकाधिक आर्थिक लाभ उठाने

के उद्देश्य से ब्रिटिश शासकों ने रेलमार्ग, सड़कें व संचार, व्यवस्था का बखूबी निर्माण किया. पर इनके बावजूद ये साधन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को परस्पर निकट लाने में उपयुक्त एवं महत्त्वपूर्ण साबित हुए. इससे कुछ सामाजिक सेवाओं को निकालने में मदद हुई. प्रो. ए. आर. देसाई के अनुसार, "बिना रेलवे, मोटर, बसों और संचार के साधनों के राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन सम्भव नहीं था. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक आन्दोलन संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया." यातायात के इन आधुनिक साधनों ने एक विशाल शक्ति के रूप में भारतीय लोगों को सामाजिक रूप से संगठित किया. रेल के कारण से जो कि लम्बी दूरी तय कर सकती थी, ऐसी रेल व्यवस्था ने उस सामाजिक व्यवस्था को नजदीक करने में सहायता की जो विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को अलग-अलग करती थी. इन साधनों के सुलभ होने पर एक जगह राष्ट्रवाद की फूटी लहरें सम्पूर्ण देश में फैल जाती थीं.

इलबर्ट बिल सम्बन्धी विवाद–राष्ट्रीय आन्दोलन को इलबर्ट बिल ने बहुत प्रोत्साहन दिया. लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में इलबर्ट विधि मंत्री था. उसने केन्द्रीय व्यवस्थापिका में एक विधेयक पारित किया, जिसमें कहा गया कि सभी न्यायाधीशों को, चाहे वे भारतीय हों या अंग्रेज, समान अधिकार प्राप्त होने चाहिये. इसके अनुसार भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों को दण्डित कर सकते थे. इसका अंग्रेजों ने पुरजोर विरोध किया. इसके फलस्वरूप 1883 में अंग्रेजी नीति के विरोध के लिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने एक कान्फ्रेंस बुलाई, जिसका परिणाम राष्ट्रवाद की जागृति में सकारात्मक रहा.

1857 की क्रान्ति–सन् 1857 का व्यापक सैनिक विद्रोह राष्ट्रवाद के उत्थान में मूल कारण रहा. गाय के मांस वाले कारतूसों को मुँह से खोलने की बात को लेकर मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ यह संग्राम राष्ट्रीयता का 'प्रथम संग्राम' कहा गया. यद्यपि क्रान्ति विफल रही पर राष्ट्रीय चेतना भारतीय मनोमस्तिष्क पर हावी हो गई. एडवर्ड थॉमसन के अनुसार, "1857 की क्रान्ति के बाद भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति एक उत्कट घृणा की भावना छा गई और क्रान्ति का विचार आते ही उनमें अंग्रेजों से बदला लेने की भावना बलवती होती गई थी."

लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति–लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति ने राष्ट्रीय चेतना को विशेष बल दिया. उसका शासन-काल सन् 1876-81 भारतीय राष्ट्रीयता के बीजारोपण का समय कहलाता है. सन् 1876 से 1878 तक दक्षिण भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा. लाखों लोगों के मारे जाने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने पीड़ितों की सहायता नहीं की, इससे भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध रोष व्याप्त हो गया. इसी दौरान लॉर्ड लिटन ने राजाओं, नवाबों, महाराजाओं का एक बहुत बड़ा दरबार किया जिस पर अत्यधिक धन व्यय किया गया एवं घोषणा की गई कि महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण कर ली है. इससे भारतीयों को क्षोभ हुआ एवं दरबार की कड़ी आलोचना की गई. इसके अलावा लॉर्ड लिटन ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए द्वितीय अफगान युद्ध में भारत का करोड़ों रुपया नष्ट कर दिया. अकाल और गरीबी से त्रस्त भारतीयों को जाग्रत करने में यह एक भयंकर मोड़ आया और राष्ट्रवाद सम्पूर्ण देश में फैल गया. ब्रिटेन ने इसी दौरान शस्त्र विधेयक लागू किया जिसके अनुसार भारतीयों को शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था, जबकि अंग्रेजों को नहीं. वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लिटन की ही देन थी, जिससे भारत के समाचार-पत्र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के लिए तरसते रहे. आयात कर का हटाना, भारतीय वस्त्रों पर चुँगी लगाना एवं अन्य इसी तरह के दमनकारी कानून राष्ट्रीयता की ज्वाला को प्रज्वलित करने में कामयाब हो सके और समस्त भारतीयों ने अंग्रेजों से छुटकारा पाने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

विभिन्न परिस्थितियों के रहते राष्ट्र के कई प्रान्तों और नगरों में अनेक राजनीतिक संगठनों की नींव पड़ चुकी थी, फिर भी एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन को स्थापित करने का अभाव खटकता रहा. इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य को एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी सर ए. ओ. ह्यूम ने किया. जो आगे चलकर 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक' कहलाए. उन्हें इस संगठन के निर्देश लॉर्ड डफरिन से प्राप्त हुए थे. इस संगठन की उत्पत्ति का उद्देश्य असन्तुष्ट भारतीय बुद्धिजीवियों के सामने सुरक्षा कवच पेश करना था. सर ए. ओ. ह्यूम ने 1 मार्च, 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखकर निःस्वार्थ भाव से मातृ सेवा में जुट जाने की अपील की, जिससे राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके एवं व्यवस्थित अनुशासित सेना तैयार की जा सके.

इसके परिणामस्वरूप सन् 1884 ई. में थियोसोफिकल कन्वेंशन हुआ, जिससे देश के बौद्धिक एवं शिक्षित बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के विचार को मूर्त रूप देने का निश्चय किया. दिसम्बर 1884 ई. में इण्डियन नेशनल यूनियन स्थापित की गई, जिसके उल्लेखनीय प्रयासों से 28 दिसम्बर, 1885 को मुम्बई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के विशाल भवन में एक कांफ्रेंस का आयोजन हुआ. इसमें भारत के सब क्षेत्रों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था. एक लम्बे विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद

के बाद इस संस्था का नाम 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' (Indian National Congress) रखा गया. इस प्रकार इस राजनीतिक संस्था का अस्तित्व भयंकर प्रयासों के चलते स्थापित हो पाया. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर टिप्पणी करते हुए डॉ. ताराचन्द लिखते हैं, "कांग्रेस का जन्म भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी, इससे एक नवयुग के आगमन की घोषणा हुई. राष्ट्रीय एकता के युग की घोषणा जो ऊपर से लादी नहीं गई थी, बल्कि जनता के संकल्प की अभिव्यक्ति थी. कांग्रेस उस नये समाज की प्रवक्ता थी, जो प्लासी के बाद हुए 100 साल के दौरान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप विकसित हुआ था. यह उस प्रक्रिया की पूर्णता थी, जिसमें सभी भारतीयों की वैयक्तिक रूप से और साथ ही सामूहिक रूप से भागीदारी थी. पर 1885 में यह बताना कठिन था कि कांग्रेस का क्या भविष्य होगा ? अन्य संस्थाओं की तरह इसे भी बहुत बुरे समय से यानी जनता की उदासीनता और सरकार की नाराजगी के दौरों से गुजरना पड़ा. इन मंजिलों से गुजर कर ही वह ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को चुनौती देने का एक शक्तिशाली औजार बन सकी."

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को तत्कालीन आवश्यकता मानते हुए सर ए. ओ. ह्यूम के जीवनी लेखक श्री वेडरबर्न कहते हैं, "भारत के विभिन्न भागों से ब्रिटिश साम्राज्य के हितैषियों द्वारा सर ह्यूम को ब्रिटिश सरकार तथा भारत के भविष्य के खतरे की चेतावनी मिल गई थी, क्योंकि जनता के कष्ट बढ़ गए थे और बुद्धिजीवी सरकार के विरुद्ध हो गये थे. दक्षिणी भारत के दंगे कुछ गिरोहों की छुटपुट डकैतियों से आरम्भ हुए, यहाँ तक कि बाद में डाकुओं के जत्थे इकट्ठे मिल गए और पुलिस के लिए अत्यन्त शक्तिशाली सिद्ध हुए और पूना की सारी सेना को उनके विरुद्ध लगाना पड़ा. उनमें से एक वर्ग के नेता ने अपने आपको शिवाजी द्वितीय कहना आरम्भ कर दिया. उसने सरकार की शक्ति को ललकारा तथा चुनौती दी. बम्बई के राज्यपाल रिचर्ड टेम्पल के सिर को काट लाने के लिए 500 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया और इस प्रकार राष्ट्रीय आधार पर विद्रोह करने का दावा किया गया. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों को स्पष्ट करते हुए लाला लाजपतराय ने कहा था, "इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का एक प्रमुख कारण यह था कि ह्यूम अंग्रेजी दमनकारी साम्राज्य से भारतीयों की सुरक्षा करने का उपाय ढूँढ़ना चाहते थे, भारतीय समाज के विकृत स्वरूप को परिष्कृत करने का उद्देश्य ह्यूम का हमेशा रहा. राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के सन्दर्भ में उनका कथन था, "भारत के मुख्य राजनीतिज्ञ एक स्थान पर इकट्ठे हों, सामाजिक गतिविधियों पर विचार-विमर्श करें और एक-दूसरे के मित्र बनें." उनकी इच्छा यह नहीं थी कि भारतीय राजनीतिक मसलों पर बहस करें. सर ए. ओ. ह्यूम जब इस सन्दर्भ में तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन से मिले तो उन्हें अपनी इस अभिव्यक्ति के साथ प्रोत्साहित किया, "भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इंग्लैण्ड के विरोधी दल की भाँति यहाँ भी कार्य कर सके और सरकार को यह बता सके कि शासन में क्या खामियाँ हैं? और उसे दूर करने का तरीका क्या हो ?" लॉर्ड डफरिन के इन सुझावों से प्रेरित होकर ए. ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया, जो व्योमेशचन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता में 28 दिसम्बर, 1885 को बम्बई में पहली बैठक सम्पन्न कर पाई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य

एक भयंकर विषम वातावरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, लेकिन उसकी स्थापना के पीछे वास्तविक उद्देश्य समझ से बाहर रहे. यद्यपि कुछ लोग कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए मानते हैं. जिन विद्वानों का मानना है कि ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षार्थ कांग्रेस की स्थापना हुई उनका कहना था कि कांग्रेस के जनक सर ए. ओ. ह्यूम एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज पदाधिकारी थे, जिन्हें तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन से लेकर अन्य अंग्रेजी राजनीतिज्ञों का समर्थन प्राप्त था. ह्यूम ने सुनिश्चित गुप्त योजना का साधन बनकर अंग्रेजी साम्राज्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर एक कवच तैयार किया. प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 1857 के सैनिक विद्रोह से अंग्रेज अधिकारियों को विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों में असन्तोष व्याप्त होता जा रहा है. भारतीयों में राष्ट्रवाद उत्पन्न हो चुका है. अतः सम्भवतः विद्रोह की ज्वाला पुनः भड़क सकती है. इसी विद्रोह के भय से मुक्ति पाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई. अंग्रेजों का उद्देश्य था कि उनके विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति न हो और इस संस्था के माध्यम से भारतीय लोगों का क्रोध शब्दों से निकलता रहे. इस भावना को स्पष्ट करने के लिए सर वेडरबर्न ने अपनी पुस्तक 'बायोग्राफिकल स्केच ऑफ ए. ओ. ह्यूम' के पृष्ठ 77 पर लिखा था,[1] "भारतीयों की शक्तिशाली और बलशाली भावनाओं के विकास के लिए एक रक्षा कवच की आवश्यकता थी और यह रक्षा कवच कांग्रेस से अच्छा कोई नहीं हो सकता था." ह्यूम ने सर

1 Indian Nationalist Movement and Thought
— Dr. K. K. Sharma, Page 12

ऑकलैण्ड कॉलविन को अपने एक पत्र में लिखा था, "कांग्रेस की स्थापना की योजना का उद्देश्य ब्रिटिश शासकों के कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न एक प्रबल एवं बढ़ती शक्ति के विकास के लिए रक्षा नली का निर्माण करना है. लॉर्ड डफरिन ने भी कांग्रेस की स्थापना को इसलिए सहमति प्रदान की क्योंकि ये एक ऐसे उत्तरदायी संगठन की खोज में थे, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनमत का सही पता लग सके. लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक 'यंग इण्डिया' में लिखा है, "कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को खतरे से बचाना था, भारतीय राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए प्रयास करना नहीं. ब्रिटिश साम्राज्य का हित प्रमुख था, भारत का गौण और इसे कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने इस उद्देश्य का पालन नहीं किया."

कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को एक देशव्यापी संगठन द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम मानने वाले दूसरी विचारधारा के लोग स्वीकारते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे देश प्रेम और राष्ट्रीयता का प्रमुख उद्देश्य था. सर ए. ओ. ह्यूम की तरफदारी करते हुए उमेशचन्द बनर्जी लिखते हैं–"ह्यूम का मुख्य उद्देश्य प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञों को देश की सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए वर्ष में एक बार एकत्रित करना था." इसी तरह की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए डॉ. ताराचन्द लिखते हैं, "सन् 1885 ई. में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के साथ ही भारत में नई जिन्दगी के स्पन्दन अनुभूत हुए. यह भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी. पहली बार देशी या विदेशी सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि कुछ दृढ़ चित्त मातृभूमि के अग्रगामी सेवकों द्वारा जो भारत के विभिन्न भागों से आये थे, राजनीतिक एकता को उभार कर सामने रखा गया. वे बम्बई में एकत्र हुए और भारत के भविष्य पर चिन्तन और विचार-विमर्श करते रहे. उन्होंने तात्कालिक शासक वर्ग को एक साहसपूर्ण चुनौती दी और यह चेतावनी दी कि भारत अब आगे अपने भाग्य को विदेशियों के हाथों में सम्पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वह अपने भाग्य के निर्माण के लिए पूर्णत कटिबद्धः है. निर्णयात्मक शब्दों की शृंखला बनाते हुए डॉ. जकारिया लिखते हैं–"लोकतन्त्र भारतीय और ब्रिटिश समर्थकों के संयुक्त प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस महान् राष्ट्रीय संस्था का जन्म इस कार्य में इन्हें प्रमुख प्रेरणा, संकीर्ण राष्ट्रीय भावों से नहीं, अपितु सत्य और न्याय के उदात्त विचारों के प्रति सच्ची लगन और शक्ति से मिली, जिनके समर्थकों को वे अपने देश के लिए गौरव की बात मानते थे और जो पिछली शताब्दी के दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग से किये गये सुखद कार्यों का परिणाम थी."

इस तरह विभिन्न द्विपक्षीय विचारधाराओं को जब तर्क की कसौटी पर कसते हैं, तो स्पष्ट होता है कि ह्यूम की मानसिकता भले ही अंग्रेजी राज के प्रति होगी, परन्तु भारतीयों के प्रति भी उसे कम सहानुभूति नहीं थी. कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन भारतीयों को एकजुट करने में रही इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता.

सन् 1885-1905 तक कांग्रेस के उद्देश्य, कार्यक्रम, प्रभाव एवं उसके प्रति ब्रिटिश शासकों का दृष्टिकोण

1 मार्च, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व सर ए. ओ. ह्यूम द्वारा किया गया. उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को सम्बोधित करते हुए अपील की– "आप लोग सर्वाधिक रूप से शिक्षित भारतीय हैं. आपको स्वाभाविक रूप से भारत की मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का महत्वपूर्ण साधन बनना चाहिए. चाहे व्यक्तिगत हो या जातीय सम्पूर्ण महत्वपूर्ण स्रोत अन्दर से होने चाहिए तथा इन सबका आधार आप लोग हो, जो इस देश के सभ्य ज्ञानी व प्रतिभा सम्पन्न नागरिक हों. आप देश के प्रिय पुत्र हो, देश इस कार्य की शुरूआत के लिए आपको देखता हो. बेकार में मेरे जैसे विदेशी भारत तथा उसके बच्चों को प्यार करते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं, व्यर्थ में ही इस देश के लिए तथा उनके भले के लिए समय व धन देते हैं तथा विचार करते हैं. बेकार ही वे संघर्ष करें तथा त्याग करें, वे अपनी शिक्षा एवं सुझावों से सहायता कर सकते हैं. वे इन कार्यकर्त्ताओं के लिए लाभस्वरूप अपना अनुभव, योग्यताएँ तथा ज्ञान प्राप्त करें, किन्तु इसमें जातीयता का आवश्यक गुण नहीं. वास्तविक कार्य तो देश के लोग स्वयं ही कर सकते हैं." जैसा मैंने पहले कहा है–"आप इस भूमि के बेटे हैं. आप में से 50 व्यक्ति भी आत्म-त्याग की संतोषजनक शक्ति, देश के लिए गर्व व पर्याप्त प्यार, पवित्रता व निःस्वार्थ देशभक्ति की भावना नहीं रखते हैं तो भारत के लिए कोई आशा नहीं रह जाती है. उसके बेटे निम्न व असहाय होकर विदेशी शासकों के हाथ में यंत्र बने रहेंगे. जब वे व्यवस्था पर चोट करेंगे, तभी स्वतन्त्र हो सकते हैं और जब तक नेताओं के विचार निम्न व स्वार्थी रहेंगे, वे देश के लिए कुछ नहीं कर सकते. हर राष्ट्र उचित प्रकार से एक अच्छी सरकार अपनी योग्यता के अनुसार रख सकता है. यदि आप देश का सबसे शिक्षित व्यक्ति चुनेंगे तो वह व्यक्तिगत सुख व स्वार्थी लक्ष्यों का तिरस्कार नहीं कर सकेगा? तुम्हारे लिए व देश के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए पूर्ण संघर्ष करेगा. एक अधिक निष्पक्ष

प्रशासन, तुम्हारे अपने मामलों का प्रबन्ध में काफी हिस्सा होगा तब हम तुम्हारे दोस्त गलत होंगे." पत्र के अन्त में उन्होंने अभिव्यक्त किया "चाहे व्यक्तिगत हो या राष्ट्रीय, आत्मबलिदान या निःस्वार्थ केवल ये ही स्वतन्त्रता व खुशी के सफल पथ-प्रदर्शक हैं." सर ए. ओ. ह्यूम की इस अपील का शिक्षित भारतीयों द्वारा उचित प्रत्युत्तर दिया गया. सम्पूर्ण देश में नेताओं से सम्बन्ध स्थापित करने के बाद ह्यूम ने दिसम्बर 1885 में देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों को संगठित कर एक सभा बुलाने का निश्चय किया. इसी दौरान ह्यूम ब्रिटेन गये और वहाँ जाकर प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिज्ञों जैसे–लॉर्ड रिपन, जॉन डाइट आदि से समर्थन प्राप्त किया. इन समस्त गतिविधियों के उपरान्त डब्ल्यू. सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में संस्कृत पाठशाला के भवन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ. सर ए. ओ. ह्यूम ने इस संस्था के सचिव के रूप में उत्तरदायित्व निभाया. प्रथम अधिवेशन में 100 सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें सर्वाधिक बम्बई के 38 सदस्य, मद्रास के 21 प्रतिनिधि, बंगाल व पंजाब से तीन-तीन प्रतिनिधि थे. इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली सभा में देश के विभिन्न भागों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए जिनमें बैरिस्टर, व्यापारी, भूमिपति, मैनेजर, डॉक्टर, पत्रकार, कानूनी सलाहकार, वकील, अधिकारी एवं सभी धर्मों के अनुयायी उपस्थित थे.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ माँगें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गईं, वे निम्नलिखित थी–

(i) केन्द्र में और प्रान्तों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए. निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए तथा उन्हें सभी प्रश्नों पर बहस करने, बजट पर वाद-विवाद करने के अधिकार दिये जाएँ.

(ii) उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर दिया जाए.

(iii) सैनिक व्यय में कमी की जाए.

(iv) एक शाही आयोग भारतीय प्रशासन की जाँच करे.

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में व्याख्यान और प्रस्तावों की भाषा पूर्णतः विनम्र थी, इसमें ब्रिटिश शासकों के प्रति सम्मान का अद्भुत प्रदर्शन हुआ था. डब्ल्यू. सी. बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अत्यन्त नम्र स्वर में कहा था–"अधिकारी वर्ग के प्रति राजभक्ति का इजहार करती कांग्रेस सिर्फ इतनी माँग करती है कि सरकार के आधार को विस्तृत किया जाए और जनता को सरकार में उसका उचित और जायज हिस्सा दिया जाए." भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में संगठन को निश्चित आकार देने बतौर कुछ उद्देश्य डब्ल्यू. सी. बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में रखे. नये संगठन के लिए सूचीबद्ध किए गए उद्देश्य निम्नलिखित थे–

1. ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय हित के लिए कार्य कर रहे व्यवस्थित कार्यकर्त्ताओं में व्यक्तिगत निष्ठा और मैत्रीभाव को बढ़ाना.

2. राष्ट्रवाद के भावों द्वारा राष्ट्रप्रेमियों के प्रत्यक्ष मित्रतापूर्वक व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्रीयवाद से उत्पन्न पक्षपात को दूर करना और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जन्मी भावनाओं को प्रोत्साहित करना.

3. शिक्षित भारतीयों के सामयिक एवं सामाजिक सुधार से सम्बन्धित विचारों को क्रियान्वित करना.

4. आगामी वर्षों में भारतीय राजनैतिक हस्तियों के सार्वजनिक हित में किए जाने वाले कार्य के तरीकों का निर्धारण करना.

समय के परिवर्तित होते रहने के साथ कांग्रेस के लक्ष्य आवश्यकतानुसार बदलते गए. प्रारम्भ में कांग्रेस ने छोटी-छोटी माँगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा, किन्तु बाद में अपने उद्देश्यों को व्यापक बनाते हुए स्वशासन की माँग की गई. प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस प्रार्थना-पत्र प्रस्ताव आदि पर ही विश्वास करती थी. आगे चलकर प्रत्यक्ष विधि, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन तक आ गई थी.

सन् 1885 से 1905 तक कांग्रेस के कार्यक्रम

सन् 1885 से 1905 तक कांग्रेस ने अनेक प्रस्ताव अपने अधिवेशनों में पास किए. प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन भारत में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर होता था. विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष निम्नलिखित माँगें रखी गई थीं–

1. गवर्नर वायसराय की विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही अधिकारियों के बजाए चुने गए सदस्यों को ही इसमें शामिल किया जाए.

2. ब्रिटिश सेना की संख्या कम की जाए और सेना पर होने वाले अत्यधिक व्यय को रोका जाए.

3. भारतीय सचिव की भारत परिषद् को हटाया जावे.

4. स्थानीय संस्थाओं पर से सरकारी नियन्त्रण हटाकर उन्हें अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाएँ.

5. नमक पर लगे कर को हटाया या कम किया जाए.

6. बेरोजगारी को मिटाने, कृषि पर से दबाव कम किए जाने के प्रयास किए जाएँ.

7. पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाए एवं नये उद्योगों की स्थापना हो.

8. कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग-अलग किया जाए.

9. विदेशों से भारतीय हितों की रक्षा की जाए.

10. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.सी.एस.) की परिक्षाएँ भारत में ही कराई जाएँ.

11. भूमि कर में कमी एवं किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त कराया जाए.

12. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया जाए. प्रेस और समाचार-पत्रों को अधिक स्वतन्त्रता दी जाए.

13. किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण सुलभ करने के लिए कृषि बैंक खोले जाएँ.

14. बड़े पदों के लिए भारतीयों की उपेक्षा न की जाए.

15. भारत की निर्धनता के कारकों को खोजकर उनको दूर किया जाए.

16. उद्योग, व्यावसायिक, टेक्नीकल कॉलेज एवं स्कूल खोले जाएँ.

17. सैनिक शिक्षा के लिए भारत में प्रशिक्षण केन्द्र लगाया जाएँ.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम युग (1885 से 1905) में कांग्रेस का आन्दोलन ह्यूम, सर वेडरबर्न, व्योमेशचन्द्र बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सर फीरोजशाह मेहता, गोपालकृष्ण गोखले, रासबिहारी बोस, रानाडे, मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक जैसे प्रखर बुद्धिवादी लोगों के हाथ में रहा.

सन् 1896-97 तथा 1899-1900 में अकाल के हालात आ जाने के कारण भारतीयों की दुर्दशा तेजी से बढ़ती जा रही थी. साथ ही अंग्रेजी सरकार इसके प्रति उदासीन रुख अपना रही थी. एक करोड़ लोग मारे जा चुके थे और अनवरत लोग भूख से मर रहे थे. इन सबके बावजूद अंग्रेज अन्न को विदेश में भिजवा रहे थे. सन् 1901 में कलकत्ता में हुए 17वें अधिवेशन में कांग्रेस ने इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी. इस स्थिति से दु:खी होते हुए तत्कालीन कांग्रेस स्वागत समिति के अध्यक्ष महाराजा जे. एन. राय ने कहा था, "प्रत्येक राजनीतिक प्रश्न मूलरूप से राजनीतिक प्रश्न है और इसमें आर्थिक प्रश्न का समावेश सर्वाधिक प्रमुख है. शीघ्र ही विश्व के बाजार रणक्षेत्र बन जाएंगे जहाँ विभिन्न राष्ट्रों के भाग्य का फैसला होगा." इसी अधिवेशन में दुर्भिक्षों की पुनरावृत्ति पर खेद प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. जिसमें दुर्भिक्षों के निम्न कारक बतलाए गये–

(अ) देशी उद्योग, व्यवसाय की अवनति;

(ब) भारतीय पूँजी का निष्कासन;

(स) कर भार में भयानक वृद्धि;

(द) प्रशासन के सैन्य एवं नागरिक विभागों में धन का अपव्यय.

कांग्रेस के 17वें अधिवेशन में ही देश में साधनों का विकास, खर्चे में कमी, कृषि विकास और उद्योगों के विकास की माँग उठाई गयी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम युग में कांग्रेस की नीति उदारवादी थी. इस दौरान कांग्रेस में क्रान्तिकारी आन्दोलन की परछाईं के बजाए सुधारवादी राजनीतिक संगठन की झलक थी. कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व था. इन लोगों का ब्रिटिश सरकार की जन्मजात न्यायप्रियता तथा प्रजातान्त्रिक भावनाओं में असीम विश्वास था, क्योंकि वे अंग्रेजी सभ्यता एवं संस्कृति के आदर्श साँचे में ढले हुए एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे. सभी उदारवादी भारत में नौकरशाही के आलोचक एवं शासन में भारतीयों को अधिक अधिकार दिये जाने के पक्षपाती थे. ब्रिटिश संगठनों, संस्थाओं और अंग्रेजों की सदाशयता में उनका अटूट विश्वास था. कांग्रेस के उन नेताओं का मानना था कि भारत संवैधानिक उपायों द्वारा ही ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति का पालन करते हुए शनैः-शनैः ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करता चला जायेगा.

इस तरह के मनोभावों का जिक्र करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. ताराचन्द लिखते हैं–"प्रारम्भिक वर्षों के कांग्रेस के अधिवेशनों की कार्यवाही बहुत संजीदा, परन्तु दबे हुए ढंग से होती थी. प्रस्तावों और व्याख्यानों में किसी प्रकार का क्रान्तिकारी जोश परिलक्षित नहीं होता था. नरमी ही इनकी विशेषता होती थी. अध्यक्षीय भाषणों में ब्रिटिश शासन की अच्छाइयाँ गिनाई जाती थीं और आश्वासन दिया जाता था कि भारत ताज के प्रति वफादार है और इसकी पुनरावृत्ति की जाती थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहना चाहता है. कांग्रेस की माँग में अवज्ञा या चुनौती का स्वर न होकर आग्रह और प्रार्थना का स्वर ही होता था. प्रारम्भ से ही उनका रुख मौलिक संवैधानिक परिवर्तनों की ओर था. प्रथम अधिवेशन में ही सर्वोच्च और स्थानीय कौंसिलों के विस्तार, उनमें काफी चुने हुए सदस्यों को लेने, उनके कार्यों की विस्तृता की बात कहीं गई थी. इसी तरह उनकी अपेक्षा जिम्मेदार सरकार के बजाय ऐसी सरकार की स्थापना की थी जिसका मूलाधार जनता के प्रतिनिधियों के साथ सलाह हो."

राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश शासन के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बताते हुए प्रेस में इसकी अत्यधिक प्रशंसा की गई थी. इन्दु प्रकाश ने लिखा था, "यह एक नये जीवन की शुरूआत थी और इसको दूषित करने वाले कुछ भी कहें, इसने राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने में सराहनीय प्रयास किया था. साथ ही विविध लोगों को समान लक्ष्यों एवं सामान्य सहानुभूति द्वारा एकसूत्र में बाँधने की कोशिश की

थी." वास्तविक तथ्य यह थे कि यह सम्मेलन एक बार हुआ और उसने न्यायपूर्ण वादा किया कि हम इस कल्पना को कि हम एक राष्ट्र नहीं हैं असत्य कर देंगे. इसे अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि हम अनेक विशेषताएँ रखते हैं, जो कि राष्ट्र का निर्माण करती हैं. हम एक-दूसरे से विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातीय व रिवाजों से विभाजित हैं. लम्बी दूरी की वजह से पृथक् हैं और जाति व भावना की एकरूपता चाहते हैं. तथापि यह स्वीकार करने योग्य है कि वर्तमान में हम राजनैतिक रूप से एक राष्ट्र हैं और कम-से-कम एक बना रहे हैं.

भले ही कांग्रेस ने इस दौरान नरम नीति अपनाई, लेकिन वह भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए काम करती रही. विदेशों में भारतीयों के प्रति सजग एवं सतर्क रही. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था, कांग्रेस ने उसका कड़ा विरोध किया. यद्यपि कांग्रेस अपने प्रयत्नों से उल्लेखनीय सफलता हासिल करने में नाकाम रही फिर भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हमेशा असन्तोष व्यक्त करती रही. सन् 1905 ई. में बंगाल का विभाजन किए जाने पर भारतीयों में असन्तोष का तूफान प्रचण्ड हो गया. बंग-भंग का उद्देश्य मुसलमानों को विभाजित कर एक प्रान्त का रूप देना था. लॉर्ड कर्जन की नीति हिन्दू और मुसलमानों में फूट डालने, लड़ाने और राज करने की थी. बंग-भंग की यह दुर्घटना सिर्फ बंगाल में नहीं, अपितु सारे देश में फैल गई जिससे विद्रोह की तीव्र ज्वाला भड़क उठी. इसी से देश में विभिन्न स्थानों पर सभाएँ होने लगीं. विदेशी माल का बहिष्कार होने लगा, स्वदेशी माल को काम में लाया जाने लगा. अंग्रेजों के स्वेच्छाचारी व्यवहार से कांग्रेस का उदारवादी विचारधारा से विश्वास हट गया.

कांग्रेस की उपलब्धियाँ

कांग्रेस की प्रार्थना, अनुनय-विनय भरे स्वरों से ब्रिटिश शासकों पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ. वर्षों तक भारतीयों की किसी माँग पर विचार नहीं किया गया. कांग्रेस को पहली सफलता सन् 1892 में मिली जब इण्डियन कौंसिल एक्ट पारित किया गया था. सन् 1889 ई. में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के वरिष्ठ सदस्य चार्ल्स ब्रेडला भी उपस्थित थे. चार्ल्स ब्रेडला भारतीय मामलों में सक्रिय रुचि दिखाते थे, जिसके कारण ब्रिटिश संसद में लोग उन्हें भारत के लिए सदस्य के नाम से सम्बोधित करते थे. ब्रेडला ने विधान परिषदों में सुधार के विषय को लेकर, कांग्रेस की माँगों को आधार बनाकर ब्रिटिश संसद के लिए विधेयक का एक प्रारूप बनाया था. वे चाहते थे कि इस विधेयक पर भारतीय नेताओं के परिपक्व विचार और प्रतिक्रियाएँ एकत्र कर यथासम्भव उनका विधेयक में समावेश कर सकें.

बम्बई के इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें भारत की प्रतिनिधि संस्थाओं की योजना की एक रूपरेखा तैयार की गई थी. इस प्रस्ताव के समर्थकों में पण्डित मदन मोहन मालवीय, विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपतराय, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर आदि थे. फरवरी 1890 ई. में चार्ल्स ब्रेडला ने इंग्लैण्ड पहुँचकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने अपना भारतीय परिषद् संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था. विधेयक के अनुसार केन्द्रीय और प्रान्तीय परिषदों का विस्तार होना था, सदस्यों की संख्या बढ़नी थी, परिषदों को आंशिक रूप में निर्वाचन के सिद्धान्त पर संगठित किया जाना था तथा उन्हें अधिक अधिकार दिये जाने थे. सन् 1889 ई. के कांग्रेस के अधिवेशन में पास की गई योजना तथा ब्रेडला के इस विधेयक को बाद में होमरूल स्कीम और होमरूल बिल के नामों से पुकारा गया. चार्ल्स ब्रेडला के इस विधेयक को पारित नहीं किया गया और सन् 1891 ई. में ब्रेडला की असामयिक मृत्यु भी हो गई. फिर भी ब्रेडला के इस प्रयास की महत्ता रही, क्योंकि पहली बार इसमें भारतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया गया और बाद में लिबरल पार्टी के विजय होने पर इसी विधेयक के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने अपना भारतीय परिषद् विधेयक पेश किया था. संसद द्वारा पारित होने के बाद यही विधेयक 1892 का अधिनियम बना. अधिनियम द्वारा केन्द्रीय और विधान परिषदों की संख्या पहले से बढ़ा दी गई. गवर्नर जनरल को परोक्ष निर्वाचन प्रणाली के सूत्रपात करने का अधिकार मिला. अधिनियम द्वारा कुछ नियमों के भीतर रहते हुए विधान परिषदों के सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद् से प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया. ये अधिकार गवर्नर जनरल की विधान परिषद् एवं प्रान्तीय विधान परिषद् दोनों को दिया गया.

कांग्रेस की उपलब्धियों को अभिव्यक्त करते हुए गुरुमुख निहालसिंह ने लिखा था, "1892 का अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयत्नों का परिणाम था." इस अधिनियम के माध्यम से कांग्रेस की सफलता का मूल्यांकन करना अधिक उपयुक्त होगा. इसी सन्दर्भ में डॉ. कश्यप लिखते हैं–"यद्यपि 1892 के अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों को दिये गये अधिकार अत्यन्त सीमित थे तथा अब भी उन्हें मतदान करने, प्रस्ताव अथवा विधेयक पारित करने अथवा पूरक प्रश्न आदि के आवश्यक अधिकार नहीं मिले थे, किन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 1892 के अधिनियम ने यह स्वीकार कर लिया था कि विधान परिषदों का कार्य केवल मात्र विधायी अथवा परामर्श देने का नहीं था और इस दृष्टि से यह अधिनियम प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना का पहला प्रमुख कदम था. पहली बार

इस अधिनियम ने शासन में कुछ प्रतिनिधिक अंश का समावेश किया तथा भारतीय सदस्यों को भी सरकारी विधेयकों पर तथा बजट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार प्रकट करने एवं सरकार के कृत्यों पर प्रश्न पूछने का अधिकार कुछ हद तक दिया. निःसंदेह यह अधिनियम सांविधानिक सुधारों की दिशा में प्रगतिकारक चरण था."

1892 ई. के भारतीय परिषद् के अधिनियम के पास हो जाने के बाद कांग्रेस की माँगों में सर्वाधिक महत्त्व इस बात को दिया गया कि आई.सी.एस. की परीक्षा भारत और इंग्लैण्ड में साथ-साथ हुआ करें. कांग्रेस के प्रयत्न सर्वथा व्यर्थ नहीं गये, क्योंकि भारतीयों की इस माँग के समर्थन में ब्रिटिश लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया. 1893 ई. में कांग्रेस अधिवेशन की दूसरी बार अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की जिन्हें इस दौरान ब्रिटिश लोकसभा का सदस्य चुन लिया गया था. कांग्रेस के लिए यह गौरव की बात थी कि उसका एक सदस्य विदेशी हुकुमत की संसद का सदस्य था. कांग्रेस ने अपने विभिन्न अधिवेशनों में न केवल कतिपय राजनीतिक प्रश्नों की ओर विदेशी शासन का ध्यान आकर्षित किया, अपितु भारत के व्यावसायिक और औद्योगिक दोनों प्रकार के हितों की रक्षा का भी प्रयत्न किया. कांग्रेस ने सरकार से सन् 1898 ई. के राजद्रोह विधेयक तथा सन् 1704 ई. के सरकारी रहस्य जैसे–दमनकारी कानूनों को हटा लेने का भी आग्रह किया. सी. वाई. चिन्तामणि ने लिखा है–"सन् 1905 ई. तक कांग्रेस समतल पथ पर दौड़ती रही. सार्वजनिक महत्ता का ऐसा कोई भी विषय नहीं था, जिसने उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट न किया हो और विभिन्न विषयों पर पास किए गये प्रस्तावों में व्यक्त विचार आन्दोलन के नेताओं की राजनीतिक बुद्धिमत्ता के साक्षी थे."

कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश शासकों का दृष्टिकोण

कांग्रेस की स्थापना के प्रारम्भ में ब्रिटिश शासकों का दृष्टिकोण सहयोगपूर्ण था. सरकार ने उसके संस्थापकों के विचारों का स्वागत और प्रोत्साहन किया. कई भारतीय और अंग्रेज पदाधिकारियों ने कांग्रेस की स्थापना में भाग लिया था और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक भोज राजकीय भवन में दिया था. तीसरे अधिवेशन के अवसर पर मद्रास के गवर्नर ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को राजभवन में प्रीतिभोज के लिए आमन्त्रित किया था और स्वागत समिति के अध्यक्ष सर टी. माधवराव ने उस दौरान कांग्रेस को ब्रिटिश शासन की महान् विजय और गौरव की वस्तु कहा था. सरकार द्वारा कांग्रेस को जो समर्थन प्रारम्भ में प्राप्त था, उसके ही कारण कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षानली बताया जाता है. सम्पूर्ण शब्दों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि प्रारम्भिक दिनों में कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण सहयोग और सहानुभूति पूर्ण था.

सन् 1888 ई. से ब्रिटिश शासकों का कांग्रेस के प्रति रुख लगातार कड़वा होता चला गया. शासक वर्ग का सहयोग सन्देह में बदलने लगा. इसका एकमात्र कारण भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार में आकस्मिक वृद्धि था. इसी समय से कांग्रेस को ब्रिटिश शासक खतरा समझने लगे. उन्हें अनुभूति होने लगी कि कांग्रेस की प्रगति से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रचार-प्रसार को बल मिलेगा. एक भोज के दौरान लॉर्ड डफरिन के शब्द अंग्रेजों के कांग्रेस के प्रति अचानक बदले रुख को स्पष्ट करते हैं–"अब कांग्रेस का रुझान राजद्रोह की ओर हो गया है. परन्तु ये संस्था शिक्षित भारतीयों का नाममात्र का प्रतिनिधित्व करती है." डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि संस्था कहा था. अंग्रेजी समाचार-पत्रों ने खुली आलोचना प्रारम्भ कर दी और अनवरत हर कहीं कांग्रेस को बन्द करने की माँग की जाने लगी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहबाद में हुए चौथे अधिवेशन में भयंकर कठिनाइयाँ सामने आने लगीं. यू.पी. के गवर्नर सर ऑकलैण्ड के विरोधस्वरूप सम्मेलन के लिए मकान नहीं मिल सका और दरभंगा नरेश को राजकीय भवन के सामने का भवन खरीद कर कांग्रेस को देना पड़ा. इससे कॉलविन को भयंकर क्षोभ हुआ और सरकारी दौरे के बहाने वे इलाहाबाद छोड़कर ही चले गए. इसके बाद से सरकार ने आदेश निकाल दिया कि कोई भी राजकीय कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन में आगे से भाग नहीं ले सकेगा. कांग्रेस के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करने के प्रयास किये गये. मुसलमानों को विशेष सुविधाएँ दी गईं. राष्ट्रीय एकता की भावना पर कुठाराघात कर सरकार ने राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल डालने का असफल प्रयास किया. मुसलमानों का प्रयोग 'फूट डालो और राज करो' के लिए होने लगा. कभी कांग्रेस को स्थापित करने का सुझाव देने वाले लॉर्ड डफरिन अब अखिल भारतीय कांग्रेस को अपना पतन मानने लगे थे. कांग्रेस की माँगों पर सचिव सर ए. ओ. ह्यूम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लॉर्ड डफरिन की अभिव्यक्ति थी, "ह्यूम नाम का एक दुष्ट व्यक्ति था जिसे लॉर्ड रिपन ने बहुत सिर चढ़ाया और जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात होता है कि वह होमरूल आन्दोलन को भड़काने वालों में प्रमुख है. यह बहुत ही चालाक, पर कुछ सिरफिरा अहंकारी और नैतिकताहीन व्यक्ति है जिसे सत्य की कोई परवाह नहीं है."

तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 'पागलों की सभा', बचकाना, इटन और हैरो की

वाद-विवाद सभा, बाबुओं की संसद, खुर्दबीन से देखी जाने वाली अल्पसंख्या जैसे घटिया विशेषणों का प्रयोग किया गया. साम्राज्यवाद के महान् प्रतिपादक लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस की विषम परिस्थितियों में भारत सचिव के पास जाकर आनन्द प्रकट किया कि कांग्रेस की मौत बहुत करीब है. उसने कहा, "मेरा यह अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई पतन की ओर जा रही है और मेरी एक महान् आकांक्षा यह है कि भारत में रहते समय उसकी शान्तिमय मौत में मैं सहायता दे सकूँ." ब्रिटिश सरकार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति आकस्मिक परिवर्तित रुख को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए डॉ. ताराचन्द लिखते हैं, "सरकार की प्रतिक्रिया थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत ताश की दीवार नहीं थी कि कांग्रेस का बिगुल बजते ही ढह जाए." सन् 1888 ई. तक कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश साम्राज्य का रुख यकायक कठोर एवं रूखा बन गया था.

कांग्रेस का उदारवादी (नरमपंथी) चरण

सन् 1885 ई. में स्थापित कांग्रेस पर सन् 1905 में बंग विभाजन तक उदारवादियों का प्रभुत्व रहा. भारतीय नेताओं के स्वर में सम्मान एवं ब्रिटिश सरकार के प्रति श्रद्धाभाव हमेशा परिलक्षित होता रहा था, लेकिन लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के बाद स्थिति काबू से बाहर हो गई. सम्पूर्ण देश में असन्तोष और आक्रोश की लहर फैल गयी. कई शिक्षित भारतीयों की मानसिकता नम्र स्वर एवं सम्मान से परे मुकाबले की बन गई और कांग्रेस में उदारवादी विचारधाराओं को चुनौती देना प्रारम्भ किया. इसके फलस्वरूप सन् 1906 ई. में सूरत विभाजन हुआ. कांग्रेस स्पष्ट रूप से दो खेमों में विभाजित हो गयी–उदारवादी खेमा और उग्रवादी खेमा. सन् 1915 तक दोनों गुट अलग-अलग होकर कार्य करते रहे. सन् 1916 ई. में मिसेज एनीबेसेन्ट की मध्यस्थता में दोनों गुटों में समझौता हुआ जो ज्यादा समय तक नहीं रह सका. उदारवादी विचारधारा गुट का अस्तित्व उग्रवादी विचारधारा गुट की अपेक्षाकृत घटता गया. अन्ततः सन् 1918 ई. में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कर ली. इसके बाद धीरे-धीरे एक प्रधान राजनीतिक शक्ति के रूप में पहचाने जाने वाले उदारवादी अपनी पहचान खो बैठे.

उदारवादी राजनैतिक विचारधारा के प्रतीकों में प्रमुख रूप से महादेव गोविन्द रानाडे (1842-1901), दादाभाई नौरोजी (1825-1917), फीरोजशाह मेहता (1845-1915), सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (1848-1925), गोपालकृष्ण गोखले (1866-1915), वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री (1869-1946) आदि थे.

उदारवादी विचारधारा, मनोवृत्ति एवं कार्य-पद्धति

ग्रेट ब्रिटेन में उदारवाद सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धान्त था, विशेषकर उस समय जब उसकी शक्ति का विस्तार भारत में हुआ. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक नेता इस विचार से प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय लोगों में उदारवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया. उदारवादी धारणाओं के उन नेताओं ने उदारवादी परम्पराओं के अनुरूप नागरिक अधिकारों और प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की माँग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नये महत्त्वपूर्ण अध्याय का सूत्रपात किया. उनकी आर्थिक राष्ट्रवाद की रूपरेखा कट्टर नहीं थी, तथापि सामाजिक वर्गों के हितों के अनुकूल थी, जो धीरे-धीरे राष्ट्र में प्रमुखता से छा गयी. उदारवाद का एक नवीन पहलू राजनीतिक विरोध के प्रति एक संयत अथवा मितवादी दृष्टिकोण भी था. इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को उन भारतीय नेताओं ने चुनौती दी, जो 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में एक प्रबल राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे. उसी समय से प्रारम्भिक नेताओं और उनके अनुयायियों को प्रायः उदारवादी या नरमपंथी (Moderates) और उनके नेतृत्व को चुनौती देने वालों को उग्रवादी या उग्रपंथी (Extremists) कहा जाने लगा. नरमपंथी नेता इस बात को स्वयं स्वीकार करते थे कि उनके चिन्तन और दर्शन में उदारवाद और मितवाद (Liberalism and Moderation) का समन्वय है. उदारवादी नेताओं के उत्कर्ष गोपालकृष्ण गोखले ने अपने राजनीतिक गुरु महादेव गोविन्द रानाडे द्वारा उदारवादी विचारधारा के सम्बन्ध में दिये वक्तव्य को इस तरह स्पष्ट किया था–"उदारवाद या मितवाद (Liberalism and Moderation) हमारे संघ के सिद्धान्त होंगे. उदारवाद की भावना में जाति, मत-मतान्तरों, सम्प्रदायों से मुक्ति, मानवीय गुणों को मानने वाले और न्याय की कामना करने वालों के प्रति श्रद्धा, शासकों के प्रति वैधानिक रूप में उचित स्वामी-भक्ति एवं कानूनी रूप से समानता की माँग सन्निहित है. अप्राप्य आदर्शों, उद्देश्यों की तरफ आकर्षित न हों, अपितु उन आदर्शों और अधिकारों की प्राप्ति के लिए कदम उठाये जायें जो आपसी समझदारी एवं सद्भाव से प्राप्त किये जा सकते हों." सन् 1885 से 1905 ई. तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उन्हीं नेताओं का प्रभुत्व रहा जो उदारवादी विचारधारा के थे. इसलिए इस युग को नरम राष्ट्रवाद का युग या उदारवाद का युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. इस दौरान मुख्य रूप से शिक्षित, मध्यम वर्ग व बुद्धिजीवियों का प्रवेश ही हो पाया था. लगभग सारे नेता अपने उदारवादी व्यवसाय चिकित्सा, कानून, अध्यापन, इंजीनियरिंग आदि से आये थे. अधिकांश सदस्य शहरी थे, इसलिए कांग्रेस इस अवधि में पूर्णतः शहरी संगठन थी.

उदारवादी विचारधारा के नेता देश की दुर्दशा के मूल में आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन को दोषी ठहराते थे. ब्रिटिश न्याय भावना एवं शासन में उनका पूरा विश्वास था, उन्होंने भारत की प्रगति के लिए ब्रिटिश सरकार की स्थिरता को स्वीकार किया. गोपालकृष्ण गोखले ने ब्रिटिश शासन को "शान्ति का आशीर्वाद, कानून व व्यवस्था की स्थापना, पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता का परिचय, भाषण, संस्थाओं को बढ़ावा देने वाले कारकों को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रोत्साहन मानते हुए इसका श्रेय ब्रिटिश सरकार को दिया."

उदारवादियों के सिद्धान्त

उदार विचारों वाले राष्ट्रवादी, जो प्रारम्भिक दौर के नेतृत्वकर्त्ता थे उनकी मानसिकता भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को क्रान्तिकारी रूप देने की नहीं थी. वे स्वाभाविक रूप से राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार लाने के पक्षधर थे. उनके अग्रलिखित सिद्धान्त उदारवादी विचारधारा को पूर्णतः स्पष्ट करने में सफल हो सकेंगे–

ब्रिटिश शासन के प्रति दृढ़ आस्था–उदारवादी नेताओं की ब्रिटिश शासकों के प्रति भयंकर आस्था थी. वे ब्रिटिश शासन को वरदान मानते थे. कारण जो भी हों पर अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व सम्पूर्ण भारत में अशान्ति फैली हुई थी. उस दौरान भारत में अंग्रेजों ने शान्ति स्थापित की थी. इसी सम्बन्ध में गोपालकृष्ण गोखले ने कहा है–"ब्रिटिश राज के बारे में कोई व्यक्ति चाहे कितना ही बेकार समझे, लेकिन यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि अंग्रेजों ने यहाँ आकर शान्ति स्थापित की है. शान्ति के बिना कोई उन्नति सम्भव नहीं है". हमारे देश में अव्यवस्था उत्पन्न करना कठिन कार्य नहीं है, ऐसा यहाँ सैकड़ों वर्षों से होता रहा है, परन्तु एक शताब्दी के समय में अंग्रेजों ने जो शान्ति-व्यवस्था स्थापित की थी उसका कोई विकल्प ढूँढ़ना आसान नहीं है. इसके साथ ही उन नेताओं का ब्रिटिश शासकों की न्यायप्रियता में विश्वास था. शिक्षण संस्थाओं और ब्रिटिश लोकतन्त्रीय संस्थाओं को वे भारत के लिए अत्यधिक उपयोगी मानते थे. ब्रिटिश शासन के सम्बन्ध में कांग्रेस के पूना अधिवेशन में दिया गया वक्तव्य ब्रिटिश शासन के प्रति अन्धविश्वास को स्पष्ट करता है–"अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी कामनाएँ ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़ गई हैं तथा कांग्रेस स्वतन्त्र रूप से यह स्वीकार करती है कि हमारी प्रगति ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही पूरी हो सकती है".

स्वशासन का लक्ष्य–उदारवादी नेता भारत के लिए औपनिवेशिक शासन (Dominion Status) के समर्थक थे, पूर्ण स्वराज्य के प्रति उनकी कोई भावना नहीं थी. वे कनाड़ा तथा अमरीका जैसे अधिराज्यों की तरह भारत को भी स्वशासनपूर्ण राष्ट्र बनाना चाहते थे. ब्रिटिश साम्राज्य से भारत के रिश्तों को तोड़ना उनके लिए सम्भव नहीं था. अधिराज्य को प्राप्त करने के सम्बन्ध में गोपालकृष्ण गोखले की इलाहाबाद अधिवेशन में सन् 1907 ई. में दिये गये भाषण की अभिव्यक्ति–"अन्य लोगों की तरह ही मेरे देशवासियों की स्थिति इस देश में हो, यह मेरी हार्दिक कामना है. मैं बिना जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र के भेदभाव के प्रत्येक स्त्री और पुरुष के पूर्ण विकास का समर्थक हूँ. मैं चाहता हूँ कि उन पर किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रतिबन्ध न लगाया जाये. मैं चाहता हूँ कि भारत संसार के महान् देशों में राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और कला-क्षेत्र में अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण करे. मैं चाहता हूँ कि ये समस्त आदर्श ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत ही प्राप्त हों."

संवैधानिक उपायों में विश्वास–आन्दोलनात्मक तरीकों की अपेक्षा उदारवादियों का विश्वास संवैधानिक तरीकों में ज्यादा था. संवैधानिक उपायों से तात्पर्य था कि अंग्रेज शासकों को अपने कष्ट दूर करने के लिए आवेदन-पत्र दिए जाएँ और भारत की जनता के कष्टों का ज्ञान उन्हें भली प्रकार से कराया जाए. वे सरकार की रचनात्मक आलोचना एवं निष्क्रिय प्रतिरोध में विश्वास में रखते थे. जनमत को प्रबल बनाने के लिए जुलूस और जलसों का सहारा नहीं लेते थे. वे आक्रमणकारी सिद्धान्तों के विरुद्ध थे. उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के विरोध से जनता का कष्ट और अधिक बढ़ेगा.

राष्ट्रीय सेवा एवं एकता में विश्वास–उदारवादियों का सर्वाधिक ध्यान राष्ट्र सेवा की ओर केन्द्रित था. वे भारतीयों की सर्वांगीण उन्नति के पक्षधर थे, ताकि राष्ट्रीय एकता की नींव सुदृढ़ हो सके. वे हिन्दू-मुस्लिम में मतभेद को भारत के भविष्य का अन्धकार मानते थे. वे भेदभाव की अपेक्षा सहयोग, प्रेम, मैत्री पर अधिक बल देते थे. राष्ट्र की उन्नति के मूल में भारतीयों की नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक योग्यताओं के विकास को भी अत्यन्त आवश्यक मानते थे. वे नैतिक उत्थान उच्च चरित्र, कठोर परिश्रम और त्याग से देश को उत्कर्ष तक पहुँचाने के संदेशवाहक थे. इन्हीं विचारों के संरक्षण के लिए 12 जून, सन् 1905 ई. को उदारवादी राष्ट्रवाद के प्रमुख गोपालकृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ (Servants of Indian Society) बनाया था.

उदारवादियों की कार्यपद्धति एवं राजनीतिक सफलताएँ

साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन–साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन उदारवादी विचारकों का सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था. उनका मानना था कि ब्रिटिश आर्थिकवाद में निहित

उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अधीन रखता है. एकमात्र कारण यही था कि उपनिवेशवादी सरकार के विरुद्ध उनकी लगभग सभी नीतियों के खिलाफ उदारवादियों ने आन्दोलन किए. उदारवादी युग के नेताओं ने तत्कालीन भारतीयों की गरीबी को निरन्तर अपने भाषणों और लेखों में ब्रिटेन के आर्थिक शोषण से जोड़ते हुए अंग्रेजी सरकार के समक्ष रखा. इस हालात को स्पष्ट करते हुए दादाभाई नौरोजी ने कहा था–"भारतवासी मात्र परजीवी दास थे. वे अमरीकी गुलामों से भी ज्यादा खराब थे, क्योंकि उनकी देखरेख उन अमरीकी गुलामों द्वारा की जाती थी जिनके वो गुलाम थे." उन्होंने परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग के विनाश एवं आधुनिक उद्योग के विकास को बाधित करने वाली सरकार की आर्थिक नीतियों की निन्दा की. उदारवादी नेताओं ने स्पष्ट किया था कि विदेशी पूँजी का अस्वस्थ निवेश न केवल वर्तमान, अपितु भावी पीढ़ी के लिए भी एक आर्थिक तथा राजनैतिक खतरा पैदा करने वाला है. उदारवादियों ने देश की गरीबी को दूर करने के लिए सुझाव दिया कि भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को विशेषकर आधुनिक उद्योगों को विकसित किया जाए और पारम्परिक उद्योगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाए. प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवादियों ने देश के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के कारण 'स्वदेशी अपनाओ' जैसे विचारों को भी प्रचारित और प्रसारित किया. व्यापारिक यातायात की नीतियों को उन्होंने देश में आर्थिक विकासोन्मुखी बनाने के लिए अंग्रेजों को सुझाव दिया.

प्रशासनिक सुधार–उदार राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के साम्राज्यवादी दमनकारी प्रशासनिक पहलुओं की निर्भय होकर आलोचना की. दादाभाई नौरोजी, गोखले एवं रानाडे ने निरन्तर अपने भाषणों एंव लेखों द्वारा सरकार की दमनकारी एवं शोषण की नीति की बखिया उधेड़ी. इस दौरान दादाभाई ने एक पुस्तक (Poverty and Unbritish Rule in India) लिखी, जिसमें अंग्रेजी दमनकारी नीति एवं धन चूसने के सिद्धान्तों की जमकर आलोचना की गई थी. उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा–"इंग्लैण्ड 3,00,00,000 पौण्ड प्रतिवर्ष भारत से ले जा रहा है जिससे भारत एक दिन पूर्णतः निर्धन हो जायेगा."

इसी तरह की शोषक नीति की आलोचना करते हुए सन् 1907 ई. के अधिवेशन में गोपालकृष्ण गोखले ने अपने बजट भाषण में कहा था–"मेरे महामहिम यह एक कटु सत्य है कि प्रत्येक दस में से नौ बालक अँधेरे और अज्ञान में पल रहे हैं एवं प्रत्येक पाँच में से चार गाँव दुःखी हैं. ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय नागरिकों से द्वितीय नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाता है. ब्रिटिश नागरिक एवं अन्य उपनिवेश में रहने वाले लोग उच्च नागरिकता से विभूषित हैं. सभ्य संसार में भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ के नागरिक देश की सुरक्षा के उत्तरदायित्व में भागीदार नहीं बनाये जाते. वार्षिक मृत्यु-दर, प्लेग और अकाल को छोड़कर गत बीस वर्षों से लगातार बढ़ रही है. संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ योग्य, शिक्षित और प्रतिभाशाली नागरिकों को उच्चतर दायित्वों से पृथक् रखा जाता हो." उदारवादियों ने प्रशासनिक सुधार आन्दोलन में सबसे बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सेवाओं के उच्चतर श्रेणी के भारतीयकरण की माँग उठाई. इस माँग के आर्थिक, राजनैतिक एवं नैतिक आधार प्रस्तुत किये गये. आर्थिक आधार पर कहा गया था कि यूरोपवासियों को दिये जाने वाले ऊँचे वेतनों के कारण भारतीय वित्त पर भारी बोझ पड़ता था. इसका राजनीतिक आधार यह था कि यूरोपीय नागरिक प्रशासक भारतीय आवश्यकताओं की उपेक्षा करते थे तथा भारतीय पूँजीपतियों की कीमत पर यूरोपीय पूँजीपतियों के पक्ष पोषक थे और इसका नैतिक आधार यह था कि उसने भारतीय चरित्र को बौना बना दिया था एवं अपने स्वयं के देश में ही हीनता के कगार पर ला दिया था. उदारवारियों ने पुलिस तथा सरकारी एजेन्टों के जनसाधारण के प्रति क्रूर और दमनकारी व्यवहार का भी भयंकर विरोध किया था. इसके अलावा उनकी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने की दूरदर्शितापूर्ण माँग जनता के लिए सुरक्षा का आयाम थी.

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा–उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि से प्रबुद्ध थे. नागरिक अधिकारों में भाषण, प्रेस, विचार और संगठन बनाने की स्वतन्त्रता के प्रति उनका तीव्र आकर्षण था. इसीलिए जब भारतीय नागरिकों के अधिकारों को सीमित या कुण्ठित करने का प्रयास किया जाता था, तब-तब भारतीयों ने जोरदार ढंग से सरकार पर अस्वस्थ कदम न उठाने का दबाव डाला.

सन् 1889-90 ई. के दौरान सरकारी गोपनीयता को बनाये रखने के नाम पर समाचार-पत्रों की आलोचना करने के अधिकार को सरकार द्वारा समाप्त करना चाहा तो इसका भयंकर विरोध हुआ. राष्ट्रीय समाचार-पत्र और राजनीतिक संगठन नागरिक अधिकारों पर हुए इस आक्रमण का बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने गिरफ्तारी देकर देशव्यापी विरोध आन्दोलन किया. उदारवादियों की इस नीति के फलस्वरूप नागरिक सुरक्षा का यह संघर्ष स्वतन्त्रता संघर्ष का एक अभिन्न अंग बन गया.

आधुनिक राज्य और समाज–कांग्रेस के उदारवादी विचार-धाराओं के नेताओं ने जागृति के विचारों और जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की. उन्होंने थोड़े से लोगों की दी गई व्यक्तिगत सुविधाओं का दोष अन्यायपूर्वक बताते हुए सामाजिक समानता के सिद्धान्तों को व्यवहार में लाने की अपील की. हिन्दू समाज के पुनर्निर्माण के लिए अतीत के आदर्शों की स्थापना उनकी माँग नहीं थी, अपितु यह

पुनर्निर्माण राज्य के उन आधुनिक सिद्धान्तों के आधार पर किए जाने की माँग थी, जिनका विचार उन्होंने पाश्चात्य विद्वानों, राजनीतिज्ञों एवं दार्शनिकों से प्राप्त किया था. उदारवादी नेता अतीत के पुनर्जीवन में नहीं भविष्य के सुधारों में विश्वास करते थे. उन्होंने सिविल मैरिज जैसे सामाजिक सुधारों का स्वागत किया एवं इनको लागू करने के लिए राज्य की भूमिका पर जोर दिया. हिन्दुओं की नैतिक और सामाजिक दिशाओं को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने उसे राष्ट्रीय आत्महित से जोड़ते हुए कहा, "यदि हम अपने देशवासियों के एक बड़े हिस्से को अज्ञान और अवनति तथा हिकारत के गड्ढे में ढकेल रहे हैं, तो यह आशा कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और हम अपने देश को विश्व के मध्य सम्मानपूर्ण स्थान दिला सकेंगे." सन् 1897 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए सी. शंकरन् नायर ने कहा था "हिन्दू धर्म के एकान्तवास को भंग करने के लिए उन्मुक्त सामाजिक सम्पर्क और कार्य की एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निम्न वर्गों तक शिक्षा का वरदान प्रसारित करने के लिए हमें एक कठोरतापूर्ण धर्म-निरपेक्ष सरकार की निरन्तरता की आवश्यकता है और यह उचित है कि हम ऐसी सरकार के प्रति उदारवादी चिन्तन और प्रगति से परिपूर्ण सहानुभूति रखें."[1]

प्रमुख उदारवादी विचारक

फीरोजशाह मेहता (1845-1915)–शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधत्व करने वाले फीरोजशाह मेहता उदारवादी युग के महान् राजनीतिज्ञ थे. फीरोजशाह जनसाधारण की आकांक्षाओं और कठिनाइयों के प्रति व्यापक सहानुभूति अपने हृदय में रखते थे. सर फीराजशाह मेहता का जन्म सन् 1845 ई. में हुआ था. उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व गौरवशाली एवं आचरण अत्यन्त उज्जवल और राजसी रहा. एम.ए. पास करने के बाद वे कानून के अध्ययन के लिए इंग्लैण्ड गए. सन् 1867 ई. तक इंग्लैण्ड में रहकर उन्होंने अत्यधिक ख्याति प्राप्त की. दादाभाई नौरोजी से इनका परिचय इंग्लैण्ड में ही हुआ था. दादाभाई नौरोजी ने फीरोजशाह की योग्यता, लगन एवं राजनीतिक उपयोगिता को पहचानकर उसे भारतीय राष्ट्रवाद के लिए विकसित करने का प्रयास किया. अपने विदेशी प्रवास के दौरान पश्चिमी उदारवाद ने उनके अन्तरतम को छू लिया. पाश्चात्य विचारकों में कार्लाइल, रस्किन, मिल, ब्राइट, ग्लेडस्टन आदि की उदारवादी विचारधारा ने उन्हें प्रभावित किया. इसके बाद से ही उन्होंने सार्वजनिक सेवा प्रारम्भ कर दी. राष्ट्रवाद का उदय उनका मकसद बन गया. सन् 1869 ई. में भारत लौटने पर उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं से वंचित रह जाने के भय से ही जज का पद नहीं स्वीकारा. इसके बाद वे सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में कूद पड़े. गोपालकृष्ण गोखले के साथ मिलकर उन्होंने भारत में उदारवादी विचारधारा को एक नई शक्ति एवं राह दी. विप्लवकारी और क्रान्तिकारी योजनाओं के विरुद्ध वे हमेशा रहे. उनकी अन्त तक आकांक्षा यही रही कि राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय समाज ब्रिटिश शासन के प्रति हमेशा सहानुभूति बनाए रखे, क्योंकि ब्रिटेन के साथ भारत के सम्बन्ध से ही भारत को लाभ है. तत्कालीन साम्राज्यवादी एवं कूटनीति, दमनकारी नीतियों के परिवेश में भावनात्मक निर्णय की अपेक्षा उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण को अधिक महत्त्व दिया. भले ही उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्थायित्व दिया, फिर भी परिस्थितियों के अनुरूप वे निर्भीक, उत्कृष्ट एवं योग्य देशभक्त थे. कानूनी ज्ञान के कारण फीरोजशाह संवैधानिक ढंग से सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते थे. दादाभाई नौरोजी के सहयोग से अपने इंग्लैण्ड प्रवास के दौरान सन् 1897 ई. में वे लन्दन सोसायटी ऑफ इण्डियन्स और ईस्ट इण्डियन सोसाइटी के सदस्य बने. इसके अलावा ईस्ट इण्डिया सोसाइटी की मुम्बई शाखा का सक्रिय कार्यभार भी उन्होंने सँभाला. सन् 1872 ई. में मुम्बई निगम के सदस्य और तीन बार चेयरमैन चुने गए. मुम्बई निगम में रहते हुए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा सहायता एवं जल सप्लाई आदि से सम्बन्धित समस्याओं से निजात पाने के लिए सहायता की. निगम में अर्थव्यवस्था के सुधार से सम्बन्धित विचारों की व्यावहारिकता एवं सुझाव अत्यन्त प्रशंसनीय रहे. सन् 1888 ई. का मुम्बई का विधान परिषद् और नगरपालिका अधिनियम उनके द्वारा ही सम्पन्न हो पाया. वे उन उदारवादी विचारधारा के प्रमुख व्यक्तियों में से थे, जो कांग्रेस से प्रारम्भ से जुड़े रहे थे. ब्रिटिश प्रशासन की खामियों को प्रदर्शित करने में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा था. इलबर्ट बिल के विरोध में उनकी भूमिका स्मरणीय रही. लम्बे अन्तराल तक उन्होंने कांग्रेस के पीछे एक प्रमुख एवं वास्तविक शक्ति बनकर कार्य किया. उस दौरान राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र से सम्बद्ध रचनात्मक नवीन कार्य जो भी हुए, वे उनकी सक्रिय सदस्यता वाली संस्थाओं द्वारा ही सम्भव हो पाये. सन् 1907 ई. में सूरत अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के कार्यों में सक्रियात्मक भाग लिया. इसके बाद की परिस्थितियों ने उन्हें विचारधारा से दूर रहने को विवश कर दिया और लाहौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 24वें अधिवेशन में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सभापति बनने से पूर्व ही इस्तीफा दे दिया, जिसे पंडित मदनमोहन मालवीय ने स्वीकार किया. बदरुद्दीन तैय्यबजी और तैलंग के

1. विपिन चन्द्र, अमलेश त्रिपाठी : स्वतन्त्रता संग्राम, पृष्ठ 65-68

साथ मिलकर उन्होंने सन् 1885 ई. में मुम्बई प्रेसिडेन्सी एसोसिएशन की स्थापना की. उस समय इस एसोसिएशन की भूमिका राजनीतिक मामलों पर अभिव्यक्ति करना होता था. सन् 1886 ई. में मुम्बई विधान परिषद् के सदस्य नियुक्त होकर लगातार सन् 1892 से 15 वर्षों तक विधान परिषद् के निर्वाचित सदस्य रहे. इसके पश्चात् 13 वर्षों तक भारतीय विधान परिषद् की सदस्यता उन्होंने अत्यन्त समर्पित एवं लगन, सेवाभाव रखते हुए पूरी की. फीरोजशाह की इन उपलब्धियों एवं विशेषताओं के आगे ब्रिटिश दमनकारी एवं साम्राज्यवादी शासकों को भी झुकना पड़ा था. इसी के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने फीरोजशाह मेहता को सन् 1894 में सी.आई.आई. और सन् 1904 में के.सी.आई. के खिताब से विभूषित किया. फीरोजशाह मेहता संविधानवादी और उदारवादी थे तथा भारत के लिए ब्रिटिश शासन के लाभों में उनकी आस्था जीवनपर्यन्त रही. इसके साथ-साथ अन्य राजनैतिक उदारवादी नेतृत्वों की अपेक्षा ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी एवं दमनकारी तत्वों का वे जीवनपर्यन्त विरोध करते रहे. सन् 1913 में मुम्बई क्रॉनिकल के संस्थापक सर फीरोजशाह मेहता पूर्ण रूपों में साहसी, निर्भीक एवं कार्यकुशल, शान्तिप्रिय एवं उदारवादी विचारधारा के व्यक्तित्व थे. इस महान् व्यक्तित्व का देहान्त 5 नवम्बर, 1915 ई. को गुर्दों के खराब हो जाने से हो गया.

गोपालकृष्ण गोखले (1866-1915)–महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में ब्राह्मण परिवार में सन् 1866 ई. में गोपालकृष्ण गोखले का जन्म हुआ था. गोपालकृष्ण गोखले महादेव गोविन्द रानाडे जो पेशे से न्यायाधीश थे, को अपना आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु मानते थे. वे फीरोजशाह मेहता एवं दादाभाई नौरोजी के उदारवादी विचारों से मिलते हुए विचारों के व्यक्तित्व थे. उनका जीवन प्रारम्भ से ही सरल एवं संयमशील रहा था एवं उनके बौद्धिक गुण बचपन में ही उज्ज्वल भविष्य के भावी सोपान का संकेत दे चुके थे. जब गोपालकृष्ण गोखले मात्र 13 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहान्त हो गया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कठिन परिश्रम कर अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ी. उल्लेखनीय है उन्होंने अध्ययन काल का पूरा समय सड़क की रोशनी में पढ़कर व्यतीत किया था. सन् 1884 ई. में मुम्बई के एलफिन्सटन कॉलेज से बी.ए. पास करने के पश्चात् वे पूना के अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गये, जो आगे चलकर फर्ग्युसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ. सन् 1902 ई. में गोपालकृष्ण गोखले इसी कॉलेज के प्रिंसीपल पद से रिटायर हुए. महादेव गोविन्द रानाडे पर गोखले की कर्त्तव्य-परायणता एवं बुद्धिमत्ता का बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 22 वर्ष की उम्र में सन् 1888 ई. में गोखले को प्रसिद्ध राजनीतिक संस्था 'सार्वजनिक सभा' का मन्त्री बना दिया और शीघ्र ही वे प्रान्त के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाने लगे. सार्वजनिक सभा के प्रमुख पत्र 'क्वार्टरली रिव्यू' (Quarterly Review) के वे इसी दौरान सम्पादक भी रहे. इसी अवधि में गोखले अल्पायु में ही विज्ञान परिषद् के सदस्य बन गए. उन्होंने परिषद् में रहते हुए सरकार की भूमि-राजस्व सम्बन्धी नीति पर बहुत ही प्रभावोत्पादक भाषण दिया. गोपालकृष्ण गोखले का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश कांग्रेस के सदस्य के रूप में 1889 ई. में यानी उनकी 23 वर्ष की अवस्था में हो गया था. सन् 1895 ई. में वे कांग्रेस के मंत्री बने और कई वर्षों तक लगातार मुम्बई शाखा के मंत्री बने रहे. उन्होंने 1892 एक्ट को तर्कसंगत रूप से प्रकाशित किया. सन् 1897 ई. में वे दक्षिण शिक्षा प्रतिनिधि के रूप में वेल्वी कमीशन के समक्ष गवाही देने के लिए इंग्लैण्ड गए, जहाँ पर उन्होंने अपने बजट के प्रति सुझाव दिया कि इम्पीरियल कौंसिल में बजट पास होने के बाद ही उसे भारत सरकार में पेश करना चाहिए. सन् 1902 में रिटायरमेंट के तुरन्त बाद वे केन्द्रीय विधान परिषद् के सदस्य बने. केन्द्रीय विधान परिषद् में सदस्यता के दौरान उन्होंने नमक कर हटाने, अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को प्रारम्भ करने, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को उपयुक्त अवसर दिये जाने, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियन्त्रण को हटाने एवं अनावश्यक सैन्य खर्च एवं नागरिक अधिकारों पर अपव्यय को दूर करने के अत्यन्त सराहनीय प्रयास किये.

सन् 1905 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में वे सभापति चुने गये. उसी दौरान बंगाल का विभाजन हुआ, जिससे उन्हें अत्यन्त दुखानुभूति हुई. इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा–"जो कुछ मैं कह सकता हूँ यह है कि जनता व नौकरशाही के बीच पूर्ण सहयोग की समाप्ति की अत्यन्त सम्भावना है." बनारस कांग्रेस सभापति की हैसियत से उन्होंने राजनीतिक शस्त्र के रूप में बहिष्कार को समर्थित किया और कहा कि लोक भावनाओं की अनुकूलताओं पर इसको प्रयोग में लाना श्रेयस्कर है. सन् 1906 ई. में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता की भावनाओं को अवगत कराने के लिए उन्हें इंग्लैण्ड भेजा गया, जिस समय उनके दिए गए भाषणों को इंगलैण्डवासियों ने सराहा एवं 'नेशन' नामक एक पत्र के सम्पादक ने उनके बारे में लिखा–"गोखले की तुलना में इंग्लैण्ड में कोई राजनेता आज नहीं है और तुलनात्मक दृष्टि में सर एस्क्विथ से भी बड़े हैं. राष्ट्रवाद का परचम लहरा देने वाले उदारवादी विचारधारा के दृढ़ व्यक्तित्व गोपालकृष्ण गोखले ने सन् 1905 ई. में 'भारत सेवक समिति' नामक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की. देशभक्ति का संदेश देने वाली इस संस्था ने एक न्यूनतम अन्तराल में श्रीनिवास शास्त्री, जी. के. देवधर, एम. एम. जोशी, पण्डित हृदयनाथ कुंजरू और अमृतलाल ठक्कर जैसे

राष्ट्रवादी एवं प्रखर बौद्धिक उदारवादी व्यक्तित्व पैदा किये. सन् 1907 ई. के सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से गोखले ने समर्पित भाव से कांग्रेस के कार्यकलापों में भाग लिया और अनेक वर्षों तक नरम दल के नेता के रूप में वे कांग्रेस के कर्णधार बने रहे. अनेक बार उन्हें इंग्लैण्ड जाना पड़ा और हर बार अपने भाषणों से उन्होंने ब्रिटिश जनता को बता दिया कि वे उनकी श्रेष्ठता में विश्वास अवश्य करते हैं; लेकिन कमियों पर अपनी प्रतिक्रिया जताये बिना नहीं रह सकते, भले ही उनकी विरोध शैली शिष्ट और नरम क्यों न हो ? सन् 1904 ई. में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सी.आई.ई. के खिताब से विभूषित किया था. सन् 1909 ई. की दमनकारी और नौकरशाही नीतियों के लिए अंग्रेजों को जमकर कोसा. सन् 1912 ई. में गोखले दक्षिण अफ्रीका गये, जहाँ पर रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए उन्होंने गांधीजी का सहयोग दिया. गोपालकृष्ण गोखले को गांधीजी अपना आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु मानते थे. जनवरी सन् 1915 ई. में गोखले के कहने पर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारत के सुधारों की एक योजना तैयार की थी, जिसे गोखले की 'राजनीतिक वसीयत' या इच्छा-पत्र (Political Testament) कहा जाता है. राष्ट्रवाद और शिक्षा के प्रचार-प्रसार में उनका अन्तिम समय व्यतीत हुआ. सन् 1915 ई. में फरवरी के महीने में इस महान् राष्ट्रवादी उदारवादी विचारक का स्वर्गवास हो गया. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें महाराष्ट्र का रत्न, भारत का हीरा, देश सेवकों का राजा से सम्बोधित किया था. लाला लाजपत राय ने गोपाल कृष्ण गोखले को विशुद्ध उदारवादी एवं उत्कर्ष राष्ट्रवादिता का सितारा बताते हुए सर्वश्रेष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्त्ता घोषित किया था.

महादेव गोविन्द रानाडे–भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रमुख विचारधारा के विभिन्न नेतृत्वकर्त्ताओं में महादेव गोविन्द रानाडे का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सभी क्षेत्रों में रचनात्मक सुझाव प्रस्तावित किये. वे स्वतन्त्रता, सामाजिक उन्नति और वैयक्तिक चरित्र की पुनर्स्थापना के महान् समर्थक थे. उन्होंने उदात्त भारतीय राष्ट्रवाद की कामना की तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष बड़े ही सुदृढ़ एवं उपयोगी सुझाव रखे. भारतीय इतिहास और राजनीतिक के क्षेत्र में अपने देशभक्तिपूर्ण विचारों के कारण उनका सर्वोच्च स्थान रहा है. जस्टिस गोविन्द रानाडे कांग्रेस में एक उच्च शिखर के समान थे और कांग्रेस आन्दोलन को उन्होंने स्फूर्ति प्रदान की थी. सन् 1895 ई. में पूना अधिवेशन के दौरान जब इस बात पर मतभेद पैदा हुआ कि कांग्रेस समाज सुधार के मामलों और समाज सुधार सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या नहीं, तब जस्टिस रानाडे ने सहिष्णुता और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से मामला सुलझा दिया. रानाडे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और सर ए. ओ. ह्यूम तक ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था. गोपालकृष्ण गोखले उनके योग्यतम राजनीतिक शिष्य थे. रानाडे का मस्तिष्क राजनीति के क्षेत्र में इतना स्फटिक, प्रतिभामय और स्पष्ट था कि कांग्रेस के नेता सभी प्रकार की राजनीतिक समस्याओं पर उनसे परामर्श करते अवश्य थे. भारतीय राजनीति में रानाडे उदारवादी चिन्तन के प्रमुख स्तम्भ थे. उदारवादी भावना से अभिप्रायः उनका जाति और धर्म सम्बन्धी राग-द्वेष से ऊपर उठ जाना और उन बातों के प्रति लगाव जिससे मनुष्यों की न्याय शृंखला जुड़ी होती है, से था. शासकों के प्रति वह निष्ठा जो उन्हें इसलिए मिलनी ही चाहिए कि वे कानून से बँधे हुए हैं, किन्तु साथ ही शासितों के लिए भी समानता प्राप्त करना, क्योंकि कानून के अन्तर्गत उन्हें यह अधिकार मिला हुआ है. नरमी भावना से तात्पर्य प्राकृतिक विकास की पद्धति से धीरे-धीरे संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा उपायों को अपनाना, जिससे न्याय और समझौते का दृष्टिकोण पूर्णतः वास्तविक अस्तित्व में रह पाए.

महादेव गोविन्द रानाडे क्रान्तिकारी, हिंसात्मक एवं विद्रोहात्मक साधनों के खिलाफ थे. जनता के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने सरकार से आवेदन करने के संवैधानिक साधनों पर बल दिया. सन् 1874 ई. में कांग्रेस की स्थापना से ग्यारह वर्ष पूर्व रानाडे ने ब्रिटिश संसद के पास एक याचिका भेजी थी, जिसमें माँग की गई थी कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने दिया जाए तथा भारतीय मसलों के निर्णय करने में उनकी सहमति ली जाए. इस याचिका में उन्होंने भारत की स्वशासी संस्थाओं की स्थापना के लिए इच्छा जाहिर की. सचमुच में गोविन्द रानाडे उदात्त भारतीय राष्ट्रवाद के गुरु थे और भारतीय राष्ट्रवाद का ऐतिहासिक आधार उनके सिद्धान्तों में एक मुख्य तत्त्व था. रानाडे की दृष्टि में सारे भारत को एकता के सूत्र में बाँधने वाली प्रवृत्तियाँ ब्रिटिश शासन की ही देन थीं, जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं. नियमों से पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, नियन्त्रित कानूनों से मुक्त न्याय व्यवस्था, रेल और तार जैसी आधुनिक संचार साधन प्रणाली, अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य संस्कृति तथा विज्ञान से परिपूर्ण आधुनिक ज्ञान, एक ऐसा आर्थिक ढाँचा भी जो ब्रिटेन की कार्यप्रणाली पर आधारित हो. भारत-ब्रिटिश सम्बन्धों को क्षति न पहुँचाने के रानाडे के सिद्धान्त को लोकमान्य तिलक ने देशभक्ति का विरोधी माना, कुप्रथाओं से दूर करने के रानाडे के गम्भीर प्रयत्नों को ब्रिटिश संस्कृति का आक्रमण मान लिया गया और मुसलमानों के आक्रामक होते हुए भी जब रानाडे ने हिन्दुओं और

मुसलमानों के समझौते के लिए जो सौहार्द्रपूर्ण मध्यम मार्ग अपनाया उसे उनकी कायरता समझी गई, लेकिन रानाडे का विश्वास था कि भारत में सामाजिक और नागरिक जागरूकता सिर्फ पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के सम्पर्क से लाई जा सकती है. भारत में ब्रिटिश शासन को वरदान के रूप में मानते हुए उन्होंने कहा कि देशवासियों को ब्रिटिश सम्पर्क से सुनियोजित राजनीतिक शिक्षा मिल सकेगी. उनकी दृष्टि में अंग्रेज जाति की नैतिक एवं राजनीतिक भावना सर्वोपरि थी. सिर्फ अंग्रेजी की प्रशंसा ही उन्होंने जीवन-पर्यन्त नहीं की. श्रेष्ठता, न्यायिकता से परे उन्होंने अंग्रेजी कूटनीति, साम्राज्यवादी नीति की खुलकर आलोचना भी की थी. उन्होंने भूमि अधिकरण एवं वंचित भूमि राजस्व व्यवस्था, उत्तर-दायित्वपूर्ण पदों से भारतीयों को पृथक् रखने की व्यवस्था, को भी कठोरता से लिया. उन्होंने ब्रिटिश शासन की उस औद्योगिक नीति को भी अनुचित बताया, जिसके फलस्वरूप भारत ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल का पोषक और उन कारखानों द्वारा निर्मित माल की बिक्री का बाजार बन गया था. अत्यधिक केन्द्रीयकृत व्यवस्था का भी रानाडे ने विरोध किया. रानाडे ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को हीन समझने की नीति को उनके नैतिक पतन का कारक माना. उन्होंने अपनी मर्यादित आवाज में अंग्रेजों को ललकारा कि भारतीय राष्ट्र को बलपूर्वक कभी भी स्थायी रूप से दबाकर नहीं रखा जा सकता और ईश्वरेच्छा से अथवा ब्रिटिश उदाहरण एवं अनुशासन से प्रोत्साहित होकर उस देश के लोगों को एक स्वशासित समाज के स्तर तक उठना ही होगा और इंग्लैण्ड के अन्तर्गत उसके मित्र के रूप में रहते हुए अपने मामलों को खुद ही हल करना सीखना होगा. इसी तरह रानाडे की स्वतन्त्रता सम्बन्धी मान्यता भी उदारवादी थी जिसका स्पष्ट अर्थ था, 'निश्चित मापदण्डों की सीमा में स्वतन्त्रता का उपभोग.' उनकी दृष्टि में अनियन्त्रित स्वतन्त्रता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक थी. सन् 1893 ई. में रानाडे ने अपने एक भाषण में कहा था, "स्वतन्त्रता का अर्थ है कानून बनाना, कर लगाना, दण्ड व्यवस्था स्थापित करना और अधिकारियों की नियुक्ति करना. एक स्वतन्त्र देश और गुलाम देश में मात्र अन्तर इतना-सा है कि स्वतन्त्र राष्ट्र में किसी प्रकार का दण्ड देने से पूर्व ही नियम बने होते हैं. कर लगाने से पूर्व उसके लिए जनता की स्वीकृति ली जाती है और विधि निर्माण से पूर्व जनमत लिया जाता है."

दादा भाई नौरोजी–दादा भाई नौरोजी एक उत्कृष्टतम् उदारवादी राष्ट्रीय विचारधारा के प्रमुख व्यक्तित्व थे. उनका जन्म सन् 1825 ई. में हुआ था. कांग्रेस की स्थापना से पूर्व लगभग 40 वर्षों तक वे भारत में सार्वजनिक जीवन को संगठित करते रहे और कांग्रेस की स्थापना के बाद 20 वर्षों से भी अधिक समय तक वे राष्ट्रीय भारत के सर्वमान्य नेता रहे. देशवासियों ने उन्हें भारत का पितामह (Grand old man of India) की उपाधि दी, जो उनकी एकमात्र स्नेहिल उत्कृष्टता का परिणाम था. दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक विचार तत्कालीन उदारवादी एवं मितवादी समन्वित चिन्तन से प्रभावित थे. उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था, लेकिन उनके जीवन के अन्तिम वर्षों में वे ब्रिटिश शासन के प्रति कठोर हो गए. ब्रिटिश उपेक्षावृत्ति और शोषणवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध जीवनपर्यन्त उन्होंने कड़ाई से मुकाबला किया एवं अंग्रेजी साम्राज्यवाद, आर्थिक शोषण की नीति को परिवर्तित करने के लिए मात्र संवैधानिक एवं उदार उपायों को ही उपयोग में लिया. दादा भाई नौरोजी ने निरंकुश साम्राज्यवादी नैतिक शक्ति में विश्वास प्रकट किया और भारतीय आकांक्षाओं तथा भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश जनता में स्वस्थ चेतना जाग्रत करने का भरसक प्रयास किया. दादा भाई नौरोजी ने व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में नैतिक शक्ति का आह्वान किया. नैतिकता ही किसी सत्ता को स्थायित्व दे सकती है. राजनैतिक सत्ता के नैतिक आधार की उन्होंने जबर्दस्त वकालात की और स्पष्ट किया कि न्याय उदारता और भावना की आधारशिलाओं पर ही राजनैतिक व्यवस्था की एकता कायम रखी जा सकती है. कोई भी राजनैतिक व्यवस्था यदि वह पाशविक बल पर आधारित है, तो कभी भी चिरस्थायी नहीं हो सकती. सन् 1893 ई. में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान उनके कथित वक्तव्यों से उनकी राजनीतिक एवं चारित्रिक मनोवृत्ति का स्पष्टीकरण मिलता है. किसी भी साम्राज्य का निर्माण भले ही अस्त्र-शस्त्रों के बल पर हो सकता है पर उसका परीक्षण केवल शाश्वत नैतिक शक्ति के आधार पर ही सम्भव है. अतः यह आवश्यक है कि सैनिक अथवा अस्त्र-शस्त्र बल की अपेक्षा शुभ संकल्पों एवं पारस्परिक दृढ़ विश्वास को राजनीतिक शक्ति का आधार बनाए जाए. इंग्लैण्ड ने पाशविक बल और उत्तेजना की नीति का अनुसरण किया तो यह निश्चित है कि उसका साम्राज्य विघटन की ओर अग्रसर होगा.

दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश संस्थाओं और ब्रिटिश चरित्र की जहाँ उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा की, वहाँ दोषों की निर्भीक आलोचना से भी वे कतराये नहीं. उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि ब्रिटिश जनता अपने कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनी रही, तो भारत स्वशासन की दिशा में निश्चयपूर्वक आगे बढ़ सकेगा. दादा भाई नौरोजी का कहना था कि जनता को अपने दुखड़ों के आगे ब्रिटिश शासन की अच्छाइयों को नहीं भूलना चाहिए. इस देश में ब्रिटिश शासन के स्थायित्व को मानकर ही आगे कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि उसी पर हमारी आशाएँ निर्भर हैं. भारत का भाग्य ब्रिटिश शासन के साथ जुड़ा हुआ है और किसी अन्य शासनों

को हम अपने सिर पर नहीं लादना चाहते. ब्रिटिश शासन के इस गुणगान के पीछे दादा भाई नौरोजी के मन में गौरी हुकूमत का कोई भय या आतंक नहीं था. दादा भाई एक उदारवादी राजनीतिज्ञ थे, जो भारत की आवाज, योग और आवश्यकता को संयुक्त भाषा में संवैधानिक ढंग से पेश करना चाहते थे. दादा भाई के अनुसार ब्रिटिश शासन-प्रणाली विनाशकारी और निरंकुश है तथा इंग्लैण्ड के लिए आत्मघाती एवं उसके राष्ट्रीय चरित्र, आदर्शों, परम्पराओं के प्रतिकूल है. उन्होंने इस शासन व्यवस्था को एक क्रूर स्वांग की संज्ञा देते हुए इसमें व्यावहारिक परिवर्तन की माँग की. दादा भाई ने बताया कि इंग्लैण्ड को भारत से प्रतिवर्ष कितना धन प्राप्त होता है और किस तरह भारतीय शासन में भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता. यदि वर्तमान निर्गम बन्द कर दिये जाएँ और देश के विधि निर्माणकारी गतिविधियों में भारतीय प्रतिनिधियों को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार दे दिया जाए, तो भारतीयों को ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत उज्ज्वल और सहज भविष्य की आशा हो सकती है.

दादा भाई ने भारत के पक्ष में ब्रिटेन में निरर्थक प्रचार किया. उन्हें विश्वास था कि यदि ब्रिटिश जनता को भारतीय स्थिति और भारतीय समस्याओं तथा मानव के प्रति सही जानकारी दी गई और भारत के बारे में ब्रिटिश जनता का अज्ञान मिटा दिया गया तो दोनों देशों के सम्बन्ध सुदृढ़ हो जायेंगे और दोनों ही देशों को इससे स्थायी लाभ होगा. इसी अनुभूति के कारण दादा भाई नौरोजी ने डब्ल्यू. सी. बनर्जी की सहायता से 'लंदन इण्डियन सोसाइटी' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों और भारतीयों का सम्पर्क बढ़ाना था. एसोसियेशन के समारोह में दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में ही होना चाहिए. उन्होंने अपनी शिकायतों की, एक लम्बी सूची तैयार कर ब्रिटिश शासकों के समक्ष पेश की, जिसमें शिक्षा के मामले में उदासीनता, भारतीय शासन में भारतीयों को उचित स्थान न देना, बार-बार अकाल पड़ना, सिंचाई और आवागमन के साधनों का अभाव आदि प्रदर्शित किया. दादा भाई ने ब्रिटिश जनता की नैतिकता को उकसाते हुए अनुरोध किया कि वह अपने स्वभाव और आदर्शों के अनुरूप ही भारत पर शासन करे और जो कुछ उसके कर्त्तव्य हों उन्हें ईमानदारी से पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दे. दादा भाई ने प्रस्ताव किया कि भारत और इंग्लैण्ड में सिविल सर्विसेज के लिए एक साथ प्रतियोगितात्मक परीक्षा की व्यवस्था हो. दादा भाई नौरोजी ने "भारत में भारतीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता के प्रमाण" नामक एक 95 पृष्ठ की पुस्तिका अंग्रेजों को सौंपते हुए सिद्ध किया कि शासन के विभिन्न विभागों में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त शिक्षक भारतीयों ने योग्यता और ईमानदारी से काम किया है और कर रहे हैं. दादा भाई नौरोजी ने कहा कि नैतिकता और संवैधानिक विधि दोनों का तकाजा है कि इंग्लैण्ड भारत पर भारतवासियों के कल्याण के लिए ही शासन करें. ब्रिटिश शासन का शासित राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य है कि वह भारत में फैली हुई विभिन्नता, निर्मम कष्टों को दूर करें. भारतीयों को राजनीतिक और आर्थिक कष्टों से छुटकारा दिलाने में ही ब्रिटिश चरित्र की नैतिकता है.

दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश निरंकुश साम्राज्यवाद की नैतिक बुराइयों का पर्दाफाश किया. उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद न केवल प्रशासनिक बुराइयों का, अपितु गम्भीर आर्थिक हलचलों का भी जनक है. निरंकुश शासकों की औपनिवेशिक जनता के साथ अहंकार और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने की आदत पड़ गई है. दादा भाई नौरोजी ने चेतावनी दी कि इंग्लैण्ड ने संवैधानिक सरकार के लिए जो वीरतापूर्ण संघर्ष किये हैं उनका इतिहास वास्तविक रूप से गौरवपूर्ण है. 10 जनवरी, 1906 ई. में गोखले के सम्मान में आयोजित एक रात्रि भोज में दादा भाई नौरोजी ने अभिव्यक्त किया था, "जिन उपनिवेशों को स्वशासन का अधिकार मिल गया है वे समृद्ध हो रहे हैं. भारत को स्वशासनाधिकार नहीं मिला है, इसलिए उसकी दशा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन हमारा 52 वर्षों का आन्दोलन असफल नहीं हो गया है. यदि भारत की समस्त जनता एक बार कह दे कि हम स्वशासन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो उनका कहना अभी बेकार नहीं जायेगा, जा ही नहीं सकता." दादा भाई नौरोजी का व्यवहार लगातार उग्र होता चला गया. सन् 1900 ई. में नेटिव रिफार्म क्लब में कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पूर्व उन्होंने कहा था, "यह कहा जाता है शासकों ने सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाया है, परन्तु वास्तव में यह कानून इसलिए बनाया गया है कि सुरक्षित ढंग से हमारी सम्पत्ति उठा ले जा सकें. ब्रिटिश सरकार अकाल, महामारी और भुखमरी द्वारा लाखों लोगों को बड़ी सादगी और वैज्ञानिक ढंग से मार रही है. अंग्रेज उन प्रवीण शल्य चिकित्सकों की तरह है जो अपने तेज औजारों से दिल को काटकर खून की एक-एक बूँद तक निकाल लेते हैं और उसका निशान तक नहीं छोड़ते." अन्ततः भारत माँ के इस महान् सपूत को सन् 1917 ई. में हमने अनचाहे मन से खो दिया.

उग्रवाद में वृद्धि तथा कांग्रेस में 1907 ई. का विभाजन

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन विभिन्न परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ता रहा. सन् 1905 ई. तक उस पर उदारवादी और नरम नीति के विचारकों का आधिपत्य रहा. इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में विचारधाराएँ बदलने लगीं और दूसरे चरण के रूप में उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ.

यद्यपि सन् 1905 ई. के बाद भी उदारवादी या मितवादी विचारधारा का प्रभाव कायम रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी के अन्त में और 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ऐसी निराशाजनक घटनाएँ घटीं, जिससे उदारवादी विचारधाराओं के प्रति असंतोष बढ़ता गया. उदारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और नरम वैधानिक साधनों के स्थान पर उग्र साधनों को अपनाए जाने पर बल दिया जाने लगा और इस समय से ही उग्रवाद का प्रारम्भ हुआ. उग्रवाद शब्द (Radicalism or Extremism) के प्रयोग की प्रारम्भिक अवस्था के समय का विश्लेषण करते हुए लोकमान्य तिलक, जो स्वयं भी एक उग्रवादी थे, ने कहा था, "हमारी नीतियों के सन्दर्भ से दो नए शब्द हाल ही में अस्तित्व में आये हैं, वे हैं–नरमपंथी (Moderates) और उग्रवादी (Extremists). इन शब्दों का समय के साथ विशिष्ट सम्बन्ध है. अतः समय के अनुसार ही इनमें परिवर्तन आता जायेगा. आज के उग्रवादी कल नरमपंथी बन जाएंगे. ठीक उसी प्रकार कि आज के नरमपंथी कल उग्रवादी थे. उग्रवाद से तात्पर्य उन लोगों के राजनीतिक दर्शन से है, जो भारत में 20वीं शताब्दी के आरम्भ में उग्रवादी समझे जाते थे. इन उग्रवादियों में लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, अरविन्द घोष, विपिन चन्द्र पाल और अन्य उनके समर्थक प्रमुख थे. सन् 1916 से 1918 ई. की अवधि में श्रीमती एनीबेसेन्ट और इण्डियन होमरूल में उनके सहयोगी भी सरकार तथा उदारवादी नेताओं द्वारा उग्रवादी ही माने जाते थे."

उग्रवाद का प्रारम्भ

सन् 1885 ई. से लेकर सन् 1906 ई. तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनेक माँगें कीं. उन माँगों पर ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल, लाला लाजपत राय का कांग्रेस की नीतियों से मतभेद उत्पन्न हो गया. सन् 1906 ई. में कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, सर फीरोजशाह मेहता, गोपालकृष्ण गोखले, मदनमोहन मालवीय, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और रमेशचन्द्र दत्त जैसे नेताओं का आधिपत्य था. ये सभी नेता संवैधानिक नियमों और ब्रिटिश को ईश्वरीय स्वरूप मानने में विश्वास रखते थे, लेकिन इन सब बातों का तरीका लाला लाजपत राय एवं बाल गंगाधर तिलक को रास नहीं आया. तभी से उग्रवाद का प्रारम्भ हुआ. इसकी वास्तविक स्थिति को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए इतिहासकार डॉ. ताराचन्द लिखते हैं–"सरकारी विरोध तथा घृणा से अविचलित होकर राजनीतिक आन्दोलन जोर पकड़ता और बढ़ता चला गया. राष्ट्रीय कांग्रेस हर साल अपने वार्षिक अधिवेशनों में सरकार की आधारभूत त्रुटियों और सामयिक गलतियों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करती रही. प्रान्तों में राजनैतिक सम्मेलन होते थे और कांग्रेस के प्रस्तावों को दोहराया जाता था. भारत में सर्वत्र संस्थाओं की ओर से सभाएँ होती थीं और सरकार की आलोचना की जाती थी. अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के पत्र राष्ट्रीय नेताओं के विचारों का प्रचार करते थे. राजनीतिक साहित्य बराबर छपता और देश में बाढ़ की तरह फैलता रहा, साथ ही बहुत से राजनीतिक कार्यकर्त्ता छोटी या बड़ी सभाओं में भाषण देकर जनता की राजनीतिक जागृति को बढ़ाते थे."

इस प्रकार जब हालत में काफी उथल-पुथल थी तब सरकार के रुख से निराश होकर ह्यूम ने राष्ट्र से यह अपील की थी कि "प्रत्येक भारतीय जो हमारी मातृभूमि पर साँस लेता है, हमारा साथी, हमारा सहकर्मी, हमारा समर्थक बने और यदि जरूरत पड़े तो वह उस युद्ध में हमारा सैनिक भी बन जाए, जिससे काब्डेन और उसके वीर साथियों की तरह हम न्याय, स्वतन्त्रता और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे." इस प्रकार से कांग्रेस ने सौम्य तरीकों की सीमाओं से निकलकर देशभर में राजनीतिक आन्दोलन करने का विचार फैला. सब वर्गों के लोगों से धन, इकट्ठा करने की मंत्रणाएँ होती थीं. शहरों और जिलों की सभाओं में बोलने के लिए व्याख्याता भेजे जाते थे और साहित्य का वितरण किया जाता था. उस दौरान दो पुस्तिकाएँ निकली थीं–कांग्रेस क्या है ? (कांग्रेस कैटेकिज्म) और "कमक्खतपुर के मौलवी फदरुद्दीन और राम बख्स से बातचीत" जिसमें जमींदारी, तानाशाही नीतियों की जमकर आलोचना की गई थी और सारी बुराइयों को दूर करने का एकमात्र साधन प्रतिनिधि शासन बताया गया था. इस प्रचार-प्रसार की इंग्लैण्ड में भयंकर आवश्यकता हुई और कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इस कार्य के लिए बनीं, जिसमें वेडरबर्न अध्यक्ष, विलियम डिग्बी सचिव, दादा भाई नौरोजी एवं अन्य अंग्रेज सदस्य के रूप में हुए एवं इसी दौरान इण्डिया नामक पत्र कांग्रेस के विचारों के प्रचार के लिए निकाला गया.

इस कार्य की शुरूआत ह्यूम ने की अवश्य, लेकिन इसका विस्तार लोकमान्य तिलक, पाल, लाल, अरविन्द घोष जैसे नेताओं ने किया. उस दौरान प्रचलित धीमी एवं मर्यादित राजनैतिक विचारधारा से, जिसमें सभी नेता उच्च वर्गों के व्यक्ति और पेशेवर वर्ग के सफल व्यक्ति थे, इसके बावजूद तिलक आदि नेताओं को इसकी कार्यप्रणाली पसन्द नहीं आई. वे कांग्रेस की आवेदन-निवेदन वाली नीति के विरुद्ध थे और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि सक्रिय राजनीतिक आन्दोलन के तरीके अपनाए जाएं. कांग्रेस के तरीकों की अक्षमता एवं असफलता पर सन् 1893 ई. में इन्दूप्रकाश में लेखमाला लिखी, जिसको "न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड" नाम दिया. उन नेताओं ने विधायक परिषदों के विस्तार और भारत और इंग्लैण्ड में एक साथ होने वाली परीक्षाओं को हाथ की सफाई बताया. उन्होंने चेतावनी भी दी–"अंग्रेजी राज्य के दुर्ग की दीवारें अभी फटी नहीं हैं और गरीबी की काली छाया दिन पर दिन देश पर फैलती जा रही है."

कांग्रेस के सिद्धान्तों से उग्रवादी सहमत नहीं थे. उन्होंने इसे एक मध्यमवर्गीय, स्वार्थी, सार्वजनिक कार्य में भोली तथा निःस्वार्थ देशभक्ति का खोखला दावा करने वाली संस्था माना था. इसी सम्बन्ध में उनके विचारों से असहमत होते हुए अरविन्द घोष ने कहा था–"यह कांग्रेस खिलौनों से खेलती है न कि गम्भीर प्रश्नों को लेकर या तथ्यों को समाहित रखती है. इसने अपने को, भारतीय जनता को, शक्तिशाली बनाने की कोई चेष्टा नहीं की. विशाल जनता के हृदय को छूने में ये असफल रही है. सर्वहारा वर्ग ही सबसे महत्वपूर्ण है, सही और सफल नीति यही होगी कि देश की सारी शक्ति को जाग्रत किया जाए और इस प्रकार इसे यानी जनशक्ति के परिणाम तथा सामर्थ्य को अनन्त रूप से बढ़ाया जाए." अरविन्द की इस उक्ति को चरितार्थ करने में जनशक्ति के परिणाम तथा सामर्थ्य को बढ़ाने में भयंकर भूमिका का निर्वाह लाल, बाल, पाल ने मिलकर किया. लैंसडाऊन के जाने से पूर्व ही भविष्य के काले स्वप्न आशंकाएँ बनकर नजर आने लगे. भारत का असंतोष हद तक बढ़ गया और भारतीय जनता में विश्वास, भय और आशाएँ तरंगित हो उठीं. अकाल, ताऊन और साम्प्रदायिक दंगों के चारों तरफ आतंक छा गया. इन सबके साथ भारत में धार्मिक पुनरुज्जीवन की भावनाएँ सबके दिल पर छा चुकी थीं. लोगों में अपने आत्म-सम्मान, गौरव और अतीत की उत्कृष्टता की जागृति हो चुकी थी. स्वामी विवेकानन्द की विजय यात्राओं ने सिद्ध कर दिया था कि पश्चिमी देशों से कहीं अधिक पूर्वी देश श्रेष्ठ हैं और इस समय भारत के बाहर की स्थिति यह थी कि एक लम्बे अर्से से विश्व में निर्विवाद प्रभुत्व के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के सामने प्रतियोगी एवं प्रतिद्वन्दी आ खड़े हुए थे. संयुक्त राज्य अमरीका और जर्मनी, इंग्लैण्ड को औद्योगिक विकास में पीछे छोड़ गये थे. जर्मनी के युवा महत्त्वाकांक्षी शासक कैसर विलियम द्वितीय ने अपने मन्त्री बिस्मार्क से शासन अपने हाथ में ले लिया था. सीधे शब्दों में इंग्लैण्ड के सामने चारों तरफ से प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति बन चुकी थी. जर्मनी लगातार विदेशी उपनिवेशों का दावा कर रहा था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए चुनौती था. इन सबके अलावा रूस पूर्व में प्रशान्त महासागर की तरफ लगातार बढ़ता चला आ रहा था. इसी दौरान जापान सारे यूरोप के लिए खतरा बन चुका था. ऐसी भयानक परिस्थिति में सन् 1893 ई. में एल्गिन भारत आया था, जिसने आई परिस्थितयों का डटकर मुकाबला किया. उदारवादी विचारधारा के लोगों का प्रभुत्व समाप्त प्रायः हो गया था और नए भारतीय नेता उग्रवादी विचारधारा को लेकर भारत में प्रवेश कर चुके थे. इन उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक सबसे प्रमुख थे, जिन्होंने अपनी युवावस्था में ही देश की सेवा में जीवन अर्पित करने का संकल्प कर लिया था. उग्रवादी नेताओं के सहयोग से उन्होंने एक विद्यालय और अंग्रेजी में 'मराठा' के नाम से और मराठी में 'केसरी' नाम से दो समाचार-पत्र जनता को शिक्षा देने के लिए तथा जनमत संग्रह करने के लिए चलाए थे. इनके द्वारा समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता, सरकार की साम्राज्यवादी नीति एवं तरीकों की बहुत आलोचना की जाती थी. सन् 1890 में सहवास वय विधेयक का विरोध कर उग्रवाद आन्दोलन ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की थी. सरकार के मुसलमानों को समर्थन दिए जाने की आशंका से सन् 1893 ई. में उनके द्वारा चलाया गया गौरक्षा आन्दोलन भी अत्यन्त प्रशंसनीय रहा.

उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के कारण

उग्रवाद का उदय विकृत परिस्थितियों में आकस्मिक रूप से हुआ था. उसके उदय के मूल में निम्नलिखित कारण थे–

उदारवाद की असफलता–कांग्रेस की स्थापना से सन् 1905 ई. तक लगातार उदारवादियों का प्रभुत्व रहा, लेकिन प्रार्थना-याचना आदि के अपने वैधानिक और नरमपंथी साधनों से वे भारत के हित में कोई विशेष सफलताएँ अर्जित नहीं कर सके. शताब्दी की समाप्ति तक किसानों, मजदूरों और गाँव के सम्भ्रान्त लोगों के मन में असन्तोष और निराशा हरदम बढ़ती रही. सन् 1892 ई. के अधिनियम के अन्तर्गत किए गये सुधार पूर्णतः अनुपयुक्त थे. कांग्रेस ने प्रतिवर्ष सुधार सम्बन्धी माँगों का प्रस्ताव करना जारी रखा, लेकिन सरकार ने इस अनुरोध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया. अतः आश्चर्य नहीं कि उन नरमपंथी नेताओं की लोकप्रियता निरन्तर घटने लगी, जो सरकार से सुधार की प्रार्थना करते ही जा रहे थे. जो भवितव्यता थी, एक लम्बी संख्या में तुरन्त परिवर्तन चाहने वाले, शक्ति की दम पर खुद की ताकत से सरकार बदलने वाले उग्रवादी नेताओं का उदय हुआ.

ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति एवं खराब शासन–ब्रिटिश शासन ने अपनी प्रतिक्रियावादी नीति से भारतीयों को विक्षुब्ध कर दिया. सन् 1888-1894 ई. तक लॉर्ड लैंसडाऊन ने ऐसे विधेयक पारित किये, जिससे मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयाँ आने लगीं. सन् 1894 से 1898 ई. तक लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल था. उसने नौकरशाही और दमनकारी नीति से भारतीयों को कड़े विधानों के द्वारा परेशान किया और रोजमर्रा पर अनावश्यक व्यय करने लगा. कलकत्ता कॉर्पोरेशन कानून, भारतीय यूनिवर्सिटीज एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आदि अनेक कानून बनाकर देश में असन्तोष फैला दिया. उसकी क्रूर नीति से उदारवादी हार गये और आन्दोलनवादी शक्ति का प्रारम्भ हुआ. इसके अलावा इसका दूसरा प्रमुख कारण इंग्लैण्ड के अनुसार दल का खराब शासन था. सन् 1882 से 1902 ई. तक अधिकांश समय तक

इंग्लैण्ड का प्रधानमंत्री सैलिसवरी रहा, जो स्वयं एक अच्छा आदमी होते हुए साम्राज्यवादी नीति रोकने में नाकामयाव रहा था. इसी तथ्य को प्रकाशित करते हुए आर. सी. दत्त लिखते हैं–"सैलिसवरी स्वयं साम्राज्यवादी नहीं था, परन्तु वह समयानुसार बदल जाता और उसमें विरोध करने की शक्ति नहीं रह जाती थी. लॉर्ड हेमिल्टन, जोकि लंदन में भारत के कार्यकाल का प्रधान था, भारत की ओर कोई सहानुभूति नहीं रखता था." 20 सितम्बर, 1899 ई. को उसने लॉर्ड कर्जन को लिखे पत्र में व्यक्त किया था, "मेरा विचार है कि शासन को वास्तविक खतरा अब नहीं 50 वर्ष के पश्चात् होगा और उसे हमें अपनाना होगा. यदि हम शिक्षित हिन्दू दल को दो भागों में बाँट सकते हैं जिसके परस्पर विरोधी विचार हों तो हमें इस प्रकार की फूट से अपनी सरकार की वर्तमान पद्धति पर शिक्षा के प्रसार के कारण होने वाले लगातार और तीक्ष्ण आक्षेपों के विरुद्ध अपनी स्थिति दृढ़ करनी चाहिए." उस दौरान हेमल्टिन अपने पद पर था फिर भी अकाल, महामारी के प्रति उदासी रहा, जिससे बड़ा भारी रोष भारत में व्याप्त हो गया.

भारत की आर्थिक विषमता और शोषण–अट्‌ठारहवीं शताब्दी में भारत में अनेक कुटीर उद्योग, पारम्परिक व्यवसाय एवं कृषि पैदावार जोरों पर थी, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में आते ही देश को कंगाल वना दिया. भारत को कच्चा माल का केन्द्र और इंग्लैण्ड के पक्के माल को बेचने का बाजार बना दिया, जिससे भारत की स्थिति दयनीय हो गई. सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश तंगदस्त हो गया. इसके परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी के अन्त तक भारतीयों को भीषण आर्थिक संकट, अकाल एवं महामारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रिटिश शासन सहयोग करने में उत्साहहीन रहा. लाखों-करोड़ों लोग भूख से मरते रहे और अंग्रेज अनाज को विदेशों में भेजते रहे. इससे भारतीयों को स्वशासन की आवश्यकता महसूस हुई. इस दौरान उदारवादियों की प्रार्थनाएँ एवं आवेदनों पर मात्र उपहास किया गया. इससे नवयुवकों और नेताओं के एक वर्ग में विश्वास होने लगा कि वे ब्रिटिश शासन का अन्त करके ही रहेंगे, इसके लिए भले ही उन्हें क्रान्तिकारी नीति या हिंसा अपनानी पड़े.

प्रवासी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार–ब्रिटिश उपनिवेशों के निवासी भारतीयों को काले-गोरे के भेद से विभाजित कर उन्हें वर्वर यातनाएँ, असभ्य और अभद्र व्यवहार से पीड़ित किया जाता था. अप्रवासी भारतीयों को हिंसक वारदातों से तड़फाया जाता था. भारतीयों को प्रवासी देशवासियों के व्यवहार से परेशान होकर उग्रवाद के रूप में उदित होना पड़ा.

लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन–सन् 1898 ई. से 1905 ई. तक लॉर्ड कर्जन का आधिपत्य रहा, उसकी प्रतिक्रियावादी नीति और नौकरशाही ने भारतीयों को झकझोर दिया और पुराने नेताओं की अनुनय-विनय की नीति के अस्तित्व को ठुकरा दिया, जिससे भारतीयों में एक नये वर्ग का उदय हुआ जो हिंसक और क्रान्तिकारी नीति पर आधारित था. लॉर्ड कर्जन ने अन्याय की एक शृंखला में ऑफिसिएल सीक्रेट्स बिल पास कर भारतीयों को भड़का दिया. सन् 1899 ई. में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता निगम विधेयक पास करवाया, जिससे उसने निगम की स्वतन्त्रता को नष्ट कर ब्रिटिश अधिकारियों का कन्ट्रोल बढ़ा दिया गया. सन् 1904 ई. में उसने यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया, जिससे यूनिवर्सिटी की आन्तरिक एकता की स्वतन्त्रता नष्ट कर दी गई और उन पर सरकारी कन्ट्रोल स्थापित किया गया. फरवरी 1905 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दीक्षान्त समारोह में लॉर्ड कर्जन ने कहा था, "सत्य का उच्च आदर्श अधिकतर पश्चिमी विचार है. इस आदर्श ने पहले पश्चिमी नैतिक परम्परा में उच्च स्थान लिया. इसके बाद यह आदेश पूर्व में आया जहाँ पहले चारों ओर चालाकी एवं कुटिलता विद्यमान थी." इस भाषण को सुनते ही भारतीय जनता में आक्रोश छा गया. भारतीयों के प्रतिनिधिमण्डल ने कर्जन को अपने वास्तविक भारतीय चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए मिलना चाहा पर नहीं मिल सके. इसके वाद गोखले और लाला लाजपत राय को इंग्लैण्ड भेजा गया, जिसका परिणाम भी नगण्य ही रहा. इसके बाद दूसरी प्रमुख उत्तरदायी घटना बंगाल विभाजन उग्रवाद के उत्थान के मूल में रही. लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल एक बहुत बड़ा प्रान्त था. उसमें सारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर शामिल था. लॉर्ड कर्जन ने हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास कर राष्ट्रवाद को बाधित किया. उसने पूर्व के मुसलमानों को बताया कि बंगाल के बाँटने से पूर्वी बंगाल में उनका बहुमत हो जायेगा और उन पर हिन्दुओं की प्रधानता नहीं रहेगी. इसके बाद सन् 1905 ई. में बंगाल विभाजन हुआ. इस चुनौती का सामना करने के लिए लोगों ने प्रतिज्ञा की और सभा, प्रार्थनाओं की अपेक्षा प्रभावशाली उपायों की आवश्यकता बतलाई, जिससे उग्रवाद का उदय हुआ.

पारिस्थितिकी विषमता, अकाल और प्लेग का आतंक–सन् 1894-1898 ई. तक लॉर्ड एल्गिन के काल में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे लाखों लोग मारे गए. इसका प्रभाव 70,000 वर्ग मील तक पड़ा और लगभग दो करोड़ लोगों की जानें चली गईं. अकाल की छाया दूर हुई नहीं थी कि पूना में बड़ा भारी प्लेग फैल गया. प्लेग को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों ने जनता का कोई सहयोग नहीं दिया. इसकी कड़ी आलोचना में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार-पत्र 'केसरी' में लिखा. परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के एक नवयुवक दामोदर हरि चापेकर ने भड़क कर पूना के प्लेग कमिश्नर रैण्ड और उसके सहायक लेफ्टीनेंट एम्हर्स्ट की

हत्या कर दी. उस नवयुवक को एवं उसके छोटे दो भाइयों को फाँसी की सजा दी गई और उस नवयुवक को भड़काने के आरोप में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक को 18 माह की सख्ती से कैद की सजा दी गई. इससे भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश छा गया और उदारवादी नीति के सिद्धान्तों को तोड़ा जाने लगा. सर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने लिखा था, "हम पूना में दण्ड देने वाली पुलिस को दोषी ठहराना गलत समझते हैं. तिलक और पूना के अन्य पत्रों के सम्पादकों को कैद में डालना ब्रिटिश शासकों की बेहूदगी है. तिलक की कैद पर सारा राष्ट्र रो रहा है. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त करना हमारा बहुमूल्य अधिकार है और हम इसके लिए जी-तोड़ संघर्ष करेंगे." इन सभी कारणों का मिला-जुला परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी मार्ग का उदय हुआ जिसे उग्रवादी कहा जाने लगा. सन् 1905 ई. में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने भारतीयों का स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का आह्वान किया. सन् 1906 ई. में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादी व उग्रवादी दलों में मतभेद उग्र हो गया. अगले वर्ष सन् 1907 ई. में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस संगठन दो दलों उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गया. अधिवेशन में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में उग्रवादी विचारधारा के नेताओं ने स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार सम्बन्धी प्रस्तावों के पास किए जाने का आग्रह किया. उदारवादियों ने उग्रवादियों का विरोध किया. इसके फलस्वरूप आपसी मतभेद की सीमा टूट जाने से उग्रवादी कांग्रेस से बाहर निकाल दिये गये. इसके बाद सन् 1916 ई. तक कांग्रेस में उदारवादियों का प्रभुत्व रहा. मिसेज एनीबेसेन्ट एवं अन्य नेताओं के सहकार से सन् 1916 ई. में दोनों दलों में समझौता हो गया, लेकिन वो स्थायी न रहकर 20वीं शताब्दी तक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की तीन विचारधाराएँ एवं तीन प्रकार के आन्दोलनात्मक स्रोत बन गए.

प्रमुख उग्रवादी विचारक

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (1856-1920)–लोकमान्य तिलक का जन्म सन् 1856 ई. में एक ऐसे महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसका सम्बन्ध इतिहास के गौरवशाली पेशवाओं से था. बचपन से ही तिलक मेधावी और प्रखर व्यक्तित्व के धनी थे. सन् 1879 ई. में उन्होंने एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी. कॉलेज के दिनों से ही वे सार्वजनिक कार्यों की ओर उन्मुख हो गये थे. चूँकि गणित के प्रतिभावान छात्र होने के नाते उनसे पूछा गया कि वे गणित में एम.एस.सी. के बजाय एल-एल.बी. क्यों कर रहे हैं ? तो उन्होंने उत्तर दिया था–"मैं अपना जीवन देश के जन-जागरण में लगाना चाहता हूँ और मेरा मानना है कि इस कार्य के लिए साहित्य अथवा किसी अन्य विज्ञान, गणित की उपाधि की अपेक्षा कानून का ज्ञान अधिक उपयोगी होगा. मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें मुझे ब्रिटिश शासकों से संघर्ष न करना पड़े." प्रारम्भिक दिनों के राष्ट्रीय मंच में उन्होंने धूम मचा दी थी. लोग स्नेह एवं सम्मान से अविभूत होकर उन्हें लोकमान्य, जनता के प्रिय नायक तथा सर्वसम्मानित कहकर पुकारते थे. मानो यह सारे राष्ट्र की श्रद्धांजलि हो. लोकमान्य तिलक का राजनीतिक मन्त्र "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूँगा" अधिकांश सजग भारतीयों के होठों पर था. तिलक वे पहले नेता थे जिन्होंने राजनीतिक आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए धार्मिक जोश का प्रयोग किया. वे कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे, कर्मठ, साहसी सेनानी थे, जिन्होंने अपनी अनवरत साधना और महान् बलिदान के द्वारा भारतीय स्वाधीनता के भव्य महल में नींव डालने की भूमिका अदा की थी. वे प्रत्येक पहलू में यथार्थ और आदर्श से घिरे हुए रहते थे. अब तक कांग्रेस के मंच पर आये सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों से ज्यादा महान् वे थे, क्योंकि क्रान्तिकारी के साथ वे प्रखर बौद्धिक एवं विद्वान् थे. गीता दर्शन पर उनका भाष्य और 'आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन्स' नामक यह ग्रन्थ जिसमें हिन्दुओं के आदिग्रन्थ वेदों जन्म-स्थान आर्कटिक प्रदेश में सिद्ध किया गया था, उनके विस्तृत अध्ययन और अनुसन्धान में गहरी रुचि के प्रमाण हैं.

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सार्वजनिक सेवावधि के चार दशकों में शक्ति के रूप में प्रस्फुटित हुए. एक शिक्षा शास्त्री के रूप में उन्होंने पूना न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्षिण शिक्षा समाज तथा फर्ग्युसन कॉलेज के व्यवस्थापक के रूप में ख्याति अर्जित की. अपने अथक् परिश्रम से उन्होंने वस्तुतः महाराष्ट्र में एक शैक्षणिक क्रान्ति ही उत्पन्न कर दी. ओरियन्टल सोसाइटी के लिए ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों की प्राचीनता सिद्ध करने वाले एक विद्वतापूर्ण निबन्ध के कारण देश-विदेश में उनकी ख्याति फैल गई. लोकमान्य तिलक ने आर्थिक अन्याय के प्रति लोहा लिया. सन् 1896 ई. में अकाल में लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किये. सन् 1889 ई. से कांग्रेस में अपने प्रवेश के बाद से ही एक राजनीतिक नेता के रूप में कांग्रेस के कार्यकलापों में तिलक ने उल्लेखनीय भूमिका अदा की. उदारवादियों की नीति से असन्तुष्ट तिलक ने अपनी शक्ति महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आन्दोलन को सुसंगठित करने में लगाई और भारतीय नवयुवकों में यह भाव भरने की चेष्टा की, "देश अपनी स्वतन्त्रता किसी की दया के बल पर नहीं, अपितु अपने सामर्थ्य के बल पर अर्जित करे. अपने दो समाचार-पत्र–केसरी और मराठा तथा शिवाजी और गणेश उत्सवों द्वारा उन्होंने जनता में देशभक्ति की भावना फूँक दी

तथा उसने अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति उत्पन्न की. 19 दिसम्बर, 1893 ई. के अपने प्रमुख समाचार-पत्र 'केसरी' में लोकमान्य तिलक ने अपनी मनोवृत्ति को उद्‌घाटित करते हुए लिखा था, "भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय-विनय कर हम कुछ नहीं पा सकते. ऐसे प्रयत्न करना पत्थर पर सिर टकराने के समान है." सन् 1897 ई. में तिलक मुम्बई विधान परिषद् के सदस्य चुने गए, जहाँ उन्होंने सदस्यीय सेवा के दौरान सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की. महाराष्ट्र में अकाल और पूना में प्लेग के समय जनता के कष्टों के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से क्षुब्ध होकर दो नवयुवकों ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैण्ड तथा एक अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी. तिलक का इस हत्याकाण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं था, किन्तु ब्रिटिश सरकार ने उन पर हिंसा और राजद्रोह भड़काने का आरोप लगाकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 18 मास का कठोर कारावास का दण्ड दे दिया. तिलक की गिरफ्तारी ने न केवल महाराष्ट्र को वरन् सम्पूर्ण भारत को उग्र बना दिया और ब्रिटिश सरकार को यह अनुभव हो गया कि तिलक का जनता पर कितना प्रभाव है ? तिलक की महानता इस बात में निहित थी कि सरकार के प्रति बर्बर रवैये के फलस्वरूप उन्होंने कभी सार्वजनिक जीवन से मुख नहीं मोड़ा और न वे कभी निराशावाद से अभिभूत होकर बौद्धिक अन्तर्मुखी ही बने. प्राचीन युग के महान् ऋषियों की भाँति उन्होंने सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से अविचलित होकर सहन किया. सन् 1905 ई. में बंग-भंग के समय तिलक का राजनीतिक कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर सम्पूर्ण भारत हो गया. 'केसरी' के माध्यम से उन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज्य का संदेश जन-जन तक पहुँचाया. लाल-बाल-पाल ने देश में वस्तुतः एक संगठित उग्रवादी और राष्ट्रवादी दल को राष्ट्रीय रंगमंच पर ला खड़ा किया. कांग्रेस के उदारवादी नेता तिलक के उग्र और यथार्थवादी विचारों से सहमत नहीं हो सके. फलस्वरूप कांग्रेस के नरम और गरम दल में मतभेद की खाई चौड़ी होती गई और अन्ततः सन् 1907 ई. में 'सूरत की फूट' के रूप में सामने आई. इसके बाद सन् 1915 तक अपने अलग अस्तित्व के साथ कांग्रेस उग्रवादी स्वरूप में काम करती रही. सन् 1908 ई. में तिलक को राजद्रोह के मिथ्या आरोप में पुनः गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कारावास का दण्ड देकर माण्डले जेल में भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने दो विख्यात ग्रन्थ-रत्नों–गीतारहस्य और 'द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन्स' की रचना की. ये दोनों ही ग्रन्थ लोकमान्य तिलक के विशाल ज्ञान, ऐतिहासिक शोध, गाम्भीर्यता और विचारों की उत्कृष्टता के परिचायक बन गये.

सन् 1914 ई. में कारावास से मुक्त होने पर तिलक पुनः राष्ट्रीय संगठन के कार्य में समर्पित हो गये. सन् 1916 ई. से सन् 1920 ई. तक उन्होंने होमरूल लीग का प्रचार करके कांग्रेस के कार्य–देश के स्वाधीनता संघर्ष को आगे बढ़ाया. एनीबेसेन्ट के प्रयत्नों से तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए और अन्त तक इसी में रहे. सन् 1918 ई. में वे सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये, लेकिन शिरोल केस के सिलसिले में इंग्लैण्ड चले जाने से वे इस गौरवशाली पद को स्वीकार न कर सके. सन् 1920 ई. के सितम्बर मास में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जब लोग तिलक के सभापति चुने जाने की आशा कर रहे थे तभी यकायक मृत्यु ने अपने आगोश में इस महान् व्यक्ति को समेट लिया. सन् 1920 ई. में 21 जुलाई को मुम्बई में आकस्मिक बीमारी से स्वाधीनता संग्राम के इस विकट योद्धा का स्वर्गवास हो गया. पर इस समय तक तिलक सचमुच कांग्रेस का रूपान्तर कर चुके थे और उसे सुदृढ़ नौकरशाही विरोधी मोर्चे में परिवर्तित कर चुके थे.

लाला लाजपत राय (1865-1959) और उनकी राजनीतिक मनोवृत्ति–लाला लाजपतराय का जन्म 28 जनवरी, 1865 ई. को हुआ था. वे पंजाब केसरी के नाम से सारे भारतवासियों की जुबां पर छाये हुए थे. वे एक महान् राष्ट्रवादी एवं आधुनिक भारत के अग्रणी राज नेता थे. उनका सारा जीवन त्याग, बलिदान और निष्ठा से भरा हुआ था. राष्ट्रीय मुक्ति के सम्बन्ध में उनकी धारणा बहुत विशुद्ध और व्यापक थी तथा समाज सुधार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति उनका प्रेम अनुकरणीय था. वे उत्कृष्ट कोटि के लेखक और विद्वान् थे. उनकी पुस्तकें–यंग इण्डिया, अनहैप्पी इण्डिया, इंग्लैण्ड्स डेट टू इण्डिया उनके ज्ञान की विशालता एवं राष्ट्रीयता की उत्कृष्ट भावना को प्रदर्शित करती है. लाला लाजपत राय का जीवन कर्म और संघर्ष का जीवन था और उनका आदर्श भारतीय राष्ट्रीयवाद का आदर्श था. ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए वे भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान के समर्थक थे. पंजाब के लुधियाना जिले के जगराव नामक छोटे से गाँव के इस व्यक्ति ने देश के हित के लिए कठिन-से-कठिन यातनाएँ भोगीं और स्वतन्त्रता यज्ञ में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी. उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से बी.ए. पास किया और सन् 1885 ई. में वकालात पास की. अपने प्रारम्भिक जीवन में ही उन्होंने हिसार में वकालात शुरू कर दी. उन्होंने आर्य समाज और डी.ए.वी. कॉलेज की लाहौर में स्थापना के लिए अत्यन्त सहयोग दिया. लाला लाजपत राय ने देश की राजनीति में सक्रिय प्रवेश सन् 1905 ई. में किया. उस दौरान बंग-भंग जोरों पर था. उन्होंने लॉर्ड कर्जन की कूटनीति एवं साम्राज्यवाद का डटकर मुकाबला किया. सन् 1905 में उन्हें गोपालकृष्ण गोखले के साथ कांग्रेस ने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश शासन एवं जनता के सामने रखने के लिए इंग्लैण्ड भेजा. वहाँ से वे

इंग्लैण्डवासियों की नागरिक स्वतन्त्रता और राजनीतिक अधिकारों पर वल देने की प्रवृत्ति से अत्यन्त प्रभावित हुए. लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बताया कि ब्रिटिश लोगों की भारतीय मामलों के प्रति कोई रुचि नहीं है. इसलिए भारतीयों को विदेशी सहायता पर निर्भर रहने के बजाए अपने बल पर अपनी जनशक्ति को संगठित कर ब्रिटिश शासकों को विवश कर स्वशासन और स्वराज्य का अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए. अन्य उग्रवादी नेताओं की तरह लाला लाजपत राय भी उग्रवादी, समाजवाद के प्रतीक एवं पूँजीवादी आर्थिक शोषण के विरुद्ध धारणा वाले महान् राष्ट्रीय भक्त थे. वे किसानों और मजदूरों के हमेशा पक्ष में रहे. सन् 1907 ई. में उन्होंने सरदार अजीत सिंह से मिलकर कोलोनाइजेशन बिल (Colonization Bill) के विरुद्ध आन्दोलन चलाया. इस पर ब्रिटिश सरकार आतंकित हो उठी और प्रतिक्रियावादी नीति के तहत दोनों राष्ट्र-भक्तों सरदार अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय को बिना मुकदमा चलाए देश निर्वासन का दण्ड देकर बर्मा (म्यांमार) की माण्डले जेल में 6 माह तक रखा. 18 नवम्बर, सन् 1907 ई. को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. वे छूटकर लाहौर पहुँचे. उसी दौरान कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिये उनका नाम प्रस्तावित किया, लेकिन गोखले के विरोध करने पर लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया. लाला लाजपत राय कांग्रेस में मतभेद के आकांक्षी नहीं थे. लाला लाजपत राय राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी प्रचार, निष्क्रिय प्रतिरोध एवं संवैधानिक आन्दोलन के महान् समर्थक थे.

सन् 1914 ई. में उन्होंने एक शैक्षणिक ट्रस्ट की स्थापना की और अपने गाँव में ही **राधाकृष्ण हाई स्कूल** की नींव रखी. सन् 1914 ई. में भारत के किसी काम से लाला लाजपत राय को इंग्लैण्ड जाना पड़ा. दुर्भाग्यवश उसी दौरान प्रथम महायुद्ध छिड़ गया. अन्ततः सन् 1919 ई. तक वे बाहर रहकर ही स्वराज्य आन्दोलन, स्वाधीनता संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ते रहे. सन् 1919 ई. में भारत में आकर उन्होंने पंजाब में मार्शल लॉ और अमृतसर में जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड देखा. समस्त घटनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए सन् 1920 ई. में कलकत्ता में एक अधिवेशन का आयोजन किया, जिसके सभापति लाला लाजपत राय स्वयं चुने गये. चूँकि उनकी विचारधारा असहयोग आन्दोलन से मेल नहीं खाती थी, फिर भी कांग्रेस के आन्दोलन छेड़ देने से उन्होंने असहयोग आन्दोलन का डटकर प्रचार-प्रसार किया. इस आन्दोलन के कारण उन्हें जेल की सजा मिली. जेल से छूटने के बाद उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज्य दल को संगठित किया और केन्द्रीय विधान परिषद् का चुनाव जीता. वे केन्द्रीय विधान सभा में स्वराज्य दल के उपनेता चुने गये. स्वराज्य दल की मुसलमान तुष्टिकरण नीति से असन्तुष्ट होकर उन्होंने मदन मोहन मालवीय के साथ स्वराज्य दल से अलग होकर हिन्दू महासभा का गठन किया, यद्यपि वे राष्ट्रवादी थे और राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे, फिर भी हिन्दू हितों की उपेक्षा उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होती थी. वे पाश्चात्य सभ्यता-संस्कृति की तुलना में भारतीय सभ्यता संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे एवं उसकी रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते थे.

लाला लाजपत राय ने सन् 1921 ई. में पुरुषोत्तम दास टंडन से मिलकर **लोक सेवक मण्डल** की स्थापना की थी. वे समाचार-पत्रों को राष्ट्रीय भावना की जागृति के लिए मूल अस्त्र या साधन के रूप में स्वीकारते थे. उन्होंने स्वयं ने वन्दे मातरम्, उर्दू दैनिक एवं पीपुल (People) नामक अंग्रेजी समाचार-पत्र निकालना शुरू किया था. मैजिनी और गैरीबाल्डी पर लिखी उनके द्वारा उर्दू में जीवनियाँ राष्ट्रभक्ति को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण रहीं. उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण सन् 1925 ई. में कलकत्ता में उन्हें हिन्दू महासभा का अध्यक्ष चुना गया. साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 30 अक्टूबर, 1928 ई. को एक बड़ा भारी जुलूस उन्होंने निकाला. उसी दौरान पुलिस अधिकारी साण्डर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए. इसी के विरोध में शाम को एक विराट सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लाजपत राय ने कहा–"मेरे शरीर पर लगा हुआ लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील की तरह साबित होगा." इन घावों के कारण एक महान् देशभक्त, ओजस्वी वक्ता, उच्चकोटि के साहित्यकार की मृत्यु 17 नवम्बर, 1928 ई. को हो गई. उसी महान् माँ के सपूत की यादगार में 17 नवम्बर, 1959 में डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने पंजाब में लुधियाना के गाँव में उनका स्मारक स्थापित किया था.

विपिन चन्द्र पाल (1858-1932) और उनके राजनीतिक विचार–विपिन चन्द्र पाल का जन्म सन् 1858 ई. में असम के सिलहट जिले में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में शामिल है. वे अत्यन्त उच्चकोटि के उग्रवादी नेता थे और उनके विचार लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मिलते-जुलते हुए थे. विपिन चन्द्र पाल ने भारतीय राजनीति में प्रवेश एक उदारवादी नेता की तरह किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति में विशेषकर बंग-भंग की घटना ने उनके हृदय में तूफान खड़ा कर दिया और उग्रवादी विचारधारा के पोषक बन गये. लाल, बाल, पाल उन तीनों नेताओं के सहयोग से देश में अभूतपूर्व भावात्मक और व्यावहारिक एकता का वातावरण पैदा हुआ. विपिन चन्द्र पाल राष्ट्रवाद के नये पोषक थे. सन् 1908 ई. के बाद उनके राजनीतिक चिन्तन में पुनः परिवर्तन दिखायी दिया और वे अन्तर्राष्ट्रीयवाद की ओर झुक गये. सन् 1921 ई. में विभिन्न कारणों के फलस्वरूप उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और

राजनीति से पूरी तरह अलग हो गये. विपिन चन्द्र पाल ने समाज तथा राष्ट्र के सावयवी सिद्धान्त पर विश्वास प्रकट किया. वे राष्ट्र को कृत्रिम व्यक्तियों का ढेर नहीं, अपितु सावयव के रूप में स्वीकार करते थे, जिसका मूलाधार नैतिक और बौद्धिक बन्धन था. विपिन चन्द्र पाल संकुल आत्मा को राष्ट्रवाद की संज्ञा देते थे. राष्ट्र को वे भौतिक नहीं, अपितु आध्यात्मिक और नैतिक सावयव के रूप में स्वीकार करते थे. उन्होंने अपनी पुस्तक 'स्वदेशी और स्वराज्य' में राजनीति को शतरंज के खेल के रूप में स्वीकारा था. विपिनचन्द्र पाल ने अपने प्रमुख समाचार-पत्र 'वन्देमातरम्' के माध्यम से देशवासियों को स्वराज्य का सन्देश दिया. वे स्वराज्य को दैवीय अवतार या ईश्वर के वरदान के रूप में मानते थे. विपिनचन्द्र पाल ने स्वालम्बन, स्वनिर्णय और स्वाधिकारों को सर्वाधिक महत्त्व दिया तथा भिक्षावृत्ति को निन्दनीय माना था.

विपिनचन्द्र पाल ने दैवीय लोकतन्त्र (Divine Democracy) के आदर्श का प्रतिपादन किया और स्पष्ट किया कि ऐसा लोकतन्त्र यूरोप और पश्चिम के लोकतन्त्रों से कहीं उत्कृष्ट एवं महान् है. पाल ने स्वराज्य का अर्थ दैवी लोकतन्त्र से लेते हुए बताया कि भारत की स्वाधीनता देश के ऐतिहासिक आदर्शों के अनुरूप होनी चाहिए. विपिन चन्द्र पाल ने स्वराज्य और स्वतन्त्रता को पर्यायवाची नहीं माना. उन्होंने कहा कि स्वराज्य का अर्थ है स्वशासन और स्वतन्त्रता का आशय है पृथक् होना. विपिन चन्द्र पाल ने ब्रिटिश साम्राज्य में अन्तर्निहित विकास को पहले से ही महसूस कर राष्ट्रमण्डल की सम्भावना का संकेत देकर अपनी विलक्षण दूरदर्शिता का परिचय दिया. वे लम्बे अन्तराल तक जेल रहे. उन्होंने हमेशा पूर्ण स्वराज्य का समर्थन ही किया था. वे स्वराज्य या स्वशासन को ब्रिटिश सरकार के उपहार के रूप में नहीं, अपितु जनशक्ति, जनमत द्वारा प्राप्त करना चाहते थे. वे प्रान्तों, जिलों, गाँवों को भी स्वायत्तता देने के पक्ष में थे. उनमें अद्भुत वक्तव्य शक्ति थी, जिससे वे जन-जागृति एवं राष्ट्रवाद के उत्थान में उल्लेखनीय कार्य कर सके. इस राष्ट्रवादी महान् व्यक्तित्व को हमने सन् 1932 ई. में देखते-देखते इस जहाँ से अलविदा कह दिया.

सन् 1909 ई. का अधिनियम 'फूट डालो और शासन करो' की नीति–सन् 1857 ई. के विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर भारतीय प्रशासन का सीधा नियन्त्रण इंग्लैण्ड के मुकुट एवं संसद के नियन्त्रण में आ गया. सरकार ने अन्तःस्थिति को देखते हुए 'प्रतिक्रियावादी नीति' अपनाई. ब्रिटिश सरकार की वह नीति 'फूट डालो और शासन करो' (Divide and Rule) की नीति बन गई. अंग्रेजों ने भारत में साम्प्रदायिकता में वृद्धि कर भारत को विभाजित कर दिया. इसी के साथ ब्रिटिश सरकार ने उच्चतर शिक्षा में कटौती का प्रयास किया, रूढ़िवादी तत्वों को बढ़ाया. राजाओं, जमींदारों एवं भू-स्वामियों को अपना समर्थक बनाकर प्रेस पर नियन्त्रण लगा दिया. समय चलते विभिन्न अधिनियम पारित हुए. 1853 ई. के चार्टर एक्ट में कानून बनाने की व्यवस्था अत्यन्त दोषपूर्ण थी. विधान परिषद् एवं गवर्नर जनरल में आपसी तालमेल नहीं बैठ पाता था. कौंसिल के रवैये के फलस्वरूप निर्णय लेने में विलम्ब होता था. इसे दूर करने के लिए सन् 1861 ई. में भारतीय परिषद् अधिनियम पारित किया गया. इस अधिनियम की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित थीं–

(a) वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार कर दिया गया था. परिषद् में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई. इसका नाम 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' (Imperial legislative council) कर दिया गया. कानून के जानकार को इसका 5वाँ सदस्य बनाया गया था.

(b) वायसराय को सुविधानुसार नियम बनाने की अनुमति दे दी गई थी. प्रशासनिक विभाग विभिन्न सदस्यों को सौंप दिये गये थे, जिसके लिए वे वायसराय के प्रति उत्तरदायी होते थे. महत्त्वपूर्ण विभागीय समस्याओं के लिए वायसराय से परामर्श लिया जाता था.

(c) वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 रखने की व्यवस्था की गई थी. यह परिषद् कानून बनाती थी. अतिरिक्त सदस्यों में कम-से-कम आधे सदस्य गैर-सरकारी होते थे और ये सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत होता था. 'ऊँची श्रेणी' के भारतीयों को दो वर्ष के लिए सदस्य मनोनीत किया जाता था.

(d) विधायिका परिषद् (Legislative Council) द्वारा पास किए गए कानून को वायसराय द्वारा सहमति के बाद लागू किया जा सकता था. भारत सचिव को इन कानूनों को रद्द करने का अधिकार था.

(e) बम्बई और मद्रास के लिए कानून बनाने एवं संशोधन करने के लिए गवर्नरों को प्रान्तीय विधानसभाओं के गठन का अधिकार दिया गया था. गवर्नरों को कम-से-कम 4 और अधिक-से-अधिक 8 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला हुआ था. इनमें आधे सदस्य दो वर्ष के लिए गैर-सरकारी मनोनीत किये जाते थे.

(f) संकटकालीन परिस्थितियों में विधान परिषद् की अनुमति के बिना वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था. इनकी अवधि मात्र 6 महीनों की थी.

यह अधिनियम भारतीय जनमत का प्रतिनिधित्व न कर प्रतिक्रियावादी तत्वों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे. यह जनसाधारण की समस्याओं से असम्बन्धित अधिनियम था. भारतीयों के विरोध के कारण 1889 ई. में कांग्रेस के प्रस्ताव के आधार पर एक निजी विधेयक हाऊस ऑफ

कॉमन्स के सदस्य ब्रेडला ने 1890 ई. में पेश किया. भारत सचिव लॉर्ड क्रॉप के सुझाव पर लॉर्ड्स सभा में भी एक विधेयक पेश किया गया जो 1892 ई. में इण्डियन कौंसिल एक्ट के नाम से पारित हुआ. 1892 ई. के इस अधिनियम ने भारतीयों और कांग्रेस को क्षुधित कर दिया. इसके परिणामस्वरूप भारतीय और अधिक अधिकारों की माँग करने लगे. सरकार की दमनवादी नीतियों एवं बंग-भंग योजना से भारतीय उग्र हो गये. कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों–उदारवादी एवं उग्रवादी में विभाजित हो गयी. इसी समय आतंकवादी राष्ट्रीयता का उदय हुआ. इसके फलस्वरूप मुसलमान कांग्रेस से दूर होते चले गये. सन् 1906 ई. में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिससे साम्प्रदायिकता का उदय हुआ. तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिण्टो ने कांग्रेस के उदारवादी एवं मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाने के लिए 1892 ई. के अधिनियम में राजनैतिक एवं संवैधानिक सुधार की योजना भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले के साथ ब्रिटिश संसद के सामने रखी. सन् 1909 ई. में ब्रिटिश संसद ने इस योजना को पारित कर दिया, जिसे मिण्टो-मार्ले सुधार योजना के नाम से जाना गया. इस अधिनियम के द्वारा विधायिका का पुनर्गठन किया गया. इस विधायिका में केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानसभाओं में तीन प्रकार के सदस्य एवं तीन प्रकार की विचित्र निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई.

अधिनियम की धाराएँ–केन्द्रीय विधानसभा–मिण्टो-मार्ले सुधार अधिनियम–1909 ई. के तहत् वायसराय की व्यवस्थापिका सभा (Imperial Legislative Council) में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या वढ़ाकर 69 कर दी गई. इन सदस्यों में 32 गैर-सरकारी एवं 37 सरकारी सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था की गई. सरकारी सदस्यों में 28 वायसराय द्वारा मनोनीत एवं 9 पदेन सदस्य थे. गैर-सरकारी सदस्यों में 27 सदस्यों का निर्वाचन होता था तथा 5 का मनोनयन वायसराय द्वारा किया जाता था. निर्वाचित सदस्य विशेष वर्गों एवं हितों का प्रतिनिधित्व करते थे. 9 सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय विधानमण्डलों में गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा किया जाता था एवं शेष 18 सदस्यों को जमींदार एवं व्यापारिक संघ द्वारा चुना जाता था.

इण्डिया कौंसिल एवं भारतीय केन्द्रीय कौंसिल में भारतीयों का प्रवेश–मिण्टो-मार्ले सुधार अधिनियम, 1909 के द्वारा भारतीयों को इण्डिया कौंसिल एवं वायसराय की कौंसिल में प्रवेश पाने की अनुमति प्रदान की गई.

प्रान्तीय विधानसभाएँ–प्रान्तीय विधानसभाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई. मद्रास, बम्बई, बंगाल एवं संयुक्त प्रान्त की विधानसभाओं में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 50 तक कर दी गई, दूसरे प्रान्तों में यह सदस्य संख्या अधिकतम 30 रखी गई थी. प्रान्तीय विधानमण्डलों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत था, जो निर्वाचित, मनोनीत एवं गैर-सरकारी सदस्य होते थे. निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन जमींदार एवं व्यापारिक संघों, नगरपालिकाओं, जिलामण्डलों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता था.

साम्प्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था–इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी. मुसलमान सामान्य निर्वाचन एवं पृथक् रूप से मतदान करने के लिए स्वतन्त्र थे. केन्द्रीय विधानमण्डल में मुसलमानों के लिए पाँच स्थान सुरक्षित किये गये थे.

निर्वाचन प्रणाली–विधानमण्डल के निर्वाचनों में तीन प्रकार के निर्वाचन समूह की प्रणाली अपनाई गई थी. पहले समूह में साधारण मतदाता, दूसरे वर्ग में मुसलमान मतदाता एवं तीसरे समूह में व्यापारिक संघ, विश्वविद्यालय, जमींदार आदि का विशिष्ट वर्ग होता था.

विभिन्न मताधिकार–सभी को मत देने का समान अधिकार नहीं था. मत देने के लिए अमीर वर्ग को विशिष्ट योग्य माना जाता था. मुसलमानों को मत देने के अधिकार की योग्यता में सरलता थी, जबकि गैर-मुस्लिमों के लिए यह जटिल प्रक्रिया थी.

विधानसभा के कार्यों में वृद्धि–सन् 1909 के अधिनियम के द्वारा विधानसभाओं के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया. सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, सुझाव देने एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार दिये गये. बजट पर बहस करने के लिए विस्तृत नियम बनाये गये.

मुस्लिम लीग एवं लखनऊ समझौता

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में उदारवाद, उग्रवाद और आतंकवाद का विशेषरूप से प्रथम महायुद्ध के आस-पास तक रहा. गांधी युग में यह प्रवृत्तियाँ विशिष्ट और प्राथमिक रूप से प्रभावी नहीं रहीं, लेकिन साम्प्रदायिकता की लहर सम्पूर्ण राष्ट्रीय आन्दोलन पर छाई रही. इस विष लहर ने अन्त में देश का विभाजन किया और भारत माँ की छाती में ऐसा गहरा घाव किया जिसका इलाज सदियों तक सम्भव नहीं है. भारत में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं रखी. सर्वप्रथम मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदय हुआ और तब प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दू साम्प्रदायिकता संगठन भी अस्तित्व में आए. मुस्लिम साम्प्रदायिकता को तीव्र रूप में उभारने और अखण्ड भारत के दो टुकड़े करके 1947 में पाकिस्तान का निर्माण करने में मुस्लिम लीग का निर्णायक हाथ रहा, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी.[1]

1. Mehta, Pardhan : The Communist Triangle. P. 68–69

मुस्लिम लीग की स्थापना से पूर्व मुस्लिम साम्प्रदायिकता

प्रारम्भ से ही भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या का मूल कारण धार्मिक कारण नहीं, अपितु राजनीतिक कारण रहा है और देश को आधुनिक राजनीति की इस विष-वेल को हम यदि ब्रिटिश शासन की सन्तान कहें, तो कोई अतिश्योक्ति न होगी. भारत की राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी परम्परागत नीति 'फूट डालो और राज्य करो' का आश्रय लिया. हिन्दुओं और मुसलमानों के धार्मिक-सामाजिक मतभेदों का पूरा लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई, क्योंकि अंग्रेजों की प्रभुता के पूर्व मुसलमान ही इस देश के भाग्य-विधाता थे. 1857 के विद्रोह के बारे में अंग्रेजों का विश्वास था कि इस क्रान्ति में प्रमुख हाथ मुसलमानों का ही था. इससे पूर्व वहावी आन्दोलन के बारे में भी अंग्रेजों का इसी प्रकार विचार रहा था. सर जॉन रे के अनुसार विद्रोह के प्रमुख षड्यन्त्रकारी मुसलमान थे और एच. सी. ब्राउन की दृष्टि में ये मुसलमान निश्चित रूप से वहावी थे.

लगभग 1871 ई. तक ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के साथ विरोध और हिन्दुओं के साथ पक्षपात की नीति पर आचरण किया. शासन, वाणिज्य और उद्योगों में मुसलमानों का भाग या तो बहुत कम अथवा बिलकुल नहीं था, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश नीति में एक निश्चित परिवर्तन आया. हिन्दुओं ने अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति से पूरा लाभ उठाया और उनके हृदय में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के विचार घर करने लगे. अतः अंग्रेजों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, क्योंकि उन्हें डर लगा कि कहीं मुस्लिम पर भी राष्ट्रीयता का रंग न चढ़ जाए. हिन्दू-मुस्लिम गठबन्धन ब्रिटिश हितों के लिए घातक हो सकता था. ब्रिटिश सरकार की इस इच्छा पूर्ति में सर्वाधिक सहयोग सर सैयद अहमद खाँ से मिला. अंग्रेज यह भाँप गये कि मुसलमानों की ओर से ब्रिटिश साम्राज्य को कोई खतरा नहीं रह गया है, किन्तु हिन्दुओं में जो जागरण फैल रहा है और नया राष्ट्रवाद पनप रहा है उसकी रीढ़ तोड़ना आवश्यक है. इस अनुभूति का यह परिणाम था कि अंग्रेजों ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित कर हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट डालना प्रारम्भ कर दिया. उन्होंने मुसलमानों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना शुरू किया और स्वाभाविक था कि दूसरे पक्ष की ओर से इसका सकारात्मक उत्तर मिलता.

सर सैयद के विशेष प्रयत्नों से मुसलमानों ने ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी दिखलानी शुरू की मुस्लिम राजनीति में सर सैयद ने पदार्पण करके 'दो राष्ट्र सिद्धान्त' (Two Nation Theory) का प्रतिपादन किया.[1] 1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना के बाद तो अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतिभार के रूप में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का सुविचारित ढंग से संगठन प्रारम्भ कर दिया. अंग्रेजों की प्रेरणा से 1873 ई. में मुस्लिम एंग्लो-ओरिएन्टल रक्षा परिषद् की स्थापना की गयी. 1905 ई. में बंगाल विभाजन किया गया. बंगाल विभाजन के मूल में भी हिन्दू और मुसलमानों के बीच विभाजन की खाई खोदकर राष्ट्रीयता की उमड़ती धारा को अवरुद्ध करने की नीति सक्रिय थी. 1906 ई. के अन्त में वायसराय के निजी सचिव डनलप स्मिथ तथा थियोडोर बेक के उत्तराधिकारी आर्चिबोल्ड की प्रेरणा से मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल आगा खाँ के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिन्टो से मिला और उसने मुसलमानों के लिए कुछ विशेष रियायतों तथा साम्प्रदायिक चुनावों की माँग की. वायसराय ने सहानुभूति दिखाई और सिद्धान्त रूप में शिष्टमण्डल की माँगों के साथ सहमति प्रकट की. मुस्लिम शिष्टमण्डल का लॉर्ड मिन्टो से यह मिलन मौलाना मोहम्मद अली के शब्दों में 'सिखाया-पढ़ाया तमाशा' था. मिन्टो ने मुसलमानों को साम्प्रदायिकता की दिशा में प्रोत्साहित करते हुए कहा– "तुम्हारी यह बात ठीक है कि मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएँ, क्योंकि अल्पसंख्यक होने के कारण तुम्हारी जाति के उम्मीदवारों को बहुमत वाली हिन्दू जाति के सामने जीतने की कोई आशा नहीं है. तुम यह ठीक कहते हो कि तुम्हारी जाति का महत्व संख्या के आधार पर न लगाया जाए और राजनीतिक महत्व और ब्रिटिश साम्राज्य की सेवाओं के आधार पर लगाया जाए." दिसम्बर 1906 ई. में मुस्लिम हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई.

मुस्लिम साम्प्रदायिकता के जन्म के कारण

मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उदय और मुस्लिम लीग के जन्म के मूल में अनेक कारण थे. अंग्रेज प्रशासकों और गैर-सरकारी अंग्रेज व्यक्तियों ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करने में सहयोग दिया. इसमें सर सैयद अहमद, बेक और लॉर्ड मिन्टो की गतिविधियाँ विशेष महत्वपूर्ण रहीं. मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उदय के कारण निम्नलिखित थे–

1. **मुसलमानों की अधोगति और उनमें असन्तोष की भावना**–भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना से मुसलमानों की स्थिति पर गहरा कुठाराघात हुआ. देश से उनका राजनीतिक प्रभुत्व सदा के लिए समाप्त हो गया–कल के शासक अब दास हो गए. राजनीतिक क्षेत्र में तो उनका पराभव हुआ ही, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी स्थिति दयनीय होती गयी. सरकारी नौकरियों और दस्तकारी के पतन ने उनकी आर्थिक हालत को बिगाड़ दिया. अंग्रेजी शिक्षा के प्रति प्रारम्भ में अरुचि रही. अतः सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के

---

1. Subhash Kashyap : op. cit. P. 62.

क्षेत्र में वे हिन्दुओं से पिछड़े रहे. दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विकास से मुस्लिम सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति को भी आघात पहुँचने लगा. राजनीतिक चेतना भी जाती रही. इस प्रकार, जैसा कि सर विलियम हंटर का मत है कि एक अमीर गर्वपूर्ण और वीर जाति को निर्धन एवं निरक्षर जनसमूह में बदल दिया गया तथा उसके उत्साह को मिट्टी में मिला दिया गया. अपनी गिरती हुई स्थिति का अहसास करके मुसलमानों में असन्तोष की भावना घर करने लगी जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप उसमें राजनीतिक जागरूकता और हिन्दुओं के प्रति द्वेष का विकास हुआ और अन्त में उनकी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को सम्बल मिला.

2. **वहावी आन्दोलन**–मुसलमानों के इस आन्दोलन में उनके असन्तोष की अभिव्यक्ति पाई जाती है. हिन्दू समाज से ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि के रूप में जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आन्दोलन शुरू हुए उनसे हिन्दुओं में राजनीतिक और सामाजिक सुधार आन्दोलन शुरू हुए. उनसे हिन्दुओं में राजनीतिक और सामाजिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ. हिन्दुओं के इस नवजागरण का प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा, उनमें वहावी आन्दोलन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य इस्लाम की कमजोरियों को देखकर उसमें स्फूर्ति और जागृति पैदा करना था.

18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अरव के पुनरुत्थानवादियों ने वहावी आन्दोलन आरम्भ किया, जिससे प्रभावित होकर सैयद अहमद ब्रेल्वी ने इस्लाम धर्म को पुनः अपनी मौलिक पवित्रता प्रदान करने के लिए इस आन्दोलन का भारत में भी सूत्रपात किया. शुरू में वहावीवाद ने सिखों तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का रूप लिया. ब्रिटिश सरकार ने इस आन्दोलन को कुचल दिया तथापि इसने मुसलमानों में जिस धार्मिक एवं साम्प्रदायिक चेतना को जगाया वह नहीं दव सकी.

3. **अलीगढ़ आन्दोलन तथा अहमदिया आन्दोलन**–इन दो मुस्लिम सुधार आन्दोलनों ने भी मुस्लिम धार्मिक कट्टरता और साम्प्रदायिकता को उभारा. सर सैयद के अलीगढ़ आन्दोलन ने तो इसमें विशेष योगदान दिया. सर सैयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना करके मुस्लिम विश्व-विद्यालय की नींव डाली. सर सैयद अहमद खाँ की उदार विचारधारा 1885 ई. से निश्चित रूप से पीछे हटने लगी और उनमें यह विश्वास पनपता गया कि "भारत के लिए स्वराज्य की कल्पना विलकुल अव्यावहारिक और हानिकारक है तथा मुसलमानों की सुरक्षा और दृढ़ता (अलीगढ़ आन्दोलन के वुनियादी विचार) मुसलमानों और अंग्रेजों के मेल से ही होगी." वास्तव में भारत में भी मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों का रुख बदल चुका था और उनकी नीति मुस्लिम समाज को अपनी ओर मिलाने की थी. डब्ल्यू. एस. ब्लण्ट ने मुसलमानों से अपना 'हक' माँगने की अपील की और कहा–"यदि मुसलमान केवल अपनी शक्ति पहचान लें, तो उनकी अवहेलना नहीं होगी तथा सरकार उनसे बुरा व्यवहार नहीं करेगी." इंग्लैण्ड से हमें बरावर विद्रोह का भय बना रहता है और यदि मुसलमान एक शब्द भी कह देता है, तो उस पर हिन्दुओं से ज्यादा ध्यान दिया जाता है. अतः यदि मुसलमान चुप बैठे रहे और तकदीर कोसते रहे, तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश जनता को उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं होगी. अहमदिया आन्दोलन मिर्जा गुलाम अहमद कादिनी के नेतृत्व में शुरू हुआ. इस आन्दोलन ने सभी धर्मों में सुधार को लेकर अपना लक्ष्य बनाया. 1885 ई. में अन्जुमन-ए-हिमायत-इस्लाम की स्थापना हुई जिसने मुसलमानों की सामाजिक नैतिकता में वृद्धि करने की और बौद्धिक उन्नति करने की चेष्टा की.

इन विभिन्न आन्दोलनों के फलस्वरूप भारतीय मुसलमानों में राजनीतिक जागृति फैली, उनकी शिक्षा में सुधार हुआ उनके दृष्टिकोण में कुछ व्यापकता आई, लेकिन इन आन्दोलनों ने साम्प्रदायिकता की भावना को आगे बढ़ाया, कम नहीं किया. जहाँ हिन्दुओं ने अपने में आत्मविश्वास की पुनः प्राप्ति के लिए अपने धार्मिक और ऐतिहासिक भूतकाल पर दृष्टि डाली, वहाँ मुसलमानों ने प्रारम्भिक इस्लाम और अरव के अतीतकालीन इतिहास का सहारा लिया. फलस्वरूप इससे न केवल भारतीयों और पश्चिमियों के बीच संघर्ष विन्दु उत्पन्न हुए (क्योंकि भारतीय पाश्चात्य सांस्कृतिक और धार्मिक आक्रमण का मुकाबला करना चाहते थे, बल्कि हिन्दुओं और मुसलमानों में भी परस्पर फूट फैली, क्योंकि उनमें से प्रत्येक अपने पृथक् आध्यात्मिक स्रोतों और अपनी पृथक् बौद्धिक शक्ति पर विश्वास करता था.

4. **हिन्दू धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव**–19वीं शताब्दी के हिन्दू धार्मिक आन्दोलनों का एक प्रभाव यह पड़ा कि मुसलमानों में संगठित होने की भावना को वल मिला. हिन्दू नव-जागरण की प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमानों में भी धार्मिक जागृति की भावना को बल मिला. सुधार आन्दोलनों के अतिरिक्त तिलक के शिवाजी समारोह और गणपति महोत्सव को कट्टरपंथी मुसलमानों ने विपरीत अर्थों में लिया और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को कट्टर हिन्दू धार्मिकता के साथ सम्बद्ध कर दिया. हिन्दू धर्म सुधार आन्दोलनों, उत्सवों और कार्यक्रमों से मुसलमानों में शंका के भावों का सम्बल मिला और उनकी साम्प्रदायिकता में उभार आया. विभिन्न धार्मिक आन्दोलनों ने साम्प्रदायिकता को किस प्रकार बढ़ावा दिया. इस पर इतिहासकार डॉ. ताराचन्द के विचार उल्लेखनीय हैं–

"19वीं सदी में जो पुनर्जीवनवादी आन्दोलना फैले, उनसे परस्पर सन्देह और भय और तीखे हो गये. दिल्ली के शाह, वलीउल्ला तथा देव बन्द में उनके शिष्यों द्वारा स्थापित विद्यालय और सैयद अहमद खाँ के आन्दोलनों ने मुस्लिम

समाज में धार्मिक जोश जगाने की कोशिश की. ये सुधारक मुसलमानों में फैले हुए उन रीति-रिवाजों को हटाना चाहते थे, जो भारतीयों के साथ रहने के कारण उनमें चले गये थे. हिन्दुओं में कलकत्ता के राधाकृष्णन देव की धर्म सभा, जो 19वीं सदी में हिन्दू धर्म को सुधारकों और ईसाई मिशनरियों से बचाने के लिए स्थापित हुई थी, सक्रिय थी. बंकिमचन्द्र चटर्जी जैसी साहित्यिक प्रतिभाओं ने अपनी लेखनी का प्रयोग इसे जनप्रिय बनाने के लिए किया. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 1875 ई. में बम्बई में आर्य समाज की नींव डाली, पर इसका प्रभाव उत्तर भारत में भी फैला. उन्होंने हिन्दुओं को वेदों की ओर वापस जाने को कहा और हिन्दुओं को फिर से हिन्दू बनाने का प्रयास किया जिन्होंने धर्म छोड़ दिया था. पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप जिस धार्मिक उदासीनता का विस्तार हुआ था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों और अनुष्ठानों का प्रचार करने के लिए बहुत सक्रियता दिखाई पड़ी. यह आन्दोलन केवल उच्चतर वर्गों तक ही सीमित नहीं था. यह बहुत-सी ऐसी जातियों पर भी असर डाल रहा था, जो अब तक छोटी समझी जाती थीं. जैसे-जैसे उन कथित छोटी जातियों ने हिन्दू समाज में ऊपर उठने की कोशिश की त्यों-त्यों वे हिन्दू धर्म के अनुष्ठानों में और भी कट्टर होते गये. हिन्दू पुनरूज्जीवनवाद ने उनमें प्राचीन परम्पराओं के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न कर दी.

इस प्रकार से दोनों सम्प्रदायों में समानान्तर आन्दोलन चले जिनके उद्देश्य एक से थे और उपाय भी वे ही थे. दुर्भाग्य से इस सम्बन्ध में उनमें कोई सहयोग नहीं हुआ कि उनके अन्दर की उदारता तथा सहिष्णुता को बल पहुँचाया जाए. इसके विपरीत वे एक-दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे. ये आन्दोलन प्रतिवाद पर ही जोर देते थे और आक्रामक थे. दोनों आन्दोलनों में यह भावना थी कि हम सही हैं और इस प्रकार दूसरों से श्रेष्ठता की ओर "मैं तुम से अधिक पवित्र हूँ" यह भावना जोर पकड़ती गई. ये दो सम्प्रदाय संकीर्ण स्वार्थ का जो रुख ग्रहण कर रहे थे वह अब सरकार के भेदभाव और पक्षपात से और बढ़ गया. स्वार्थ का संघर्ष बढ़ता चला गया. इसलिए आश्चर्य नहीं कि धार्मिक पुनरूज्जीवन के कारण साम्प्रदायिक भावनाएँ बढ़ीं, विशेषकर इसलिए कि देश की आर्थिक स्थिति में बेरोजगारी की भयंकर समस्या के समाधान के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी. इस स्थिति में हर दृष्टि और संयम की आवश्यकता थी. इन दोनों सम्प्रदायों के स्थायी स्वार्थ एक ही थे और उनके तात्कालिक अभाव उनकी सामान्य पराधीनता से उत्पन्न हुए थे. पर हर वर्ग अपनी उन्नति करने के चक्कर में ऐसी नीतियों का अनुसरण करता रहा, जिससे उनके बीच की खाई और चौड़ी हो गई. परस्पर दोषारोपण और गाली-गलीज के कारण, वे तीसरे पक्ष के हाथ में पड़ गये. जिसने इन घटनाओं का दोहरा लाभ उठाया. भारत पर अंग्रेजों की पकड़ और भी मजबूत हो गई और ब्रिटिश शासन को वह समर्थन मिला जिसकी उसे बहुत आवश्यकता थी. विभिन्न कारणों से 1885 ई. से पहले ही साम्प्रदायिक सन्देह और अनैक्य पैदा हो गया. इस समय मुसलमानों में बहुत उग्र पृथक्तावादी थे, जो यह कहते थे कि हिन्दुओं से बिलकुल अलग हो जाया जाए और अंग्रेज शासकों के साथ अधिक-से-अधिक दोस्ती की जाए. इन लोगों में शायद अमीर अली सबसे प्रमुख थे, जिन्होंने 1877 ई. में नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि मुसलमान नौजवानों को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाए. इंग्लैण्ड में पढ़ते समय ही वह इस विषय में दिलचस्पी रखते थे. उन्होंने तब यह कहा था कि यदि भारतीय मुसलमानों का राजनैतिक प्रशिक्षण हिन्दुओं के साथ समानान्तर रेखा में नहीं चलेगा, तो वे निश्चित रूप से नई राष्ट्रीयता के उठते हुए ज्वार में डूब जाएंगे. सैयद अहमद खाँ ने उस समय सैयद अमीर अली के इस कार्य का समर्थन करने से इनकार कर दिया था. पर जब 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरम्भ हुआ, तो सैयद अमीर खाँ के मन में सोए हुए सन्देह और भय सतह पर आ गये.

5. ब्रिटिश नीति में परिवर्तन : सर सैयद अहमद और बेक की भूमिका–ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक चरणों में अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई. उनका विचार था कि मुस्लिम अंग्रेजी राज के शत्रु थे और हिन्दू मित्र, लेकिन हिन्दू राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही विदेशी शासकों की नीति में परिवर्तन आया. मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खाँ और प्रिन्सीपल बेक ने अंग्रेजों और मुसलमानों के मेल की दिशा में विशेष प्रयास किया.

सर सैयद अहमद खाँ को विश्वास हो गया कि जब तक अंग्रेजों से मुसलमानों का गठबन्धन नहीं होगा तब तक मुसलमानों की दशा में सुधार नहीं हो सकता. अतः उन्होंने प्रयत्न किया कि मुसलमानों से राजद्रोह के कलंक को मिटा दिया जाए. 1857 ई. के विद्रोह से अंग्रेज बहुत नाराज थे और मुसलमानों पर इस प्रकार टूट पड़े थे मानो वे उनके असली शत्रु और भयंकर प्रतिद्वन्द्वी हों. विद्रोह की विफलता हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों के लिए ज्यादा विपत्तिजनक थी. सर सैयद अहमद खाँ ने 'भारत के वफादार मुसलमान' (Loyal Mohammadans of India) नामक पत्र का प्रकाशन कर अपने विचारों का प्रचार किया. 'पायोनियर' नामक समाचार-पत्र में उन्होंने ऐसे लेख प्रकाशित किए जिनसे

अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच सद्‌भावना उत्पन्न हुई. सर सैयद के विचारों और कार्यों के फलस्वरूप मुसलमानों की राजभक्ति पर सन्देह के बादल कुछ समय में दूर हो गये.[1]

1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना के कुछ ही अर्से बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वह एक सम्भावित खतरा महसूस होने लगा. प्रति तोलन (Counter Poise) के सिद्धान्त पर आचरण करते हुए, उत्साही पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति भार (Counter Weight) के रूप में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का संगठन करना प्रारम्भ कर दिया. फूट डालो और राज करो के इस खेल में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें सर सैयद अहमद खाँ के से प्रभाव और प्रतिष्ठा वाले मनुष्य के सहयोग को प्राप्त करने में अपूर्व सफलता प्राप्त हुई. अंग्रेजों ने भी, जैसा कि बम्बवाल ने लिखा है कि सर सैयद ने अपने मुसलमानों की दशा को उन्नत करने में सहायक होगा और राष्ट्रवादियों से मिलना उन्हें पुनः खेद, श्रम और अश्रु में डुबो देगा. सर सैयद ने अपने मुसलमान साथियों को चेतावनी दी कि कांग्रेस ने भारतवर्ष में ब्रिटिश पद्धति के प्रतिनिध्यात्मक शासन का अभिप्राय है "हिन्दुओं का शासन". सर सैयद अहमद खाँ का तर्क था कि चूँकि देश के अधिकतर भाग में हिन्दुओं का ही बहुमत है, अतः वे ही सदैव सत्तारूढ़ रहेंगे और मुसलमानों को उनकी अधीनता सहनी पड़ेगी.

साम्प्रदायिक वातावरण के निर्माण में प्रिंसीपल बेक की विशेष भूमिका रही. बेक अलीगढ़ कॉलेज का यूरोपीय प्रिंसीपल था. सर सैयद के साम्प्रदायिक विचारों के पीछे थ्योडोर बेक ने एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य किया. बेक ने विशेषरूप से प्रयास किया कि सर सैयद राष्ट्रवाद से अलग रहें और अंग्रेजों तथा मुसलमानों में निकटतम सम्पर्क स्थापित हो. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है. बेक ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को उकसाने और भारत की दो महान् जातियों में फूट डालने के लिए यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान हिन्दुओं के बहुमत के अधीन हो जाएँ. इस स्थिति को मुसलमान कभी चुपचाप नहीं करेंगे. प्रिंसीपल बेक के प्रभाव से सर सैयद अहमद का प्रतिक्रिया-वादी-सम्प्रदायवादी स्वरूप अधिक उभर आया. मुख्यतः बेक के प्रभाव से ही वे राष्ट्रीय आन्दोलन से विमुख हो गये और कांग्रेस से असहयोग करते हुए उन्होंने कांग्रेस के विरोध में एक प्रतिक्रियावादी संगठन की भी स्थापना की. उनके प्रभाव के अन्तर्गत 'सेन्ट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसियेशन' तथा 'मोहम्मडन लिटरेरी सोसायटी' ने भी कांग्रेस से सहयोग किया. सन् 1886 में सर सैयद ने 'मोहम्मडन एजूकेशन कांग्रेस' की स्थापना की. जिसका उद्देश्य शिक्षित मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने से रोकना था. 1885 ई. में उन्होंने "मोहम्मडन डिफेन्स एसोसिएशन ऑफ अपर इण्डिया" की स्थापना की, जिसके सचिव वे स्वयं और बेक थे. इस संगठन का उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस का विरोध और अंग्रेजों से सहयोग करने की दिशा में प्रेरित करना था. इस संगठन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे–

(i) अंग्रेजों और सरकार को मुस्लिम विचारधारा से परिचित करना तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना.

(ii) ऐसे उपायों पर बल देना जिनसे भारत में ब्रिटिश शासन सुदृढ़ बने.

(iii) जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति की भावना का प्रसार करना.

6. **फूट डालो और शासन करो की नीति**–अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन की नीति द्वारा मुस्लिम साम्प्रदायिकता को हर तरफ से बढ़ावा दिया. इसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीयवाद के उमड़ते हुए ज्वार को रोकना था. अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने यह महसूस किया कि हिन्दू और मुसलमान–भारत की इन दो महान् जातियों में फूट डालकर ही नवजाग्रत राष्ट्रवाद का मार्ग अवरुद्ध किया जा सकता है और अन्दर से विभाजित भारतीय उपनिवेश पर इच्छानुकूल शासन किया जा सकता है. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल में मुम्बई के गवर्नर एलफिन्सटन ने कहा था–'फूट डालो शासन करो' पुराना रोमन मंत्र और यही हमारा भी होना चाहिए. अशोक मेहता एवं अच्युत पटवर्द्धन ने लिखा कि अपने विख्यात कौशल से, जिसने हाल तक उनकी कूटनीति के विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली बना दिया था, ब्रिटिश शासकों ने अपने के हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच रखा तथा एक साम्प्रदायिक त्रिकोण के निर्माण का निश्चय किया जिसका वे आधार बने. 'फूट डालो और शासन करो' की नीति पर चलते हुए अंग्रेजों ने उससे पहले मुसलमानों को सेना के उच्च पदों से वंचित करके उनका स्थान हिन्दुओं को दे दिया. सरकारी सेवाओं में भी यही किया गया. कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मुस्लिम विरोधी और हिन्दू पक्षी नीति अपनाई गई, लेकिन 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में ब्रिटिश शासकों के रुख में परिवर्तन आने लगा और यह नीति मुस्लिम पक्षी तथा हिन्दू विरोधी हो गई. अब अंग्रेज मुसलमानों से साँठ-गाँठ बढ़ाने लगे और उन्हें साम्प्रदायिक आधार पर विशेष राजनीतिक अधिकार देने की बात करने लगे. विधान सभाओं को पृथक् प्रतिनिधित्व देकर मुस्लिम साम्प्रदायिकता की जड़ विधिवत् मजबूत बनाई गई.

1. डॉ. ताराचन्द : भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ 327-328

7. **पृथक् शिक्षण संस्थाओं की स्थापना**–भारत में जन जागरण के फलस्वरूप विभिन्न सम्प्रदायों और जातियों के लोग अपनी पृथक् शिक्षण संस्थाएँ खोलने लगे. कुल शिक्षण संस्थाओं की प्रकृति ऐसी थी जिससे साम्प्रदायिक भावना को प्रोत्साहन मिला. मुसलमानों ने देव वन्द में दारूल-उलूम खोला, आर्य-समाजियों ने गुरूकुल स्थापित किये सनातनियों ने ऋषि कुलों की नींव डाली. धार्मिक आधार पर ही अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय का सूत्रपात हुआ. इन संस्थाओं ने विभिन्न सम्प्रदायों को निकट लाने की अपेक्षा एक-दूसरे से पृथक् अथवा दूर करने में सहयोग दिया.

8. **बंगाल का विभाजन**–लॉर्ड कर्जन की कुटिल नीति ने हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव को बढ़ाया. मुस्लिम साम्प्रदायिकता को तेजी से उभारने के लिए कर्जन ने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई. उसने पूर्वी बंगाल का दौरा किया और मुसलमानों में यह प्रचार किया कि बंगाल के विभाजन की योजना को मुस्लिम समाज के काम के लिए लागू किया गया है. कर्जन को अपनी कूटनीति में काफी सफलता मिली और मुसलमानों को विश्वास हो चला कि ब्रिटिश सरकार का रुख सही है और मुसलमानों को विश्वास तथा हिन्दुओं के हित में कोई मेल नहीं है. डॉ. के. बम्बवाल ने लिखा है 'बंगाल का विभाजन' देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के सहबल (Counter Poise of Natives against Natives) के कार्यक्रम में एक कदम था. इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि कर्जन ने शासन-सम्बन्धी सुविधाओं के आधार पर बंगाल विभाजन का औचित्य सिद्ध करने की चेष्टा की, परन्तु सत्य तो यह है कि बंगाल-विभाजन के मूल में हिन्दुओं और मुसलमानों के विभाजन की खाई खोदकर राष्ट्रीयता की प्रवाहमान धारा को अवरुद्ध करने की नीति काम कर रही थी.[1] इन विभिन्न कारणों से मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उदय और विकास को बल मिला. गैर-सरकारी हस्तियों में सर सैयद अहमद, अमीर अली, प्रिंसीपल बेक आदि की प्रमुख भूमिका रही और सरकारी हस्तियों में लॉर्ड मिण्टो का योग उल्लेखनीय रहा.

मुस्लिम लीग : स्थापना और विकास (1906–1916)

दिसम्बर 1906 में मुस्लिम हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई. मुस्लिम सामन्ती तत्वों द्वारा संचालित यह एक छोटी उच्चवर्गीय संस्था थी, किन्तु अंग्रेजों ने प्रारम्भ से ही प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि मुसलमानों की नई पीढ़ी को कांग्रेस से अलग रखा जाए, ताकि मुस्लिम हितों के नाम पर कांग्रेस की शक्ति पर अंकुश रखा जा सके.

मुस्लिम शिष्टमण्डल, 1906 और पृथक् प्रतिनिधित्व की माँग : लॉर्ड मिन्टो की भूमिका

1 अक्टूबर, 1906 ई. को छिपे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के संकेतानुसार मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल लॉर्ड मिण्टो से मिला, जिसके नेता सर आगा खाँ थे. मुस्लिम शिष्टमण्डल ने भारत के वायसराय के समक्ष एक स्मृति-पत्र पेश करके निम्नलिखित माँगें पेश की गईं–

(1) मुसलमानों के लिए पृथक् चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था हो.

(2) सुधार के बाद बने हुए विधानमण्डलों में मुसलमानों को उनकी आबादी से अधिक स्थान दिया जाये.

(3) सरकारी नौकरियाँ मुसलमानों को अधिक दी जाएं.

(4) सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना में सरकारी सहायता दी जाए.

(5) यदि गवर्नर जनरल की कौंसिल में किसी भारतीय को नियुक्त किया जाए, तो मुसलमानों के हितों का ध्यान रखा जाए.

मुस्लिम शिष्टमण्डल ने वायसराय को यह विश्वास दिलाया कि सरकार मुसलमानों के हितों की वृद्धि करके, उनकी राजभक्ति को और अधिक दृढ़ बना सकेगी. इस शिष्टमण्डल का वायसराय की सेवा में उपस्थित होने का अभिप्राय था कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भेद की खाई निरन्तर चौड़ी होती जा रही है, परन्तु इसके लिए भी भारत ब्रिटिश नौकरशाहों और उन पृथकृतावादी तत्वों के निकट ही ऋणी हैं जोकि उनके हाथों में खिलौने बनकर खेले. 1923 ई. में मौलाना मोहम्मद अली ने ठीक ही कहा था कि यह शिष्टमण्डल सरकारी आदेशानुसार निर्मित हुआ था. इस सारी कार्यवाही का प्रबन्ध आर्चिबोल्ड ने, जोकि बेक के सुयोग्य उत्तराधिकारी थे और जिनके कन्धों पर मि. बेक के अधूरे कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व आ पड़ा था, किया था. आर्चिबोल्ड और वायसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी कर्नल डनलप स्मिथ ने आपस में सारी लिखा-पढ़ी कर रखी थी. शिष्टमणडल के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रबन्ध की जो बातें थीं, उन सबको इन व्यक्तियों ने आपस में अच्छी तरह से तय कर रखा था–उन दोनों ने यह निश्चित कर लिया था कि शिष्टमण्डल को वायसराय से क्या कहना है यह मान लेना स्वाभाविक है कि वायसराय भी इन सारी कार्यवाहियों से

1. Mehta & Patvardhan : TheCommunist Triangle Page 958.

अनभिज्ञ नहीं थे. 10 अगस्त, 1906 ई. के अपने पत्र में आर्चिबोल्ड ने नवाब मोहिशिनुल्मुल्क को सारी हिदायतें दे दी थीं. इस पत्र को डॉ. बम्बवाल ने इस प्रकार उद्धृत किया है– अपने पत्र में आर्चिबोल्ड ने लिखा–"हिज एक्सीलेन्सी दि वायसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी कर्नल डनलप स्मिथ ने मुझे लिखा है कि हिज एक्सीलेन्सी मुस्लिम शिष्टमण्डल से भेंट करने के लिए प्रस्तुत हैं. उनकी राय है कि श्रीमान् को एक औपचारिक पत्र लिख देना चाहिए जिसमें कि उनसे सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा माँगी जाए. इस विषय में मैं कतिपय सुझाव उपस्थित करना चाहूँगा. औपचारिक पत्र को मुसलमानों के कतिपय प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर सहित भेजा जाना चाहिए. शिष्टमण्डल में सभी प्रान्त के प्रतिनिधि होने चाहिए यह तीसरी विचारणीय बात प्रतिवेदन का विषय है. मैं यहाँ यह सुझाव देना चाहूँगा कि प्रतिवेदन के प्रारम्भ में राजभक्ति का गम्भीर समाश्वासन होना वांछनीय है. स्वशासन की दिशा में एक कदम बढ़ाने के सरकारी निर्णय की प्रशंसा होनी चाहिए, परन्तु अपनी इस आशंका को व्यक्त कर देना चाहिए कि यदि निर्वाचन के सिद्धान्त का सूत्रपात कर दिया जाता है, तो वह अल्पमतों के हितों में बाधक ही सिद्ध होगा. अत्यन्त विनयपूर्वक यह सुझाव होना चाहिए कि मुस्लिम लोकमत को जानने के लिए धर्म के आधार पर मनोनयन (Nomination) या प्रतिनिधित्व का सूत्रपात होना वांछनीय है. हमें यह भी कह देना चाहिए कि भारत जैसे देश के लिए जमींदारों के मतों को भी वजन देना आवश्यक है, परन्तु इन सब दृष्टिकोणों में, मैं पृष्ठभूमि में ही रहूँ, इस बात का आप सदैव ध्यान रखें. ये आपकी ओर से आवश्यक है. मैं आपके लिए प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार कर सकता हूँ या उसका संशोधन कर सकता हूँ. यह तो आप जानते ही हैं कि इन चीजों को ठीक-ठाक भाषा में कलमबद्ध कर देने का मुझे ज्ञान है. हमारे पास समय थोड़ा है. यदि इस थोड़े समय में हम एक शक्तिशाली आन्दोलन का संगठन करना चाहते हैं, तो हमें अविलम्ब कार्य करना चाहिए."

लॉर्ड मिण्टो ने मुस्लिम शिष्टमण्डल के साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँगों को संघर्ष स्वीकार किया. इस प्रकार भारतीय इतिहास में पहली बार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को सरकारी स्तर पर स्वीकार कर साम्प्रदायिकता को खुला प्रोत्साहन दिया गया. लॉर्ड मिण्टो ने मुस्लिम शिष्टमण्डल को बलपूर्वक इस बात का आश्वासन दिया कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की अवश्यमेव रक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा, "आपका यह दावा न्याय युक्त है कि आपकी स्थित का मूल्यांकन आपकी संख्या शक्ति के आधार पर जो उसने साम्राज्य के प्रति की है, होना चाहिए. मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ." लॉर्ड मिण्टो ने यह भी कहा, "मुझे आपकी भाँति इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भारतवर्ष में चलाई गई कोई भी निर्वाचन प्रणाली उपद्रवात्मक असफलता को प्राप्त होगी. यदि वह इस महाद्वीप की जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के विश्वासों और परम्पराओं की अवहेलना करके जनता को व्यक्तिगत निर्वाचनाधिकार प्रदान करेगी."

इस प्रकार एक 'सिखाया-पढ़ाया तमाशा' सम्पन्न हुआ. लॉर्ड मिण्टो कांग्रेस की प्रतिद्वन्द्वी संस्था चाहते थे और उनकी कूटनीति सफल हुई. 28 मई, 1906 ई. को लॉर्ड मिण्टो ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था–"जहाँ तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, यह आन्दोलन बहुत हद तक विद्रोहात्मक है और मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि आगे चलकर इससे भय की सम्भावना होगी. इधर मैंने इस विषय में बहुत विचार किया है और अन्त में इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि कांग्रेस की प्रतिद्वन्द्वी संस्था की स्थापना सम्भव है.[1]

भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने मिण्टो के साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का विरोध किया. वे संयुक्त प्रतिनिधित्व के पक्ष में थे. ब्रिटिश समर्थक समाचार-पत्र 'स्टेट्मेन्स' में लॉर्ड मिण्टो की योजना को घृणास्पद बतलाया गया और भारतीय राष्ट्रवादियों ने भी इस योजना का खुला विरोध किया, लेकिन लॉर्ड मिण्टो अपने विचारों पर अडिग रहा और भारत में 'मुस्लिम साम्प्रदायिकता का जनक' बन गया. मुस्लिम शिष्टमण्डल के समक्ष उसका भाषण 'मुसलमानों का अधिकार-पत्र' हो गया. भारत सचिव लॉर्ड मार्ले को अपनी इच्छा और विचारों के विपरीत लॉर्ड मिण्टो का प्रस्ताव मान लेना पड़ा और 1909 ई. के मार्ले मिण्टो सुधारों में साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् चुनावों की व्यवस्था का समावेश कर दिया गया. इसके बाद तो हिन्दू-मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ती ही गई और पृथक् चुनावों का परिणाम हुआ पृथक् राष्ट्रीयता की विचारधारा और अन्त में देश का विभाजन और दो पृथक् राष्ट्रों की स्थापना. पण्डित नेहरू ने अपनी 'डिस्कवरी ऑफ इण्डिया' (हिन्दुस्तान की कहानी) में साम्प्रदायिक चुनावों का उल्लेख करते समय लिखा है–

"पृथक् निर्वाचन से वे समुदाय जो कमजोर थे या पिछड़े हुए थे और ज्यादा कमजोर हो गए. उससे अलहदगी की भावना को बढ़ावा मिला और राष्ट्रीय एकता की उन्नति में बाधा पड़ी. पृथक् निर्वाचन का अर्थ था लोकतन्त्र से इनकार. उसने अत्यन्त प्रतिक्रियावादी ढंग के नये निहित स्वार्थ पैदा किए, उससे देश के सामने जो वास्तविक समस्याएँ थीं उनसे ध्यान हटा दिया. उन्होंने भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू को भारी आघात पहुँचाया. हर प्रकार की पृथकता की भावनाओं को जन्म दिया और अन्त में देश के बँटवारे की ही बात सामने आई."

1. Rajendra Prasad : India Divided, Page 96.

मुस्लिम लीग की स्थापना, दिसम्बर 1906

शिमला मुस्लिम प्रतिनिधिमण्डल की सफलता से कट्टरवादी मुस्लिम समाज काफी उत्साहित हुआ. ब्रिटिश समर्थन से प्रोत्साहित होकर 30 दिसम्बर, 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की नींव रखी गई. यह भारतीय मुसलमानों का प्रथम साम्प्रदायिक संगठन था. मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य रखे गए–

(1) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य की तरह भक्ति उत्पन्न करना और यदि ब्रिटिश सरकार की नीति के बारे में उनसे कोई गलत धारणा हो, तो उसे दूर करना.

(2) मुसलमानों की माँगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना और उनके हितों की रक्षा करना.

(3) उपर्युक्त उद्देश्यों के विरुद्ध न जाते हुए मुसलमानों एवं अन्य जातियों में यथासम्भव मेल-मिलाप पैदा करना.

मुस्लिम लीग के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रवादियों को यह विश्वास हो गया कि इसका दृष्टिकोण साम्प्रदायिकता और हठधर्मी का दृष्टिकोण रहेगा. लीग का उद्देश्य था, विदेशी हुकूमत के प्रति राजभक्ति में वृद्धि करना और राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रवाह को रोकना. कई मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना का विरोध किया. एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता ने कहा था, "मेरे सहधर्मियों द्वारा भारत में असभाधेय भाव पैदा करने का प्रयत्न प्रशंसनीय नहीं है यह पंदौरा की पेटी सिद्ध होगा और भारत को भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा." 1908 ई. में मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों को आवादी से अधिक स्थान विधानमण्डलों में दिये जाने की माँग की. यह माँग भी की गई प्रिवी-कौंसिल में एक हिन्दू नियुक्त किया जाए तो मुसलमान भी अवश्य नियुक्त किया जाए तथा सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को काफी प्रतिनिधित्व दिया जाए. 1909 ई. के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पुनः इन्हीं माँगों को दोहराया और इंग्लैण्ड में अपने शिष्टमण्डल भेजे. भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साम्प्रदायिक प्रयत्नों का घोर विरोध किया, परन्तु फल नहीं निकला.

सरकार द्वारा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्वीकृति : 1909 के मार्ले मिण्टो सुधार

लॉर्ड मिण्टो के आग्रह पर कि भारतीय मुसलमानों को सन्तुष्ट करने के नाम पर पृथक् निर्वाचनों की माँग को मानना जरूरी है. भारत सचिव लॉर्ड मार्ले को भी अपनी इच्छा और विचारों के विपरीत यह प्रस्ताव मान लेना पड़ा और 1909 ई. के मार्ले-मिण्टो सुधारों में साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् चुनावों की व्यवस्था का समावेश कर दिया गया. नवाब सादिक अली खाँ ने 1908 ई. में कहा था, "वर्गीय एवं धार्मिक प्रतिनिधित्व योजना की सबसे खतरनाक माँग है–मुसलमानों को यह बतलाना कि उनका राजनीतिक हित हिन्दुओं से भिन्न है, ठीक नहीं है. मुसलमानों के दृष्टिकोण से भी यह सिद्धान्त खतरे से भरा हुआ है." 1909 ई. के अधिनियम (मार्ले-मिण्टो सुधार) में पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार करके भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में साम्प्रदायिक विष-वृक्ष का बीजारोपण कर दिया गया. 1909 ई. के अधिनियम के अन्तर्गत मुसलमानों और गैर-मुसलमानों की मताधिकार सम्बन्धी योग्यताओं में भी बड़ा अन्तर रखा गया. उदाहरणार्थ 3000 रुपए की वार्षिक आय पर कर देने वाले मुसलमानों को मताधिकार प्राप्त था, जबकि 3 लाख की आमदनी पर कर देने वाले किसी हिन्दू, पारसी या ईसाई को यह अधिकार नहीं था. इसी तरह वह प्रत्येक मुसलमान, जिसे बी. ए. पास किये हुए पाँच वर्ष हो गये हैं, मत दे सकता था, जबकि अन्य जातियों के व्यक्ति जिसे तीस वर्ष भी क्यों न हो गये हों, मतदान का अधिकार नहीं था. अधिनियम द्वारा प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में मुसलमानों को खास रियासतें दी गयीं. उन्हें केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान परिषदों में उनकी संख्या के अनुपात से अधिक सदस्यता प्रदान की गयी. मुसलमानों की परिषदों में उचित प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से ही अधिनियम द्वारा साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारम्भ किया गया. 1909 ई. के सुधारों ने भारत विभाजन के बीज बो दिये. मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन प्रणाली दिये जाने से लगभग छः करोड़ भारतीय शेष भारतीय जनता से पृथक् हो गये. आगा खाँ के शब्दों में "लॉर्ड मिण्टो ने हमारी माँगों को स्वीकार करके एक ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात किया जो ब्रिटिश सरकार की भारत सम्बन्धी संवैधानिक माँगों का आधार बने रहे और जिनके अनिवार्य परिणामों के रूप में भारत का विभाजन और पाकिस्तान का जन्म हुआ." गांधीजी ने कहा था, "यदि यह अधिनियम पारित नहीं होता, तो हम (हिन्दू-मुस्लिम) स्वयं इस जातिगत मनोमालिन्य का समाधान कर लेते." ब्रिटिश कूटनीति की यह भारी सफलता थी कि उन्हें अपनी चालाकी और मक्कारी से भारत के लगभग 6 करोड़ 20 लाख मुसलमानों को भारतीय जनजीवन की धारा से पृथक् कर दिया था. रेम्जे मैकडोनाल्ड के अनुसार, "पूर्व प्रचारित घृणा के आधार पर हिन्दू और मुस्लिम जातियों में घृणा के बीज बो दिये गये.

मुस्लिम लीग (1910–1916)

मुस्लिम लीग की स्थापना से लगभग चार वर्ष बाद तक उस पर पृथकृतावादी और साम्प्रदायिक तत्वों का प्रभाव अधिक था, किन्तु 1910 ई. के समाप्त होते-होते लीग की प्रतिक्रियावादी नीति कुछ शिथिल पड़ गई. इसके बाद 1916 ई. में लखनऊ समझौते तक का काल लीग की नीति में

परिवर्तन का काल है. लीग की नीति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण निम्नलिखित थे–

1. भारतीय मुसलमानों की नई पीढ़ी राष्ट्रीयता की ओर झुक गई और लीग में इस युवा पीढ़ी के प्रभाव से राष्ट्रीय विचारों का विकास हुआ.

2. मुस्लिम राष्ट्रवाद की भावना के विकास ने अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में भारी योग दिया. इंग्लैण्ड और रूस टर्की के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति का अनुसरण कर रहे थे, जिससे भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग को बहुत धक्का पहुँचा. टर्की-सुल्तान अब्दुल हामिद द्वारा प्रोत्साहित 'पान इस्लामिक आन्दोलन' ने भारतीय मुसलमानों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला. 1912-13 के बल्कान युद्धों ने भारत में टर्की के प्रति सहानुभूति की एक शक्तिशाली लहर पैदा कर दी और डॉ. अंसारी भारत से टर्की को एक मेडिकल मिशन भी ले गए. टर्की के प्रति ब्रिटेन के शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण ने भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश विरोध भावनाएँ उत्पन्न कीं और ये भावनाएँ तब और भी प्रबल हो गयीं जब टर्की ने ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध लड़ा. ब्रिटेन इस्लाम के शत्रु के रूप में देखा जाने लगा और देशभक्त मुस्लिम मस्तिष्कों को उत्तेजित करने लगा. जब "अन्तिम बची हुई मुस्लिम शक्ति के समाप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया" तो अंग्रेजों के प्रति भारतीय मुसलमानों के विश्वास का आधार डाँवाडोल होने लगा. मुस्लिम साम्प्रदायिकता को गति अवरुद्ध हुई और भारतीय मुसलमान राष्ट्रवादी चश्मे से झाँकने लगे.

3. भारतीय मुसलमान कांग्रेस के निकट आने लगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रति सरकारी रुख में परिवर्तन हो गया था. यद्यपि मार्ले-मिण्टो सुधारों में भारी दोष थे तथापि कांग्रेस इन सुधारों को क्रियान्वयन करने की यथाशक्ति चेष्टा कर रही थी और नये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्ज का कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रहा. लॉर्ड हार्डिंग्ज की मेल-जोल की नीति के फलस्वरूप मुस्लिम पृथकतावाद में पहले जैसा जोर नहीं रहा और वह धीमा पड़ गया.

4. 12 दिसम्बर, 1911 को वंग-भंग का अन्त कर दिया गया. इसने मुसलमानों पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला, क्योंकि सरकार ने वंग-भंग को रद्द करने का निर्णय करने से पूर्व मुसलमानों से परामर्श तक नहीं किया था. इससे मुसलमान रुष्ट हो गये और अंग्रेजों की नेकनीयती में उनका विश्वास डगमगाने लगा. इस असन्तोष का परिणाम यह हुआ कि वे राष्ट्रीय आन्दोलन में शरीक हो गए.

5. मुस्लिम राष्ट्रवाद के उत्कर्ष अथवा लीग से साम्प्रदायिकता को शिथिल करने का अन्तिम और सबसे महत्वपूर्ण कारण अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉ. अन्सारी, अली बन्धुओं तथा हकीम अजमल खाँ जैसे नये नेताओं का प्रभाव था. नवयुवक आजाद की गम्भीर विद्वता और भारत से बाहर की इस्लामी दुनिया के ज्ञान की सर्वत्र धाक जमी हुई थी. आजादी के व्यापक और बुद्धिसंगत दृष्टिकोण ने उन्हें सिर से पैर तक भारतीय राष्ट्रीयतावादी बना दिया. 1912 ई. में अब्दुल कलाम आजाद ने उर्दू साप्ताहिक 'अलहिलाल' को प्रकाशित करना शुरू किया. इस पत्र में अपने संक्षिप्त जीवन में ही भारतीय मुसलमानों पर राष्ट्रवाद के पक्ष में गहरा प्रभाव डाला और उन्हें आशा तथा साहस के एक उच्चतम धरातल पर ला खड़ा किया. जब से मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, अब्दुल कलाम आजाद उसकी नीतियों से सन्तुष्ट नहीं थे. उन्होंने अपनी लेखनी से अनुदारता और राष्ट्रीयता के इस शक्तिशाली गढ़ पर आक्रमण किया. आजाद के लेखों ने ब्रिटिश शासकों को क्रुद्ध कर दिया, अलहिलाल से जमानतें माँगी गयी और 1914 ई. में उसके प्रेस को जब्त कर लिया गया, जिसका अर्थ था कि 'अलहिलाल' समाप्त हो गया. लीग पर अलीगढ़ कॉलेज ग्रुप का नियन्त्रण था और आजाद उसकी नीतियों से सन्तुष्ट नहीं थे. अब्दुल कलाम आजाद की आवाज के साथ ही मौलाना मोहम्मद अली की आवाज मिली हुई थी. वंग-भंग के रद्द हो जाने से मौलाना अली को धक्का पहुँचा, अंग्रेजों से वे रुष्ट हो गये और कट्टर राष्ट्रवादी बन गये. टर्की के लिए उन्होंने जबरदस्त आन्दोलन चलाया, 1915 ई. में युद्ध पर्यन्त के लिए उन्हें अपने भाई मौलाना शौकत अली के साथ अन्तर्वासित कर दिया गया. आजाद को भी चार वर्षों के लिए अन्तर्वासित कर दिया गया. अली बन्धुओं के खिलाफत आन्दोलन के प्रभाव से मुस्लिम अली जिन्ना का प्रयत्न भी यह रहा कि लीग में राष्ट्रवादी तत्वों की विजय हो. यह आश्चर्य की बात है कि प्रारम्भिक राष्ट्रवादी जिन्ना आगे चलकर घोर राष्ट्रवादी बन गया.

इन सब कारणों का प्रभाव यह हुआ कि 22 मार्च, 1913 ई. को लीग ने अपने उद्देश्यों में भी परिवर्तन कर लिया. अब उसका उद्देश्य "ब्रिटिश सत्ता के अन्तर्गत भारत के लिए उचित स्वशासन की प्राप्ति" हो गया. इस उद्देश्य का कांग्रेस ने स्वागत किया. 1914 ई. के लीग के सम्मेलन में राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा. इस अधिवेशन में हिन्दू और मुसलमानों की सद्भावना की स्थापना पर विशेष बल दिया गया और राष्ट्रवादी शक्तियों का यह प्रयास रहा कि लीग और कांग्रेस परस्पर निकट आएँ. 1914 ई. के अधिवेशन में डॉ अन्सारी और मौलाना आजाद के प्रयत्न इस दिशा तक सफल हुए कि लीग और कांग्रेस में सहयोग की भावना दृढ़ हो गई. ब्रिटिश कूटनीतिक चाल के बावजूद राष्ट्रवादी नेता इस बात के लिए निरन्तर सचेष्ट रहे कि हिंदू-मुस्लिम एकता 'दिन-दूनी और रात चौगुनी' बढ़े और हिन्दू-मुसलमान दोनों मिलकर एक सामान्य राजनीतिक लक्ष्य

की प्राप्ति की ओर शक्तिशाली कदम उठाएँ तथा एक ऐसे महान् भारत का निर्माण करें जो अशोक कालीन भारत से अधिक विशाल और अकबरकालीन भारत से कहीं अधिक उन्नत हो. इस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना का प्रयत्न भी इस दिशा में रहा कि कांग्रेस और लीग एक-दूसरे के अधिक निकट आएँ. मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप कांग्रेस और लीग में परस्पर एक समझौता हो जाने का आधार तैयार हो गया. लीग के 1915 के मुम्बई अधिवेशन में, जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन भी हो रहा था, पण्डित मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजनी नायडू जैसे कई कांग्रेसी नेता सम्मिलित हुए. एक प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय किया गया कि भारत में शासन सुधार की एक ऐसी योजना तैयार की जाए, जिससे कांग्रेस और लीग एक साथ मिलकर प्रयत्न करें. दूसरी ओर कांग्रेस ने भी एक प्रस्ताव द्वारा अपनी महासमिति को आदेश दिया कि वह लीग से परामर्श करके शासन सुधार योजना को तैयार करने के लिए कांग्रेस तथा लीग दोनों को स्वीकार हो. शासन सुधार योजना को तैयार करने के लिए कांग्रेस तथा लीग द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गई. दोनों दलों का संयुक्त अधिवेशन सन् 1916 ई. लखनऊ में हुआ जो 'लखनऊ समझौता–1916' (The Lucknow Pact—1916) के नाम से विख्यात है लखनऊ-कांग्रेस अपने ढंग की अद्वितीय संस्था थी. एक तो उसमें हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य हुआ तथा दूसरा इसमें स्वराज्य की योजना पेश हुई थी. कांग्रेस के दो दल जो 1907 ई. में अलग-अलग थे, इस समय एक हो गये. सब लोग एकजुट हो गये थे.

लखनऊ समझौता

लखनऊ समझौता सम्पन्न होने की घटना को तत्कालीन नेताओं ने 'राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में एक नये मोड़ की संज्ञा दी थी. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के शब्दों में, "भारत के इतिहास में यह सुनहरा दिन था." इसी परिप्रेक्ष्य में गुरुमुख निहालसिंह लिखते हैं–"इस प्रकार भारत की दो बड़ी जातियों ने और दो बड़ी राजनीतिक संस्थाओं ने एक कार्यक्रम को अपना और इस रूप में इनके द्वारा विशेषकर नरम और उग्र पक्ष में फिर से एक हो जाने पर, ब्रिटिश भारत की राजनीतिक दृष्टि से जागी हुई सारी जनता का प्रतिनिधित्व हुआ.

कांग्रेस-लीग योजना या लखनऊ समझौते में निम्नलिखित शर्तें रखी गई थीं–

1. केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानसभाओं में 80 प्रतिशत निर्वाचित और 20 प्रतिशत मनोनीत सदस्य होने चाहिए.

2. केन्द्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 150, मुख्य प्रान्तों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या कम-से-कम 125 और अन्य प्रान्तों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या 50 से 75 तक होनी चाहिए.

3. विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाए और मताधिकार को यथासम्भव विस्तृत किया जाए.

4. विधानसभाओं में मुसलमानों को पृथक् प्रतिनिधित्व दिया जाए. विभिन्न विधानसभाओं में उनकी संख्या इस प्रकार हो–केन्द्रीय विधानसभा एक-तिहाई पंजाब–50 प्रतिशत, संयुक्त प्रान्त–30 प्रतिशत, बंगाल–40 प्रतिशत, बिहार–25 प्रतिशत, मुम्बई–एक तिहाई, मध्य प्रदेश–15 प्रतिशत तथा मद्रास के लिए 15 प्रतिशत स्थान दिये जावें. इस तरह से मुसलमानों को केन्द्रीय व्यवस्थापिका में 1/3 भाग आरक्षित मिल गये. साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की भी व्यवस्था की गई थी. इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित किया गया था कि एक सम्प्रदाय विशेष के 3/4 सदस्य किसी प्रस्ताव का विरोध करेंगे, तो वह पारित नहीं होगा. भारतीय परिषद् की समाप्ति, प्रान्तीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने, केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषद् के 80% सदस्यों के चुनाव तथा प्रतिरक्षा एवं विदेश नीति को छोड़कर सभी विभागों पर पूर्ण नियन्त्रण की माँग जैसे मुद्दे भी इन शर्तों में शामिल थे.

स्मरणीय तथ्य

- भारत के राज्यसचिव लॉर्ड मार्ले एवं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिण्टो ने 1892 ई. के भारतीय परिषद् अधिनियम में संशोधन की संस्तुति ब्रिटिश संसद के समक्ष रखी, जिसे पास होने के बाद 'मिण्टो-मार्ले सुधार अधिनियम' कहा गया.
- कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ में 1916 में एक समझौता हुआ जिसे 'लखनऊ पैक्ट' कहा गया.
- सन् 1837 ई. में कलकत्ता में एक जमींदारों का संगठन स्थापित किया गया था, जिसे 'लैण्डहोल्डर्स सोसाइटी' कहा गया.
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसम्बर, 1885 को 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बम्बई में व्योमेशचन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ.
- दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितम्बर, 1825 को बम्बई में हुआ था.
- 'जनता के मित्र' नामक पत्रिका का प्रकाशन सर ए. ओ. ह्यूम ने प्रारम्भ किया था, जिसमें भारतीयों की समस्याओं के लेख प्रकाशित होते थे.
- बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 ई. को महाराष्ट्र के रत्नगिरी नगर में हुआ था.

- 'कमल एवं करार नामक' गुप्त संस्था की सदस्यता अरविन्द घोष ने लंदन में ग्रहण की थी.
- मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 30 दिसम्बर, 1906 को हुई थी.
- 'इण्डियन होमरूल लीग' की स्थापना 28 अप्रैल, 1916 को बेलगाँव में 'जोसेफ बपतिस्ता' के सुझाव पर हुई थी.
- गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ दाण्डी नामक गाँव में समुद्र के जल से नमक बनाकर किया था. 12 मार्च, 1930 को अपने 79 सहयोगियों के साथ वे दाण्डी यात्रा पर निकले थे.
- 'तोहफत-उल-मुहीद्दीन' फारसी भाषा में 1809 ई. में राजा राम मोहन राय ने लिखी थी, जिसका अर्थ 'एकेश्वरवादियों का उपहार' होता था.
- लॉर्ड रिपन ने 1882 ई. में डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया था, जिसका उद्देश्य 1854 ई. के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था.
- थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सन् 1875 ई. में न्यूयार्क में ब्लावेट्स्की एवं कर्नल एम. एस. ऑल्काट ने की थी.
- डी.ए.वी. कॉलेज की स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती की मृत्यु के पश्चात् लाहौर में 1886 ई. में हुई थी.
- साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठियों की चोट से 17 नवम्बर, 1928 ई. को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई.
- '1857 ई. का भारतीय स्वातन्त्र्य का युद्ध' नामक पुस्तक वीर सावरकर ने लिखी थी.
- तुर्की का खलीफा समूचे विश्व का सुन्नी मुसलमानों का धर्म गुरु माना जाता था.
- "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा"–यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था.
- अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ (All India National Liberal Federation) की स्थापना सन् 1918 ई. में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी.
- सन् 1917 ई. में ब्रिटिश सरकार ने डॉ. माइकेल सैंडलर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया जिसे सैंडलर आयोग कहा गया. इसके जिम्मे कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जाँच करने का कार्य सौंपा गया था.
- डॉक्टर आत्माराम पाण्डुरंग ने सन् 1867 ई. में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी.
- स्वामी विवेकानन्द के गुरु 'रामकृष्ण परमहंस (1834-86)' कलकत्ता के एक मन्दिर 'दक्षिणेश्वर' के पुजारी थे.
- ब्रिटिश संसद ने 1784 ई. में एक नया कानून बनाया जो पिट्स इण्डिया एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ. इस कानून के द्वारा कम्पनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गयी.
- प्रसिद्ध विद्वान् आर. पी. दत्त ने अपनी पुस्तक 'आज का भारत' (India Today) में ब्रिटिश साम्राज्यवादी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों को तीन भागों में बाँटा है–

  (a) व्यापारिक काल (1757-1813)

  (b) आदर्श काल (1813-1858)

  (c) वित्त साम्राज्यवाद (19वीं शताब्दी)
- काबुल में राजा महेन्द्र प्रताप, बरकतुल्ला और ओबेदुल्ला के प्रयासों से दिसम्बर, 1915 में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार बनाई गई जिसके अध्यक्ष महेन्द्र प्रताप थे.
- 'आनन्द मठ' नामक उपन्यास के लेखक बंकिम चन्द्र चटर्जी थे. वन्दे मातरम इसी में लिखा गया था.
- विपिन चन्द्र पाल का जन्म 1858 ई. में असम के सिलहट जिले में हुआ था एवं सन् 1932 में इनकी मृत्यु हो गई थी.
- सितम्बर 1946 में बंगाल प्रान्तीय किसान सभा ने तेभागा आन्दोलन चलाया था, जिसमें किसानों को उपज का 2/3 भाग देने की माँग की गई थी.

विशिष्ट स्मरणीय तथ्य

स्वतन्त्रता–संग्रामकालीन धार्मिक एवं समाज सुधार आन्दोलन की संस्थाएँ

क्र. सं.	नाम संस्था	संस्थापक	स्थान	स्थापना वर्ष
1.	आत्मीय सभा	ज्योतिबा फूले, राजा राममोहन राय	बंगाल	1815 ई.
2.	ब्रह्म समाज	राजा राममोहन राय	बंगाल	1828 ई.
3.	हिन्दू कॉलेज	डेविड हेयर	कलकत्ता	1822-23 ई.
4.	तत्वबोधिनी सभा	देवेन्द्रनाथ टैगोर	बंगाल	1826 ई.
5.	यंग बंगाल आन्दोलन	हेनरी विवियन डिरोजियो	बंगाल	1826 ई.

6.	रहनुमाई माजदायासन समाज	दादा भाई नौरोजी, फखोन नौरोजी	बम्बई	1851 ई.
7.	राधास्वामी सत्संग	शिवदयाल साहेब	आगरा	1861 ई.
8.	मानव धर्मसभा	मंचाराम	प. भारत में	1844 ई.
9.	मुहम्मडन लिट्रेरी सोसाइटी	—	कलकत्ता	1863 ई.
10.	आदि ब्रह्म समाज	केशवचन्द्र सेन	कलकत्ता	1865 ई.
11.	लन्दन इण्डिया कमेटी	सी. पुरुषोत्तम मुदालियर	लन्दन	1862 ई.
12.	ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन	दादा भाई नौरोजी	लन्दन	1866 ई.
13.	नेशनल इण्डियन एसोसिएशन	मेदी कारपेन्टर	लन्दन	1867 ई.
14.	प्रार्थना समाज	महादेव गोविन्द रानाडे, आत्माराम पाण्डुरंग	महाराष्ट्र	1867 ई.
15.	स्वामी नारायण सम्प्रदाय	सन्त स्वामी नारायण (सहजानंद)	दक्षिणी भारत	1861 ई.
16.	साइंटिफिक सोसाइटी	सर सैय्यद अहमद खाँ	अलीगढ़	1864 ई.
17.	पूना सार्वजनिक सभा	रानाडे एवं चिपलंकर	पुणे	1870 ई.
18.	ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इण्डिया (वेद समाज)	श्रीधरालु नायडू	मद्रास	1871 ई.
19.	सत्यशोधक समाज	ज्योतिबा फुले, तेलंग बराकड़े	पुणे	1873 ई.
20.	अलीगढ़ आन्दोलन	सर सैय्यद अहमद खाँ	अलीगढ़	1875 ई.
21.	आर्य समाज	स्वामी दयानन्द स्वामी	बम्बई	1875 ई.
22.	राजमुन्दरी सोशल रिफोर्म एसोसिएशन	वीर सेलिंगम पंतलु	हैदराबाद	1878 ई.
23.	थियोसोफिकल सोसाइटी	कर्नल अंकाट एवं मैडम ब्लाटवस्की	आड्यार (मद्रास)	1882 ई.
24.	राष्ट्रीय समाज सुधार समिति	एम. जी. रानाडे	बम्बई	1887 ई.
25.	अहमदिया आन्दोलन	मिर्जा गुलाम अहमद	गुरुदासपुर	1889 ई.
26.	रामकृष्ण मिशन	स्वामी विवेकानन्द	वैल्लूर	1897 ई.
27.	पहला विधवा आश्रम	डी. के. कर्वे	पुणे	1899 ई.
28.	एस.एन.डी.पी. योगम्	नारायण गुरु	केरल	1903 ई.
29.	देवबन्द स्कूल	अबुल कलाम आजाद	देवबन्द	1912 ई.
30.	हिन्दू महासभा	मदनमोहन मालवीय	हरिद्वार	1915 ई.
31.	साबरमती आश्रम	महात्मा गांधी	अहमदाबाद	1917 ई.
32.	विश्वभारती	रवीन्द्रनाथ टैगोर	कलकत्ता	1918 ई.
33.	बहिष्कृत हितकारिणी सभा	बी. आर. अम्बेडकर	–	1924 ई.
34.	हरिजन संघ	महात्मा गांधी	अहमदाबाद	1932 ई.

विदेशों में प्रमुख भारतीय क्रान्तिकारी संगठन

क्र.सं.	नाम संगठन	संस्थापक	स्थापना वर्ष	देश
1.	इण्डिया हाउस	श्यामजी कृष्ण वर्मा	1904 ई.	लन्दन (इंग्लैण्ड)
2.	अभिनव भारत	वी. डी. सावरकर	1906 ई.	लन्दन (इंग्लैण्ड)
3.	इण्डियन इण्डिपेण्डेन्स लीग	तारकनाथ दास	1907 ई.	अमरीका
4.	गदर पार्टी	लाला हरदयाल, बरकतुल्ला एवं रामचन्द्र	1913 ई.	सेन फ्रांसिस्को (अमरीका)
5.	इण्डियन इण्डिपेन्डेन्स लीग	वीरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल	1914 ई.	बर्लिन (जर्मनी)
6.	इण्डियन इण्डिपेन्डेन्स लीग एवं गवर्नमेन्ट	राजा महेन्द्र प्रताप	1915 ई.	काबुल (अफगानिस्तान)
7.	इण्डियन इण्डिपेन्डेस लीग	रास बिहारी बोस	1942 ई.	टोकियो (जापान)
8.	आजाद हिन्द फौज	रास बिहारी बोस	1942 ई.	टोकियो (जापान)
9.	आजाद हिन्द फौज	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	1943 ई.	सिंगापुर

अंग्रेजकालीन प्रमुख समाचार-पत्र

क्र. सं.	नाम पत्र/पत्रिका	संस्थापक	भाषा	स्थान	प्रथम प्रकाशन वर्ष
1.	सोमनाथ	ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	बंगाली	कलकत्ता	1859 ई.
2.	इण्डियन मिरर	मनमोहन घोष, देवेन्द्रनाथ टैगोर	अंग्रेजी	कलकत्ता	1861 ई.
3.	टाइम्स ऑफ इण्डिया	अंग्रेजी प्रेस	अंग्रेजी	बम्बई	1861 ई.
4.	इन्दुप्रकाश	एम. जी. रानाडे	मराठी	बम्बई	1861 ई.
5.	नेटिव ओपिनियन	वी. एन. माण्डलिक	अंग्रेजी	बम्बई	1864 ई.
6.	पायनियर	अंग्रेजी प्रेस	अंग्रेजी	इलाहाबाद	1865 ई.
7.	ज्ञान प्रदायिनी	नवीनचन्द्र राय	हिन्दी	लाहौर	1866 ई.
8.	कविवचन सुधा	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	हिन्दी	वाराणसी	1867 ई.
9.	अमृत बाजार पत्रिका	शिशिर घोष/मोतीलाल घोष	बंगाली	कलकत्ता	1868 ई.
10.	मद्रास मेल	अंग्रेजी प्रेस	अंग्रेजी	मद्रास	1868 ई.
11.	बंग-दर्शन	बंकिमचन्द्र चटर्जी	बंगाली	कलकत्ता	1873 ई.
12.	ट्रिब्यून	सर दयाल सिंह मजीठिया	अंग्रेजी	लाहौर	1877 ई.
13.	हिन्दी प्रदीप	बालकृष्ण भट्ट	हिन्दी	वाराणसी	1877 ई.
14.	स्टेट्समैन	रॉबर्ट नाइट	अंग्रेजी	कलकत्ता	1878 ई.
15.	बंगाली	एस. एन. बनर्जी	अंग्रेजी	कलकत्ता	1879 ई.
16.	बंगवासी	जोगिन्दर नाथ बोस	बंगाली	कलकत्ता	1881 ई.
17.	मराठा	आगरकर	अंग्रेजी	बम्बई	1881 ई.
18.	केसरी	केलकर	मराठी	बम्बई	1881 ई.
19.	इण्डिया	दादा भाई नौरोजी	अंग्रेजी	बम्बई	1890 ई.
20.	हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड	सच्चिदानन्द सिन्हा	अंग्रेजी	दिल्ली	1899 ई.
21.	इण्डियन रिव्यू	जी. ए. नटेशन	अंग्रेजी	मद्रास	1900 ई.
22.	इण्डियन ओपिनियन	महात्मा गांधी	अंग्रेजी	द. अफ्रीका	1903 ई.
23.	इण्डियन सोशियोलोजिस्ट	श्यामजी कृष्ण वर्मा	अंग्रेजी	लन्दन	1905 ई.
24.	युगान्तर	बारीन्द्र घोष, भूपेन्द्र दत्त	बंगाली	कलकत्ता	1906 ई.
25.	मॉर्डन रिव्यू	रामानन्द चटर्जी	अंग्रेजी	कलकत्ता	1907 ई.
26.	वन्दे मातरम्	हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा	अंग्रेजी	पेरिस	1909 ई.
27.	प्रताप	गणेश शंकर विद्यार्थी	हिन्दी	कानपुर	1910 ई.
28.	अल हिलाल	अबुल कलाम आजाद	उर्दू	कलकत्ता	1912 ई.
29.	बॉम्बे क्रॉनिकल	फीरोजशाह मेहता	अंग्रेजी	बम्बई	1913 ई.
30.	गदर	लाला हरदयाल	अंग्रेजी	सेन फ्रांसिस्को	1913 ई.
31.	कॉमनवील	एनीबेसेन्ट	अंग्रेजी	बम्बई	1914 ई.
32.	न्यू इण्डिया	एनीबेसेन्ट	अंग्रेजी	बम्बई	1914 ई.
33.	सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया	श्रीनिवास शास्त्री	अंग्रेजी	मद्रास	1918 ई.
34.	इण्डिपेन्डेन्ट	मोतीलाल नेहरू	अंग्रेजी	इलाहाबाद	1919 ई.
35.	नवजीवन	महात्मा गांधी	गुजराती	अहमदाबाद	1919 ई.
36.	यंग इण्डिया	महात्मा गांधी	अंग्रेजी	अहमदाबाद	1919 ई.
37.	हिन्दुस्तान टाइम्स	के. एम. पणिक्कर	अंग्रेजी	बम्बई	1922 ई.
38.	हरिजन	महात्मा गांधी	हिन्दी	पुणे	1933 ई.

स्वाधीनता संघर्ष की प्रमुख क्रान्तिकारी घटनाएँ

क्र. सं.	घटना	वर्ष	स्थान	क्रान्तिकारी
1.	लै. आयर्स्ट एवं कमिश्नर रेण्ड हत्याकाण्ड	1897 ई.	पुणे	चापेकर बन्धु
2.	अलीपुर षड्यन्त्र	1908 ई.	मुजफ्फरपुर	प्रफुल्लचाकी एवं खुदीराम बोस
3.	जैक्सन हत्याकाण्ड	1909 ई.	नासिक	अनन्त कन्हेरे
4.	कर्नल वाली हत्याकाण्ड	1909 ई.	लन्दन	मदनलाल धींगरा
5.	दिल्ली बम काण्ड	1912 ई.	दिल्ली	रासबिहारी बोस एवं बसन्त कुमार
6.	काकोरी ट्रेन डकैती काण्ड	1927 ई.	काकोरी	अशफाक उल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल
7.	साण्डर्स हत्याकाण्ड	1928 ई.	लाहौर	सरदार भगतसिंह
8.	शस्त्रागार डकैती काण्ड	1930 ई.	चटगाँव	सूर्यसेन
9.	जनरल डायर हत्याकाण्ड	1940 ई.	लन्दन	सरदार उधमसिंह

स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित पुस्तकें एवं उनके लेखक

क्र. सं.	नाम पुस्तक	लेखक
1.	एकेश्वरवादियों को उपहार	राजा राममोहन राय
2.	असबाबे बगावते हिन्द	सर सैय्यद अहमद खाँ
3.	सत्यार्थ प्रकाश	दयानन्द सरस्वती
4.	पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया	दादा भाई नौरोजी
5.	आनन्दमठ	बंकिम चन्द्र चटर्जी
6.	वाम बोधिनी	केशवचन्द्र सेन
7.	सोशल रिफार्म्स एण्ड राइज ऑफ द मराठा पॉवर	एम. जी. रानाडे
8.	गोरा	रवीन्द्रनाथ टैगोर
9.	द हंग्री स्टोन्स (क्षुधित पाषाण)	रवीन्द्रनाथ टैगोर
10.	कपाल कुण्डला	बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय
11.	चन्द्रशेखर	बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय
12.	हाउ इण्डिया फॉट फॉर फ्रीडम	एनीबेसेन्ट
13.	इण्डिया ए नेशन	एनीबेसेन्ट
14.	ए नेशन इन मेकिंग	एस. एन. बनर्जी
15.	भारत दुर्दशा	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
16.	द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन्स	लोकमान्य तिलक
17.	गीता रहस्य	लोकमान्य तिलक
18.	नील दर्पण	दीनबन्धु मित्र
19.	भारत का आर्थिक इतिहास	आर. सी. दत्त
20.	होम एण्ड द वर्ल्ड	रवीन्द्रनाथ टैगोर
21.	गीतांजलि	रवीन्द्रनाथ टैगोर
22.	हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज	लाला लाजपत राय
23.	अनहैप्पी इण्डिया	लाला लाजपत राय
24.	पॉलिटिकल टेस्टामेन्ट ऑफ गोखले	गोपालकृष्ण गोखले
25.	भारत-भारती	मैथिलीशरण गुप्त
26.	सांग ऑफ इण्डिया	सरोजिनी नायडू
27.	ब्रोकन विंग	सरोजिनी नायडू
28.	हिन्द स्वराज	महात्मा गांधी
29.	माई एक्सपेरीमेन्ट विद ट्रुथ	महात्मा गांधी
30.	इण्डिया फोर इण्डियन्स	सी. आर. दास
31.	एसेज ऑन गीता	अरविन्द घोष
32.	लाइफ डिवाइन	अरविन्द घोष
33.	तराने हिन्द	मुहम्मद इकबाल
34.	सोजे वतन	मुंशी प्रेमचन्द
35.	गोदान	मुंशी प्रेमचन्द
36.	गबन	मुंशी प्रेमचन्द
37.	कर्मभूमि	मुंशी प्रेमचन्द
38.	द वार ऑफ इण्डियन इण्डिपेन्डेंस	वी. डी. सावरकर
39.	हिंट्स फोर सेल्फ कल्चर	लाला हरदयाल
40.	इण्डिया विन्स फ्रीडम	अब्दुल कलाम आजाद
41.	इण्डिया डिवाइडेड	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
42.	इण्डियन फिलोसॉफी	डॉ. एस. राधाकृष्णन्
43.	रिलीजन एण्ड कल्चर	डॉ. एस. राधाकृष्णन्
44.	डिस्कवरी ऑफ इण्डिया	जवाहर लाल नेहरू
45.	एन. ऑटोबायोग्राफी	जवाहर लाल नेहरू
46.	समाजवाद	डॉ. सम्पूर्णानन्द
47.	आर्यों का आदि देश	डॉ. सम्पूर्णानन्द
48.	द रीडल्स ऑफ हिन्दूइज्म	बी. आर. अम्बेडकर
49.	गुले नगमा	फिराक गोरखपुरी
50.	इण्डियन स्ट्रगल	सुभाष चन्द्र बोस
51.	दादा कामरेड	यशपाल
52.	इण्डिया दैट वाज वण्डर	ए. एल. बाशम
53.	इण्डियन अनरेस्ट	वेलेन्टाइन शिरोल

प्रमुख भारतीय क्रान्तिकारी संगठन

क्र. सं.	संगठन	संस्थापक	स्थान	स्थापना वर्ष
1.	मित्र मेला	सावरकर बन्धु	पूना	1901 ई.
2.	अनुशीलन समिति	ज्ञानेन्द्र नाथ बोस	मिदनापुर	1902 ई.
3.	अभिनव भारत	वी. डी. सावरकर	पूना	1904 ई.
4.	स्वदेश बान्धव समिति	अश्विनी कुमार दत्त	बारिसाल	1905 ई.
5.	अनुशीलन समिति	बारीन्द्र कुमार घोष एवं भूपेन्द्र दत्त	ढाका	1907 ई.
6.	भारत माता सोसाइटी	अजित सिंह एवं अम्बा प्रसाद	पंजाब	1907 ई.
7.	हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन	शचीन्द्रनाथ सान्याल	कानपुर	1924 ई.
8.	नौजवान सभा	भगतसिंह	लाहौर	1926 ई.
9.	हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन	चन्द्रशेखर	दिल्ली	1928 ई.

भारत के वायसराय एवं उनका काल

क्र. सं.	वायसराय	काल
1.	लॉर्ड केनिंग	1858-62 ई.
2.	लॉर्ड एल्गिन	1862-63 ई.
3.	सर जॉन लॉरेन्स	1864-69 ई.
4.	लॉर्ड मेयो	1869-72 ई.
5.	लॉर्ड नार्थ ब्रुक	1872-76 ई.
6.	लॉर्ड लिटन	1876-80 ई.
7.	लॉर्ड रिपन	1880-84 ई.
8.	लॉर्ड डफरिन	1884-88 ई.
9.	लॉर्ड लैंसडाउन	1888-94 ई.
10.	लॉर्ड एल्गिन-II	1894-99 ई.
11.	लॉर्ड कर्जन	1899-1905 ई.
12.	लॉर्ड मिन्टो द्वितीय	1903-10 ई.
13.	लॉर्ड हॉर्डिंग	1910-16 ई.
14.	लॉर्ड चेम्सफोर्ड	1916-21 ई.
15.	लॉर्ड रीडिंग	1921-26 ई.
16.	लॉर्ड इरविन	1926-31 ई.
17.	लॉर्ड विलिंगटन	1931-36 ई.
18.	लॉर्ड लिनलिथगो	1936-44 ई.
19.	लॉर्ड वैवेल	1944-47 ई.
20.	लॉर्ड माउण्टबेटन	1947-48 ई.

ब्रिटिशकालीन भारतीय प्रान्त

1.	मद्रास	7.	उड़ीसा
2.	बम्बई	8.	मध्य प्रान्त
3.	बंगाल	9.	संयुक्त प्रान्त
4.	पंजाब	10.	असम
5.	सिन्ध	11.	उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त
6.	बिहार		

भारत के गवर्नर जनरल

क्र. सं.	गवर्नर जनरल	कालक्रम
1.	लॉर्ड विलियम बैंटिंक	1833-35 ई.
2.	सर चार्ल्स मेटकॉफ	1835-36 ई.
3.	लॉर्ड ऑकलैण्ड	1836-42 ई.
4.	लॉर्ड एलन	1842-44 ई.
5.	लॉर्ड हार्डिंग	1844-48 ई.
6.	लॉर्ड डलहीजी	1848-56 ई.
7.	लॉर्ड केनिंग	1856-58 ई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : विशिष्ट तथ्य

1.	स्थापना वर्ष	28 दिसम्बर, 1885 ई. में
2.	संस्थापक	ए. ओ. ह्यूम
3.	स्थापना स्थल	गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के भवन में
4.	प्रथम अध्यक्ष	व्योमेश चन्द्र बनर्जी
5.	प्रमुख सदस्यगण	(i) फीरोजशाह मेहता (ii) दादा भाई नौरोजी (iii) दीनेशा एदलजी वाचा (iv) वी. राघवाचारी (v) काशीनाथ तैलंग (vi) एन. जी. चन्द्रावरकर (vii) एस. सुब्रह्मण्यम्
6.	कांग्रेस शब्द	उत्तरी अमरीका के इतिहास से 'कांग्रेस' शब्द लिया गया है जिसका अर्थ 'लोगों का समूह' होता है.

विगत वर्षों में आई.ए.एस. (प्री.) में पूछे गये प्रश्न

1. किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभभाई पटेल को सरदार की पदवी (Title) से विभूषित किया गया था ?
   (A) खेड़ा सत्याग्रह (B) नमक सत्याग्रह
   (C) व्यक्तिगत सत्याग्रह (D) बारदोली सत्याग्रह

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. 1922 के बारदोली प्रस्ताव ने किसानों को कर न देने को तथा काश्तकारों को लगान न देने को कहा.
   2. गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों से नियन्त्रण छीनकर अपना नियन्त्रण स्थापित करने वाला अकाली आन्दोलन व्यापक असहयोग आन्दोलन का ही एक भाग था.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/ हैं ?
   (A) केवल 1 (B) केवल 2
   (C) 1 और 2 दोनों (D) न ही 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित में से किन वकीलों ने असहयोग आन्दोलन के आरम्भ होने पर अपनी वकालत त्याग दी थी ?
   1. आसफ अली 2. सी. राजगोपालाचारी
   3. सैफुद्दीन किचलू 4. टी. प्रकाशम

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–
   (A) केवल 1 तथा 2 (B) केवल 1, 2 तथा 3
   (C) केवल 3 तथा 4 (D) 1, 2, 3 तथा 4

4. कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि कांग्रेस द्वारा एक कार्यकारी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो कांग्रेस का दिन प्रतिदिन का कामकाज देखे ?
   (A) एनी बेसेंट (B) बाल गंगाधर तिलक
   (C) मदन मोहन मालवीय (D) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

5. 1905-07 वर्षों के दौरान कांग्रेस में उग्रपन्थियों (Extremists) तथा नरमपंथियों (Moderates) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. उग्रपंथी स्वदेशी तथा बहिष्कार आन्दोलन को बंगाल से बाकी सारे देश में फैलाना चाहते थे.
   2. नरमपंथी बहिष्कार को धीरे-धीरे विदेशी वस्तुओं से बढ़ाकर सरकार के साथ सहयोग के अथवा साहचर्य के सभी प्रकारों पर लागू करना चाहते थे.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?
   (A) केवल 1 (B) केवल 2
   (C) 1 और 2 दोनों (D) न ही 1 और न ही 2

6. निम्नलिखित में से कौनसा/से 1908 के मध्य से स्वदेशी आन्दोलन की अवनति का/के कारण था/थे ?
   1. सरकार के द्वारा कठोर दमन
   2. कांग्रेस में आन्तरिक कलह (Internal squabbles)
   3. एक सक्षम संगठन तथा पार्टी संरचना का अभाव

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–
   (A) केवल 1 (B) केवल 1 तथा 2
   (C) केवल 2 तथा 3 (D) 1, 2 तथा 3

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. स्वदेशी आन्दोलन की औपचारिक घोषणा 1905 में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा बुलाई गई एक सभा में बरीसाल में की गई थी.
   2. बंगाल विभाजन के दिन विख्यात बहिष्कार प्रस्ताव स्वदेशी आन्दोलन के नेताओं द्वारा बंगाल में पारित किया गया था.
   3. चिदम्बरम पिल्लै स्वदेशी आन्दोलन को मद्रास प्रेसीडेंसी में ले गए.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?
   (A) केवल 1 (B) 1 तथा 3
   (C) 2 तथा 3 (D) केवल 3

8. वह क्या तात्कालिक कारण था जिसके फलस्वरूप प्लेग कमेटी के चेयरमैन रैण्ड की तथा लेफ्टिनेन्ट आयर्स्ट की 1898 में हत्या हुई ?
   (A) बालगंगाधर तिलक की, सरकार द्वारा प्लेग की स्थिति से निपटने की नीति की आलोचना के फलस्वरूप, होने वाली गिरफ्तारी जिसने पूना सार्वजनिक सभा के कार्यकर्ताओं को हिंसक बना दिया
   (B) प्लेग सम्बन्धित सरकारी कामकाज के प्रति आमतौर पर असन्तोष था
   (C) प्लेग प्रभावित क्षेत्रों में पूना सार्वजनिक सभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा पीटे जाने के कारण जनता में रोष उत्पन्न हुआ
   (D) महाराष्ट्र के कुछ उग्रपंथी नेताओं ने अति उत्साह के साथ ब्रिटिश शासकों तथा भारतीय जनता के मध्य संघर्ष की अवस्था को उग्र किया

9. निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय था ?
   (A) अक्षय कुमार दत्त (B) गोपाल हरि देशमुख
   (C) ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (D) महादेव गोविन्द रानाडे

10. भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वह कौनसा प्रथम भारतीय था जिसे गवर्नर-जनरल की कौंसिल का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था ?
    (A) राजा किशोरी लाल गोस्वामी
    (B) मोतीलाल नेहरू
    (C) सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा
    (D) तेज बहादुर सेप्रू
11. ब्रिटिश सरकार ने संविभाग व्यवस्था को सर्वप्रथम कब चलाया?
    (A) 1853 ई. में (B) 1858 ई. में
    (C) 1861 ई. में (D) 1892 ई. में
12. निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य रूप से उदारवादियों का मुखपत्र था?
    (A) न्यू इण्डिया (B) लीडर
    (C) यंग इण्डिया (D) फ्री प्रेस जर्नल
13. निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी थी?
    1. विष्णु कृष्ण चिपलुंकर
    2. गोपाल गणेश अगरकर
    3. माधवराव नाम जोशी
    4. राव बहादुर माधवराव वासुदेव बर्वे
    (A) 1, 2 एवं 4 (B) 1, 3 एवं 4
    (C) 2, 3 एवं 4 (D) 1, 2 एवं 3
14. होमरूल आन्दोलन के नेताओं ने 'होमरूल' शब्द कहाँ के सदृश आन्दोलन से ग्रहण किया था?
    (A) आयरलैण्ड (B) स्कॉटलैण्ड
    (C) संयुक्त राज्य अमीरात (D) कनाडा
15. निम्नलिखित में से कौनसा सही सुमेलित है?
    (A) निबन्धमाला – विष्णुशास्त्री चिपलंकर
    (B) सुधारक – शिशिर कुमार घोष
    (C) रफ्त गोफ्तार – आगरकर
    (D) संवाद प्रभाकर – बाल गंगाधर तिलक
16. किस निम्नांकित में वे सिद्धान्त एवं संवैधानिक प्रावधान प्रतिबिम्बित हुए जो बाद में मॉण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में समाविष्ट किये गये थे?
    (A) नेहरू रिपोर्ट (B) वावेल प्लान
    (C) लखनऊ समझौता (D) पूना समझौता
17. लॉर्ड मैकाले सम्बद्ध था–
    (A) सेना के सुधार से
    (B) सती प्रथा की समाप्ति से
    (C) विधि संहिताकरण से
    (D) स्थायी बन्दोबस्त से
18. भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ किया–
    (A) सर सैयद अहमद खाँ ने
    (B) अब्दुल लतीफ ने
    (C) बदरुद्दीन तैयब जी ने
    (D) सैयद अमीर अली ने
19. उन्नीसवीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेन्ट के प्रेरक थे–
    (A) रसिक कुमार मलिक
    (B) रामतनु लाहिड़ी
    (C) हेनरी विवियन डेरीजियो
    (D) पियरीचन्द्र मित्रा
20. विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुन्दरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था–
    (A) वीरेशलिंगम ने (B) के. टी. तेलंग ने
    (C) बेहरामजी ने (D) गोपालाचारियार ने
21. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए–

    सूची-I (व्यक्ति)
    (a) बाबा रामसिंह (b) मिर्जा गुलाम अहमद
    (c) मुकुन्द दास (d) नौरोजी फरदीनजी

    सूची-II (आन्दोलन)
    (1) सत्य महिमा धर्म
    (2) रहनुमाई माजदयासन सभा
    (3) नामधारी आन्दोलन
    (4) अहमदिया आन्दोलन

    कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	4	1	2
(B)	4	3	1	2
(C)	4	3	2	1
(D)	3	4	2	1

22. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

    सूची-I
    (a) समाचार-पत्र (Incitement to offence) अधिनियम
    (b) भारतीय प्रेस (Emergency Powers) अधिनियम
    (c) भारतीय प्रेस अधिनियम
    (d) वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम

    सूची-II
    1. 1908 2. 1931
    3. 1910 4. 1878

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	1	4
(B)	2	4	3	1
(C)	1	2	3	4
(D)	1	2	4	3

23. व्यक्तियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौनसा एक, उन व्यक्तियों का युग्म है जो अंग्रेज अधिकारियों की इंगलैण्ड में हत्या करने के आरोप में फाँसी पर लटकाये गये?
(A) राजगुरू और सुखदेव
(B) खुदीराम बोस और सूर्य सेन
(C) मदनलाल ढींगरा और ऊधम सिंह
(D) कर्तार सिंह सराबा और अशफाक उल्लाह खान

24. निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक (Founder) था?
(A) खान अब्दुल गफ्फार खान
(B) अब्दुल रब नशतर
(C) शौकतउल्लाह अंसारी
(D) खान अब्दुल कय्यूम खान

25. निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए–
1. एन. एम. जोशी 2. दीवान चमनलाल
3. शिव राव 4. वी. वी. गिरि
उपर्युक्त सभी व्यक्ति निम्नलिखित में से किस आन्दोलन में सम्बद्ध थे?
(A) साम्यवादी (Communist) आन्दोलन
(B) किसान सभा आन्दोलन
(C) मजदूर संघ (Trade union) आन्दोलन
(D) स्टेट पीपुल्स मूवमेंट

26. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए–
1. स्वराज पार्टी की स्थापना
2. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड
3. कांग्रेस-लीग समझौता
4. चौरी-चौरा घटना
इनके घटित होने का सही कालानुक्रम (Chronological sequence) है–
(A) 2, 3, 1, 4 (B) 3, 2, 1, 4
(C) 3, 2, 4, 1 (D) 2, 3, 4, 1

27. निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए–
1. बलवंतराय मेहता 2. जे. एन. सेन गुप्ता
3. शार्दूल सिंह कवीशर 4. सुधाकर राव
इनमें से कौन-कौन ऑल इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेन्स (AISPC) के प्रमुख संयोजक नहीं थे?
(A) 2 और 3 (B) 1, 2 और 4
(C) 1, 3 और 4 (D) 2, 3 और 4

28. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए–
1. अगस्त प्रस्ताव
2. पूना समझौता
3. तृतीय गोलमेज सम्मेलन
4. साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (Communal Award)
इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है–
(A) 4, 3, 2, 1 (B) 4, 2, 3, 1
(C) 1, 2, 3, 4 (D) 3, 2, 1, 4

29. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I
(a) अब्दुल कय्यूम खान (b) हकीम अजमल खान
(c) चौधरी खलीक उज्जमा (d) फजलुल हक

सूची-II
1. दिल्ली
2. बंगाल
3. यू. पी.
4. उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रान्त (NWFP)

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	1	2	3
(B)	4	1	3	2
(C)	1	4	2	3
(D)	1	4	3	2

30. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I
(a) सुभाष चन्द्र बोस (b) अबुल कलाम आजाद
(c) राजेन्द्र प्रसाद (d) जवाहरलाल नेहरू

सूची-II
1. 'इण्डिया विन्स फ्रीडम'
2. 'विदर इण्डिया'?
3. 'इण्डिया स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम'
4. 'इण्डिया डिवाइडेड'

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	4	3	2
(B)	3	2	4	1
(C)	3	1	4	2
(D)	4	1	2	3

31. सूची-I (कांग्रेस सत्र) को सूची-II (संकल्प) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I कांग्रेस सत्र (Congress Sessions)

(a) लाहौर, 1929 (b) कराची, 1931

(c) फैजपुर, 1936 (d) रामगढ़, 1940

सूची-II संकल्प (Resolutions)

1. मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम 2. राष्ट्रीय एकता

3. मौलिक अधिकार 4. पूर्ण स्वराज

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	1	4	2
(B)	4	3	1	2
(C)	4	2	1	3
(D)	1	3	2	4

32. **कथन (A) :** जनरल डायर ने जलियाँवाला बाग की भीड़ पर बिना किसी पूर्व सूचना के गोली चलाई, जब तक कि गोलियाँ खत्म नहीं हो गईं.

कारण (R) : यह गोली न केवल सेना की नैतिक हिम्मत बढ़ाने के लिए चलाई गई, बल्कि पंजाब में भय उत्पन्न करने के लिए भी.

कूट :

(A) A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है

(B) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(C) A सही है, परन्तु R गलत है

(D) A गलत है, परन्तु R सही है

33. 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में निम्नलिखित में से किसने एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र, एक राष्ट्रीय विद्यालय तथा एक राष्ट्रीय व्यायामशाला की स्थापना की एवं 'राष्ट्रीय' शब्द को लोकप्रिय बनाया ?

(A) ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर (B) राजनारायण बोस

(C) नवगोपाल मित्र (D) सत्येन्द्रनाथ टैगोर

34. निम्नलिखित में से किसने आर्य महिला सभा की स्थापना की ?

(A) राजकुमारी अमृतकौर ने

(B) नेल्ली सेनगुप्ता ने

(C) दुर्गाबाई देशमुख ने

(D) पंडिता रमाबाई ने

35. अक्टूबर 1943 में सुभाष चन्द्र बोस ने आरजी हुकूमत-ए-हिन्द की स्थापना की–

(A) रंगून में (B) सिंगापुर में

(C) जर्मनी में (D) जापान में

36. स्ट्रेची आयोग सम्बन्धित था–

(A) वर्नाकुलर प्रेस से (B) अकाल से

(C) शिक्षा से (D) स्थानीय स्वायत्त शासन से

37. बंगाल विभाजन दिवस (16 अक्टूबर, 1905) को मनाने का सुझाव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था–

(A) एकता दिवस के रूप में

(B) रक्षाबन्धन दिवस के रूप में

(C) काला-दिवस के रूप में

(D) भाईचारा दिवस के रूप में

38. निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशनों में से किस एक में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया ?

(A) बेलगाँव, 1934 (B) कलकत्ता, 1928

(C) लाहौर, 1929 (D) कराची, 1930

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया.
2. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधीजी ने भाग लिया.
3. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपरान्त गांधी-इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ.
4. साम्प्रदायिक पंचाट गोलमेज सम्मेलनों से सम्बद्ध है.

उपर्युक्त में से कौन सही है ?

(A) 1, 2 और 3 (B) 1, 3 और 4

(C) 1, 2 और 4 (D) 2, 3 और 4

40. निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इण्डियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य था ?

(A) पी. आनन्द चारलू

(B) फीरोजशाह मेहता

(C) आनन्द मोहन बोस

(D) जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर

41. निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए—

1. एनी बेसेन्ट 2. बाल गंगाधर तिलक
3. मोहम्मद अली जिन्ना 4. महात्मा गांधी

इनमें से कौन होमरूल आंदोलन के साथ सम्बद्ध थे ?

(A) 1, 2 और 4 (B) 2, 3 और 4

(C) 3 और 4 (D) 1, 2 और 3

42. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के उपरान्त राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं हुई थी–

(A) तामलुक में (B) सतारा में

(C) मुंगेर में (D) तलचर में

43. सूची-I (साहित्यिक कृतियाँ) को सूची-II (व्यक्ति) के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–

सूची-I (साहित्यिक कृतियाँ)	सूची-II (व्यक्ति)
(a) दीन मित्रा	1. सी.वी. रमन पिल्लै
(b) मार्तन्ड वर्ण	2. मुकुम राव पाटिल
(c) न्यू इण्डिया	3. विष्णु कृष्ण चिपलुन्कर
(d) निबन्धनाल	4. विपिन चन्द्र पाल

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	4	1	2
(B)	2	1	4	3
(C)	3	1	4	2
(D)	2	4	1	3

44. प्रजामण्डल अथवा ऑल इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पूर्णतः घुल-मिल गई–
(A) 1939 में कांग्रेस मंत्रिमण्डलों के त्यागपत्र के समय
(B) भारत छोड़ो आंदोलन के समापन के समय
(C) सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारम्भ के समय
(D) सत्ता हस्तांतरण के समय

45. **कथन (A)** : स्वराज दल की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुई थी.
कारण (R) : 1919 अधिनियम के अन्तर्गत सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत की थी, जबकि सी. राजगोपालाचारी तथा उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया था.
कूट :
(A) A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(B) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) A सही है, परन्तु R गलत है
(D) A गलत है, परन्तु R सही है

46. 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर आयोजित की गई थी?
(A) लखनऊ (B) दिल्ली
(C) अलीगढ़ (D) पोरबन्दर

47. निम्न में से किस भारतीय को अंग्रेजों द्वारा भारतीय सिविल सेवा से पदच्युत किया गया था?
(A) सत्येन्द्रनाथ टैगोर (B) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
(C) आर. सी. दत्त (D) दादाभाई नौरोजी

निर्देश–आगामी प्रश्न में दो वक्तव्य हैं. एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है. इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए–
कूट :
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(B) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है.
(C) A सही है, परन्तु R गलत है.
(D) A गलत है, परन्तु R सही है.

48. **कथन (A)** : साइमन कमीशन के विरोध में निकाले गए जुलूस में पुलिस द्वारा लाठी-प्रहार में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई.
कारण (R) : साइमन कमीशन में सदस्य के रूप में एक भी भारतीय शामिल नहीं था.

49. 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला वायसराय था–
(A) वेवल (B) लिनलिथगो
(C) विलिंगडन (D) ब्रैवर्न

50. असम स्वतन्त्र प्रान्त बनाया गया था, जब–
(A) कर्जन ने सन् 1905 ई. में बंगाल का विभाजन किया
(B) मिण्टो ने 1905-1906 में नये सुधार प्रस्ताव घोषित किए
(C) 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया
(D) 1919 में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए

51. सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्द्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धान्त के रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी–
(A) 1833 (B) 1853
(C) 1858 (D) 1882

52. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची-I (राष्ट्रवादी लेखक)	सूची-I (रचनाएँ)
(a) कृष्णजी प्रभाकर खाडिलकर	(1) झाँसी की रानी
(b) सुभद्रा कुमारी चौहान	(2) कीचक वध
(c) सआदत हसन मिण्टो	(3) काली सलवार
(d) वल्लथोल नारायण मेनन	(4) एन्पे गुरुनाथन

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	1	3	2
(B)	3	4	2	1
(C)	2	1	3	4
(D)	2	3	1	4

53. तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नांकित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया–
    (A) दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार
    (B) बम्बई प्रान्त में स्वदेशी आन्दोलन
    (C) सविनय अवज्ञा आन्दोलन
    (D) सामाजिक सुधारों की माँग

54. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?
    (a) चित्तू पाण्डे – भारत छोड़ो आन्दोलन
    (b) लक्ष्मी स्वामिनाथन – आई.एन.ए.
    (c) शशिभूषण राय चौधरी – असहयोग आन्दोलन
    (d) गुरुदीत सिंह – अनुशीलन पार्टी
    कूट :
    (A) 1, 2 (B) 1, 3
    (C) 2, 4 (D) 3, 4

उत्तरमाला

1. (D)	2. (B)	3. (D)	4. (B)	5. (A)
6. (D)	7. (D)	8. (B)	9. (B)	10. (C)
11. (C)	12. (A)	13. (D)	14. (A)	15. (A)
16. (C)	17. (C)	18. (A)	19. (C)	20. (A)
21. (A)	22. (C)	23. (C)	24. (A)	25. (C)
26. (C)	27. (D)	28. (B)	29. (B)	30. (C)
31. (B)	32. (A)	33. (C)	34. (D)	35. (B)
36. (B)	37. (B)	38. (D)	39. (C)	40. (C)
41. (D)	42. (C)	43. (B)	44. (B)	45. (A)
46. (B)	47. (B)	48. (B)	49. (B)	50. (C)
51. (B)	52. (C)	53. (A)	54. (A)	

संकेत

2. 1922 के बारदोली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आन्दोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई.

4. तिलक के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया था. बाद में 1920 में गांधीजी के सुझाव पर कांग्रेस संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए.

7. स्वदेशी आन्दोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के फेडरेशन हॉल में हुई.

46. 24 नवम्बर, 1919 को दिल्ली में हुई और गांधीजी अध्यक्ष चुने गए.

48. साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में ही जुलूस निकाला गया था, किन्तु विरोध जुलूस पर लाठी चार्ज तथा लाला लाजपत राय की मृत्यु एक स्वतंत्र घटना हो जाती है.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. इण्डियन एसोसियेशन की स्थापना किसने की ?
    (A) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने
    (B) विपिनचन्द्र पाल ने
    (C) बाल गंगाधर तिलक ने
    (D) महात्मा गांधी ने

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ?
    (A) 25 दिसम्बर, 1885 (B) 28 दिसम्बर, 1905
    (C) 28 दिसम्बर, 1885 (D) 1 जनवरी, 1880

3. बंगाल विभाजन कब हुआ था ?
    (A) 17 दिसम्बर, 1948 (B) 16 अक्टूबर, 1905
    (C) 15 नवम्बर, 1906 (D) 16 नवम्बर, 1910

4. ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की ?
    (A) राजा राममोहन राय
    (B) रवीन्द्रनाथ टैगोर
    (C) स्वामी दयानन्द सरस्वती
    (D) स्वामी विवेकानन्द

5. ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन् में हुई ?
    (A) 1818 (B) 1834
    (C) 1830 (D) 1828

6. राजा राममोहन राय का देहान्त कब हुआ था ?
    (A) 27 सितम्बर, 1833 (B) 26 जनवरी, 1835
    (C) 27 अक्टूबर, 1830 (D) इनमें से कोई नहीं

7. सती प्रथा का अन्त किसने किया था ?
    (A) राजा राममोहन राय ने
    (B) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने
    (C) लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने
    (D) लॉर्ड हेस्टिंग्स ने

8. स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म कब हुआ था ?
    (A) 12 जनवरी, 1824 (B) 13 जनवरी, 1830
    (C) 15 फरवरी, 1824 (D) 12 फरवरी, 1824

9. आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी ?
    (A) 7 अप्रैल, 1875 ई. (B) 8 अप्रैल, 1870 ई.
    (C) 3 अप्रैल, 1874 ई. (D) 4 अप्रैल, 1873 ई.

10. रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई ?
    (A) 1890 में (B) 1896 में
    (C) 1895 में (D) 1891 में

11. रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की ?
    (A) राजा राममोहन राय

(B) रवीन्द्रनाथ टैगोर
(C) स्वामी विवेकानन्द
(D) स्वामी दयानन्द सरस्वती

12. थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की ?
(A) लॉर्ड विलियम बैंटिंक
(B) मैडम ब्लेवेटस्की एवं कर्नल आल्कॉट
(C) लॉर्ड विलियम बैंटिंक एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स
(D) इनमें से कोई नहीं

13. थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी ?
(A) 1875 ई. में (B) 1870 ई. में
(C) 1872 ई. में (D) 1873 ई. में

14. मिसेज एनी बेसेन्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षा कब चुना गया था ?
(A) 1910 ई. में (B) 1905 ई. में
(C) 1917 ई. में (D) 1906 ई. में

15. 'भारत भारती' नामक पुस्तक के लेखक कौन थे ?
(A) रवीन्द्रनाथ टैगोर (B) बंकिमचन्द चटर्जी
(C) मैथिलीशरण गुप्त (D) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

16. लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में विधिमन्त्री कौन था ?
(A) लॉर्ड विलियम बैंटिंक (B) इलवर्ट
(C) लॉर्ड हेस्टिंग्स (D) इनमें से कोई नहीं

17. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे ?
(A) इलवर्ट (B) एनी बेसेन्ट
(C) सर ए. ओ. ह्यूम (D) इनमें से कोई नहीं

18. लाला लाजपत राय द्वारा लिखित पुस्तक है–
(A) भारत भारती (B) आनन्द मठ
(C) यंग इण्डिया (D) इनमें से कोई नहीं

19. बम्बई से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था ?
(A) सर ए. ओ. ह्यूम (B) एनी बेसेन्ट
(C) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (D) डब्ल्यू. सी. बनर्जी

20. सूरत विभाजन कब हुआ ?
(A) 1910 में (B) 1907 में
(C) 1905 में (D) 1911 में

21. 12 जून, 1905 को भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की ?
(A) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने (B) डब्ल्यू. सी. बनर्जी ने
(C) गोपालकृष्ण गोखले ने (D) इनमें से कोई नहीं

22. 'Poverty and Unbritish Rule in India' नामक पुस्तक के लेखक थे–
(A) दादा भाई नौरोजी (B) गोपालकृष्ण गोखले
(C) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (D) एनी बेसेन्ट

23. सन् 1885 ई. में मुम्बई प्रेसिडेन्सी एसोसिएशन की स्थापना किसने की ?
(A) दादा भाई नौरोजी (B) फीरोजशाह मेहता
(C) श्रीनिवास शास्त्री (D) इनमें से कोई नहीं

24. ब्रिटिश सरकार ने 1894 में सी.आई.आई. और सन् 1904 ई. में के.सी.आई. के खिताब से किसको विभूषित किया ?
(A) दादा भाई नौरोजी (B) फीरोजशाह मेहता
(C) श्रीनिवास शास्त्री (D) गोपालकृष्ण गोखले

25. सन् 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कौन सभापति चुने गये ?
(A) गोपालकृष्ण गोखले (B) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
(C) फीरोजशाह मेहता (D) दादा भाई नौरोजी

26. 'भारत दुर्दशा' नामक पुस्तक के लेखक थे–
(A) रवीन्द्रनाथ ठाकुर (B) प्रेमचन्द
(C) यशपाल (D) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

27. सर ए. ओ. ह्यूम ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था ?
(A) गोविन्द रानाडे (B) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
(C) गोपालकृष्ण गोखले (D) इनमें से कोई नहीं

28. सन् 1893 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे ?
(A) गोपालकृष्ण गोखले (B) विपिनचन्द्र पाल
(C) दादा भाई नौरोजी (D) फीरोजशाह मेहता

29. लन्दन इण्डियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी ?
(A) विपिनचन्द्र पाल ने (B) दादा भाई नौरोजी ने
(C) फीरोजशाह मेहता ने (D) गोपालकृष्ण गोखले ने

30. सन् 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे–
(A) विपिनचन्द्र पाल (B) बालगंगाधर तिलक
(C) डॉ. रासविहारी बोस (D) इनमें से कोई नहीं

31. सन् 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट किसने बनाया ?
(A) लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने
(B) लॉर्ड कर्जन ने
(C) लॉर्ड हेस्टिंग्स ने
(D) सर. ए. ओ. ह्यूम ने

32. 'आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन्स' नामक ग्रन्थ किसने लिखा ?
(A) लाला लाजपत राय
(B) लोकमान्य बालगंगाधर तिलक
(C) विपिनचन्द्र पाल
(D) डॉ. रासविहारी बोस

33. अप्रैल सन् 1916 में स्वराज्य आन्दोलन किसने प्रारम्भ किया ?
   (A) बाल गंगाधर तिलक (B) लाला लाजपत राय
   (C) दादा भाई नौरोजी (D) इनमें से कोई नहीं

34. अनरैस्ट इण्डियन के लेखक सर वैलेन्टाइन शिरोल ने किसको भारतीय अशान्ति का जनक कहा था ?
   (A) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (B) बाल गंगाधर तिलक
   (C) लाला लाजपत राय (D) डब्ल्यू. सी. बनर्जी

35. लोकमान्य तिलक ने 20 अप्रैल, 1920 को किस दल की स्थापना की थी ?
   (A) भारतीय सेवक संघ
   (B) नव राष्ट्रीय दल
   (C) कांग्रेस लोकतन्त्रीय दल
   (D) इनमें से कोई नहीं

36. 'अनहैप्पी इण्डिया' के लेखक कौन हैं ?
   (A) बाल गंगाधर तिलक (B) लाला लाजपत राय
   (C) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (D) दादा भाई नौरोजी

37. लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी ?
   (A) 17 नवम्बर, 1928 (B) 19 दिसम्बर, 1920
   (C) 16 नवम्बर, 1922 (D) 14 दिसम्बर, 1919

38. 17 नवम्बर, 1959 में किसने पंजाब में लुधियाना के गाँव में लाला लाजपत का स्मारक स्थापित किया ?
   (A) पं. जवाहरलाल नेहरू ने
   (B) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने
   (C) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने
   (D) लाल बहादुर शास्त्री ने

39. विपिनचन्द्र पाल का जन्म किस जिले में हुआ था ?
   (A) सिलहट (B) मेरठ
   (C) टंकारा (D) पोरबन्दर

40. '1857 का स्वाधीनता संग्राम' नामक पुस्तक किसने लिखी ?
   (A) वीर सावरकर (B) चन्द्रशेखर आजाद
   (C) सुखदेव (D) लाला लाजपत राय

41. 23 अप्रैल, 1916 को पूना में 'होमरूल लीग' की शुरूआत सर्वप्रथम किसने की ?
   (A) लाला लाजपत राय (B) एनीबेसेन्ट
   (C) बाल गंगाधर तिलक (D) इनमें से कोई नहीं

42. सविनय अवज्ञा आन्दोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया ?
   (A) पं. जवाहरलाल नेहरू (B) महात्मा गांधी
   (C) लाल बहादुर शास्त्री (D) इनमें से कोई नहीं

43. गांधीजी के नेतृत्व में सन् 1942 ई. में कौनसा आन्दोलन चलाया गया ?
   (A) भारत छोड़ो आन्दोलन
   (B) सविनय अवज्ञा आन्दोलन
   (C) असहयोग आन्दोलन
   (D) इनमें से कोई नहीं

44. मद्रास में 'अखिल भारतीय होमरूल लीग' की स्थापना कब हुई ?
   (A) 1 दिसम्बर, 1916 (B) 1 सितम्बर, 1916
   (C) 2 दिसम्बर, 1917 (D) 2 सितम्बर, 1918

45. असहयोग आन्दोलन कब शुरू हुआ था ?
   (A) 1925 में (B) 1926 में
   (C) 1920 में (D) 1922 में

46. गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था ?
   (A) 1930 में (B) 1931 में
   (C) 1929 में (D) 1920 में

47. द्वितीय महायुद्ध कब प्रारम्भ हुआ ?
   (A) 3 सितम्बर, 1939 (B) 4 सितम्बर, 1940
   (C) 4 दिसम्बर, 1948 (D) 4 अप्रैल, 1905

48. मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी ?
   (A) 1907 में (B) 1910 में
   (C) 1906 में (D) 1911 में

49. शायर अमीर अली ने नेशनल मोहम्डन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी ?
   (A) 1877 में (B) 1879 में
   (C) 1875 में (D) 1870 में

50. प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी ?
   (A) डॉ. आत्मा पाण्डुरंग (B) वीर सावरकर
   (C) राजा राममोहन राय (D) स्वामी विवेकानन्द

उत्तरमाला

1. (A)	2. (C)	3. (B)	4. (A)	5. (D)
6. (A)	7. (A)	8. (A)	9. (A)	10. (B)
11. (C)	12. (B)	13. (A)	14. (C)	15. (C)
16. (B)	17. (C)	18. (C)	19. (D)	20. (B)
21. (C)	22. (A)	23. (B)	24. (B)	25. (A)
26. (D)	27. (A)	28. (C)	29. (B)	30. (C)
31. (B)	32. (B)	33. (A)	34. (C)	35. (C)
36. (B)	37. (A)	38. (B)	39. (A)	40. (A)
41. (C)	42. (B)	43. (A)	44. (B)	45. (C)
46. (B)	47. (A)	48. (C)	49. (C)	50. (A)

6

गांधीजी एवं उनकी विचारधारा
(Gandhiji and his thoughts)

[जन जुटाव के लिए गांधीजी द्वारा अपनाया गया तरीका-खिलाफत एवं असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं भारत छोड़ो आन्दोलन, राष्ट्रीय आन्दोलन में अन्य विचारधाराएँ—क्रान्तिकारी आन्दोलन, वामपंथ, सुभाषचन्द्र बोस तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना

(Gandhian techniques of mass-mobilisation Khilafat and Non-Co-operations Movement, Civil Disobedient and Quit India Movement, Other Strands in the National Movement—Revolutionaries, the Left, Subhash Chandra Bose and the Indian National Army)]

गांधीजी एवं उनकी विचारधारा

महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय क्षितिज पर आगमन बीसवीं सदी के दूसरे दशक के अंत में हुआ. उन्होंने जिस राजनीतिक संघर्ष की शुरूआत की, उसका प्रशिक्षण उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के प्रवासकाल के दौरान प्राप्त किया था. 1891 ई. में वे वकालत पास करके इंग्लैण्ड से भारत लौटे और अभिभापक के रूप में स्थापित होने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली. जब उन्होंने यह देखा वे इस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्होंने नेपाल की दादा अब्दुल्लाह एण्ड कम्पनी का यह प्रस्ताव मान लिया कि वे अफ्रीका में अदालत में पेश एक मामले में उनके सलाहकार हों. दक्षिण अफ्रीका में पहुँचने के थोड़े दिन बाद ही उन्हें एक ऐसा कटु अनुभव हुआ कि जो उनके जीवन मार्ग को ही बदल गया. वह अनुभव केवल उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में उनकी भावना को आघात पहुँचाने वाला था. इससे क्षुब्ध होकर उनका मन आंदोलित हो उठा और उन्होंने जाति भेदभाव को दूर करने के लिए तथा भारतीयों के ओहदे को ऊँचा उठाने का संकल्प कर लिया.

दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे थे, वे अंग्रेजों की जातीय भेदभाव की नीति से त्रस्त थे. इस भेदभाव की नीति का विरोध गांधीजी ने शुरू किया. गांधीजी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट होने के बाद भी ट्रेन से नीचे उतार दिया गया, होटल में कमरा चाहने पर उन्हें जवाब मिला कि कमरा खाली नहीं है. गांधीजी ने प्रिटोरिया में भारतीयों की बैठक आयोजित करके उनसे अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करने की अपील की. जब वे प्रिटोरिया में अपने मुवक्किल का मुकदमा समाप्त होने पर भारत लौटने की तैयारी करने लगे तो इससे पूर्व ही भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने का मामला उठ खड़ा हुआ. इसके अलावा उन पर 3 पौण्ड प्रतिवर्ष का मतदान टैक्स लगाया गया. इस प्रकार का भेदभाव गांधीजी से सहन नहीं हुआ और वे करीब महीने भर के लिए वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए, किन्तु उनके महीने भर का पड़ाव वर्षों में बदल गया और वे करीब 22 वर्ष बाद अफ्रीका से लौटे. दक्षिणी अफ्रीका में गांधीजी ने सत्याग्रह आंदोलन किया. गांधीजी के दक्षिणी अफ्रीका के संघर्ष की कहानी के इस प्रथम दौर में (1894-1906) उनकी राजनीतिक गतिविधियों की प्रणाली नरम रही. इस दौरान वे अपने कार्यों के सम्बन्ध में सरकार को ज्ञापन और याचिकाएँ भेजते रहे. उनका विश्वास था कि उनकी समस्याओं पर सरकार अवश्य ध्यान देगी. इसके अलावा भारतीयों को एक सूत्र में बाँधने के उद्देश्य से उन्होंने 'नेशनल भारतीय कांग्रेस' का गठन किया और 'इंडियन ओपिनियन' नामक अखबार

निकालने की प्रक्रिया शुरू की. सुमित सरकार की ओर से उनके आंदोलन को अनिवार्यतः व्यापारियों व वकीलों के आंदोलन की संज्ञा दी गई.

गांधीजी के द्वारा चलाए गए अफ्रीका संघर्ष के दूसरे चरण की शुरूआत 1906 ई. से हुई. इस समय तक उपनिवेशों की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो चुका था और उन्हें स्वायत्तता भी प्राप्त हो गई थी. 1906 ई. के बाद गाँधीजी ने एक नई शुरूआत की. यहीं से मूल गांधीवादी प्रणाली की शुरूआत मानी जाती है. दक्षिणी अफ्रीका में गाँधीजी ने टाल्सटॉय में फार्म और फिनिक्स सेटमेंट की स्थापना की तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अहिंसक सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया गया. इस कार्यक्रम के तहत विशिष्ट कानूनों के शान्तिपूर्ण उल्लंघन, सामूहिक हड़ताल, गिरफ्तारियां एवं मार्च निकालने की योजना बनाई गई थी. इसके समग्र प्रभाव का दोहरा स्वरूप था जन सामान्य का उभार, किंतु साथ ही जन-गतिविधियों को नेता द्वारा पूर्व निर्धारित सीमाओं तक और सर्वोपरि अहिंसक पद्धतियों तक ही कड़ाई से सीमित रखना. 1906 ई. के ट्रांसवाल के पंजीयन अध्यादेश के अनुसार हर भारतीय का पंजीकरण करवाना अनिवार्य था. भारतीयों ने गांधीजी के नेतृत्व न मानने का निर्णय किया. इसी दरम्यान सरकार की ओर से एक और कानून बनाया गया जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकना था. दो और मुद्दे थे, जिन पर गांधीजी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया. पहला, जो विवाह ईसाई पद्धति से नहीं हुए थे उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया तथा दूसरा, भूतपूर्व अनुबंधित श्रमिकों पर तीन पाउंड का कर लगाया गया था. इसके एवज में गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था. तात्कालिक सरकार से कई बार समझौता वार्ता होने का परिणाम यह हुआ कि गाँधीजी की माँगें मान ली गई. भारतीयों पर तीन पौंड का टैक्स खत्म करने, भारतीय विवाहों को वैध मानने, अप्रवास एवं निवास नियंत्रणों में ढील देने तथा शराबबंदी प्रथा को बंद करने जैसी माँगें मुख्य रूप से मान ली गई.

महात्मा गांधी का वापस भारत आगमन–46 वर्ष की अवस्था में जनवरी, 1915 ई. में महात्मा गांधी का वापस भारत आगमन हुआ. उन्होंने अपने कार्यों को निर्विघ्न सम्पन्न करने के लिए भारत की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया. गोखले की सलाह पर उन्होंने एक वर्ष शान्तिपूर्वक बिना किसी आंदोलन को क्रियान्विति देकर बिताया. 1916 ई. में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई. 1917 ई. में उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के आधार पर दो प्रमुख सफलताएँ प्राप्त कीं. पहली, भारतीय मजदूरों को बलपूर्वक अंग्रेजी उपनिवेशों में काम करने के लिए ले जाने की पद्धति को बंद करवाया और चम्पारन (बिहार) में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करवाया. चम्पारन के बाद अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को सफल बनाना और खेड़ा जिले में कृषकों को लगान में छूट दिलवाना उनके अहिंसात्मक सत्याग्रह की ही सफलता थी.

गाँधीजी का पूर्व के अनुभव–19वीं शताब्दी की शुरूआत में चम्पारन में अंग्रेजी बागान मालिकों ने एक अनुबंध के तहत अपनी जमीन के 3/20 वें हिस्से पर नील की खेती करने को बाध्य कर दिया था. इसको तिनकठिया पद्धति कहा जाता था, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक नील की माँग काफी कम हो गई. इसका परिणाम यह हुआ कि बागान मालिक और किसान दोनों ही इसकी खेती से छुटकारा पाना चाहते थे. अंग्रेज बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैरकानूनी करों की दरें काफी बढ़ा दीं जिससे किसानों के साथ किए गए अनुबंध से वे मुक्त हो सकें. चम्पारन के किसानों ने गांधीजी को आमंत्रित किया. सरकार की ओर से गांधीजी के चम्पारन प्रवेश पर रोक लगा दी गई, लेकिन उन्होंने इस आदेश की अवहेलना की. सरकार ने इस विषय को ज्यादा तूल देना उचित नहीं समझा और गाँधीजी को चम्पारन में प्रवेश करने की अनुमति दे दी. गांधीजी ने चम्पारन पहुँचकर किसानों की समस्या का जायजा लिया और उस सम्बन्ध में अंग्रेज सरकार से बातचीत करके उसका हल निकाला, फलतः तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया.

19वीं शताब्दी के अंत में गुजरात के खेड़ा जिले के किसान जो कि अनाज, कपास तथा तम्बाकू का उत्पादन करते थे, अकाल पड़ने के कारण बड़े असहाय हो गए. उनके लिए सरकार के लिए मालगुजारी देना बहुत कठिन हो गया. आम उपभोग की वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए थे. इस मामले को भी गांधीजी ने अपने हाथ में लिया. उन्होंने सर्वेट ऑफ इंडिया सोसायटी के सदस्यों के साथ पूरी जाँच-पड़ताल की और अपने सहयोगियों के साथ किसानों को सलाह दी कि वे इस सरकारी आदेश के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें. सरकार ने लगान न देने वाले लोगों की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया, इस पर गांधीजी ने सरकार से कहा कि जो किसान लगान देने की स्थिति में हैं वे स्वतः ही लगान दे देंगे, बशर्ते कि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दें. इस आदेश को सरकार ने मान लिया और गरीब किसानों का लगान माफ कर दिया गया.

फरवरी 1918 ई. में अहमदाबाद के मिल मालिकों ने कीमतें बढ़ने के बाद भी 1917 ई. से दिए जाने वाले बोनस को बंद करने की मंशा जाहिर की. मजदूरों की माँग यह थी कि बोनस के स्थान पर उनकी मजदूरी में 35 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, जबकि मिल मालिक 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करना नहीं चाहते थे. गांधीजी ने इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार किया. मिल मालिकों

ने वादाखिलाफी करते हुए 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की ही हामी भरी. इसका परिणाम यह हुआ कि गांधीजी के नेतृत्व में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी. इस हड़ताल में प्रमुख बात यह रही कि गाँधीजी ने इसमें सर्वप्रथम भूख हड़ताल के अस्त्र को काम में लिया. भूख हड़ताल का परिणाम यह रहा कि मिल मालिकों को मजदूरों की माँग माननी पड़ी.

इस प्रकार के नेतृत्वों से गाँधीजी आम जनता के सम्पर्क में आए और उन्हें तरह-तरह के आंदोलनों के माध्यम से जनता की समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया. इन आंदोलनों के दौरान बहुत से कार्यकर्ता जैसे राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, इंदुलाल याज्ञिक और शंकर लाल बैंकर आदि आजीवन गाँधीजी के अनुयायी बन गए. इन आंदोलनों ने गांधीजी को एक जनप्रिय नेता तथा भारतीय राजनीति के प्रमुख स्तम्भ के रूप में स्थापित कर दिया.

असहयोग आंदोलन

प्रथम विश्व युद्ध की शुरूआत पर गाँधीजी 1915 ई. में भारत लौटे थे. इस युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों को अपना समर्थन दिया. उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें 'केसर ए हिंद' की उपाधि प्रदान की. गांधीजी ने 1916 ई. में साबरमती में शुरू किया गया आश्रम उनकी तमाम गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया. उनके द्वारा अनेक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनके कारण उन्हें एक जननायक के रूप में भारतीय जनता मानने लगी. इसके साथ ही कुछ ऐसी ही घटनाओं का भी प्रमुख स्थान रहा जिन्होंने गांधीजी को असहयोग आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया और राजनीति के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ.

असहयोग आंदोलन की भूमिका

रॉलेट एक्ट–युद्ध के समय एक ओर तो सरकार मांटेग्यू घोषणा के आधार पर भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देकर अपनी उदारता की भावना प्रदर्शित कर रही थी तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन कर रही थी. इस दिशा में सरकार का एक नया कार्य यह था कि न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का उपाय सुझा सके. समिति ने इसके लिए कठोर नियमों की सिफारिश की. अप्रैल, 1818 ई. में समिति की रिपोर्ट आई. भारतीयों के कड़े विरोध के बाद भी सरकार ने 21 मार्च, 1919 ई. को रॉलेक्ट एक्ट पास कर दिया. भारतीय नेताओं ने इसे 'काले कानून' की संज्ञा देते हुए विरोध प्रदर्शित किया. इसके विरोध में भारतीय नेताओं ने एक नारा दिया–"कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं". मदनमोहन मालवीय मजरूल, हक और जिन्ना ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका से इसके विरोध में त्यागपत्र दे दिया. गांधीजी ने इसका विरोध करने के लिए समूचे देश में हड़ताल करने का ऐलान कर दिया. इसके परिणामस्वरूप दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों पर हड़ताल और आयोजनों के रूप में इसका विरोध दर्शाया गया. सरकार की ओर से इसे दबाने के प्रयास किए गए. अनेक स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएँ हुईं. सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलाईं, अनेक लोग मारे गए. सबसे भीषण स्थिति पंजाब में हुई. जब गांधीजी ने वहाँ की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से वहाँ जाने की योजना बनाई तो उनके पंजाब-प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया. पंजाब के उप गवर्नर जनरल ओ. डायर ने पूरे पंजाब में आतंक का राज्य स्थापित कर दिया. इसी दरम्यान 9 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर हिंदू-मुसलमानों ने संयुक्त रूप से जुलूस निकाला.

इससे घबराकर सरकार ने दो प्रमुख नेताओं, डॉ. सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार करके अमृतसर से निर्वासित कर दिया. इस घटना से लोगों में रोष बढ़ गया. निर्वासन का विरोध करने के लिए एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिस पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं. इससे क्रुद्ध होकर भीड़ ने अनेक सरकारी भवनों, पोस्ट ऑफिसों तथा बैंकों में आग लगा दी और कुछ अंग्रेजों की हत्या भी कर दी.

जलियाँवाला बाग हत्याकांड–नित प्रतिदिन बढ़ते जनाक्रोश को दबाने के लिहाज से जनरल डायर 11 अप्रैल को अमृतसर पहुँचा. उसने वहाँ पहुँचते ही समूचे अमृतसर में फौजी शासन लागू कर दिया. इस आदेश की उसने विधिवत् घोषणा भी नहीं करवाई. अनेक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. भारतीय नेताओं की ओर से पुलिस ज्यादती और निर्वासन के विरोध में 13 अप्रैल की संध्या को जलियांवाले बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया. इस आमसभा में लगभग 20 हजार लोगों ने भाग लिया. निहत्थी भीड़ के साथ महिलाएँ भी अपने बच्चों के साथ इस आमसभा में पहुँची. आमसभा की कार्रवाई के मध्य में ही जनरल डायर अपने सौ सिपाहियों और दो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहाँ पहुँचा. उसने कुछ सैनिकों को बाग के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कुछ को गोलियाँ चलाने की आज्ञा दे दी. इस समय शाम के करीब 5 बजे थे. दस मिनट तक हुई गोलीबारी में करीब 1650 चक्र गोलियाँ चलाई गईं. इस घटना में करीब एक हजार लोग मारे गए तथा घायलों का तो ओर-छोर ही नहीं था. इस घटना को अंजाम देकर घायलों को वहीं छोड़कर डायर वहाँ से चलता बना. 15 अप्रैल को समूचे अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया.

उन्होंने प्रयास ऐसा किया कि पंजाब से बाहर इस घटना की खबर तक नहीं लगे. पंजाब में बाहर से प्रवेश करने वालों को पाबंद कर दिया गया. इस घटना से भी सैनिक प्रशासन को संतोष नहीं हुआ, बेकसूर लोगों को कोड़े लगवाए गए, पेट के बल चलने को मजबूर किया गया, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों पर भी घोर अत्याचार किए गए. सरकार ने जनरल डायर के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उसको 20,000 की थैली भेंट की. इससे भारतीयों में असंतोष और अधिक बढ़ गया. कांग्रेस के द्वारा एक जाँच समिति नियुक्त की गई. बाद में अंग्रेजों के प्रति बढ़ते विरोध को ध्यान में रखकर सरकार ने भी 'हंटर कमेटी' बहाल की. इस समिति ने भी डायर के कार्य को उचित नहीं ठहराया. गिलबर्ट स्लेटर के शब्दों में' "अपने कार्यों से डायर ने पंजाब को बचा लिया मगर भारत को खो दिया". बाद में अमृतसर की घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गांधीजी ने भी कहा था– "प्लासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और अमृतसर ने उसे हिला दिया".

खिलाफत आंदोलन के कारण

तुर्की का खलीफा समूचे विश्व के सुन्नी मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था. भारतीय मुसलमान भी धार्मिक बंधनों के आधार पर उससे जुड़े हुए थे. प्रथम विश्व युद्ध होते ही भारतीय मुसलमानों के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया था. युद्ध की शुरूआत के समय तो ये लोग ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार थे. प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड की ओर से मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया गया था कि सरकार तुर्की की अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखेगी. प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी के साथ मिलकर भाग लिया. 1918 ई. से मित्रराष्ट्रों की विजय व जर्मनी की हार होने लगी. जर्मनी और तुर्की दोनों को समर्पण करना पड़ा. प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होने के बाद ब्रिटेन का रुख ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की के खलीफा के प्रति बदल गया. इंग्लैण्ड और फ्रांस ने अन्य विजित शक्तियों के साथ मिलकर साम्राज्य का बँटवारा कर दिया. इतना ही नहीं ब्रिटेन के उकसावे पर अरबों ने भी खलीफा के विरुद्ध बगावत कर दी. इस्लाम की पवित्र भूमि, अरब प्रदेश पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मैंडेट पद्धति द्वारा अधिकार कर लिया. इन घटनाओं ने भारतीय मुसलमान में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति क्रोध भड़का दिया. वे तुर्की के सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए तैयार हो गए.

खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य–खिलाफत आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य खलीफा की सर्वोच्चता और उसकी शक्ति को स्थापित करना था. इसका आरम्भ एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन के रूप में हुआ, लेकिन शीघ्र ही वह साम्राज्यवादी और राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग बन गया. खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में आंदोलन चलाए गए. जगह-जगह खिलाफत कमेटियाँ बनाई गई. दिसम्बर 1918 ई. में कांग्रेस और लीग की एक साथ बैठकें हुई. डॉ. एम. ए. अंसारी ने अरब प्रदेश को खलीफा को लौटाने की माँग की. कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया. खिलाफत के आंदोलन ने कांग्रेस तथा लीग के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम एकता को समर्थन दिया. गांधीजी ने भी इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया. वे 1919 ई. में दिल्ली में हुए खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए. 1920 ई. में हिन्दू तथा मुस्लिमों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिला, माँगें उसके सामने रखीं, परन्तु कोई हल नहीं निकला. इसलिए जून 1920 ई. में खिलाफत कमेटी ने असहयोग का निर्णय किया. एक अगस्त 1920 ई. से गांधीजी ने असहयोग आंदोलन का भी निर्णय लिया. इसके साथ ही खिलाफत कमेटी ने भी असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दिया.

असहयोग आंदोलन की तरह ऊपरी तौर पर खिलाफत आंदोलन भी विफल हो गया. यह आंदोलन 1924 ई. में समाप्त हुआ इस आन्दोलन ने उदार राष्ट्रवादी मुसलमानों को राष्ट्रीय संग्राम में शरीक होने का मौका दिया जिसको इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जाता है.

असहयोग आंदोलन की शुरूआत–प्रथम युद्ध के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट, अकाल, महामारी, 1919 ई. के सुधारों से व्याप्त असंतोष का वातावरण, सरकार की दमन नीति तथा भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना ने असहयोग आंदोलन के लिए पर्याप्त माहौल पैदा कर दिया. 1920 ई. में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में गाँधीजी ने बहिष्कार और असहयोग की नीति का ऐलान कर दिया. विरोध स्वरूप गांधीजी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया. दिसम्बर 1920 ई. के दिन नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ने गांधीजी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी. असहयोग के दो पक्ष थे– प्रथम, रचनात्मक तथा द्वितीय, विध्वंसात्मक. पहले वर्ग में स्वदेशी को प्रोत्साहन देने, असहयोग आंदोलन के लिए 'तिलक कोष' में एक करोड़ रुपए की राशि एकत्र करने, स्वयंसेवकों का दल तैयार करने, चरखा एवं कताई-बुनाई का प्रसार-प्रचार करने, राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने, हिंदू-मुस्लिम एकता बढ़ाने जैसे कार्यक्रम रखे गए तथा दूसरे वर्ग, विध्वंसात्मक कार्रवाई में स्थानीय संस्थाओं से त्यागपत्र देने, सरकारी उत्सवों व समारोहों का बहिष्कार, अदालतों तथा विद्यालयों की उपेक्षा तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर मेसोपोटामिया युद्ध में भर्ती होने से इनकार करने को कहा गया. 1920 ई. में होने वाले चुनावों के बहिष्कार की भी योजना बनाई गई.

असहयोग आंदोलन का आरम्भ–इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधीजी ने ही किया. सरकारी उपाधि कैसर-ए-हिन्द को उन्होंने लौटा दिया. उनका अनुसरण करते हुए कविवर रबीन्द्रनाथ ठाकुर सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी सम्मानजनक उपाधियाँ लौटा दीं. मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, राजेन्द्र प्रसाद जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी. हजारों छात्रों ने स्कूलों से नाता तोड़ लिया. विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई. अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई, जिनमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्व-विद्यालय आदि प्रमुख थे. लाखों की संख्या में स्वयंसेवक तैयार हुए. जगह-जगह पर प्रदर्शन तथा हड़तालों का आयोजन हुआ.

सरकार द्वारा दमन की नीति तथा असहयोग आंदोलन का समापन–जब 1921 ई. तक असहयोग आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया था तो उसी दौरान नवम्बर, 1921 ई. में युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का बम्बई आगमन हुआ. उनके विरोध में जुलूस निकाले गए, प्रदर्शन तथा हड़ताल की गई. सरकार की ओर से की गई गोलीबारी में अनेक व्यक्ति मारे गए. सरकार आंदोलनकर्ताओं का दमन करने का मानस बना चुकी थी, उसने कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया. हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी. गिरफ्तारियों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि उन्हें रखने के लिए जेल में जगह तक नहीं रही. सिर्फ गांधीजी के अलावा सभी आंदोलनकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए थे. 1922 ई. की फरवरी को गांधीजी ने वायसराय को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि अगर सरकार अपना दमनचक्र बंद नहीं करेगी तो उन्हें बारदोली (गुजरात) में नया आंदोलन सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ेगा. सरकार के लिए यह विपत्ति का समय था. इसी दरम्यान 5 फरवरी, 1922 ई. को चौरी-चौरा (गोरखपुर) की दुर्घटना हो गई. यहाँ भी सरकार की गोलियों से अनेक लोग हताहत हो गए. इस घटना के बारे में सुनकर उन्होंने तत्काल असहयोग आन्दोलन बंद कर दिया. उनके इस निर्णय से हालांकि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल, चितरंजन दास, सुभाष चन्द्र बोस आदि ने इस निर्णय को अनुचित बताया. परन्तु गांधीजी यह समझते थे कि सभी नेताओं के जेल चले जाने पर जनता दिशाहीन एवं हिंसक हो गई थी. हिंसा के द्वारा सरकार का मुकाबला करना सम्भव नहीं था, अतः आंदोलन को बन्द करना ही उचित था.

सविनय अवज्ञा आंदोलन–महात्मा गांधी ने नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने मार्च, 1930 ई. से एक नई दिशा तय करना निश्चित किया. इस नई दिशा की शुरूआत सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं डांडी मार्च से हुई.

आंदोलन के कारण–तात्कालिक राजनीतिक एवं आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण इस आंदोलन की क्रियान्विति हुई.

तात्कालिक राजनीतिक कारण–1928 ई. में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार किए जाने के समय से घटनाचक्र तेजी से चला. नेहरू रिपोर्ट से कांग्रेस और लीग दोनों ही असंतुष्ट थे. एक तरफ भारत में नई शक्तियों का उदय हो रहा था तो दूसरी ओर कांग्रेस में अन्दर ही अन्दर विद्रोह की भावना पनपने लगी थी. छात्र आंदोलन, कम्युनिस्ट विचारधारा का जन्म, छात्र शक्ति का उदय, किसानों व मजदूरों का शोषण आदि से तात्कालिक परिस्थितियाँ विषम हो चली थीं. स्वतंत्रता की माँग बढ़ने लगी थी. इस भावना को सही दिशा देने एवं उसका सही उपयोग करने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाना जरूरी था, अतः गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरूआत की.

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी का प्रभाव–विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी का भारत में यह प्रभाव पड़ा कि यहाँ की समूची अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई. अनाज का उत्पादन कम हो गया, मूल्यों में वृद्धि हो गई, निर्यात कम हो गया. इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने धन का निष्कासन कम नहीं किया. विदेशी वस्तुओं के आगमन से यहाँ के अनेक कारखाने बन्द हो गए तो कुछ का उत्पादन कम हो गया. किसान तो पहले से ही सरकारी दमन से ग्रस्त थे. इसी क्रम में इस अर्थव्यवस्था से पूँजीपति व मध्यमवर्ग भी त्रस्त होने लगा. देश का वातावरण दिन-प्रतिदिन सरकार विरोधी होता गया. इस प्रकार सरकार के प्रति विषम परिस्थितियों का फायदा उठाकर गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरूआत की.

भारत की प्रलयकारी स्थिति–भारत की तात्कालिक स्थिति इतनी विस्फोटक थी कि आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ने लगी थीं. मेरठ षड्यंत्र केस तथा लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधाराओं को और उग्र बना दिया.

सरकार की गलत दमन नीति–अब सरकार कांग्रेस तथा अन्य संगठनों की राष्ट्रीय भावना से तंग आ चुकी थी. वह नित नए दमन के उपाय ढूँढ़ती. इसी संदर्भ में सरकार ने जनवरी 1929 ई. में 'पब्लिक सेफ्टी बिल' या 'काला कानून' पेश किया, जिसे विधानमंडल ने पूर्व में अस्वीकार कर दिया. इस बिल से भी जनता में असंतोष फैला.

लॉर्ड इरविन की घोषणा–31 अक्टूबर, 1929 ई. को लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा की कि "अंग्रेजी सरकार यह समझती है कि 1917 ई. की घोषणा में यह बात अन्तर्निहित है कि भारत को औपनिवेशक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा और इसकी घोषणा करने का अधिकार मुझे दिया गया है". इस घोषणा से भारतीयों में एक नई चेतना का प्रस्फुरण हुआ.

इरविन की इस घोषणा से गांधी, जिन्ना विट्ठलभाई पटेल इत्यादि ने वायसराय से मुलाकात की, लेकिन उन्हें संतोष-जनक उत्तर नहीं दिया गया और दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद में इरविन की घोषणा (दिल्ली घोषणा-पत्र) पर असंतोष व्यक्त हो गया.

कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन–लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने सरकार से 'पूर्ण स्वाधीनता' की माँग रखी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा– "आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य. हमारे लिए स्वतंत्रता के मायने है ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता". 31 दिसम्बर, 1929 ई. की मध्य रात्रि को रावी नदी पर तिरंगा फहराया गया तथा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई. फरवरी, 1930 ई. में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी को उचित समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का अधिकार दे दिया. लाहौर अधिवेशन से प्रभावित होकर ही खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने भी कांग्रेस में शामिल होने का निश्चय किया.

सरकार के साथ समझौते का प्रयास–गांधीजी ने आंदोलन शुरू करने से पूर्व वायसराय से बातचीत कर समझौता करने का प्रयास किया. उन्होंने 11 सूत्रीय माँगों का प्रारूप वायसराय के समक्ष रखा और कहा कि यदि सरकार इनको मान लेगी तो आंदोलन नहीं किया जाएगा. उनकी माँगें निम्नलिखित थीं–

1. लगान की राशि आधी की जाए
2. विनिमय की दर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए
3. सैनिक खर्च में 50% की कमी हो
4. असैनिक कर्मचारियों के वेतन में कमी हो
5. रक्षात्मक शुल्क लगे और विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए.
6. भारतीय समुद्रतट केवल भारतीय जहाजों के लिए ही सुरक्षित हो.
7. गुप्तचर विभाग या तो समाप्त कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो.
8. भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने का अधिकार मिले तथा इसके लिए अनुमति पत्र प्रदान किए जाएँ.
9. नमक कर समाप्त किया जाए
10. नशीली वस्तुओं की बिक्री बंद की जाए
11. सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए और निर्वासित भारतीयों को स्वदेश आने की अनुमति दी जाए.

गांधीजी के इस पत्र पर वायसराय ने कोई ध्यान नहीं दिया और उनसे मिलने से भी मना कर दिया. इसी बीच सुभाष चन्द्र बोस व अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, फलतः गांधीजी को अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा. उन्होंने अपने आंदोलन की शुरूआत दांडी नामक गांव में समुद्र के जल से नमक बनाकर करने का निश्चय किया. 12 मार्च, 1930 ई. को वे अपने 79 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 200 मील की दूरी पर समुद्र तट पर बसे दांडी के लिए निकल पड़े. उनके साथ सैकड़ों लोग थे. सुभाष चन्द्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के 'पेरिस मार्च' व मुसोलिनी के 'रोम मार्च' से की है.

5 अप्रैल, 1930 ई. को गांधीजी ने दांडी पहुँचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्वक सरकारी कानून का उल्लंघन किया. इस घटना से समूचे भारत में आंदोलन की लहर-सी दौड़ गई. जगह-जगह प्रदर्शन तथा जुलूसों का आयोजन हुआ. जिसके फलस्वरूप सत्याग्रहियों को पकड़-पकड़ कर जेल में भरा जाने लगा. अनेक लोगों को गोली का शिकार होना पड़ा. 15 मई, 1930 ई. को स्वयं गांधीजी भी गिरफ्तार हुए. उनके गिरफ्तार होने से आंदोलन और भड़क उठा. चटगांव पर सूर्यसेन एवं उनके साथियों ने अधिकार कर लिया. पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में गढ़वाली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया. सरकार को अब गांधी तथा कांग्रेस के महत्व को विश्वास में लेना आवश्यक हो गया.

भारत छोड़ो आंदोलन–क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारतीय नेताओं में क्षोभ उत्पन्न होने के साथ ही देशवासियों में भी निराशा व्याप्त हो गई. विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति भी कमजोर पड़ गई थी. भारत पर जापानी हमले की संभावना बन रही थी. मलाया तथा बर्मा में जापानियों ने उपद्रव शुरू कर दिया था. जापानी प्रगति को देखकर अंग्रेजों ने भी पीछे हटने की योजना बनाई. इससे बंगाल के औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाने का खतरा पैदा हो गया. इस स्थिति को देखकर गांधीजी के मन में यह बात आई कि इस समय निराशा और घबराहट से जनता को सिर्फ इसी बात के आधार पर बचाया जा सकता है कि यदि उसके मन में यह बैठा दिया जाए कि उसे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है. अंग्रेजी सत्ता पर निर्भर नहीं रहना है. इसलिए गांधीजी ने अंग्रेजों से 'भारत छोड़ने' और भारतीयों को सत्ता सौंपने की बात कही. हालांकि उनके इस कार्य से नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वगैरह प्रसन्न नहीं थे. सरदार पटेल और गांधीजी के प्रयासों से अंततः जुलाई, 1942 ई. में वर्धा में कांग्रेस महासमिति ने गांधीजी के 'अहिंसक विद्रोह' को स्वीकृति प्रदान कर दी 7 अगस्त, 1942 ई. को बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें महत्वपूर्ण अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया. प्रस्ताव में कांग्रेस अध्यक्ष आजाद ने घोषणा की–"कौम चुपचाप देखती

नहीं रह सकती जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा है. हिंदुस्तान ने जम्हूरी मुल्कों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने बाइज्जत हाथ मिलाना भी नामुमकिन बना दिया. अंग्रेज अगर चाहें तो हिंदुस्तान छोड़कर जा सकते हैं. लेकिन हिंदुस्तानी इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह उनका घर है. इसलिए उन्हें ऐसी ताकत पैदा करनी होगी जो ब्रिटिश बेड़ी को उतार फेंके और किसी भी नए हमलावर के किसी भी हमले को रोक सके."

प्रस्ताव में कहा गया कि भारत तथा संयुक्त राष्ट्र दोनों के हित में यह बात है कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति यथाशीघ्र हो. इससे भारत तथा संयुक्त राष्ट्र में मित्रता प्रगाढ़ होगी. नाजीवाद, फासिज्म और साम्राज्यवाद के आक्रमण के खिलाफ लड़ने की शक्ति पैदा होगी. मुस्लिम लीग को यह आश्वासन दिया गया कि संविधान की रचना इस प्रकार से की जाएगी, जिससे संघ में सम्मिलित होने वाली इकाइयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, परन्तु शेष अधिकार केन्द्र के पास रहेंगे. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक, किन्तु व्यापक जन आंदोलन (भारत छोड़ो आंदोलन) प्रारम्भ करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया. गांधीजी ने अपने भाषण में 8 अगस्त, 1942 ई. की रात्रि में कहा–"मैं तुरन्त स्वतंत्रता चाहता हूँ, अगर हो सके तो आज ही रात को, पौ फटने से पहले .... मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज पर संतुष्ट नहीं हो सकता .... यह है एक मंत्र, बड़ा छोटा सा, जो मैं आपको देता हूँ. इस मंत्र को आप हृदय में अंकित कर सकते हैं .... मंत्र है "करो या मरो".

आंदोलन की शुरूआत–9 अगस्त, 1942 ई. को सुबह ही महात्मा गांधी वर्किंग कमेटी के सदस्य तथा अन्य नेता बम्बई तथा देश के अन्य भागों से गिरफ्तार कर लिए गए. गांधीजी को पूना में आगा खाँ पैलेस में सरोजनी नायडू के साथ तथा राजेन्द्र प्रसाद को पटना में एवं जयप्रकाश नारायण को हजारी बाग केन्द्रीय कारागार में रखा गया.

इस प्रकार नेताओं की गिरफ्तारी से जनता में आक्रोश भड़क गया और देशव्यापी आंदोलन, जुलूस, हड़ताल तथा प्रदर्शन के साथ हिंसा की घटनाएं भी हुईं. जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर 'आजाद दस्ता' गठित किया और स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी करने लगे. सरकार भी इस आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास कर रही थी. पुलिस की ओर से चलाई गई गोलियों में करीब 10,000 लोग मारे गए. गाँवों पर कर बढ़ा दिया गया, अमानवीय तथा अमानुषिक घटनाओं में वृद्धि कर दी गई. ग्रामीणों को बेवजह कोड़ों की मार लगाई गई. 'भारत छोड़ो आंदोलन' पर इतिहासकार विपिन चन्द्र, अमलेश त्रिपाठी और वरुण देव ने लिखा था–अलग-अलग व्यक्तियों ने जो कार्रवाई शुरू की वह बढ़कर एक आंदोलन में बदल गई. सरकार ने अपना गुस्सा दिखाया तथा आतंक व जुल्म की बागडोर ढीली कर दी गई. देश एक पुलिस राज्य में बदल गया. जिस समय कांग्रेस के आह्वान पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था उस समय देश के कुछ प्रमुख व्यक्ति और राजनीतिक दल इस आंदोलन के विरोधी बन गए. मुस्लिम लीग इस आंदोलन से अलग रही. कुछ समय पश्चात् उसने 'भारत छोड़ो आंदोलन' के जवाब में 'बाँटो और भागो' का नारा दिया. कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी स्वयं को आंदोलन से अलग रखा. देशी रियासतों का भी समर्थन नहीं मिलने से सरकार की ओर से इस आंदोलन को कुचल दिया गया.

आंदोलन का महत्व–भले ही यह आंदोलन कुचल दिया गया लेकिन इससे अंग्रेजी शासन में यह संदेश गया कि भारतीय अब किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता हासिल करके ही रहेंगे. चाहे उन्हें कितना ही बलिदान देना पड़े. अंग्रेजी शासकों को भी यह आभास हो गया था कि अब उनकी सत्ता कुछ ही दिन कायम रह पाएगी.

राष्ट्रीय आंदोलन में अन्य विचारधाराएँ–स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिस तरह कांग्रेस ने जनजाग्रति का अभियान छेड़ा उसी तरह से अन्य क्रांतिकारी विचारधाराओं का भी जन्म हुआ. जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित थीं–

समाजवादी आंदोलन–समाजवादी आंदोलन का जन्म 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हुआ. विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण व्यापार में बहुत तेजी से गिरावट आई. लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो गए. दूसरी तरफ समाजवादी देश रूस अपनी योजनाओं के आधार पर नित नई सफलताएं प्राप्त कर रहा था. इसके विकास ने विश्व के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया. इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा. इस समय 1932 ई. तक वस्तुओं की कीमतें 50% तक घट गई थीं. 1934 ई. तक आते-आते समाजवादियों ने कांग्रेस के अन्दर ही अपने आपको संगठित करना शुरू कर दिया. मई, 1934 ई. में पटना में जयप्रकाश नारायण ने अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन की स्थापना की. कांग्रेस की ढुलमुल नीति इन्हें पसन्द नहीं थी.

साम्यवादी आंदोलन–साम्यवादी वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते थे तथा इनमें प्रगाढ़ता का बाहुल्य देखा जा सकता था. समाजवादियों का साम्यवादियों की अपेक्षा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा. इस आंदोलन के परिणामस्वरूप ही कांग्रेस ने निरपेक्ष असांप्रदायिक स्तर पर भारतीय जनता की रहनुमाई करते हुए भारतवासियों की मुक्ति के लिए जेहाद छेड़ी और उसे तार्किक परिणति दी.

साम्यवादियों ने भारतीय मजदूरों को क्रांति के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया. भारतीय क्रांतिकारी एम. एन. राय ने

17 अक्टूबर, 1920 ई. को ताशकंद में हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की. भारत के विभिन्न भागों में कम्यूनिस्ट ग्रुप खड़े किए गए. सभी कम्यूनिस्ट ग्रुपों को मिलाकर 'साम्यवादी दल' की स्थापना की गई. दिसम्बर 1925 ई. में यह संस्था अस्तित्व में आई. इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आधिपत्य से मुक्ति के अतिरिक्त उत्पादन तथा वितरण के साधनों के समाजीकरण पर आधारित मजदूरों तथा किसानों का गणतंत्र स्थापित करना था.

श्रमिक वर्ग का आंदोलन–1853 ई. में श्रमिक वर्ग की स्थापना हुई. उद्योगों के विकास के साथ ही इनकी संख्या में भी वढ़ोतरी होती गई. मिल मालिक इनसे 12 घंटे तक काम करवाते तथा इनका शोषण भी किया जाता था. धीरे-धीरे इनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागी और श्रमिकों के ब्रिटिश साम्राज्यवादियों तथा भारतीय पूँजीपतियों का विरोध करना शुरू कर दिया. इन विरोधों में 1907 ई. में हुई रेलवे हड़ताल तथा 1908 ई. में तिलक को जेल दिए जाने के कारण बम्बई के मजदूरों ने जो हड़ताल की, उसका प्रमुख स्थान रहा.

वामपंथी विचारधारा का विकास–1920-22 ई. के दौरान अनेक छोटे-छोटे कम्यूनिस्ट दल भी बम्बई, मद्रास एवं अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर उभर कर सामने आने लगे थे और उन्होंने श्रमिकों के लिए जी तोड़ काम करना शुरू किया.

1927 ई. के बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन में वामपंथी नेतृत्व विकसित हुआ और इसमें वामपंथी, राष्ट्रवादी, समाजवादी तथा साम्यवादी नेता आए. इस नए नेतृत्व ने तेजी से पुराने नेतृत्व का विस्थापन शुरू कर दिया. 1922 ई. से ही भारतीय जनमानस में समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा फैल चुकी थी और इस प्रकार देश में समाजवादी तथा साम्यवादी दलों की स्थापना का श्री गणेश हो गया था. भारत में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का एक कारण जहाँ रूसी समाजवादी सरकार की सफलता थी, वहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य में कई अनेक तथ्य भी वामपंथी विचारधारा के प्रसार-प्रचार के कारण बने. मजदूर संगठनों ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में विशेष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. लगभग सभी सम्बद्ध दलों ने औद्योगिक क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाते समय मजदूरों की आर्थिक माँगों को साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष के साथ जोड़ने का कार्य किया.

सुभाष चन्द्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना

1942 ई. से लेकर 1945 ई. तक का समय भारतीय राजनीति के लिए निष्क्रिय काल माना जाता है क्योंकि देश के लगभग प्रमुख नेता जेलों में बन्द थे. जनता का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था. भले ही गतिविधियाँ ठप्प प्रायः थीं, परन्तु जितनी भी घटनाएँ थीं उनको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे युवा नेता सुभाष चन्द्र बोस.

सुभाष का जीवन एवं कार्य–सुभाष का जन्म 23 जनवरी, 1897 ई. को कटक (उड़ीसा) में हुआ था. अंग्रेजी शासकों की विभेद की नीति तथा देश प्रेम के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी तथा देशसेवा में लग गए. देशबंधु चितरंजन दास के सम्पर्क में आकर वे कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुए. नेहरू तथा बोस कांग्रेस के वामपंथी दलों का प्रतिनिधित्व करते थे. बोस ने स्वराज दल के गठन और इसके प्रचार में महती भूमिका निभाई. गांधी-इरविन समझौता तथा नेहरू रिपोर्ट से वे अप्रसन्न थे. नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के लिए उन्होंने 'इंडिपेंडेंट लीग' बनाई. साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रश्न पर गांधीजी के विचारों की आलोचना की. 1939 ई. में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ. गांधीजी पट्टाभिसीतारमैया को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाना चाहते थे और वामपंथी सुभाष के पक्ष में थे. फलतः दोनों में चुनाव हुआ और सीतारमैया की हार हुई. कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 सदस्यों में से नेहरू समेत 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. दक्षिणपंथी तथा वामपंथी सुभाष के मध्य मतभेद इतने बढ़ गए कि कांग्रेस के पुनः विभाजन की नौबत आ गई. इससे बचने के लिए सुभाष ने अप्रैल, 1939 ई. में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया. सुभाष ने कांग्रेस के अन्दर ही 'फारवर्ड ब्लॉक' की स्थापना की. कांग्रेस ने उन्हें तीन वर्षों के लिए किसी भी पद पर बने रहने से रोक दिया. 2 जुलाई, 1940 ई. को सुभाष को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया. 1941 ई. में नजरबन्द रहते हुए भी वे भागकर काबुल, मास्को के रास्ते बर्लिन पहुँचे. वहाँ उन्होंने युद्धबन्दी भारतीयों को संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए कमर कस ली. बर्लिन से वे जापान चले गए. वहाँ वे रासबिहारी बोस द्वारा स्थापित भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया. उन्होंने सिंगापुर में 1943 ई. में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई. जर्मनी में उन्हें 'नेताजी' की उपाधि प्रदान की गई. देशवासियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था–"तुम मुझे खून दो-मैं तुम्हें आजादी दूँगा" उन्होंने आजाद हिंद फौज को 'दिल्ली चलो' का नारा देकर प्रेरित किया. बर्मा के रास्ते वे कोहिमा तक बढ़ आए और वहां स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया. दुर्भाग्यवश इसी समय जापानी सेना की हार होने लगी और उसे बर्मा से लौटना पड़ा, फलतः आजाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा. सिंगापुर से वे टोकियो की ओर बढ़े, परन्तु रास्ते में ही 18 अगस्त, 1945 ई. को एक विमान दुर्घटना में वे मारे गए. उनके अथक प्रयासों से भारतीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली.

स्मरणीय तथ्य

- भारतीय राष्ट्रीय क्षितिज पर महात्मा गांधी का आगमन बीसवीं सदी के दूसरे दशक के अन्त में हुआ.
- वे 1841 ई. में वकालत पास करके इंग्लैण्ड से भारत लौटे और अभिभाषक के रूप में स्थापित होने की कोशिश की.
- उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही 'नेटाल भारतीय कांग्रेस' की स्थापना की.
- उनके द्वारा चलाए गए अफ्रीका संघर्ष के दूसरे चरण की शुरूआत 1906 ई. से हुई.
- मूल गांधीवादी प्रणाली की शुरूआत 1906 ई. से हुई.
- गांधीजी के द्वारा 1916 ई. में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई.
- अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने 1918 ई. में गांधीजी के नेतृत्व में हड़ताल की.
- अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल के तहत गांधीजी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का सहारा लिया.
- अंग्रेज सरकार ने 21 मार्च, 1919 ई. को रॉलेट एक्ट पास किया, जिसे भारतीय इतिहास में काले कानून की संज्ञा से परिभाषित किया गया.
- काले कानून के विरोध में मदनमोहन मालवीय, मजरूल हक और जिन्ना ने व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया.
- जनरल डायर 11 अप्रैल, 1919 ई. को अमृतसर पहुँचा और वहाँ फौजी शासन की शुरूआत की.
- पुलिस ज्यादती और निर्वासन के विरोध में 13 अप्रैल की संध्या को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20 हजार लोगों ने भाग लिया.
- जलियांवाले बाग हत्याकांड में करीब एक हजार लोग मारे गए तथा अनेकों घायल हो गए.
- खिलाफत आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य खलीफा की सर्वोच्चता और उसकी शक्ति को स्थापित करना था.
- गांधीजी ने 1 अगस्त, 1920 ई. से असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया.
- असहयोग आंदोलन की शुरूआत में गांधीजी ने अंग्रेजी सरकार के विरोधस्वरूप अपनी सरकारी उपाधि 'कैसर-ए-हिंद' को वापस कर दिया.
- 1921 ई. में युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का बम्बई आगमन हुआ.
- 5 फरवरी, 1922 ई. को गोरखपुर में चौरा-चौरी घटना हुई.
- कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहर लाल नेहरू ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की माँग रखी.
- 7 अगस्त, 1942 ई. को बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया.
- 1853 ई. में श्रमिक वर्ग की स्थापना की गई.
- 1942 ई. से लेकर 1945 ई. तक का काल भारतीय राजनीति के लिए निष्क्रिय काल माना जाता है.
- सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 ई. में उड़ीसा के कटक में हुआ.
- गांधीजी अफ्रीका में 22 वर्ष तक प्रयास करने के बाद 46 वर्ष की उम्र में भारत लौटे.
- गांधीजी के दक्षिणी अफ्रीका के संघर्ष की कहानी का प्रथम दौर 1894 से 1906 ई. तक चला.
- गांधीजी ने 'इंडियन ओपीनियन' नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया.
- दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने फार्म और फिनिक्स सेटमेंट की स्थापना करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अहिंसक सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया.
- रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में भारतीय नेताओं ने एक नारा दिया–"कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं".
- जनरल डायर के आदेश के कारण जलियाँवाला बाग हत्याकांड हुआ. इसके एवज में उसके इस कार्य के इनाम स्वरूप जनरल डायर को सरकार की ओर से 20,000 की थैली भेंट की गई थी.
- प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होने के बाद ब्रिटेन का ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की के खलीफा के प्रति रुख बदल गया.
- 1919 ई. में दिल्ली में हुए खिलाफत आंदोलन के गांधीजी अध्यक्ष चुने गए.
- गांधीजी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के दो पक्ष थे–1. रचनात्मक तथा 2. विध्वंसात्मक.
- 31 दिसम्बर, 1929 ई. की मध्य रात्रि को रावी नदी पर तिरंगा फहराया गया.
- 12 मार्च, 1930 ई. को अपने 79 समर्थकों को साथ लेकर गांधीजी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया.
- 5 अप्रैल, 1929 ई. को दांडी पहुँचकर गांधीजी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया.
- 7 अगस्त, 1942 ई. में बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में यह घोषणा की गई– "भारतीय कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती, जब उसकी तकदीर का फैसला होने

जा रहा है. अंग्रेज चाहे तो हिंदुस्तान छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह उनका घर है".

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने 'आजाद दस्ता' की स्थापना की.
- "भारत छोड़ो" के जवाब में मुस्लिम लीग ने नारा दिया "बाँटो और भागो."
- मई, 1934 ई. में पटना में जयप्रकाश नारायण ने अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन की स्थापना की.
- भारतीय क्रांतिकारी एम. एन. राय ने 17 अक्टूबर, 1920 ई. में ताशकंद में हिंदुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई.
- सुभाष चन्द्र बोस के विचार नेहरू तथा गांधी से नहीं मिलते थे. अतः उन्होंने 'इंडिपेंडेंट लीग' की स्थापना की.
- इसके साथ ही सुभाष ने कांग्रेस के अन्दर ही 'फारवर्ड ब्लाक' का भी गठन किया.
- 1941 ई. में नजरबन्द रहते हुए भी वे काबुल, मास्को के रास्ते बर्लिन पहुँचे.
- जापान में रासबिहारी बोस द्वारा स्थापित भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया.
- उन्होंने सिंगापुर में 1943 ई. में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई.
- 18 अगस्त, 1945 ई. में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई.

विशिष्ट स्मरणीय तथ्य

महात्मा गांधी : सम्पूर्ण कालानुक्रम

2 अक्टूबर, 1869	काठियावाड़ (पोरबन्दर) के वैश्य परिवार में करमचन्द गांधी उर्फ काबा गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई से मोहनदास करमचन्द गांधी का जन्म.
1876	माता-पिता के साथ राजकोट गए. बारह वर्ष की उम्र तक प्राथमिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की. एक व्यवसायी गोकुलदास माकनजी की पुत्री कस्तूरबा के साथ सगाई हुई.
1881	राजकोट में उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश.
1883	कस्तूरबा से विवाह.
1884-85	मांसाहार का प्रारम्भ किया, लेकिन माता-पिता से विश्वासघात न करने के कारण एक वर्ष बाद परित्याग कर दिया. 63 वर्ष की उम्र में पिता का देहान्त.
1887	मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की. भावनगर (काठियावाड़) के एक महाविद्यालय में प्रवेश लिया. प्रथम सत्र की समाप्ति होने पर पढ़ाई छोड़ दी.
4 सितम्बर, 1888	समुद्र के रास्ते से इंग्लैण्ड के लिए रवाना हुए.
28 अक्टूबर, 1888	लन्दन पहुँचे. नृत्य और संगीत की शिक्षा लेना प्रारम्भ किया. शाकाहार भोजन पर रहे.
1889	पहली बार गीता का अध्ययन किया. मितव्ययी जीवनचर्या का प्रारम्भ किया.
1890	शाकाहारी क्लब चलाया.
जून 1890	लन्दन की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की.
सितम्बर 1890	शाकाहारी सभा में शामिल हुए.
10 जून, 1891	बैरिस्टर हुए.
12 जून, 1891	समुद्री मार्ग से भारत के लिए रवाना हुए.
जुलाई 1891	बम्बई पहुँचे.
नवम्बर 1891	बम्बई उच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया.
1892	राजकोट और बम्बई में वकालत के लिए संघर्ष किया. राजकोट में विधिक ड्राफ्ट्स मेन बन गए.
अप्रैल 1893	कानूनी काम से एक मुसलमान फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने पर दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान किया.
मई-जून 1893	रंगभेद के कई अनुभव हुए. जातीय पूर्वाग्रहों के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया.
22 अगस्त, 1894	नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की.
1 सितम्बर, 1894	नेटाल के सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के रूप में नाम रजिस्टर कराया. वहाँ पर नाम रजिस्टर कराने वाले पहले भारतीय बने. बाइबिल एवं कुरान का अध्ययन किया. लियो टॉलस्टाय की पुस्तक 'किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू' का अध्ययन किया.
1895	दक्षिणी अफ्रीकी भारतीयों की समस्याओं के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हुए. द इण्डियन फ्रैंचाइजा एन अपील टु एवरी ब्रिटन इन साउथ अफ्रीका' जारी की.
जुलाई 1896	भारत वापस आए तथा दक्षिणी अफ्रीकी भारतीयों की ओर से आन्दोलन प्रारम्भ किया.

14 अगस्त, 1896	राजकोट में 'द ग्रीन पैम्पलैट' प्रकाशित किया. दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की शिकायत के सम्बन्ध में भारतीयों को जानकारी देने के उद्देश्य से पूना, कलकत्ता, मद्रास एवं मुम्बई का दौरा किया.
30 नवम्बर, 1896	पत्नी और बच्चों के साथ समुद्र के रास्ते से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए.
13 जनवरी, 1897	डरबन उतरने पर, दक्षिण अफ्रीका में अनुबन्धित भारतीय मजदूरों की हालत पर भारत में उनके द्वारा दिए गए भाषणों की रिपोर्ट से उत्तेजित होकर भीड़ द्वारा उनका घेराव किया गया.
20 जनवरी, 1897	आक्रमणकारियों पर मुकदमा चलाने से इन्कार किया.
6 अप्रैल, 1897	डरबन में घटी घटनाओं एवं उसकी पृष्ठ भूमि के सम्बन्ध में औपनिवेशिक राज्यमंत्री चैम्बर लैन को लम्बा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया.
1898-99	लोकेशनों और भारतीयों के व्यापार सम्बन्धी अधिकारों पर प्रतिबन्धों के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस औपनिवेशिक तथा साम्राज्यिक प्राधिकारियों के सामने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया.
1899	बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलैन्स कोर की स्थापना की. युद्ध पदक से सम्मानित.
1900	दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की समस्या पर दादाभाई नौरोजी के संकल्प के प्रारूप को कांग्रेस अधिवेशन में भेजा.
18 अक्टूबर, 1901	समुद्री मार्ग से भारत के लिए रवाना.
27 अक्टूबर, 1901	कांग्रेस के समक्ष दक्षिण अफ्रीका के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया.
28 जनवरी, 1902	रंगून गए.
1 फरवरी, 1902	गोखले के साथ कलकत्ता में एक माह रहे. राजकोट वापिस आकर वकालत करने लगे.
जुलाई, 1902	राजकोट से बम्बई आकर वकालत प्रारम्भ की.
नवम्बर, 1902	ट्रांसवाल में एशिया-विरोधी कानून के विरुद्ध भारतीयों के मामले का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका आमंत्रित.
दिसम्बर, 1902	डरबन पहुँचे. चैम्बर लेन से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया.
1903	ट्रांसवाल के सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी के रूप में नाम रजिस्टर कराया. ट्रांसवाल ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना की.
जून, 1903	'इण्डियन ओपिनियन' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ.
1904	जॉन रस्किन की पुस्तक 'अन टू द लास्ट' का अध्ययन किया. डरबन (नेटाल) के पास फिनीक्स आश्रम की स्थापना की. जोहान्सबर्ग में प्लेग फैलने पर अस्पताल की व्यवस्था की. गुजराती में आहार विज्ञान पर क्रमबद्ध लेख लिखे, कुछ समय बाद इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जो 'गाइड टू हैल्थ' शीर्षक से प्रकाशित हुई.
1905	बंगाल विभाजन का विरोध किया. विलायती वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया. ब्रिटिश उच्च आयुक्त लॉर्ड मेलबोर्न को ट्रान्सवाल के भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया.
12 मई, 1906	भारत के लिए होमरूल का समर्थन किया.
जून-जुलाई, 1906	जुलू विद्रोह में भारतीय स्ट्रेचर-वाहक कोर की स्थापना की. जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने की शपथ ली.
11 सितम्बर, 1906	जोहान्सबर्ग में भारतीयों की विशाल सभा को सम्बोधित किया जिसमें ताजा जारी किए गए ट्रांसवाल एशियाई कानून संशोधन अध्यादेश के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध करने की शपथ ली गई.
जनवरी-फरवरी, 1907	नैतिक धर्म पर गुजराती में आठ लेख लिखे, जो इण्डियन ओपिनियन में साप्ताहिक तथा एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए.
मार्च, 1907	ट्रांसवाल की पार्लियामेन्ट में एशियाई पंजीकरण अधिनियम पास हुआ. भारतीयों ने विरोध प्रकट करने के लिए सभाएँ आयोजित कीं.
अप्रैल, 1907	प्रिटोरिया में स्मट्स से मिले और उन्हें जनसभाओं में पास किए गए संकल्पों से अवगत कराया. इण्डियन ओपिनियन में ब्लैक-एक्ट का विरोध करने की शपथ ली.
मई, 1907	ब्लैक-एक्ट को ब्रिटिश सम्राट् की स्वीकृति प्राप्त हुई.
जुलाई, 1907	ब्लैक-एक्ट का विरोध करते हुए जनसभा को सम्बोधित किया.
अगस्त, 1907	पंजीकरण अधिनियम की आलोचना करते हुए स्मट्स को पत्र लिखा जिसमें कुछ संशोधनों का सुझाव दिया.
दिसम्बर, 1907	स्मट्स ने गांधीजी पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया.
8 जनवरी, 1908	सरकार से पंजीकरण अधिनियम को निलम्बित करने के लिए कहा, स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए प्रस्ताव किया.

10 जनवरी, 1908	निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर 'सत्याग्रह' शब्द अपनाया. ट्रांसवाल छोड़ने में असफल होने के कारण दो माह के कारावास का दण्ड मिला.
30 जनवरी, 1908	प्रिटोरिया में जनरल स्मट्स से मिलने के लिए बुलाया गया और समझौता होने पर कारावास से छोड़ दिया गया.
10 फरवरी, 1908	समझौते के अन्तर्गत भारतीयों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपने अंगुलिछाप दिए जाने को अपने हितों के प्रति विश्वासघात मानते हुए पठानों द्वारा गांधीजी पर लगभग घातक आक्रमण. अपने आक्रमणकारियों पर मुकदमा चलाने से इनकार.
मार्च-जून, 1908	अधिनियम को रद्द करने के वचन को पूरा कराने के लिए स्मट्स से बातचीत. स्मट्स द्वारा वचन निभाने से इनकार.
जुलाई, 1908	स्मट्स के साथ किया गया पत्र-व्यवहार प्रकाशित. भारतीयों ने एक विशाल जनसभा में अंगुलिछाप देने से इनकार करने का निश्चय किया और पंजीकरण प्रमाण पत्र को जला दिया.
अगस्त, 1908	भारत में ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा के प्रयोग को व्यर्थ एवं हानिकारक बताया. स्मट्स से ब्लैक-एक्ट को रद्द करने की अपील की. पंजीकरण प्रमाण-पत्र को जलाया गया. पुनः निष्क्रिय प्रतिरोध का आरम्भ.
1 सितम्बर, 1908	संशोधित पंजीकरण अधिनियम को सम्राट् की स्वीकृति प्राप्त. स्मट्स ने समझौते के लिए भारतीय शर्तों को अस्वीकार किया.
15 अक्टूबर, 1908	गांधीजी बन्दी बनाए गए एवं दो माह के कठोर कारावास की सजा दी गई.
12 दिसम्बर, 1908	फोक्सरूस्ट जेल से रिहा. दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के भारतीयों के साथ कठोर अपमानजनक और निष्ठुर व्यवहार को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हानिकारक बताते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दक्षिण अफ्रीका पर संकल्प पारित किया गया.
16 जनवरी, 1909	पंजीकरण प्रमाण-पत्र न दिखा पाने के लिए फोक्सरूस्ट में गिरफ्तार हुए. देश निकाला दिया गया, वापिस आ गए और फिर से गिरफ्तार कर लिए गए, परन्तु जमानत पर छोड़ दिए गए.
20 जनवरी, 1909	समाचार-पत्रों में लेख लिखकर भारतीयों से अन्तिम संघर्ष के लिए तैयार होने का आह्वान किया.
25 फरवरी, 1909	फोक्सरूस्ट में गिरफ्तार, तीन महीने की सजा दी गई.
2 मई, 1909	प्रिटोरिया केन्द्रीय जेल में स्थानान्तरण.
24 मई, 1909	जेल से रिहा किए गए.
21 जून, 1909	भारतीयों का मामला प्रस्तुत करने के लिए हाजी हबीब के साथ प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैण्ड रवाना हुए.
10 जुलाई, 1909	लन्दन पहुँचे. लॉर्ड एम्पथिन की सहायता से प्रभावशाली ब्रिटिश नेताओं और जनसमुदाय को भारत के मामले की सही जानकारी देने तथा साम्राज्यिक अधिकारियों के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निरन्तर कार्य करते रहे.
1 अक्टूबर, 1909	निष्क्रिय प्रतिरोध आन्दोलन के सम्बन्ध में टॉलस्टॉय को पत्र लिखा.
9 नवम्बर, 1909	'द टाईम्स' द्वारा ट्रांसवाल कानूनों पर गांधीजी और सरकार के बीच समझौता वार्ता असफल हो जाने का समाचार प्रकाशित.
10 नवम्बर, 1909	टॉल्सटाय के पत्र का उत्तर दिया. अपनी जीवनी डोर्क के हाथों भेजी.
13 नवम्बर, 1909	इंग्लैण्ड से दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान. एस. एस. किण्डोनन कासल पर 'हिन्दस्वराज' लिखा.
30 नवम्बर, 1909	दक्षिण अफ्रीका पहुँचे.
दिसम्बर, 1909	दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष की प्रशंसा करते हुए और अनुबन्ध की प्रथा पर रोक लगाने की माँग करते हुए लाहौर कांग्रेस द्वारा संकल्प पारित.
4 अप्रैल, 1910	लियो टॉल्सटाय को इण्डियन होमरूल की प्रति भेजी तथा उनसे उस पर सम्मति देने का अनुरोध किया.
30 मई, 1910	टॉल्सटाय फार्म की नींव रखी.
4 दिसम्बर, 1910	टॉल्स्टाय को श्रद्धांजलि अर्पित की
जनवरी, 1911	अप्रवासी प्रतिबन्ध विधेयक में संशोधनों के सम्बन्ध में स्मट्स से लिखा-पढ़ी की. स्मट्स ने आश्वासन दिया कि कानूनों में रंग भेद सम्बन्धी कोई दोष नहीं रहेगा.
27 मार्च, 1911	केपटाऊन में स्मट्स से साक्षात्कार किया.
22 अप्रैल, 1911	निष्क्रिय प्रतिरोध आन्दोलन को निलम्बित करने पर स्मट्स भारतीयों द्वारा माँगे गए आश्वासन देने के लिए सहमत हो गए.

3 मई, 1911	स्मट्स से भेंट की. स्मट्स द्वारा एशियाई पंजीकरण तथा अप्रवासी प्रतिबन्ध अधिनियम को रद्द करने का वचन देने पर एक अस्थायी समझौता हुआ.
24 जून, 1911	राज्याभिषेक के अवसर पर सम्राट् के प्रति निष्ठा व्यक्त की.
8 दिसम्बर, 1911	गोखले को दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमन्त्रित किया.
16 मार्च, 1912	गोखले द्वारा अनुबन्ध प्रथा का उन्मूलन करने के प्रयत्नों की प्रशंसा की.
12 सितम्बर, 1912	फीनिक्स ट्रस्ट की स्थापना की.
22 अक्टूबर, 1912	गोखले के साथ दक्षिण अफ्रीका, लौरेन्को, मारकीस मोजम्बिक एवं जंजीबार का दौरा किया. यूरोपीय परिधान एवं दूध का त्याग कर दिया.
18 जनवरी, 1913	'इण्डियन ओपिनियन' में वर्ष के अन्त तक भारत वापस जाने की संभावना का जिक्र किया.
14 मार्च, 1913	सिअरले के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दक्षिण अफ्रीका में हुए भारतीय विवाह अमान्य हैं.
30 मार्च, 1913	सिअरले के निर्णय का भारतीयों की विशाल जनसभा द्वारा विरोध.
7 जून, 1913	भेदभाव मूलक कानूनों का कठोरता से प्रयोग किए जाने तथा सत्याग्रह फिर से प्रारम्भ होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए भारत लौट जाने का विचार स्थगित कर दिया.
15 सितम्बर, 1913	निष्क्रिय प्रतिरोध का पुनः प्रारम्भ.
16 सितम्बर, 1913	कस्तूरबा को बन्दी बनाया गया.
17 अक्टूबर, 1913	न्यू कासन गए, अनुबन्धित भारतीयों से आग्रह किया कि जब तक 3 पाउंड का कर रद्द न कर दिया जाए तब तक काम बन्द कर दें. 300 खनिकों ने हड़ताल कर दी.
24 अक्टूबर, 1913	ट्रांसवाल की ओर मार्च करने का प्रस्ताव किया गया
28 अक्टूबर, 1913	न्यू कासल से मार्च प्रारम्भ हुआ.
30 अक्टूबर, 1913	चार्ल्स टाऊन पहुँचे.
3 नवम्बर, 1913	गिरफ्तारी देने के लिए ट्रांसवाल की ओर मार्च की घोषणा की.
6 नवम्बर, 1913	ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया. पामफोर्ड में गिरफ्तार किए गए.
7 नवम्बर, 1913	फोक्सरुस्ट में जमानत पर रिहा कर दिए गए. मार्च करने वालों में फिर सम्मिलित हो गए.
8 नवम्बर, 1913	स्टैंडरटन में गिरफ्तार किए गए, मुचलके पर रिहाई, मार्च जारी.
9 नवम्बर, 1913	टीकवर्थ में गिरफ्तार किए गए, वेलफोट में ले जाए गए.
11 नवम्बर, 1913	डंडी में नौ माह के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया.
13 नवम्बर, 1913	फोक्सरूस्ट जेल ले जाए गए.
14 नवम्बर, 1913	फोक्सरूस्ट में नया अभियोग चलाए जाने पर तीन माह का दण्ड दिया गया.
18 दिसम्बर 1913	बिना शर्त रिहा कर दिए गए. अनुबन्धित मजदूरों की पौशाक पहनने लगे. एक बार भोजन करने का निश्चय किया गया.
13-16 जनवरी, 1914	स्मट्स से साक्षात्कार किया, प्रस्ताव प्रस्तुत किए.
22 जनवरी, 1914	स्मट्स से समझौता हो जाने पर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया. फार्म के निवासियों के नैतिक चूक के लिए पश्चात्ताप के रूप में 14 दिन का उपवास किया.
जून, 1914	भारतीय राहत अधिनियम पारित किया गया.
18 जुलाई, 1914	भारत के लिए इंग्लैण्ड के रास्ते जलपोत से रवाना हुए.
4 अगस्त, 1914	लन्दन पहुँचे.
अक्टूबर, 1914	भारतीय स्वयंसेवक कोर की स्थापना की. स्वयंसेवक कोर की तैनाती. कोर के कार्य में प्रशासनिक हस्तक्षेप होने पर सत्याग्रह किया.
19 दिसम्बर, 1914	भारत के लिए जलपोत से रवाना हुए.
9 जनवरी, 1915	भारत पहुँचे. एम्बुलैन्स सेवाओं के लिए 'कैसर-ए-हिन्द' स्वर्णपदक से सम्मानित किया गया.
20 मई, 1915	अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की (इसी आश्रम को बाद में साबरमती आश्रम कहा गया).
1915-16	भारत और बर्मा का दौरा किया, रेल में तृतीय श्रेणी की यात्रा की.
1917	अनुबन्धित भारतीयों के उत्प्रवास के विरुद्ध सफलतापूर्वक आन्दोलन चलाया. बड़े पैमाने पर हस्तनिर्मित कपड़ा बनाने के लिए चरखे के उपयोग का मन में विचार आया.

अप्रैल, 1917	नील की खेती में मजदूरों के हालात की जाँच करने के लिए चम्पारन (बिहार) गए. बन्दी बनाए गए और बाद में छोड़ दिए गए. रैयत की शिकायतों की जाँच करने के लिए बिहार सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्य नियुक्त हुए.
जनवरी-मार्च, 1918	अहमदाबाद में कपड़ा मजदूरों का मामला हाथ में लिया और विवाद को शांतिपूर्वक हल करने के लिए उपवास किया. फसल न होने पर लगान मुल्तवी कराने के लिए जिला खेड़ा (बम्बई) में सत्याग्रह प्रारम्भ किया.
27 अप्रैल	दिल्ली में वायसराय के युद्ध सम्मेलन में भाग लिया और उसे हिन्दुस्तानी में संबोधित किया, तत्पश्चात् सेना में लोगों की भर्ती के लिए खेड़ा जिले का दौरा किया.
28 फरवरी, 1919	रौलट बिल को वापस लिया जाए, इसके लिए सत्याग्रह करने की शपथ पर हस्ताक्षर किए.
6 अप्रैल	अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन का उद्घाटन किया, देशव्यापी हड़ताल हुई.
8-11 अप्रैल, 1919	पंजाब में प्रवेश न करने के आदेश को मानने से इनकार करने के लिए दिल्ली जाते हुए बंदी बनाए गए, बम्बई वापस लाया गया, अनेक शहरों में हिंसा भड़क उठी.
13 अप्रैल	अमृतसर में जलियांवाला बाग की दुःखद घटना घटी. सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलाईं जिससे 1000 से अधिक लोगों की जानें गईं. साबरमती आश्रम के पास सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया और पश्चाताप के रूप में तीन दिन के उपवास की घोषणा की.
14 अप्रैल	नाडियाड में सत्याग्रह के बारे में अपनी 'भयंकर भूल' को स्वीकार किया. पंजाब में मार्शल लॉ की घोषणा हुई.
18 अप्रैल	सत्याग्रह स्थगित कर दिया.
सितम्बर	गुजराती मासिक पत्रिका 'नवजीवन' का सम्पादन सँभाला; बाद में, यह हिन्दी में भी साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ.
अक्टूबर	अंग्रेजी साप्ताहिक 'यंग इंडिया' का संपादन संभाला; पंजाब में सरकारी ज्यादतियों की जाँच के लिए गठित गैर-सरकारी समिति में सम्मिलित हुए.
24 नवम्बर	दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की.
दिसम्बर	अमृतसर में, कांग्रेस द्वारा मांटेग्यू-चैम्सफोर्ड सुधारों को स्वीकार किए जाने की सलाह दी.
जनवरी 1920	तुर्की के सुल्तान को (जो मुसलमानों का खलीफा भी था) इस्लाम के पवित्र स्थलों पर अपने अधिराजत्व से वंचित न करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से वायसराय के पास जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया.
1 अगस्त	कैसर-ए-हिंद पदक, जुलू युद्ध पदक तथा बोअर युद्ध पदक को वापस करते हुए वायसराय को पत्र लिखा.
सितम्बर	कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन द्वारा पंजाब और खिलाफत सम्बन्धी अन्यायों की समाप्ति के लिए गांधीजी के असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति.
नवम्बर	अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की.
दिसम्बर	नागपुर कांग्रेस में उनके इस संकल्प को स्वीकार किया गया कि कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों के लिए सभी वैध और शांतिपूर्ण साधनों द्वारा स्वराज की प्राप्ति है.
अप्रैल, 1921	राष्ट्रीय रचनात्मक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भारत में कांग्रेस के एक करोड़ सदस्य बनाने, तिलक स्वराज फंड के लिए एक करोड़ रुपया जमा करने और 20 लाख चर्खों की स्थापना का कार्यक्रम प्रारम्भ किया.
अगस्त	विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार के अभियान का नेतृत्व किया और बम्बई में विदेशी कपड़ों की विशाल होली जलाई.
दिसम्बर	अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा उन्हें अपना सर्वेसर्वा (डिक्टेटर) मानकर सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गईं.
1 फरवरी, 1922	बारदोली (गुजरात) में सत्याग्रह आंदोलन चलाने के इरादे का वायसराय को नोटिस दिया.
5 फरवरी	चौरीचौरा (उत्तर प्रदेश) की दुखांत घटना पर, जिसमें भीड़ द्वारा 21 पुलिस कांस्टेबलों और एक उपनिरीक्षक को जिंदा जला दिया गया था, पांच दिन का उपवास किया और सत्याग्रह आंदोलन की योजना को त्याग दिया.
10 मार्च	साबरमती में राजद्रोह के लिए गिरफ्तार किया गया और (18 मार्च को) छह वर्ष के कारावास का दंड दिया गया.
जनवरी-फरवरी, 1924	सैसून अस्पताल, पूना में (12 जनवरी को) ऐपेंडिसाइटिस का आपरेशन किया गया और 5 फरवरी को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया.

अप्रैल	'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' पत्रिकाओं के सम्पादक का कार्य फिर से हाथ में लिया.
18 सितम्बर	हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का उपवास प्रारम्भ किया.
दिसम्बर	बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की.
सितम्बर 1925	चर्खा कातने वालों के 'अखिल भारतीय संघ' की स्थापना की.
नवम्बर	आश्रमवासियों द्वारा किए दुष्कर्मों के लिए उनकी ओर से सात दिन का उपवास किया. अपनी आत्मकथा 'द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ' लिखना प्रारम्भ किया.
नवम्बर 1927	लंका की यात्रा पर गए.
दिसम्बर 1928	कलकत्ता कांग्रेस में यह संकल्प प्रस्तुत किया कि यदि 1929 के अन्त तक भारत को स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया जाता तो फिर उसका लक्ष्य स्वतंत्रता ही होगा.
दिसम्बर 1929	लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में उनके आग्रह पर यह घोषित किया गया कि कांग्रेस के मतानुसार स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वराज (अर्थात् पूर्ण स्वतंत्रता).
फरवरी 1930	अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा साविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस के सर्वेसर्वा (डिक्टेटर) नियुक्त किए गए.
2 मार्च	वायसराय को पत्र लिखा कि यदि कांग्रेस की माँगों को नहीं माना गया तो वे नमक कानून भंग करेंगे.
12 मार्च	डांडी समुद्र-तट के लिए यात्रा आरम्भ की, जहाँ उन्होंने औपचारिक रूप से नमक हाथ में लिया (अप्रैल 6).
5 मई	गिरफ्तार किए गए और बिना मुकदमा चलाए जेल भेज दिए गए; संपूर्ण भारत में हड़ताल हुई; वर्ष की समाप्ति तक 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया.
26 जनवरी, 1931	जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया गया.
फरवरी-मार्च	वायसराय के साथ कई बार वार्ता हुई जिसके परिणामस्वरूप इरविन-गांधी समझौता हुआ.
29 अगस्त	द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र-प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए समुद्र के रास्ते इंग्लैंड के लिए रवाना हुए.
सितम्बर-दिसम्बर	सम्मेलन के सत्रों में भाग लिया.
5 दिसम्बर	इंग्लैण्ड से भारत के लिए प्रस्थान.
28 दिसम्बर	बम्बई उतरे.
4 जनवरी, 1932	गिरफ्तार किए गए और बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिए गए.
20 सितम्बर	साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था का उन्मूलन कराने के लिए जेल में 'आमरण अनशन' प्रारम्भ किया.
26 सितम्बर	भारत सरकार द्वारा हरिजनों के सम्बन्ध में उनकी माँगें मान लिए जाने पर उपवास तोड़ दिया.
11 फरवरी 1933	अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाश्य साप्ताहिक पत्र 'हरिजन' की स्थापना की.
8 मई	आत्मशुद्धि के लिए दोपहर से 21 दिन का उपवास प्रारम्भ किया, रात 9 बजे बिना शर्त रिहा कर दिए गए.
9 मई	सविनय अवज्ञा आंदोलन छह सप्ताह के लिए स्थगित करने की घोषणा की और सरकार से अपने अध्यादेशों को वापस लेने की माँग की.
29 मई	उपवास तोड़ दिया.
26 जुलाई	सत्याग्रह आश्रम को विघटित कर दिया.
30 जुलाई	सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से प्रारम्भ करने के लिए अहमदाबाद से रास तक 33 अनुगामियों सहित मार्च करने के अपने निर्णय की सूचना बम्बई सरकार को दी.
31 जुलाई	गिरफ्तार कर लिए गए और मुकदमा चलाए बिना जेल भेज दिए गए.
4 अगस्त	छोड़ दिए गए और एक प्रतिबंध आदेश को भंग करने के लिए फिर से बंदी बना लिए गए.
16 अगस्त	छूआछूत-विरोधी प्रचार को जारी रखने के लिए सुविधाओं से वंचित किए जाने पर उपवास किया.
23 अगस्त	बिना शर्त रिहा कर दिया गया.
7 नवम्बर	हरिजन-उद्धार के लिए दौरा प्रारम्भ किया.
17 सितम्बर, 1934	ग्रामीण उद्योगों के विकास, हरिजन-सेवा और बुनियादी हस्तशिल्पों के जरिए शिक्षा देने के कार्य में लग जाने के लिए 1 अक्टूबर से राजनीति से संन्यास लेने के निर्णय की घोषणा की.
26 अक्टूबर	अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ का उद्घाटन किया.
30 अप्रैल, 1936	मध्यप्रांत में वर्धा के निकट एक गांव, सेवाग्राम को अपना मुख्यालय बनाकर वहीं रहने लगे.

22 अक्टूबर, 1937	वर्धा में शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बुनियादी हस्तशिल्पों के जरिए शिक्षा देने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की.
3 मार्च, 1939	प्रशासन में सुधार लाने के शासन के वायदे को पूरा कराने के लिए राजकोट में 'आमरण अनशन' प्रारम्भ किया और वायसराय के हस्तक्षेप पर 7 मार्च को यह अनशन समाप्त कर दिया.
जुलाई. तथा सितम्बर. 1940	युद्ध की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए वायसराय द्वारा निमंत्रित किए जाने पर उनसे भेंट की.
अक्टूबर	वैयक्तिक सविनय अवज्ञा के लिए स्वीकृति दी, सत्याग्रह विषय पर 'हरिजन' में प्रकाश्य रिपोर्टों तथा लेखों के पूर्व-सेंसर की सरकारी माँग पर 'हरिजन' और संबद्ध साप्ताहिक-पत्रों का प्रकाशन स्थगित कर दिया गया.
30 दिसम्बर, 1941	अपने ही अनुरोध पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व से भारमुक्त हुए.
18 जनवरी, 1942	'हरिजन' और सम्बद्ध साप्ताहिक पत्रिकाएँ फिर से प्रारम्भ की गईं.
27 मार्च	नयी दिल्ली में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स से भेंट की; तत्पश्चात् क्रिप्स के प्रस्तावों को एक 'उत्तरदिनांकित' (पोस्ट डेटेड) चैक बताया.
मई	ब्रिटिश सरकार से 'भारत छोड़ने' के लिए अपील किया गया.
8 अगस्त	'भारत छोड़ो' संकल्प के निहितार्थों पर प्रकाश डालने के लिए बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक को सम्बोधित किया.
9 अगस्त	गिरफ्तार किए गए और पूना में आगा खाँ महल में नजरबन्द कर दिए गए.
15 अगस्त	आगा खाँ महल में गांधीजी के निजी सचिव महादेव देसाई का हृदयगति रुक जाने से देहांत.
अगस्त-दिसम्बर	दंगों के सम्बन्ध में वायसराय तथा भारत सरकार से पत्राचार.
10 फरवरी, 1943	21 दिन का उपवास प्रारम्भ किया, जो 3 मार्च को तोड़ा.
22 फरवरी, 1944	आगा खाँ महल में कस्तूरबा गांधी का निधन.
6 मई	बिना शर्त रिहा किया गया.
9-27 सितम्बर	एम. ए. जिन्ना से पाकिस्तान के सम्बन्ध में बातचीत जारी रखी.
2 अक्टूबर	75वें जन्म-दिवस के अवसर पर कस्तूरबा स्मारक के लिए 110 लाख रुपए (8,25,000 पौंड) की राशि भेंट की गई.
17 अप्रैल, 1945	आगामी सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य में घोषणा करते हुए कहा कि, "समानता और भारत की स्वतंत्रता के बिना शांति असम्भव है." जर्मनी और जापान के लिए भी न्यायोचित शांति की माँग की.
19 दिसम्बर	शांति निकेतन में सी. एफ. एंड्रूज स्मारक अस्पताल की नींव रखी.
दिसम्बर-जनवरी 1945-46	बंगाल और असम का दौरा किया.
जनवरी तथा फरवरी, 1946	छूआछूत के विरोध तथा हिंदुस्तानी के प्रचार के लिए दक्षिण भारत का दौरा किया.
10 फरवरी	हरिजन और सम्बद्ध साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रकाशन फिर से आरम्भ किया.
अप्रैल	दिल्ली में केबिनेट मिशन के साथ राजनीतिक वार्ता में भाग लिया.
5-12 मई	शिमला गए; शिमला सम्मेलन आयोजित; विचार-विमर्श निष्फल सिद्ध हुआ.
16 मई	केबिनेट मिशन ने अपनी योजना की घोषणा की.
18-19 मई	केबिनेट मिशन के साथ उनकी योजना पर चर्चा की.
26 मई	तत्कालीन परिस्थितियों में, ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज को सर्वश्रेष्ठ माना.
6 जून	मसूरी गए.
7 जून	दिल्ली वापस आए.
10 जून	मित्र देशों की विजय पर यह कहते हुए हर्ष प्रकट करने से इन्कार किया कि यह "असत्य पर सत्य की विजय नहीं है."
11 जून	वायसराय ने गांधीजी से साक्षात्कार किया; केन्द्र में साझा सरकार का प्रस्ताव रखा.
16 जून	केबिनेट मिशन की बातचीत स्थगित हो गई; वायसराय ने अन्तरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा.
18 जून	कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने अंतरिम सरकार की योजना को स्वीकार करने का निर्णय लिया.
20-21 जून	कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लिया, क्रिप्स ने गांधीजी से भेंट की.

23 जून	कांग्रेस को अंतरिम सरकार में शामिल न होकर केवल संविधान सभा में सम्मिलित होने की सलाह दी.
24 जून	केबिनेट मिशन से भेंट की.
28 जून	दिल्ली से पूना के लिए रवाना हुए. रास्ते में गाड़ी को पटरी से उतारने के प्रयत्न किए गए.
7 जुलाई	बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को सम्बोधित किया; कांग्रेस ने केबिनेट मिशन की 16 मई की योजना को स्वीकार कर लिया.
31 जुलाई	जिन्ना ने 'सीधी कार्रवाई' करने की धमकी दी.
12 अगस्त	वायसराय ने कांग्रेस को अस्थायी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की घोषणा की.
16-18 अगस्त	कलकत्ता में भीषण नर-संहार.
24 अगस्त	वायसराय वेवल ने योजना का रेडियो पर प्रसारण किया.
27 अगस्त	गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार से बंगाल त्रासदी को दोहराने के विरुद्ध चेतावनी देते हुए तार दिया; वेवेल को भी पत्र लिखा.
4 सितम्बर	अंतरिम सरकार बनाई गई.
26 सितम्बर	वेवेल से साक्षात्कार किया.
9 अक्टूबर	जिन्ना की 9-सूत्री माँगों के विषय में कांग्रेस को सूचित किया गया.
10 अक्टूबर	नौआखली में नरसंहार.
15 अक्टूबर	मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गई.
28 अक्टूबर	कलकत्ता के लिए प्रस्थान. बिहार में दंगे-फसाद प्रारम्भ.
6 नवम्बर	नौआखली के लिए प्रस्थान, 'आंशिक उपवास' के बारे में वक्तव्य जारी किया, नौआखली का दौरा आरम्भ.
20 नवम्बर	बिना किसी को साथ लिए अकेले ही नौआखली के दौरे पर निकल पड़े.
20 दिसम्बर	श्रीरामपुर में एक माह का प्रवास पूरा किया.
25 दिसम्बर	नोआखाली में उन्होंने कहा, "ईश्वर मेरी जमकर परीक्षा ले रहा है".
30 दिसम्बर	जवाहरलाल नेहरू गांधी से आकर मिले जिनसे उन्होंने कहा, "मेरा विवेक मेरे हृदय के भावों का पूरी तरह समर्थन कर रहा है".
2 जनवरी, 1947	उन्होंने कहा, "मेरे चारों तरफ अंधेरा-ही-अंधेरा है". श्रीरामपुर से पैदल दौरे पर चल पड़े.
3-29 जनवरी	बिहार में दंगों से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया.
30 जनवरी	पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए. नए वायसराय माउंटबेटन दिल्ली पहुँचे.
1-2 अप्रैल	गांधीजी ने दिल्ली में एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन को सम्बोधित किया.
15 अप्रैल	जिन्ना के साथ मिलकर साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए संयुक्त रूप से अपील जारी की गई.
29 अप्रैल	बिहार गए.
1 मई	कांग्रेस कार्यकारिणी ने सैद्धांतिक रूप से देश का विभाजन स्वीकार कर लिया.
5 मई	एक साक्षात्कार में गांधीजी ने इस बात से इनकार किया कि भारत का साम्प्रदायिक आधार पर विभाजन अपरिहार्य है.
24 मई	बिहार से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया.
31 मई	गांधीजी ने घोषणा की कि विभाजन से पहले शांति स्थापित होनी चाहिए. यह भी कि वे भारत के जीवच्छेदन (विभाजन) के निर्णय में भागीदार नहीं हैं.
2 जून	वायसराय ने देश-विभाजन की योजना प्रस्तुत की; कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इसे अपनी स्वीकृति दी.
3 जून	भारतीय नेताओं द्वारा माउंटबेटन की योजना पर रेडियो भाषण.
6 जून	गांधीजी ने पाकिस्तान को स्वीकार करते हुए माउंटबेटन को लिखा कि वे जिन्ना को कांग्रेस के साथ पिछले सभी विवादग्रस्त विषयों को मित्रतापूर्ण ढंग से निपटाने के लिए राजी करें.
12 जून	कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को सम्बोधित किया.
जुलाई	'भारत स्वतंत्रता बिल' पास हुआ.
27 जुलाई	भारत की रियासतों के राजाओं से जनता के वर्चस्व को एक विशेषाधिकार मानने की अपील की.
14 अगस्त	अंग्रेजों की दासता से मुक्ति पाने पर अगले दिन का हर्षोल्लास दिवस के रूप में स्वागत, परन्तु देश-विभाजन की निंदा, पाकिस्तान का जन्म.
15 अगस्त	कलकत्ता में हिंदू-मुसलमानों में भाई-चारा.
16 अगस्त	कलकत्ता में हुए इस चमत्कार का स्वागत.

1 सितम्बर	कलकत्ता की शांति को नौ दिन का आश्चर्य बताया, उपवास का निश्चय.
2 सितम्बर	कलकत्ता के घर में भारी भीड़ ने उन्हें घेरा, नोआखाली जाने का विचार त्याग दिया, शांति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को तेज़ किया.
4 सितम्बर	उपवास तोड़ दिया.
7 सितम्बर	कलकत्ता से दिल्ली के लिए प्रस्थान; दंगों से पीड़ित क्षेत्रों का प्रतिदिन दौरा करना प्रारम्भ किया.
24 सितम्बर	पाकिस्तानी हमलावरों द्वारा कश्मीर पर हमला.
25 सितम्बर	कश्मीर भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ.
26 सितम्बर	चर्चिल के 'भारत में सर्वनाश' वक्तव्य की आलोचना.
1 नवम्बर	भारतीय सेना का जूनागढ़ में प्रवेश.
3 नवम्बर	जूनागढ़ भारत में सम्मिलित हो गया. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को सम्बोधित किया.
11 नवम्बर	जूनागढ़ के भारत में सम्मिलित होने का समर्थन.
25 दिसम्बर	भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रतापूर्ण समझौते का आग्रह.
30 दिसम्बर	भारत द्वारा कश्मीर-विवाद संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत.
12 जनवरी, 1948	दिल्ली में साम्प्रदायिक शांति के लिए उपवास करने का निर्णय, माउंटबेटन गांधीजी को उपवास न रखने के लिए राजी करने में असफल.
15 जनवरी	स्वास्थ्य की स्थिति 'नाजुक'. भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा पाकिस्तान को देय 55 करोड़ की राशि अदा किए जाने के निर्णय का स्वागत किया. साम्प्रदायिक शांति की स्थापना के लिए उपवास जारी रखा.
17 जनवरी	चिकित्सकों ने चेतावनी दी कि उपवास समाप्त कराना अब नितांत आवश्यक है. केन्द्रीय शांति समिति का गठन जिसने 'शांति के लिए शपथ' लेने का निर्णय लिया.
18 जनवरी	शांति समिति ने 'शपथ' पर हस्ताक्षर किए, 'शांति-शपथ' गांधीजी को प्रस्तुत की गई, गांधीजी ने उपवास तोड़ा.
20 जनवरी	प्रार्थना-सभा में बम फटा.
27 जनवरी	महरौली में मुसलमानों के मेले में गए.
29 जनवरी	क्रुद्ध शरणार्थियों द्वारा गांधीजी से संन्यास लेकर हिमालय चले जाने की माँग.
30 जनवरी	कांग्रेस को लोक सेवक संघ में रूपांतरित करने के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया; प्रार्थना-सभा में जाते समय उनकी हत्या कर दी गई.

विगत वर्ष में पूछे गये प्रश्न

1. निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने 1930 में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था ?
   (A) मोहनदास करमचन्द गांधी
   (B) मदन मोहन मालवीय
   (C) मोतीलाल नेहरू
   (D) मुहम्मद अली

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   जब महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा तब,
   1. कलकत्ता में सी. आर. दास की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र बुलाया गया था.
   2. यह प्रस्ताव विशेष सत्र में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/ हैं ?
   (A) केवल 1 (B) केवल 2
   (C) 1 और 2 दोनों (D) न ही 1 और न ही 2

3. विख्यात आई. एन. ए. मुकदमे में वकील कौन था?
   (A) भूलाभाई देसाई (B) आसफ अली
   (C) राजेन्द्र प्रसाद (D) राजगोपालाचारी

4. महात्मा गांधी के रामराज्य के दो सिद्धान्त थे–
   (A) सत्य तथा अहिंसा
   (B) उचित साधन तथा उचित उद्देश्य
   (C) खादी तथा अहिंसा
   (D) सत्याग्रह तथा अहिंसा

निर्देश–(प्रश्न 5-6) आगामी प्रश्नों में दो वक्तव्य हैं. एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है. इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों के उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए–

कूट :
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(B) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) A सही है, परन्तु R गलत है
(D) A गलत है, परन्तु R सही है

5. **कथन (A)** : महात्मा गांधी द्वारा 1932 में पूना में उपवास रखा गया.

   कारण (R) : साम्प्रदायिक पंचाट के अन्तर्गत हरिजनों के लिए पृथक् चुनाव अधिकारों के प्रावधान के महात्मा गांधी विरोधी थे.

6. **कथन (A)** : महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया गया.

   कारण (R) : आन्दोलन का सी. आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था.

उत्तरमाला

1. (D) 2. (D) 3. (A) 4. (B) 5. (A) 6. (C)

संकेत

1. प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख भारतीय नेता थे–तेज-बहादुर सप्रू, जिन्ना, अम्बेडकर आदि.
2. कलकत्ता के विशेष अधिवेशन (1920) की अध्यक्षता लाजपत राय ने की थी.
6. सी. आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू दोनों ने आन्दोलन में भाग लिया था.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय क्षितिज पर आगमन कब हुआ ?
   (A) बीसवीं सदी के दूसरे दशक में
   (B) बीसवीं सदी के मध्य में
   (C) बीसवीं सदी के तीसरे दशक में
   (D) बीसवीं सदी के चौथे दशक में
2. गांधीजी इंग्लैण्ड से वकालत पास करके भारत कब लौटे?
   (A) 1892 ई. में (B) 1893 ई. में
   (C) 1891 ई. में (D) 1895 ई. में
3. दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी कितने वर्ष रहे ?
   (A) 20 वर्ष (B) 25 वर्ष
   (C) 40 वर्ष (D) 22 वर्ष
4. दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने कौनसा आंदोलन चलाया ?
   (A) सत्याग्रह आंदोलन (B) असहयोग आंदोलन
   (C) नमक आंदोलन (D) कोई नहीं
5. गांधीजी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष का प्रथम दौर का काल था–
   (A) 1890-1900 तक (B) 1894-1906 तक
   (C) 1894-1920 तक (D) 1890-1892 तक
6. मूल गांधीवादी प्रणाली की शुरूआत कबसे हुई ?
   (A) 1907 ई. से (B) 1908 ई. से
   (C) 1906 ई. से (D) 1910 ई. से
7. अफ्रीका से जब गांधीजी भारत लौटे तो उनकी उम्र कितनी थी ?
   (A) 50 वर्ष (B) 55 वर्ष
   (C) 46 वर्ष (D) 42 वर्ष
8. अफ्रीका से गांधीजी कौनसे वर्ष में भारत लौटे ?
   (A) 1916 में (B) 1915 में
   (C) 1920 में (D) 1918 में
9. गांधीजी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई ?
   (A) बम्बई में (B) अहमदाबाद में
   (C) कलकत्ता में (D) बिहार में
10. साबरमती आश्रम की स्थापना कौनसे सन् में हुई ?
    (A) 1916 में (B) 1920 में
    (C) 1917 में (D) 1918 में
11. गांधीजी के नेतृत्व में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने हड़ताल कब की ?
    (A) 1920 में (B) 1925 में
    (C) 1926 में (D) 1918 में
12. प्रथम विश्व युद्ध का समापन कब हुआ ?
    (A) 1918 में (B) 1917 में
    (C) 1920 में (D) 1925 में
13. रॉलेक्ट एक्ट कब पास किया गया ?
    (A) 22 मार्च, 1919 को (B) 23 मार्च, 1919 को
    (C) 21 मार्च, 1919 को (D) 25 मार्च, 1919 को
14. 'काले कानून' की संज्ञा किसे दी गई थी ?
    (A) रॉलेक्ट एक्ट को (B) होमरूल को
    (C) चौरी-चौरा कांड को (D) फौजी प्रशासन को
15. "कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं" यह नारा किसके विरोध में दिया गया ?
    (A) शोषण नीति के विरोध में
    (B) पूँजीपतियों के विरोध में
    (C) रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में
    (D) इनमें से कोई नहीं
16. जलियाँवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ ?
    (A) सर टॉमस रॉ (B) जनरल डायर
    (C) क्लाइव (D) होमर

17. जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ ?
(A) फिरोजपुर में (B) अमृतसर में
(C) चंडीगढ़ में (D) पठानकोट में

18. जलियांवाला कांड में कितने लोग हताहत हुए ?
(A) करीब 5 हजार (B) करीब 2 हजार
(C) करीब 1 हजार (D) करीब 3 हजार

19. जलियांवाला कांड कब हुआ ?
(A) 13 अप्रैल, 1919 (B) 16 अप्रैल, 1919
(C) 20 अप्रैल, 1919 (D) 18 अप्रैल, 1919

20. 'जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड' के उपलक्ष्य में जनरल डायर को सरकार की ओर से इनाम स्वरूप कितने की थैली भेंट की गई ?
(A) 25 हजार (B) 21 हजार
(C) 22 हजार (D) 20 हजार

21. अमृतसर में फौजी शासन किसने लागू किया ?
(A) सर टॉमस रो ने (B) जनरल डायर ने
(C) क्लाइव ने (D) मैकाले ने

22. अमृतसर में मार्शल लॉ लागू किया गया.
(A) 15 अप्रैल, 1919 को
(B) 16 अप्रैल, 1919 को
(C) 18 अप्रैल, 1919 को
(D) 20 अप्रैल, 1919 को

23. "अपने कार्यों से डायर ने पंजाब को तो बचा लिया मगर भारत को खो दिया" ये शब्द किसके थे ?
(A) क्लाइव के (B) गिलबर्ट स्लेटर के
(C) मैकाले के (D) इनमें से कोई नहीं

24. "प्लासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और अमृतसर ने उसे हिला दिया" ये कथन थे–
(A) मदनमोहन मालवीय के (B) तिलक के
(C) महात्मा गांधी के (D) सुभाष के

25. समूचे विश्व के सुन्नी मुसलमानों का धर्मगुरु कौन माना जाता था ?
(A) तुर्की का खलीफा (B) अरब का खलीफा
(C) रोम का खलीफा (D) बंगाल का खलीफा

26. महात्मा गांधी दिल्ली में हुए खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब चुने गए ?
(A) 1920 में (B) 1919 में
(C) 1921 में (D) 1922 में

27. गांधीजी ने असहयोग की नीति का ऐलान कब किया ?
(A) 1940 में (B) 1920 में
(C) 1915 में (D) 1930 में

28. गांधीजी ने अंग्रेज सरकार की ओर से प्राप्त उपाधि 'कैसर-ए-हिंद' को किसके समर्थन में लौटा दिया ?
(A) सविनय अवज्ञा आंदोलन के पक्ष में
(B) भारतीय राष्ट्रीय के समर्थन में
(C) असहयोग आंदोलन के पक्ष में
(D) इनमें से कोई नहीं

29. गांधीजी के असहयोग आंदोलन को स्वीकृति कब मिली ?
(A) 1920 में (B) 1922 में
(C) 1921 में (D) 1923 में

30. गांधीजी के असहयोग आंदोलन को स्वीकृति कहाँ मिली ?
(A) बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में
(B) इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में
(C) कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में
(D) नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में

31. असहयोग आंदोलन के कितने पक्ष थे ?
(A) 2 (B) 4
(C) 6 (D) 3

32. "युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स" का भारत में आगमन कब हुआ ?
(A) 1925 में (B) 1926 में
(C) 1921 में (D) 1920 में

33. गोरखपुर में चौरी-चौरा की घटना कब हुई ?
(A) 5 फरवरी, 1922 को
(B) 6 फरवरी, 1922 को
(C) 7 फरवरी, 1922 को
(D) 8 फरवरी, 1922 को

34. सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार की गई–
(A) 1930 में (B) 1920 में
(C) 1925 में (D) 1928 में

35. सरकार ने 'पब्लिक सेफ्टी बिल' कब पेश किया ?
(A) 1929 में (B) 1930 में
(C) 1927 में (D) 1919 में

36. लाहौर अधिवेशन में 'पूर्ण स्वाधीनता' की माँग किसने रखी ?
(A) नेहरू ने (B) गांधी ने
(C) तिलक ने (D) गोखले ने

37. यह किसने कहा कि "हमारा एक ही लक्ष्य है–स्वाधीनता का लक्ष्य?"
(A) गोखले ने (B) गांधी ने
(C) तिलक ने (D) नेहरू ने

38. 31 दिसम्बर, 1929 की मध्य रात्रि को किस नदी पर तिरंगा फहराया गया ?
(A) रावी पर (B) झेलम पर
(C) चिनाव पर (D) तवी पर

39. कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधीजी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का अधिकार कब दिया ?
(A) फरवरी 1932 में (B) फरवरी 1936 में
(C) फरवरी 1933 में (D) फरवरी 1930 में

40. किस अधिवेशन से प्रभावित होकर अब्दुल गफ्फार खान ने कांग्रेस में शामिल होने का निश्चय किया ?
(A) बम्बई अधिवेशन (B) बंगला अधिवेशन
(C) लाहौर अधिवेशन (D) कलकत्ता अधिवेशन

41. गांधीजी ने दांडी के लिए प्रस्थान कब किया ?
(A) 12 मार्च, 1936 (B) 12 मार्च, 1932
(C) 12 मार्च, 1935 (D) 12 मार्च, 1930

42. साबरमती आश्रम से दांडी कितनी दूर था ?
(A) 500 किमी (B) 200 किमी
(C) 400 किमी (D) 250 किमी

43. जब गांधीजी ने दांडी को प्रस्थान किया तो उनके साथ कितने सहयोगी थे ?
(A) 79 (B) 80
(C) 69 (D) 72

44. गांधीजी दांडी कब पहुँचे?
(A) 6 अप्रैल, 1930 (B) 5 अप्रैल, 1930
(C) 7 अप्रैल, 1940 (D) 7 अप्रैल, 1932

45. अगस्त प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया ?
(A) बम्बई में (B) मद्रास में
(C) बिहार में (D) कलकत्ता में

46. अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया ?
(A) 7 अगस्त, 1942 (B) 8 अगस्त, 1940
(C) 9 अगस्त, 1941 (D) 10 अगस्त, 1942

47. गांधीजी ने यह कब कहा कि "मैं तुरन्त स्वतंत्रता चाहता हूँ, अगर हो सके तो आज ही रात को........."
(A) 9 अगस्त, 1942 (B) 18 अगस्त, 1942
(C) 8 अगस्त, 1942 (D) 10 अगस्त, 1942

48. 9 अगस्त, 1942 को गांधीजी को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ कैद में रखा गया ?
(A) पूना में (B) बम्बई में
(C) इलाहाबाद में (D) कलकत्ता में

49. जहाँ गांधीजी को कैद किया गया, उस स्थान का क्या नाम था ?
(A) आगा खाँ पैलेस (B) हजारी बाग कारागार
(C) नरीमन प्वाइंट (D) इनमें से कोई नहीं

50. 'आजाद दस्ते' का गठन किसने किया ?
(A) बाल गंगाधर तिलक ने
(B) जयप्रकाश नारायण ने
(C) गांधीजी ने
(D) सुभाष ने

51. मुस्लिम लीग ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' के जवाब में क्या नारा दिया ?
(A) बाँटों और भागो (B) स्वतंत्रता दो
(C) निष्पक्षता बरतो (D) इनमें से कोई नहीं

52. असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग ने सहयोग दिया या नहीं–
(A) हाँ (B) नहीं
(C) तटस्थ रही (D) इनमें से कोई नहीं

53. मुस्लिम लीग के साथ ही एक पार्टी और थी जिसने असहयोग आंदोलन में समर्थन नहीं किया–
(A) कम्यूनिस्ट पार्टी (B) कांग्रेस पार्टी
(C) नरम दल (D) गरम दल

54. स्वतंत्रता संग्राम के लिए समाजवादी आंदोलन का जन्म कब हुआ ?
(A) बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक में
(B) बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में
(C) बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में
(D) बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में

55. 'अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन' की स्थापना किसने की ?
(A) तिलक ने (B) गोखले ने
(C) जयप्रकाश नारायण ने (D) गांधी ने

56. जयप्रकाश नारायण के अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन का गठन कब किया ?
(A) मई 1934 में (B) मार्च 1934 में
(C) अप्रैल 1934 में (D) जून 1934 में

57. जयप्रकाश नारायण ने उक्त सम्मेलन की स्थापना कहाँ पर की थी ?
(A) कलकत्ता में (B) मद्रास में
(C) बम्बई में (D) पटना में

58. भारत में श्रमिक वर्ग का जन्म कब हुआ ?
(A) 1854 में (B) 1852 में
(C) 1853 में (D) 1800 में

59. हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ ?
(A) 17 अक्टूबर, 1920 (B) 13 अक्टूबर, 1926
(C) 18 अक्टूबर, 1920 (D) 13 नवम्बर, 1920

60. हिंदुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे ?
(A) एन. एम. राय (B) एम. एन. राय
(C) एल. एम. राय (D) एम. एल. राय

61. हिंदुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई ?
(A) बंगाल में (B) बिहार में
(C) ताशकंद में (D) लाहौर में

62. 'साम्यवादी दल' कब अस्तित्व में आया ?
(A) 1920 में (B) 1921 में
(C) 1925 में (D) 1930 में

63. भारतीय जनमानस में समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा का फैलाव कबसे शुरू हुआ था ?
(A) 1926 से (B) 1922 से
(C) 1923 से (D) 1924 से

64. 1942 से लेकर 1945 तक का समय भारतीय राजनीति के लिए कहा जाता है–
(A) स्वर्णिम काल (B) सामान्य काल
(C) निष्क्रिय काल (D) इनमें से कोई नहीं

65. सुभाष चन्द्र बोस का जन्म कहाँ हुआ ?
(A) कटक में (B) बंगाल में
(C) कलकत्ता में (D) पटना में

66. सुभाष चन्द्र बोस का जन्म कब हुआ ?
(A) 24 जनवरी, 1897 (B) 28 जनवरी, 1897
(C) 23 जनवरी, 1897 (D) 20 जनवरी, 1897

67. नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के लिए उन्होंने किसकी स्थापना की ?
(A) इंडिपेंडेंट कांग्रेस (B) इंडिपेंडेंट कॉन्फ्रेंस
(C) इंडिपेंडेंट लीग (D) युवा मोर्चा

68. सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा कब दिया ?
(A) मई 1939 में (B) अप्रैल 1939 में
(C) जून 1939 में (D) जुलाई 1939 में

69. सुभाष के इस्तीफा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बना ?
(A) गांधी (B) तिलक
(C) राजेन्द्र प्रसाद (D) लाजपत राय

70. सुभाष को भारत रक्षा कानून के तहत् कब गिरफ्तार किया गया ?
(A) 3 जुलाई, 1940 को (B) 2 जुलाई, 1940 को
(C) 5 जुलाई, 1940 को (D) 10 जुलाई, 1940 को

71. सुभाष जी बर्लिन कब पहुँचे ?
(A) 1942 में (B) 1943 में
(C) 1941 में (D) 1945 में

72. भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया ?
(A) सुभाष ने (B) तिलक ने
(C) गांधी ने (D) गोखले ने

73. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी ?
(A) बम्बई में (B) लंदन में
(C) नागपुर में (D) सिंगापुर में

74. रासबिहारी बोस ने जापान में किसकी नींव रखी ?
(A) हिंदुस्तान स्वतंत्रता लीग
(B) भारतीय स्वतंत्रता लीग
(C) हिंदुस्तान कांग्रेस
(D) भारतीय कांग्रेस

75. सुभाष चन्द्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया ?
(A) 1943 में (B) 1908 में
(C) 1942 में (D) 1945 में

76. भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ हुआ था ?
(A) मलेशिया में (B) सिंगापुर में
(C) जापान में (D) जर्मनी में

77. सुभाषजी को नेताजी की उपाधि कहाँ मिली ?
(A) जर्मनी में (B) जापान में
(C) लंदन में (D) लाहौर में

78. "तुम मुझे खून दो–मैं तुम्हें आजादी दूँगा"–यह नारा किसने दिया ?
(A) गोखले (B) तिलक
(C) बोस (D) गांधी

79. 'आजाद हिंद फौज' का गठन किसने किया ?
(A) सुभाष (B) नेहरू
(C) गांधी (D) तिलक

80. 'आजाद हिंद फौज' को किस नारे से सुभाष ने प्रेरित किया ?
(A) लंदन चलो (B) दिल्ली चलो
(C) कलकत्ता चलो (D) मद्रास चलो

81. सुभाष ने बर्मा के रास्ते से कहाँ पहुँचकर भारतीय झंडा फहराया ?
(A) कोहिमा में (B) जर्मनी में
(C) जापान में (D) लंदन में

82. सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु कब हुई ?
(A) 19 अगस्त, 1945 को
(B) 18 अगस्त, 1945 को
(C) 10 अगस्त, 1946 को
(D) 20 अगस्त, 1945 को

उत्तरमाला

1. (A)	2. (C)	3. (D)	4. (A)	5. (B)
6. (C)	7. (C)	8. (B)	9. (B)	10. (A)
11. (D)	12. (A)	13. (C)	14. (A)	15. (C)
16. (B)	17. (B)	18. (C)	19. (A)	20. (D)
21. (B)	22. (A)	23. (B)	24. (C)	25. (A)
26. (B)	27. (B)	28. (C)	29. (A)	30. (D)
31. (A)	32. (C)	33. (A)	34. (D)	35. (A)
36. (A)	37. (D)	38. (A)	39. (D)	40. (C)
41. (D)	42. (B)	43. (A)	44. (B)	45. (A)
46. (A)	47. (C)	48. (A)	49. (A)	50. (B)
51. (A)	52. (B)	53. (A)	54. (D)	55. (C)
56. (A)	57. (D)	58. (C)	59. (A)	60. (B)
61. (C)	62. (C)	63. (B)	64. (C)	65. (A)
66. (C)	67. (C)	68. (B)	69. (C)	70. (B)
71. (C)	72. (A)	73. (A)	74. (B)	75. (A)
76. (B)	77. (A)	78. (C)	79. (A)	80. (B)
81. (A)	82. (B)			

7

भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति में अलगाववादी प्रवृत्तियाँ
(Separatist Trend in Indian Nationalist Politics)

[मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा, 1945 ई. के बाद की स्थिति, साम्प्रदायिक हिंसा, देश का विभाजन एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति (The Muslim League and The Hindu Mahasabha, The Post-1945 Developments, Partitions and Independence)]

भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति में अलगाववादी प्रवृत्तियाँ

हिन्दू और मुसलमानों के मध्य उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक पर्याप्त सहयोग एवं समर्पण की भावना थी. 1857 ई. के दौरान वे कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय सहयोग दिया. 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अनेक कारण ऐसे रहे जिनके कारण भारत में साम्प्रदायिकता ने जन्म लिया और यह साम्प्रदायिकता इस हद तक बढ़ी कि इसका परिणाम भारत विभाजन के रूप में देखना पड़ा. उन तात्कालिक कारणों में से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित थे जोकि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में साम्प्रदायिकता को प्रविष्ट करने में में प्रभावी सिद्ध हुए.

'फूट डालो-राज करो' की नीति–अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति भारत में सांप्रदायिकता फैलाने में सबसे प्रमुख कारण रही. अंग्रेजों को मुगल शासकों से सदैव भय बना रहा. उनका प्रयास सदैव मुस्लिम शासकों को दबाने में ही लगा रहा. स्थिति यहाँ तक थी कि 1857 ई. के बाद अंग्रेज जहाँ हिन्दुओं से नरमी से पेश आते थे वहीं वे मुसलमानों के साथ आक्रामक रुख अपनाते थे. एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में ही 27,000 मुसलमानों को फाँसी की सजा दी गई थी. मुसलमानों का राजनीतिक अधःपतन करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. लार्ड एलिनबरो ने स्पष्ट कहा था "यह जाति (मुसलमान) सिद्धांततः हमसे विद्वेष रखती है और इसी कारण हमारी नीति हिन्दुओं को सन्तुष्ट करने की है." इस नीति के कारण शासन एवं सेना में मुसलमानों का प्रवेश बन्द कर दिया गया. हिन्दू और मुसलमानों के मध्य खाई बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने अदालतों में उर्दू के स्थान पर हिन्दी भाषा के प्रयोग के लिए किए गए आंदोलन को अपना समर्थन दिया जिससे उत्तर प्रदेश व बिहार के मुसलमानों में वैमनस्यता पनप गई. विभिन्न वर्गों के हितों और स्वार्थों को अलग-अलग प्रश्रय देकर सरकार ने भारत में साम्प्रदायिक भावना का बीजारोपण किया जिसके भयंकर परिणाम निकले.

मुसलमानों का आर्थिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ापन–हिन्दुओं को अंग्रेजों की ओर से सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर दिए जाने के कारण मुसलमान और पिछड़ते चले गए. अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई बंगाल की स्थायी भू-व्यवस्था ने पुराने भूमिपतियों का जिनमें अनेक मुसलमान थे, नाश कर दिया. उनकी जगह जमींदारों का नया वर्ग पैदा हुआ, जिनमें अनेक हिन्दू थे, परिणामस्वरूप मुसलमानों का हिन्दुओं के प्रति विद्वेष बढ़ना स्वाभाविक ही था. अपनी रूढ़िवादिता और कट्टरता के कारण मुसलमानों के द्वारा शिक्षा का लाभ नहीं लिया गया और वे सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ते गए. ज्यों-ज्यों उनका पिछड़ना जारी रहा, त्यों-त्यों आपसी वैमनस्यता परवान चढ़ने लगी.

धर्म सुधार आंदोलनों का प्रभाव–धर्म सुधार आंदोलनों का प्रभाव यह पड़ा कि अमूमन प्रत्येक धर्म सुधारक ने अपने-अपने धर्म के ही गौरव को बढ़ाने के प्रयास किए. जहाँ हिन्दू धर्म सुधारक आर्य धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने में लगे थे, वहीं मुसलमान सभी गैर-मुसलमानों के प्रति धर्म युद्ध का नारा देकर देश में 'दार-उल-इस्लाम' की स्थापना करना चाहते थे. इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों वर्ग एक-दूसरे को शंका की नजर से देखने लगे.

साम्प्रदायिक इतिहास की शिक्षा का प्रभाव–अंग्रेज और उनसे प्रभावित कुछ भारतीय इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर ऐसे इतिहास की रचना की जिसने हिन्दू मुसलमानों के मध्य फूट का बीजारोपण कर दिया. धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास हिन्दू काल और मुसलमान काल में विभक्त हो गया. इतिहासकारों ने हिन्दू राजाओं के काल को स्वर्णिम काल की संज्ञा दी. इतिहासकारों ने कुछ ऐसा लिखा कि मुसलमानों तथा हिन्दुओं में आपसी विद्वेष का पनपना स्वाभाविक था.

हिन्दू कट्टरपंथ का उदय–साम्प्रदायिकता का विकास करने में हिन्दू कट्टरपंथ ने भी योगदान दिया. हिन्दू धर्म सुधारकों ने हिन्दुओं में जातीय श्रेष्ठता का दंभ भर दिया. वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और दूसरों को खास कर मुसलमानों को हेय दृष्टि से देखने लगे. इस प्रकार का वातावरण दोनों वर्गों के मध्य आपसी सौहार्द्रता कम करता गया.

अलीगढ़ आंदोलन और सर सैय्यद अहमद खाँ की भूमिका–सर सैय्यद अहमद खाँ ने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा के प्रति प्रेरित किया. हालांकि वे पूर्व में दोनों वर्गों के हितैषी थे, परन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण कालांतर में उनके विचारों में परिवर्तन आया. वे रूढ़िवादी और साम्प्रदायिक बनते गए. उनको प्रजातंत्र की स्थापना उचित नहीं लगी. उन्हें यह भय हुआ कि संसदात्मक प्रजातंत्र के फलस्वरूप पूरा देश दो दलों हिन्दू तथा मुसलमानों में बँट जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक मुसलमान कभी सत्ता में नहीं आ सकेंगे फलतः उन्होंने अंग्रेजी राज और मनोनीत प्रशासकों को उचित माना. उनका मानना था कि कांग्रेस मुख्यतः हिन्दुओं की हितैषी है, अतः वे इसके प्रबल विरोधी बन गए. 1888 ई. में इलाहाबाद अधिवेशन के समय उन्होंने कांग्रेस को तोड़ने का जी तोड़ प्रयास किया. इस प्रयास में विफल रहने पर उन्होंने "यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन", 1888 ई. की स्थापना की तथा इसके बाद 'मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल डिफेंस एसोसिएशन', 1893 ई. की स्थापना की. पहली संस्था के द्वारा कांग्रेस व हिन्दू विरोधी प्रचार किया गया तथा द्वितीय संस्था के द्वारा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को उनके ऐतिहासिक योगदान और राजनीतिक महत्व के आधार पर प्रस्तुत किया गया. संस्था ने यू. पी. में हिन्दुओं के समान प्रतिनिधित्व, पृथक् निर्वाचन पद्धति एवं आरक्षण की माँग की. 1888 ई. में सैय्यद अहमद ने यह भी कहा कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग 'कौम' (राष्ट्र) हैं, जिनके अपने-अपने स्वार्थ हैं. इन विचारों ने हिन्दू-मुस्लिमों को बजाय पास आने के और दूर कर दिया.

मुस्लिम लीग की स्थापना–मुसलमानों ने अपनी सुरक्षा के लिहाज से कांग्रेस से विमुख होकर एक राजनीतिक संगठन अलग बनाने का निश्चय किया. चूँकि कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज चिंतित थे, वे स्वयं उसके प्रभाव को कम करने की फिराक में थे, अतः उन्होंने मुस्लिमों का इस कार्य में सहयोग किया. कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य आर्चबोल्ड तथा वायसराय मिंटो के प्राइवेट सेक्रेटरी डनलप स्मिथ ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उसके संकेत पर 36 मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खाँ की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर, 1906 ई. को वायसराय मिंटो से शिमला में मिला. शिष्टमंडल ने वायसराय को राजभक्ति का आश्वासन दिया तथा अपने लिए कुछ सुविधाओं की माँग की. इन माँगों में प्रमुख थीं–मुसलमानों को उनके राजनीतिक महत्व और साम्राज्य की रक्षा में की गई सेवाओं के आधार पर व्यवस्थापिका सभाओं में स्थान देना, नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व देना, हाईकोर्ट तथा अन्य अदालतों में मुसलमान न्यायाधीशों की बहाली एवं मुस्लिम निर्वाचक मंडल की स्थापना करना. वायसराय ने उनकी माँगों को उचित ठहराते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया. इस निर्णय से उत्साहित होकर मुसलमानों ने एक केन्द्रीय संगठन बनाने की योजना बनाई. दिसम्बर, 1906 ई. में ढाका में मोहम्मडन एजूकेशन कांग्रेस में भाग लेने के लिए प्रमुख मुसलमान एकत्र हुए थे. वहीं संस्था के निर्माण की योजना बनी. 30 दिसम्बर, 1906 ई. को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन मुल्क, आगा खां और नवाब बकर-उल-मुल्क के प्रयासों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया.

मुस्लिम लीग के उद्देश्य–मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित बिन्दुवार रेखांकित किया जा सकता है–

1. भारत के मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी बढ़ाना तथा सरकार के प्रति गलतफहमी को दूर करना.

2. भारत के मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को विनीत ढंग से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना.

3. पहले दोनों उद्देश्यों को नुकसान पहुँचाए बिना मुसलमानों तथा अन्य सम्प्रदायों के मध्य मैत्री भाव का प्रचार करना.

हिन्दू महासभा–मुसलमानों की राह पर चलते हुए हिन्दू समुदाय ने भी विधायिकाओं में पृथक् निर्वाचन मंडल एवं सरकारी नौकरियों की माँग करनी शुरू कर दी. उन्होंने यू. पी. व बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी इस सुविधा को पाने के लिए अंग्रेज सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया. उन्होंने हिन्दी को हिन्दुओं की तथा उर्दू को मुसलमानों की भाषा बनाकर साम्प्रदायिकता का रुख और तेज कर दिया. उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में उर्दू के बदले देवनागरी लिपि में हिन्दी को शासन की भाषा के रूप में माँग की जाने लगी. हिन्दुओं की माँग के आधार पर 1900 ई. में

लेफ्टीनेंट गवर्नर ऐंथनी मैक्डनेल ने हिन्दी को न्यायालयों की वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जो हिन्दू-मुसलमानों के सम्बन्धों में दरार का प्रमुख कारण बनी. मुस्लिम साम्प्रदायिकता के जवाब में हिन्दुओं ने भारतीय इतिहास की उपनिवेशी मनोवृत्ति को पूरी तरह स्वीकार करते हुए उन्होंने मध्यकाल में मुसलमानों के 'अत्याचारी शासन' तथा मुस्लिम दमन से हिन्दुओं का बचाव करने में अंग्रेजों की विमुक्तिकारी भूमिका की भी चर्चा की. वस्तुतः 1870 ई. से प्रारम्भ होने वाले दशक से ही हिन्दू जमींदार, साहूकारों एवं मध्यमवर्गीय व्यवसायियों ने मुस्लिम विरोधी नारे लगाना प्रारम्भ कर दिया था. 1907 ई. के दौरान पंजाब में हिन्दू महासभा की स्थापना की गई, परन्तु एक राजनीतिक शक्ति के रूप में यह संस्था 1920 ई. में ही जाकर प्रतिष्ठित हो पाई थी.

साम्प्रदायवादियों की यह सामान्य नीति रही कि दूसरे के कार्य-कलापों की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई ही उनके द्वारा की जा रही है. इस प्रकार एक-दूसरे के द्वारा परस्पर दोषारोपण की प्रक्रिया चलती रही. मुसलमानों का कांग्रेस के प्रति रुझान कम होता गया. इसका प्रमाण इसी बात से मिलता है जब भी कहीं कांग्रेस का अधिवेशन होता उसमें मुस्लिमों की संख्या बहुत कम रहती. इस प्रकार साम्प्रदायिकता अपने इस रूप में सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुई थी और इसने हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख तथा पारसियों को काफी हद तक प्रभावित किया. जब साम्प्रदायिकता का बीजारोपण हो गया तो इसके विभिन्न रूपों को एक-दूसरे से पोषण मिला. मुसलमानों में सामंती तथा नौकरशाही का सामाजिक दबाव हिन्दुओं की तुलना में बहुत अधिक था, जबकि हिन्दुओं में आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग तथा उभरते हुए पूँजीवादी वर्ग को सामाजिक प्राधान्य प्राप्त था. मुस्लिम लीग को कट्टरपंथी बनाने में हिन्दू साम्प्रदायिकता एवं हिन्दू महासभा का भी बहुमूल्य योगदान था. हिन्दू महासभा की नीतियों और कार्यों ने मुसलमानों में असुरक्षा की भावना बढ़ा दी. हिन्दू महासभा, आर्य समाज एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहयोग से हिन्दू साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रही थी. इसने दावा किया कि भारत के अधिकतर मुसलमान हिन्दू धर्म के परिवर्तित हुए लोग हैं. उनके शुद्धीकरण की व्यवस्था की गई. जिससे वे फिर से हिन्दू धर्म में सम्मिलित किए जा सकें. मुस्लिम लीग द्वारा दिए गए 'दो पृथक् राष्ट्र' के सिद्धान्त को हिन्दू महासभा ने स्वीकार किया और नारा दिया–"हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए," साम्प्रदायिक दंगों में इसने हिन्दुओं की रक्षा भी की. इस संस्था ने मुसलमानों के द्वारा माँगे जाने वाली प्रत्येक माँग का विरोध किया. इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों में आतंक और घबराहट की भावना व्याप्त हो गई और उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे भारत में असुरक्षित हैं. इसी भावना के कारण वे विभाजन की माँग करने लगे.

1945 ई. के बाद की स्थिति और साम्प्रदायिक हिंसा– अंग्रेजी शासन के अन्तिम दो वर्षों में जो घटनाएँ घटीं, उनमें दो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं– ब्रिटिश कांग्रेसी एवं लीग के नेताओं के मध्य अत्यन्त धीमी गति से चलने वाली बातचीत जिसके साथ-साथ साम्प्रदायिकता का प्रवाह भी तेज हो चला था. 1913 ई. में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए. 1924 ई. में उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अधिकतर मुसलमानों के हितार्थ ही सोचने लगे, परन्तु उनके व्यापक प्रचार के बाद भी साम्प्रदायिक नीतियों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा तो उनके मन में यह ख्याल आया कि यदि वे उग्रवादी जनाधारित राजनीति का सहारा नहीं लेंगे तो धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे. सरकार के द्वारा जो माँगें मान ली जाती थीं उसके बाद भी कोई न कोई नई माँग रखना उस समय की आवश्यकता बन गई थी. यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सम्प्रदायवादियों की स्थिति और उनके अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगने का खतरा था. इस प्रकार के सोच व परिस्थितियों ने जिन्ना को उग्रवादी राजनीति की ओर ढकेल दिया. 3 मार्च, 1941 ई. को अलीगढ़ में दिए गए एक भाषण में उन्होंने कहा था कि "पाकिस्तान न केवल हासिल किया जा सकता है, बल्कि अगर आप इस देश में इस्लाम को पूरी तरह खत्म होने से रोकना चाहते हैं तो एकमात्र यही मकसद हो सकता है". 1941 ई. में ही मद्रास में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने कहा कि "हम किसी भी हालत में अखिल भारतीय संविधान और केन्द्र में एक सरकार नहीं चाहते. हम इस महाद्वीप में स्वाधीन राष्ट्र और स्वाधीन राष्ट्र के लिए कृत संकल्प हैं". अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद 1809 ई. में कूपलैण्ड योजना के अनुसार बनारस की एक साम्प्रदायिक घटना हुई. इसके बाद 1871-72 ई. में साम्प्रदायिकता की बड़ी घटना हुई. 1922 ई. से लेकर 1928 ई. के बीच का काल विशेष दुर्भाग्यपूर्ण रहा. इस दरम्यान 88 दंगों का हवाला मिलता है. इन दंगों में करीब चार सौ से अधिक लोग मारे गए थे. इनमें से कुछ दंगे तो ऐसे थे जिनका आधार आर्थिक समस्या था, परन्तु उन्हें जानबूझकर साम्प्रदायिकता का रूप दे दिया गया था. कलकत्ता में अगस्त 1946 ई. में हुए दंगों ने पाँच दिन में ही पाँच हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. उसके बाद नोवाखाली (बंगाल) में हिन्दुओं तथा बिहार में मुस्लिम हत्याकांडों ने तो इतिहास में एक नया अध्याय ही जोड़ दिया. विभाजन के समय उत्तर भारत के दंगे, गांधीजी की हत्या भी इन्हीं दंगों की श्रेणी में थी.

देश का विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति

आजादी और विभाजन की शुरूआत–क्रिप्स मिशन के असफल हो जाने के बाद 1942 ई. की अगस्त क्रांति की हिंसक घटनाओं का दोषारोपण सरकार ने महात्मा गांधी पर

किया. सरकार की ओर से गांधीजी तथा कांग्रेस पर ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने ही जनमानस को हिंसा करने पर मजबूर किया है. इस पर गांधीजी ने कहा कि उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए तथा मुकदमा चलाया जाए, परन्तु सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी. लाचार होकर गांधीजी ने जेल में ही 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च, 1943 ई. तक 21 दिनों का उपवास रखा. गांधीजी के निरन्तर गिरते स्वास्थ्य को लेकर सम्पूर्ण देश में उन्हें रिहा करने की माँग की गई. इस प्रश्न पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों ने त्यागपत्र भी दे दिया, फिर भी सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया. बाद में अधिक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण सरकार ने गांधीजी को स्वतः ही 1944 ई. में जेल से रिहा कर दिया.

राजगोपालाचारी योजना–जेल से रिहा होने के बाद गांधीजी ने राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिहाज से प्रयास किया. राजगोपालाचारी की योजना को स्वीकृति प्रदान कर उन्होंने साम्प्रदायिकता से उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध दूर करने का प्रयास किया. राजगोपालाचारी की योजना के अनुसार मुस्लिम लीग को भारत की स्वतंत्रता की माँग का समर्थन करना था तथा अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ सहयोग करना था. युद्ध की समाप्ति पर भारत के उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व के उन क्षेत्रों में जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक थे, एक आयोग के मार्फत इन इलाकों को स्पष्ट करना था. इन इलाकों में जनमत के आधार पर यह तय करना था कि वे भारत में रहना चाहते हैं या अलग होना. बँटवारे की स्थिति में प्रतिरक्षा, संचार, आवागमन एवं जनसंख्या का आदान-प्रदान एक समझौते द्वारा तय किया जाएगा. परन्तु ये सभी शर्तें तभी लागू हो सकती थीं जब अंग्रेज भारत की सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे.

गांधी-जिन्ना वार्ता–महात्मा गांधी ने राजगोपालाचारी की योजना के अनुसार कार्य करते हुए जिन्ना से भेंट करके इस योजना को स्वीकार करने के लिए कहा. गांधी तथा जिन्ना की वार्ता करीब दो सप्ताह चली, परन्तु अन्त में फेल हो गई. हालांकि गांधीजी बँटवारे को लेकर सहमत तो थे, परन्तु उनकी भावना यह थी कि बँटवारा तो हो, लेकिन एक संयुक्त परिवार की तरह. उधर जिन्ना की माँग यह थी कि पाकिस्तान में सिंध, उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, बंगाल, असम और बलूचिस्तान भी शामिल हों. गांधीजी की इच्छा थी कि देश का बँटवारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हो जबकि जिन्ना की तमन्ना यह थी कि बँटवारा स्वतंत्रता से पूर्व ही हो जाए. यह वार्ता भी असफल हो गई, लेकिन जिन्ना ने इस वार्ता को भारत-पाक विभाजन के मध्य एक प्रमुख हथियार के रूप में काम में लिया.

वैवेल योजना और शिमला सम्मेलन–अक्टूबर, 1943 ई. में लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वैवेल भारत के नए वायसराय बने. द्वितीय विश्व युद्ध भी 1945 ई. में समाप्त हो चुका था. इंग्लैण्ड में चुनाव होने वाले थे. इसलिए चर्चिल की सरकार लेबर दल के बढ़ते प्रभाव को देखकर भारत में पुनः संवैधानिक सुधारों का नाटक करने लगी. चर्चिल ने मार्च 1945 ई. में वैवेल को विचार-विमर्श के लिए लंदन बुलाया वापस आकर जून में उसने संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की.

इस योजना पर विचार किए जाने के उद्देश्य से 25 जून, 1945 ई. को भारतीय प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया गया. इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया तथा साथ ही गांधीजी पर नजरबंदी हटा ली गई.

25 जून, 1945 ई. को वैवेल की अध्यक्षता में शिमला में सम्मेलन की शुरूआत हुई, जिसमें कांग्रेस और लीग के अलावा सिख, दलित वर्ग तथा केन्द्रीय विधान सभा के यूरोपियन दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था. सम्मेलन में वैवेल ने अपना प्रस्ताव रखा. साम्प्रदायिक समस्या का निराकरण कर संवैधानिक गतिरोध को हटाना एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् का नए सिरे से गठन करना इस प्रस्ताव का उद्देश्य था. नगर परिषद् में वायसराय और प्रधान सेनापति के अलावा सभी भारतीय सदस्य रखे जाने थे. सारे विभाग भारतीयों को सौंप दिए जाने वाले थे. नए कौंसिल का कार्य प्रशासन एवं संविधान निर्माण पद्धति को निश्चित करना था. इसके साथ ही वायसराय के अधिकारों में कटौती नहीं करने का प्रस्ताव था, लेकिन यह आश्वासन दिया गया कि वह विवेकहीन तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा. इसी के साथ ही साथ राजनीतिक दलों की एक सम्मिलित सभा बुलाई जानी थी जिससे कि कार्यकारिणी परिषदों की सर्वमान्य या पृथक् सूचियाँ तैयार करके नियुक्तियाँ की जा सकें.

यहाँ तक तो वैवेल की सोच सही एवं प्रगतिशील थी, परन्तु साम्प्रदायिकता को कम करने के बजाय इसने इसे बढ़ाया ही. कार्यकारिणी परिषद् को लेकर विवाद खड़ा हो गया. अनुसूचित जाति के नेताओं ने भी पृथक् नामांकन का अधिकार माँगा. जिन्ना ने माँग की कि सूची तैयार करने का अधिकार मुस्लिम लीग को ही मिले. जिन्ना की अदूरदर्शिता तथा हठधर्मिता तथा वैवेल की अदूरदर्शिता के कारण शिमला सम्मेलन सार्थक नहीं रहा. 14 जुलाई, 1945 ई. को वायसराय ने सम्मेलन को असफल कहकर बंद कर दिया.

समझौते के नए प्रयास–जुलाई 1945 ई. में इंग्लैंड में चुनाव हुए जिसमें लेबर पार्टी को बहुमत मिला. अब चर्चिल के स्थान पर एटली प्रधानमंत्री बने. लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती थी. उसने भारत की समस्या के विषय में वैवेल को इंग्लैण्ड बुलाकर बातचीत की. एटली ने भारत में प्रांतीय और केन्द्रीय विधान सभाओं के लिए चुनाव करवाने

की भी घोषणा की. 1945-46 ई. के चुनावों में सामान्य स्थानों पर कांग्रेस को और मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर लीग को सफलता मिली. केन्द्रीय विधान सभा में कांग्रेस को 57 और लीग को 30 स्थान मिले. इसी प्रकार प्रांतों में भी कांग्रेस को बहुमत मिला जिससे हिन्दू बहुसंख्यक प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने. बंगाल और सिंध में लीग की सरकार बनी, परन्तु पंजाब में खिजर हयात खाँ के नेतृत्व में संविद सरकार बनी.

कैबिनेट मिशन योजना–महायुद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज सरकार की स्थिति बड़ी नाजुक थी और वह किसी भी प्रकार भारतीयों को संतुष्ट कर अपना राज्य बनाए रखना चाहती थी. उसके सामने सबसे प्रमुख समस्या यह थी कि वह अब भारतीय शासन तंत्र, सेना तथा पुलिस पर भी निर्भर नहीं रह सकती थी. समूचे भारत में आंदोलन हो रहे थे, देशी राजा-महाराजा भी विद्रोह कर रहे थे. पुलिस भी विद्रोह में शामिल हुई. सबसे विकट स्थिति तो तब बनी जब 18 फरवरी, 1946 ई. को बम्बई में नौसेना के नाविकों ने विद्रोह कर दिया. इस प्रकार की परिस्थिति देखकर सरकार घबरा गई. 19 फरवरी, 1946 ई. को एटली ने भारत की समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन (मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल) भारत भेजने की घोषणा की. बाद में उन्होंने यह भी कहा कि भारत को यह तय करने का अधिकार है कि उसका संविधान कैसा होगा. एटली ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी सुरक्षा की माँग की, परन्तु उसने साथ ही यह भी कहा कि "हम बहुसंख्यक समाज की अग्रगति को रोकने का अधिकार अल्पसंख्यक समाज को नहीं दे सकते." यह एक महत्वपूर्ण घोषणा थी. इसमें प्रथम बार भारत के लिए स्वाधीन शब्द का प्रयोग किया गया था.

कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 ई. को दिल्ली पहुँचा. मिशन का उद्देश्य यह था कि भारतीय जनमत के नेताओं के साथ मिलकर भारत में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को जल्दी सम्भव बनाया जाए. यह मिशन तीन सप्ताह तक विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करता रहा, इससे जिन्ना ने यह भलीभांति समझ लिया था कि वे बिना उसकी सहमति के भी सत्ता को भारतीयों के लिए हस्तांतरित कर सकते हैं.

कैबिनेट मिशन की योजना में सबसे बड़ा गुण यह था कि इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बहुत करीब ला दिया. डॉ. जैन के अनुसार "कांग्रेस को संतुष्ट रखने के लिए संगठित भारत की व्यवस्था की गई और मुस्लिम लीग तथा भारतीय नरेशों को संतुष्ट रखने के लिए उस संघ को दुर्बल रखा गया. अन्तरिम सरकार में समस्त उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंप दिए गए, परन्तु मिशन ने सिखों के हितों को ध्यान में नहीं रखा. उसके द्वारा खड़ी की गई प्रांतों के गुट बनाने की व्यवस्था दोषपूर्ण तथा अव्यावहारिक थी. संविधान बनाने की प्रणाली भी जटिल थी परन्तु फिर भी मिशन ने देशवासियों के मध्य एक नई आशा स्वतंत्रता की प्राप्ति का संचार किया.

अंतरिम सरकार की स्थापना–हालांकि शुरू में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया, परन्तु कांग्रेस को अंतरिम सरकार की योजना रास नहीं आई. इस पर लीग ने यह दावा किया कि वह कांग्रेस के बगैर भी अंतरिम सरकार का गठन कर सकती है. वायसराय की ओर से लीग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया. इस कृत्य से जिन्ना का नाराज होना स्वाभाविक था. जब जिन्ना को ऐसा लगा कि संविधान सभा में लीग की स्थिति कमजोर है, 29 जून, 1946 ई. को उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकृत कर दिया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली.

इसी दरम्यान 8 अगस्त, 1946 ई. को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास कराकर अंतरिम सरकार बनाने की योजना स्वीकार कर ली. सरकार के निर्माण के लिए वायसराय ने कांग्रेस के पास निमंत्रण भेजा. जवाहर लाल नेहरू ने जिन्ना को भी सरकार में शामिल होने के लिए कहा परन्तु जिन्ना अपनी बात पर अड़े रहे. 24 अगस्त, 1946 ई. को वायसराय ने अंतरिम सरकार के 14 मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी. नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाए गए थे. इस अंतरिम सरकार को 2 सितम्बर को कार्यभार सँभालना था. बाद में वायसराय के कहने पर अक्टूबर, 1946 ई. में जिन्ना ने भी सरकार में शामिल होना तय कर लिया था.

मुस्लिम राजनीति व बँटवारे की माँग–दिसम्बर, 1906 ई. में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई. मिण्टो मार्ले सुधार योजना के द्वारा 1909 ई. में मुसलमानों के लिए पहली बार अधि-प्रतिनिधित्व एवं पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था की गई. प्रथम युद्ध के समय लीग ने भी अंग्रेजों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया. जिन्ना भी कांग्रेस के साथ थे. वे 1913 ई. के कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, जो लंदन गया था, उसमें शामिल भी हुए. 1916 ई. में कांग्रेसी-लीग समझौता अथवा लखनऊ समझौते ने कांग्रेस व लीग को एक-दूसरे के निकट ला दिया. 1923 ई. से लेकर 1928 ई. तक हिन्दू प्रतिक्रियावादियों और मुसलमान साम्प्रदायिकतावादियों के चलते भारत के विभिन्न भागों में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए. 1928 ई. में साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रश्न को लेकर लीग में फूट पड़ गई. इस दौरान जिन्ना लीग के सबसे अधिक ताकतवर नेता के रूप में उभरे. नेहरू रिपोर्ट को जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया. अपने अविश्वास के चलते मार्च 1929 ई. में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री माँगें रख दीं, जोकि गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम माँग का आधार बनीं. जब जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया तो मुस्लिम लीग

ने कांग्रेस विरोधी और ब्रिटिशपरस्त रुख धारण कर लिया. वह अंग्रेजों से सहूलियत पाने की आशा रखती थी. इसलिए वह कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुई, परन्तु गोलमेज सम्मेलन में उसने साम्प्रदायिक प्रश्नों को तेजी के साथ उछाला.

गोलमेज सम्मेलन और मुस्लिम राजनीति–गोलमेज सम्मेलनों के बाद भारतीय राजनीति में मुस्लिम साम्प्रदायिकता में बढ़ोत्तरी होती गई. भारत की संवैधानिक समस्या को हल करने के लिए लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन हुए. प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवम्बर, 1930 ई. में लीग ने विचित्र रुख अपनाया. मुसलमानों में भी दो विचारधाराएँ थीं. बंगाल तथा पंजाब के नेता जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की माँग कर रहे थे, परन्तु अन्य क्षेत्रों में अधिप्रतिनिधित्व की माँग की जा रही थी. इसके साथ ही पृथक् निर्वाचन और संयुक्त निर्वाचन की माँग भी जोर पकड़ रही थी. परन्तु इस प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हुआ और प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ.

सितम्बर 1931 ई. में द्वितीय गोलमेज का आयोजन हुआ. इस सम्मेलन में भी साम्प्रदायिकता का प्रश्न मुख्य रूप से उभरकर आया. गांधीजी ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की कोशिश भी की परन्तु वे असफल रहे. ब्रिटिश अधिकारियों तथा साम्प्रदायिक तत्वों ने गांधीजी के खिलाफ एक मोर्चा कायम कर लिया. इस पर गांधीजी ने कहा–"साम्प्रदायिक मतभेद की बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गरमी में पिघल जाएगा". परन्तु उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. चूँकि अंग्रेज साम्प्रदायिकता की आड़ में भारत में संवैधानिक सुधारों एवं स्वतन्त्रता की आकांक्षाओं को नष्ट करना चाहते थे, अतः मैक्डोनाल्ड ने यह तर्क दिया कि चूँकि भारतीय प्रतिनिधियों में आपसी मतभेद हैं, अतः अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक प्रश्नों का निवटारा सरकार स्वयं कानून बनाकर करेगी, परिणामस्वरूप निराश और दुःखी होकर गांधीजी लौट आए और इस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल ही रहा.

साम्प्रदायिक निर्णय–द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने साम्प्रदायिकता और तेज कर दी. ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैक्डोनाल्ड ने 14 अगस्त, 1932 ई. को अपना प्रसिद्ध साम्प्रदायिक निर्णय दिया. इस व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले सम्प्रदायों में मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों, भारतीय ईसाइयों इत्यादि को शामिल किया गया. उनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई. अछूतों को सवर्ण हिन्दुओं से अलग निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व दिया गया. जिन क्षेत्रों में हिन्दुओं की संख्या कम थी वहाँ उन्हें मुसलमानों जैसी सुविधाएँ नहीं दी गईं. इसके विपरीत जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या कम थी वहाँ जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया. पंजाब और बंगाल में जहाँ मुसलमान बहुमत में थे, उनके लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था की गई. इस प्रकार यू. पी., बिहार तथा मद्रास के मुसलमानों को प्रसन्न करने तथा कांग्रेस के प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई थी. इस प्रकार की दोगली नीति ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को अधिक बढ़ावा दिया. मुस्लिम लीग का आलम यह था कि वह मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ माँगने लगी और शीघ्र ही पाकिस्तान की माँग भी होने लग गई.

भारत सरकार अधिनियम और प्रांतीय सरकारों का गठन–मार्च, 1933 ई. में तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया. इसी के आधार पर 1935 ई. का भारत सरकार अधिनियम पास हुआ. हालांकि यह अधिनियम न तो कांग्रेस को और न ही मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर सका. हालांकि इन दोनों ने ही इसे अस्वीकार कर दिया, परन्तु 1937 ई. में होने वाले प्रांतीय चुनावों में दोनों ने हिस्सा लिया. इन चुनावों में कांग्रेस को अधिक सफलता मिली.

चुनावों के बाद जब सरकार गठन का नम्बर आया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद स्पष्ट हो गए. जिन्ना ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की प्रतिनिधि पार्टी बनाने की भरसक कोशिश की. उन्हें यह आशा थी कि जहाँ कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला वहाँ वह सरकार बनाने के लिए लीग का समर्थन लेगी. उधर कांग्रेस बहुमत प्राप्त प्रांतों में भी लीग को शामिल करने को तैयार थी, परन्तु उसकी शर्त थी कि लीग अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दे, परन्तु लीग ने ऐसा नहीं किया. परिणामस्वरूप कांग्रेस ने भी उसे सरकार में शामिल नहीं किया. 6 बहुमत प्राप्त प्रांतों में कांग्रेस की सरकार स्वतः ही बन गई. पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम तथा सिंध में भी कांग्रेस ने अन्य दलों का सहयोग लेकर सरकार बनाई, लेकिन लीग को शामिल नहीं किया. कांग्रेस के इस कृत्य से जिन्ना क्रुद्ध और निराश हो गए. सिर्फ बंगाल तथा पंजाब में क्रमशः प्रजा पार्टी और यूनियनिस्ट के सहयोग से लीग सरकार में सम्मिलित हो सकी. इस निराशा के बाद जिन्ना ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि, "मुसलमानों को अधिकाधिक विरोधी बनाने का उत्तरदायित्व कांग्रेस नेताओं पर है" अब उनकी एक ही मंशा थी कि प्रत्येक मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना व विरोध करना.

सिकंदर जिन्ना पैक्ट–मुस्लिम लीग का 1937 ई. में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ. इसी अधिवेशन में जिन्ना और पंजाब के मुख्यमंत्री सर सिकंदर हयात खाँ के मध्य समझौता हुआ, जिसे सिकंदर-जिन्ना पैक्ट के नाम से जाना

जाता है. इस समझौते के अनुसार पंजाब में उनके दल (यूनियनिस्ट पार्टी) के सदस्यों को मुस्लिम लीग की सदस्यता दिलाने की माँग की गई, परन्तु मंत्रिमंडल यूनियनिस्ट दल का ही कहा जाना था. यह कोई लिखित समझौता नहीं था केवल मात्र घोषणा भर ही थी. दोनों ही पार्टियों के अपने-अपने स्वार्थ थे. सिकंदर ऐसा करके मुस्लिम लीग के सम्भावित हमले से बचना चाहते थे और जिन्ना पंजाब में अपनी पार्टी का वर्चस्व चाहते थे. अतः 1938 ई. में पंजाब में नई मुस्लिम लीग को जिसमें यूनियनिस्ट का प्रभाव ज्यादा था, मान्यता प्रदान कर दी गई.

पीरपुर समिति का गठन–हालात यहाँ तक पहुँचे कि जिन्ना हमेशा कांग्रेस पर दोषारोपण करते और उधर कांग्रेस मुस्लिम लीग की आलोचना करने लगी थी. 1938 ई. में मुस्लिम लीग ने एक जाँच कमेटी 'पीरपुर समिति' के नाम से गठित की, जिसका कार्य हिन्दू मुसलमानों के ऊपर हुए अत्याचारों की जांच करना था. राजा मोहम्मद मेंहदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया.

पीरपुर समिति की देखरेख में बिहारशरीफ रिपोर्ट तथा फज्ल-उल-हक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें कांग्रेस के अत्याचारों का वर्णन था. इसके बाद भी कांग्रेस ने जिन्ना को समझाने का प्रयास किया, परन्तु जिन्ना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 1938 ई. में उन्होंने गांधी को स्पष्ट रूप से लिखा–"अब हम एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ हमको संदेह की भाषा छोड़ देनी चाहिए. आप यह स्वीकार करें कि मुस्लिम लीग भारत के समस्त मुसलमानों की प्रामाणिक तथा प्रतिनिधि संस्था है. आप और कांग्रेस दोनों केवल हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं". इसके बाद कांग्रेस तथा लीग के रास्ते अलग-अलग हो गए.

मुक्ति दिवस मनाना–जब सरकार से इस्तीफा दे दिया गया तो जिन्ना अत्यंत प्रसन्न हुए. 22 दिसम्बर, 1939 ई. को कांग्रेसी शासन अत्याचारों के खिलाफ मुस्लिम लीग ने 'मुक्ति दिवस' मनाने का निश्चय किया. जिन्ना ने अपने मन के भावों को इस प्रकार व्यक्त किया–"कांग्रेस शासन की समाप्ति पर यह सभा चैन की सांस लेती है और आज के दिन को अधिनायकवाद, दमन और अन्याय से मुक्ति का दिवस मानती है". इसके बाद भी जगह-जगह पर प्रदर्शन करके मुस्लिम लीग ने कड़ा प्रतिरोध जाहिर किया.

देश के विभाजन की माँग

जिन्ना का रोष दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था. उन्होंने माँग की कि भावी संविधान में कांग्रेस और लीग को समान अधिकार मिलने चाहिए. मुसलमान किसी भी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें बहुसंख्यक हिन्दुओं की सरकार हो. चूँकि मुसलमानों में पृथकतावादी तत्व बहुत पहले से ही थे और वे मुसलमानों के लिए अलग देश की माँग कर रहे थे. इस माँग को रखने वाले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ भारतीय मुसलमान थे जिनका नेतृत्व चौधरी रहमत अली कर रहे थे. उनकी अध्यक्षता में लंदन में "पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट" चलाया जा रहा था. उन्होंने 1933 ई. में यह कहा कि हिन्दुस्तान एक, महादेश है, वह एक राष्ट्र नहीं, बल्कि दो राष्ट्र हैं. एक हिन्दू तथा दूसरा मुसलमान. हिन्दुस्तान का नाम 'इंडिया' के 'बदले' 'दीनिया' कर दिया जाना चाहिए. हिन्दुस्तान में बंगिस्तान (बंगाल), उस्मानिस्तान (हैदराबाद), म्यूनिस्तान (राजस्थान) आदि सूबों को अलग-अलग सूबों के रूप में गठित करके सबका एक संघ 'पाकिस्तान' बना देना चाहिए. रहमत अली, अब्दुल लतीफ तथा सिकंदर हयात आदि ने भारत विभाजन की अलग-अलग योजनाएँ पेश कीं. शुरूआत में तो लीग का कहना यह था कि ये योजनाएँ केवल व्यावहारिक ही हैं, परन्तु बाद में उसका रवैया बदल गया. 1940 ई. में उसने अलग से पाकिस्तान बनाने की माँग रख दी.

मुस्लिम लीग की ओर से 1940 ई. में लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसे हम 'पाकिस्तान प्रस्ताव' के नाम से जानते हैं, हालांकि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था. सिकंदर हयात खाँ, फज्ज उल हक, खलीक-उ-जम्मा ने इस प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था. इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन का यह दृढ़ विचार है कि इस देश में कोई भी संवैधानिक योजना उस समय तक मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जब तक वह इस आधार पर न बनी हो कि उत्तर, पश्चिमी और पूर्वी भारत के मुसलमानों के बहुसंख्यक भौगोलिक दृष्टि से संलग्न क्षेत्रों को पृथक् स्वायत्त सम्पन्न स्वतंत्र राज्यों में न बना दिया जाए. यह अस्पष्ट प्रस्ताव था. इसकी वास्तविक रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा लीग की वर्किंग कमेटी को सौंपा गया.

पाकिस्तान बनाने की माँग के कारण

यहाँ यह गौरतलब है कि मुस्लिम लीग जो पहले कांग्रेस की ही तरह भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थी वह अचानक कैसे अलग पाकिस्तान बनाने की माँग करने लगी ? इसके भी कई कारण थे जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं–

अंग्रेजों की चाल–चूँकि अंग्रेजों की यह चाल थी कि "फूट डालो और राज करो". इस नीति के मार्फत वे अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते थे. अतः अंग्रेज प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से मुस्लिमों को तथा लीग को अपने पक्ष में मिलाने लगे. मुसलमानों की उचित-अनुचित माँगों को मानकर उन्होंने उनको अपने कब्जे में कर लिया तथा साम्प्रदायिकता की आड़ में पाकिस्तान की माँग के लिए उकसाया.

1937 ई. के चुनावों में विफलता व आतंक की भावना–1937 ई. में जो चुनाव हुए उनमें लीग की अपेक्षा कांग्रेस को अधिक सफलता मिली. कांग्रेस ने न तो लीग का समर्थन ही लिया और न ही उसे सरकार में शामिल किया, जिससे लीग का नाराज होना तथा कांग्रेस व हिन्दुओं का विरोध करना लाजिमी था. उन्हें यह भी डर था कि हिन्दू बहुल प्रांतों में कांग्रेसी सरकार द्वारा उन पर अत्याचार किया जाएगा, जिससे उनका रवैया कांग्रेस विरोधी होता गया. यह भी प्रचारित किया गया कि भारतीय संसदात्मक प्रणाली में मुसलमान सदैव अल्पमत में रहेंगे और उनके हितों पर भी आंच आ सकती है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिहाज से मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बना दिया जाए. विभाजन की योजनाएँ 1930 ई. से ही बनने लगी थीं. इन योजनाओं पर अंग्रेजों की प्रतिक्रिया जानने के लिए 1938 ई. में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें लीग की कार्यकारिणी के दो सदस्य भी थे, पेलेस्टाइन सम्मेलन में भाग लेने के लिए मिस्र गया. उन लोगों ने इंग्लैण्ड में भारत सचिव व उपसचिव से भारत विभाजन की योजना पर बातचीत की और उनकी सहमति जानकर 1939 ई. में भारत लौटा. इससे जिन्ना की हौसलाअफजाई हुई और उन्होंने 1940 ई. में 'पाकिस्तान प्रस्ताव' पेश किया.

लीग की शक्ति में विकास–लीग की शक्ति में अचानक वृद्धि होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारण रहा. 1936-39 ई. के दौरान लीग की शक्ति में तेजी के साथ वृद्धि हुई. 1927 ई. में जहाँ इसकी सदस्य संख्या 1330 थी वहीं 1938 ई. में यह लाखों में पहुँच गई. 1944 ई. तक यह 44 लाख तक हो गई. अपनी ताकत के आधार पर ही लीग ने ऐसी माँगें रखकर अपना प्रभुत्व दिखाना शुरू कर दिया था. इस प्रकार के व्यवहार से कांग्रेस तथा लीग में वैमनस्यता बढ़ती गई.

हिन्दू साम्दायिकता का विकास–हिन्दू महासभा की नीतियों एवं क्रियाकलापों ने मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी. हिन्दू महासभा, आर्य समाज, एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहयोग से हिन्दू साम्प्रदायिकता का प्रचार किया जा रहा था. इन संस्थाओं का कहना था कि मुसलमानों का मुख्य भाग हिन्दू धर्म से परिवर्तित लोगों का है. इनके शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए जिससे वे पुनः हिन्दू धर्म में प्रविष्ट हो सकें.मुस्लिम लीग के द्वारा दिए गए नारे "दो पृथक् राष्ट्र" का जवाब देते हुए हिन्दू संस्थाओं ने नारा दिया "हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए" इन संस्थाओं के आक्रामक तेवर देखते हुए मुसलमानों में यह भय व्याप्त हो गया कि उनके हित भारत में सुरक्षित नहीं है. इसलिए भारत विभाजन की माँग जोर पकड़ने लगी.

कांग्रेस की नीतियाँ–जहाँ मुस्लिम स्वयं अपना अलग अस्तित्व चाहते थे वहीं कांग्रेस की नीतियाँ भी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी रहीं. कांग्रेस की ओर से मुसलमानों को अपने प्रभाव में लाने के प्रयास से लीग के नेताओं में घबराहट फैली. मुसलमानों को लीग की तरफ आकृष्ट करने के उद्देश्य से लीग ने पाकिस्तान बनाने की माँग करनी शुरू कर दी. उत्तर प्रदेश में नेहरू तथा पुरुषोत्तमदास टंडन ने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दीं जिनसे मुस्लिम लीग का सरकार में रहना लगभग असम्भव-सा हो गया. इसी प्रकार सरदार पटेल ने मुंबई में अल्पसंख्यक पारसी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया और हिन्दू नेता बी. जी. खेर को मुख्यमंत्री बनाया. गांधी पर पटेल के प्रभाव से भी मुस्लिम लीग को शंका होती थी कि सभी कांग्रेसी हिन्दूपरस्त नीति अपना रहे हैं. ऐसी परिस्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए लीग ने विभाजन की योजना रखी.

अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन–द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन तथा मित्र राष्ट्रों की स्थिति नाजुक हो गई थी. इस युद्ध में भारतीयों का सहयोग आवश्यक था. अतः भारत में राजनीतिक वातावरण को शांत बनाए रखने की खातिर 8 अगस्त, 1940 ई. को वायसराय ने 'अगस्त प्रस्ताव' पेश किया. इस प्रस्ताव में विशेषरूप से मुस्लिम हितों की बात थी. इसमें यह स्पष्ट रूप से उद्घोषित किया गया कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी. कांग्रेस इस प्रस्ताव से नाखुश थी. इस कारण से उसने इसका विरोध किया, परन्तु मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माँग स्वीकार न किए जाने का बहाना बनाकर ऊपर से तो अपनी असहमति जाहिर कर दी, परन्तु अन्दर से वह संतुष्ट थी, क्योंकि उसके हाथ में अब एक ऐसा हथियार आ गया था, जिसके कारण वह अपनी मांग पूरी करवा सकती थी.

"भारत छोड़ो आंदोलन" तथा "बाँटो और भागो" का नारा–कांग्रेस ने 1942 ई. में सरकारी रवैये से तंग आकर अंग्रेजों के खिलाफ "भारत छोड़ो" का नारा दिया. इस भारत छोड़ो आंदोलन से लीग तटस्थ रही. दिसम्बर, 1942 ई. में लार्ड लिनलिथगो ने जब भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने की बात कही तो लीग क्रोधित हो उठी. उसने 1943 ई. में कराची अधिवेशन में "अंग्रेजो भारत छोड़ो" नारे के जवाब में "अंग्रेजो बाँटो और भागो" का नारा बुलंद किया. उसकी मंशा यह थी कि अंग्रेज लीग के लिए पाकिस्तान सौंप दें और यहाँ से चले जाएँ. उसने भारतीय एकता को बनाए रखने वाले संविधान को लागू करने का विरोध करने के लिए समितियाँ भी बनाईं.

प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस–महात्मा गांधी ने राजगोपालाचारी योजना के बाद जिन्ना से भेंट की और इस योजना को स्वीकार करने के लिए कहा, परन्तु जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया. कैबिनेट मिशन शिमला समझौते की असफलता के बाद भारत लौटा. इसने अंतरिम सरकार की व्यवस्था की परन्तु पाकिस्तान की माँग को ठुकरा दिया. बदले में कांग्रेस और लीग दोनों ने मिशन को तो स्वीकार किया, परन्तु अंतरिम सरकार में शामिल होने के प्रश्न पर समस्या खड़ी हो गई. पहले कांग्रेस ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया तो लीग ने बिना कांग्रेस के सहयोग से ही सरकार बनाने का दावा किया, परन्तु वायसराय कांग्रेस को अलग रखकर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने लीग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. इस पर नाराज होकर लीग ने 27 जुलाई, 1946 ई. को कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार करके 16 अगस्त, 1946 ई. को पाकिस्तान के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय किया. बाद में जब कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार हुई तो नेहरू ने जिन्ना को भी सरकार में शामिल करने का सुझाव दिया, परन्तु जिन्ना अपनी ही जिद पर अड़े रहे. 16 अगस्त, 1946 ई. को कोलकाता, में भयानक दंगा-फसाद हुआ. उस समय लीगियों ने नारा लगाया, "लड़कर लेंगे पाकिस्तान". इन दंगों में हजारों लोग मारे गए. नोआखली, बिहार तथा अन्य जगहों पर भी दंगे भड़के. लीग इस समय बड़ी हताश थी तथा उसका यह प्रयास था कि किसी भी तरह सत्ता को हथियाया जाए जिससे देश का विभाजन किया जाए और मुसलमानों को एक सुरक्षित स्थान मिल सके.

लीग का सरकार में प्रवेश–जब अंतरिम सरकार गठन होने का समय आया तो वायसराय ने लीग को भी सरकार में शामिल होने का न्यौता दिया. जिन्ना के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप लीग भी सरकार में शामिल हो गई. सरकार में लीग के नेता लियाकत अली को वित्त विभाग सौंपा गया था. लियाकत अली ने ऐसा बजट बनाया जिसमें साम्प्रदायिकता का पुट था. नए बजट में व्यापारी तथा उद्योगपतियों पर 25% कर लगाया गया, जिससे अधिकतर हिन्दुओं में रोष व्याप्त हो गया. भाषा तथा आंतरिक व्यवस्था पर भी कांग्रेस तथा लीग में बराबर मतभेद बना रहा.

लंदन कांफ्रेंस–3 दिसम्बर से लेकर 6 दिसम्बर, 1946 ई. तक लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गतिरोध दूर करना. सम्मेलन में कोई ठोस परिणाम नहीं आए और सम्मेलन असफल हो गया. दिसम्बर, 1946 ई. को होने वाली संविधान सभा की बैठक का लीग द्वारा बहिष्कार कर दिया गया.

एटली की घोषणा–भारत की तत्कालीन स्थिति से चिंतित होकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी, 1947 ई. को यह घोषणा की कि अंग्रेज जून, 1948 ई. से पूर्व ही सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे. घोषणा में यह भी कहा गया कि अगर संविधान सभा उस तिथि तक कोई संविधान तैयार नहीं कर सकेगी तो अंग्रेजी सरकार यह निश्चित करेगी कि सत्ता किसे सौंपी जाए–किसी केन्द्रीय सरकार को या प्रांतीय सरकारों को. सत्ता के हस्तांतरण के कार्य को पूरा करने के लिए लॉर्ड वैवेल की जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को नए वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया.

सत्ता का हस्तांतरण और माउंटबेटन की योजना–जब लगभग यह तय हो गया कि भारत को स्वतंत्रता मिल ही जाएगी तब बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे हुए. इसमें लीग, हिन्दू महासभा और अकाली दल तीनों ने हिस्सा लिया. लाहौर में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हुए. तक्षशिला, लाहौर, अमृतसर, रावलपिंडी, बिहार, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में भीषण नरसंहार हुआ. इसी वातावरण के दौरान 24 मार्च, 1947 ई. को नए वायसराय ने पदभार सँभाला. लीग और कांग्रेस में इतना मतभेद बढ़ गया कि अब उनका समझौता होना किसी भी कीमत पर सम्भव नहीं था. अप्रैल, 1947 ई. में गांधी ने माउंटबेटन से मुलाकात की तथा विभाजन नहीं करने का प्रस्ताव किया. वे जिन्ना को भी सरकार बनाने देने के लिए भी राजी थे. गांधीजी ने कहा–"अगर कांग्रेस बँटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर होकर गुजरना पड़ेगा. जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं भारत के बँटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊँगा और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूँगा." बाद में नेहरू तथा पटेल के दबाव में गांधी को भी विभाजन की बात स्वीकार करनी पड़ी.

माउंटबेटन की योजना को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया वहाँ से यह 16 जुलाई, 1947 ई. को पास हुई. कांग्रेस वर्किंग, कमेटी ने विभाजन को मत विभाजन के बाद स्वीकार किया वहीं मुस्लिम लीग ने इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया. भारतीय स्वाधीनता विधेयक के आधार पर भारत को मध्य रात्रि में आजादी मिली. 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और रात के ठीक बारह बजे 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत स्वतंत्र हुआ. जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और लियाकत अली प्रधानमंत्री बने. भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने. 15 अगस्त, 1947 ई. को अनेक साम्राज्यों की राजधानी दिल्ली पहली बार 'लोकराज' की राजधानी बनी. संविधान सभा में नेहरू ने घोषणा की–"आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई. भारत ने पुनः अपने आपको प्राप्त कर लिया."

भारत विभाजन का उत्तरदायित्व

भारत विभाजन के लिए कुछ इतिहासकार नेहरू, पटेल, जिन्ना को, कुछ ने अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि इस बारे में आज तक भी निश्चय नहीं हो पाया है फिर भी कुल मिलाकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश राज तीनों को ही इसका उत्तरदायी माना जाना चाहिए. तीनों ने समय-समय पर जो नीतियाँ अपनाईं, वे ही इस विभाजन का कारण बनीं. इसका श्रीगणेश ब्रिटिश राज ने ही किया.

मार्ले मिण्टो सुधार योजना के तहत पहली बार मुसलमानों को राजनीतिक बढ़ावा देने, भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिक तथ्यों को उभारने की कोशिश की गई थी. लॉर्ड मिण्टो ने ही "मुस्लिम राष्ट्र" शब्द का व्यवहार पहली बार किया तथा मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था की. 1921 ई. में जिन्ना मुस्लिम लीग से अलग हो गए तथा गांधी की नीतियों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे. कांग्रेस की नीतियों ने इस दरार को और बढ़ाया. गांधीजी ने मुसलमानों को संतुष्ट कर तथा भारत की अखंडता को बचाए रखने के प्रयास में 1940 ई. में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में बँटवारे के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, परन्तु उनका कहना था कि यह संयुक्त परिवार की तरह ही होना चाहिए. वे वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित एक संविधान सभा की व्यवस्था चाहते थे तथा मुसलमानों को यह निर्णय लेने का अधिकार देना चाहते थे कि वे स्वयं निश्चित करें कि वे अलग रहना चाहते हैं अथवा संयुक्त परिवार के सदस्य रूप में.

गांधी तथा कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मुस्लिम लीग को समर्थन देना शुरू कर दिया, ताकि लीग का उन्हें सहयोग मिलता रहे. इसी उद्देश्य से 8 अगस्त, 1940 ई. को लिनलिथगो ने जिन्ना को आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों की राय लिए बगैर सरकार किसी भी प्रकार का संवैधानिक परिवर्तन नहीं कर सकेगी. इस प्रकार से जिन्ना के हाथों में 'वीटो' का अधिकार आ गया और उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी. जिन्ना को यह महत्वपूर्ण अधिकार दिलाने में भारत सचिव लियोपोल्ड एमरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा. इसके अलावा सी. राजगोपालाचारी के क्रिया-कलापों ने भी जिन्ना के कार्यों को आसान बनाने का काम किया. उन्होंने 1941 ई. के अंत में मद्रास में कांग्रेस विधायक दल से एक प्रस्ताव पारित करवाया जिसमें राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए कांग्रेस को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया. लीग ने इस अधिवेशन में पाकिस्तान की माँग की थी, परन्तु कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया.

राजगोपालाचारी की तरह नेहरू ने भी अप्रत्यक्ष रूप से विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया. कांग्रेस ने 1942 ई. के क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक प्रस्ताव में नेहरू ने कहा कि वह प्रस्तावित भारत संघ में किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध रखने पर सहमत नहीं है. न्यूज क्रॉनिकल नामक समाचार-पत्र के प्रतिनिधि से एक साक्षात्कार में नेहरू ने यह भी कहा कि हालांकि कांग्रेस ने क्रिप्स के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, परन्तु भारत अंग्रेजों की सहायता के लिए तैयार है. भूलाभाई देसाई ने भी लियाकत अली के साथ समझौता करने का प्रयास किया. गांधीजी ने भूलाभाई को इस कार्य में समर्थन दिया. भूलाभाई की योजना थी कि पुनर्गठित मंत्रिमंडल में कांग्रेस और लीग बराबर-बराबर स्थान बाँट लें. लॉर्ड वैवेल ने इस योजना को हिन्दू मुसलमानों के मध्य बँटवारा का नाम दिया न कि कांग्रेस व लीग के मध्य बँटवारा. इस प्रस्ताव के विफल होने पर गांधीजी की सहमति से राजगोपालाचारी ने अपनी योजना प्रस्तुत की, (सी. आर. फॉर्मूला) तथा जिन्ना से वार्ता आरम्भ की. परन्तु यह विफल हो गई. जिन्ना को ब्रिटेन से गुप्त आश्वासन मिल रहा था. कूपलैंड योजना पहले ही तैयार की जा चुकी थी. इस योजना के अनुसार भारत का विभाजन चार भागों में किया जाना था–सिंधु घाटी, गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा तथा दक्कन. इन चार भागों में से दो में मुस्लिम बहुमत और दो में हिन्दू बहुमत होना था जिससे कि केन्द्र में शक्ति संतुलन रखा जा सके. देशी राज्यों के लिए एक या अनेक संघों की व्यवस्था थी. वस्तुतः चर्चिल चाहते थे कि भारत छोड़ने के बाद भी अंग्रेज इस उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव जहाँ तक सम्भव हो बनाए रख सकें. इस उद्देश्य की पूर्ति बिना पाकिस्तान निर्माण के संभव नहीं थी. इसलिए वे जिन्ना को गुप्त रूप से 'कठौती में पाकिस्तान' दे रहे थे. इसके अलावा गांधीजी ने जिन्ना से भेंट करके उन्हें राजगोपालाचारी योजना को स्वीकार करने को कहा, परन्तु जिन्ना इस पर तैयार नहीं हुए. गांधी जिन्ना वार्ता की विफलता ने जहाँ गांधीजी को निराश किया, वहीं जिन्ना और कांग्रेस के अन्य नेताओं का विचार अनुदार बना दिया. मौलाना आजाद के अनुसार जिन्ना से वार्ता करना गांधीजी की एक महान् भूल थी. इससे जिन्ना को बहुत अधिक महत्व मिला. पाकिस्तान निर्माण को सहज बनाने के लिए नेहरू, पटेल तथा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भी कम उत्तरदायी नहीं थे. गांधी की सहमति लिए बिना ही तीनों ने मार्च, 1947 ई. में जिन्ना के 'दो राष्ट्र सिद्धान्त' को स्वीकृति प्रदान कर पंजाब का हिन्दू एवं मुसलमान बहुल इलाकों में विभाजन करने का

प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में रखा. कांग्रेस के इन महत्वपूर्ण नेताओं की मनोभावनाओं का अंदाजा लगाकर माउंटबेटन ने मई, 1947 ई. में विभाजन की पूरी योजना तैयार कर ली. सरदार पटेल ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर उसे पूरा समर्थन प्रदान किया. नेहरू ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी. गांधी और आजाद इसका विरोध करते रहे. कांग्रेस के नेता अब तत्काल स्वतंत्रता चाहते थे, भले ही स्वाधीनता का मूल्य उन्हें विभाजन के रूप में देना पड़े. 3 जून, 1947 ई. को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में माउंटबेटन योजना पर विचार किया गया. 14 जून, 1947 ई. को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई. गोविन्द वल्लभ पन्त ने माउंटबेटन योजना को स्वीकृत करने का प्रस्ताव पेश किया. नेहरू तथा पटेल ने प्रस्ताव का समर्थन किया. मौलाना आजाद तथा अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया. गांधीजी ने भी प्रस्ताव स्वीकार करने का अनुरोध किया. उनका कहना था कि वे सदैव विभाजन के विरोधी रहे, परन्तु अब विभाजन के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं था. इसके बाद भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका. प्रस्ताव के पक्ष में 29 तथा विपक्ष में 15 मत आए. सिर्फ 14 मतों के बहुमत से कांग्रेस ने भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया.

अतः उपर्युक्त वर्णन से यह निष्कर्ष सामने आता है कि भारत का विभाजन एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें समय-समय पर विभिन्न भूमिकाओं का अपना सहयोग रहा. इसके लिए न तो ब्रिटिश राज, जिन्ना, कांग्रेस, गांधी, नेहरू या पटेल अथवा साम्प्रदायिकता की भावना अकेले उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि चाहे-अनचाहे ढंग से सभी ने इसमें सहयोग दिया.

भारत विभाजन के परिणाम

बहुत लम्बे समय से भारतीयों की प्रतीक्षारत मनोकामना आजादी मिलने के रूप में पूरी तो हो गई, परन्तु पड़ी बहुत महँगी. बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे-फसाद हुए. पंजाब, बंगाल, दिल्ली आदि स्थानों पर भीषण नरसंहार हुआ जिसमें लाखों व्यक्तियों को जान-माल से हाथ धोना पड़ा. शरणार्थियों की समस्या भी अपने आप में एक विकट समस्या थी. दूसरी विकट समस्या थी देशी रियासतों की. सबसे अधिक विकट स्थिति कश्मीर में बनी, परन्तु सरदार पटेल ने अपने प्रयासों से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया. अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएँ भी आईं. विभाजन के सबसे अधिक दुखद परिणामों में था राष्ट्रपिता गांधी की हत्या. 30 जनवरी, 1948 ई. को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोड़से ने गोली मारकर हत्या कर दी. यही सबसे दुखद पहलू रहा.

स्मरणीय तथ्य

- अंग्रेजों के द्वारा "फूट डालो-राज करो" की नीति के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में साम्प्रदायिकता की भावना ने जन्म लिया.
- धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय हिन्दू राजाओं के काल को इतिहासकारों ने स्वर्णिम काल की संज्ञा दी है.
- भारतीय इतिहास हिन्दू काल तथा मुस्लिम काल के नाम से विभक्त हो गया. जिससे हिन्दू तथा मुसलमानों में मतैक्य स्थापित नहीं हो सका.
- हिन्दू धर्म सुधारकों ने हिन्दुओं में जातीयता का दंभ ऐसा भरा कि वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और खासकर मुसलमानों को हेय दृष्टि से देखने लगे.
- मुसलमानों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने वाले सर सैय्यद अहमद खाँ थे. ये पूर्व में तो हिन्दू तथा मुस्लिम वर्ग दोनों के हितैषी थे, परन्तु बाद में मुस्लिम समर्थक होकर रह गए.
- सर सैय्यद अहमद खाँ को यह भय था कि संसदात्मक प्रजातंत्र के फलस्वरूप समूचा देश हिन्दू तथा मुस्लिम दो सम्प्रदायों में बँट जाएगा जिससे मुसलमानों को सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी राज का बना रहना ही उचित समझा.
- कांग्रेस को तोड़ने के प्रयास में असफल रहने पर उन्होंने 1888 ई. में यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन तथा 1893 ई. में मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की.
- उपर्युक्त पहली संस्था के द्वारा कांग्रेस व हिन्दू विरोधी प्रचार किया गया तथा दूसरी संस्था द्वारा मुसलमानों के हितों के संरक्षण में बात उठाई गई.
- सर सैय्यद अहमद खाँ का मानना था कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग-अलग 'कौम' (राष्ट्र) हैं.
- 30 दिसम्बर, 1906 ई. में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन मुल्क, आगा खाँ तथा बकर-उल-मुल्क के प्रयासों से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई.
- लेफ्टीनेंट गवर्नर एंथनी मेक्डेनल ने न्यायालयों में हिन्दी को वैकल्पिक भाषा के रूप में स्थान दिया.
- 1907 ई. में हिन्दू महासभा की स्थापना हुई.
- हालांकि हिन्दूमहासभा का निर्माण 1907 ई. में हो गया था, परन्तु राजनीतिक शक्ति के रूप में यह संस्था 1920 ई. में ही प्रतिस्थापित हो पाई थी.

- मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र भारत के लिए नारा दिया था "दो पृथक् राष्ट्र", जबकि हिन्दुओं की पार्टी हिन्दू महासभा का नारा था "हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए".
- जिन्ना 1913 ई. में मुस्लिम लीग में शामिल हुए.
- कलकत्ता में अगस्त, 1946 ई. में जो दंगे हुए उनमें करीब 5 हजार लोग पांच ही दिन में मौत के घाट उतारे गए.
- भारत विभाजन के मध्य गांधी-जिन्ना की वार्ता का प्रमुख सहयोग रहा. इस वार्ता में गांधीजी की यह इच्छा थी कि यदि बँटवारा हो तो संयुक्त परिवार की तरह हो तथा स्वतंत्रता के बाद हो, जबकि जिन्ना स्वतंत्रता से पूर्व ही बँटवारा चाहते थे.
- द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 ई. में हुई.
- शिमला समझौता सफल नहीं होने का एक प्रमुख कारण था जिन्ना की हठधर्मिता.
- 1945-46 ई. में जो चुनाव हुए, उनमें केन्द्रीय विधान सभा में कांग्रेस को 57 तथा लीग को मात्र 30 स्थान ही मिले.
- बम्बई में नौसेना के नाविकों ने 18 फरवरी, 1946 ई. को विद्रोह कर दिया.
- कैबिनेट मिशन की योजना में यह सबसे बड़ा गुण था कि उसने कांग्रेस तथा लीग के सम्बन्धों में उपस्थित बुराई को कुछ हद तक दूर करके दोनों को करीब ला दिया था.
- वायसराय के कहने पर अक्टूबर, 1946 ई. में जिन्ना ने भी सरकार में शामिल होना तय कर लिया था.
- कांग्रेस-लीग समझौता 1916 ई. में हुआ.
- 1923 ई. से लेकर 1928 ई. तक हिन्दू प्रतिक्रियावादियों और मुसलमान सांप्रदायिकतावादियों के चलते भारत के विभिन्न भागों में भीषण रक्तपात हुआ.
- प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवम्बर, 1930 ई. में हुआ.
- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितम्बर, 1931 ई. में हुआ.
- तृतीय गोलमेज सम्मेलन मार्च, 1933 ई. में हुआ.
- मुस्लिम लीग का 1937 ई. में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ, इसी अधिवेशन में सिकंदर-जिन्ना पैक्ट हुआ. जिसमें पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्यों को मुस्लिम लीग की सदस्यता दिलाने की माँग की गई, परन्तु मन्त्रिमण्डल यूनियनिस्ट दल का ही कहा जाना था.

विशिष्ट स्मरणीय तथ्य

- अंग्रेजों ने "फूट डालो और राज करो" की नीति को अपनाते हुए हिन्दुओं को सहृदयता से अपने पक्ष में किया तो वहीं मुसलमानों का अधःपतन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी.
- अंग्रेजी शासक लॉर्ड एडिनबर्ग का यह कथन स्पष्ट था कि यह जाति (मुसलमान) हमसे सिद्धांततः विद्वेष रखती है और इसी कारण हमारी नीति मुख्यतः हिन्दुओं को संतुष्ट करने की है. इसी कारण मुसलमानों का सेना तथा शासन में प्रवेश बंद कर दिया गया.
- हिन्दू-मुसलमानों के मध्य वैमनस्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंग्रेजों के न्यायालयों में उर्दू के स्थान पर हिन्दी भाषा का प्रयोग शुरू करने की इजाजत दी गयी.
- अंग्रेजों की ओर से हिन्दुओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर दिए जाने के कारण मुस्लिम पिछड़ते चले गए.
- धार्मिक उन्माद इस कदर छा रहा था कि प्रत्येक धर्म सुधारक अपने-अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने में व्यस्त था. मुसलमानों का प्रयास था कि इस देश में दार-उल-इस्लाम की स्थापना कर दी जाए.
- अंग्रेज और उनसे प्रभावित कुछ भारतीय इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर ऐसे साहित्य की रचना की जिसने भारतीय समाज में विद्वेष पैदा किया. हिन्दू और मुसलमानों के मध्य नफरत के बीज बो दिए गए.
- सर सैय्यद अहमद खाँ का मानना था कि कांग्रेस मुख्यतः हिन्दुओं की हितैषी है, इसलिए वे कांग्रेस विरोधी हो गए और मौका पड़ने पर जहाँ-तहाँ उसकी आलोचना करने लगे.
- मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे मुख्यतया मुसलमानों को सुरक्षित रखने की भावना थी. इसके बनाने में अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य आर्चबोल्ड तथा वायसराय मिंटो के प्राइवेट सैक्रेटरी डनलप स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
- दिसम्बर में 1906 ई. के तहत ढाका में मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस की बैठक हुई उसी में मुस्लिम लीग के गठन के बारे में योजना बनाई गई.
- मुसलमानों से प्रेरित होकर मुस्लिम लीग की तरह ही हिन्दुओं ने 'हिन्दू महासभा' का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्दू हितों की रक्षा करना था.

- हिन्दू महासभा की नीतियों ने मुसलमानों में भय तथा असुरक्षा की भावना पैदा कर दी, जिससे उन्हें अपना अस्तित्व ही खतरे में नजर आने लगा.
- 1913 ई. में जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाहन की तथा 1924 ई. में नया मूर्तरूप प्रदान करते हुए उसमें चेतना का संचार किया.
- उनके द्वारा साम्प्रदायिकता का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के बाद भी कोई खास असर नहीं पड़ता देखकर उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि जब तक उग्रवादी जनाधारित राजनीति का सहारा नहीं लिया जाएगा, तो वे धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे. उनकी इस विचारधारा ने उन्हें बेवजह विरोध करने को मजबूर कर दिया.
- इसी विचारधारा के फलस्वरूप उन्होंने 3 मार्च, 1941 ई. को अलीगढ़ में आयोजित एक सम्मेलन में कहा था "पाकिस्तान न केवल हासिल किया जा सकता है, बल्कि अगर आप इस देश में पूरी तरह खत्म होने से बचना चाहते हैं तो एकमात्र यही मकसद हो सकता है."
- 1922 ई. से लेकर 1928 ई. तक का समय दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि इस दौरान 88 दंगे हुए जिनमें करीब चार सौ से अधिक लोग हताहत हुए.
- क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 ई. की अगस्त क्रांति की हिंसक घटनाओं का दोषारोपण अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी पर किया. सरकार का कहना था कि यह दंगे कांग्रेस तथा गांधी ने जानबूझकर करवाए हैं.
- उपर्युक्त घटनाओं के सम्बन्ध में 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च, 1943 ई. तक गांधीजी को जेल में रखा गया जहाँ उन्होंने 21 दिन तक उपवास रखा.
- अधिक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 1944 ई. में उन्हें रिहा कर दिया गया.
- राजगोपालाचारी योजना के तहत यह प्रस्तावित था कि 'मुस्लिम लीग' भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा अंतरिम सरकार में कांग्रेस का समर्थन करे.
- राजगोपालाचारी की योजना के तहत ही गांधी ने जिन्ना से भेंट की तथा यह योजना स्वीकार करने का आग्रह किया, वार्ता एक सप्ताह चली मगर असफल रही.
- जिन्ना ने पाकिस्तान क्षेत्र में सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, बंगाल, आसाम और बलूचिस्तान को भी शामिल किया.
- अक्टूबर, 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वैवेल भारत के नए वायसराय नियुक्त हुए.
- 25 जून, 1945 ई. को शिमला में हुए सम्मेलन के आधार पर गांधीजी पर से नजरबंदी हटा ली गई तथा सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया.
- साम्प्रदायिक समस्या का निराकरण करके संवैधानिक गतिरोध को हटाना एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् का नए सिरे से गठन करना शिमला सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था.
- शिमला सम्मेलन में कांग्रेस तथा लीग के अतिरिक्त सिख, दलित वर्ग तथा केन्द्रीय विधान सभा के यूरोपियन दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था.
- जिन्ना ने माँग की 'कार्यकारिणी परिषद्' में सूची बनाने का अधिकार मुस्लिम लीग को ही मिले, अनुचित थी, जिसे नहीं माना गया और इसी आधार पर शिमला सम्मेलन सफल नहीं हो सका.
- 14 जुलाई, 1945 ई. में इंग्लैण्ड में चुनाव हुए जिसमें लेबर पार्टी को बहुमत मिला तथा चर्चिल के स्थान पर एटली प्रधानमंत्री बने.
- द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज सरकार की स्थिति बड़ी विकट थी तथा वह येन-केन-प्रकारेण भारतीयों को संतुष्ट रखकर अपना परचम फहराये रखना चाहती थी.
- 19 फरवरी, 1946 ई. को एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की.
- एटली ने यह भी घोषणा की कि भारतीयों का संविधान कैसा होगा इसका निर्णय वे स्वयं कर सकते हैं.
- इसके साथ ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह थी– "हम बहुसंख्यक समाज की अग्रगति को रोकने का अधिकार अल्पसंख्यक समाज को नहीं दे सकते."
- कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 ई. को दिल्ली पहुँचा. उसका उद्देश्य यह था कि भारतीय जनमत के नेताओं के साथ मिलकर भारत में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को अतिशीघ्र सम्भव बनाया जाए.
- संविधान सभा में लीग की स्थिति को कमजोर जानकर 29 जून, 1946 ई. को जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकृत कर दिया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही करने की धमकी दे डाली.

- 8 अगस्त, 1946 ई. को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास कराकर अंतरिम सरकार बनाने की योजना स्वीकार कर ली.
- नेहरू को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया तथा अंतरिम सरकार को 2 सितम्बर को कार्यभार सम्भालना था.
- साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रश्न पर 1928 ई. में मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई.
- लंदन में हुए तीन गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य भारत की संवैधानिक समस्या को हल करना था. गोलमेज सम्मेलनों के बाद भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई.
- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने पर गांधीजी ने कहा–"साम्प्रदायिक मतभेद की बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी में पिघल जाएगा."
- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल होने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैक्डोनाल्ड ने एक विशेष व्यवस्था दी जिसके अनुसार अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले सम्प्रदायों में मुसलमानों के अतिरिक्त सिख, दलित, पिछड़ी जाति तथा भारतीय ईसाइयों को भी शामिल किया गया. उनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई.
- तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया, उसी के आधार पर 1935 ई. का भारत सरकार अधिनियम पास हुआ.
- 1938 ई. में मुस्लिम लीग ने एक कमेटी 'पीरपुर समिति' का गठन किया, जिसका कार्य हिन्दू-मुसलमानों पर हुए अत्याचारों की जाँच करना था. राजा मोहम्मद मेंहदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था.
- बिहार शरीफ रिपोर्ट तथा फज्ल-उल-हक रिपोर्ट पीरपुर समिति की देखरेख में ही प्रकाशित की गई, जिसमें हिन्दू तथा मुस्लिमों पर हुए अत्याचारों का वर्णन था.
- 22 दिसम्बर, 1939 ई. को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया. इस अवसर पर जिन्ना ने कहा–"कांग्रेस शासन की समाप्ति पर यह सभा चैन की सांस लेती है और आज के दिन को अधिनायकवाद, दमन और अन्याय से मुक्ति का दिन मानती है."
- मुसलमान ऐसी किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें बहुसंख्यक हिन्दुओं की सरकार हो. यह कहना था उन मुस्लिमों का, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन-रत थे. इनका नेतृत्व चौधरी रहमत अली ने किया.
- चौधरी रहमत अली की अध्यक्षता में लंदन में "पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट" चलाया जा रहा था. उन्होंने 1933 ई. में यह कहा कि हिन्दुस्तान एक महादेश है, वह एक राष्ट्र नहीं, बल्कि दो राष्ट्र है. एक हिन्दू तथा दूसरा मुसलमान. हिन्दुस्तान का नाम दीनिया होना चाहिए.
- मुस्लिम लीग द्वारा अलग से पाकिस्तान बनाने की माँग 1940 ई. में रखी गई.
- 1940 ई. में आयोजित हुए लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव से जाना जाता है.
- भले ही पाकिस्तान बनाने की माँग स्पष्ट रूप से जब भी स्पष्ट हुई हो, परन्तु इसकी योजनाएँ, तो 1930 ई. से ही बनने लगी थीं.
- 1927 ई. में लीग की सदस्य-संख्या जहाँ मात्र 1330 ही थी वह 1940 ई. में बढ़कर 44 लाख हो गई.
- मुस्लिम लीग ने "अंग्रेजों भारत छोड़ो" नारे के जवाब में "अंग्रेजों बांटो और भागो" का नारा बुलंद किया.
- 16 अगस्त, 1946 ई. को कलकत्ता में भयानक दंगे हुए तब लीगियों ने नारा लगाया "लड़कर लेंगे पाकिस्तान".
- अंतरिम सरकार में लीग के नेता लियाकत अली को वित्त मंत्री का पद सौंपा गया. उन्होंने वैमनस्यता की भावना से प्रेरित होकर बजट बनाया जिसमें उद्योगपतियों पर 25% कर लगाया गया था.
- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी, 1947 ई. को यह घोषणा कर दी कि अंग्रेज जून 1948 ई. से पूर्व ही भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे.
- माउंटबेटन की योजना 16 जुलाई, 1947 ई. को पास हुई.
- भारत को मध्य रात्रि को आजादी मिली. 14 अगस्त, 1947 ई. को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत आजाद हुआ.
- स्वतंत्रता मिलने के बाद जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर और लियाकत अली प्रधानमंत्री बने.
- इसी प्रकार स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद.
- लॉर्ड मिण्टो ने 'मुस्लिम राष्ट्र' शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था.
- राजगोपालाचारी की योजना को सी. आर. फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है.

विगत वर्ष में पूछे गये प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. अखिल भारतीय हिन्दू महासभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के महाराज की अध्यक्षता में हुआ था.
   2. 1928 में हिन्दू महासभा के जबलपुर अधिवेशन में गैर-हिन्दुओं को हिन्दू के रूप में परिवर्तित करने का आह्वान करने वाले प्रस्ताव स्वीकृत किए गए.

   उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/ हैं ?
   (A) केवल 1 (B) केवल 2
   (C) 1 और 2 दोनों (D) न ही 1 और न ही 2

2. 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था?
   (A) नवाब सलीमुल्ला (B) सैयद अहमद खाँ
   (C) आगा खाँ (D) सैयद अमीर अली
3. सिकन्दर हयात खाँ किसका प्रतिनिधित्व करते थे?
   (A) मुस्लिम लीग (B) खुदाई खिदमतगार
   (C) कृषक प्रजा पार्टी (D) यूनियनिस्ट पार्टी

उत्तरमाला

1. (C) 2. (C) 3. (D)

संकेत

3. सिकन्दर हयात खाँ नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. भारत में साम्प्रदायिकता की शुरूआत कब हुई ?
   (A) उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में
   (B) उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में
   (C) उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में
   (D) इनमें से कोई नहीं
2. साम्प्रदायिकता फैलाने में सबसे प्रमुख कारण था.
   (A) 'फूट डालो और राज करो' की नीति
   (B) स्वार्थ सिद्धि जमींदारों की
   (C) कांग्रेसियों की सत्ता लोलुपता
   (D) मुस्लिम-लीग का धार्मिक दृष्टिकोण
3. "यह जाति (मुसलमान) हमसे सिद्धांततः वैर रखती है." यह कथन किसका था ?
   (A) लॉर्ड मिण्टो (B) लॉर्ड क्लाइव
   (C) लॉर्ड एलिनबरो (D) लॉर्ड मैकाले
4. हिन्दू-मुसलमानों के मध्य खाई बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया ?
   (A) न्यायालयों में उर्दू के स्थान पर हिन्दी भाषा को मान्यता दी
   (B) न्यायालयों में हिन्दी के स्थान पर उर्दू भाषा को मान्यता दी
   (C) दोनों भाषाओं को हटाकर अंग्रेजी को स्थान दिया
   (D) इनमें से कोई नहीं
5. अंग्रेजों द्वारा सरकारी नौकरियों में हिन्दुओं को मुसलमानों की अपेक्षा स्थान दिए जाते थे–
   (A) कम (B) अधिक
   (C) समान (D) कोई नहीं
6. अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई बंगाल की स्थायी भू-व्यवस्था ने पुराने भूमिपतियों का नाश कर दिया जिसके कारण–
   (A) जमींदारों का उदय हुआ
   (B) सामंतों का उदय हुआ
   (C) सरदारों का उदय हुआ
   (D) भू-मालिकों का उदय हुआ
7. मुसलमानों को शिक्षा का पूरा लाभ क्यों नहीं मिला ?
   (A) साम्प्रदायिकता के कारण
   (B) धर्मान्धिता के कारण
   (C) सामाजिकता के कारण
   (D) रूढ़िवादिता और कट्टरता के कारण
8. धर्म सुधारकों का मुख्य उद्देश्य होता था–
   (A) अपने धर्म को बढ़ावा देना
   (B) अपने धर्म की बुराई दूर करना
   (C) दूसरों की शिक्षा ग्रहण करना
   (D) धार्मिक आयोजन करना
9. मुसलमान हिन्दुस्तान में किसकी स्थापना करना चाहते थे ?
   (A) दारुल-उलूम की (B) दार-उल-इस्लाम की
   (C) दार-उल-हक की (D) इनमें से कोई नहीं
10. धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास कितने वर्गों में बँट गया ?
    (A) एक (B) दो
    (C) तीन (D) चार
11. इतिहासकारों ने हिन्दू राजाओं के काल को कहा है–
    (A) स्वर्णिम युग (B) रजत युग
    (C) ताम्र युग (D) कोई नहीं
12. अंग्रेजी शिक्षा के प्रति मुसलमानों को प्रेरित करने वाला कौन था ?
    (A) सर सैयद अहमद खाँ (B) अब्दुल गनी
    (C) महबूब खाँ (D) सीमांत गांधी

13. सर सैय्यद अहमद खाँ ने इलाहाबाद अधिवेशन के समय किसको तोड़ने का प्रयास किया ?
    (A) आर. एस. एस. (B) मुस्लिम लीग
    (C) कांग्रेस (D) जनतंत्र

14. उपर्युक्त इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ ?
    (A) 1890 ई. में (B) 1891 ई. में
    (C) 1892 ई. में (D) 1888 ई. में

15. सर सैय्यद अहमद खाँ कांग्रेस को तोड़ने में असफल रहने पर किस पार्टी को जन्म दिया ?
    (A) मुस्लिम लीग
    (B) यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन
    (C) मोहम्मडन एंग्लो ऑरिएंटल डिफेंस
    (D) इनमें से कोई नहीं

16. यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोशिएसन का प्रमुख कार्य था–
    (A) हिन्दू विरोधी प्रचार
    (B) हिन्दुओं को सहयोग
    (C) मुस्लिम समुदाय में जागृति
    (D) हिन्दुओं में जागृति

17. एंग्लो ऑरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई ?
    (A) 1892 ई. में (B) 1894 ई. में
    (C) 1895 ई. में (D) 1893 ई. में

18. एंग्लो ऑरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का प्रमुख कार्य क्या था ?
    (A) हिन्दुओं का विरोध
    (B) हिन्दुओं का समर्थन
    (C) हिन्दुओं के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा
    (D) मुसलमानों के राजनीतिक हकों की सुरक्षा

19. हिन्दुओं और मुस्लिम दो अलग 'कौम' (राष्ट्र) हैं, यह किसने कहा ?
    (A) सर टॉमस रो (B) मुहम्मद उल हक
    (C) सर सैयद अहमद खाँ (D) जिन्ना

20. उपर्युक्त बात सर सैय्यद खाँ ने कब कही ?
    (A) 1890 ई. में (B) 1891 ई. में
    (C) 1887 ई. में (D) 1888 ई. में

21. एक अक्टूबर 1906 को शिमला में मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला. उस शिष्टमंडल में कितने लोग थे ?
    (A) 40 (B) 35
    (C) 36 (D) 45

22. उपर्युक्त शिष्टमंडल किसकी अध्यक्षता में लॉर्ड मिंटो से मिला ?
    (A) जिन्ना (B) आगा खाँ
    (C) अहमद खाँ (D) इनमें से कोई नहीं

23. मुस्लिम-लीग के निर्माण की योजना कहाँ बनी ?
    (A) लंदन (B) स्पेन
    (C) पुर्तगाल (D) जापान

24. मुस्लिम-लीग की स्थापना कब हुई ?
    (A) 28 दिसम्बर, 1906 ई. को
    (B) 30 दिसम्बर, 1908 ई. को
    (C) 25 दिसम्बर, 1907 ई. को
    (D) 30 दिसम्बर, 1906 ई. को

25. उर्दू के बदले देवनागरी लिपि में हिन्दी को शासन की भाषा के रूप में मांग कब की जाने लगी ?
    (A) उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक में
    (B) उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में
    (C) उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक में
    (D) उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में

26. न्यायालयों में उर्दू के स्थान पर हिन्दी भाषा को वैकल्पिक मान्यता देने वाला शासक कौन था ?
    (A) गवर्नर जनरल
    (B) जनरल डायर
    (C) गवर्नर एंथनी मैक्डोनल
    (D) ए. ओ. ह्यूम

27. हिन्दी को उर्दू के स्थान पर वैकल्पिक भाषा का दर्जा न्यायालयों के लिए कब मिला ?
    (A) 1903 ई. में (B) 1900 ई. में
    (C) 1910 ई. में (D) 1909 ई. में

28. हिन्दू जमींदार, साहूकार तथा मध्यमवर्गीय उद्योगपतियों ने हकीकत में कब से मुस्लिम विरोधी नारे लगाने शुरू किए ?
    (A) 1870 ई. से (B) 1872 ई. से
    (C) 1860 ई. से (D) 1874 ई. से

29. हिन्दू महासभा की स्थापना कब हुई ?
    (A) 1910 ई. में (B) 1911 ई. में
    (C) 1908 ई. में (D) 1907 ई. में

30. हिन्दू महासभा की स्थापना कहाँ हुई ?
    (A) पंजाब में (B) लाहौर में
    (C) पाकिस्तान में (D) बंगाल में

31. हिन्दू महासभा राजनीतिक शक्ति के रूप में कब प्रतिष्ठापित हो पाई ?
    (A) 1922 ई. में (B) 1920 ई. में
    (C) 1911 ई. में (D) 1923 ई. में

32. मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हितों को देखते हुए क्या नारा दिया ?
    (A) अंग्रेजो ! बाँटो और भागो
    (B) दो पृथक् राष्ट्र
    (C) पाकिस्तान लेकर रहेंगे
    (D) इनमें से कोई नहीं

33. मुसलमानों द्वारा दिए गए "दो पृथक् राष्ट्र" के मुकाबले हिन्दू महासभा ने कौनसा नारा दिया ?
    (A) हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए
    (B) मुसलमानो होश में आओ
    (C) अंग्रेजों, भारत छोड़ो
    (D) इनमें से कोई नहीं

34. जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए ?
    (A) 1922 ई. में (B) 1912 ई. में
    (C) 1914 ई. में (D) 1913 ई. में

35. जिन्ना ने लीग को पुनर्जीवित कब किया ?
    (A) 1925 ई. में (B) 1922 ई. में
    (C) 1924 ई. में (D) 1920 ई. में

36. "पाकिस्तान न केवल हासिल किया जा सकता है, बल्कि अगर आप इस देश में इस्लाम को पूरी तरह से खत्म होने से बचाना चाहते हैं तो एकमात्र यही मकसद हो सकता है" ये शब्द किसके थे ?
    (A) मोहम्मद अली जिन्ना
    (B) सर सैयद अहमद खाँ
    (C) मुहम्मद-उल-हक
    (D) मौलाना आजाद

37. उपर्युक्त शब्द जिन्ना ने कब कहे ?
    (A) 3 मार्च, 1948 ई.
    (B) 3 अगस्त, 1947 ई.
    (C) 3 मार्च, 1941 ई.
    (D) 3 अगस्त, 1942 ई.

38. उपर्युक्त शब्द जिन्ना ने कहाँ कहे थे ?
    (A) बंगलौर में (B) लाहौर में
    (C) तेहरान में (D) अलीगढ़ में

39. "हम किसी भी हालत में अखिल भारतीय संविधान तथा केन्द्र में एक जैसी सरकार नहीं चाहते, यह कहना किसका था ?
    (A) जिन्ना का (B) लियाकत अली का
    (C) मंसूर पटौदी का (D) उमर-उल-हक का

40. कलकत्ता में अगस्त, 1946 ई. में हुए साम्प्रदायिक दंगों में पाँच दिनों में लगभग कितने लोग मारे गए ?
    (A) 8 हजार (B) 5 हजार
    (C) 6 हजार (D) 10 हजार

41. सरकार ने सन् 1942 ई. में हुई अगस्त क्रांति की हिंसक घटनाओं का दोषी किसे बताया ?
    (A) मौलाना आजाद को (B) रणजीत सिंह को
    (C) गांधी को (D) लाजपत राय को

42. 21 दिनों तक उपवास गांधीजी ने कब रखा ?
    (A) 10 फरवरी से 3 मार्च, 1943 में ई.
    (B) 10 फरवरी से 3 मार्च, 1944 में ई.
    (C) 10 फरवरी से 3 मार्च, 1929 में ई.
    (D) 10 फरवरी से 3 मार्च, 1909 में ई.

43. गांधी-जिन्ना वार्ता कितने दिन तक चली ?
    (A) तीन सप्ताह (B) चार सप्ताह
    (C) दो सप्ताह (D) पाँच सप्ताह

44. "देश का बँटवारा हो तो एक संयुक्त परिवार की तरह तथा वह भी स्वतंत्रता के बाद", यह कथन किसका था?
    (A) जिन्ना का (B) गांधी का
    (C) आजाद का (D) लियाकत अली का

45. भारत-पाक विभाजन के मध्य किसको प्रमुख हथियार के रूप में काम में लिया गया था ?
    (A) गांधी-मिंटो वार्ता (B) मिंटो योजना
    (C) गांधी-जिन्ना वार्ता (D) होमरूल आंदोलन

46. लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर भारत का नया वायसराय कौन बना ?
    (A) लॉर्ड मैकाले (B) लॉर्ड वैवेल
    (C) लॉर्ड माउंटबेटन (D) लॉर्ड क्लाइव

47. लॉर्ड वैवेल कब भारत के वायसराय बनकर आए ?
    (A) अक्टूबर 1944 में ई.
    (B) अक्टूबर 1943 में ई.
    (C) अक्टूबर 1950 में ई.
    (D) अक्टूबर 1941 में ई.

48. द्वितीय विश्वयुद्ध कब समाप्त हुआ ?
    (A) 1945 ई. में (B) 1946 ई. में
    (C) 1948 ई. में (D) 1950 ई. में

49. वैवेल को किसने विचार-विमर्श के लिए लंदन बुलाया ?
(A) ए. ओ. ह्यूम ने (B) सर टॉमस रो ने
(C) क्लाइव ने (D) चर्चिल ने

50. वैवेल को लंदन में विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से चर्चिल ने कब बुलाया ?
(A) मार्च 1945 ई. में (B) अप्रैल 1945 ई. में
(C) मई 1945 ई. में (D) जून 1945 ई. में

51. शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया ?
(A) 28 जून, 1945 ई. (B) 29 जून, 1945 ई.
(C) 25 जून, 1945 ई. (D) 27 जून, 1945 ई.

52. शिमला सम्मेलन असफल क्यों हुआ ?
(A) जिन्ना की हठधर्मिता के कारण
(B) कांग्रेस की हठधर्मिता के कारण
(C) लीग की हठधर्मिता के कारण
(D) इनमें से कोई नहीं

53. शिमला सम्मेलन की समाप्ति कब हुई ?
(A) 16 जुलाई, 1945 ई. को
(B) 15 जुलाई, 1946 ई. को
(C) 14 जुलाई, 1945 ई. को
(D) 20 जुलाई, 1947 ई. को

54. जुलाई 1945 ई. में इंग्लैंड में हुए चुनावों में किसे सफलता मिली ?
(A) डेमोक्रेटिक पार्टी को (B) लेबर पार्टी को
(C) कंजरवेटिवव पार्टी को (D) इनमें से कोई नहीं

55. लेबर पार्टी के बहुमत में आने के बाद चर्चिल के स्थान पर कौन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना ?
(A) एटली (B) रॉबर्ट हुक
(C) मैकुडोनल (D) रॉबर्ट ब्राउन

56. 1945-46 में केन्द्रीय विधानसभाओं के लिए जो चुनाव हुए उनमें कांग्रेस को कितने मत मिले ?
(A) 60 (B) 58
(C) 57 (D) 75

57. उपर्युक्त चुनावों में मुस्लिम लीग को कितने मत मिले ?
(A) 72 (B) 60
(C) 30 (D) 32

58. पंजाब में संविदा सरकार किसके नेतृत्व में बनी ?
(A) खिजर हयात खाँ (B) अब्दुल बेग
(C) अब्दुल गनी (D) जिन्ना

59. बम्बई में नौसेना के नाविकों ने सरकार के प्रति विद्रोह का रवैया कब अपनाया ?
(A) 18 फरवरी, 1947 ई. को
(B) 18 फरवरी, 1948 ई. को
(C) 18 फरवरी, 1920 ई. को
(D) 18 फरवरी, 1946 ई. को

60. एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने की घोषणा कब की ?
(A) 19 फरवरी, 1946 ई.
(B) 19 फरवरी, 1942 ई.
(C) 19 फरवरी, 1950 ई.
(D) 19 फरवरी, 1943 ई.

61. "हम बहुसंख्यक समाज की अग्रगति को रोकने का अधिकार अल्पसंख्यक समाज को नहीं दे सकते" यह कथन किसका है ?
(A) क्लाइव (B) मौलाना आजाद
(C) गांधी (D) एटली

62. कैबिनेट मिशन कब दिल्ली पहुँचा ?
(A) 24 मार्च, 1946 ई.
(B) 28 मार्च, 1946 ई.
(C) 23 मार्च, 1946 ई.
(D) 25 मार्च, 1946 ई.

63. लीग की कमजोर स्थिति को देखकर जिन्ना के कैबिनेट मिशन की योजना को कब अस्वीकार कर दिया ?
(A) 28 जून, 1916 ई. (B) 29 जून, 1917 ई.
(C) 29 जून, 1946 ई. (D) 30 जून, 1918 ई.

64. जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए सीधी कार्रवाई करने के लिए कौनसी तिथि घोषित की थी?
(A) 16 अगस्त, 1946 ई.
(B) 15 अगस्त, 1946 ई.
(C) 17 अगस्त, 1942 ई.
(D) 20 अगस्त, 1946 ई.

65. कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास कराकर अंतरिम सरकार बनाने की योजना कब स्वीकार की ?
(A) 10 अगस्त, 1940 ई.
(B) 16 अगस्त, 1943 ई.
(C) 8 अगस्त, 1939 ई.
(D) 8 अगस्त, 1946 ई.

66. वायसराय ने अंतरिम सरकार के लिए मंत्रिमंडल की घोषणा कब की ?
(A) 28 अगस्त, 1946 ई.
(B) 29 अगस्त, 1946 ई.
(C) 24 अगस्त, 1946 ई.
(D) 25 अगस्त, 1946 ई.

67. उपर्युक्त मंत्रिमंडल में प्रारम्भ में कितने सदस्य रखे गए ?
(A) 20 (B) 15
(C) 16 (D) 14

68. अंतरिम सरकार को कार्यभार कब सँभालना था ?
(A) 4 सितम्बर, 1946 ई.
(B) 2 सितम्बर, 1946 ई.
(C) 8 सितम्बर, 1946 ई.
(D) 3 सितम्बर, 1946 ई.

69. जिन्ना ने अंतरिम सरकार में शामिल होना कब तय किया ?
(A) अक्टूबर, 1946 ई. (B) नवम्बर, 1946 ई.
(C) दिसम्बर, 1946 ई. (D) फरवरी, 1946 ई.

70. मुसलमानों के लिए पहली बार अधिप्रतिनिधित्व एवं पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई ?
(A) 1910 ई. में (B) 1911 ई. में
(C) 1909 ई. में (D) 1908 ई. में

71. किस योजना के तहत मुसलमानों के लिए अधि प्रति-निधित्व व पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था की गई–
(A) मिण्टो-मार्ले सुधार योजना
(B) होमरूल आंदोलन
(C) मुस्लिम-लीग की नीति के तहत
(D) इनमें से कोई नहीं

72. कांग्रेस-लीग समझौता कब हुआ ?
(A) 1917 ई. में (B) 1916 ई. में
(C) 1918 ई. में (D) 1915 ई. में

73. किस मुद्दे पर मुस्लिम लीग में फूट पड़ी ?
(A) साइमन कमीशन के विरोध पर
(B) अंतरिम सरकार में शामिल होने पर
(C) भारत छोड़ो आंदोलन के मुद्दे पर
(D) शिमला समझौता पर

74. साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया ?
(A) 1927 ई. में (B) 1928 ई. में
(C) 1930 ई. में (D) 1932 ई. में

75. अपने अविश्वास के चलते जिन्ना ने अपनी माँगें रखीं, जोकि गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम माँग का आधार बनीं, वे थीं–
(A) आठ सूत्रीय (B) नौ सूत्रीय
(C) चौदह सूत्रीय (D) सोलह सूत्रीय

76. प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ ?
(A) नवम्बर 1932 ई. (B) नवम्बर 1930 ई.
(C) नवम्बर 1929 ई. (D) नवम्बर 1928 ई.

77. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ ?
(A) सितम्बर 1932 ई. (B) अक्टूबर 1935 ई.
(C) सितम्बर 1931 ई. (D) अक्टूबर 1933 ई.

78. "साम्प्रदायिक मतभेद की बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता की गर्मी से पिघल जाएगा" ये शब्द किसने कहे ?
(A) लाला लाजपत राय (B) महात्मा गांधी
(C) मदनमोहन मालवीय (D) राजा राममोहन राय

79. उपर्युक्त विचार गांधीजी ने कब व्यक्त किए ?
(A) प्रथम गोलमेज सम्मेलन में
(B) द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
(C) तृतीय गोलमेज सम्मेलन में
(D) इनमें से कोई नहीं

80. अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले सम्प्रदायों में मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों तथा भारतीय ईसाइयों को शामिल किया गया तथा उनके लिए निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई. यह व्यवस्था किसने दी ?
(A) रॉबर्ट हुक ने (B) सर टॉमस रो ने
(C) मैक्डोनाल्ड ने (D) क्लाइव ने

81. उपर्युक्त व्यवस्था कब लागू की गई ?
(A) 14 अगस्त, 1932 ई. को
(B) 15 अगस्त, 1933 ई. को
(C) 16 अगस्त, 1933 ई. को
(D) 18 अगस्त, 1932 ई. को

82. तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ ?
(A) जनवरी 1933 ई. में (B) फरवरी 1933 ई. में
(C) मार्च 1933 ई. में (D) अप्रैल 1933 ई. में

83. 1935 ई. का भारत सरकार अधिनियम किसके आधार पर पास हुआ ?
(A) गांधीजी की सिफारिश पर
(B) मैक्डोनाल्ड की अनुशंसा पर
(C) तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जारी श्वेत-पत्र के आधार पर
(D) इनमें से कोई नहीं

84. "मुसलमानों को अधिकाधिक विरोधी बनाने का उत्तर-दायित्व कांग्रेसी नेताओं पर है" यह आरोप किसने लगाया ?
(A) सर सैय्यद अहमद खाँ ने
(B) जिन्ना ने
(C) मौलाना आजाद ने
(D) अब्दुल-उल-हक ने

85. सिकंदर-जिन्ना पैक्ट कब हुआ ?
(A) 1937 ई. में (B) 1938 ई. में
(C) 1928 ई. में (D) 1940 ई. में

86. सिकंदर-जिन्ना पैक्ट कहाँ हुआ ?
(A) बम्बई में (B) लाहौर में
(C) दिल्ली में (D) लखनऊ में

87. पंजाब में नई मुस्लिम लीग को कब मान्यता दी गई ?
(A) 1940 ई. में (B) 1942 ई. में
(C) 1938 ई. में (D) 1941 ई. में

88. नई मुस्लिम लीग पर किसका प्रभाव अधिक था?
(A) यूनियनिस्ट का (B) हिन्दू महासभा का
(C) आर. एस. एस. का (D) इनमें से कोई नहीं

89. पीरपुर समिति का गठन किसने किया ?
(A) हिन्दू महासभा ने (B) मुस्लिम-लीग ने
(C) आर. एस. एस. ने (D) यूनियनिस्ट ने

90. पीरपुर समिति का गठन कब किया गया ?
(A) 1940 में (B) 1942 में
(C) 1938 में (D) 1945 में

91. पीरपुर समिति का मुख्य कार्य था–
(A) हिन्दू-मुस्लिमों पर हुए अत्याचारों का आकलन
(B) केवल मुस्लिमों पर हुए अत्याचारों का आकलन
(C) केवल हिन्दुओं पर हुए अत्याचारों का आकलन
(D) दोनों के मध्य सद्‌भाव पैदा करना

92. पीरपुर समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया ?
(A) मेहंदी हसन को
(B) राजा मोहम्मद मेहंदी को
(C) अल्ताफ हुसैन को
(D) जिन्ना को

93. "अब हम एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए हैं, जहाँ हमको संदेह की भाषा छोड़ देनी चाहिए". मुस्लिम लीग ही समूचे मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था है" ये विचार किसने कहे ?
(A) अल्ताफ हुसैन ने
(B) सर सैयद अहमद खाँ ने
(C) जिन्ना ने
(D) लियाकत अली ने

94. जिन्ना ने उपर्युक्त विचार कब रखे ?
(A) 1938 ई. में (B) 1940 ई. में
(C) 1942 ई. में (D) 1950 ई. में

95. मुस्लिम-लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया ?
(A) 22 दिसम्बर, 1940 ई.
(B) 22 दिसम्बर, 1939 ई.
(C) 22 दिसम्बर, 1938 ई.
(D) 22 दिसम्बर, 1932 ई.

96. "कांग्रेस शासन की समाप्ति पर यह सभा चैन की सांस लेती है और आज के दिन को अधिनायकवाद, दमन और अन्याय से मुक्ति का दिवस मानती है. ये विचार किसने अभिव्यक्त किए ?
(A) असलम बेग ने (B) मुहम्मद-उल-हक ने
(C) जिन्ना ने (D) लियाकत अली ने

97. "मुसलमान किसी भी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें बहुसंख्यक हिन्दुओं की सरकार हो." यह कथन था–
(A) कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रों का
(B) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का
(C) जामिया मिलिया के छात्रों का
(D) इनमें से कोई नहीं

98. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मुसलमान छात्रों की माँग का नेतृत्व कौन कर रहा था ?
(A) चौधरी रहमत अली
(B) चौधरी मुहम्मद अली बेग
(C) लियाकत अली
(D) जिन्ना

99. "पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट" किसकी अध्यक्षता में चलाया जा रहा था ?
(A) जिन्ना
(B) चौधरी मुहम्मद अली बेग
(C) रहमत अली
(D) लियाकत अली

100. "पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट" कहाँ चलाया जा रहा था ?
(A) लंदन में (B) बंगलौर में
(C) दिल्ली में (D) लखनऊ में

101. "हिन्दुस्तान एक महादेश है, वह एक राष्ट्र नहीं, बल्कि दो राष्ट्र है. एक हिन्दू तथा एक मुसलमान" यह कथन किसका था?
(A) अब्दुल कलाम का (B) रहमत अली का
(C) जिन्ना का (D) मुहम्मद अली का

102. मुस्लिम-लीग ने खुले रूप में पाकिस्तान बनाने की माँग कब रखी ?
(A) 1941 ई. में (B) 1942 ई. में
(C) 1940 ई. में (D) 1939 ई. में

103. 1940 ई. में आयोजित लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है ?
(A) लीग प्रस्ताव (B) पाकिस्तान प्रस्ताव
(C) मुस्लिम प्रस्ताव (D) इनमें से कोई नहीं

104. भारत विभाजन की योजनाएँ हकीकत में कबसे बनने लगी थीं ?
(A) सन् 1932 ई. से (B) सन् 1933 ई. से
(C) सन् 1930 ई. से (D) सन् 1929 ई. से

105. पेलेस्टाइन सम्मेलन कब हुआ ?
(A) 1938 ई. में (B) 1939 ई. में
(C) 1940 ई. में (D) 1929 ई. में

106. 1927 में मुस्लिम-लीग की सदस्य संख्या कितनी थी ?
(A) 1530 (B) 1330
(C) 1830 (D) 1235

107. 1944 ई. तक मुस्लिम-लीग के सदस्यों की संख्या कहाँ तक पहुँची ?
(A) 43 लाख (B) 38 लाख
(C) 44 लाख (D) 20 हजार

108. मुस्लिमों द्वारा दिए गए नारे "दो पृथक् राष्ट्र" के विरोध में हिन्दू संस्थाओं ने क्या नारा दिया ?
(A) हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए
(B) अंग्रेजो! भारत छोड़ो
(C) हम एक हैं
(D) इनमें से कोई नहीं

109. अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया ?
(A) 9 अगस्त, 1940 ई.
(B) 8 अगस्त, 1940 ई.
(C) 10 अगस्त, 1940 ई.
(D) 11 अगस्त, 1940 ई.

110. "अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी." यह किस प्रस्ताव का मुख्य बिन्दु था ?
(A) पाकिस्तान प्रस्ताव (B) अगस्त प्रस्ताव
(C) लाहौर प्रस्ताव (D) बंगलौर प्रस्ताव

111. कांग्रेस ने "भारत छोड़ो आंदोलन" का नारा कब दिया ?
(A) 1940 ई. में (B) 1941 ई. में
(C) 1941 ई. में (D) 1942 ई. में

112. लीग ने कांग्रेस के नारे "अंग्रेजो ! भारत छोड़ो" के जवाब में कौनसा नारा दिया ?
(A) अंग्रेजो ! बाँटो और भागो
(B) पाकिस्तान लेकर रहेंगे
(C) हम सब एक हैं
(D) इनमें से कोई नहीं

113. 16 अगस्त, 1946 ई. को कलकत्ता में भयानक दंगा-फसाद हुआ तब मुस्लिम-लीग के नेताओं ने क्या नारा लगाया ?
(A) हम सब एक हैं
(B) लड़कर लेंगे पाकिस्तान
(C) अंग्रेजो ! बाँटो और भागो
(D) इनमें से कोई नहीं

114. अंतरिम सरकार में वित्तमंत्री किसे बनाया गया ?
(A) मुहम्मद अली (B) लियाकत अली
(C) जिन्ना (D) मुहम्मद फारूख

115. लियाकत अली ने प्रथम बजट में गड़बड़ी करते हुए व्यापारियों पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया, जिससे हिन्दुओं में रोष फैला.
(A) 25% (B) 30%
(C) 36% (D) 40%

116. लंदन कांफ्रेंस कब आयोजित की गई ?
(A) 4 से 6 दिसम्बर 1946 ई.
(B) 4 से 8 दिसम्बर 1946 ई.
(C) 10 से 13 दिसम्बर 1946 ई.
(D) 3 से 6 दिसम्बर 1946 ई.

117. "अंग्रेज जून 1948 ई. से पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे" यह घोषणा किसने की ?
(A) एटली ने (B) जिन्ना ने
(C) गांधी ने (D) आजाद ने

118. उपर्युक्त घोषणा एटली ने कब की ?
(A) 22 फरवरी, 1947 ई. को
(B) 23 फरवरी, 1947 ई. को
(C) 20 फरवरी, 1947 ई. को
(D) 28 फरवरी, 1947 ई. को

119. सत्ता हस्तांतरण के कार्य को पूरा करने के लिए किसको नियुक्त किया गया ?
(A) डलहौजी को (B) माउंटबेटन को
(C) क्लाइव को (D) मैकाले को

120. "जब तक मैं जिंदा हूँ, भारत के बँटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊँगा." ये विचार थे–
(A) गोविंद वल्लभ पंत के (B) राधाकृष्णन के
(C) राजेन्द्र प्रसाद के (D) महात्मा गांधी के

121. माउंटबेटन की योजना कब पास हुई ?
(A) 16 जुलाई, 1947 ई.
(B) 15 जुलाई, 1947 ई.
(C) 18 जुलाई, 1947 ई.
(D) 20 जुलाई, 1947 ई.

122. पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ ?
(A) 16 अगस्त, 1947 ई.
(B) 14 अगस्त, 1947 ई.
(C) 10 अगस्त, 1947 ई.
(D) 15 अगस्त, 1947 ई.

123. स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने ?
(A) नेहरू (B) राजेन्द्र प्रसाद
(C) पटेल (D) राधाकृष्णन

124. स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर कौन बने ?
(A) लियाकत अली (B) मुहम्मद अली
(C) मुहम्मद खाँ (D) मुहम्मद-उल-हक

125. स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने ?
(A) लियाकत अली (B) मुहम्मद अली जिन्ना
(C) मुहम्मद खाँ (D) मुहम्मद-उल-हक

126. स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन बने ?
(A) माउंटबेटन (B) सी. राजगोपालाचारी
(C) पटेल (D) आजाद

127. भारत के आजाद होने पर किसने कहा कि "आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई ?"
(A) महात्मा गांधी (B) लाजपत राय
(C) सरदार पटेल (D) नेहरू

128. सी. आर. फॉर्मूला किसकी योजना को कहा जाता था ?
(A) राजगोपालाचारी (B) लाजपत राय
(C) मैकाले (D) मैक्डोनल

129. कूपलैंड योजना के अनुसार भारत का विभाजन कितने भागों में होता था ?
(A) एक (B) दो
(C) तीन (D) चार

130. महात्मा गांधी की हत्या कब हुई ?
(A) 30 जनवरी, 1949 ई. में
(B) 31 जनवरी, 1949 ई. में
(C) 30 जनवरी, 1947 ई. में
(D) 30 जनवरी, 1948 ई. में

131. भारत कब स्वतंत्र हुआ ?
(A) 15 अगस्त, 1947 ई. को
(B) 26 जनवरी, 1950 ई. को
(C) 14 अगस्त, 1947 ई. को
(D) 25 जनवरी, 1950 ई. को

उत्तरमाला

1. (B)	2. (A)	3. (C)	4. (A)	5. (B)
6. (B)	7. (D)	8. (A)	9. (B)	10. (B)
11. (A)	12. (A)	13. (C)	14. (D)	15. (B)
16. (A)	17. (D)	18. (D)	19. (C)	20. (D)
21. (C)	22. (B)	23. (A)	24. (D)	25. (D)
26. (C)	27. (B)	28. (A)	29. (D)	30. (A)
31. (B)	32. (B)	33. (A)	34. (D)	35. (C)
36. (A)	37. (C)	38. (D)	39. (A)	40. (B)
41. (C)	42. (A)	43. (C)	44. (B)	45. (C)
46. (B)	47. (B)	48. (A)	49. (D)	50. (A)
51. (C)	52. (A)	53. (C)	54. (B)	55. (A)
56. (C)	57. (C)	58. (A)	59. (D)	60. (A)
61. (D)	62. (A)	63. (C)	64. (A)	65. (D)
66. (C)	67. (D)	68. (B)	69. (A)	70. (C)
71. (A)	72. (B)	73. (A)	74. (B)	75. (C)
76. (B)	77. (C)	78. (B)	79. (B)	80. (C)
81. (A)	82. (C)	83. (C)	84. (B)	85. (A)
86. (D)	87. (A)	88. (A)	89. (B)	90. (C)
91. (A)	92. (B)	93. (C)	94. (A)	95. (B)
96. (C)	97. (A)	98. (A)	99. (C)	100. (A)
101. (B)	102. (C)	103. (B)	104. (C)	105. (A)
106. (B)	107. (C)	108. (A)	109. (B)	110. (B)
111. (D)	112. (A)	113. (B)	114. (B)	115. (A)
116. (D)	117. (A)	118. (C)	119. (B)	120. (D)
121. (A)	122. (B)	123. (A)	124. (B)	125. (A)
126. (A)	127. (D)	128. (A)	129. (D)	130. (D)
131. (A)				

8

भारत : स्वतन्त्रता प्राप्ति से 1964 तक
(India : Independent to 1964)

[भारत स्वतन्त्रता से 1964 ई. तक, संसदीय पंथ-निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य (1950 ई. का संविधान), जवाहरलाल नेहरू का विकासवादी समाजवादी दर्शन, योजना व्यवस्था एवं राज्य नियन्त्रित औद्योगीकरण, कृषिक सुधार, गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त पर आधारित विदेश नीति, चीन के साथ सीमा संघर्ष

(India Independent to 1964. A Parliamentary Secular Democratic Republic (The 1950 Constitution) Jawahar Lal Nehru's visions of a Developed, Socialist Society, Planning & State Controlled Industrialization. Agrarian Reforms. Foreign Policy of Non-alignment, Border Conflict with China and Chinese Aggression)]

भारत की स्वतन्त्रता से 1964 ई. तक संसदीय पंथ-निरपेक्ष

भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अंग्रेजों को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि अब अधिक दिनों तक भारत को गुलाम बनाए रखना सम्भव नहीं है. इसी के मद्देनजर उन्होंने सत्ता हस्तांतरित करने एवं भारत को स्वतंत्र करने का निश्चय कर लिया. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इंग्लैण्ड में आम चुनाव हुए तो वहाँ 'लेबर पार्टी' बहुमत में आई. वहाँ के प्रधानमंत्री एटली ने सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए 'कैबिनेट मिशन' मार्च, 1946 ई. में भारत भेजा. उसकी योजना के तहत् भारत के लिए एक भावी संविधान तैयार करने और 'अंतरिम सरकार' स्थापित करने की व्यवस्था बनाई गई. इसकी खातिर संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई, 1946 ई. में निर्वाचन करवाया गया. उसने संविधान के निर्माण का जिम्मा लिया. इसकी प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसम्बर, 1946 ई. को हुआ जिसकी अध्यक्षता सदन के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की. बाद में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए. सभा के अन्य प्रमुख सदस्यों में डॉ. बी. आर. अंबेडकर, टी. टी. कृष्णमाचारी, डॉ. एस. राधाकृष्णन, के. टी. शाह, एन. गोपालस्वामी आयंगर, आदि प्रमुख व्यक्ति थे. पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल ने अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री के रूप में इस सभा की कार्यवाहियों में भाग लिया. महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं बने. तीन वर्षों की अवधि में इस सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया. इसकी बैठकें 165 दिन (11 अधिवेशनों में) हुई. 21 फरवरी, 1948 ई. को संविधान का प्रारूप तैयार हुआ. अध्यक्ष की हैसियत से डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 26 नवम्बर, 1949 ई. को इस पर हस्ताक्षर किए. मूलरूप से इस संविधान में 395 धाराएँ, जो 22 भागों में विभक्त थीं और 8 अनुसूचियाँ थीं. 26 जनवरी, 1950 ई. को यह संविधान लागू किया गया.

लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय संविधान की विशेषताएँ

लिखित तथा निर्मित संविधान—भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि यह लिखित है इसलिए यह ब्रिटिश संविधान से अलग है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान अलिखित है. ब्रिटिश संविधान विकसित है और हमारा संविधान निर्मित है, क्योंकि इसे संविधान निर्माताओं ने बड़े परिश्रम से बनाया था.

ब्रिटिश संविधान की अपेक्षा यहाँ का संविधान कठोर है. हमारा संविधान अमरीका के संविधान से कम कठोर है, क्योंकि देश में संविधान के संशोधन का तरीका इतना कठिन नहीं जितना कि अमरीकी संविधान में. हमारे संविधान में बहुत-सी धाराओं को पार्लियामेंट में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से और कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत से संशोधित किया जा सकता है. कुछ धाराएँ ऐसी भी हैं जो राज्यों को प्रभावित करती हैं, वहाँ कम-से-कम आधे राज्यों की विधान सभाओं की स्वीकृति लेनी पड़ती है.

संसार में सबसे लम्बा संविधान–भारतीय संविधान संसार के सभी संविधानों से लंबा है. इसके इतने लंबे होने का एक कारण यह है कि इसमें न केवल केन्द्रीय, बल्कि प्रांतीय सरकार के ढाँचे और शक्तियों का भी वर्णन है. दूसरा कारण यह है कि इसमें हरिजनों, पिछड़ी जातियों और कबीलों के लिए विशेष व्यवस्था है. संविधान की लम्बाई का तीसरा कारण यह है कि इसमें न केवल मौलिक अधिकारों, बल्कि राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का भी वर्णन है. आयरलैंड को छोड़कर अन्य देशों के संविधानों में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन नहीं है. इसके अलावा इसमें केन्द्र तथा राज्यों में सम्बन्धों का विस्तारपूर्वक वर्णन होने से, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन होने, कई शासन सम्बन्धी व्यवस्थाओं का वर्णन होने से, इसमें न केवल उच्चतम न्यायालय, बल्कि उच्च न्यायालयों की शक्तियों और ढाँचे का विस्तारपूर्वक वर्णन होने से, सार्वजनिक सेवाओं, लोक सेवा आयोग, चुनाव कमीशन तथा वित्त आयोग इत्यादि की शक्तियों का वर्णन होने तथा इसको अधिकतर 1935 ई. के एक्ट के अनुसार ढाले जाने के कारण हमारे संविधान का विस्तार बहुत अधिक हो गया है. श्री निवासन ने ठीक ही कहा है कि–"हमारा नया संविधान 1935 ई. के भारतीय अधिनियम के समान ही न केवल एक संविधान है, अपितु एक विस्तृत कानून संहिता भी है जिसमें देश की सारी वैधानिक और शासन सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है."

जब इस संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमेन डॉ. भीमराव अंबेडकर से संविधान के अधिक लंबा हो जाने की बात कही गई तो उन्होंने कहा–"संविधान के स्वरूप का प्रशासन के स्वरूप से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है. सम्भव है कि हमारे प्रशासक संविधान का अर्थ ही गलत लगाएँ. हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी सर्वसाधारण जनता को भी संविधान के अर्थों को ग्रहण करने में कुछ समय अवश्य लगेगा. भारत में सर्वत्र लोकतन्त्र की कमी है, अतः यही ठीक है कि हम भविष्य के विधायकों के ऊपर शासन व्यवस्था का स्वरूप न छोड़ें. इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान में प्रशासन सम्बन्धी विस्तृत आदेश अभी से दे दिए जाएँ."

संविधान की प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान स्रोत, प्रशासनिक व्यवस्था और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है. इस संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है–"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्णप्रभुत्व सम्पन्न (धर्म-निरपेक्ष, समाजवादी) लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म एवं पूजा की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए समानता तथा उन सभी में भ्रातृत्व–जिसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित रहे, का वर्धन करने के लिए, इस संविधान सभा में आज 26 नवम्बर, 1949 ई. को इसके द्वारा इस संविधान को स्वीकार करते हैं, कानून का रूप देते हैं और अपने इस संविधान को अर्पण करते हैं."

इस प्रस्तावना से यह सिद्ध होता है कि इस संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा, भारत की जनता के लिए किया गया. इसके बनने के बाद भारत एक सर्वप्रभुत्वसंपन्न देश बन गया. इस संविधान का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना और सबको न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करना तथा बंधुत्व की भावना का विकास करना है. संविधान की मूल प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी', 'राष्ट्र की अखंडता' जैसे शब्द नहीं थे, इन्हें 42वें संशोधन (नवम्बर 1976) के द्वारा जोड़ा गया. भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान से मिलती-जुलती है.

संविधान की विशालता–भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है इसकी विशालता. अमरीका के संविधान में 7, कनाडा में 147, स्विट्ज़रलैंड में 123 धाराएँ हैं वहीं भारतीय संविधान में 395 धाराएँ, 22 भाग और 9 अनुच्छेद हैं. जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे लंबा और ब्योरेवार संविधान कहा है तथा एम. पी. पायली ने भी इसे विशालकाय संविधान की संज्ञा दी है.

संविधान के संशोधन की प्रक्रिया–भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया भी अपने आप में इसकी एक प्रमुख विशेषता है. लचीला होते हुए भी इसमें नमनशीलता के तत्व मौजूद हैं. इसमें न तो ब्रिटेन के संविधान की तरह अत्यंत लचीलापन है और न ही अमरीका के संविधान की तरह अत्यधिक कठोर है. इसमें संशोधन की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है.

संविधान में संशोधन संसद के बहुमत द्वारा, विशिष्ट बहुमत द्वारा या राज्य की विधानमंडलों की सहमति से किया जाता है. साथ ही साथ आपातकाल में संविधान का स्वरूप स्वतः संघात्मक से एकात्मक हो जाता है. इस प्रकार भारतीय संविधान को नमनशील कहा जा सकता है, परन्तु इसमें अनमनशीलता के गुण भी मौजूद हैं. संशोधन की व्यावहारिक प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है. कुछ विशेष परिस्थितियों में संशोधन करने के लिए संसद के दो-तिहाई बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है. अगर संघ में और राज्यों में एक ही दल की सरकार नहीं हो तो संशोधन कठिन हो जाता है. यह स्थिति अमरीका के संविधान से मिलती-जुलती है. अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान लचीला होते हुए भी कठोर है.

सर्वप्रभुत्वसम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना

संविधान के निर्माताओं ने इतिहास से सबक लेकर राजतंत्र को समाप्त करके एक गणराज्य की स्थापना की. यह गणराज्य स्वयंप्रभु है, इस पर किसी विदेशी सत्ता का प्रभाव नहीं है. यह संविधान जनता की मर्जी से, जनता द्वारा और जनता के लिए बनाया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना है. संविधान की प्रस्तावना में ही इन उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है.

संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था–भारतीय संविधान के आधार पर भारत में संसदीय प्रशासनिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है. अमरीका की तरह राष्ट्रपति प्रणाली नहीं. यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था को ही बनाए रखा गया है. केन्द्र तथा राज्य दोनों ही जगह यही व्यवस्था विद्यमान है. इस व्यवस्था के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों में जनता द्वारा चुने हुए बहुमत दल के प्रधान (प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री) ही वास्तविक रूप में शासन प्रधान होते हैं. राष्ट्रपति या राज्यपाल तो नाममात्र के संवैधानिक प्रधान होते हैं. वे मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करते हैं. संसद या विधानमंडल अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है. अगर वह जनता की आकांक्षाएँ पूरी नहीं करती है, तो जनता के हाथों में यह अधिकार सुरक्षित रहता है कि वह अगले चुनावों में सरकार को बिना क्रांति के बदल दें. यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली के साथ-साथ राष्ट्रपति प्रणाली के तत्व भी संविधान में मौजूद हैं. आकस्मिक विपत्ति के अवसर पर अत्यधिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है. विशेष प्रकार की परिस्थिति में कोई महत्त्वकांक्षी राष्ट्रपति स्वयं भी शासन की बागडोर अपने हाथों में ले सकता है.

संघात्मकता एवं एकात्मकता का मिश्रण–भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि इसमें संघात्मक एवं एकात्मक संविधानों का गुण भी मौजूद है. हालांकि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप भारत में संघात्मक व्यवस्था ही कायम की गई है जिसके आधार पर सिद्धान्ततः राज्य सरकारों को आंतरिक प्रशासन, विधि निर्माण एवं न्यायपालिका के क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त है फिर भी अनेक व्यवस्थाओं द्वारा केन्द्रीय सरकार को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है. उदाहरण के लिए दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण, संघवर्ती एवं समवर्ती अधिकारों की सूची, अवशिष्ट अधिकारों का केन्द्र में सुरक्षित होना, एक नागरिकता की व्यवस्था इत्यादि अनेक तत्व ऐसे हैं जो एकात्मक संविधान का आभास देते हैं. संकटकाल में तो केन्द्र के अधिकार और भी अधिक बढ़ जाते हैं. यह व्यवस्था भारत जैसे विशाल देश की एकता एवं अखंडता को एक सूत्र में बाँधे रखने के उद्देश्य से की गई थी. सामान्य तौर पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की सीमाओं का उल्लेख कर इसे संघात्मक स्वरूप ही प्रदान किया गया है.

नागरिकों के मूल अधिकार–तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध जनता की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की भी व्याख्या की है. संविधान के तीसरे भाग में 12 से 35 तक की धाराओं में इन अधिकारों की चर्चा की गई है. नागरिकों को यह भी सुविधा है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की भी शरण ले सकता है, लेकिन ये अधिकार भी सर्वोपरि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर भी कुछ सीमाएँ हैं. उदाहरण के लिए आपातकाल में इन अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त संसद कानून बनाकर इन अधिकारों में संशोधन कर सकती है. इसके अलावा इन्हें समाप्त भी कर सकती है. इन्हीं अधिकारों का उपयोग करके 44वें संशोधन (1979) ई. के अनुसार सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार मूल अधिकारों की सूची से अलग कर दिए गए. मूल अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये नाममात्र को ही प्राप्त हैं. सरकार जब चाहे तब इसको वापस ले सकती है या इन्हें निलंबित कर सकती है.

नागरिकों के मूल अधिकार निम्नलिखित हैं–

1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार
6. सम्पत्ति का अधिकार
7. सांविधानिक उपचारों का अधिकार

नागरिकों के कर्तव्य–हालांकि संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, परन्तु 42वें संशोधन (1976) में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से इसमें नागरिकों के कर्तव्यों को भी शामिल किया गया. इसकी प्रेरणा चीन व रूस के संविधान से ली गई थी.

भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित हैं–

1. संविधान का पालन करना.
2. राष्ट्रीय आदर्शों का पालन करना.
3. भारत की सार्वभौमिकता, एकता व अखंडता के प्रति निष्ठावान होना व इनकी रक्षा करना.
4. देश की रक्षा व सेवा को तत्पर रहना.
5. देश में भाईचारे की भावना विकसित करना.
6. भारतीय संस्कृति का सम्मान करना एवं इसकी सुरक्षा करना.
7. देश के प्राकृतिक वातावरण की समृद्धि में योगदान देना, उसकी सुरक्षा करना तथा प्राणीमात्र के प्रति दयाभाव रखना.
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान एवं सुधार की भावना विकसित करना.
9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना.
10. राष्ट्र के निरंतर विकास के लिए प्रयत्न करना.

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व

संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है. इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है. इनके द्वारा राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोककल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा. संविधान के चौथे भाग की धारा 36 से 51 तक में इन नीति-निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है. ये तत्व मुख्यतः आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था से सम्बद्ध हैं. इसके अनुसार राज्य ऐसे प्रबंध करेगा जिससे सभी नागरिकों की आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी हों एवं किसी का आर्थिक शोषण नहीं हो. समाज के कमजोर वर्गों के बौद्धिक एवं नैतिक स्तर का विकास हो, निष्पक्ष न्याय, समान कानून एवं ग्राम पंचायतों का विकास हो, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्‌भावना का विकास हो. संविधान के 42वें संशोधन के आधार पर इन तत्वों का विस्तार किया गया. इसके अनुसार राज्य का उद्देश्य बच्चों के समुचित विकास के लिए अवसर प्रदान करना, युवकों का नैतिक शोषण करना, समाज के कमजोर और दलित वर्गों के लिए न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, मजदूरों की सुरक्षा तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना है. मूल अधिकारों एवं नीति-निर्देशक तत्वों में अन्तर है. जहाँ अधिकारों की प्राप्ति के लिए नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है वहीं नीति-निर्देशक तत्वों की पूर्ति के लिए सरकार बाध्य नहीं है. इन उद्देश्यों को आदर्श रूप में वह अपने सामने रखती है, इसकी पूर्ति के लिए सरकार प्रयास करती है, परन्तु इसको पूरा करने के लिए प्रतिबन्धित नहीं है. इसलिए प्रो. के. टी. शाह ने इन्हें एक ऐसे 'चैक' के समान बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर आधारित है.

इकहरी नागरिकता की व्यवस्था–देश में बसने वाली विभिन्न जातियों, धर्मों के व्यक्तियों के बीच समानता एवं एकता की भावना विकसित कर भारत की एकता व अखंडता को बरकरार रखने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई. यह जन्म, निवास या स्वेच्छा से ग्रहण की जा सकती है.

शक्ति के पृथक्कीकरण का सिद्धान्त–संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के अधिकारों और कर्तव्यों का विभाजन कर दिया है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारुरूप से चलाया जा सके तथा असीमित शक्तियों पर भी नियन्त्रण रखा जा सके. न्यायपालिका को सिद्धान्ततः स्वतन्त्र रखा गया है. उनके कार्यों की समीक्षा विधायिकाओं में नहीं की जा सकती. इस प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपाल शासन प्रधान होते हुए भी विधायिका के नियंत्रण से ऊपर हैं, परन्तु अधिकारों का विभाजन सीमित अर्थों में ही है.

न्यायालय की सर्वोच्चता–संविधान निर्माताओं ने न्यायालय को सर्वोच्चता प्रदान की है. इसके अन्तर्गत, उच्चतम न्यायालय को केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच मतभेदों तथा संविधान की धाराओं की सही व्याख्या करने का अधिकार दिया गया. न्यायपालिका को संविधान का व्याख्याता एवं संरक्षक बनाया गया है, लेकिन इसके साथ-साथ संसद की सर्वोच्चता स्वीकार कर संसद को यह भी अधिकार प्रदान किया गया है कि वह न्यायालयों के अधिकारों तथा सीमा में परिवर्तन कर सके. 42वें संशोधन ने तो न्यायालय के अधिकारों को सीमित कर संसद की सर्वोच्चता स्वीकार कर ही ली. इस प्रकार भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं संसदीय सर्वोच्चता का अभूतपूर्व मिश्रण देखने को मिलता है.

विश्व के प्रमुख संविधानों की छाप–भारत के संविधान में विश्व के अनेक प्रमुख संविधानों की विशेषताओं को समाहित किया गया है. दूसरे अर्थों में कहा जाए तो भारतीय संविधान

विश्व संविधानों का मिश्रण ही है. भले ही मिश्रण है यह, परन्तु इसमें अन्य संविधानों का अंधानुकरण नहीं किया गया है.

इस संविधान में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, कनाडा की तरह शक्तिशाली केन्द्र, आस्ट्रेलिया के संविधान की तरह समवर्ती सूची, आयरिश के संविधान की तरह नीति-निर्देशक तत्त्वों की व्यवस्था की गई है. संविधान के संशोधन की व्यवस्था, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, मौलिक अधिकारों एवं न्यायपालिका संविधान की प्रस्तावना तथा कानून की प्रक्रिया की स्थापना पर क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, अमरीका, जापान का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है. विश्व के विख्यात संविधानों की अच्छाइयों को लेकर एवं भारत की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे संविधान का निर्माण किया गया है. समय-समय पर इसमें संशोधन कर इसे और भी अच्छा बनाने की कोशिशें की गई हैं. संविधान में गांधीवादी व मार्क्सवादी विचारधारा का भी मिश्रण पाया जाता है.

इनके अलावा भारतीय संविधान की अन्य विशेषताएँ भी हैं. इसमें राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने वाले तत्वों पर बल दिया गया है. समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रभाषा अपनाई गई है. अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था की गई है. भारतीय संविधान भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास का सर्वोपरि साधन है. इसके द्वारा पूरे देश में समान कानून की व्यवस्था की गई है. भारतीय संविधान विश्व शांति का भी समर्थक है.

भारतीय संविधान की आलोचना–कुछ आलोचकों ने भारतीय संविधान की कुछ कमियों को उजागर करते हुए इसकी आलोचना भी की है. संविधान सभा में अनेक सदस्यों द्वारा इसके स्वरूप पर आपत्ति उठाई गई थी. आलोचना का एक बिन्दु यह भी रहा है कि इसमें प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्णतया तिलांजलि दे दी गई है. इसके अतिरिक्त केन्द्र को इतनी अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि एकात्मक संविधान का बोध होता है. मौलिक अधिकारों पर इतने अधिक प्रतिबंध हैं कि उनका महत्त्व ही समाप्त प्रायः हो जाता है. राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को न्यायिक संरक्षण प्रदान नहीं करके उन्हें एक थोथा आदर्श मात्र बना कर रख दिया गया है. इन आलोचनाओं के कुछ कारणों में सत्यता का बोध होता है, फिर भी इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जिन परिस्थितियों में हमारे संविधान का निर्माण हुआ, उनमें इससे दूसरी व्यवस्था करना एक दुष्कर कार्य था. हमारे संविधान निर्माताओं के जो लक्ष्य थे–भारत में एक सर्वप्रभुत्व सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना एवं भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसमें हमारा संविधान पूरी तरह सफल रहा है. प्रसिद्ध विद्वान् एम. बी. पायली ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि "भारतीय संविधान कार्य करने लायक एक दस्तावेज है, यह आदर्शों एवं वास्तविकताओं का मिश्रण है. इसने सभी लोगों को एक साथ रहने एवं एक नए और स्वतंत्र भारत के निर्माण का आधार प्रदान किया है."

नेहरू का विकासवादी-समाजवादी दर्शन

नेहरू ने समाजवाद की व्याख्या करते हुए समाजवाद को राज्य द्वारा उत्पादित साधनों पर नियन्त्रण स्वीकारा है. समाजवादी व्यवस्था शोषण का प्रतिकार प्रस्तुत करती है. संग्रह की सामाजिक प्रवृत्ति को नियन्त्रित करने की विशेषता समाजवाद में है. अतः यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त विचारधारा समाजवाद में ही निहित है. समाजवाद के द्वारा समाज से भुखमरी, बेकारी व गरीबी को काफी हद तक हटाया जा सकता है. नेहरूजी का समाजवाद के प्रति गहरा विश्वास था. वे इसे केवल साधन ही नहीं मानते थे. वे वैज्ञानिक समाजवाद से अधिक प्रभावित इसलिए थे, क्योंकि उनका मानना था कि वह समाज में आधुनिकता का नव संदेश देने में सक्षम है. उनका यह भी मत था कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की गति को तेज करके राष्ट्रीय जीवन का लोकतांत्रिकरण किया जा सकता है. वे कहते थे कि भारत में समाजवाद का प्रचार-प्रसार भारतीय परिप्रेक्ष्य एवं पर्यावरण के अनुरूप ही किया जाना चाहिए. इस सम्बन्ध में उन्होंने गांधीजी के न्यासिता सिद्धान्त को समाजवाद के अनुरूप नहीं माना था. राष्ट्र की न्यासिता, व्यक्ति अथवा समाज की न्यासिता से कहीं ऊपर थी. सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण से ही राष्ट्र की न्यासिता प्राप्त हो सकती है, ऐसा उनका विचार था. उनके विचारों पर मार्क्सवाद का प्रभाव परिलक्षित होता था. वे उसके द्वारा प्रतिपादित वर्गविहीन समाज तथा इतिहास की आर्थिक व्यवस्था को स्वीकार करते थे. अपनी रूस यात्रा के अनुभवों के आधार पर उन्होंने मार्क्सवाद के वैज्ञानिक समाजवादी पक्ष का समर्थन किया था. वे मानते थे कि रूस ने विज्ञान तथा प्रविधि का प्रयोग करके मानव के आर्थिक शोषण को कम किया है. उनकी नजर में समाजवाद व्यक्तिवाद का तत्सम रूप था. वे मार्क्सवाद की उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे जिसमें व्यक्ति को समष्टि में परिवर्तित कर दिया गया है. समाजवाद में प्राप्त भौतिक सम्पन्नता व्यक्तिगत अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का विलोम नहीं है, सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को वे पूर्णतः समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे. वे चाहते थे कि सम्पत्ति अधिकार सहकारिता के आधार पर हो. सम्पत्ति अधिकार सहकारिता पर आधारित होने से मुनाफाखोरी पर रोक लग सकती है, इसके वे प्रबल

पक्षधर थे. उनकी मान्यता थी कि साधनों के उचित वितरण से सम्पत्ति के एकाधिकार अथवा केन्द्रीयकरण से बचा जा सकता था. हालांकि राज्य का बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा भी पैदा कर सकता था. इस के प्रति नेहरू बहुत जागरूक थे. समाजवादी राज्य द्वारा औद्योगीकरण का प्रसार होने से राज्य की शक्ति बढ़ती है, परन्तु चुनौती का सामना उचित आर्थिक समायोजन तथा योजनाबद्ध विकास पर सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से ही किया जा सकता है. छोटे-छोटे उद्योग औद्योगिक विकेन्द्रीकरण में महत्त्वपूर्ण सहायक होते हैं. वे ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास किये जाने के प्रबल पक्षधर थे. उनका कहना था कि गाँवों का आधुनिकीकरण करके ग्रामीणों को शहरों की चकाचौंध करने वाली प्रवृत्ति से बचाया जा सकता है. गाँवों के समग्र विकास के लिए वे सामुदायिक विकास योजनाओं तथा विस्तार सेवाओं को बढ़ाने के प्रति प्रयासरत थे. नेहरू का राष्ट्रवाद उनके अन्तर्राष्ट्रवाद के समकक्ष था. वे केवल देशभक्ति अथवा राष्ट्रवाद के संकीर्ण धरातल पर अवस्थित रहना नहीं चाहते थे.

नेहरू के मन-मस्तिष्क पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव 1926-27 ई. की रूस यात्रा से स्थिर हो गया था. वे रूस द्वारा प्राप्त आर्थिक विकास से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (1929 ई.) के अध्यक्षीय भाषण में समाजवादी दर्शन के विश्वव्यापी सामाजिक प्रभाव को व्यक्त किया था. समाजवादी पद्धति भारत की दरिद्रता एवं आर्थिक विषमता को दूर कर सकेगी, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया. सन् 1931 ई. में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव उन्हीं के प्रभाव से पारित हो पाया था. 1936 ई. के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने भूमि तथा चंद व्यक्तियों के हाथ में उद्योगों के स्वामित्व की निंदा करते हुए जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात कही थी. हालांकि वे मार्क्स की विचारधारा से पूर्णतया सहमत नहीं थे और उन्होंने विशेषरूप से वर्ग संघर्ष की अवधारणा को भी नहीं स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में पूँजीपतियों द्वारा साधनहीन किसानों एवं श्रमिकों के शोषण के प्रति गहरा प्रतिशोध था. वे समाजवादी प्रक्रिया के तहत आर्थिक शोषण को खत्म करना चाहते थे तथा भारत में नए आर्थिक समाज की रचना की स्थापना के लिए परिवर्तन एवं विकास की राह अपनाना चाहते थे. हालांकि उनका यह विचार तो था, परन्तु वे कहते थे कि विकास की राह शक्ति के माध्यम से नहीं, अपितु शांति के साथ होनी चाहिए. जवाहरलाल नेहरू भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए भारत में लोकतंत्र को आवश्यक मानते थे. वर्ग चेतना का अभाव, अंधविश्वास, आत्मवादिता, अकर्मण्यता आदि ऐसे मूलभूत कारण थे जिनसे नेहरू ने भारत में समाजवाद को शक्ति के बल पर लाना उचित नहीं समझा. वे चाहते थे कि जनता को जाग्रत किया जाए तथा उसमें समाजवाद के प्रति निश्चित लोकमत तैयार किया जाए ताकि सामाजिक प्रक्रिया क्रमिक तथा अनवरत रूप से शुरू हो सके. नेहरूजी ने भारत की अर्थव्यवस्था में समाजवाद को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के महत्त्व को प्रतिपादित किया. मिश्रित अर्थव्यवस्था में उन्हें भारत की दरिद्रता के निवारण के उपाय दीख रहे थे. उनके अनुसार उत्पादन के प्रमुख स्रोतों का सार्वजनिक क्षेत्र में होना स्वतः सार्वजनिक स्वामित्व में वृद्धि करते हुए देशव्यापी औद्योगीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा. उनके द्वारा स्वीकृत मिश्रित अर्थव्यवस्था का कार्य राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता तथा राष्ट्रीय आय में अभिवृद्धि का कारण बना. समाजवादी दृष्टिकोण के कारण ही सम्पत्ति के सम्बन्ध में नवीन धारणाएँ बनीं. सार्वजनिक उपयोग में निजी सम्पत्ति के हस्तांतरण का मार्ग भी नेहरू ने ही प्रशस्त किया. हालांकि आज भी देश में समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य पूर्णतया सम्पादित नहीं हो पाया है. नेहरूजी ने समाजवादी देशों के स्वामित्व का ही मार्ग अपनाया. नेहरूजी के समाजवादी समाज की रूपरेखा सीमित थी. वे सीमित अर्थों में समाजवाद का प्रयोग कर रहे थे. मिश्रित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों में पूँजीपतियों को पूर्णतया समाप्त करने का कोई कार्यक्रम नहीं था. उन्हें समाप्त करने के लिए परोक्ष रूप से सामाजिक क्षेत्र का विस्तार करने का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है.

योजना व्यवस्था एवं औद्योगीकरण

जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार एवं बड़े-बड़े उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रारम्भ कर उन व्यवसायों से पूँजीपतियों को वंचित कर दिया, किन्तु देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा विशेषतः उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए छोटे उद्योगों एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखना आवश्यक था. नेहरू का आर्थिक कार्यक्रम सह अस्तित्व का प्रतीक था, अन्यथा वे निजी क्षेत्र को समूल नष्ट करने का विचार प्रस्तुत करते. समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के शांतिपूर्ण प्रयासों में वर्ग-संघर्ष की स्थिति को टालना तथा इस संघर्ष को पारस्परिक वार्ता, मजदूर संगठनों के विकास एवं बढ़ते हुए प्रभाव तथा उपभोगी व्यवस्थापन के माध्यम से दूर करने का उनका विचार सर्वथा समाजवादी था. वे समाजवाद को भारतीय पर्यावरण के अनुकूल स्थिति में ढालना चाहते थे. रूस अथवा चीन का अक्षरशः अनुकरण करने का उनका कोई इरादा नहीं था. इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बैंकों के राष्ट्रीयकरण अथवा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का जो कार्य सम्पन्न हुआ, वह नेहरू के द्वारा

किए गए प्रयासों का ही प्रतिफल था. नेहरूजी ने समाजवादी समाज की स्थापना का पहला चरण हमारे समक्ष रखा था और उसे गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया. वे केवल एक वैचारिक समाजवादी ही नहीं, राजनीतिक यथार्थवादी भी थे. उन्हें निजी उद्योगों की राष्ट्रीय उत्पादन में अभिवृद्धि करने की क्षमता का पूरा अहसास था और उसका उन्होंने पूर्ण उपयोग भी किया तथा उन्होंने सामान्यजन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के भरसक प्रयत्न भी किए.

उनकी लोकतांत्रिक समाजवाद में गहरी निष्ठा थी. वे उत्पादन में वृद्धि करने के पक्षधर थे, जिसके लिए उन्होंने भारत में राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थन किया. उत्पादन पर जोर देना उनके बारे में यह सिद्ध करता है कि वे पूँजीवादी व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त करने के पक्षधर नहीं थे. उल्लेखनीय है कि पूँजीवादी व्यवस्था उत्पादन प्रधान होती है, जबकि साम्यवादी अथवा पूर्णतया समाजवादी व्यवस्था में उपभोग पर अधिक ध्यान दिया जाता है. नेहरू समाजवाद के लक्ष्य की ओर तो बढ़ना चाहते थे, किन्तु वे स्वयं को पूँजीवादी व्यवस्था के प्रति अपने झुकाव नहीं रोक पाते थे. नेहरूजी ने राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थन करते हुए भारत में प्रतिरक्षा तथा कुछ अन्य प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया. हालांकि इन उद्योगों पर व्यय करने के लिए प्राप्त धनराशि को नए उद्योगों की स्थापना में लगाया जा सकता था तथा निजी उद्योगों के लिए भी रास्ता खुला था, किन्तु इतना सब कुछ होने के बाद भी नेहरू ने यह सुझाव दिया कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उत्पादन के श्रेष्ठ साधनों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखा जाए, ताकि निजी व्यवसायियों के हाथ में जाकर वे निजी एकाधिकार की वस्तु न बन जाएँ. समतापूर्ण वितरण तथा समुचित उत्पादन की समस्या का निराकरण करने के लिए नेहरूजी ने साम्यवाद तथा पूँजीवाद का रास्ता अपनाया. उनके अनुसार जनता का जीवन स्तर उन्नत करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जीवनयापन के साधन उपलब्ध कराना भारत के समाज की मूलभूत आवश्यकता थी. नेहरू ने जहाँ समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति पर बल दिया, वहीं उसे औद्योगीकरण के लिए भी आवश्यक बताया. वे निजी उद्योगों का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते थे. उनका विचार था कि निजी व्यवसायियों को भी उद्योग-धंधे चलाने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए. उनका मानना था कि अपनी आवश्यकता तथा क्षमता के अनुसार आर्थिक कार्यक्रम तय किए जाने चाहिए. नेहरू के अनुसार भारत जैसे देश के सामने अनेक समस्याएँ तथा संघर्ष भरा वातावरण है. नेहरू के अनुसार भारतवासी अमरीका की तरह लम्बे समय तक आर्थिक विकास की प्रतीक्षा नहीं कर सकते. भारत की बड़ी-बड़ी योजनाओं को भारत के निजी उद्योग नहीं चलाते. राज्य द्वारा चलाए जाने पर भी ये योजनाएँ तुरन्त लाभ देना शुरू नहीं करतीं. इसके लिए कुछ समय चाहिए. उन्होंने भारत के उद्योगपतियों को पैसे बनाने की कला में निपुण बताया. इतना कहने के बाद भी नेहरू ने उद्योगपतियों को व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में विवेक शून्य करार दिया, क्योंकि भारतीय उद्यमियों के समय के साथ-साथ आगे बढ़ने के स्थान पर प्राचीन विगलित मुक्त व्यापार को बन्द नहीं किया. जवाहरलाल नेहरू ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निजी सम्पदा में अभिवृद्धि करने के स्थान पर सार्वजनिक हितों के संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध किया, नेहरू का मानना था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के मार्फत कल्याणकारी राज्य की स्थापना सम्भव है मगर कल्याणकारी राज्य को समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित करना उनकी नजर में ठीक नहीं था. नेहरू जी का मानना था कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य समाजवाद अथवा साम्यवाद द्वारा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हमारी राष्ट्रीय आय में अत्यधिक वृद्धि न हो जाए. समाजवाद अथवा साम्यवाद हमारी वर्तमान सम्पदा का विभाजन कर सकते हैं, किन्तु भारत में निर्धनता के अलावा विभाजन के लिए कुछ भी नहीं है, केवल गिने-चुने धनाढ्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को इधर-उधर बाँटने से हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती. आर्थिक साधनों के अभाव में लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना असंभव है. जनकल्याण की नींव अभाव की अर्थव्यवस्था पर कभी नहीं टिक सकती. इसके लिए आवश्यक है प्रचुर अर्थव्यवस्था की, जो प्रत्येक अभाव को दूर कर सके. नेहरूजी ने समाजवाद की धारणा को लचीली, विकास के लिए उन्मुख, गत्यात्मक मानते हुए किसी विशेष दिशा में ढालने के बजाय सर्वतोमुखी विचार के रूप में जाँचा तथा परखा. उनके अनुसार अत्यधिक विकसित औद्योगिक समुदाय का समाजवाद कृषि-प्रधान व्यवस्था के समाजवाद से भिन्न होगा. समाजवाद को किसी दृढ़ परिभाषा में बाँधने के स्थान पर आवश्यकतानुसार किए गए जनोपयोगी कार्यों को समाजवादी कार्यक्रम की संज्ञा दी जा सकती है. पूँजीवादी व्यवस्था के संग्रहकारी समाज के स्थान पर सहयोग एवं सहकार पर नए समाज के निर्माण का मार्ग सुझाने के कारण अपने आप में विशिष्ट है.

सर्वाधिकारवादी राज्य के अन्तर्गत समाजवाद की स्थापना त्वरित गति से होती है. इसके विपरीत लोकतांत्रिक पद्धति से समाजवाद की स्थापना धीरे-धीरे होती है. लोकतांत्रिक समाजवाद मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है. नेहरू के कथनानुसार भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आदर्श को स्वीकार किया है, अतः केवल भौतिक समृद्धि ही प्राप्त कर अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकती. हमें भौतिक सम्पदा

के साथ-साथ मानव की रचनात्मक शक्ति में भी वृद्धि करनी चाहिए. लोकतंत्र तथा समाजवाद को समन्वित करने के शांतिपूर्ण उपायों पर अमल करना है. दमन अथवा हिंसा के स्थान पर सद्भाव तथा सहयोग के जरिए लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेहरू ने इस संदर्भ में तानाशाही शासकों को भी सद्भाव तथा सहयोग का अवलम्बन लेते हुए लोकतांत्रिक सरकारों के लिए अपरिहार्यता पूर्व बल दिया तथा इसके लिए भरसक प्रयत्न भी किए.

गुटनिरपेक्षता

गुटनिरपेक्षता की नीति को सबसे पहले व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय भारत को ही जाता है. स्वतंत्र भारत ने इसको अपनी विदेश नीति का आधार बनाया और भीषण कठिनाइयों के बाद भी इसको अनवरत् रूप से आगे बढ़ाया. इसके बाद धीरे-धीरे गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या बढ़ती गई. सन् 1961 में बेलग्रेड के गुट- निरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने, 1973 ई. में अल्जीरिया में आयोजित शिखर सम्मेलन में 76 देशों ने और 1976 ई. में कोलंबो में आयोजित शिखर सम्मेलन में 85 देशों ने भाग लिया. भारत विश्व के सभी गुटनिरपेक्ष देशों की 'आशा' है और विश्व मंच पर भारत की आवाज का पहले से कहीं अधिक महत्त्व है. गुटनिरपेक्षता की नीति आज अंतर्राष्ट्रीय जगत् में स्थायी रूप धारण कर चुकी है और एक वास्तविकता बन चुकी है. गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था–

"यदि हम अपने आपको किसी एक गुट के साथ जोड़ लेते हैं, तो एक प्रकार से शायद यह अच्छा कदम सिद्ध होगा, लेकिन हमें ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण दुनिया को इससे लाभ की अपेक्षा हानि होगी. इससे हम दुनिया में अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकेंगे."

गुटनिरपेक्षता का अर्थ व उसके तत्त्व

गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या अलग रहते हुए स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन देना. इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता नहीं हैं. जो देश गुट- निरपेक्षता की नीति अपनाते हैं, वे विश्व की घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी स्पष्ट और रचनात्मक नीति अपनाते हैं, जो विश्व शांति रखने में सहायक हो. भारत सरकार के एक प्रकाशन के अनुसार–"गुटनिरपेक्षता का अर्थ है अपनी स्वतंत्र रीति-नीति', गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य-अनौचित्य को देखा जा सकता है. एक गुट के साथ मिलकर उचित-अनुचित का विचार किए बिना आँख मूँदकर पीछे-पीछे चलना गुट-निरपेक्षता नहीं है".

तटस्थता और गुटनिरपेक्षता पर्यायवाची शब्द नहीं हैं. इन दोनों में यह समानता तो है कि दोनों के अन्तर्गत शीतयुद्ध के समय संघर्ष से अलग रहा जाता है, लेकिन आधारभूत अंतर यह है कि जहाँ वास्तविक युद्ध छिड़ने पर एक तटस्थ राष्ट्र युद्ध से अलग रहता है, वहीं गुटनिरपेक्ष देश किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध में भागीदार हो सकता है. उसकी नीति न्याय का समर्थन करती हुई सकारात्मक होती है. गुट-निरपेक्षता कोई निष्क्रिय सिद्धान्त नहीं है. इस नीति के तहत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है.

इसका स्पष्ट रूप से जो अर्थ सामने आता है वह है, किसी भी देश के साथ गुटबंदी में सम्मिलित न होना, पश्चिमी या पूर्वी गुट के किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से न बँधना, प्रत्येक प्रकार की आक्रामक संधि से दूर रहना. शीतयुद्ध से अलग रहना, राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेशी नीति का संचालन करना. सन् 1961 ई. में गुटनिरपेक्षता के तीन प्रमुख नेहरू, नासिर और टीटो ने गुटनिरपेक्षता के निम्न-लिखित पाँच तत्त्व स्वीकार किए थे–

1. सदस्य-देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो.
2. सदस्य-देश उपनिवेश का विरोध करता हो.
3. सदस्य-देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो.
4. सदस्य-देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, और.
5. सदस्य-देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने सीमा क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो.

सन् 1946-47 में भारत ने गुटनिरपेक्षता का जो बीज बोया वह समय के साथ पेड़ बनकर आज के समय में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बन गया है. नेहरू के ये शब्द आज भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं, जितने कि उस समय थे.

"जहाँ स्वतंत्रता के लिए खतरा हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहाँ आक्रमण होता हो, वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे". गुटनिरपेक्षता की नीति राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक हैं. यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखती, बल्कि दोनों पक्षों की स्थिति को समझकर उचित पक्ष का समर्थन करने को तत्पर रहती है. गुटनिरपेक्षता की नीतियों को अपनाने वाले देशों का यह विश्वास होता है कि सैनिक संधियों का विरोध किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की संधियाँ

सहयोग के लिए नहीं, अपितु विरोध का परिणाम होती हैं, जिन्हें तोड़ने का एकमात्र उपाय युद्ध अथवा पारस्परिक वैमनस्य है.

गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक

विलियम हेंडर्सन ने गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए आठ कारकों का उल्लेख किया है, जो कि निम्न-लिखित हैं–

1. पश्चिमीकरण का विरोध
2. नवप्राप्त स्वतंत्रता को कायम रखने का संकल्प
3. भावनाओं की प्रगाढ़ता, किन्तु भौतिक कमजोरियाँ
4. विदेशी व्यवहार का अज्ञान अथवा उदासीनता
5. मार्क्सवाद का प्रभाव
6. साम्यवादी चीन के साथ समायोजित होने की आवश्यकता
7. गुटनिरपेक्षता को शान्ति जल मानने का विश्वास
8. गुटनिरपेक्षता द्वारा साम्यवाद को रोका जा सकता है.

इन कारकों में प्रथम प्रेरक शक्ति राष्ट्रवाद की भावना है. राष्ट्रवाद और गुटनिरपेक्षता के बीच सहयोग इसी बात से स्पष्ट है कि नवोदित राष्ट्रों के नेता गुटनिरपेक्षता के समर्थन में राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं. जान मारकस के अनुसार, "जब कभी तटस्थता की नीति का प्रभाव हुआ है, तो वह मुख्यतः राष्ट्रवाद की धारणा के आधार पर ही सम्भव हुआ है." दूसरी सहायक परिस्थिति उपनिवेश का विरोध है. बांडुंग सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया था कि यदि किसी देश को सैनिक संगठन में शामिल होने को मजबूर करने वाली कोई स्थिति नहीं है, तो उपनिवेश विरोधी भावना उसे गुट-निरपेक्षता की दिशा में प्रेरित करेगी. तीसरी सहायक परिस्थिति नवोदित राज्यों की अर्द्धविकसित स्थिति है. इन देशों की रुचि शस्त्रास्त्रों की प्रतियोगिता से बचकर आर्थिक पुनर्निर्माण में अधिक है और केवल गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर ही ये देश विश्व के विरोधी गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

गुटनिरपेक्षता की बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रमाण हमें गुटनिरपेक्ष देशों के विभिन्न शिखर सम्मेलनों से प्राप्त होता है. ये शिखर सम्मेलन कहाँ-कहाँ और कब-कब हुए, एक दृष्टि डालना ठीक रहेगा.

शिखर सम्मेलन कब और कहाँ

सम्मेलन	स्थान	वर्ष
प्रथम शिखर सम्मेलन	बेलग्रेड	1–6 सितम्बर, 1961
द्वितीय शिखर सम्मेलन	काहिरा	5–10 अक्टूबर, 1964
तृतीय शिखर सम्मेलन	लुसाका	8–10 सितम्बर, 1970
चतुर्थ शिखर सम्मेलन	अल्जीरिया	5–9 सितम्बर, 1973
पाँचवाँ शिखर सम्मेलन	कोलम्बो	16–19 अगस्त, 1976
छठा शिखर सम्मेलन	हवाना	3–9 सितम्बर, 1979
सातवाँ शिखर सम्मेलन	नई दिल्ली	7–12 मार्च, 1983
आठवाँ शिखर सम्मेलन	हरारे	1–6 सितम्बर, 1986
नौवाँ शिखर सम्मेलन	बेलग्रेड	4–7 सितम्बर, 1989
दसवाँ शिखर सम्मेलन	जकार्ता	1–7 सितम्बर, 1992
ग्यारहवाँ शिखर सम्मेलन	कार्टाजेना	18–20 अक्टूबर, 1995
बारहवाँ शिखर सम्मेलन	डरबन	2-3 सितम्बर, 1998
तेरहवाँ शिखर सम्मेलन	कुआलालम्पुर	20–25 फरवरी, 2003
चौदहवाँ शिखर सम्मेलन	हवाना	11–16 सितम्बर, 2006
पन्द्रहवाँ शिखर सम्मेलन	मिस्र	2009 में प्रस्तावित

गुटनिरपेक्ष देश के रूप में भारत

टी. एन. कौल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था–"अगर पिछले 25 वर्षों पर दृष्टिपात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब हम इस बात पर ध्यान दें कि स्वाधीनता के समय भारत आज की अपेक्षा संसार की शक्ति राजनीति में कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने की कम क्षमता रखता था. लेकिन भय और अविश्वास, शक्ति संतुलन, प्रभाव क्षेत्र, शीतयुद्ध और सैनिक संधियों वाले तत्कालीन विश्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण से एक नया वातावरण पैदा किया था.

भारत ने अपने भाग्य निर्माण या ऐसे ही किसी अन्य उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रवेश नहीं किया, बल्कि इसके पीछे यथार्थवाद की भावना थी, जिसका आधार उसकी अपनी परिस्थितियों की वास्तविकता तथा उसके आसपास के राजनीतिक जीवन के तथ्य थे, जिनके कारण गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई". स्वाधीन भारत की नीति सैनिक अथवा राजनीतिक गठबंधनों से तटस्थ रहने की थी, परन्तु यह निष्क्रियता की नीति नहीं थी.

यह नीति परिस्थितियों के अनुकूल विश्वशांति और उपनिवेशों को स्वाधीनता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्रियाशीलता की नीति थी. गुटनिरपेक्ष देश के रूप में भारत को शीघ्र ही मान्यता मिल गई. गुटनिरपेक्ष देश के रूप में भारत ने इस नीति को बखूबी आगे बढ़ाया और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए. उदाहरण के लिए–

(1) सबसे पहले कोरिया के संकट के समय भारत की स्वतंत्र फैसला कर सकने की क्षमता को तथा शीत युद्ध से प्रभावित इस मामले में उसकी कार्यवाई को मान्यता मिली.

(2) 8 सितम्बर, सन् 1951 को भारत ने सैनफ्रांसिस्को में होने वाली जापान शांति शक्ति में अमरीका की शर्तों पर आपत्ति प्रकट कर, एक बार फिर अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण का परिचय दिया.

(3) कोरिया की तरह ही हिन्द-चीन में भी भारत का प्रयास इस क्षेत्र को शीतयुद्ध का शिकार बनने से रोकना था. भारत की दृष्टि में यह संकट साम्राज्यवाद की पुनः स्थापना के विरुद्ध राष्ट्रवादी संघर्ष था. यहाँ भी भारत ने अमरीका के इस इरादे का विरोध किया कि वह फ्रांसीसी सरकार द्वारा हो-ची-मिन्ह के विरुद्ध युद्ध में तेजी लाने का प्रयास करें.

(4) सन् 1956 ई. के स्वेज नहर के संकट के प्रति भारत के रवैये ने गुटनिरपेक्ष देशों की एकजुटता को मजबूत करने तथा उनकी स्वाधीनता के प्रदर्शन में सहायता की. भारत ने ब्रिटेन-फ्रांस की नीति का विरोध किया.

(5) सन् 1961 ई. में बेलग्रेड में आयोजित धर्म निरपेक्ष सम्मेलन में शीतयुद्ध के खिलाफ भारत की भूमिका प्रमुख रही.

(6) नवम्बर 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत को पश्चिमी देशों से बिना शर्त अविलंब सैनिक सहायता प्राप्त हुई और रूस का समर्थन भी मिला.

(7) सितम्बर 1965 में भारत-पाक के युद्ध में असंलग्नता की नीति की शक्ति को एक बार फिर सिद्ध करके दिखा दिया गया.

(8) दिसम्बर 1971 में बांग्लादेश के कारण जो भारत-पाक युद्ध हुआ उसने गुटनिरपेक्षता की नीति को पुनः सही सिद्ध करके दिखाया. पाकिस्तान को हथियार देने वाले देश पाकिस्तान को अंगूठा दिखा गए और देखते-देखते पाकिस्तान अपने एक भू-भाग को अपनी ही मूर्खता से खो बैठा.

वर्तमान परिस्थितियों में गुटनिरपेक्षता का महत्त्व

निम्नलिखित कारणों से गुटनिरपेक्षता का महत्त्व बढ़ता अनवरत् बढ़ता रहा है–

(1) गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है.

(2) गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की आवाज संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिक प्रखर और प्रबल है.

(3) समूचे विश्व में गुटनिरपेक्षता की शक्ति को संतुलनकारी शक्ति के रूप में मान्यता मिल चुकी है.

(4) गुट निरपेक्षता की नीति "जीओ और जीने दो" का सिद्धान्त अपनाती है.

(5) गुटनिरपेक्ष की नीति शस्त्रीकरण को हतोत्साहित करके आर्थिक समृद्धि और शांति के पक्ष का अनुसरण करती है.

(6) यह नीति उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ है.

(7) गुटनिरपेक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर सिद्धान्त को प्रश्रय देती है.

(8) गुटनिरपेक्षता की नीति का मूलमंत्र है "विश्व बंधुत्व का विकास".

(9) गुटनिरपेक्षता की नीति सैनिक गुटों और सैनिक संधियों का तिरस्कार कर राष्ट्रीय-हितों पर अधिक ध्यान देती है.

(10) गुटनिरपेक्षता की नीति लचीली है तथा सतत विकासशील है.

आधुनिक संदर्भ में गुटनिरपेक्षता को साम्राज्यवाद-विरोध का सूचक माना जाता है. यहाँ यह बात भी गौरतलब है कि अधिकांश गुटनिरपेक्ष देश वे ही हैं जो कुछ समय पूर्व तक औपनिवेशिक दासता के शिकार थे. गुटनिरपेक्ष नीति कितनी प्रभावी सिद्ध हो सकती है इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि पहले तो भारत को विश्व के दोनों गुटों से सहायता मिलती रही, लेकिन जब विकसित राष्ट्रों ने अपनी दबाव नीति अपनाई, तो भारत भीषण संकटों को भी झेल गया, क्योंकि दूसरे शक्तिशाली गुट ने भारत की गुटनिरपेक्षता को पूर्ण समर्थन एवं सम्मान दिया था. इस प्रकार एक महान् पूँजीवादी शक्ति के अनेक षड्यंत्र रखे रह गए. अतः गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त आज की परिस्थितियों में अपनी अहमियत बनाए हुए है, इसे नकारा नहीं जा सकता.

भारत की विदेश नीति

भारत की विदेश नीति का निर्धारण भारत की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में किया गया था. भारत ने समाजवादी समाज की स्थापना को निर्धारित किया था और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत को साम्यवादी तथा पश्चिमी राष्ट्रों से अपने सम्बन्ध मधुर रखते हुए दोनों से आर्थिक सहायता प्राप्त करनी थी. भारत के सामाजिक जीवन के आधुनिकीकरण तथा प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए शिथिल आर्थिक व्यवस्था को संबल प्रदान करना बहुत जरूरी था. राजनीतिक लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता तथा आर्थिक विकास में सम्पन्नता लाने की दृष्टि से विदेश नीति को उसी दिशा तथा क्रम में निर्धारित किया गया. बांडुंग सम्मेलन में नेहरू के सफल नेतृत्व के कारण एशिया तथा अफ्रीका के देशों को नई प्रेरणा तथा

शक्ति प्राप्त हुई. नेहरू का इरादा था कि समूचे विश्व में शांति तथा मतैक्य की भावना स्थापित हो, इसलिए उनका सम्पूर्ण प्रयास विदेश नीति को उच्च शिखर पर पहुँचाने का था. उनका यह मानना था कि भारत पार्थक्य की नीति का अनुसरण कर विश्व राजनीति से अलगाव नहीं रह सकता था. भू-राजनीति एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए नेहरू ने, वसुधैवकुटुम्बकम्, के सिद्धान्त में आस्था प्रकट की. हालांकि नेहरू के विचारों में आदर्श एवं उच्च नैतिक सिद्धान्तों का विशेष पुट था, फिर भी उनकी विदेश नीति को केवल आदर्शात्मक नहीं माना जा सकता. उनका भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने का उद्देश्य आदर्शपूर्ण यथार्थ का था. भारत अन्य देशों से अधिक नैतिकता का दावा नहीं कर सकता. गांधीजी के साधन-साध्य सम्बन्धों के नैतिक औचित्य को पूर्ण मान्यता प्राप्त करते हुए भी भारत राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि नहीं दे सकता था. इस प्रकार नेहरू की विदेश नीति के आदर्शात्मक पक्ष यथार्थवाद से असम्बद्ध नहीं थे.

भारत की विदेशनीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था– भारत का पंचशील सिद्धान्तों में विश्वास. पंचशील की मान्यता को नेहरू के ही प्रयत्नों का परिणाम माना जा सकता है. नेहरू ने इसी आधार पर भारत-चीन समझौता किया.

भारतीय विदेश नीति की दूसरी विशेषता थी 'असंलग्नता की नीति का अनुसरण'. सही मायने में देखा जाए तो असंलग्नता की नीति विदेश नीति का साधन थी, न कि स्वयमेव साध्य. असंलग्नता के प्रति लगाव होने का अर्थ नहीं था कि राष्ट्रीय नीति एवं क्रियाविधि की स्वतंत्रता का ही त्याग कर दिया जाए. भारत की विश्व राजनीति में सक्रियता एवं गतिशीलता को देखते हुए उसे तटस्थवाद का समर्थक नहीं माना जा सकता. विदेश नीति के तहत असंलग्नता की नीति का उद्देश्य विश्व के व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का था. भारत की विदेश-नीति में विश्व शांति की कामना इसलिए नहीं की गई थी कि भारत अपना आर्थिक विकास चाहता था, अपितु इस धारणा में यह विश्वास निहित था कि शांतिमय जीवन चिंतन तथा क्रियाशीलता का आधार है. अपनी विदेश नीति के तहत नेहरू ने औपनिवेशिक शक्ति से दबे जनमानस के आत्मनिर्णय के अधिकार को सर्वव्यापी बनाने का प्रयास किया तथा उसे विश्व शांति की आवश्यक शर्त बताया. नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में रंगभेद तथा प्रजातीय भेदभाव का व्यापक विरोध किया गया. उनको अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा विश्व शांति के संदर्भ में आपसी सौहार्द्र से ही अधिक उपयुक्त लगता था.

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भारत की विदेश नीति को उन्होंने इतना अधिक सशक्त बना दिया था कि भारत विश्व के प्रत्येक कोने में अमरीका को छोड़कर अपने सम्बन्ध स्थापित कर सका. विदेश नीति के कारण ही अरब देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सके. चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने से भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ी, क्योंकि एक ओर घिनौनी आक्रमणकारी तस्वीर विश्व के सामने आई तो दूसरी ओर भारत ने अपने प्रतिरक्षा प्रयासों को नया मोड़ दिया. विदेश नीति पर चलकर ही भारत ने अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को सबल बनाया और आक्रमण-कारियों को मुँहतोड़ जवाब दिया. नेहरू की यह विदेश नीति कालजयी सिद्ध हुई और भारत की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर साख बढ़ाने में कामयाब हुई.

भारत-चीन सम्बन्ध

प्राचीनकाल से भारत एवं चीन के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं. एक-दूसरे राष्ट्र ने पड़ोसी की भूमिका का उत्कृष्ट स्वरूप में निर्वहन किया है. व्यापारिक एवं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भी लम्बे अन्तराल से चीन एवं भारत में माधुर्यता कायम रही है. चीन में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का वर्चस्व रहा है और इस मायने से भारत चीन का धर्मगुरु है. इतिहास साक्षी है ह्वेनसांग, फाह्यान, इत्सिंग जैसे कई चीनी यात्री अनवरत् भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्ति के लिए आते रहे हैं. श्रेष्ठ सम्बन्धों के अतिरिक्त भारत की हिमालय शृंखलाओं ने भारत को चीन के प्रति निश्चिन्त बनाए रखा है. कालान्तर में दोनों राष्ट्र विदेशी आधिपत्य में आ गए, इसके फलस्वरूप सम्बन्धों में दूरियाँ बढ़ती गईं. सन् 1947 में भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तथा दूसरी तरफ सन् 1948 में कोमिन्तांग सरकार के पतन के पश्चात् चीन सन् 1949 में साम्यवादी देश के रूप में उभरा. पुनः दोनों देशों के मध्य अन्तर्सम्बन्धों की महत्ता का अनुभव किया गया. यहाँ यह बताना उचित होगा कि भारत की विदेश-नीति में चीन के साथ शान्ति एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना मूल लक्ष्य रहा है. किसी भी काल में अपने पड़ोसी के प्रति भारत का दृष्टिकोण दूषित नहीं रहा. इस सन्दर्भ में शान्ति एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की भारतीय भावना को स्पष्ट करने के लिए पं. जवाहर लाल नेहरू के कथन को उद्धृत करना श्रेयस्कर होगा–

> *"चीन अपने इतिहास के साथ एक महान् शक्तिशाली देश है. वह हमारा पड़ोसी है. वह युगों से हमारा मित्र रहा है और यह मित्रता बनी रहेगी और बढ़ेगी, फूलेगी."*
>
> पं. जवाहर लाल नेहरू
> 7 सितम्बर, 1946,
> ऑल इण्डिया रेडियो प्रसारण

दिसम्बर 1949 में भारत ने साम्यवादी चीन को पूर्ण मान्यता प्रदान कर अपनी द्विपक्षीय मित्रता एवं सहयोग की उत्कट इच्छा को और अधिक स्पष्ट कर दिया. अमरीका

आदि विभिन्न देशों द्वारा आलोचना करने के उपरान्त भी भारत चीन से मित्रता करने के सन्दर्भ में तनिक भी विचलित नहीं हुआ, लेकिन यह सब एक तरफा सिद्ध हुआ. चीन की कठोर नीति के फलस्वरूप भारत-चीन सम्बन्धों का प्रारम्भ ठीक ढंग से न हो सका. 1949 ई. में चीन ने गैर-साम्यवादी देशों के साथ कठोर नीति अपनाना प्रारम्भ कर दिया. चीन भारत की स्वतन्त्रता को अवास्तविक एवं गुट निरपेक्षता की नीति को मात्र दिखावा मानता था. चीन ने भारत को पश्चिमी साम्राज्यवाद का पिछलग्गू एवं नेहरू को बूर्जुआ, साम्राज्यवादियों का दास एवं प्रतिक्रियावादी चरित्र वाला बताया. इस तरह 1952 तक भारत के प्रति चीन का व्यवहार नकारात्मक, कठोर एवं उपेक्षित रहा, जबकि भारत की नीति हमेशा उसके पक्ष में रही. उल्लेख करना अत्यावश्यक होगा कि गैर-साम्यवादी राष्ट्रों में भारत एकमात्र ऐसा देश था, जिसने उसे राजनयिक मान्यता भी दी एवं द्विपक्षीय मैत्री का प्रस्ताव भी. भारत ने पग-पग पर चीन को एक अच्छे मित्र की तरह सहयोग दिया. अमरीका द्वारा 1950-51 में कोरिया युद्ध में नाराजगी प्रदर्शन के चलते भी भारत ने चीन का पक्ष लिया. 1950 से 1951 तक कोरिया युद्ध के विराम में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शान्ति सेना को कोरिया में 38वें अक्षांश को पार करने के निर्देश देने के समय भारत ने ही इसका कड़ा विरोध किया था एवं इसे खतरनाक पश्चिमी नीति कहा था. नवम्बर 1950 में जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं को पीछे हटा दिया था एवं चीन को आक्रामक कहा था– इस प्रस्ताव पर भारत ने अपना मत देने से इनकार कर दिया था. उस दौरान चीन ने भारत की प्रशंसा की थी, लेकिन चीन एवं भारत के मध्य माधुर्यता स्थायी न रह सकी. साम्यवादी शासन स्थापित होने के पश्चात् चीन ने देश की सीमाओं के विस्तार का निर्णय लिया जिसके चलते अल्पसंख्यक समुदाय को आतंकित किया जाने लगा. चीन तिब्बत को अधिकार में लेने के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाने लगा, जबकि तिब्बत चीन का भाग नहीं था. भारत ने इस सन्दर्भ में चीन को सुझाव दिया कि वह तिब्बत के आध्यात्मिक एवं धार्मिक नेता से उनकी प्रभुसत्तात्मक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए बातचीत करें. चीन ने भारत के इस सुझाव की भर्त्सना की एवं इसे चीन के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप तथा भारत को 'आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवाद' का दलाल कहा. अक्टूबर 1950 में चीन ने अपनी सेना तिब्बत में भेजकर उस पर सैनिक नियन्त्रण कर लिया. इससे भारत को गहरा धक्का लगा. 26 अक्टूबर, 1950 को भारत ने इसके विरोध में एक पत्र लिखा.

"विश्व की वर्तमान घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में चीनी सेनाओं द्वारा तिब्बत पर किए गए आक्रमण को भारत सोचनीय समझता है और भारत सरकार की पक्की सम्मति में यह आक्रमण न तो चीन के हित में और न ही शान्ति के हित में है."

इस विरोध पत्र की चीन ने भर्त्सना की तथा प्रत्युत्तर में कहा कि भारत को उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है. भारत ने चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने के कारण तिब्बत आक्रमण के प्रति उदासीन नजरिया रखते हुए अत्यधिक सहनशीलता का परिचय दिया. मई 1951 में चीन ने दलाईलामा के एक प्रतिनिधि को 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया. इस समझौते के तहत तिब्बत 'चीन का एक क्षेत्र' हो गया. इस तरह तिब्बत को अवास्तविक स्वायत्तता प्रदान की गई.

सितम्बर 1952 में भारत एवं चीन के मध्य समन्वयात्मक समझौता हुआ. उसके बाद से भारतीय मिशन को ल्हासा में महावाणिज्य दूतावास का दर्जा दे दिया गया. इस तरह चीन-तिब्बत आक्रमण की बातें चीन एवं भारत द्वारा भुला दी गईं. एक-दूसरे ने आपस में समझना शुरू किया 26 जनवरी, 1951 को बीजिंग में भारतीय दूतावास में भारतीय गणतन्त्र समारोह के अवसर पर माओ ने भारत एवं चीन की मित्रता को नया आयाम प्रदान किया. 1951 ई. में जापान के साथ शान्ति सन्धि करने के उद्देश्य से अमरीका द्वारा सेनफ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें चीन को नहीं बुलाए जाने के कारण भारत ने भी अस्वीकार कर दिया. अब चीन को पूरी तरह विश्वास हो गया था कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में पूर्णतः स्वतन्त्र एवं तटस्थ है.

पंचशील सिद्धान्त एवं तिब्बत समझौता

यह भारतीय-चीनी मैत्री का परिपक्व काल था. तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई के मध्य 29 अप्रैल, 1954 को 8 वर्षीय व्यापार एवं परस्पर सम्पर्क सन्धि पर समझौता हुआ. इस समझौते में चीन एवं भारत ने पाँच सिद्धान्तों को मानने का संकल्प किया जिसे पंचशील सिद्धान्त कहा जाता है. इस समझौते से दोनों देशों के मध्य मैत्री सम्बन्धों में प्रगाढ़ता दृष्टिगत हुई. चीन ने भारत की प्रभुसत्ता एवं सीमाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का वचन दिया. भारत द्वारा तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेने से भी दोनों देशों के मध्य निकटता आई, जो विश्व समस्याओं से लेकर पश्चिम नीतियों तक के दृष्टिकोण में एकमत रही.

भारत एवं चीन के मध्य सम्बन्ध सुधारने के लिए भारतीय नेताओं द्वारा की गई चीन यात्रा

क्र. स.	चीन की यात्रा पर जाने वाले नेता/नेतृत्व दल	समय (यात्राकाल)	उल्लेखनीय वार्ताएँ/समझौते अन्य तथ्य
1.	श्री विजयलक्ष्मी पण्डित	सन् 1952 में	विजयलक्ष्मी पण्डित के नेतृत्व में भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल चीन लोक गणराज्य के आमन्त्रण पर चीनी यात्रा पर गया. इस दौरान चीन ने मैत्री सम्बन्धों में घनिष्ठता की इच्छा प्रकट की थी.
2.	पं. जवाहरलाल नेहरू (तत्कालीन प्रधानमंत्री)	18 अक्टूबर, 1954	दोनों देशों में निकटता आई थी. पंचशील पर आस्था प्रकट की गई थी. हिन्दी-चीनी भाई-भाई की गूँज प्रस्फुटित होने लगी थी.
3.	बी. डी. जत्ती उपराष्ट्रपति (तत्कालीन)	1 अक्टूबर, 1978	चीन की स्थापना की 21 वीं वर्षगाँठ पर आयोजित महोत्सव में उपस्थित हुए थे. द्विपक्षीय मैत्री एवं आपसी सहयोग पर चर्चा हुई थी.
4.	सुब्रह्मण्यम स्वामी (ससंद सदस्य)	अक्टूबर 1978	माकपा के प्रतिनिधिमण्डल एवं सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यात्रा की थी. पारस्परिक सम्बन्धों में मधुरता पर बल देने की बात कही गई.
5.	मृणालिनी साराभाई	नवम्बर 1978	मृणालिनी साराभाई के नेतृत्व में भारतीय नृत्य मण्डली चीन यात्रा पर गई. सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा सम्बन्ध सुधारने की दिशा में पहल की गई.
6.	अटल बिहारी वाजपेयी (तत्कालीन विदेशमंत्री)	12–17 फरवरी, 1979	वाजपेयी जी की यात्रा 'टोही मिशन' के नाम से ख्यात. सीमा विवाद के हल ढूँढ़ का प्रयास. चीन द्वारा वियतनाम पर आक्रमण करने के कारण यात्रा अधूरी रह गई. विशेष वार्ता न हो सकी.
7.	राजीव गांधी (तत्कालीन प्रधानमंत्री)	19–23 दिसम्बर, 1988	चीन के राष्ट्रपति यांग शान कुन प्रधानमंत्री लिंग पेंग एवं शीर्ष नेता शियाओपिंग से वार्तालाप हुई. आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि के लिए संयुक्त आयोग का गठन किया गया. उड्डयन सेवाओं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चस्तरीय सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.
8.	आर. वेंकटरमन (तत्कालीन राष्ट्रपति)	17–22 मई, 1992	चीन के राष्ट्रपति यांग शाकुन के आमन्त्रण पर चीन गए. प्रथम भारतीय राष्ट्राध्यक्ष चीन की यात्रा पर गए. हिन्दी-चीनी भाई-भाई के युग को स्मरण किया तथा दोनों राष्ट्रपतियों ने प्रतिबद्धता को दोहराया.
9.	पी. वी. नरसिंहराव (तत्कालीन प्रधानमंत्री)	सितम्बर 1993	भारत और चीन के ऐतिहासिक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. वास्तविक नियन्त्रण रेखा का पालन करने, सीमा पर सेना को कम करने, पर्यवेक्षकों द्वारा सीमा विवाद को हल करने सीमा पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने का समझौता किया गया. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नाम गया एवं चीन के स्वायत्तशासी क्षेत्र तिब्बत के जिड्वाँ से एक अतिरिक्त व्यापार मार्ग खोलने, रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों के आदान-प्रदान एवं पर्यावरण के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.
10.	के. आर. नारायणन (तत्कालीन उपराष्ट्रपति)	अक्टूबर 1994	चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जिआंग जेमिन के साथ मुलाकात हुई. सरकारी अधिकारियों को बहुप्रवेश-वीसा जारी करने पर एक समक्ष याद-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए. द्विपक्षीय व्यापार पर वार्ता की गई.
11.	एस. बी. चह्वाण (तत्कालीन गृहमन्त्री)	जुलाई 1995	दोनों देशों के अधिकारियों/नेताओं को एक दूसरे देश की यात्रा के प्रोत्साहन के लिए वार्ता. भारत एवं चीन द्वारा तेजी से आर्थिक एवं सामाजिक विकास करने एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध बनाने पर विचार-विमर्श.
12.	मन्त्रालय स्तरीय मण्डल	26 फरवरी, 1999	1997 के एक समझौते के तहत् विचार-विमर्श के लिए चीन भेजा गया. चीन ने इसे सकारात्मक एवं प्रगतिवादी दृष्टिकोण नाम दिया था.
13.	साझे कार्य समूह की बैठक	अप्रैल 1999	द्विपक्षीय मैत्री एवं आपसी सहयोग के लिए वार्ता हुई.
14.	जसवन्त सिंह (विदेश मन्त्री)	जून 1999	चीन के नेताओं से उच्चस्तरीय वार्तालाप की भारत एवं चीन के मध्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को विकसित करने का निर्णय लिया. सुरक्षा वार्तालाप के लिए सहमति की. कारगिल युद्ध पर वार्तालाप की गई.
15.	के. आर. नारायणन (राष्ट्रपति)	मई 2000	द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापार सम्बन्धों को विकसित करने की बात पर गौर किया गया. सीमा एवं अन्य मुद्दों पर वार्तालाप हुई.

16.	जॉर्ज फर्नाण्डिस	21-28 अप्रैल, 2003	दोनों देशों के मध्य विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा, भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, पारस्परिक सैन्य सहयोग पर वार्ता.
17.	अटल बिहारी वाजपेयी	22–27 जून, 2003	आसियान सिक्योरिटी फोरम में सहभागिता करना, अमरीका के कारण. विश्व व्यवस्था में उत्पन्न असन्तुलन का मूल्यांकन करना, भारत-चीन संयुक्त कार्यदल द्वारा सीमा रेखा पर सन्तुलन के प्रयास करना, चीन-पाक के हथियार व्यापार पर विचार करना, तिब्बत एवं सिक्किम को लेकर व्यावहारिक कार्यवाही करना, आर्थिक व तकनीकी रूप से आपस में सहयोग करने पर बातचीत की गई.

पंचशील के सिद्धान्त

1. *एक-दूसरे देश की सीमाओं एवं प्रभुसता की आपसी स्वीकृति.*
2. *एक-दूसरे के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करना.*
3. *एक दूसरे पर आक्रमण न करना.*
4. *समानता तथा आपसी हितों की रक्षा.*
5. *शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व.*

जून 1954 में चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ एन लाई ने भारत की यात्रा की. यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया तथा दोनों नेताओं (पं. जवाहर लाल नेहरू एवं चाऊ-एन-लाई) ने पंचशील सिद्धान्त के प्रति अपनी आस्था प्रकट की. भारतीय इतिहास में चीनी भारतीय सम्बन्ध के इस काल को 'प्रमोद काल' कहा जाता है. उस दौरान दोनों देशों में 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई की अवधारणा स्पष्टतः परिलक्षित होती थी. अक्टूबर 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने चीन की यात्रा की. अप्रैल 1955 में 'बाण्डुंग कॉन्फ्रेंस (बाण्डुंग सम्मेलन) का आयोजन हुआ, जिसमें भारत एवं चीन के प्रधानमंत्री ने आपसी मैत्री एवं सहयोग का उत्कृष्टतम परिचय दिया. भारत एवं चीन के मध्य अच्छे सम्बन्धों के चलते नवम्बर-दिसम्बर 1956 में चाऊ-एन-लाई ने भारत की दूसरी यात्रा की, जिससे दोनों देशों के मध्य अन्तर्सम्बन्धों में अत्यन्त निकटता आ गई. 1 अप्रैल, 1955 को ल्हासा प्रलेख पर हस्ताक्षर, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को प्रवेश एवं ताईवान समस्या पर समर्थन का पूर्व आश्वासन देने के भारतीय सहयोग से चीन को आशानुरूप सुखदता का एहसास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप चीन ने भारत को गोआ के मामले में सहयोग दिया तथा संगठित रूप से 'सीटो' (SEATO) का विरोध किया.

भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त

1. *गुट निरपेक्षता.*
2. *उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध.*
3. *नस्लीकृत भेदभाव के प्रति विरोध.*
4. *साधनों की शुद्धता.*
5. *पंचशील.*
6. *विश्वशान्ति के लिए समर्थन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग.*
7. *तीसरे विश्व के साथ, विशेषकर एशिया एवं अफ्रीकी देशों के साथ एकता कायम रखना.*
8. *सबके साथ विशेषकर पड़ौसी देशों के साथ मित्र भाव से रहना.*
9. *राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्वतन्त्र एवं तटस्थ विदेश नीति.*
10. *निःशस्त्रीकरण विशेषकर परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन.*
11. *शान्तिजन्य परमाणु नीति.*

भारत एवं चीन के मध्य सीमा विवाद

मैत्री सम्बन्धों में व्यवस्थित प्रक्रिया के फलस्वरूप यकायक दरार आ गई. 1954 में चीन में प्रकाशित कुछ मानचित्रों में चीन ने एक भारतीय हिस्से को चीन का हिस्सा प्रदर्शित कर रखा था. अक्टूबर 1954 में अपनी चीन यात्रा के दौरान पं. जवाहर लाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई को इस ओर ध्यान दिलाया. इसके प्रत्युत्तर में चाऊ-एन-लाई ने बताया कि ये मानचित्र कोमिन्तांग सरकार के पुराने मानचित्र हैं. पर्याप्त समय मिलने पर इनमें संशोधन कर दिया जाएगा. इन सबके बावजूद चीन ने बाराहोती (बड़ाहोती) में एक सैनिक शिविर स्थापित कर लिया. शिपकी दर्रे से 10 मील नीचे यह अवस्थित था. अप्रैल 1956 में चीन ने उत्तर प्रदेश के निलांग क्षेत्र में प्रवेश कर लिया. 6 महीने में चीन ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर शिपकी दर्रे को पार कर लिया. इसके अतिरिक्त भारत पर आरोप लगाते हुए चीन ने पत्र लिखा कि भारतीय सेना ने बूजे (बड़ाहोती) नामक स्थल पर अवैध अधिकार कर रखा है. भारत ने मात्र विरोध-स्वरूप पत्र लिखा कि "यह स्थान भारतीय प्रदेश में है और यहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा सेना की चौकी है." इसके बाद नवम्बर 1956 एवं जनवरी 1957 में चाऊ-एन-लाई भारत की यात्रा की. इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि "सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है. कुछ साधरण-सी समस्याएँ हैं जिनको मित्रतापूर्ण तरीकों से हल कर लिया जाना चाहिए," लेकिन इसी दौरान चीन ने अपनी कुटिल हरकतों को रंग देना प्रारम्भ कर दिया. ठीक उसी अन्तराल में चीन ने सिक्यांग-तिब्बत सड़क के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया. पूर्वी

लद्दाख से होकर इस सड़क को गुजरना था. इस तरह 1957 ई. तक भारत की सीमाओं पर उल्लंघन का कार्य चीन द्वारा जारी रखा गया. 1958 ई. के शरदकाल तक भारत को इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई. चीनी सेनाओं ने बाराहोती एवं अक्साई-चिन क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर लिया एवं जुलाई 1958 में चीन ने भारत के खुरनाक जिले पर अधिकार कर लिया. भारत को चीन के इस प्रकार के व्यवहार पर अत्यन्त क्षोभ हुआ एवं उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना प्रारम्भ किया. एक बार पुनः दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में कटुता आ गई. जुलाई 1958 में ही चीन के एक मासिक-पत्र 'चाइना पिक्टोरियल' में कुछ ऐसे मानचित्र प्रकाशित किए गए थे, जिनमें भारत के एक बड़े क्षेत्र को चीन का हिस्सा दर्शाया गया था. भारत सरकार ने चीन को इस ओर ध्यान दिलाया. प्रत्युत्तर में उसकी परिवर्तित मानसिकता उभर कर सामने आई. "चीन सरकार ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया है और न ही सीमा-समस्या से सम्बन्धित देशों से इस सम्बन्ध में कोई वार्ता हुई है. अतः इन नए मानचित्रों को बदलना सम्भव नहीं है."

इस प्रकार चीन ने अपने वक्तव्य के जरिए सीमास्थल को विवादस्पद घोषित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया. सितम्बर 1958 में चीनी सैनिकों ने नेफा के लोहित मण्डल में घुसपैठ प्रारम्भ कर दी. भारत सरकार को अक्टूबर 1958 में अक्साई-चिन सड़क के निर्माण एवं नेफा में घुसपैठ की जानकारी प्राप्त हुई. भारत ने विरोधस्वरूप दो पत्र चीन को लिखे. इन सबके बावजूद भी चीन की अतिक्रमण प्रक्रिया जारी रही. भारत-तिब्बत सीमा पर लैयथल एवं सांगचो-माला में चीनी सैनिकों ने बाहरी चौकियाँ स्थापित कर लीं.

अन्ततः इन घटनाओं ने दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का रूप ले लिया. चीन निरन्तर भारतीय सीमा पर अतिक्रमण करता रहा. सितम्बर 1958 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इस अतिक्रमण का पत्र द्वारा विरोध किया, जिसके उत्तर में चाऊ-एन-लाई ने 23 जनवरी, 1959 को लिखा–"भारत एवं चीन के मध्य कभी भी सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ है और तथाकथित सीमाएं चीन के विरुद्ध किए गए साम्राज्यवादी षड्यन्त्र का परिणाम मात्र है." इसी दौरान 1959 में तिब्बत समस्या एक बार फिर उभर कर सामने आई. 9 मार्च, 1959 को चीन के विरोध में ल्हासा में प्रदर्शन किया गया एवं तिब्बत की मन्त्रिपरिषद् ने तिब्बत को स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर दिया. चीन लोक गणराज्य की सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया. इन जटिल परिस्थितियों में तिब्बत के नेता दलाईलामा ने अपने समर्थकों के साथ तिब्बत छोड़कर भारत में शरण ली. भारत ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण प्रदान की. इस बात पर चीन ने भारत का विरोध किया एवं अतिक्रमण की प्रक्रिया को अनवरत रखा. 7 अगस्त, 1959 को चीन के सैनिकों की एक टुकड़ी ने खिंजमेन में प्रवेश किया तथा 25 अगस्त, 1959 को बड़ी शृंखला में चीनी सैनिकों ने नेफा के सावन मण्डल एवं लौंगजू की भारतीय सीमा चौकी पर आधिपत्य कर लिया. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू इस मुद्दे को शान्ति से सुलझाने की सोचते रहे और यह क्रमशः उलझता रहा. भारत चीन के मध्य मैत्री स्थापना का स्वप्न टूटता-सा नजर आने लगा. सन् 1960 के प्रारम्भ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई को सीमा विवाद सुलझाने की दृष्टि से भारत आमन्त्रित किया. अप्रैल 1960 में चाऊ-एन-लाई नेहरू के आमन्त्रण पर भारत आए और भारत में 6 दिन का प्रवास किया. दोनों ओर से गम्भीर होने के फलस्वरूप सीमा विवाद का कोई हल नहीं ढूँढा जा सका. नेहरू अपने वैध दावे पर स्थिर रहे और चाऊ-एन-लाई अक्साई-चीन एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चीनी दावे पर दृढ़ रहा. इस प्रकार के कठोर रुख के चलते 1960 के नेहरू एवं चाऊ एन लाई की सीमा विवाद की वार्ता का कोई सुखद परिणाम सामने नहीं आया. लम्बे अन्तराल तक चलती रही वार्ताओं के असफल रहने के बावजूद दिसम्बर 1960 में भारतीय एवं चीनी प्रतिनिधियों ने दोनों की ओर से दो विभिन्न रिपोंट्स प्रकाशित की गईं, जिससे सीमा सम्बन्धी विवाद और अधिक गहराता गया. भारत के प्रतिनिधि मण्डल ने वार्ता के दौरान 630 प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किया था जिनमें 516 प्रशासनिक तथ्यों एवं पारस्परिक सुझावों पर अनुमोदित तथा 49 वैधानिक (कानूनी) थे. चीनी प्रतिनिधि मण्डल ने वार्ता के दौरान 245 प्रमाण-पत्र पेश किए गए थे, जिनमें 47 कानूनी एवं शेष 198 पारस्परिक एवं प्रशासनिक तथ्यों पर आधारित थे. चीन ने भारतीय क्षेत्र का 12000 वर्ग मील क्षेत्र अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर लिया–यह वार्ता के दौरान उठाया गया. किसी भी तरह की वार्ताओं का चीन पर कोई असर नहीं हुआ. भारत को उसकी दुष्टप्रवृत्तियों का पूर्व अंदेशा हो गया. 1961 में लद्दाख और नेफा क्षेत्रों पर युद्ध की स्थिति नजर आने लगी. अप्रैल 1961 में सिक्किम, मई 1961 में लद्दाख के चसूल क्षेत्र में, 1 जुलाई, 1961 में नेफा के कासेग मण्डल में चीन ने आधिपत्य करना प्रारम्भ कर दिया. अगस्त 1961 में चीनी सैनिकों द्वारा लद्दाख में तीन चौकियाँ स्थापित कर ली गईं. भारत ने भी स्थिति को समझकर अपने क्षेत्रों में नई चौकियाँ स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया. चीन ने भारत की इस कार्यवाही का विरोध किया. जनवरी 1962 में चीनी सैनिकों ने नेफा के सौंगुज को पार किया एवं जून 1962 में लद्दाख क्षेत्र में चिप चाप एवं सपानगुर क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया. गम्भीर आक्रमण परिस्थितियों के चलते जुलाई 1962 में चीन ने गल्वान घाटी को चारों ओर से घेर लिया. 8 सितम्बर, 1962 को थंगला

पठार पर अतिक्रमण करते हुए नेफा के अग्रिम क्षेत्रों में आधिपत्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ते रहे. इसी दौरान चीनी सैनिकों ने मेकमोहन रेखा पार करके भारत की सीमा में प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया. अतिक्रमण के साथ-साथ गोलाबारी भी प्रारम्भ कर दी गई. 20 अक्टूबर, 1962 को सुबह चीन ने भारत पर युद्ध की शुरूआत की. चीनी सैनिकों ने इस दिन पूर्व एवं पश्चिमी क्षेत्रों में व्यापक आक्रमण किया. भारत युद्ध की मानसिकता में नहीं था. अतएव इस तरह की तैयारी भी नहीं की गई थी. इस युद्ध में नेफा में भारत की पराजय हुई. भारतीय सैनिकों ने साधन-हीनता के अभाव में भी साहस एवं धैर्य का परिचय दिया. भारत चीन के पूर्ण स्तरीय आक्रमण की सोच से चिन्तित हो गया. भारत मित्र राष्ट्रों से सहायता लेने के पक्ष में था, लेकिन 21 नवम्बर, 1962 को चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी.

भारत एवं चीन के मध्य सम्बन्ध सुधारने के लिए चीनी नेताओं द्वारा की गई भारत यात्रा

क्र. सं.	भारत की यात्रा पर आने वाला नेता/नेतृत्व दल	समय (यात्राकाल)	उल्लेखनीय वार्ताएँ/समझौते अन्य तथ्य
1.	च्यांग-काई-शेक	सन् 1942 में	भारत में चीन के जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के प्रतिसहानुभूति प्रकट की गई.
2.	चाऊ एन लाई	25 जून, 1954 में	पंचशील पर आस्था प्रकट की.
3.	चारू-एन-लाई (चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री)	28 नवम्बर-10 दिसम्बर, 1956 में	भारतीय संसद को सम्बोधित किया. भारत एवं चीन की मित्रता पर बल दिया. अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए शक्ति प्रयोग की निंदा की गई. पंचशील पर विश्वास एवं आस्था प्रकट की गई.
4.	चाऊ-एन-लाई (चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री)	अप्रैल, 1960 में	सीमा विवाद पर वार्ता के लिए 6 दिन तक भारत में प्रवास किया. नेहरू एवं चाऊ-एन-लाई दोनों अपने तथ्यों पर अड़े रहे. अन्ततः मामला निष्कर्षहीन रहा.
5.	चीनी खिलाड़ियों का दल	1975 में	कलकत्ता में आयोजित टेबिल टेनिस की प्रतियोगिता में चीनी दल ने भाग लिया. सम्बन्धों में मधुरता लाने का प्रयास किया गया.
6.	वांग-पिंग-नान	जनवरी 1978 में	वांग पिंग नान के नेतृत्व में उच्चस्तरीय चीनी प्रतिनिधिमण्डल भारत में आया. व्यापार, वाणिज्य प्रतिनिधिमण्डल भारत आया. दोनों देशों के मध्य 1 करोड़ 20 लाख का व्यापार हुआ.
7.	चीनी कृषि वैज्ञानिक दल	सितम्बर 1978	द्विपक्षीय मैत्री एवं सहयोग पर बल दिया.
8.	कुआ फेंग	जून 1981	सीमा विवाद एवं अन्य सम्बन्धों के सामान्यीकरण पर राजी. भारतीयों को मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने की अनुमति प्रदान की.
9.	फुहाओ	16 मई, 1982	फुहाओ के नेतृत्व में चीन का प्रतिनिधिमण्डल भारत-चीन सीमा विवाद पर वार्ता के लिए भारत आया. व्यापारिक पक्षों पर वार्ता हुई. एशियाई खेलों में चीनी दल ने भाग लिया
10.	चीन के वरिष्ठ अधिकारियों का दल	24 अक्टूबर-30 अक्टबर, 1983	भारतीय एवं चीन के वरिष्ठ अधिकारियों में वार्ता हुई. सीमा विवाद पर भारत के क्षेत्रवार विचार करने के प्रस्ताव को चीन ने स्वीकार कर लिया.
11.	ली फंग (चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री)	11 दिसम्बर-17 दिसम्बर, 1991	31 वर्ष बाद चीनी प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए. शंघाई एवं मुम्बई में वाणिज्य दूतावास खोलने, चीन एवं भारत के मध्य सीमा व्यापार प्रारम्भ करने एवं अन्तरिक्ष अनुसंधान विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए.
12.	जियांग जेमिन (चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति)	नवम्बर 1996	चीन के राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रथम यात्रा. दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे के विरुद्ध अपनी सैनिक क्षमता का प्रयोग न करने का वचन दिया. वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर आक्रमण नहीं करने का समझौता किया.
13.	वंग जीक्सून (चीन के विदेशमंत्री)	जुलाई 2000	भारत यात्रा के दौरान विदेशी मंत्री जसवन्त सिंह ने वार्तालाप की. सीमा विवाद के शीघ्र समाधान सीमा रेखांकन एवं शान्ति मुद्दों पर वार्तालाप हुई. एक-दूसरे के लिए उच्चस्तरीय सैनिक सहयोग एवं सेना प्रमुखों की यात्रा की वार्ता की गई.

कोलम्बो प्रस्ताव

भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद से उपजे युद्ध के कारण आई कटुता एवं सुलह के लिए एशिया एवं अफ्रीका के कुछ मित्र राष्ट्रों ने पहल की. यह सम्मेलन 10–12 दिसम्बर, 1962 में श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में आयोजित किया गया इसीलिए इसे कोलम्बो प्रस्ताव कहा जाता है. कोलम्बो प्रस्ताव में वर्मा (म्यांमार), कम्बोडिया, घाना, श्रीलंका, इण्डोनेशिया एवं संयुक्त अरव गणराज्य के प्रतिनिधि सम्मिलित थे.

कोलम्बो प्रस्ताव के सूत्र

1. *वर्तमान नियन्त्रण रेखा भारत-चीन सीमा विवाद के समाधान का आधार मानी जाए.*
2. *(अ) पश्चिमी क्षेत्र में चीन वर्तमान रेखा से 20 किमी पीछे अपनी सैनिक चौकियाँ हटा लें.*

   (ब) भारत इस क्षेत्र में अपने वर्तमान हालात को बनाए रखे.

   (स) समस्या के समाधान होने तक दोनों देश इस क्षेत्र को सेना रहित रखें एवं इस क्षेत्र का निरीक्षण असैनिक अधिकारियों द्वारा किया जाए.
3. *पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान नियन्त्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा माना जाए.*
4. *मध्य क्षेत्र में सीमा का निर्धारण शान्तिपूर्ण तरीकों से किया जाए.*
5. *इन प्रस्तावों की स्वीकृति से दोनों देश आपसी वार्ता के जरिए निर्णय ले सकते हैं.*

युद्धोत्तरकाल में आपसी सम्बन्धों में गतिरोध

चीन के आक्रमण से भारत-चीन सम्बन्धों में अचानक कटुता आ गई. भारत की साख अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो गई. भारत को नेफा में हार का सामना करना पड़ा और इससे कई अफ्रीकी एवं एशियाई राष्ट्रों के भारतीय दृष्टिकोण में अन्तर आ गया. भारत की हार से पाकिस्तान भी प्रोत्साहित हुआ और उसके मन में विचार आया कि वह भी कश्मीर का सैनिक समाधान इस स्थिति में भारत पर थोप सकता है. इस आशय से 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भारत के वहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान को करारी मात दी. पकिस्तान की सेना ने भारत के आगे समर्पण कर दिया जो विश्व का सवसे अधिक सैनिकों का समर्पण था. चीन के आक्रमण से भारत को आर्थिक नुकसान भी हुआ. भारत को मजबूर होकर सैनिक व्यय में वृद्धि करनी पड़ी. चीन के आक्रमण से भारत को एक वहुत बड़ा लाभ भारतीय सुरक्षा के प्रति सचेत रहने का हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को परिष्कृत किया. सीमा विवाद से उपजे युद्ध के पश्चात् भारत और चीन सम्बन्धों में गतिरोध आ गया. दिसम्बर 1962 से लेकर 1970-71 तक भारत एवं चीन के मध्य की सारी बातें द्विपक्षीय मैत्री, सहयोग, व्यापार, पंचशील सिद्धान्त भुला दी गईं. युद्धोत्तर काल में भारत एवं चीन में राजदूतों की नियुक्ति नहीं की गई. दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक सम्बन्ध भी प्रभारी राजदूत के स्तर तक आ गए. चीन ने भारत के प्रति दुष्टतापूर्ण रवैया एक वार फिर प्रारम्भ कर दिया. भारत को सिक्किम एवं भूटान के मामले में विस्तारवादी नीति का पोषक चीन द्वारा वताया गया. कई छोटे देशों से उसी दौरान चीन ने सीमा विवादों को सुलझाकर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया. चीन ने भारत को साम्राज्यवादी हाथों की कठपुतली एवं साम्राज्यवादियों का पिट्ठू कहना प्रारम्भ कर दिया. इन सवके अतिरिक्त हर मायने से चीन ने अपनी वेहूदगीपूर्ण हरकतों को जारी रखा. भारत के विरुद्ध कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को आर्थिक, सैनिक सहयोग एवं पूर्ण समर्थन देकर भड़काने की कोशिश की गई. पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा के सम्बन्ध में चीन ने पाकिस्तान के साथ एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए. 1965 में भारत-पाक युद्ध में चीन ने पाकिस्तान को हर सम्भव सहायता प्रदान की. जिस दौरान भारत के सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को परास्त कर रहे थे. उस समय चीन ने भारत-चीन सीमा पर भी तनाव पैदा करने की कोशिश की. पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से चीन को कराकोरम क्षेत्र में वसा दिया एवं पाक अधिकृत कश्मीर का 2600 वर्ग मील का भू-भाग चीन को सौंप दिया गया. पाकिस्तान के क्वेटा अणु संयन्त्र में चीन के परमाणु वैज्ञानिकों ने कार्य किया. चीनी सरकार ने पुनः विवाद उठाने की दृष्टि से 16 सितम्वर, 1965 को भारत को अल्टीमेटम दिया. इस तरह 1962 से उत्तरोत्तर 1970-71 तक भारत और चीन के मध्य सम्बन्धों में कटुता वरकरार रही. भारतीय इतिहास में भारत-चीन सम्वन्धों के इस काल को 'टकराव एवं तनाव का काल' कहा जाता है.

भारत एवं चीन सम्बन्धों का सामान्यीकरण

सन् 1971 भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की उत्कृष्टता की दिशा में सुखदतम सिद्ध हुआ. 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय के फलस्वरूप दक्षिण एशिया में भारत एक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया.

तृतीय विश्व में भारत एक नेता के रूप में सामने आया तथा गुट निरपेक्ष आन्दोलन से उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई. सन् 1971 में भारत-सोवितय सन्धि पर हस्ताक्षर करने से भारत एव सोवियत के मध्य मित्रता में वृद्धि हुई, जिससे चीन को बढ़ती हुई सोवियत शक्ति से डर

लगने लगा. इसके परिणामस्वरूप चीन को भारत के साथ सम्बन्ध पुनः सुधारने की आवश्यकता हुई. यद्यपि 1970 के दौरान ही सम्बन्धों में सुधार के संकेत मिलने लगे थे. बीजिंग में 'मई दिवस स्वागत समारोह' में भारतीय प्रभारी राजदूत का 'माओ-त्से-तुंग' ने स्वागत करते हुए अभिव्यक्त किया था "भारत एक महान् देश है तथा भारत और चीन बहुत पहले अच्छे मित्र थे उन्हें फिर मित्र बनना चाहिए." यह दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध सुधार की एक बहुत बड़ी पहल थी. भारतीय इतिहास में इस घटना को 'माओ मुस्कराहट' के नाम से जाना जाता है. सम्बन्ध सुधारने की दिशा में 1971 में चीन के राजदूत ने भारतीय राजदूत डी. पी. धर से मास्को में तीन बार मुलाकात कर सम्बन्धों में मधुरता लाने के प्रयासों पर बल दिया. अक्टूबर 1971 में चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह के दिल्ली में हुए आयोजन में भारतीय विदेश सचिव के नेतृत्व में भारतीय अधिकारियों ने भाग लिया. यह भारत का चीन के प्रति मैत्री भाव प्रदर्शन का सकारात्मक पहलू था. भारत सरकार ने इसी दिशा में अग्रसर होते हुए दिसम्बर 1971 में चीनी दूतावास के बाहर लगी पुलिस चौकी को हटा दिया गया. उल्लेखनीय है चीनी दूतावास के बाहर लगी इस चौकी को भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित गया था. नवम्बर 1971 में चीन ने अफ्रीकी-एशियाई मैत्री टेबिल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें भारत की टीम ने भी भाग लिया. इस तरह टूटते हुए सम्बन्धों में एक बार पुनः सामान्यीकरण की स्थिति प्रस्फुटित हुई, इसे 'पिंगपांग कूटनीति' का जन्म भी कहा जाता है.

भारत की मानसिकता इस समय भी मैत्रीभाव के पुनर्स्थापन की थी. इसे पूरी तरह समझने के लिए 15 दिसम्बर, 1972 को राज्य सभा में तत्कालीन विदेश मन्त्री स्वर्णसिंह द्वारा राज्य सभा में की गई भारत-चीन सम्बन्धों की समीक्षा को उद्धृत करना श्रेयस्कर होगा. "भारत बीती हुई बातों को बिसारने एवं चीन के साथ नए सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार है. भूगोल ने हमें इस महान् देश का पड़ोसी बनाया, हम चीन को और चीन भारत को अब और अधिक दूर नहीं रख सकता. युगों से सीमा विवाद कई देशों में रहा और इनका समाधान भी शान्तिपूर्ण ढंग से हुआ. इसलिए हमें ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि भारत और चीन इस समस्या का कोई समाधान नहीं ढूँढ़ सकेंगे." भारत की पारदर्शी मानसिकता के बावजूद भी चीन के सन्दर्भ में सम्बन्ध सुधार की स्थिति कुछ हद तक शंकास्पद ही थी. 1973 में एक बार फिर चीन ने सकारात्मक रुख का प्रदर्शन किया. 1963 से चले आ रहे भारत-चीन सीमा पर लाउड स्पीकर प्रचार युद्ध को बन्द कर दिया गया. भारत के विदेश राज्यमन्त्री सुरेन्द्रपाल सिंह ने तत्कालीन परिस्थितियों में इसे चीन के सकारात्मक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं अमरीका के भतपूर्व राजदूत गालब्रैथ ने अप्रैल 1973 में अपनी चीनी यात्रा के समय चीन के सकारात्मक रुख का अनुभव किया. 1974 में भारत ने अणु परीक्षण किया जो शान्तिपूर्ण रहा. 1975 में भारत ने सिक्किम को भारतीय गणराज्य का अंग बना लिया.

इस दौरान भारत और चीन के मध्य सम्बन्धों में स्पष्ट दृष्टिकोण सामने नहीं आ सका. चीन अणु परीक्षण एवं सिक्किम के सन्दर्भ में लगातार आलोचनात्मक वक्तव्य देता रहा. सीमा पर भी छुट-पुट घटनाएँ जारी रहीं. इन सबके फलस्वरूप दोनों देशों के सम्पर्कों का क्रम जारी रहा. मैत्री भाव प्रदर्शन का सिलसिला मात्र बातों में चलता रहा. भारत ने पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से अप्रैल 1976 में के.आर. नारायणन को पीकिंग में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया. चीन ने भारत के इस कार्य की सराहना की और लगभग पाँच महीने बाद चेन चाओ युवान (Chen–Chao–Yuan) को भारत में चीनी राजदूत नियुक्त कर दिया गया. 1976 में पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना हुई. 1976 के अन्त में व्यापारिक वृद्धि एवं सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से भारत एवं चीन सम्बन्धों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अत्यधिक बल मिला.

सन् 1977 में भारत में जनता पार्टी ने सत्ता सँभाली. जनता पार्टी की भारतीय सरकार ने गुट निरपेक्ष नीति को सच्चे अर्थों में प्रयुक्त किया. चीन ने भारत की प्रशंसा की. इसके परिणामस्वरूप 1977 से 1979 के दौरान भारत और चीन के मध्य व्यापारिक सम्पर्कों में वृद्धि हुई. अप्रैल 1977 में भारत एवं चीन ने 13.2 करोड़ रुपए मूल्य की एक व्यापार सन्धि पर हस्ताक्षर किए. इस दौरान दोनों देशों के मध्य खेल, सांस्कृतिक, इस्पात, विज्ञान एवं तकनीकी में व्यापक सहयोग किया गया. फरवरी 1978 में चीन से सोलह सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भारत की यात्रा पर आया, जिसमें व्यापार वृद्धि पर बातचीत की गई. मार्च 1978 में वांग पिन्नाग के नेतृत्व में चीनी सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल भारत आया जिन्होंने तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री के साथ 90 मिनट तक विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के सम्बन्धों में परिवर्तन आया. 1978 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री ह्वांग ह्वा तथा भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 45 मिनट तक मुलाकात की. उस दौरान वाजपेयी को चीन के विदेश मंत्री ने चीन आने का आमन्त्रण दिया. फरवरी 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की और चीनी नेताओं के साथ वार्तालाप भी की. यह यात्रा दुर्भाग्यपूर्ण रही. चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया इससे वाजपेयी ने क्षुब्धता जाहिर करते हुए यात्रा को खत्म कर भारत लौटने का निर्णय लिया.

जनवरी 1980 में भारत में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार सत्ता में आई. यह भारत एवं चीन सम्बन्धों का एक नया युग था. सीमा विवाद को लेकर इस युग में दोनों देशों के मध्य कई वार्ताओं का दौर सम्पन्न हुआ. वार्ता का पहला दौर दिसम्बर 1981 में बीजिंग में दूसरा दौर जुलाई 1982 में एवं वार्ता का तीसरा दौर जनवरी 1983 में बीजिंग में सम्पन्न हुआ. इन सभी वार्ताओं में सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया. दोनों देश अपनी जिद पर अड़े रहे. न भारत अक्साई-चिन के साथ का 5000 वर्ग किमी का क्षेत्र छोड़ने को तैयार था और न ही चीन 1959 से पहले की सीमा पर लौटने के लिए तैयार. अतएव सीमा विवाद का गतिरोध पूर्ववत् बना रहा. चीन अपनी पुरानी नीति 'एक मुश्त सौदे द्वारा सीमा विवाद को हल करने से पहले सामान्यीकरण की नीति पर पूर्ववत् अड़ा रहा. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं चीन के प्रधानमंत्री जोआ जियांग के मध्य, अक्टूबर 1985 में न्यूयार्क में वार्ता हुई, जिसमें पूर्वी क्षेत्र की सीमा की समीक्षा की. इस वार्ता में कृषि, शिक्षा, कम्प्यूटर, उद्योग, भौतिकी, बायो तकनीकी प्लाज्मा क्षेत्रों के शिष्टमण्डलों ने आदान-प्रदान का समझौता किया गया.

1986 में सम्बन्धों में पुनः दरार आ गई. मेकमोहन रेखा के दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश के कमांग मण्डल के चियांग ड्रेग क्षेत्र पर जून 1986 में चीन ने घुसपैठ करना प्रारम्भ कर दिया. 21-22 जुलाई , 1986 को बीजिंग में सम्पन्न हुई सातवें दौर की वार्ता में भारत ने इसे उठाया. चीन ने इस सन्दर्भ में कहा कि ये क्षेत्र वास्तविक नियन्त्रक रेखा के उत्तर में है और उसकी सीमा के अन्तर्गत आता है. इतना ही नहीं चीन ने सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश (नेफा) पर अपना दावा कर दिया. इस तरह 1986 में भारत और चीन के मध्य सम्बन्धों में कटुता बनी रही. 1986 में भारत और चीन के मध्य 140 मिलियन डॉलर का व्यापार किया गया. 27 मई, 1987 को भारत एवं चीन के मध्य एक व्यापार समझौता हुआ, जिसमें जनवरी 1987 से मार्च 1988 तक 150–200 मिलियन डॉलर के व्यापार में वृद्धि का दोनों देशों का लक्ष्य था. इस समझौते के तहत भारत से कच्चा लोहा चीन को भेजा जाना था. सीमा विवाद पर स्थिति पूर्ववत् बनी रही. दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में सुधार दृष्टिगोचर दिसम्बर 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद हुआ. इस यात्रा में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों पर जोर दिया गया. इसके अतिरिक्त एक संयुक्त कार्य प्रचालन समूह (Joint Working Group) के निर्माण की योजना बनाई गई जिसमें भारत के विदेश सचिव सभापति होंगे एवं चीन के विदेशी मामलों के उपमन्त्री उसमें शामिल होंगे. चीन और भारत ने व्यापार, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अन्य गतिविधियों का सकारात्मक मूल्यांकन किया गया. समझौते के तहत 6 से 8 जुलाई, 1989 को संयुक्त कार्य प्रचालन समूह की बैठक हुई, जिसमें तीन दौरों में वार्ता हुई. इस वार्ता में जटिल सीमा समस्या पर विचार-विमर्श किया गया. इसमें भारतीय विदेश सचिव एस. के. सिंह ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया था. संयुक्त कार्य संचालन दल के गठन एवं प्रथम बैठक से सीमा समस्या पर चल रहे गतिरोध की समाप्ति हो गई. सितम्बर 1989 में दोनों देशों के मध्य एक व्यापारिक समझौता पुनः हुआ. मार्च 1990 में चीन के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की, जिसमें उसने कश्मीर मसले पर यथार्थवादी बयान दिया. संयुक्त कार्य संचालन दल (JWG) की दूसरी बैठक दिल्ली में अगस्त 1990 में सम्पन्न हुई, जिसमें दोनों देशों ने विस्तृत रूप से सीमा विवाद पर वार्तालाप की. इस बैठक में अगली बैठक चीन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया. संयुक्त कार्य संचालन दल की दूसरी बैठक में भी सीमा विवाद का मुद्दा पूर्ववत् रहा.

1992 में चीन के प्रधानमंत्री ली. पेंग भारत आए पहले की तरह औपचारिकताएँ पूरी की गईं. वार्ताएँ हुईं, लेकिन मुद्दा निष्कर्षहीन रहा. 1992 में आपसी यात्राओं का दौर चलता रहा. जून 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन ने एवं रक्षामंत्री शरद पवार ने बीजिंग की यात्रा की. इस दौरान दोनों देशों के सम्बन्धों में सामान्यीकरण के प्रयास किए गए. फरवरी 1992 में ही बम्बई एवं शंघाई में महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने का निर्णय लिया गया. सन् 1993 में 25-26 जून को संयुक्त संचालन समूह दल की छठी बैठक का आयोजन किया गया. जिस पर सीमा विवाद में आपसी विश्वास में वृद्धि की गई. 1993 में चीन में भारत उत्सव का आयोजन किया जो दोनों देशों के मध्य एक अत्यन्त सुखद परिस्थिति का प्रतीक था. अक्टूबर 1994 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने सात दिन की चीन यात्रा की. यहाँ पर उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिआंग-जेमिन के साथ मुलाकात की. इस दौरान सरकारी अधिकारियों को बहु प्रवेश बीसा जारी करने के लिए समझ याद-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए. जुलाई 1995 में भारत के तत्कालीन गृहमन्त्री एस. बी. चह्वाण ने चीन की यात्रा की. अपनी यात्रा में दोनों देशों ने आपसी यात्रा को प्रोत्साहन के लिए अत्यावश्यक माना गया. अगस्त 1995 में संयुक्त कार्य समूह (JWG) की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर से दो भारतीय एवं दो चीनी सैनिक चौकियाँ हटाने, अरुणाचल प्रदेश के चार क्षेत्रों से अपने-अपने सैनिक पीछे हटाने का निर्णय लिया गया. इस तरह 1996 तक दोनों देशों के सम्बन्धों में सामान्यीकरण की परिस्थितियाँ विद्यमान रहीं.

चीन के साम्यवादी दल के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता एवं चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने नवम्बर 1996 में तीन दिन की भारत यात्रा की. यह चीन के राष्ट्रपति द्वारा की गई

पहली यात्रा थी. इस यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता किया गया, जिसके अन्तर्गत वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर एक-दूसरे द्वारा आक्रमण नहीं करने का वचन दिया. दोनों देशों ने अपने सैनिक बल का प्रयोग नहीं करने का एवं हिमालय की झगड़े वाली सीमा पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने का समझौता किया गया था. इस यात्रा के समय 11 सूत्रीय समझौता किया गया था. अक्टूबर 1997 में भारत और चीन के मध्य तेल एवं गैस को प्राप्त करने की भागीदारी के लिए एक समझौता किया गया था. सन् 1998 में दोनों देशों के मध्य पुनः तनाव पैदा हो गया. भारत ने 11 से 13 मई, 1998 के मध्य पाँच परमाणु परीक्षण कर अपने आपको परमाणु शस्त्र धारक देश घोषित किया था. इसी दौरान भारत के रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नाण्डीस ने चीन को भारत का शत्रु न. वन की संज्ञा दे डाली थी, जिससे चीन की मानसिकता यकायक द्विपक्षीय मैत्री की ओर विकृत हो उठी. चीन ने अमरीका एवं अन्य देशों के साथ मिलकर NPT एवं CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर बाध्यता प्रकट करना प्रारम्भ कर दिया. 5 जून, 1998 को चीन के द्वारा दबाव बनाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा परीक्षण वन्द करने, शस्त्र विकास कार्यक्रम बन्द करने एवं NPT, CTBT पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव पास कराया गया.

भारत-चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक उपलब्धि रही सिक्किम में नाथू ला के रास्ते व्यापार पर चीन की सहमति

जुलाई 1998 में एशियान रीजनल फोरम (ASEAN Regional Forum–ARF) की बैठक में जसवन्त सिंह एवं चीन के विदेश मन्त्री तांग जियाशां के मध्य वार्ता हुईं. दोनों ने उच्च सरकारी विचार-विमर्श को जारी रखने का निर्णय लिया. अक्टूबर 1998 में चीन ने वाजपेयी की दलाईलामा के साथ मुलाकात की आलोचना की और इसे चीन के विरुद्ध तिब्बत कार्ड का प्रयोग कहा. 26 फरवरी, 1999 को भारत ने सम्बन्धों में मिठास लाने की पहल करते हुए एक मन्त्रालय स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल वार्षिक विचार-विमर्श के लिए चीन भेजा. चीन के रुख को भारतीय मन्त्रालय मण्डल ने अपने हित में नहीं पाया. चीन ने अवश्य इसे सकारात्मक एवं प्रगतिवादी दृष्टिकोण नाम दिया. अप्रैल 1999 में साझे कार्य समूह (JWG) की बीजिंग में 11वीं बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों में विकास के नए पहलुओं पर बातचीत हुई. एक बार पुनः दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में सुधार के आसार आशातीत प्रतीत होने लगे. जून 1999 में भारतीय विदेशमंत्री जसवन्त सिंह ने चीन की यात्रा कर वहाँ के नेताओं से उच्चस्तरीय वार्तालाप की. दोनों देशों के मध्य परस्पर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने की दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया गया. भारत चीन के व्यापार को 2 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ाने एवं साझे कार्य समूह की गतिविधियों में वृद्धि के लिए भी निर्णय लिया गया. चीन ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को दोषी ठहराया. फरवरी 2000 में भारत ने चीन को WTO सदस्यता प्राप्त करने के लिए समर्थन दिया था. मार्च 2000 में भारत एवं चीन के मध्य बीजिंग में सुरक्षा वार्तालाप का पहला दौर प्रारम्भ हुआ जो सचिव स्तरीय था. सुरक्षा वार्तालाप दो दिनों तक चला. इस कार्यक्रम में चीन ने भारत को CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया. मई 2000 में भारत के राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने चीन की यात्रा कर दोनों देशों के सभी हितकर मुद्दों पर वार्तालाप की. भारत एवं चीन ने द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापार सम्बन्धों में वृद्धि करने के लिए प्रयास करने की प्रतिबद्धता प्रकट की, लेकिन सीमा विवाद पर कोई निष्कर्षजन्य बात नहीं हो पाई.

भारत-चीन सम्बन्धों में हिन्दी-चीनी भाई-भाई की चली आ रही पुरानी कावत को नये सिरे से सम्बल प्रदान करने की दिशा में सन् 2003 में भारत के प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री की यात्रा से दोनों देशों के नागरिकों की उम्मीदों को फिर से बल मिलने लगा है.

भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की चीन यात्रा एक सुखद आश्चर्य सिद्ध हुई है. इस यात्रा के परिणाम इतने उत्साहवर्द्धक रहे हैं कि यह यात्रा भारत-चीन सम्बन्ध के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है. जैसाकि सर्वविदित है. भारत-चीन सम्बन्धों में उतार-चढ़ाव रहा है. 1950 के दशक में हिन्दी चीनी भाई-भाई के नारे आकाश में गूँज रहे थे तथा भारत और चीन की मित्रता इसकी मिसाल थी कि दो पड़ोसी राज्यों को किस प्रकार दोस्त बन कर रहना चाहिए. 1950 के दशक का अन्त तथा 1960 के दशक का आरम्भ दोस्ती के स्थान पर दुश्मनी के साथ हुई. हिन्दी चीनी भाई-भाई के स्थान पर आकाश में तोपों की गड़गड़ाहट गूँज उठी. सीमा विवाद ने खुले युद्ध का रूप धारण कर लिया दोस्त-दोस्त न रहे. दुश्मनी तथा उससे पैदा हुई दूरी का दौर देर तक चला.

एक लम्बे अरसे के बाद ही दोनों सरकारों को यह सद्‌बुद्धि आ सकी कि उन्हें अपने विवादों का समाधान वार्ता के द्वारा करना चाहिए. राजीव गांधी तथा नरसिम्हाराव के प्रधान मंत्रित्वकाल में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई. ऐसा प्रतीत होता है कि भारत-चीन सम्बन्धों की गाड़ी पटरी पर आ रही है.

उचित ठहराने के लिए अमरीका की सरकार को लिखे गए पत्र में वाजपेयी ने चीन की तरफ से उत्पन्न खतरे को विस्फोट के लिए उत्तरदायी बताया. इस चीन विरोधी मुहिम ने भारत-चीन सम्बन्धों को पुनः कोल्ड स्टोरेज में पहुँचा दिया. सम्बन्धों की यह पृष्ठभूमि नई शुरूआत को अलग ही महत्व प्रदान करती है.

भारत चीन सीमा विवाद पर एक नजर

सीमा विवाद सुलझान के लिए नई व्यवस्था के तहत् भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा तथा चीन की ओर से विदेश विभाग में वरिष्ठ उपमंत्री दे विनजुओ को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि सीमा विवाद सहित दोनों देशों के बीच लम्बित विवादों का शीघ्र ही निपटारा हो सके.

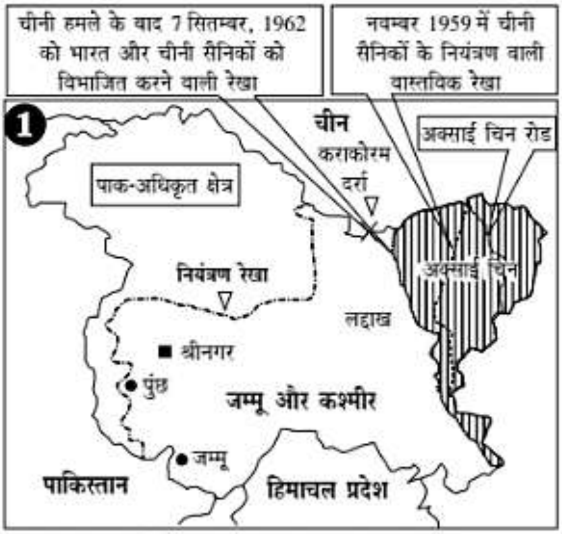

1 1962 से चीन के कब्जे में लद्दाख के अक्साई चिन का 38,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र.

कराकोरम दर्रे के पश्चिम में 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दिया हुआ है.

2 7 सितम्बर, 1962 को भारत और चीनी सैनिकों को विभाजित करने वाली मेकमोहन लाइन.

- इतने बड़े भू-भाग पर कब्जे के अतिरिक्त अरुणाचल के 90,000 वर्ग किमी और बाराहोती के 40 वर्ग किमी क्षेत्र पर भी चीन अपना दावा करता है. वर्तमान में बाराहोती का क्षेत्र विसैन्यीकृत क्षेत्र के रूप में माना जाता है.
- नीचे के मानचित्र में पूर्वी क्षेत्र 7 सितम्बर, 1962 को भारत और चीनी सैनिकों को विभाजित करने वाली रेखा दिखाई गई है. इस क्षेत्र में यही वास्तविक और पारम्परिक रेखा थी, जो 1914 के शिमला समझौते के अनुसार तय की गई और यही मेकमोहन लाइन के रूप में जानी जाती थी. इसके बाद भी इस क्षेत्र में चीन ने एक और लाइन तक अपना दावा जताया.

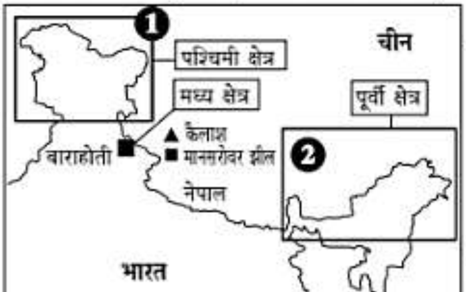

किन्तु वाजपेई की वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के आरम्भ के दिनों में सम्बन्धों के सुधार की इस प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया. वाजपेई सरकार में तथा भारतीय जनता पार्टी में एक सशक्त चीन विरोधी लॉबी रही है जिसकी कमान एक तरह से, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के संयोजक तथा भारत सरकार में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नान्डीज के हाथ में रही. इस लॉबी ने चीन की ओर से भारत के लिए खतरे का हौवा खड़ा किया. चीन पर भारत को निशाना बनाकर मिसाइलें तैनात करने तथा भारत की सैनिक घेराबन्दी करने का आरोप लगाया गया. यहाँ तक कि पोखरण द्वितीय के विस्फोट को

यह उल्लेखनीय है कि भारत-चीन सम्बन्धों में नए युग की सूत्रपात करने वाली यात्रा के लिए जमीन तैयार करने का काम रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नान्डीज की चीन यात्रा तथा वाजपेई की पश्चिम यात्रा ने की. चीन विरोधी फर्नान्डीज की यात्रा भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार का आधार बने इसे प्रकृति का व्यंग्य ही कहा जा सकता है. अप्रैल 2003 की अपनी चीन यात्रा के दौरान फर्नान्डीज ने चीन के प्रधानमंत्री देन जियाबाओ तथा चीन के केन्द्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख जियांग झेमिन के साथ वार्ता की. 21–28 अप्रैल की इस

चीन यात्रा ने चीन के सम्बन्धों में फर्नान्डीज के विचारों को परिवर्तित करने का काम किया. उन्हें यह विश्वास हो गया कि चीन की जनता भारत को प्यार करती है तथा चीन की सरकार वास्तव में भारत के साथ घनिष्ठ मैत्री स्थापित करने तथा इसके मार्ग के सभी अवरोधों को दूर करने के लिए उत्सुक है.

इसके बाद ही अपनी यूरोप यात्रा के दौरान वाजपेई ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग नगर में चीन के राष्ट्रपति हु जिन्ताओ से मुलाकात की. यह दो शीर्ष नेताओं के मध्य प्रथम मुलाकात थी. इस मुलाकात में दोनों ही पक्षों ने एशिया के इन दो प्रमुख देशों के मध्य मित्रता व सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया. वाजपेई ने कहा कि **भारत चीन मित्रता 21वीं सदी को एशियाई सदी में बदल सकती है.** चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कोंग कुआन के अनुसार दोनों नेताओं की वार्ता बहुत ही सफल रही तथा पारस्परिक सम्वन्धों को घनिष्ठ बनाने के लिए मिलकर प्रयास करने का निर्णय उनके द्वारा लिया गया. इस मुलाकात की सफलता ने ही वाजपेई को प्रेरित किया कि वह चीन यात्रा के लिए वर्ष के अन्त तक प्रतीक्षा न करके पहले ही उसे कर लें.

वाजपेई की यह पाँच दिवसीय यात्रा 22 जून से 27 जून तक चली. इस यात्रा के दौरान 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए तथा 23 जून को चीन तथा भारत के मध्य व्यापक सहयोग एवं सम्बन्धों पर सिद्धान्त की घोषणा जारी की गई.

इस घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु था तिब्बत के प्रश्न पर भारत द्वारा चीन की स्थिति को स्वीकार कर लेना. घोषणा में कहा गया **"भारतीय पक्ष यह स्वीकार करता है कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र पीपुल्स रिपब्लिक ऑव चाइना का अभिन्न अंग है तथा पुनः दोहराता है कि वह तिब्बतियों को चीन विरोधी कार्यवाहियाँ चलाने की अनुमति नहीं देगा."** चीन ने भारत के इस रुख की घोषणा की सराहना करते हुए यह स्पष्ट किया कि वह तिब्बत को चीन से अलग तथा स्वतंत्र करने की कोशिशों का दृढ़ता से विरोध करेगा. घोषणा में यह भी कहा गया कि भारत उन देशों में से है जिन्होंने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि केवल एक चीन है. अब भी भारत अपनी इस नीति पर कायम है. **दूसरे शब्दों में भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार कर लिया कि ताईवान भी चीन का अभिन्न अंग है.**

तिब्बत तथा ताईवान पर चीन की स्थिति को स्वीकार कर भारत सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाया है. यह तिब्बत का प्रश्न था जिसने भारत तथा चीन के रिश्तों में कटुता के बीज बोए थे. भारत में दलाई लामा की मौजूदगी तथा तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली सक्रिय भारतीय लॉबी हमेशा चीन को खटकती रही. भारत की नई घोषणा इस बिन्दु पर चीन को आश्वस्त कर उसे विवाद के अन्य मुद्दों पर उदार एवं समझौतापूर्ण रुख अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है.

भारत की घोषणा ने चीन को आश्वस्त भले ही किया हो, किन्तु इसकी भारत के तिब्बत समर्थक खेमे में तीखी प्रतिक्रिया हुई है. इस खेमे के अनुसार तिब्बत के प्रश्न पर भारत ने चीन के समक्ष समर्पण कर दिया तथा तिब्बत की स्वतंत्रता वाली जनता को धोखा दिया है. यह खेमा याद दिलाता है कि यही **अटल बिहारी वाजपेई हैं जिन्होंने 1959 में दलाई लामा के स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देने की पुरजोर वकालात की थी.** डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का 24 अक्टूबर, 1962 को एक सभा में कहा **"तिब्बत को चीन की लौह गिरफ्त से मुक्त कराना होगा."** स्वाभाविक रूप से भारत में रह रहे लाखों तिब्बती शरणार्थियों ने घोषणा का स्वागत दुःख, क्षोभ, क्रोध एवं अवसाद के साथ किया.

भारतीय खेमे को यह आशा थी कि एक हाथ ले दूसरे हाथ से दे के सिद्धान्त के अनुसार चीन भी तिब्बत के बदले सिक्किम पर भारत के पक्ष को मान्यता देगा. यह आशा पूर्णरूप से फलीभूत नहीं हुई तथा चीन ने सिक्किम के भारतीय गणतंत्र का एक राज्य होने की कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से भारत की स्थिति को मान्यता मिली तथा उसका पक्ष मजबूत हुआ. सीमा पर व्यापार में वृद्धि के लिए नए द्वार खोलने के फैसले के अन्तर्गत चीन ने तिब्बत के रे-किंगगांग को तथा भारत ने सिक्किम के चांग्गू को इसके लिए चुना. विशेषज्ञों के अनुसार इसे स्वीकार करके दोनों ने क्रमशः तिब्बत तथा सिक्किम पर एक-दूसरे की सम्प्रभुता को भी मान्यता प्रदान की. जहाँ भारत यह मानता है कि सिक्किम पर चीन ने उसके दावे को स्वीकार कर लिया, वहीं चीन का कहना है कि सिक्किम पर उसका रुख अब भी पहले का है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है.

23 जून की घोषणा में भारत तथा चीन के मध्य जिन सिद्धान्तों पर सहमति हुई वह निम्नलिखित थे–

(i) भारत तथा चीन की सरकार पंचशील, समानता तथा पारिस्परिक सम्मान के सिद्धान्त के आधार पर एक-दूसरे के साथ दीर्घकालिक सहयोग पर आधारित भागीदारी को विकसित करेंगे.

(ii) एशिया तथा विश्व में शान्ति, स्थायित्व तथा सम्पन्नता को बनाए रखना तथा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में घनिष्ठ पारस्परिक सहयोग दोनों ही देशों के हित में है तथा वह इस दिशा में कार्य करेंगे.

(iii) दोनों देशों के साझा हित उनके मध्य पाए जाने वाले मतभेदों से कहीं अधिक वजनी तथा महत्वपूर्ण हैं. भारत तथा चीन को एक-दूसरे से कोई खतरा नहीं है. दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे के विरुद्ध न तो शक्ति का प्रयोग करेगा और न ही प्रयोग करने की धमकी देगा.

(iv) भारत तथा चीन सभी स्तर पर तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बन्धों में गुणात्मक सुधार करने के लिए कदम उठाएंगे तथा आपसी मतभेदों को शान्तिपूर्वक तार्किक एवं निष्पक्ष रूप से हल करने के लिए कदम उठाएंगे.

वर्तमान में सीमा विवाद भारत तथा चीन के मध्य मतभेद का प्रमुख एवं संवेदनशील मुद्दा है. इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए कोई जल्दबाजी भारत तथा चीन के नेताओं ने नहीं दिखाई. दोनों पक्षों का सोच शायद यह रहा है कि बजाए इसके कि वह सीमा-विवाद पर बहस में उलझ जाएं तथा उसका नकारात्मक असर दूसरे क्षेत्रों में बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने की प्रक्रिया पर पड़े उससे अच्छा यह होगा कि अन्य क्षेत्रों में सम्बन्धों में गुणात्मक सुधार करते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ सीमा विवाद पर विचार किया जाए. यही सोच था जिसके तहत वाजपेई ने प्रस्तावित किया कि सीमा विवाद पर व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विचार करने के लिए दोनों सरकारें विशेष प्रतिनिधियों को नियुक्त करें. चीन ने इस प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार कर लिया. **सीमा विवाद के सन्दर्भ में विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति एक ठोस कदम कहा जा सकता है.** भारत ने विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र को विशिष्ट प्रतिनिधि नियुक्त किया तथा चीन ने विदेश विभाग में वरिष्ठतम् डिप्टी मिनिस्टर दाई बिंगगुओ (Dai Bingguo) को नियुक्त किया. विशेष प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के साथ ही दोनों पक्षों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि वास्तविक अधिकार रेखा (Line of Actual Control) पर जो समझौते अभी तक हुए हैं. उनका पूर्णनिष्ठा के साथ पालन किया जाए. इस संदर्भ में नियुक्त किए गए संयुक्त आयोग अपने कार्य को पहले की तरह बेरोक टोक करते रहेंगे. दोनों पक्षों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि अब तक सीमा विवाद का अन्तिम रूप से समाधान नहीं हो जाता है दोनों पक्ष सीमा क्षेत्र में शान्ति बनाए रखेंगे.

वाजपेई की चीन यात्रा ने भारत तथा चीन के मध्य आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों को और घनिष्ठ बनाने में भी भूमिका अदा की है. भारत तथा चीन के मध्य व्यापार के विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा भारत का यह भय रहा है कि चीन अपने माल से भारत के बाजार को पाट देगा तथा उसका भारत के उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. अब भारत अपने इस भय पर काबू पा चुका है. प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हुए समझौते के अनुसार दोनों देशों ने अगले दो वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 10 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है. दोनों पक्षों में यह भी सहमति हुई कि विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में दोनों के हितों से जुड़े मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे. भारत चीन के मध्य बढ़ता आर्थिक सहयोग दोनों देशों की आर्थिक प्रगति में सहायक सिद्ध होगा.

भारत चीन की बढ़ती हुई मित्रता का विश्व राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा. आज विश्व समुदाय एक ध्रुवीय जगत् में संयुक्त राज्य अमरीका की दादागिरी से चिन्तित है. ऐसी स्थिति में भारत-चीन की मित्रता अमरीकी वर्चस्व के लिए चुनौती बन कर उभर सकती है तथा एक ध्रुवीय विश्व को बहुध्रुवीय विश्व में बदलने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है. यह मित्रता चीन, भारत तथा अमरीका के पारस्परिक रिश्तों पर भी अलग-अलग ढंग से असर डाल सकती है. वाजपेई सरकार के पद ग्रहण करने के समय से ही चीन को यह चिन्ता सता रही थी कि अमरीका भारत को उसके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है. वाजपेई सरकार की अमरीकी परस्त नीति ने इस चिन्ता को बढ़ाने का ही काम किया. अब चीन को यह भय नहीं रहा. दूसरी ओर भारत को यह शिकायत रही कि अमरीका उसकी सारी कोशिश एवं तरफदारी के बावजूद उसकी जायज शिकायतों पर भी ध्यान नहीं देता है. अब चीन के साथ अपनी बढ़ती दोस्ती को अमरीका के ऊपर दबाव डालने के लिए ठीक उसी प्रकार प्रयोग में ला सकेगा जिस प्रकार पहले समाजवादी रूस तथा अन्य समाजवादी देशों के साथ अपनी मित्रता को लाता था. चीन के साथ सम्बन्धों का सुधार एक अन्य दृष्टि से भी भारत के लिए सुकून का विषय हो जाता है. चीन और पाकिस्तान के घनिष्ठ सम्बन्ध जगजाहिर हैं. पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति में भारत की एक बड़ी चिन्ता 'चाइना फैक्टर (China Factor) को लेकर रहती थी. प्रगाढ़ होती भारत चीन मैत्री यह सुनिश्चित करेगी कि अपने दो मित्रों के मध्य झगड़ा होने की स्थिति में चीन या तो तटस्थ रहे या ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका अदा करे. वह पाकिस्तान के पक्षधर के रूप में सामने ना आए.

भारत चीन मित्रता केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही आर्थिक क्षेत्र में भी अमरीकी वर्चस्व को समाप्त करके बहुध्रुवीयता को स्थापित करने में मददगार सिद्ध होगी. विश्व के दो सबसे बड़े बाजारों तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं की संयुक्त आवाज को दबाना विश्व व्यापार संगठन को नियंत्रित करने वाले बड़े पूँजीवादी देशों के लिए सम्भव नहीं रहेगा.

भारत एवं चीन के मध्य अर्सों से चली आ रही द्विपक्षीय मैत्री की आकांक्षा कई अस्थिर दौरों से गुजरती रही है. दोनों राष्ट्रों में जिद की भावना के फलस्वरूप सीमा विवाद प्रारम्भ से लेकर आज तक बना हुआ है. चीन वास्तविक स्थिति को समझकर क्षणिक समझौतावादी नीति से इस विवाद को सुलझा सकता है, लेकिन अभी आगे भी सीमा पर कोई सशक्त निर्णय समझौता हो पाएगा शंकास्पद ही है.

स्मरणीय तथ्य

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब इंग्लैण्ड में आम चुनाव हुए तो वहाँ 'लेबर पार्टी' बहुमत में आई.
- भारत में सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिशन मार्च, 1946 ई. में भारत भेजा गया.
- भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए 1946 ई. में निर्वाचन कराया गया.
- संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसम्बर, 1946 ई. को किया गया.
- इस बैठक की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की.
- संविधान का प्रारूप 21 फरवरी, 1948 ई. को तय किया गया.
- भारतीय संविधान में न केवल केन्द्रीय, बल्कि प्रांतीय सरकार के ढाँचे और शक्तियों का भी वर्णन है. इसके साथ ही इसमें हरिजनों, पिछड़ी जातियों और कबीलों के लिए विशेष व्यवस्था है, इस वजह से भारतीय संविधान अन्य राष्ट्रों के संविधान से अधिक लम्बा है.
- भारत के अलावा सिर्फ आयरलैंड के संविधान में ही राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है.
- भारतीय संविधान को 1935 ई. के एक्ट के अनुसार ढाले जाने के कारण भी इसका अत्यधिक विस्तार हो गया है.
- भारतीय संविधान का उद्देश्य है–धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना, सबको न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करना तथा बंधुत्व की भावना का विकास करना.
- भारतीय संविधान ब्रिटेन के संविधान की तरह न तो अत्यंत लचीला है और न ही अमरीका के संविधान की तरह कठोर.
- भारतीय गणराज्य स्वयंप्रभु है. इस पर किसी विदेशी सत्ता का प्रभाव नहीं है.
- अगर मंत्रिपरिषद् जनता की आशा के अनुसार कार्य न करे तो उसे यह अधिकार है कि वह चुनावों के माध्यम से सरकार को बदल दे.
- भारतीय संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों ही शक्तियाँ मौजूद हैं.
- भारतीय संविधान में इंदिरा गांधी के प्रयासों से भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों को संविधान में समाहित किया गया.
- नीति-निर्देशक तत्त्वों की चर्चा संविधान के चौथे भाग में की गई है.
- नीति-निर्देशक तत्त्व ऐसे चैक के समान है, जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर आधारित है.
- नेहरू के अनुसार समाजवादी व्यवस्था शोषण का प्रतिकार प्रस्तुत करती है.
- नेहरू का मानना था कि समाजवाद में प्राप्त भौतिक सम्पन्नता व्यक्तिगत अभिव्यक्ति एवं स्वतन्त्रता का विलोम नहीं है.
- नेहरू के मन एवं मस्तिष्क पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव 1926-27 ई. की रूस यात्रा के समय दृढ़ हो गया था.
- हालांकि जवाहरलाल नेहरू पर समाजवाद की गहरी छाप थी, परन्तु उनका मन रूस एवं चीन की मान्यताओं को अक्षरशः मानने के लिए तैयार नहीं था.
- नेहरूजी ने राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थन करते हुए भारत में प्रतिरक्षा तथा कुछ अन्य प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया था.
- नेहरू ने जहाँ समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति पर बल दिया, वहीं उसे औद्योगीकरण के लिए भी आवश्यक बताया.
- वर्तमान में भारत विश्व के सभी गुटनिरपेक्ष देशों की 'आशा' के नाम से जाना जाता है.
- गुटनिरपेक्षता का अर्थ है, "अपनी स्वतन्त्र रीति-नीति."
- भारत की विदेश नीति का निर्धारण भारत की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में किया गया था.
- सन् 1949 ई. में कोमिंतांग सरकार के पतन के बाद चीन साम्यवादी देश के रूप में उभरकर सामने आया.
- गैर-साम्यवादी देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था. जिसने चीन को राजनैतिक मान्यता दी तथा द्विपक्षीय मैत्री का प्रस्ताव भी रखा.
- मई 1951 में चीन ने दलाईलामा के एक प्रतिनिधि को 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया.
- 29 अप्रैल, 1954 को भारत तथा चीन के मध्य 8 वर्षीय व्यापार एवं परस्पर संधि पर समझौता हुआ.
- 20 अक्टूबर, 1962 को सुबह चीन ने भारत पर युद्ध की शुरूआत की.
- 1993 में चीन में भारत उत्सव का आयोजन किया गया.

विशिष्ट स्मरणीय तथ्य

- भारत की आजादी के बाद जो संविधान बना उसमें 395 धाराएँ और 8 अनुसूचियाँ थीं. धाराएँ 22 भागों में विभक्त थीं.
- भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया.
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमरीकी संविधान से मिलती-जुलती है.
- संविधान के तीसरे भाग में 12 से 35 तक की धाराओं में नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या की गई है.
- भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, कनाडा की तरह शक्तिशाली केन्द्र, आस्ट्रेलिया के संविधान की तरह समवर्ती सूची तथा आयरिश के संविधान की तरह नीति-निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है.
- प्रसिद्ध विद्वान् एम. वी. पायली ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है "भारतीय संविधान कार्य करने लायक एक दस्तावेज है, तथा यह आदर्शों एवं वास्तविकताओं का मिश्रण है."
- नेहरूजी सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को पूर्णतः समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, वे चाहते थे कि सम्पत्ति अधिकार सहकारिता के आधार पर हो.
- सन् 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव नेहरू के प्रभाव से ही पारित हो पाया था.
- इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कार्य नेहरूजी के ही प्रयासों का प्रतिफल था.
- समाजवाद के बारे में नेहरूजी का कहना था– सर्वाधिकारवादी राज्य के अन्तर्गत समाजवाद की स्थापना त्वरित गति से होती है तथा लोकतांत्रिक पद्धति से समाजवाद की स्थापना धीरे-धीरे होती है.
- गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या 1961 में 25, 1973 में 76 और 1976 में 85 थी.
- विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ रहकर या अलग रहते हुए स्वतन्त्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन देना ही गुटनिरपेक्षता की परिभाषा है.
- सन् 2001 का शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ.
- भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धान्त है. पंचशील सिद्धान्त का अनुसरण.
- अक्टूबर 1950 में चीन ने अपनी सेना भेजकर तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया.
- 1952 में भारत एवं चीन के मध्य समन्वयात्मक समझौता हुआ. उसके बाद से भारतीय मिशन को ल्हासा में वाणिज्य दूतावास का दर्जा दे दिया गया.
- जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई के मध्य 29 अप्रैल, 1954 को 8 वर्षीय व्यापार एवं परस्पर सम्पर्क सन्धि पर समझौता हुआ. इस समझौते के तहत चीन एवं भारत ने पाँच सिद्धान्तों को मानने का संकल्प किया, जिसे पंचशील का सिद्धान्त कहा जाता है.
- चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई ने जून 1954 में भारत की प्रथम यात्रा की.
- चाऊ-एन-लाई ने नवम्बर-दिसम्बर 1956 में दूसरी बार भारत की यात्रा की.
- चीन ने अपने मासिक पत्र "चाइना पिक्टोरिअल" में कुछ ऐसे मानचित्र प्रकाशित किए, जिनमें भारत के एक बड़े क्षेत्र को चीन का हिस्सा दर्शाया गया था.
- 9 मार्च, 1959 को चीन के विरुद्ध प्रदर्शन किया तथा तिब्बत की मंत्रिपरिषद् ने तिब्बत को स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर दिया.
- सीमा विवाद सुलझाने की दृष्टि से नेहरू ने चाऊ-एन-लाई को 1960 के प्रारम्भ में भारत आने का न्यौता दिया.
- 21 नवम्बर, 1962 को चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी.
- 1965 ई. में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, परन्तु उसे मुँह की खानी पड़ी.
- सन् 1971 को भारत-चीन के सम्बन्धों को लेकर भारत के लिए सुखदतम काल कहा जाता है.
- अफ्रीकी एशियाई मैत्री टेबिल टेनिस प्रतियोगिता के आयोजन से चीन तथा भारत के सम्बन्धों में सामान्यी-करण पैदा हुआ जिसे 'पिंगपांग' की कूटनीति कहा जाता है.
- भारत ने सिक्किम को 1975 ई. में भारतीय गणराज्य का अंग बनाया.
- फरवरी, 1978 ई. में चीन से 16 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आया.
- जून 1986 ई. में चीन ने मेकमोहन रेखा के दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश के कमांग मंडल के चियांग ड्रेग क्षेत्र पर घुसपैठ करना प्रारम्भ कर दिया.
- 5 जून, 1998 ई. को चीन के द्वारा दबाव बनाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा परीक्षण बन्द करने, शस्त्र विकास कार्यक्रम बन्द करने एवं NPT तथा CTBT पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव पास कराया गया.
- **नागरिकों के मूल अधिकार–**
  1. समानता का अधिकार (Right to equality)
  2. स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against exploitation)
4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of religion)
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (Cultural & Educational Rights)
6. सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property)
7. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedy)

- **नागरिकों के 42वें संशोधन के अनुसार कर्तव्य–**
  1. संविधान का पालन करना.
  2. राष्ट्रीय आदर्शों का पालन करना.
  3. भारत की सार्वभौमिकता, एकता तथा अखण्डता के प्रति निष्ठावान होना एवं इसकी रक्षा करना.
  4. देश की रक्षा एवं सेना को तैयार रहना.
  5. देश में भाईचारे की भावना का विकास करना.
  6. भारतीय संस्कृति का सम्मान करना एवं इसकी सुरक्षा करना.
  7. देश के प्राकृतिक वातावरण की समृद्धि में सहयोग देना, उसकी सुरक्षा करना एवं प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव प्रदर्शित करना.
  8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान एवं सुधार की भावना विकसित करना.
  9. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना.
  10. राष्ट्र के निरन्तर विकास के लिए प्रयत्न करना.

विगत वर्षों में आई.ए.एस. (प्री.) में पूछे गये प्रश्न

1. निम्नलिखित में से किसके अन्तर्गत अक्टूबर 1947 में भारत के संविधान का प्रथम ड्राफ्ट संविधान सभा की सलाहकार शाखा द्वारा तैयार किया गया था ?

(A) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
(B) जवाहरलाल नेहरू
(C) के. एम. मुंशी
(D) बी. एन. राउ

2. फरवरी 1947 में निम्नलिखित में से किसने यह महत्वपूर्ण घोषणा की कि महामहिम की सरकार का यह स्पष्ट आशय था कि जून 1948 तक, जिम्मेदार भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तान्तरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ?

(A) क्लीमेंट एटली (B) लॉर्ड माउंटबेटन
(C) विंस्टन चर्चिल (D) लॉर्ड पेथिक लारेंस

3. प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को वायसराय की एग्जीक्यूटिव कौंसिल का उपाध्यक्ष नामांकित किया गया.
2. बाद में सैयद अली जहीर तथा सर शफात अहमद खाँ वायसराय की एग्जीक्यूटिव कौंसिल में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के रूप में सम्मिलित हुए.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/ हैं ?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न ही 1 और न ही 2

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. तेज बहादुर सप्रू ने नेहरू रिपोर्ट का मसौदा बनाने में भाग लिया.
2. नेहरू रिपोर्ट ने पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र का सिद्धान्त स्वीकार किया.
3. नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्थिति को भारत द्वारा वांछित शासन के प्रकार के रूप में परिभाषित किया.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/ हैं ?

(A) केवल 1 (B) केवल 2 तथा 3
(C) केवल 1 तथा 3 (D) 1, 2 तथा 3

5. 1962 के भारत-चीन संघर्ष के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवम्बर 1962 में राष्ट्रपति केनेडी से सैन्य सहायता माँगी.
2. संयुक्त राज्य अमरीका ने चीन के विरुद्ध सहायतार्थ दस C-130 मालवाहक वायुयान तथा B-47 बमवर्षक विमानों के दो स्क्वाड्रन भेजे.
3. नवम्बर 1962 में जब जनरल थापर ने अपना त्यागपत्र दिया तब नव-नियुक्त रक्षामन्त्री ने नए सेनाध्यक्ष के लिए जनरल जे. एन. चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/ हैं ?

(A) 1, 2 तथा 3 (B) केवल 2 तथा 3
(C) केवल 1 (D) केवल 3

6. सूची-I (जलविद्युत शक्ति परियोजना) को सूची-II (अवस्थिति) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I

(a) सलाल जलविद्युत शक्ति परियोजना

(b) वालीमेला परियोजना

(c) शरावती परियोजना

(d) कोयना परियोजना

सूची-II

1. कर्नाटक   2. जम्मू और कश्मीर
3. महाराष्ट्र   4. उड़ीसा

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	1	2	3
(B)	2	1	3	4
(C)	2	4	1	3
(D)	3	4	1	2

7. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
   1. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्–शान्तिस्वरूप भटनागर
   2. भारतीय सांख्यिकी संस्थान–पी. सी. महालनोबिस
   3. परमाणु ऊर्जा आयोग–एच.एन. सेठना
   4. अन्तरिक्ष आयोग–एम.जी.के. मेनन

   इनमें से कौन-कौनसे युग्म सही सुमेलित हैं?

   (A) 1, 2 और 4   (B) 1, 3 और 4
   (C) 1, 2 और 3   (D) 2, 3 और 4

8. निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए–
   1. जे. बी. कृपलानी   2. अजय घोष
   3. षण्मुखम चेट्टी   4. जॉन मथाई

   इनमें से कौन-कौन स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में प्रमुख विरोधी व्यक्तित्वों (Opposition personalities) के समूह हैं?

   (A) 1, 2 और 3   (B) 1, 3 और 4
   (C) 1 और 2   (D) 3 और 4

9. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए–
   1. हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही
   2. गोआ की स्वतंत्रता (Liberation of Goa)
   3. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर में मृत्यु
   4. कश्मीर का भारत में अधिमिलन

   इन घटनाओं का सही कालानुक्रम (Chronological Order) है–

   (A) 1, 4, 3, 2   (B) 1, 4, 2, 3
   (C) 4, 1, 2, 3   (D) 4, 1, 3, 2

10. संविधान की मसौदा समिति के सम्मुख आमुख (प्रस्तावना) को किसने प्रस्तुत किया?

    (A) जवाहरलाल नेहरू   (B) बी. आर. अम्बेडकर
    (C) बी. एन. राव   (D) महात्मा गांधी

11. डोमिनियन पद (स्टेटस) के प्रदान करने के आधार पर भारत व पाकिस्तान की दो केन्द्रीय सरकारों के अन्तरित करने का सुझाव किसने दिया?

    (A) जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल
    (B) गांधीजी व जवाहरलाल नेहरू
    (C) लॉर्ड माउन्टबेटन व जवाहरलाल नेहरू
    (D) वी. पी. मेनन व सरदार पटेल

12. निम्न में से कौनसा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?

    (A) 1887 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र–कलकत्ता
    (B) 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र–लखनऊ
    (C) 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र–गया
    (D) 1939 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र–त्रिपुरी

उत्तरमाला

1. (D)   2. (A)   3. (D)   4. (C)   5. (A)
6. (C)   7. (C)   8. (C)   9. (D)   10. (A)
11. (D)   12. (A)

संकेत

1. संविधान सभा के राजनीतिक सलाहकार बी. एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया.
3. लीग के सदस्य थे–लियाकत अली, आई. आई. चुन्दरीगर, जोगेन्द्रनाथ मण्डल, गजनफर अली खाँ, एवं अब्दुल रब नस्तर.
4. नेहरू रिपोर्ट ने पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन मण्डल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की अनुशंसा की थी.
12. 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैण्ड में जब आम चुनाव हुए तो कौनसी पार्टी बहुमत में आई ?

   (A) लेबर पार्टी   (B) कांग्रेस
   (C) सोसलिस्ट   (D) जनतन्त्र

2. भारत में सत्ता हस्तान्तरण करने की शर्तों पर कैबिनेट मिशन कब भारत आया ?

   (A) जनवरी 1946 में   (B) फरवरी 1946 में
   (C) मार्च 1946 में   (D) अप्रैल 1946 में

3. संविधान सभा निर्माण के लिए प्रथम बैठक कब आयोजित हुई ?

   (A) 5 दिसम्बर, 1946   (B) 6 दिसम्बर, 1946
   (C) 8 दिसम्बर, 1946   (D) 9 दिसम्बर, 1946

4. उपर्युक्त सभा की अध्यक्षता किसने की ?
   (A) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (B) सच्चिदानन्द
   (C) नेहरू (D) गांधी
5. संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई ?
   (A) 170 (B) 165
   (C) 180 (D) 172
6. संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ ?
   (A) 21 फरवरी, 1948 (B) 21 फरवरी, 1950
   (C) 21 फरवरी, 1951 (D) 21 फरवरी, 1949
7. संविधान के प्रारूप पर अध्यक्ष की हैसियत से किसने हस्ताक्षर किए ?
   (A) डॉ. राधाकृष्णनन (B) नेहरू
   (C) महात्मा गांधी (D) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
8. उपर्युक्त संविधान प्रारूप पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अध्यक्ष की हैसियत से हस्ताक्षर कब किए ?
   (A) 26 जनवरी, 1949 (B) 26 जनवरी, 1948
   (C) 26 नवम्बर, 1949 (D) 30 नवम्बर, 1949
9. भारतीय संविधान में कितनी धाराएँ हैं ?
   (A) 395 (B) 396
   (C) 295 (D) 380
10. भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं ?
   (A) 8 (B) 9
   (C) 10 (D) 12
11. भारतीय संविधान कब लागू किया गया ?
   (A) 26 जनवरी, 1951 (B) 26 जनवरी, 1950
   (C) 27 जनवरी, 1947 (D) 28 जनवरी, 1955
12. संसार के संविधानों में सबसे लम्बा संविधान है–
   (A) पाकिस्तान का (B) अमरीका का
   (C) भारत का (D) ब्रिटेन का
13. भारत के अलावा किस राष्ट्र को छोड़कर उनके संविधानों में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का वर्णन नहीं है ?
   (A) लन्दन (B) ब्रिटेन
   (C) आयरलैण्ड (D) जापान
14. हमारे संविधान का विस्तृत रूप है–
   (A) 1935 के एक्ट के अनुसार
   (B) 1936 के एक्ट के अनुसार
   (C) 1937 के एक्ट के अनुसार
   (D) 1942 के एक्ट के अनुसार
15. "हमारा नया संविधान 1935 के भारतीय अधिनियम के समान ही न केवल एक संविधान है, अपितु एक विस्तृत कानून संहिता भी है" ये उद्गार किसके हैं ?
   (A) श्री ब्रह्मचारी (B) कृष्णमाचारी
   (C) आयंगर (D) श्रीनिवासन
16. "संविधान के स्वरूप का प्रशासन के स्वरूप से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है." यह कथन किसका है ?
   (A) महात्मा गांधी (B) जवाहरलाल नेहरू
   (C) डॉ. अम्बेडकर (D) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
17. अमरीका के संविधान में कितनी धाराएँ हैं ?
   (A) 6 (B) 7
   (C) 8 (D) 9
18. कनाडा के संविधान में कितनी धाराएँ हैं ?
   (A) 248 (B) 148
   (C) 147 (D) 247
19. स्विट्ज़रलैण्ड के संविधान में कितनी धाराएँ हैं ?
   (A) 123 (B) 124
   (C) 125 (D) 126
20. "भारतीय संविधान विशालकाय संविधान है." यह कथन किसका है ?
   (A) प्रो. एम. वी. पायली (B) वी. एम. भटनागर
   (C) राधाकृष्णनन (D) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
21. भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली के साथ-साथ और कौनसी प्रणाली के तत्व मौजूद हैं ?
   (A) प्रधानमन्त्री प्रणाली (B) राष्ट्रपति प्रणाली
   (C) मुख्यमन्त्री प्रणाली (D) इनमें से कोई नहीं
22. देश में आकस्मिक विपत्ति के समय अत्यधिक शक्ति किसके पास होती है ?
   (A) मुख्यमन्त्री (B) प्रधानमन्त्री
   (C) राष्ट्रपति (D) विधायक
23. संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्याख्या किन धाराओं में है ?
   (A) 12 से 35 (B) 13 से 36
   (C) 12 से 28 (D) 18 से 56
24. संविधान में नागरिकों के कर्तव्य कब शामिल किए गए ?
   (A) 1972 में (B) 1976 में
   (C) 1975 में (D) 1980 में
25. संविधान में नागरिकों के कर्तव्य कौनसे संशोधन के तहत शामिल किए गए ?
   (A) 41वें (B) 43वें
   (C) 44वें (D) 42वें
26. संविधान में नागरिकों के कर्तव्य किसके प्रयास से शामिल हुए ?
   (A) इंदिरा गांधी (B) लाजपत राय
   (C) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (D) महात्मा गांधी

27. संविधान में नीति-निर्देशक तत्वों की व्याख्या किस भाग में की गई है ?
(A) प्रथम (B) द्वितीय
(C) तृतीय (D) चतुर्थ

28. "संविधान एक चैक के समान है, जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर आधारित है." यह कथन किसका है ?
(A) प्रो. के. टी. शाह
(B) प्रो. के. वी. शर्मा
(C) प्रो. के. एस. नम्बूदरीपाद
(D) इनमें से कोई नहीं

29. संविधान का व्याख्याता तथा संरक्षक किसे बनाया गया है ?
(A) कार्यपालिका (B) न्यायपालिका
(C) व्यवस्थापिका (D) इनमें से कोई नहीं

30. संविधान में किस-किस विचारधारा का मिश्रण मिलता है ?
(A) मार्क्सवादी व गांधीवादी
(B) नाजीवाद व फासीवाद
(C) साम्यवाद व फासीवाद
(D) नाजीवाद व साम्यवाद

31. "भारतीय संविधान कार्य करने लायक एक दस्तावेज है." यह कथन किसका है ?
(A) गांधी (B) नेहरू
(C) प्रो. एम. वी. पायली (D) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

32. "समाजवाद के द्वारा भुखमरी, बेरोजगारी व गरीबी को हटाया जा सकता है." यह कथन किसका है ?
(A) पं. नेहरू (B) सरदार पटेल
(C) लाजपत राय (D) सुभाष चन्द्र

33. सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की गति को तेज करके राष्ट्रीय जीवन का क्या किया जा सकता है ?
(A) विकेन्द्रीकरण (B) लोकतांत्रिकरण
(C) समाजीकरण (D) एकीकरण

34. नेहरू ने गांधीजी के किस सिद्धान्त को समाजवाद के उपयुक्त नहीं माना ?
(A) न्यासिता सिद्धान्त (B) सार्वभौम सिद्धान्त
(C) एकेश्वर सिद्धान्त (D) बहुलवादी सिद्धान्त

35. नेहरू के मन मस्तिष्क पर किस यात्रा के समय समाजवाद का प्रभाव पड़ा ?
(A) रूस (B) अमरीका
(C) इंग्लैण्ड (D) लन्दन

36. रूस की यात्रा पं. नेहरू ने कब की ?
(A) 1927-28 (B) 1928-29
(C) 1930-31 (D) 1926-27

37. कराची के कांग्रेस अधिवेशन में प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीय-करण का प्रस्ताव किसके प्रयास से पास हुआ ?
(A) नेहरू (B) गांधी
(C) राजेन्द्र प्रसाद (D) लाजपत राय

38. "भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए लोकतन्त्र आवश्यक है." यह कथन किसका है ?
(A) मदनमोहन मालवीय (B) गंगाधर तिलक
(C) गोविन्द रानाडे (D) नेहरू

39. नेहरूजी उत्पादन में वृद्धि करने के पक्षधर थे, जिसके लिए उन्होंने किस नीति का सहारा लिया ?
(A) राज्यीकरण (B) राष्ट्रीयकरण
(C) वैश्वीकरण (D) एकीकरण

40. "भारत के उद्योगपति पैसे बनाने में माहिर हैं." यह कथन है–
(A) नेहरू का (B) मैकाले का
(C) गोल्ड स्मिथ का (D) महात्मा गांधी का

41. सर्वाधिकारवादी राज्य के अन्तर्गत समाजवाद की स्थापना होती है–
(A) मध्यम गति से (B) तीव्रगति से
(C) मन्दगति से (D) इनमें से कोई नहीं

42. "हमें भौतिक सम्पदा के साथ-साथ मानव की रचनात्मक शक्ति को भी बढ़ाना है." ये उद्‌गार किसने व्यक्त किए ?
(A) नेहरू (B) बालगंगाधर तिलक
(C) सी. वी. पन्त (D) राममनोहर

43. गुटनिरपेक्षता की नीति को सर्वप्रथम व्यावहारिक स्वरूप किस राष्ट्र ने प्रदान किया ?
(A) अमरीका (B) भारत
(C) जापान (D) इण्डोनेशिया

44. गुट निरपेक्ष प्रथम शिखर सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया ?
(A) 20 (B) 25
(C) 30 (D) 22

45. द्वितीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों की संख्या थी–
(A) 50 (B) 25
(C) 76 (D) 75

46. तृतीय शिखर सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई ?
(A) 85 (B) 90
(C) 70 (D) 72

47. "यदि हम अपने आपको किसी एक गुट के साथ जोड़ लेते हैं तो एक प्रकार से शायद यह अच्छा होगा, लेकिन हमें ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण दुनिया को इससे लाभ के बजाय हानि होगी." यह कथन किसका है ?
(A) महात्मा गांधी (B) राजेन्द्र प्रसाद
(C) नेहरू (D) रानाडे

48. तीन प्रमुख नेता नेहरू, नासिर तथा टीटो ने गुटनिरपेक्षता के पाँच तत्वों को कब स्वीकारा ?
(A) 1972 में (B) 1922 में
(C) 1961 में (D) 1967 में

49. "गुटनिरपेक्षता" का बीजारोपण कब हुआ ?
(A) 1946-47 (B) 1947-48
(C) 1949-50 (D) 1935-36

50. "जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खतरा हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहाँ आक्रमण होता हो, वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे." ये विचार किसके हैं ?
(A) रानाडे (B) मालवीय जी
(C) नेहरू (D) इंदिरा गांधी

51. विलियम हेंडर्सन ने गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए कितने कारकों का उल्लेख किया है ?
(A) पाँच (B) छह
(C) सात (D) आठ

52. "जब कभी तटस्थता की नीति का प्रभाव हुआ है तो वह मुख्यतः राष्ट्रवाद की धारणा पर ही हुआ है"–ये शब्द किसने कहे ?
(A) जान पाल (B) जान मारकस
(C) लॉर्ड वेलेजली (D) गांधी

53. "यदि किसी देश को सैनिक संगठन में शामिल होने को मजबूर करने वाली कोई स्थिति नहीं है तो उपनिवेश विरोधी भावना उसे गुटनिरपेक्षता की दिशा में प्रेरित करेगी." यह वाक्य किस सम्मेलन में कहा गया ?
(A) लाहौर सम्मेलन (B) शिमला सम्मेलन
(C) बांडुंग सम्मेलन (D) कलकत्ता सम्मेलन

54. प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ ?
(A) बेलग्रेड में (B) श्रीलंका में
(C) काहिरा में (D) लुसाका में

55. प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ ?
(A) 1960 में (B) 1961 में
(C) 1970 में (D) 1972 में

56. 2001 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है ?
(A) ढाका (बांग्लादेश) (B) रूस
(C) चीन (D) कोलम्बो (श्रीलंका)

57. "अगर 25 वर्षों पर दृष्टिपात किया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा जा सकता है."–ये कथन है–
(A) टी. वी. कौल का (B) टी. सी. कौल का
(C) टी. एम. कौल का (D) टी. एन. काटे

58. चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया ?
(A) 1962 (B) 1963
(C) 1964 (D) 1965

59. बांग्लादेश के कारण भारत-पाक युद्ध कब हुआ ?
(A) 1969 में (B) 1960 में
(C) 1971 में (D) 1973 में

60. गुटनिरपेक्षता संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सिद्धान्त को प्रश्रय देती है ?
(A) चार्टर सिद्धान्त (B) पौलीमर सिद्धान्त
(C) हार्टर सिद्धान्त (D) इनमें से कोई नहीं

61. अधिकांश गुटनिरपेक्ष देश वे ही हैं, जो शिकार थे–
(A) साम्राज्यवादी दासता के
(B) औपनिवेशी दासता के
(C) साम्यवादी दासता के
(D) फासीवाद दासता के

62. भारत की घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में किस नीति का गठन किया गया ?
(A) शांति की नीति (B) विदेश नीति
(C) उपनिवेशवाद की नीति (D) इनमें से कोई नहीं

63. बांडुंग सम्मेलन में किसके नेतृत्व के कारण एशिया तथा अफ्रीका के देशों को नई प्रेरणा मिली ?
(A) नेहरू (B) गांधी
(C) तिलक (D) बोस

64. भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है–
(A) पंचशील सिद्धान्त में विश्वास
(B) समाजवाद में विश्वास
(C) राष्ट्रवाद में विश्वास
(D) एकीकरण में विश्वास

65. भारत ने किसके आधार पर अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को सबल बनाया ?
(A) मैत्री नीति (B) समाजवादी नीति
(C) विदेश नीति (D) साम्राज्यवादी नीति

66. चीन में सर्वाधिक लोग किस धर्म को मानने वाले हैं ?
(A) हिन्दू (B) बौद्ध
(C) सिख (D) ईसाई

67. चीन किस विचारधारा का एक देश है ?
(A) साम्यवादी (B) समाजवादी
(C) साम्राज्यवादी (D) नाजीवादी

68. भारत को आजादी कब मिली ?
(A) 26 जनवरी, 1950 (B) 15 अगस्त, 1947
(C) 28 जनवरी, 1956 (D) 14 अगस्त, 1947

69. साम्यवादी चीन को पूर्ण मान्यता प्रदान कर अपनी द्विपक्षीय मित्रता एवं सहयोग की इच्छा को भारत ने कब जाहिर किया ?
(A) दिसम्बर 1949 में (B) जनवरी 1949 में
(C) फरवरी 1949 में (D) मार्च 1949 में

70. चीन ने कब अपनी सेना तिब्बत में भेजकर उस पर सैनिक नियन्त्रण कायम कर लिया ?
(A) नवम्बर 1950 (B) दिसम्बर 1951
(C) अक्टूबर 1950 (D) दिसम्बर 1952

71. भारत ने चीन के प्रति विरोध पत्र प्रथम बार कब लिखा ?
(A) 26 अक्टूबर, 1950 (B) 27 अक्टूबर, 1950
(C) 28 अक्टूबर, 1950 (D) 30 अक्टूबर, 1950

72. चीन ने दलाईलामा के एक प्रतिनिधि को कब 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया ?
(A) मई 1952 (B) मई 1951
(C) अप्रैल 1951 (D) मई 1953

73. भारत व चीन के मध्य समन्वयात्मक समझौता कब हुआ ?
(A) अक्टूबर 1952 (B) दिसम्बर 1952
(C) सितम्बर 1952 (D) नवम्बर 1952

74. बीजिंग में भारतीय दूतावास में भारतीय गणतन्त्र समारोह के अवसर पर माओ ने भारत एवं चीन की मित्रता को नया आयाम कब दिये?
(A) 26 जनवरी, 1950 (B) 26 जनवरी, 1951
(C) 27 जनवरी, 1949 (D) 28 जनवरी, 1956

75. जापान के साथ शान्ति संधि करने के लिहाज से अमरीका से सेन फ्रांसिस्को में बैठक कब बुलाई ?
(A) 1950 में (B) 1955 में
(C) 1951 में (D) 1952 में

76. 8 वर्षीय व्यापार एवं परस्पर सम्पर्क संधि किसके मध्य हुई ?
(A) भारत-चीन (B) भारत-रूस
(C) रूस-चीन (D) भारत-जापान

77. उपर्युक्त संधि कब हुई ?
(A) 28 अप्रैल, 1954 (B) 27 अप्रैल, 1950
(C) 29 अप्रैल, 1954 (D) 28 अप्रैल, 1957

78. चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई ने भारत की प्रथम यात्रा कब की ?
(A) जून 1954 (B) अप्रैल 1954
(C) अगस्त 1954 (D) मई 1954

79. भारत के प्रधानमन्त्री नेहरू ने चीन यात्रा किस माह में की ?
(A) नवम्बर 1954 (B) अक्टूबर 1954
(C) दिसम्बर 1954 (D) फरवरी 1954

80. चाऊ-एन-लाई ने दूसरी भारत यात्रा किस माह में की ?
(A) दिसम्बर (B) जनवरी
(C) फरवरी (D) मार्च

81. ल्हासा प्रलेख पर हस्ताक्षर कब किए गए ?
(A) 1 अप्रैल, 1956 (B) 1 अप्रैल, 1955
(C) 2 अप्रैल, 1956 (D) 2 अप्रैल, 1956

82. चीन ने भारत के खुरनाक जिले पर कब अधिकार जमा लिया ?
(A) जुलाई 1958 (B) अगस्त 1960
(C) अगस्त 1952 (D) अगस्त 1952

83. चीन के किस मासिक-पत्र में आपत्तिजनक मानचित्र प्रकाशित किए गए ?
(A) बौद्ध भिक्षु (B) चाइना पिक्टोरियल
(C) चाइना गजट (D) चाइना आब्जर्वर

84. उपर्युक्त आपत्तिजनक मानचित्र कब प्रकाशित किए गए ?
(A) 1958 में (B) 1969 में
(C) 1957 में (D) 1960 में

85. चीनी सैनिकों ने नेफा के लोहित मंडल में घुसपैठ कब शुरू की ?
(A) दिसम्बर 1958 (B) जनवरी 1958
(C) सितम्बर 1958 (D) मई 1958

86. भारत सरकार को लोहित मंडल घुसपैठ का पता कब चला ?
(A) अक्टूबर 1958 (B) जुलाई 1958
(C) दिसम्बर 1958 (D) नवम्बर 1958

87. तिब्बत समस्या दोबारा कब उभरकर सामने आई ?
(A) 1958 में (B) 1960 में
(C) 1959 में (D) 1965 में

88. चीन के विरोध में ल्हासा में प्रदर्शन कब किया गया ?
(A) 9 मार्च, 1959 को (B) 10 मार्च, 1959 को
(C) 12 मार्च, 1959 को (D) 15 मार्च, 1959 को

89. नेहरू ने चाऊ-एन-लाई को सीमा विवाद सुलझाने की दृष्टि से कब भारत आमन्त्रित किया ?
 (A) 1959 में (B) 1960 में
 (C) 1961 में (D) 1962 में

90. अप्रैल 1960 में चाऊ-एन-लाई ने भारत आने पर कितने दिन का प्रवास किया ?
 (A) 6 दिन (B) 7 दिन
 (C) 8 दिन (D) 10 दिन

91. चीन ने भारतीय क्षेत्र का कितने वर्गमील क्षेत्र अनधिकार कब्जा किया ?
 (A) 14,000 वर्ग मील (B) 12,000 वर्ग मील
 (C) 10,000 वर्ग मील (D) 8,000 वर्ग मील

92. चीन के द्वारा लद्दाख में तीन सैनिक चौकियाँ कब स्थापित की गईं ?
 (A) 1961 में (B) 1958 में
 (C) 1952 में (D) 1962 में

93. चीन ने भारत पर हमले की शुरूआत कब की ?
 (A) 21 अक्टूबर, 1962 (B) 20 अक्टूबर, 1962
 (C) 25 अक्टूबर, 1962 (D) 30 अक्टूबर, 1962

94. चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा कब की ?
 (A) 22 नवम्बर, 1962 (B) 23 नवम्बर, 1963
 (C) 21 नवम्बर, 1962 (D) 30 नवम्बर, 1962

95. पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कब किया ?
 (A) 1965 (B) 1950
 (C) 1951 (D) 1952

96. "भारत एक महान् देश है तथा भारत व चीन बहुत पहले अच्छे मित्र थे." यह किसने कहा ?
 (A) माओ-त्से-तुंग (B) दलाई लामा
 (C) चाऊ-एन-लाई (D) इनमें से कोई नहीं

97. माओ-त्से-तुंग ने उपर्युक्त बात कब कही ?
 (A) लाहौर अधिवेशन में
 (B) कलकत्ता में
 (C) मई दिवस स्वागत समारोह में
 (D) इनमें से कोई नहीं

98. चीन का राष्ट्रीय दिवस समारोह कब आयोजित हुआ ?
 (A) 1971 में (B) 1972 में
 (C) 1973 में (D) 1970 में

99. उपर्युक्त समारोह कहाँ हुआ था ?
 (A) लखनऊ में (B) कलकत्ता में
 (C) दिल्ली में (D) मद्रास में

उत्तरमाला

1. (A)	2. (C)	3. (D)	4. (B)	5. (B)
6. (A)	7. (D)	8. (C)	9. (A)	10. (D)
11. (B)	12. (C)	13. (C)	14. (A)	15. (D)
16. (C)	17. (B)	18. (C)	19. (A)	20. (A)
21. (B)	22. (C)	23. (A)	24. (B)	25. (D)
26. (A)	27. (D)	28. (A)	29. (B)	30. (A)
31. (C)	32. (A)	33. (B)	34. (A)	35. (A)
36. (D)	37. (A)	38. (D)	39. (B)	40. (A)
41. (B)	42. (A)	43. (B)	44. (B)	45. (C)
46. (A)	47. (C)	48. (C)	49. (A)	50. (C)
51. (D)	52. (B)	53. (C)	54. (A)	55. (B)
56. (A)	57. (D)	58. (A)	59. (C)	60. (A)
61. (B)	62. (B)	63. (A)	64. (A)	65. (C)
66. (B)	67. (A)	68. (B)	69. (A)	70. (C)
71. (A)	72. (B)	73. (C)	74. (B)	75. (C)
76. (A)	77. (C)	78. (A)	79. (B)	80. (A)
81. (B)	82. (A)	83. (B)	84. (A)	85. (C)
86. (A)	87. (C)	88. (A)	89. (B)	90. (A)
91. (B)	92. (A)	93. (B)	94. (C)	95. (A)
96. (A)	97. (C)	98. (A)	99. (C)	

9

आधुनिक भारत के महान् व्यक्तित्व
(The Great Personalities of Modern India)

महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi)
(1869-1948)

वास्तविक नाम	–	मोहनदास करमचन्द गांधी
प्रचलित नाम	–	महात्मा गांधी, बापू, मेनियो
उपाधियाँ	–	महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, कर्मवीर
जन्म	–	2 अक्टूबर, 1869
पिता	–	करमचन्द गांधी उर्फ काबा गांधी (पोरबन्दर, राजकोट और बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री)
माता	–	पुतलीबाई (काबा गांधी की चौथी पत्नी)
भाई-बहिन	–	1. मूली बेन, 2. पानकुंवर बेन, 3. लक्ष्मीदास (कालिदास), 4. रालियत बेन, 5. कृष्णदास
परिवार	–	सम्पन्न वैश्य परिवार
जन्म-स्थल	–	पोरबन्दर (काठियावाड़) (पोरबन्दर को उस समय सुदामापुरी भी कहते थे.)
शिक्षा	–	(i) प्राथमिक शिक्षा (राजकोट में 1876 से 1880 तक) (ii) उच्च प्राथमिक शिक्षा (राजकोट में 1881 से 1886 तक) (iii) माध्यमिक (मैट्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण की (राजकोट से 1887 में) (iv) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश (भावनगर, काठियावाड़ के शामलदास महाविद्यालय में 1888 में) (v) सत्र के अन्त में पढ़ाई समझ न आने के कारण छोड़ दी. (vi) संगीत एवं नृत्य की शिक्षा ली (लंदन में सन् 1888 में) (vii) लंदन की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की. (जून 1890 इंग्लैण्ड से) (viii) 10 जून, 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की.
पेशा	–	(i) राजकोट और मुम्बई में वकालत के लिए संघर्ष किया (नवम्बर 1891) (ii) राजकोट में लीगल ड्राफ्ट्स मैन बने. (1892 ई. में) (iii) मुसलमान फर्म में कानूनी कार्यवाही के लिए नियुक्त हुए एवं दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान किया. (अप्रैल 1893) (iv) नेटाल के सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के रूप में नाम दर्ज करवाकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले पहले भारतीय बने. (1 सितम्बर, 1894) (v) राजकोट में वकालत की (1 फरवरी, 1902) (vi) राजकोट से मुम्बई आकर वकालत की. (जुलाई 1902) (vii) ट्रांसवाल के सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी के रूप में नाम रजिस्टर करवाया. (1903)

विवाह – व्यवसायी गोकुलदास माकनजी की पुत्री कस्तूरबा के साथ 1876 ई. में सगाई एवं 1883 ई. में विवाह.

स्थापित संस्थाएं – (i) शाकाहारी क्लब (1890 ई. में लंदन में)

(ii) नेटाल भारतीय कांग्रेस (22 अगस्त, 1894 ई. में)

(iii) भारतीय एम्बुलेंस कोर (1899 ई. में)

(iv) ट्रान्सवाल ब्रिटिश इण्डियन एसोसि-एशन (1903 ई. में)

(v) फिनीक्स आश्रम (डरबन के पास 1904 ई. में)

(vi) भारतीय स्ट्रेचर वाहक कोर (जून 1906 ई. में दक्षिण अफ्रीका में)

(vii) टॉलस्टॉय फार्म (30 मई, 1902 ई. को दक्षिण अफ्रीका में)

(viii) फीनिक्स ट्रस्ट (12 सितम्बर, 1912 ई. में)

(ix) भारतीय स्वयंसेवक कोर की स्थापना (अक्टूबर 1914 ई. में)

(x) सत्याग्रह आश्रम (अहमदाबाद में 20 मई, 1915 ई. को) इसी आश्रम को कालान्तर में साबरमती आश्रम कहा गया.

(xi) गुजरात विद्यापीठ की स्थापना (अहमदाबाद, नवम्बर 1920 ई. में)

(xii) अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ (सितम्बर 1925 ई. में)

(xiii) अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ (26 अक्टूबर, 1934 ई. में)

(xiv) सी. एफ. एण्ड्रूज स्मारक अस्पताल (शान्ति निकेतन परिसर में, 19 दिसम्बर, 1945 ई. में)

(xv) सेवाग्राम आश्रम की स्थापना (30 अप्रैल, 1936 ई. कोवर्धा में)

(xvi) गौसेवा संघ की स्थापना (30 सितम्बर, 1941 ई. में)

सन्तान – चार पुत्र–(i) हरिलाल, (ii) रामदास, (iii) मणिलाल, (iv) देवदास.

अध्ययन – (i) शाकाहार पर सॉल्टस की पुस्तक का 9 नवम्बर, 1988 में अध्ययन किया, जिसका गांधीजी पर गहरा असर पड़ा.

(ii) पहली बार सन् 1889 ई. में गीता का अध्ययन किया.[1]

(iii) सितम्बर 1894 ई. में बाइबिल एवं कुरान का अध्ययन किया.

(iv) 1 सितम्बर, 1894 ई. को लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का अध्ययन किया.

(v) जॉन रस्किन की पुस्तक 'अनटू द लास्ट' का सन् 1904 ई. में अध्ययन किया.

विदेश यात्रा – (i) 4 सितम्बर, 1888 ई. को पहली बार समुद्र के रास्ते से इंगलैण्ड गए, 28 अक्टूबर, 1888 ई. को लंदन पहुँचे (अध्ययन के लिए).

(ii) दक्षिण अफ्रीका के लिए अप्रैल 1893 ई. में प्रस्थान किया (कानूनी कार्य से)

(iii) 28 जनवरी, 1902 ई. को रंगून के लिए यात्रा की.

(iv) दिसम्बर 1902 ई. में डरबन की यात्रा की.

(v) 21 जून, 1909 ई. को इंगलैण्ड की यात्रा की (भारतीयों का पक्ष रखने के लिए)

(vi) 13 नवम्बर, 1909 ई. को इंगलैण्ड से दक्षिणी अफ्रीका के लिए रवाना.

(vii) 22 अक्टूबर, 1912 ई. को गोपालकृष्ण गोखले के साथ द. अफ्रीका, लौरेन्को, मारकीस, मोजम्बिक एवं जंजीबार का दौरा किया.

(viii) 4 अगस्त, 1914 ई. को लंदन पहुँचे.

(ix) 1915-16 ई. में बर्मा का दौरा किया.

(x) नवम्बर 1927 ई. में श्रीलंका की यात्रा पर रवाना हुए.

(xi) 30 अगस्त, 1931 ई. को समुद्र के रास्ते से इंगलैण्ड के लिए रवाना हुए. (द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए)

लेखन – (i) 1895 ई. में 'द इण्डियन फ्रेंचाइजा एन अपील टू एवरी ब्रिटन इन साउथ अफ्रीका' का प्रकाशन किया.

(ii) राजकोट में 'द ग्रीन पैम्पलेट' को 14 अगस्त, 1896 ई. को प्रकाशित किया.

(iii) सन् 1904 ई. में गुजराती में 'आहार विज्ञान' पर लेख लिखे. इनको अंग्रेजी भाषा में अनुदित कर 'गाइड टू हैल्थ' नामक पुस्तक प्रकाशित की.

(iv) एस. एस. किण्डोनन कासल पर 13 नवम्बर, 1909 ई. को 'हिन्दु स्वराज' लेख लिखा.

---

1 महात्मा गांधी ए क्रॉनोलॉजी के अनुसार गांधीजी ने पहली बार जून 1890 में गीता का अध्ययन किया था.

(v) गुजराती मासिक पत्रिका 'नवजीवन' का सितम्बर 1919 ई. में सम्पादन कार्य सँभाला. यह पत्रिका आगे चलकर हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई.

(vi) अंग्रेजी साप्ताहिक 'यंग इण्डिया' का अक्टूबर 1919 ई. में सम्पादन कार्य सँभाला.

(vii) नवम्बर 1925 ई. में अपनी आत्म-कथा 'द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेन्ट्स विद ट्रुथ' का लेखन कार्य प्रारम्भ किया.

(viii) अंग्रेजी और हिन्दी में साप्ताहिक पत्र 'हरिजन' का 11 फरवरी, 1933 ई. को प्रकाशन प्रारम्भ किया.

(ix) 'माई अर्ली लाइफ' नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया.

(x) 'माई चाइल्डहुड' नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया.

(xi) 'इण्डियन ओपिनियन' पर लेख एवं पुस्तक लिखी.

सम्मान एवं पुरस्कार – (i) सन् 1899 ई. में युद्ध पदक से सम्मानित.

(ii) 'केसर-ए-हिन्द' स्वर्ण पदक एम्बुलैन्स सेवाओं के लिए 9 जनवरी, 1915 ई. को दिया गया.

(iii) 'जुलु' युद्ध पदक एवं बोअर युद्ध पदक प्रदान किया गया.

गिरफ्तारी एवं जेल – (i) 10 जनवरी, 1908 ई. से 30 जनवरी, 1908 ई. तक जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में जेल में समय व्यतीत किया. (ट्रांसवाल छोड़ने में असफल रहने पर)

(ii) 15 जनवरी, 1908 ई. से दो माह के लिए प्रिटोरिया, वाकर्वास्ट (Walkar-wast) की जेल में रहे.

(iii) 8 नवम्बर, 1913 ई. को पामफील्ड (Palmfield) में गिरफ्तार हुए एवं रिहा किए गए.

(iv) 9 नवम्बर, 1913 ई. को ट्रिकवर्थ (Trick Worth) में गिरफ्तार हुए एवं रिहा किए गए.

(v) 11 नवम्बर, 1913 ई. से 18 दिसम्बर, 1913 ई. तक वाकर्वुआस्ट (Walkarwust) में गिरफ्तार हुए

(vi) 17 अप्रैल, 1917 ई. को मोतीहारी में गिरफ्तारी का नोटिस जारी हुआ, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए.

(vii) 9 अप्रैल, 1919 ई. को दिल्ली जाते समय ट्रेन में गिरफ्तार हुए एवं 11 अप्रैल, 1919 ई. तक पनवेल बम्बई जेल में रहे.

(viii) 21 मार्च, 1922 ई. से 11 जनवरी, 1924 ई. तक यरवदा जेल में रहे (साबरमती में राजद्रोह के कारण)

(ix) 12 जनवरी, 1924 ई. से 5 फरवरी, 1924 ई. तक गिरफ्तार रहे, बीमार होने पर सैशन हॉस्पीटल, पूना में एपेंडि-साइटिस का ऑपरेशन कराया गया.

(x) 5 मई, 1930 ई. से 26 जनवरी, 1931 ई. तक यरवदा जेल में रहे.

(xi) 4 जनवरी, 1932 से 8 मई, 1933 ई. तक यरवदा जेल में रहे.

(xii) 1 अगस्त, 1933 ई. को साबरमती जेल में गिरफ्तार हुए.

(xiii) 2 अगस्त, 1933 ई. से 4 अगस्त, 1933 ई. तक यरवदा जेल में रहे.

(xiv) 4 अगस्त, 1933 ई. से 23 अगस्त, 1933 ई. तक यरवदा जेल में रहे.

(xv) 9 अगस्त, 1942 ई. से 6 मई, 1944 ई. तक यरवदा जेल (आगा खाँ महल) में रहे.

पिताजी का देहान्त – (i) सन् 1885 ई. में 63 वर्ष की उम्र में गांधीजी के पिता का देहान्त हो गया.

माँ का देहान्त – (i) 12 जनवरी, 1891 को माँ का देहावसान हो गया.

प्रमुख व्रत एवं उपवास – (i) सन् 1913 ई. में एक सप्ताह के लिए अवकाश रखा. (फीनिक्स आश्रम में दो व्यक्तियों से नैतिक चूक हो जाने के पश्चाताप करने के लिए)

(ii) सन् 1914 ई. में 14 दिन के लिए उक्त कारण से पुनः उपवास किया. (उपवास 22 जनवरी, 1914 ई. से प्रारम्भ किया.)

(iii) 1 जून, 1915 ई. को फीनिक्स आश्रम के बच्चों द्वारा झूठ बोलने के कारण.

(iv) 11 सितम्बर, 1915 ई. को फीनिक्स आश्रम में हरिजनों के प्रवेश के कारण आश्रमवासियों ने उपवास किया. गांधीजी ने भी आश्रमवासियों के इस कृत्य के परिणाम के रूप में उपवास किया.

(v) 15 मार्च, 1918 ई. से 17 मार्च, 1918 ई. तक अहमदाबाद कपड़ा मजदूरों के लिए उपवास रखा.

(vi) 6 अप्रैल, 1919 ई. को सत्याग्रह आन्दोलन के प्रथम दिवस पर उपवास किया.

(vii) 13 अप्रैल, 1919 ई. को जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के परिणामस्वरूप हुई अशान्ति के लिए उपवास रखा.

(viii) 14-15 अप्रैल, 1919 ई. को जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड के कारण बम्बई, अहमदाबाद एवं अन्य भागों में हुए विद्रोह के फलस्वरूप हुई अशान्ति के लिए उपवास रखा.

(ix) 19 नवम्बर से 21 नवम्बर, 1921 ई. तक एवं 28 नवम्बर, 1921 ई. को बम्बई में हुए विद्रोह के कारण उपवास किया.

(x) 12 से 16 फरवरी, 1922 ई. में चौरी-चौरा हत्याकण्ड के दौरान उपवास किया.

(xi) 17 से 30 सितम्बर, 1924 ई. में हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिए उपवास रखा.

(xii) 24 से 30 नवम्बर, 1925 ई. में आश्रमवासियों के दुष्कृत्य के कारण पश्चाताप के रूप में उपवास किया.

(xiii) 22 से 24 जून, 1928 ई. तक आश्रमवासियों के नैतिक पतन के कारण उपवास रखा.

(xiv) 20 से 25 सितम्बर, 1932 ई. तक हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन मण्डलों की व्यवस्था का उन्मूलन कराने के लिए उपवास रखा (साम्प्रदायिक अधिनिर्णय स्थगित हो जाने के बाद उपवास तोड़ा.)

(xv) 3 दिसम्बर, 1932 ई. को आत्मशुद्धि के लिए उपवास रखा.

(xvi) 8 मई से 28 मई, 1933 ई. तक अपनी एवं सहयोगियों की आत्मशुद्धि के लिए व्रत रखा.

(xvii) 16 से 22 अगस्त, 1933 ई. तक हरिजन सेवा से सम्बन्धित छूट को स्थगित करने के कारण उपवास रखा.

(xviii) 7 से 13 अगस्त, 1934 ई. में पं. लालनाथ के चोटग्रस्त हो जाने पर उपवास किया.

(xix) 3 से 6 मार्च, 1939 ई. में राजकोट के शासक द्वारा वादा नहीं निभा पाने के कारण उपवास रखा.

(xx) 12 से 13 नवम्बर, 1940 ई. में एक सहयोगी के ऊपर चोरी का सन्देह करने पर एक दिन का उपवास किया.

(xxi) 5 से 7 मई, 1941 ई. में बम्बई एवं अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दंगों के कारण 72 घण्टों तक उपवास किया.

(xxii) 29 जून, 1941 ई. को साम्प्रदायिक एकता के लिए एक दिन का उपवास किया.

(xxiii) 10 से 28 फरवरी, 1943 ई. एवं 1 से 2 मार्च, 1943 ई. में ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाने के कारण उपवास किया.

(xxiv) 30 नवम्बर, 1944 ई. को उपवास किया.

(xxv) 20 अक्टूबर, 1946 ई. को कॉपीराइटर द्वारा मुस्लिम लीग से उनके पत्राचार में त्रुटि करने के कारण व्रत किया.

(xvi) 15 अगस्त, 1947 ई. को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के विरोध में एक दिन का उपवास किया.

(xvii) 13 से 17 जनवरी, 1948 ई. तक साम्प्रदायिक दंगों के कारण दिल्ली में उपवास किया.

निजी जीवन पर कुछ प्रयोग–

(i) सन् 1884-85 ई. में मांसाहार का सेवन करना प्रारम्भ किया, माता-पिता से विश्वास-घात न करने के कारण मांस सेवन छोड़ा.[1]

(ii) 1885 में धूम्रपान के लिए अपने नौकर की जेब से पैसे चुराये, भाई का सोना चुराया, लेकिन बाद में सब सच पिताजी के समक्ष उगल दिया. पिताजी के क्षमा करने के बाद से सच बोलना जीवन का ध्येय बना लिया.

(iii) 28 अक्टूबर, 1888 ई. को शाकाहार भोजन पर रहने का अभ्यास किया.

(iv) जैन संन्यासी बेचरजी स्वामी के कहने पर जनवरी 1888 में मांस, स्त्री और शराब को स्पर्श नहीं करने का संकल्प लिया.

(v) सितम्बर 1890 ई. में शाकाहारी सभा में शामिल हुए.

(v) जून-जुलाई 1906 ई. में जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन की शपथ ली.

(vi) अहिंसा के प्रयोग को अगस्त, 1908 ई. में सर्वोत्कृष्ट बतलाया.

---

1 महात्मा गांधी ए क्रोनोलॉजी : प्रकाशन भारत सरकार, पृष्ठ 1 पर गांधीजी द्वारा मांसाहार करने का वर्ष 1883 बतलाया गया है.

(vii) 22 अक्टूबर, 1912 ई. को यूरोपीय वस्त्र एवं दूध का सेवन करना बन्द किया.

(viii) 18 दिसम्बर, 1913 ई. को अनुबन्धित मजदूरों की पोशाक पहनना प्रारम्भ किया. इसी दिन एक बार भोजन करना निश्चित किया.

(ix) हस्त निर्मित कपड़ा बनाने के लिए चरखे के उपयोग का विचार सन् 1917 ई. में आया.

(x) 17 सितम्बर, 1934 ई. को 1 अक्टूबर, 1934 ई. को राजनीति से संन्यास लेने के निर्णय की घोषणा की.

(xi) 10 जनवरी, 1908 ई. को पहली बार 'सत्याग्रह' शब्द को अपनाया.

पत्नी का देहावसान – 22 फरवरी, 1944 ई. में आगा खाँ के महल में.

विभिन्न मुलाकातें – (i) नवम्बर 1890 में मैडम ब्लावटस्की से परिचय हुआ.

(ii) 6 जुलाई, 1891 में रायचन्द भाई से परिचय हुआ, जिनका गांधीजी अपने ऊपर सर्वाधिक प्रभाव मानते हुए सम्मान करते थे.

(iii) 19 अगस्त, 1896 को एम. जी. रानाडे, बदरुद्दीन तैय्यब जी एवं फीरोज-शाह मेहता से बम्बई में मुलाकात की.

(iv) 12 अक्टूबर, 1896 को गोपालकृष्ण गोखले, डॉ. भण्डारकर एवं लोकमान्य तिलक से पूना में मुलाकात की.

(v) 31 अक्टूबर, 1896 को सुरेन्द्रनाथ बनर्जी से मुलाकात की.

(vi) डरबन में औपनिवेशिक राज्यमंत्री चैम्बर लैन से 6 अप्रैल, 1897 ई. को डरबन में घटी घटनाओं एवं पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए मुलाकात की.

(vii) 1 फरवरी, 1902 ई. को गोपालकृष्ण गोखले से मुलाकात की. इसी दौरान गोखले के साथ एक माह तक कलकत्ता में रहे.

(viii) 28 अक्टूबर, 1905 को जोहान्स-बर्ग में भाई परमानन्द से मुलाकात हुई.

(ix) अप्रैल 1907 ई. में प्रिटोरिया में स्मट्स से मुलाकात की.

(x) मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के मध्य 9 सितम्बर, 1944 ई. से 27 सितम्बर, 1944 ई. तक कुल 14 मुलाकातें बम्बई में हुईं.

राष्ट्रीय आन्दोलन की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ –

– (1) मई-जून 1893 ई. से दक्षिणी अफ्रीका में जातीय पूर्वाग्रहों के लिए संघर्ष का प्रारम्भ किया.

(2) सन् 1895 ई. में दक्षिणी अफ्रीकी भारतीयों की समस्याओं के प्रति प्रति-बद्धता की.

(3) जुलाई 1896 ई. में भारत में रहकर दक्षिणी अफ्रीकी भारतीयों की ओर से आन्दोलन प्रारम्भ किया.

(4) सन् 1905 ई. में बंगाल विभाजन का विरोध किया एवं विलायती वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया.

(5) 12 मई, 1906 ई. को भारत के लिए होमरूल का समर्थन किया,

(6) 10 जनवरी, 1908 ई. को निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द को अपनाया.

(7) 20 जनवरी, 1909 ई. को विभिन्न समाचारों में लेखों के माध्यम से भारतीयों को राष्ट्रीय स्तर पर संघर्षरत् रहने के लिए आह्वान किया.

(8) 17 अक्टूबर, 1913 ई. को न्यूकासन में अनुबन्धित भारतीयों से 3 पाउण्ड का कर रद्द न करने तक काम बन्द करने का आग्रह किया.

(9) सन् 1917 ई. में अनुबन्धित भारतीयों के उत्प्रवास के विरुद्ध सफलतापूर्वक आन्दोलन चलाया.

(10) जनवरी-मार्च 1918 ई. में मजदूरों के लिए लगान मुल्तवी कराने के लिए जिला खेड़ा (बम्बई) में सत्याग्रह प्रारम्भ किया.

(11) रॉलेट बिल को वापस लेने के लिए बाध्य करने के लिए सत्याग्रह करने की शपथ पर हस्ताक्षर किए गए.

(12) 6 अप्रैल, 1919 ई. को अखिल भारतीय सत्याग्रह आन्दोलन का उद्घाटन किया.

(13) 24 नवम्बर, 1919 ई. दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की.

(14) अंग्रेजी सरकार को 1 अगस्त, 1920 ई. को केसर-ए-हिन्द, जुलू युद्ध एवं बोअर युद्ध पदक विरोधस्वरूप वापस लौटा दिये गये.

(15) अप्रैल 1921 ई. में राष्ट्रीय रचनात्मक आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए भारत में कांग्रेस के एक करोड़ सदस्य बनाने, तिलक स्वराज फण्ड के लिए एक करोड़ रुपए जमा करने एवं 20 लाख चरखों की स्थापना का कार्यक्रम प्रारम्भ किया.

(16) विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार के अभियान का अगस्त 1921 ई. में नेतृत्व करते हुए तेजपुर की सार्वजनिक सभा में 22 अगस्त को विदेशी वस्त्रों को जलाया गया.

(17) बारदोली (गुजरात) में सत्याग्रह आन्दोलन चलाने के उद्देश्य से 1 फरवरी, 1922 ई. को वायसराय को नोटिस दिया.

(18) 5 फरवरी, 1922 को चौरी-चौरा की दुर्घटना पर सत्याग्रह आन्दोलन का परित्याग किया.[1]

(19) दिसम्बर 1924 ई. में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की.

(20) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने के लिए फरवरी 1930 ई. में सर्वेसर्वा नियुक्त किए गए.

(21) 12 मार्च, 1930 ई. को डाण्डी मार्च प्रारम्भ की तथा औपचारिक रूप से नमक हाथ में लिया.

(22) फरवरी-मार्च 1931 ई. में वायसराय के साथ कई वार्ताएं हुईं जिसके फल-स्वरूप गांधी-इरविन समझौता हुआ.

(23) 29 अगस्त, 1931 ई. को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए इंग्लैण्ड के लिए प्रस्थान किया.

(24) 20 सितम्बर, 1932 ई. को साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन मण्डलों की व्यवस्था का उन्मूलन कराने के लिए अनशन प्रारम्भ किया.

(25) 7 नवम्बर, 1934 ई. से हरिजन उद्धार के लिए दौरे प्रारम्भ किए.

(26) क्रिप्स के प्रस्तावों को 27 मार्च, 1942 ई. को पोस्ट डेटेड चैक (Post-dated Cheque) कहा गया.

(27) मई 1942 ई. में ब्रिटिश सरकार से भारत छोड़ने के लिए अपील की.

(28) द्विराष्ट्र के सन्दर्भ में 9 से 27 सितम्बर, 1944 ई. तक मोहम्मद अली जिन्ना से पाकिस्तान के सन्दर्भ में वार्तालाप की.

(29) 75वें जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर, 1944 ई. को कस्तूरबा स्मारक के लिए महात्मा गांधीजी को 110 लाख की राशि भेंट की गई.[1]

(30) जनवरी-फरवरी 1946 ई. में छुआछूत के विरोध एवं हिन्दुस्तानी के प्रचार के लिए दक्षिण भारत का दौरा किया.

(31) अप्रैल 1946 ई. में दिल्ली में केबिनेट मिशन के साथ राजनीतिक वार्ता में भाग लिया.

(32) 11 जून, 1946 ई. को वायसराय ने गांधीजी से साक्षात्कार किया और वायसराय ने अन्तरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा.

(33) 27 अगस्त, 1946 ई. को गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार से बंगाल त्रासदी को दोहराने के विरुद्ध चेतावनी स्वरूप तार दिया.

(34) 9 अक्टूबर, 1946 ई. को जिन्ना की 9 सूत्री माँगों के विषय में कांग्रेस को सूचित किया.

(35) 6 नवम्बर, 1946 ई. को नौआखाली में शान्ति स्थापित करने के लिए प्रस्थान किया.

(36) 1-2 अप्रैल, 1947 ई. को गांधीजी ने दिल्ली में एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन को सम्बोधित किया.

(37) 15 अप्रैल, 1947 ई. को जिन्ना के साथ मिलकर साम्प्रदायिक शान्ति के लिए अपील जारी की.

(38) 6 जून, 1947 ई. को गांधीजी ने पाकिस्तान को स्वीकार करते हुए माउण्टबेटन को लिखा कि वे जिन्ना को कांग्रेस के साथ पिछले सभी विवादग्रस्त विषयों को मित्रतापूर्ण ढंग से निपटाने के लिए राजी करें

(39) शान्ति की दिशा में गम्भीर रूप से पहल की एवं 2 सितम्बर, 1947 ई. को कलकत्ता में भारी भीड़ ने इसके लिए प्रोत्साहित किया.

(40) 7 दिसम्बर, 1947 ई. से पाकिस्तान बनने के परिणामस्वरूप हुए दंगों से प्रभावित क्षेत्रों का प्रतिदिन दौरा प्रारम्भ किया.

---

1 महात्मा गांधी–ए क्रॉनोलॉजी के अनुसार गांधीजी को उनके जन्म दिवस पर 80 लाख रुपये की राशि भेंट की गई थी.

(41) गांधीजी को 'शान्ति शपथ' 18 जनवरी, 1948 ई. को केन्द्रीय शान्ति समिति द्वारा प्रस्तुत की गई.

(42) कांग्रेस को लोकसेवक संघ में रूपान्तरित करने के लिए 30 जनवरी, 1948 ई. को एक संविधान का प्रारूप तैयार किया.

पुत्र वधुएं – 1. गुलाब (चंचल, चांची) (हरिलाल की पत्नी)

2. सुशीला (मणिलाल की पत्नी)

3. निर्मला (नीमू बेन) (रामदास की पत्नी)

महात्मा गांधी के दादा – उत्तम चन्द गांधी (ओटा बप्पा)

महात्मा गांधी की दादियाँ–

1. कादवी माँ, 2. लक्ष्मीबाई माँ (उत्तम चन्द गांधी की दो पत्नियाँ)

महात्मा गांधी के पिताजी के भाई–

1. वल्लभ जी, 2. रतनजी, 3. पीताम्बर, 4. प्रेमकुवर, 5. जीवनलाल (कादवी माँ के पुत्र-पुत्री)

2. कर्मचन्द गांधी (काबा गांधी) (लक्ष्मी माँ के एकमात्र पुत्र)

मोहनदास गांधी के बहिन दामाद–

1. धेला मेहता (मूली बेन के पति)

2. दायजी कृष्णदास मेहता (पानकंवर बेन के पति)

3. वृन्दावन दास (रालियत बेन के पति)

भाभी – 1. नन्दकुंवर बॉ (लक्ष्मीदास की पत्नी)

विभिन्न सन्दर्भों पर गांधीजी के विचार–

1. **स्वदेशी की भावना**–"स्वदेशी वह भावना है, जो हमें दूर के बजाय अपने आसपास के परिवेश के ही उपयोग और सेवा तक सीमित रखती है''''''प्रायः कहा जाता है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी का अवलम्बन कर ही नहीं सकता, जो यह आपत्ति उठाते हैं, वे 'स्वदेशी' को जीवन का नियम नहीं मानते. उनके लेखे वह एक देशभक्ति पूर्ण प्रयत्न है और उसमें कुछ ज्यादा आत्मनिग्रह करना पड़े, तो उसे छोड़ा जा सकता है.'''''स्वदेशी' एक धार्मिक नियम है और इसका पालन करते हुए किसे क्या शारीरिक कष्ट होता है, इसका कोई विचार नहीं किया जा सकता. इसके अन्तर्गत पिन या सुई से इसलिए वंचित रहना पड़े कि ये चीजें भारत में नहीं [illegible] स्वदेशी का व्रत लेने वाला ऐसी हजारों चीजों के बिना काम चलाना सीख लेगा, जो आज उसे आवश्यक लगती है.

2. **लोकतन्त्र की कल्पना**–"''''''मेरा विश्वास है कि विश्व के इतिहास में कभी भी हमारे स्वतन्त्रता के संघर्ष से अधिक लोकतन्त्री कोई संघर्ष नहीं हुआ है. मैं जब जेल में था, तब मैंने कार्लाइल की 'हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन' पढ़ी थी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने मुझसे रूसी क्रान्ति के बारे में थोड़ा-बहुत बताया है, परन्तु मेरे विचार में क्योंकि इन संघर्षों में हिंसारूपी अस्त्रों का प्रयोग किया गया था, इसलिए उनके द्वारा लोकतन्त्रीय आदर्श की स्थापना नहीं हो पाई. अहिंसा द्वारा प्रस्थापित जिस लोकतन्त्र की मैंने कल्पना की है. उस लोकतन्त्र में सबको समान स्वतन्त्रता मिलेगी, हर कोई अपना स्वामी स्वयं होगा. आज मैं ऐसे ही लोकतन्त्र की स्थापना के लिए संघर्ष करने को आपका आह्वान कर रहा हूँ. अगर एक बार यह बात आपके दिल में उतर जाए, तो आप सब हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव भूल जाएंगे और स्वयं को मात्र भारतीय समझेंगे, ऐसे भारतीय जो एक ही स्वतन्त्रता संग्राम में रत हैं."

3. **भारत देश की कल्पनामयी छवि**–"मैं एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करूँगा, जिसमें ऐसी स्थितियाँ होंगी कि सबसे गरीब लोग भी इसे अपना ही देश मानेंगे, जिसके निर्माण में उनकी आवाज प्रभावकारी होगी और भारत एक ऐसा देश होगा, जहाँ ऊँचे या नीचे वर्ग के लोग नहीं होंगे, जहाँ सभी सम्प्रदाय के लोग पूर्ण सामंजस्य के साथ रह सकेंगे''''''ऐसे भारत में न तो अस्पृश्यता का अभिशाप होगा, न शराबखोरी या नशाखोरी का.''''''महिलाएं भी पुरुषों जितने अधिकार पायेंगी''''''मेरे सपनों का भारत ऐसा ही है.

4. **प्रौढ़ शिक्षा**–"यदि प्रौढ़ शिक्षा मुझे सौंप दी जाय, तो मैं अनेक प्रौढ़ विद्यार्थियों में सबसे पहले अपने देश की महत्ता और विशालता का भाव जाग्रत करूँगा. देहातों का हिन्दुस्तान उसके गाँव तक ही सीमित होता है''''''देहातों में [illegible]

ध्यान नहीं है·········मेरे लिए प्रौढ़ शिक्षा का यह अर्थ है कि सबसे पहले प्रौढ़ को मौलिक रूप से सच्ची राजनीतिक शिक्षा दी जाए."

5. **धर्म**–"मैं अपने धर्म को प्रायः सत्य का धर्म कहता हूँ. पिछले दिनों से 'ईश्वर सत्य है' कहने के बजाय मैं कहने लगा हूँ कि 'सत्य ही ईश्वर है.' इससे मैं अपने धर्म को अधिक व्यापक बना सकता हूँ. सत्य के अतिरिक्त अन्य कोई चीज मेरे ईश्वर की इतनी पूर्णता से व्याख्या नहीं करती. मनुष्य जाति में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने भीतर सत्य का कुछ प्रकाश रखता है. हम सभी सत्य के ज्योति कण हैं."

6. **धर्म एवं राजनीति**–"मैं विश्वास नहीं करता कि धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, धर्म रहित राजनीति शव के समान है, जो दफनाने के योग्य है. धर्म रहित राजनीति एक मौत का फन्दा है·········जो कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते."

7. **ग्राम स्वराज्य**–"मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक गाँव एक पूर्ण गणराज्य है. अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए यह अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे. इस प्रकार प्रत्येक गाँव का पहला कार्य होगा–खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करना. गाँव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन तथा पाठशाला भी होनी चाहिए. प्रारम्भिक शिक्षा अन्तिम कक्षा तक अनिवार्य होगी. यथासम्भव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा."

8. **बहुमत**–"बहुमत का अर्थ यह नहीं कि वह एक व्यक्ति की भी राय को, यदि वह ठीक है, दबा दे. ठीक राय को, चाहे वह एक ही व्यक्ति की हो, बहुत की राय की अपेक्षा अधिक महत्व देना चाहिए. सच्चे लोकतन्त्र के सम्बन्ध में मेरा यही मत है."

9. **सत्याग्रह**–"जब तक शरीर अनुशासित न हो तब तक सत्याग्रही बनाना कठिन है. उसके लिए शील का पालन करना, पालन करना और निर्भयता पैदा करना आवश्यक होता है."

10. **किसान**–"देश की जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत से भी अधिक लोग किसान हैं. वही इस धरती को हरी-भरी बनाए हुए हैं. जमीन के असली मालिक किसान हैं न कि शहर में बैठे मौज उड़ाने वाले जमींदार, सारी भूमि गोपाल की है. यदि हम किसान के परिश्रम का फल उससे छीन लें, तो स्वराज्य का कोई अर्थ ही नहीं होगा. वकील, डॉक्टर या धनी जमींदार देश को सच्ची आजादी नहीं दिला सकते, वह तो किसानों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है."

गांधीजी के प्रति विभिन्न महापुरुषों के विचार–

1. **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के अनुसार**–"हमें न तो सन्त बचा सकता है, न क्रान्तिकारी, बल्कि दोनों का समन्वय ही यह कार्य कर सकता है. ऐसा समन्वय हमें गांधीजी में मिलता है, जो एक साथ सन्त भी हैं और क्रान्तिकारी भी. उनके सन्त स्वरूप में किसी पंथ विशेष की रूढ़िवादिता नहीं है. उनके लिए परम तत्व धार्मिक मतों से बड़ा है. उस एक परम श्रेष्ठ की सभी धर्म आराधना करते हैं. पवित्र अग्नि कहीं भी जल रही हो, तात्विक रूप से एक ही होती है. उसी अर्थ को समझाने के लिए हम तरह-तरह की अभिव्यक्ति का सहारा लेते हैं जिनका सम्बन्ध ऐतिहासिक घटना-चक्र से होता है. बेशक गांधीजी ने दीर्घकाल तक हमारे मुक्ति आन्दोलन का नेतृत्व, मार्गदर्शन और नियन्त्रण किया है जिसके साथ अनेक पुनीत स्मृतियाँ और बलिदानों की गाथा जुड़ी हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय पुनरुद्धार मात्र ही उनका प्रमुख अथवा मुख्य कार्य नहीं है. जब ये संघर्ष के दिन भुला दिए जाएंगे, गांधीजी इतिहास में सत्य और प्रेम के महान् मसीहा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे."

2. **आइन्स्टीन के अनुसार**–"आने वाली पीढ़ियाँ शायद यह मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि गांधीजी जैसा हाड़-मांस का पुतला कभी इस धरती पर हुआ होगा."

3. **इंदिरा गांधी के अनुसार**–"मेरे लिए गांधीजी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो मानव

याद दिलाते हैं. वह वर्तमान में जीते हुए भी अतीत से जुड़े हुए थे और भविष्य के लिए जीते थे. इस तरह उनके उच्चतम विचारों में अनन्तता झलकती है. उन्होंने तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत कुछ कहा और उनके कथन कई व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते थे. उन्होंने अपने विचारों को अपने जीवन की प्रयोगशाला में अपने ही प्रयोग के आधार पर ढाला था.

4. जवाहरलाल नेहरू के अनुसार– "स्वतन्त्रता के जनक और आज के दिन हमारा ध्यान सबसे पहले राष्ट्रपिता की ओर जाता है, जिन्होंने भारत की प्राचीन चेतना को आत्मसात् करके स्वतन्त्रता की ज्वाला को प्रज्ज्वलित रखा तथा अंधेरे को प्रकाश में बदल दिया. हालांकि उनके सुयोग्य अनुयायी नहीं बन पाए और उनके संदेश पर अमल करने में हम विफल रहे हैं, किन्तु केवल हम ही नहीं आने वाली पीढ़ियाँ भी उनके संदेश को याद रखेंगी.

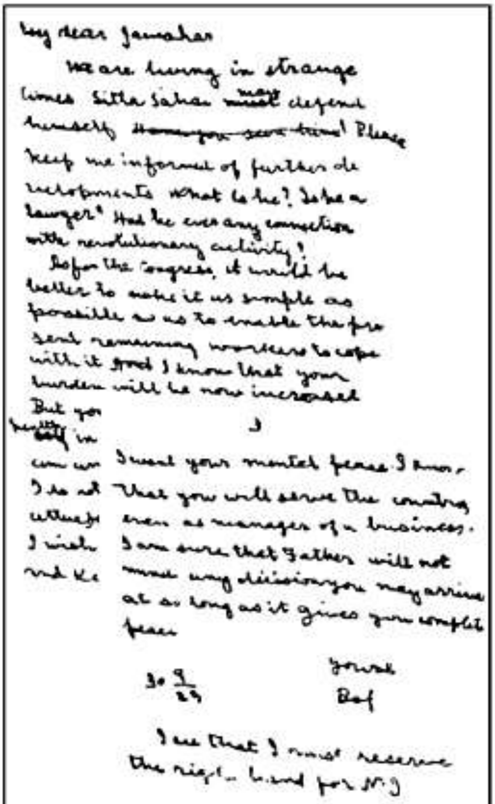

My dear Jawahar

We are living in strange times. Sitla Sahai may defend himself. Please keep me informed of further developments. What is he? Is he a lawyer? Had he ever any connection with revolutionary activity?

As for the Congress, it would be better to make it as simple as possible so as to enable the present remaining workers to cope with it. And I know that your burden will be now increased.

But you ... I want your mental peace. I know that you will serve the country even as manager of a business. I am sure that Father will not mind any decision you may arrive at as long as it gives you complete peace.

Yours
Bapu

I see that I must reserve the right hand for M.J.

गांधी की हस्तलिपि : बाएँ हाथ से

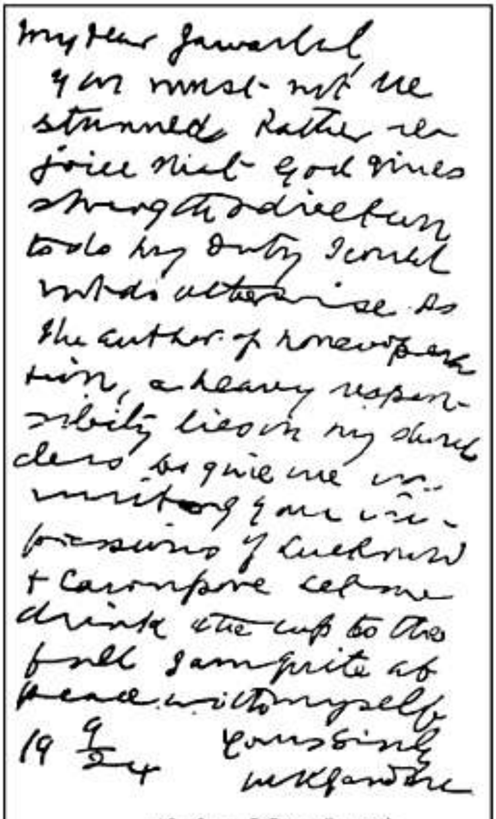

My dear Jawaharlal

You must not be stunned. Rather rejoice that God gives strength [illegible] to do my duty. I could not do otherwise. As the author of non-co-operation, a heavy responsibility lies on my shoulders [illegible] impressions of Lucknow & Cawnpore. Let me drink the cup to the full. I am quite at peace with myself.

19-9-24

Yours sincerely
M K Gandhi

गांधी की हस्तलिपि : दाएँ हाथ से

अध्यक्षता	–	1. 24 नवम्बर, 1919 ई. को अखिल भारतीय खिलाफत आन्दोलन की अध्यक्षता की. 2. दिसम्बर 1924 ई. में बेलगाँव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की.
मृत्यु के प्रयास	–	28 जून, 1946 ई. को दिल्ली से पूना जाते समय रेलगाड़ी को पटरी से उतारने के प्रयास किए गए.
मृत्यु	–	30 जनवरी, 1948 ई. को प्रार्थना सभा में जाते हुए 5 बजकर, 15 मिनट पर शाम को हत्या कर दी गई.

गांधीजी की हत्या के अभियुक्त–

1. नाथूराम गोडसे (प्रमुख)
2. शंकर किश्तैय्या (सहयोगी)
3. गोपाल गोडसे (सहयोगी)
4. मदनलाल पाहवा (सहयोगी)
5. दिगम्बर बडगे (सहयोगी)
6. नारायण आप्टे (सहयोगी)
7. वीर सावरकर (सहयोगी)
8. विष्णु करकरे (सहयोगी)

गांधीजी की हत्या में प्रयुक्त शस्त्र–

नौ एम. एम. की स्वचालित इटली निर्मित 'बेरेट्टा गन' (इसका क्रम नं. 606824 था. इसका निर्माण 1934 ई. में हुआ था. नाथूराम गोडसे को यह दण्डवते ने दी थी जिसे उसने जगदीश प्रसाद गोयल से खरीदी थी.)

महात्मा गांधी का जिन्ना के नाम पत्र–

दिनांक–24 सितम्बर, 1944

प्रिय कायदेआजम,

मेरे 22 और 23 सितम्बर के पत्रों के उत्तर में आपके 23 सितम्बर के दोनों पत्र मिले.

आपकी सहायता से समझौते पर पहुँचने के लिए मैं सभी सम्भावनाओं की खोज कर रहा हूँ, ताकि मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में उल्लिखित माँग ठीक प्रकार से पूरी की जा सके. इसलिए आपको इस बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव हमारे समझौते पर पहुँचने के मार्ग में बाधक होगा. इस प्रस्ताव में भारत *बनाम* ब्रिटेन के प्रश्न पर विचार किया गया है और वह हमारे समझौते के मार्ग में बाधक नहीं हो सकता.

मैं यह धारणा लेकर चलता हूँ कि भारत को दो या दो से अधिक राष्ट्र मानकर न चला जाय, बल्कि कई सदस्यों का एक परिवार समझा जाए, जिनमें से उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों के मुसलमान अर्थात् बलूचिस्तान, सिन्ध, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त और पंजाब का वह भाग जहाँ अन्य सभी जातियों की अपेक्षा मुसलमान पूर्ण बहुमत में हैं तथा बंगाल और असम के उन हिस्सों के मुसलमान जहाँ वह पूर्ण बहुमत में हैं, शेष भारत से अलग रहना चाहते हैं.

आपसे सामान्य आधार पर मतभेद रखते हुए भी मैं मुस्लिम लीग के सन् 1940 ई. के लाहौर प्रस्ताव में निहित विभाजन की माँग को अपने आधार पर और नीचे लिखी शर्तों पर मान लेने के लिए कांग्रेस और देश से सिफारिश कर सकता हूँ.

क्षेत्रों का सीमा निर्धारण कांग्रेस और लीग द्वारा मान्य कमीशन करे. हद बन्दी के क्षेत्रों के निवासियों की इच्छाओं का पता या तो उन क्षेत्रों की बालिग जनता के मतों द्वारा अथवा किसी ऐसे ही तरीके द्वारा लगाया जाय.

यदि विभाजन के पक्ष में मत आये, तो यह मान लिया जायेगा कि ज्यों ही भारत विदेशी प्रभुत्व से आजाद हो जाएगा ये क्षेत्र पृथक् राज्य कायम कर सकेंगे. आजाद होने पर भारत में दो सार्वभौम कायम हो सकते हैं.

विभाजन के बारे में एक सन्धि की जाएगी, जिसमें वैदेशिक मामलों, रक्षा, आन्तरिक यातायात, जकात, व्यापार जैसे विषयों के ठीक और संतोषजनक संचालन की योजना की जाएगी. यह विषय अनिवार्य तौर पर सन्धि करने वाले दोनों पक्षों के बीच समान दिलचस्पी के रहेंगे.

सन्धि में दोनों राज्यों के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की भी योजना की जाएगी.

ज्यों ही इस समझौते को कांग्रेस और लीग मंजूर कर लेंगी, त्यों ही दोनों भारत की आजादी प्राप्त करने के लिए समान मार्ग निर्धारित करेंगी, किन्तु लीग ऐसी किसी प्रत्यक्ष कार्यवाही से अलग रह सकेगी, जिसे कांग्रेस शुरू करे और जिसमें भाग लेने के लिए लीग तैयार न हो.

अगर आपको यह शर्तें मंजूर न हों, तो क्या आप मुझे निश्चित रूप में बताएंगे कि आप लाहौर प्रस्ताव की दृष्टि से मुझसे क्या मनवाना चाहेंगे और कांग्रेस से क्या सिफारिश करवाना चाहेंगे ? यदि आप कृपा कर ऐसा कर सकें, तो विचार करने के तरीकों में मतभेद होने के बावजूद मैं यह सोच सकूँगा कि किन-किन निश्चित शर्तों को मैं स्वीकार कर सकता हूँ. अपने 23 सितम्बर के पत्र में आपने लाहौर प्रस्ताव में लिखित आधार और मूलभूत सिद्धान्तों का जिक्र किया है और मुझसे उन्हें मान लेने को कहा है. निश्चय ही यह अनावश्यक है, जब मैं महसूस करता हूँ मैंने वैसी स्वीकृति से उत्पन्न होने वाले निश्चित परिणाम को स्वीकार कर लिया है.

आपका

मो. क. गांधी

स्वामी विवेकानन्द
(Swami Vivekanand)

(1863 – 1902)

वास्तविक नाम	– नरेन्द्र नाथ दत्त
आध्यात्मिक नाम	– स्वामी विवेकानन्द
जन्म	– 12 जनवरी, 1863 ई.
जन्म स्थान	– कलकत्ता
परिवार	– उच्च मध्यमवर्गीय कायस्थ
अध्ययन	– स्कोटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से 1884 में बी. ए.
आध्यात्मिक गुरु	– श्री रामकृष्ण परमहंस
संस्था	– रामकृष्ण मिशन (1 अगस्त, 1897)
संगठन	– बैल्लूर मठ (9 दिसम्बर, 1898)
नारा	– दीन-दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है.

पुस्तकें – धर्म तत्व, धर्म रहस्य, नारी रहस्य

विदेशी प्रवास – 1. शिकागो अमरीका सन् 1893
2. न्यूयार्क सन् 1895
3 इंगलैण्ड सन् 1895, 1896, 1897

मनोवृत्ति – 1. उदारवादी विचारधारा
2. हिन्दुत्व एवं अतीत भारत की महानता में विश्वास करने वाली मनोवृत्ति

उल्लेखनीय कार्य – 1. राष्ट्रवाद की जागृति
2. शिकागो धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व
3. विदेशों में हिन्दू धर्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार.

मृत्यु – 4 जुलाई, 1902 ई. बैल्लूर मठ में

स्वामी दयानन्द सरस्वती
(Swami Dayanand Sarasvati)

(1824 – 1883)

वास्तविक नाम – मूलशंकर

प्रचलित नाम – स्वामी दयानन्द

जन्म – 1824 ई. में

जन्म स्थान – मौरवी जनपद के टंकारा (सौराष्ट्र) में

परिवार – अत्यन्त सम्पन्न जमींदार ब्राह्मण

अध्ययन – टंकारा एवं मथुरा में

गुरु – स्वामी विरजानन्द (मथुरा)

संस्था – आर्य समाज (1875 ई. में)

पुस्तकें – वेदों की व्याख्या, सत्यार्थ प्रकाश

नारा – वेदों की ओर लौटो

महत्वपूर्ण कार्य – राष्ट्रवाद का उत्थान, मूर्तिपूजा, अन्ध-विश्वास एवं बाल विवाह पर प्रतिबन्ध

मृत्यु – 1883 ई. में (अजमेर में)

राजा राममोहन राय
(Raja Ram Mohan Roy)

(1772 – 1833)

वास्तविक नाम – राजा राममोहन राय

जन्म – 22 मई, 1772 ई.

जन्म स्थान – राधा नगर (कलकत्ता)

परिवार – बंगाल नवाब परिवार (ब्राह्मण)

अध्ययन – बंगाली (अपने गाँव में) पारसी, संस्कृत भाषा पटना, संस्कृत साहित्य–बनारस, लेटिन, ग्रीक, फ्रेन्च, अंग्रेजी का ज्ञान

गुरु – जर्मी बेन्थम

संस्था – 1. आत्मीय सभा (1815)
– 2. ब्रह्म समाज (20 अगस्त, 1828)
3. एंग्लो हिन्दू स्कूल
– 4. युनिटेरियन मिशन (1825)
5. वेदान्त कॉलेज (1825)

पुस्तकें – 1. तुहफत-उल-मुवाहीद्दीन (पारसी) (1903-04)
2. वेदान्त सूत्र

पत्र – संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत

विदेशी प्रवास – इंगलैण्ड (1830)

उपाधि – राजा, सन् 1830 में अकबर II द्वारा

उल्लेखनीय कार्य – 1. शिक्षा, धर्म सुधार
2. समाज सुधारक
3. उच्च पदों पर भारतीयों की भर्ती की माँग

मनोवृत्ति – 1. ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार
2. उदारवादी
3. प्रार्थना एवं अनुनय-विनय में विश्वास

मृत्यु – सन् 1833 में ब्रिस्टल (इंगलैण्ड में)

गोपाल कृष्ण गोखले (Gopal Krishna Gokhle)

(1866 – 1915)

वास्तविक नाम – गोपाल कृष्ण गोखले

जन्म – 9 मई, 1866

जन्म स्थान – कदुल्क (महाराष्ट्र) रत्नागिरी जिले में

परिवार – अत्यन्त निर्धन ब्राह्मण

अध्ययन – कोल्हापुर, मुम्बई से ग्रेजुएट (सन् 1884 में)

राजनीतिक गुरु – महादेव गोविन्द रानाडे

संस्था –
1. सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी (1905)
2. रानाडे इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक्स (1908)

पत्र – नेशन

विदेशी प्रवास – इंगलैण्ड सन् 1897 में

राजनीतिक प्रवेश – फर्ग्यूसन कॉलेज पूना से प्रिंसिपल से रिटायर होकर 1902 ई. में

राष्ट्र सेवा –
1. सार्वजनिक सभा के मंत्री (1888 ई.)
2. कांग्रेस के सदस्य (1889 ई.)
3. कांग्रेस के मंत्री (1895 ई.)
4. केन्द्रीय विधानपरिषद् के सदस्य (1902 ई.)
5. बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष (1905 ई.)

उल्लेखनीय कार्य –
1. भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन
2. अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव का विरोध
3. 1833 के चार्टर एक्ट एवं विक्टोरिया घोषणा-पत्र से अधिक ब्रिटिश सरकार से माँग

मृत्यु – 19 फरवरी, 1915 ई. को

चितरंजन दास (C. R. Das)

(1870 – 1925)

वास्तविक नाम – चितरंजन दास

जन्म – 5 नवम्बर, 1870

जन्म स्थान – कलकत्ता

पत्नी – बसन्ती देवी

परिवार – उच्च मध्यमवर्गीय

शिक्षा – स्नातक, प्रेसीडेन्सी कॉलेज कलकत्ता से

पुस्तकें – इण्डिया फोर फ्रीडम

विदेशी प्रवास – इंग्लैण्ड (1890 में)

सार्वजनिक जीवन –
1. सन् 1917 से राष्ट्रीय आन्दोलन में
2. सन् 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित

उल्लेखनीय योगदान –
1. असहयोग आन्दोलन में सक्रिय योगदान
2. मान्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार का विरोध
3. बहिष्कार के लिए भारतीयों को जागृत किया
4. स्वराज पार्टी की स्थापना में उल्लेखनीय योगदान
5. सन् 1922 में 6 मास की जेल यातना
6. चौरी-चोरा काण्ड में असहयोग की भूमिका

मृत्यु – दार्जिलिंग में 16 मई, 1925 ई.

रवीन्द्रनाथ टैगोर (R. N. Tagore)

(1861 – 1941)

वास्तविक नाम – रवीन्द्रनाथ टैगोर

उपाधि – गुरुदेव, सर, नाइट

जन्म – 7 मई, 1861 ई.

जन्म स्थान – कलकत्ता

पिता – देवेन्द्र नाथ ठाकुर

माता – शारदा देवी

परिवार – सम्पन्न ब्राह्मण परिवार

शिक्षा –
1. प्रारम्भिक शिक्षा घर में ही
2. बेकन, गेटे, एजेंलों का इंगलैण्ड में अध्ययन
3. लंदन यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया.

संस्था – शान्ति निकेतन (विश्वभारती) विश्व-विद्यालय (1901)

नारा –
1. एकला चालो रे
2. जन-गण-मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता

पुस्तकें (काव्य रचनाएं)
1. – बनफुल, कवि-काहिनी (1871) (प्रारम्भिक रचनाएं)
2. संध्या संगीत (1882)
3. कड़ि औ कोमल (1886)
4. प्रभात संगीत (1883)
5. छवि ओगान (1884)
6. मानसी (1890)
7. सोनार तटी (1894)
8. चित्रा (1896)
9. नैवेध (1901)
10. गीतांजलि (1910)
11. बलाका (काव्य संग्रह, 1916)
12. पलात का (काव्य संग्रह, 1918)
13. पूरबी (काव्य संग्रह, 1925)
14. प्रवाहिनी (काव्य संग्रह, 1925)
15. शिशु भोलानाथ (काव्य संग्रह, 1932)
16. महुआ (काव्य संग्रह, 1929)
17. वनवाणी (काव्य संग्रह, 1931)
18. परिशेष (काव्य संग्रह, 1932)
19. पुनश्च (काव्य संग्रह, 1932)
20. वीथिका (काव्य संग्रह, 1934)
21. पत्रपुट (काव्य संग्रह, 1936)
22. आरोग्य (काव्य संग्रह, 1941)
23. शेषलेखा (काव्य संग्रह, 1941)

उपन्यास एवं गद्य रचनाएँ –
1. करुणा (प्रथम उपन्यास, 1884)
2. चोखेर बाली (1903)
3. नौका डूबी (1906)
4. गोरा (1909)
5. जीवन स्मृति (1912-13)

नाट्य रचनाएं –
1. वाल्मिकी प्रतिभा (1881)
2. मायेर खेला (1888) (प्रारम्भिक गीतिनाट्य)
3. राजा ओ रानी (1889)
4. विसर्जन (1890)
5. चित्रांगदा (1892)
6. रक्त करबी (1926)
7. शारदोत्सव (1908)
8. राजा (1910)
9. अचलायतन (1912)
10. फाल्गुनी (1916)
11. नटीर पूजा (1926)
12. श्यामा (1939)

पत्र – तत्त्व बोधिनी

विदेशी प्रवास – इंगलैण्ड (1878), यूरोप, यू. एस. ए.

सार्वजनिक जीवन – 19वीं सदी में प्रवेश

उल्लेखनीय कार्य –
1. सन् 1905 ई. में स्वदेशी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया.
2. साहित्य (गीतांजली) के नोबेल विजेता (1913 में)
3. जलियाँवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड लौटाई.
4. प्रथम विश्व युद्ध में योगदान

मृत्यु – 7 अगस्त, 1941 ई. कलकत्ता

विपिन चन्द्र पाल
(Bipin Chandra Pal)

(1858 – 1932)

वास्तविक नाम – विपिन चन्द्र पाल

जन्म – 7 नवम्बर, 1858 ई.

जन्म स्थान – सियालहट (बांग्लादेश)

परिवार – सम्पन्न हिन्दू कायस्थ

अध्ययन – प्रेसीडेन्सी कॉलेज से बी. ए. 1875 में

पुस्तकें	– 1. मिसेज बेसेन्ट-ए-साइकोलोजिकल स्टडी
	2. मेमोरीज ऑफ माई लाइफ टाइम
विदेशी प्रवास	– इंग्लैण्ड (कई बार)
राजनैतिक गतिविधियाँ	– 1. द्वितीय वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन से कांग्रेस में (सन् 1886 में)
	2. उदारवादी विचारधारा के विरोधी एवं उग्रवादी विचारों के प्रमुख
	3. विदेशी सामान का बहिष्कार
	4. निष्क्रिय प्रतिरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा पर आधारित आन्दोलन
	5. कई बार जेल यात्राएँ
	6. लाल-बाल-पाल में पाल के नाम से विख्यात
	7. स्वशासन की पूर्णता पर विश्वास एवं माँग
मृत्यु	– 20 मई, 1932 ई. में

बाल गंगाधर तिलक
(Bal Gangadhar Tilak)

(1856 – 1920)

वास्तविक नाम	– बाल गंगाधर तिलक
जन्म	– 23 जुलाई, 1856 ई.
जन्म स्थान	– रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
परिवार	– निर्धन ब्राह्मण
अध्ययन	– 1. बी. ए. (पूना से) 1876 ई.
	2. कानून स्नातक 1879 ई.
संस्था	– होमरूल लीग I (महाराष्ट्र)
पत्र	– 1. केसरी 2. मराठा
पुस्तकें	– 1. गीता रहस्य
	2. आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन्स
	3. द ऑरियन (1893)
नारा	– स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है.
उपाधि	– लोकमान्य
राजनैतिक गतिविधियाँ	– 1. उग्रवाद का प्रारम्भ
	2. समाचार पत्रों से जागृति
	3. 1897 में 18 मास की जेल
	4. स्वराज्य की माँग
	5. माण्डले जेल में 6 वर्ष तक कैद (1908)
	6. होमरूल लीग आन्दोलन का प्रारम्भ
	7. लाल-बाल-पाल का प्रमुख व्यक्तित्व
मनोवृत्ति	– 1. स्वशासन स्थापना के इच्छुक
	2. ब्रिटिश सत्ता के प्रति अविश्वास
	3. प्रार्थना, अनुनय विनय विरोधी
	4. कांग्रेस विचारधारा के विपरीत मानसिकता
मृत्यु	– 1 अप्रैल, 1920 ई.

लाला लाजपत राय
(Lala Lajpat Roy)

(1865 – 1928)

वास्तविक नाम	– लाला लाजपत राय
जन्म	– 28 जनवरी, 1865
जन्म स्थान	– धुन्धिके (पंजाब)
परिवार	– हिन्दू वैश्य मध्यवर्गीय
अध्ययन	– 1. प्रारम्भिक शिक्षा अम्बाला में
	2. कानून स्नातक (लाहौर से) 1886 ई.
पुस्तकें	– 1. आर्य समाज
	2. यंग इण्डिया
	3. पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इण्डिया
	4. प्रोब्लेम ऑफ नेशनल एजूकेशन इन इण्डिया
उपाधि	– पंजाब केसरी (द लॉयन ऑफ पंजाब)
विदेशी प्रवास	– 1. इंग्लैण्ड (1905, 1907)
	2. जापान (1913 में) अमरीका
	3. यूरोप (1924, 1926, 1927)

राजनैतिक गतिविधियाँ – 1. सन् 1888 उग्रवादी विचारों के साथ कांग्रेस में प्रवेश
2. 1907 में माण्डले जेल में कैद
3. गदर पार्टी, आर्य समाज के प्रमुख कार्यकारी
4. पुनः 1921 में जेल
5. कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन (1920) के अध्यक्ष
6. स्वराज्य पार्टी के साथ राष्ट्र सेवा
7. लाल-बाल-पाल के लाल के रूप में प्रसिद्ध

मृत्यु – साइमन कमीशन विरोध में लाठी प्रहार से 30 अक्टूबर, 1928 ई. को लाहौर में

दादा भाई नौरोजी
(Dada Bhai Nauroji)

(1825 – 1917)

वास्तविक नाम – दादा भाई नौरोजी
जन्म – 4 दिसम्बर, 1825
जन्म स्थान – बम्बई
परिवार – मध्यवर्गीय पारसी
अध्ययन – बम्बई से बी. ए. (1845 ई. में)
संस्था – 1. ब्रिटिश सार्वजनिक सभा
2. पारसी लॉ एसोसिएशन
3. ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन (लंदन)
4. रहनुमाई माजदयासान
पत्र – 1. वॉयस ऑफ इण्डिया
2. रस्टे गुफ्तूर
पुस्तकें – पॉवर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया
नारा – आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम पूरे राजभक्त हैं.
विदेशी प्रवास – 1. लन्दन (1885), 2. इंगलैंड (1902)
उपाधि – भारत के पितामह

राजनैतिक गतिविधियाँ – 1. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बम्बई के सदस्य-1876 में
2. बम्बई विधान परिषद के सदस्य (1885)
3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (1886) के अध्यक्ष
4. लाहौर अधिवेशन (1893) कलकत्ता अधिवेशन (1906) के अध्यक्ष

उल्लेखनीय कार्य – 1. आई. सी. एस. परीक्षा भारत में करवाने की माँग
2. छुआछूत, जातिगत भेदभाव, शिक्षा-सुधारक के रूप में कार्य किया.
3. उदारवादी विचारधारा के प्रमुख व्यक्तित्व

मृत्यु – 1917 ई. में

बहादुर शाह जफर
(Bahadur Shah Zafar)

(1775 – 1862)

वास्तविक नाम – बहादुर शाह जफर
जन्म – 1775 ई.
अध्ययन – 1. उर्दू, पारसी, अरबी भाषाओं के ज्ञाता
2. सूफी, फिलोसफी और काव्य
गुरु – कवि इब्राहीम जैंग
राजनीति प्रवेश – 1.1837 ई. में अन्तिम मुगल सम्राट्
2. प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृत्व
मनोवृत्ति – 1. बहु-विवाह के इच्छुक
2. जीनत महल पसंदीदा पत्नी
3. भारतीय शासन के पक्षधर
उल्लेखनीय कार्य – 1. सन् 1857 के विद्रोह में भारत के प्रमुख नेता
2. मुगल साम्राज्य का अन्तिम शासक
मृत्यु – रंगून में 1862 ई. में.

महारानी लक्ष्मीबाई (Maharani Laxmibai)

(1835 – 1858)

वास्तविक नाम	– मनु बाई
प्रसिद्ध नाम	– लक्ष्मीबाई
उपाधि	– झाँसी की रानी, महारानी
जन्म	– 16 नवम्बर, 1835 ई.
जन्म स्थान	– बनारस
पति	– महाराज गंगाधर राव
पिता	– मोरोपंत बलवंत राव ताँबे
माता	– भागीरथी बाई
शिक्षा	– 1. घुड़सवारी 2. अस्त्र प्रशिक्षण 3. पारम्परिक शिक्षा
संस्था	– पेशवा संघ
मनोवृत्ति	– 1. घुड़सवारी की शौकीन 2. प्रमुख राष्ट्रवादी
राजनीतिक सहयोगी	– राव साहिब, तात्याँ टोपे, नाना साहब
राजनैतिक प्रवेश	– गोद निषेध नीति से क्षुब्ध होकर सन् 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष
उल्लेखनीय कार्य	– 1. भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रमुख कर्णधार 2. ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने के लिए झाँसी में सन् 1857 में आन्दोलन का नेतृत्व
मृत्यु	– सन् 1858 ई. में

नाना साहब (Nana Saheb)

(1824 – 1859)

वास्तविक नाम	– नाना धुंधु पंत पेशवा
जन्म	– 1824 ई. में
परिवार	– पेशवा बाजीराव II के दत्तक पुत्र
सहयोगी	– तात्याँ टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई
राजनीति प्रवेश	– सन् 1857 विद्रोही के रूप में
मनोवृत्ति	– 1. कट्टरवादी राष्ट्रवादी 2. प्रतिशोध की भावना
उल्लेखनीय कार्य	– सन् 1857 के विद्रोह में भारत की तरफ से कानपुर में नेतृत्व किया.
मृत्यु	– नेपाल में 1859 ई. में

सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Ballabhbhai Patel)

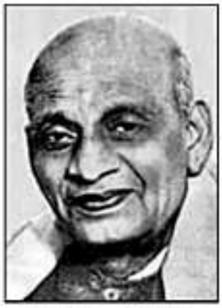

(1875 – 1950)

वास्तविक नाम	– वल्लभभाई जावेरभाई पटेल
उपाधि	– सरदार, लौह पुरुष
जन्म	– 31 अक्टूबर, 1875 ई.
जन्म स्थान	– नडियाद (गुजरात)
परिवार	– सम्पन्न कृषक
शिक्षा	– 1. मैट्रिक्यूलेशन नडियाद से (1897) 2. कानून स्नातक बोरसाद से
विदेश प्रवास	– 1910 से 1912 (इंग्लैण्ड)
राजनीतिक प्रवेश	– 1912 ई. में अहमदाबाद म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन, कांग्रेस विधान परिषद् के चेयरमैन (1928),स्वतन्त्र भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री व गृहमन्त्री (1947 से 1949), 1931 कराची कांग्रेस अधि-वेशन के अध्यक्ष
उल्लेखनीय योगदान	– 1. खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आन्दो-लन में सक्रिय भूमिका 2. बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व 3. बारदोली सत्याग्रह की सफलता से सरदार की उपाधि

4. नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आन्दोलन 1932 में सोलह महीने की जेल (यरवदा जेल भेजे गए)
5. भारत छोड़ो आन्दोलन में उत्कृष्ट योगदान
6. राष्ट्रीय एकीकरण (रियासतों का)

मृत्यु – 15 दिसम्बर, 1950 ई.

तात्याँ टोपे (Tatyan Tope)

(1813 – 1859)

वास्तविक नाम – तात्याँ टोपे
जन्म – 1813 ई. में
जन्म स्थान – पूना
परिवार – समृद्ध ब्राह्मण परिवार
सार्वजनिक जीवन – 1 मई, 1857 में नाना साहब की सेना में प्रमुख थे.
उल्लेखनीय कार्य – 1. ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध
2. सन् 1857 की प्रथम स्वतन्त्रता क्रान्ति में ग्वालियर में भारतीय नेता के रूप में

मृत्यु – 18 अप्रैल, 1859 ई. में

अबुल कलाम आजाद (Abul Kalam Azad)

(1888 – 1958)

वास्तविक नाम – मुहियुद्दीन
प्रसिद्ध नाम – मौलाना अबुल कलाम आजाद
पिता – मौलाना खैरीउद्दीन
माता – बेगम अलीहा
जन्म – 1888 ई. में
संस्था – देवबन्द स्कूल
पत्र – उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल (1912)
पुस्तकें – 1. इण्डिया विन्स फ्रीडम
2. गुबोर-खातिर
3. तसरीहात-ए-आजाद

अध्ययन – अपने पिता से इस्लाम धर्म की पारम्परिक शिक्षा
प्रभाव – सर सैय्यद अहमद की पुस्तकों का
सार्वजनिक जीवन – 1. सन् 1908 से
2. सन् 1923 दिल्ली विशेष कांग्रेस अधिवेशन एवं 1940 रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष

विदेशी प्रवास – 1908 में इराक, मिस्र, टर्की
उल्लेखनीय कार्य – 1. खिलाफत आन्दोलन में सक्रिय भूमिका
2. ब्रिटिश सरकार के विरोध में कई बार जेल
3. यू. जी. सी., एस. ई. सी. एवं एफ. ई. सी. की स्थापना में प्रमुख भूमिका रही.
4. स्वतन्त्र भारत के प्रथम शिक्षामंत्री

मृत्यु – सन् 1958 ई. में

एनी बेसेन्ट (Anni Besent)

(1847 – 1933)

प्रारम्भिक नाम – एनी वुड (शादी से पूर्व)
वास्तविक नाम – एनी बेसेन्ट
जन्म – 1 अक्टूबर, 1847 को
जन्म-स्थान – लन्दन
पाविार – सम्पन्न आयरिश परिवार
पिता की मृत्यु – क्षय रोग से हो गई जब वह मात्र 5 वर्ष की थी.

पालन-पोषण – पिता की मृत्यु के कारण प्रसिद्ध उपन्यास-कार कैप्टेन मैरियट की बहिन कुमारी मैरियट ने पालन पोषण किया.

प्रिय पुस्तकें – 1. पेराडाइज लोस्ट, 2. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस.

शिक्षा – जर्मन, फ्रांसीसी एवं संगीत का अध्ययन किया.

विवाह – सन् 1866 ई. में कैम्ब्रिज के एक अध्यापक पादरी रेवेरेन्टुं फ्रैंक बेसेन्ट से

सन्तान – 1869 में एक पुत्र एवं 1870 में एक पुत्री हुई.

तलाक – पति की धार्मिक कट्टरता के कारण 1873 में वैवाहिक सम्बन्ध टूट गए.

छद्म नाम – ऐजक्स (लेखन के लिए)

पहला सार्वजनिक भाषण – महिलाओं की राजनीतिक स्थिति (को-ऑपरेटिव इन्स्टीट्यूट में सन् 1874 में)

संस्था से सम्बन्ध –
1. नेशनल सेक्यूलर सोसायटी (राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष समाज) (इस संस्था की उपाध्यक्ष थीं)
2. थियोसोफिकल सोसायटी से
3. फेबियन सोसायटी (सन् 1885 में)
4. चारिंग क्रास संसद

पुस्तकें प्रकाशित –
1. इंगलैण्ड भारत और अफगानिस्तान (1878 ई. में)
2. आत्मकथा
3. ए स्टेडी इन कान्शसनेस
4. सनातन धर्म सीरिज (डॉ. भगवान दास के सहयोग से)

पत्र सम्पादन –
1. नेशनल रिफार्मर
2. यूनाइटेड इण्डिया
3. कॉमनवील (सन् 1914 ई. में अंग्रेजी भाषा में बम्बई से प्रकाशित)
4. न्यू इण्डिया (सन् 1914 में अंग्रेजी भाषा में बम्बई से प्रकाशित) (पूर्व नाम मद्रास स्टेण्डर्ड)

संस्था की स्थापना –
1. होमरूल लीग (तिलक के साथ 1915 ई. में पुणे में)
2. ऑल्काट पंचम, स्कूल अड्यार में
3. सन्स एण्ड डॉटर्स ऑफ इण्डिया
4. स्काउट एण्ड गार्डस ऑफ ऑनर
5. द ब्रदर्स ऑफ सर्विस
6. वाई. एम. सी. ए.

भारत में आगमन – 16 नवम्बर, 1893 को पहली बार

प्रमुख भारतीय नेताओं से भेंट – 1888 में महात्मा गांधी से एवं 1901 में पं. जवाहरलाल नेहरू से भेंट

प्रदत्त उपमा – पूर्णरूपेण श्वेत सरस्वती (पं. गंगाधर शास्त्री द्वारा)

अध्यक्षता –
1. थियोसोफिकल सोसायटी की.
2. वीमेन्स इण्डिया एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष.

उल्लेखनीय योगदान –
1. भारतीयों को हिन्दू दर्शन एवं संस्कृति के पक्ष में प्रभावित करने का उत्कृष्टम कार्य किया.
2. प्राचीन धर्म ग्रन्थों–वेदों, उपनिषदों, गीता एवं पुराणों का सरल रूप में अनुवाद कर आम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया.
3. महिलाओं को शिक्षित एवं आत्म-निर्भर बनाने के लिए प्रयास किया.
4. भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में अत्यधिक सहयोग दिया.
5. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए योजना निर्मित की.
6. होमरूल आन्दोलन के माध्यम से राष्ट्रीयता में वृद्धि की

राजनीतिक जीवन –
1. सन् 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधि बनीं.
2. सन् 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षा बनीं.

प्रसिद्ध वक्तव्य – **सरोजिनी नायडू**–'यद्यपि एनीबेसेन्ट जन्म से विदेशी थीं, किन्तु सच्चे अर्थों में वह हम सबसे अधिक भारतीय थीं. उन्होंने हमें सिखाया कि स्वतन्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए कोई भी बलिदान बहुत महान् नहीं है. भारत की लम्बाई और चौड़ाई से गुजर उन्होंने प्रेरणा के पंखों पर सवार होकर हमारे लोगों के मृत हृदयों को झकझोर कर उन्हें जीवन के उत्साह से भर दिया.

मृत्यु – 20 सितम्बर, 1933 को (अड्यार में)

वी. डी. सावरकर
(V. D. Savarkar)

(1883 – 1966)

वास्तविक नाम	–	विनायक दामोदर सावरकर
प्रचलित नाम	–	वीर सावरकर
जन्म	–	1883 ई. में
जन्म स्थान	–	भागुर (नासिक के निकट)
परिवार	–	चितपावन ब्राह्मण परिवार (मध्यमवर्गीय)
विदेशी प्रवास	–	इंग्लैण्ड (1906), (1910)
संस्था	–	अभिनव भारत (प्रारम्भ में मित्र मेला)
पुस्तकें	–	1. वार ऑफ इण्डियन इण्डिपेन्डेन्स 2. माजी जनमेथेय
सहयोगी	–	1. श्यामजी कृष्ण वर्मा, 2. लाला हरदयाल 3. मदन लाल धींगरा
जेल यात्रा	–	1. 1920 में इंग्लैण्ड जेल में. 2. अण्डमान जेल में 1911–1921 तक 3. भारत में जेल में 1921–1924 तक 4. रत्नागिरी में 1924–1937 तक
सार्वजनिक जीवन	–	1906 से 1937 में हिन्दू महासभा के अध्यक्ष
उल्लेखनीय योगदान	–	1. सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित 2. हिन्दुत्व और भारतीय संस्कृति का उत्थान की दिशा में कार्य किया. 3. क्रान्तिकारियों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उग्रवादी विचारों से संगठित किया. 4. छुआछूत और जातिवाद का खात्मा 5. स्वतन्त्र संविधान की माँग 6. सत्याग्रह आन्दोलन 1939 का आयोजन 7. मुस्लिम लीग के विभाजन का विरोध किया.
मृत्यु	–	1966 ई. में

पं. जवाहर लाल नेहरू
(Pt. Jawahar Lal Nehru)

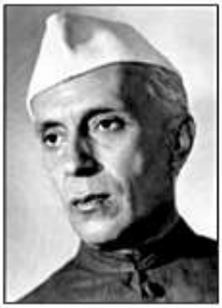

(1889 – 1964)

वास्तविक नाम	–	जवाहर लाल नेहरू
उपाधि	–	चाचा
पिता	–	पं. मोतीलाल नेहरू
जन्म	–	14 नवम्बर, 1889
जन्म स्थान	–	इलाहाबाद
परिवार	–	समृद्ध ब्राह्मण
शिक्षा	–	1. उच्च शिक्षा–हैरोज पब्लिक स्कूल इंग्लैंड 2. ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंसेज, कैमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी में स्नातक–1910 में अध्ययन
विद्यार्थी के रूप में	–	औसतन मध्यम
नारे	–	1. हू लिव्ज इफ इंडिया डाईज 2. वी हैव मैड ए ट्रायस्ट विद डेस्टिनी 3. आराम हराम है.
पुस्तकें	–	1. डिस्कवरी ऑफ इंडिया 2. ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री 3. ए बन्च ऑफ ओल्ड लेटर्स 4. मेरी आत्मकथा 5. हिज फादर टू हिज डाटर 6. ए पॉलिटिकल बायोग्राफी
सर्वप्रिय व्यक्ति	–	लेडी एडविना (लेडी माउण्टबेटन)
सार्वजनिक जीवन	–	स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेना सन् 1913 से प्रारम्भ किया, 1929 ई. में लाहौर राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, 1936 ई. में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, 1937 ई. में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की.
उल्लेखनीय योगदान	–	1. असहयोग आन्दोलन (1920–24) में सक्रिय भाग लिया.

2. सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930–33) में पूर्णतः भाग लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया.
3. भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र सेवा
4. भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय योगदान

मृत्यु – मई 1964 ई. में

सरदार भगत सिंह (Sardar Bhagat Singh)

(1907 – 1931)

वास्तविक नाम – भगत सिंह

जन्म – 1907 ई. में

जन्म स्थान – बंगा गाँव में (प. पंजाब)

पिता – किशन सिंह

माता – विद्यावती

शिक्षा – 1. डी. ए. वी. कॉलेज लाहौर से उच्च शिक्षा
2. नेशनल कॉलेज से स्नातक (1923)

नारा – इंकलाब जिन्दाबाद

संस्था – नव-जवान भारत सभा (1925)

सार्वजनिक जीवन – 1. सन् 1923 में असहयोग आन्दोलन के आह्वान में स्वयं को समर्पित कर दिया.
2. 3 फरवरी, 1928 को साइमन कमीशन का विरोध
3. 17 दिसम्बर, 1928 को ब्रिटिश पुलिस सहायक अधीक्षक सांडर्स की हत्या
4. 8 अप्रैल, 1929 बी. के. दत्त के साथ सेन्ट्रल असेम्बली में इंकलाब जिन्दाबाद के साथ बम फेंका.
5. 8 अप्रैल को आत्मसमर्पण किया.

मृत्यु – भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू पर मुकदमा चलाकर 23 मार्च, 1931 को शाम साढ़े सात बजे लाहौर सेन्ट्रल जेल में फाँसी दे दी गई.

चन्द्रशेखर आजाद (Chandra Shekhar Azad)

(1906 – 1931)

वास्तविक नाम – चन्द्रशेखर

उपनाम – आजाद

जन्म – 23 जुलाई, 1906 ई. में

जन्म स्थान – भावरा (झाबुआ, म. प्र. में)

परिवार – अत्यन्त निर्धन ब्राह्मण परिवार

पिता – सीताराम तिवारी

शिक्षा – 1. प्रारम्भिक गृह गाँव में
2. उच्च शिक्षा बनारस संस्कृत पाठशाला में

सार्वजनिक शिक्षा – 1. 15 वर्ष की आयु में असहयोग आन्दोलन
2. असहयोग आन्दोलन में गिरफ्तार
3. हिन्दुस्तान सोशियलिस्ट रिपब्लिक में शामिल, सक्रिय भूमिका

उल्लेखनीय भूमिका – 1. सभी क्रान्तिकारी विद्रोह यथा कांकोरी कांड, लाहौर काण्ड एवं एसेम्बली बम काण्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन
2. अंग्रेजों का मुँह तोड़ मुकाबला करने वाले देश का महान् सिपाही.
3. गरीब तबके को राष्ट्रीय आन्दोलन में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

मृत्यु – फरवरी 1931 ई. में

सरोजिनी नायडू (Sarojini Naidu)

(1879 – 1948)

वास्तविक नाम – सरोजिनी नायडू

उपाधि – भारत कोकिला

जन्म – 13 फरवरी, 1879 ई. में
जन्म स्थान – हैदराबाद
परिवार – सम्पन्न वैश्य परिवार
पति – डॉ. गोविन्द राजुला नायडू
पिता – डॉ. अघोरनाथ चट्टोपाध्याय
माता – वरदा सुन्दरी
अध्ययन – 1. 12 वर्ष की उम्र में मैट्रिक्युलेशन (1891 ई. में)
2. इंग्लैण्ड से उच्च शिक्षा
3. छोटी उम्र में कविता का अभ्यास
पुस्तकें – 1. सांग ऑफ इण्डिया
2. वोकनविंग
विदेशी प्रवास – इंग्लैंड में 1895 ई. में
राष्ट्रीय सेवा – 1. 1916 लखनऊ अधिवेशन में पं. जवाहर लाल नेहरू की प्रेरणा से राजनीति में प्रवेश
2. राजनीतिक नेतृत्व 1919 ई. से
3. यू. पी. की प्रथम राज्यपाल
4. 1925 ई. में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षा.
उल्लेखनीय कार्य – 1. असहयोग आन्दोलन में सक्रिय योगदान
2. नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आन्दोलन, क्रिप्स मिशन में प्रमुख योगदान
3. कई बार जेल यात्रा
मृत्यु – 2 मार्च, 1948

गोविन्द वल्लभ पन्त
(Govind Ballabh Pant)

(1887 – 1961)

वास्तविक नाम – गोविन्द वल्लभ पंत
जन्म – 10 सितम्बर, 1887 ई. को
जन्म स्थान – अल्मोड़ा
परिवार – मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार
शिक्षा – कानून स्नातक (मुईर कालेज, इलाहाबाद)
सार्वजनिक जीवन – 1. 1912 से सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ
2. यू. पी. विधान परिषद् में प्रवेश
3. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
उल्लेखनीय योगदान – साइमन कमीशन असहयोग आन्दोलन में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन एवं महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस के विवाद में मध्यस्थ की सक्रिय भूमिका निभाई.
मृत्यु – 7 मार्च, 1961 ई. में

भीमराव अम्बेडकर
(B. R. Ambedkar)

(1891 – 1956)

वास्तविक नाम – भीमराव अम्बेडकर
जन्म – 14 अप्रैल, 1891 ई. में
परिवार – सम्पन्न महर परिवार
जन्म स्थान – महु (म. प्र.)
पिता – रामजी भालोगी
माता – भीमाबाई
शिक्षा – 1. प्रारम्भिक शिक्षा (सतारा, बॉम्बे और इंग्लैण्ड में)
2. कोलम्बिया विश्वविद्यालय से 1916 ई. में पी- एच. डी.
पत्र – मूक नायक (मराठी)
राजनीतिक प्रवेश – 1. सन् 1924 से राजनीति में प्रवेश
2. बहिष्कृत हितकारिणी सभा को 1924 में संगठित किया.
3. बम्बई विधान परिषद् के सदस्य

4. गवर्नर जनरल एक्ज्यूक्युटिव काउंसिल के सदस्य (जुलाई 1942 से मार्च 1946 ई. तक)
5. भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य

संस्था – स्वतन्त्र पार्टी 1936 ई. में स्थापित की अनुसूचित जाति फेडरेशन (1942) की स्थापना

पुस्तकें – 1. कोर्ट इन इण्डिया
2. एनीहिलेशन ऑफ कास्ट
3. थॉट्स ऑफ पाकिस्तान
4. मि. गांधी एण्ड ए मेन सिफिशेन ऑफ द अनटचेवल्स
5. थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट

मृत्यु – 6 दिसम्बर, 1956

अरविन्दो घोष
(Aurobindo Ghosh)

(1872 – 1950)

वास्तविक नाम – श्री अरविन्द (अरविन्द घोष)

जन्म – 15 अगस्त, 1872 ई. को

जन्म स्थान – कलकत्ता

पिता – कृष्णधन घोष

परिवार – समृद्ध घोष परिवार

शिक्षा – 1. प्रारम्भिक (इंग्लैंड में)
2. लेटिन, ग्रीक, फ्रेन्च, जर्मन, इटा-लियन एवं स्पेनिश भाषा का 7 वर्ष तक गहन अध्ययन
3. शास्त्रीय प्रावीण्य परीक्षा-कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से
4. आई. सी. एस. उत्तीर्ण

पत्र – युगान्तर कर्मयोगी, धर्म

पुस्तकें – 1. द लाइफ डिवाइन
2. द सिंथेसिस
3. द ह्यूमन सायकल
4. सावित्री
5. द फाउण्डेशन्स ऑफ इण्डियन कल्चर
6. द आइडियल ऑफ ह्युमन युनिटी
7. द फ्यूचर पोइट्री
8. एसेज ऑन द गीता

नारा – 1. पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ वेस ऑफ नेशन
2. राष्ट्रीयता एक धर्म है, जो भगवान के यहाँ से आता है.
3. वन्दे मातरम्

सार्वजनिक कार्य – 1. इंदुप्रकाश के लेखों से 1893 ई. में सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ किया
2. बंगाल विभाजन का विरोध करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया.

उल्लेखनीय कार्य – 1. बायकॉट, स्वदेशी के आधार पर संघर्ष कर राष्ट्रीय उल्लेख के रूप में कार्य किया.
2. अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धान्त से राष्ट्रवाद की जागृति का प्रयास.
3. कई बार जेल यात्रा

मृत्यु – 5 दिसम्बर, 1950 ई.

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(Dr. Rajendra Prasad)

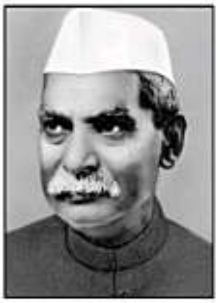

(1884 – 1963)

वास्तविक नाम – राजेन्द्र प्रसाद

जन्म – 3 दिसम्बर, 1884 ई. में

जन्म स्थान – सारन (उत्तरी बिहार)

पिता – महादेव प्रसाद

शिक्षा – 1. प्रारम्भिक शिक्षा (घर पर)
2. छपरा जिला स्कूल से हाईस्कूल
3. उच्च शिक्षा प्रेसीडेन्सी कॉलेज (सन् 1902 ई. में) कलकत्ता से

पुस्तकें – इण्डिया डिवाइडेड, सत्याग्रह इन चम्पारण, महात्मा गांधी एण्ड बिहार एट 'द' फीट ऑफ महात्मा गांधी

सार्वजनिक जीवन – 1. सन् 1916 ई. में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से राजनीति में प्रवेश
2. सन् 1916 ई. के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष
3. सुभाष चन्द्र बोस के इस्तीफे के बाद सन् 1939 ई. में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार की
4. सन् 1946 ई. में खाद्य एवं कृषि मंत्री
5. भारत के प्रथम राष्ट्रपति

मृत्यु – 28 फरवरी 1963 ई. में

आचार्य विनोबा भावे
(Acharaya Vinoba Bhave)

(1895 – 1982)

वास्तविक नाम – विनायक नरहरि भावे
प्रचलित नाम – विनोबा भावे
उपाधि – आचार्य
जन्म – 11 सितम्बर, 1895 ई. में
जन्म स्थान – गगोड़ा (महाराष्ट्र)
प्रभावित – अपनी माँ से
अध्ययन – 1. मैट्रिक्युलेशन (1913 ई. में बड़ौदा से)
2. हिन्दू स्क्रीपचर्स (बनारस से)
गुरु – महात्मा गांधी
सार्वजनिक जीवन – सन् 1916 ई. में गांधीजी से मुलाकात
उल्लेखनीय योगदान – 1. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय योगदान
2. दाण्डी मार्च (1930 ई. में) प्रथम सत्याग्रही (1940)
3. पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया.
4. स्वतन्त्रता के बाद भूदान आन्दोलन का आरम्भ किया.
मृत्यु – सन् 15 नवम्बर, 1982 ई. में

महात्मा ज्योतिबा फुले
(Mahatma Jyotiba Fule)

(1827 – 1890)

वास्तविक नाम – ज्योतिराव गोविन्दराव
प्रचलित नाम – महात्मा ज्योतिबा फुले
उपाधि – महात्मा, फुले
जन्म – सन् 1827 ई.
जन्म स्थान – पूना
प्रभाव – शिवाजी एवं वाशिंगटन का
शिक्षा – स्कोटिश मिशन स्कूल से
संस्था स्थापना – सत्य साधक समाज (1873 ई. में)
सार्वजनिक जीवन – 1. 1873 ई. से राजनीति में प्रवेश
2. पूना म्युनिसिपलिटी के सदस्य (1876 – 82 ई. तक) रहे.
उल्लेखनीय योगदान – 1. निम्न जाति वर्ग के लिए सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया.
2. महिला शिक्षा के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया.
3. हंटर कमीशन के साक्ष्य के रूप में
मृत्यु – 1890 ई. में

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर
(I. C. Vidyasagar)

(1826 – 1891)

वास्तविक नाम – ईश्वरचन्द्र विद्यासागर
जन्म – 26 सितम्बर, 1826 में
जन्म स्थान – बीरसिंघा (प. बंगाल)

परिवार – गरीब ब्राह्मण

शिक्षा – 1. संस्कृत साहित्य (संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता)
2. वेदान्त, स्मृति, न्याय, अलंकार ज्योतिष (1829-42 ई. तक)

संस्था – मेट्रोपोलिटेन कॉलेज (1864 ई. में)

पत्र – सोमप्रकाश

सार्वजनिक जीवन – सन् 1864 ई. में रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ इंग्लैण्ड की सदस्यता से सार्वजनिक जीवन की शुरूआत की.

उल्लेखनीय योगदान – 1. पुनर्विवाह, विधवा विवाह प्रचार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया
2. स्त्री शिक्षा का प्रचार किया
3. गरीब तबके को राष्ट्रीय आन्दोलन में लाने वाले महान् व्यक्तित्व के रूप में उभरकर सामने आये.

मृत्यु – 1891 ई. में

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
(Netaji Subhash Chandra Bose)

(1897 – 1945)

वास्तविक नाम – सुभाष चन्द्र बोस

उपाधि – नेताजी

जन्म – 23 जनवरी, 1897 ई. में

जन्म स्थान – कटक (उड़ीसा)

पिता – जानकी नाथ बोस

माता – प्रभावती देवी

भाई-बहिन – 14 भाई-बहिन थे

शिक्षा – 1. खेन्शा कोलेजिएट स्कूल से 1913 ई. में मैट्रिक्युलेशन (यूनिवर्सिटी में द्वितीय स्थान)
2. प्रेसीडेन्सी कॉलेज कलकत्ता से स्नातक
3. स्कोटिश चर्च कॉलेज से फिलोसफी में स्नातकोत्तर
4. आई. सी. एस. परीक्षा उत्तीर्ण (सन् 1922 ई. में इस्तीफा)
5. सन् 1914 ई. में सत्य की खोज में हिमालय प्रस्थान

संस्था – 1. फारवर्ड ब्लॉक
2. आजाद हिन्द फौज

नारा – 1. दिल्ली चलो
2. जयहिन्द
3. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा.

पुस्तकें – 1. इण्डियन स्ट्रगल
2. एन इण्डियन पिलिग्रम

सार्वजनिक जीवन – 1. सन् 1921 ई. में विदेश से लौटकर सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ किया
2. 16 जुलाई, 1921 को गांधीजी से भेंट कर स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भूमिका का प्रारम्भ किया.
3. 10 दिसम्बर, 1921 को गिरफ्तारी, 6 महीने की जेल
4. सन् 1923 ई. में बंगाल कांग्रेस कमेटी के मंत्री
5. 24 अक्टूबर, सन् 1924 को दूसरी बार गिरफ्तार माण्डले जेल में कारावास
6. सितम्बर, 1927 में अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बनाए गए.
7. सन् 1930 ई. में कलकत्ता के महापौर बने.
8. 13 फरवरी, 1933 ई. को नवीं बार जेल तथा यूरोप में निर्वासन
9. 19 फरवरी, 1938 को हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष
10. सन् 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष.
11. 29 अप्रैल, 1939 को गांधीजी एवं चन्द गांधीवादी लोगों के विरोध पर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा
12. 3 मई, 1939 को फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना
13. 22 जून, सन् 1940 को वीर सावरकर से भेंट
14. 2 जुलाई, 1940 को गिरफ्तार एवं घर में नजरबंद

पठान वेश में नेताजी अपने आवास से अंग्रेजों को चकमा देकर निकले

मेजोटा के रूप में सुभाष बोस

15. 17 जनवरी, 1941 को अंग्रेज सरकार को चकमा देकर वेश बदलकर भारत से प्रस्थान
16. 2 नवम्बर, 1941 को बर्लिन में आई. एन. ए. स्थापित
17. 24 अक्टूबर, 1943 को इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा
18. 6 अप्रैल, 1944 कोहिमा (नागालैंड) पर अधिकार

मृत्यु – 18 अगस्त, 1945 को फारमोसा के ताई हो कू विमान स्थल से उड़ान के दौरान (संभावित तथ्यों के आधार पर इसी दुर्घटना से मृत्यु मानी जाती है.)

राम प्रसाद बिस्मिल

(R. P. Bismil)

(1897 – 1927)

वास्तविक नाम – राम प्रसाद बिस्मिल

जन्म – 1897 ई. में

जन्म स्थान – शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश)

परिवार – साधारण ब्राह्मण परिवार

सहयोगी – अशफाक उल्ला खाँ

नारा – "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है."

प्रभाव – आर्य समाज एवं क्रान्तिकारियों का सर्वाधिक प्रभाव.

शिक्षा – प्रारम्भिक शिक्षा शाहजहाँपुर से प्राप्त की.

उल्लेखनीय योगदान – 1. क्रान्तिकारी राष्ट्रीयता को जाग्रत करने में सक्रिय भूमिका
2. मैनपुरी, काँकोरी काण्ड, असेम्बली बम काण्ड में सक्रिय भूमिका निभाई.

पुस्तक – आत्मकथा

मृत्यु – सन् 1927 ई. में मृत्युदण्ड, (ब्रिटिश सरकार द्वारा फाँसी)

रास बिहारी बोस[1]

(Rass Bihari Bose)

(1880 – 1945)

वास्तविक नाम – रास बिहारी बोस

जन्म – सन् 1880 ई. में

जन्म स्थान – बर्दवान

शिक्षा – 1. प्रारम्भिक शिक्षा बर्दवान में
2. स्नातक चन्देर नागौर से

सहयोगी – अमीरचन्द्र, अवध बिहारी, बालमुकुन्द, बसन्त विश्वास प्रमुख सहयोगी थे.

सार्वजनिक जीवन – 1. युगान्तर पार्टी की सदस्यता (1908) से सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ किया.
2. भारतीय स्वतन्त्र परिषद् में (1924) शामिल.
3. कैप्टन मोहन सिंह, सरदार प्रीतम सिंह के साथ आजाद हिन्द फौज को संगठित किया (1943 ई.)

विदेशी प्रवास – 1. सन् 1915 ई. में जापान
2. जापानी महिला से विवाह कर जापान की नागरिकता ग्रहण की

मृत्यु – 21 जनवरी, 1945 ई. को निधन

---

1 रास बिहारी बोस एवं डॉ. रास बिहारी घोष (अध्यक्ष–कांग्रेस के 23वें, 24वें अधिवेशन) दो अलग-अलग व्यक्ति थे. समान नाम से अधिकतर भ्रामकता पैदा हो जाती है. डॉ. रास बिहारी घोष का जन्म 1845 में एवं मृत्यु सन् 1921 में हुई थी.

शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
(Shekh Mohd. Abdullaha)

(1905 – 1982)

वास्तविक नाम – शेख मोहम्मद अब्दुल्ला

उपाधि – शेर-ए कश्मीर

जन्म – 5 दिसम्बर, 1905 ई. को

जन्म स्थान – सौरा (श्रीनगर)

परिवार – उद्योगपति मुसलमान

शिक्षा – 1. प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीनगर से प्राप्त की.
2. एम. एस. सी. (भौतिकी) सन् 1930 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से

प्रभाव – कवि इकबाल, मौलाना अब्दुल कलाम

सार्वजनिक जीवन – मुस्लिम कान्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में सन् 1932 से शुरूआत

मृत्यु – 7 सितम्बर, 1982 ई. को

जयप्रकाश नारायण
(J. P. Narayan)

(1902 – 1979)

वास्तविक नाम – जयप्रकाश नारायण

जन्म – 11 अक्टूबर, 1902 में

जन्म स्थान – सिताबदीयारा (बिहार)

परिवार – मध्यमवर्गीय कायस्थ परिवार

शिक्षा – 1. मैट्रिक्युलेशन (पटना कोलिजियेट स्कूल से)
2. उच्च शिक्षा (ओहियो यूनिवर्सिटी यू. एस. ए. से)

सार्वजनिक जीवन – 1. सन् 1929 ई. से श्रमिक कांग्रेस में शामिल
2. कांग्रेस सोशियलिस्ट पार्टी का 1934 में गठन किया

उल्लेखनीय योगदान – 1. सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1932) में सक्रिय योगदान
2. दो साल तक नासिक जेल में कैद
3. विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया

मृत्यु – 8 अक्टूबर, 1979 ई. को निधन

राजगुरु
(Rajguru)

(1908 – 1931)

वास्तविक नाम – शिवराम हरि राजगुरु

जन्म – सन् 1908 ई. में

जन्म स्थान – खेड़ (पूना)

परिवार – मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार

शिक्षा – प्रारम्भिक शिक्षा– वाराणसी से प्राप्त की

सहयोगी – चन्द्रशेखर, सरदार भगतसिंह, जतिन दास

सार्वजनिक जीवन – 17 दिसम्बर, 1928 ई. को क्रान्तिकारी अतिवादी स्वभाववश साइमन कमीशन अधिकारी सांडर्स की हत्या

मृत्यु – सरदार भगत सिंह एवं सुखदेव के साथ 23 मार्च, 1931 ई. को फाँसी दे दी गई.

मैडम भीकाजी कामां (Madame Bhikaji Kaman)

(1861 – 1936)

वास्तविक नाम – भीकाजी रूस्तम कामां

जन्म – 24 सितम्बर, 1861 ई. को

जन्म स्थान – बम्बई

परिवार – व्यावसायिक समृद्ध पारसी परिवार

पति – रूस्तम जी कामां

शिक्षा – प्रारम्भिक शिक्षा एलेक्जेंडर गर्ल्स स्कूल से

विदेशी प्रवास – लन्दन, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैण्ड, यू. एस. ए, पेरिस इत्यादि की यात्रा की.

सहयोगी – दादाभाई नौरोजी, विपिनचन्द्र पाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर इत्यादि.

सार्वजनिक जीवन –
1. वर्ष 1902 से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश
2. स्टट गार्ड में सोशियलिस्ट कांग्रेस की सदस्यता (1907) ग्रहण की
3. विदेश में भारत का राष्ट्रध्वज फहराने वाली एकमात्र महिला

मृत्यु – 1936 ई. में निधन

मोरारजी देसाई (Morarji Desai)

(1896 – 1995)

वास्तविक नाम – मोरारजी देसाई

जन्म – 29 फरवरी, 1896 ई.

जन्म स्थान – बूलसर (गुजरात)

शिक्षा – विल्सन कॉलेज बम्बई से स्नातक

पुस्तक –
1. इन माई व्यु
2. ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ

सार्वजनिक जीवन –
1. सविनय अवज्ञा आन्दोलन से (1930 से) सार्वजनिक जीवन में प्रवेश
2. बम्बई विधान परिषद में सन् 1937 ई. में चयन
3. 1937 में राजस्व एवं वनमंत्री
4. 1946 में बम्बई विधान परिषद् के लिए निर्वाचित
5. 1946 से 1952 तक गृह एवं राजस्व-मंत्री
6. 1952 से 1956 तक बम्बई के मुख्यमंत्री
7. सन् 1956 ई. में वित्तमंत्री, सन् 1958 ई. में उद्योग-मंत्री, 1966-67 में प्रशासन सुधार समिति के चेयर-मैन, मार्च 1977 में भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने.

मृत्यु – 10 अप्रैल, 1995 ई.

लाला हरदयाल (Lala Hardayal)

(1884 – 1939)

वास्तविक नाम – लाला हरदयाल

जन्म – सन् 1884 ई. में

जन्म स्थान – दिल्ली

परिवार – निम्न मध्यमवर्गीय कायस्थ परिवार

शिक्षा –
1. एम. ए. (इतिहास और अंग्रेजी में) पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से
2. सरकारी छात्रवृत्ति से ऑक्सफोर्ड एवं लन्दन विश्वविद्यालय से (1905) उच्च शिक्षा.

संस्था – गदर पार्टी (अमरीका)

पत्र – गदर, वन्दे मातरम्

विदेशी प्रवास – जर्मनी, स्वीडन, अमरीका (1927) की विदेश यात्रा

सहयोगी – श्यामजी कृष्ण वर्मा, वी. डी. सावरकर, मैडम भीकाजी कामां

पुस्तक – हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर

मृत्यु – सन् 1939 ई. में देहावसान

जमना लाल बजाज (J. L. Bajaj)

(1889 – 1942)

वास्तविक नाम – जमना लाल बजाज

जन्म – नवम्बर, 1889 ई. में

जन्म स्थान – जयपुर

पिता – सेठ बच्छराज के दत्तक पुत्र

सार्वजनिक जीवन – 1. नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के रिशेप्सन समिति के चेयरमैन से सार्वजनिक जीवन की शुरूआत की
2. महात्मा गांधी के सभी आन्दोलन सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, होमरूल लीग में सक्रिय योगदान
3. हरिजन उत्थान के लिए गांधीजी को पूर्ण सहयोग दिया

मृत्यु – 11 फरवरी, 1942 ई. में

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (Dr. Shyama P. Mukherji)

(1901 – 1953)

वास्तविक नाम – श्यामा प्रसाद मुखर्जी

जन्म – 6 जुलाई, 1901 ई. में

जन्म स्थान – कलकत्ता

पिता – आशुतोष मुखर्जी

शिक्षा – बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी कलकत्ता से

सार्वजनिक जीवन – 1. सन् 1929 ई. में बंगाल विधान परिषद् में निर्वाचित
2. सन् 1939 ई. में हिन्दू महासभा में शामिल
3. सन् 1937 ई. में बंगाल विधान परिषद् में पुनः निर्वाचित
4. स्वतन्त्र भारत के उद्योग मंत्री

संस्था स्थापना – भारतीय जनसंघ (1951 ई.) की स्थापना

उल्लेखनीय योगदान – 1. पंजाब व बिहार के आधे हिस्से को विभाजन से रोका
2. पाकिस्तान विभाजन की नेहरू नीति से क्षुब्ध होकर आन्दोलन किया

मृत्यु – मई 1953 श्रीनगर जेल में (उल्लेखनीय- कश्मीर को विघटन से रोकने के कारण गिरफ्तारी हुई थी.)

सुभद्रा कुमारी चौहान (Subhadra Kumari Chauhan)

(1904 – 1948)

वास्तविक नाम – सुभद्रा कुमारी चौहान

जन्म – सन् 1904 ई. में

जन्म स्थान – निहालपुर (इलाहाबाद)

पति – ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान

शिक्षा – इलाहाबाद से

प्रभाव – महात्मा भगवानदीन, माखनलाल चतुर्वेदी का प्रभाव

पुस्तकें – झाँसी की रानी, मुकुल, बिखरे मोती

सार्वजनिक जीवन	–	1. असहयोग आन्दोलन से सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ
		2. सन् 1940 और 1942 में जेल यात्रा
		3. सी. पी. असेम्बली में 1936 एवं 1946 ई. में निर्वाचित
मृत्यु	–	15 फरवरी, 1948 ई. में (कार दुर्घटना में)

अब्दुल गफ्फार खाँ

(Abdul Gaffar Khan)

(1890 – 1988)

वास्तविक नाम	–	खान अब्दुल गफ्फार खाँ
जन्म	–	सन् 1890 ई. में
जन्म स्थान	–	उत्तामंजथी (पश्चिमी पाकिस्तान) में
प्रसिद्ध नाम	–	सीमान्त गांधी
शिक्षा	–	मुस्लिम स्कूल पेशावर से प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की
प्रभाव	–	मौलाना अबुल कलाम का प्रभाव
संस्था	–	खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती आन्दोलन की स्थापना
सार्वजनिक जीवन	–	1. रौलट एक्ट के विरुद्ध 1919 से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश
		2. कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सक्रिय भूमिका निभाई
		3. खिलाफत आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया.
		4. सन् 1921 से 1924 ई. तक जेल यात्रा
सम्मान	–	सन् 1987 में भारत रत्न से सम्मानित
मृत्यु	–	सन् 1988 ई. में देहावसान

वासुदेव पन्त चापेकर

(Vasudev Pant Chapekar)

(1879 – 1899)

वास्तविक नाम	–	वासुदेव पन्त चापेकर
जन्म	–	1879 ई. में
जन्म स्थान	–	चिन्चवड (पूना)
पिता	–	हरिपन्त चापेकर
विशेष	–	एक परिवार के तीन क्रान्तिकारी अमर शहीद भाइयों में से सबसे बड़े.
सार्वजनिक जीवन	–	1. सन् 1886 ई. के प्लेग एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित राष्ट्र को न देख पा सकने की स्थिति में पुलिस ऑफिसर राण्ड को मार देने से सार्वजनिक रूप से सामने आये.
		2. अंग्रेजों के सहायक गणेश शंकर द्रविड की हत्या.
मृत्यु	–	8 मई, 1899 को मात्र 20 वर्ष की उम्र में फाँसी दी गई.

बालकृष्ण पन्त चापेकर

(Balkrishna Pant Chapekar)

(1873 – 1899)

वास्तविक नाम	–	बालकृष्ण पन्त चापेकर
जन्म	–	1873 ई. में

जन्म स्थान	–	चिन्चवड (पूना)
पिता	–	हरिपन्त चापेकर
परिवार	–	कोंकण से आया चितपावन ब्राह्मण परिवार
उल्लेखनीय योगदान	–	भारतीयों को प्लेग एवं अकाल से बचाने के लिए ऑफिसर राण्ड की हत्या में अपने बड़े भाई को सहयोग दिया
मृत्यु	–	9 फरवरी, 1899 ई. को अंग्रेज सरकार द्वारा फाँसी की सजा

दामोदर पन्त चापेकर
(Damodar Pant Chapekar)'

(1870 – 1898)

वास्तविक नाम	–	दामोदर पन्त चापेकर
जन्म	–	1870 ई. में
जन्म स्थान	–	चिन्चवड (पूना)
पिता	–	हरिपन्त चापेकर
परिवार	–	आध्यात्मिक परिवार
शिक्षा	–	प्रारम्भिक शिक्षा गाँव से प्राप्त की
उल्लेखनीय कार्य	–	पूना में पदस्थापित पुलिस अधिकारी राण्ड एवं उनके सहयोगी लै. आयर्स्ट की हत्या, भारतीयों को बीमारी एवं अकाल की स्थिति में सहायता नहीं करने के कारण मारा गया.
पुस्तक	–	आत्मकथा
मृत्यु	–	18 अप्रैल, 1898 ई. को अंग्रेजी सरकार द्वारा फाँसी दी गई.

पण्डित मदन मोहन मालवीय
(Pt. M. M. Malviya)

(1861 – 1946)

वास्तविक नाम	–	मदन मोहन मालवीय
उपाधि	–	पण्डित
जन्म	–	27 दिसम्बर, 1861 ई. को
माता	–	श्रीमती मूना देवी
पिता	–	श्री बृजनाथ
परिवार	–	शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक ब्राह्मण
शिक्षा	–	1. धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला से प्रारम्भिक शिक्षा 2. विद्या-धर्म प्रवर्द्धिनी स्कूल से उच्च शिक्षा
सार्वजनिक जीवन	–	1. सन् 1902 में संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद् के लिए निर्वाचित 2. कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (1909 ई.) एवं दिल्ली अधिवेशन (1918 ई.) में कांग्रेस के अध्यक्ष 3. सन् 1910 से 1920 तक केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे 4. सन् 1934 ई. में साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध किया
पत्र/पत्रिकाएं	–	लीडर, हिन्दुस्तान, अभ्युदय
विदेशी प्रवास	–	द्वितीय गोलमेज के समय लन्दन गए.
उल्लेखनीय कार्य	–	सन् 1918 ई. में बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय की स्थापना[1]
मृत्यु	–	1946 ई. में निधन.

---

1 बी. एच. यू. के प्रोस्पेक्टस एवं अन्य आधार पर स्थापना वर्ष 1916 माना जाता है.

लाल बहादुर शास्त्री
(Lal Bahadur Shastri)

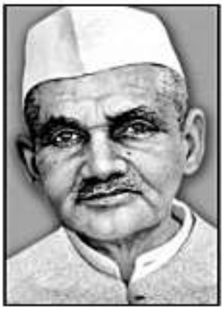

(1904 – 1966)

वास्तविक नाम – लाल बहादुर शास्त्री
जन्म – 2 अक्टूबर, 1904 ई. में
जन्म स्थान – मुगलसराय
सार्वजनिक जीवन – 1. सन् 1921 में राष्ट्रीय आन्दोलन में पदार्पण.
2. सन् 1951 में कांग्रेस के महामंत्री
3. भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रसेवा की
उल्लेखनीय कार्य – सन् 1965 ई. में भारत-पाक युद्ध में भारत को विजय दिलाने में भूमिका का निर्वहन किया.
नारा – जय जवान, जय किसान
मृत्यु – 11 जनवरी, 1966 ई. में ताशकंद (रूस) में निधन

मोतीलाल नेहरू
(Moti Lal Nehru)

(1861 – 1931)

वास्तविक नाम – मोतीलाल नेहरू
जन्म – 1861 ई. में
परिवार – कश्मीरी ब्राह्मण परिवार
सार्वजनिक जीवन – 1. स्वदेशी आन्दोलन से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश
2. अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन (1919) एवं कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन (1928) के अध्यक्ष
3. सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930) में सक्रिय भूमिका निभाई
संस्था – स्वराज दल (चितरंजन दास सहयोगी)
पुस्तक – द वॉयस ऑफ फ्रीडम
पत्र – इण्डिपेन्डेन्ट
उल्लेखनीय योगदान – 1. साइमन कमीशन का विरोध
2. आधुनिक संविधान के 'ब्लूप्रिन्ट' के निर्माता
मृत्यु – 1931 ई. में

डॉ. एस. राधाकृष्णन्
(Dr. S. Radha Krishnan)

(1888 – 1975)

वास्तविक नाम – सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
जन्म – 5 सितम्बर, 1888 ई. में
पुस्तकें – 1. हिन्दू व्यु ऑफ लाईफ
2. रिलिजन एवं सोसायटी
3. रिलिजन एण्ड कल्चर
4. इण्डियन फिलोसफी
5. ईस्ट एण्ड वेस्ट इन रिलीजन
6. आइडियलोजिस्ट व्यू ऑफ लाइफ
उल्लेखनीय योगदान – 1. भारत के उपराष्ट्रपति (1952–62) एवं राष्ट्रपति (1962-67) के रूप में राष्ट्र सेवा में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया.
2. शिक्षा का प्रसार उल्लेखनीय तरीके से किया.
पुरस्कार – 1. टेम्प्लेटन फाउण्डेशन पुरस्कार (1974) में प्राप्त किया.
2. भारत रत्न (1954) से विभूषित
मृत्यु – 1975 ई. में

मोहम्मद अली जिन्ना
(Mohd. Ali Jinna)

(1876 – 1948)

वास्तविक नाम – मोहम्मद अली जिन्ना
जन्म – 1876 ई. में
समाचार पत्र – 1. कामरेड 2. हमदर्द
सार्वजनिक जीवन – भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया.
सिद्धान्त – द्विराष्ट्र सिद्धान्त के समर्थक
मृत्यु – 1948 ई. में

बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय
(Bankim Chandra Chattopadhya)

(1838 – 1894)

वास्तविक नाम – बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय
जन्म – सन् 1838 ई. में
परिवार – समृद्ध ब्राह्मण परिवार
पुस्तकें – 1. कपाल कुण्डला
2. रजनी
3. चन्द्रशेखर
4. आनन्द मठ
5. दुर्गेशनन्दिनी
6. मृणालिनी
उल्लेखनीय योगदान – 1. राष्ट्रवादी पुस्तकों के लेखन के माध्यम से राष्ट्रीयता का प्रसार
2. आनन्द मठ के उपन्यासकार
3. वन्देमातरम् के रचयिता
मृत्यु – 1894 ई. में निधन

सी. राजगोपालाचारी
(C. Raj Gopalachari)

(1879 – 1972)

वास्तविक नाम – राजगोपालाचारी
उपाधि – चक्रवर्ती
प्रसिद्ध उपनाम – आधुनिक भारत के चाणक्य के नाम से विख्यात
पुस्तकें – 1. सभी गोल्डन ग्रेस वर्ल्ड ऑफ टाइम
2. रिलीजन एण्ड कल्चर
3. नेशन्स वायरस
4. रिकान्सिलियेशन
सार्वजनिक जीवन – 1. सभी स्वतन्त्रता आन्दोलनों में सक्रिय योगदान
2. स्वतन्त्र भारत के प्रथम एवं अन्तिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में राष्ट्रसेवा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया.
3. मद्रास के मुख्यमंत्री एवं स्वतन्त्र पार्टी के संस्थापक
4. भारत रत्न से सम्मानित (1954)
मृत्यु – सन् 1972 ई. में

श्यामजी कृष्ण वर्मा
(Shyamji Krishna Verma)

(1857 – 1930)

वास्तविक नाम – श्यामजी कृष्ण वर्मा
जन्म – 1857 ई. में

जन्म स्थान – काठियावाड़

शिक्षा – कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की. बैरिस्टर का पदभार ग्रहण किया.

सार्वजनिक जीवन – अंग्रेज पॉलिटिकल रेजीडेन्ट से परेशान होकर लन्दन में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का प्रतिनिधित्व किया.

संस्था स्थापना – 1. भारतीय स्वशासन या इण्डिया हाउस की स्थापना1905 ई. में की.
2. सन् 1905 ई. में इंगलैण्ड में होमरूल सोसायटी की स्थापना की.

पत्रिका – India Sociologist

सहयोगी – वी. डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धींगरा.

विदेशी प्रवास – इंग्लैण्ड, पेरिस, जेनेवा

मृत्यु – 30 मार्च, 1930 ई. में

सरदार ऊधमसिंह
(Sardar Udham Singh)

(1898 – 1940)

वास्तविक नाम – राम मोहम्मद सिंह आजाद

प्रसिद्ध नाम – ऊधमसिंह

जन्म – 28 दिसम्बर, 1899 ई. में

जन्म स्थान – सुनाम (पंजाब के संगरूर जिले में)

पिता – सरदार टहल सिंह

प्रारम्भिक शिक्षा – 1. पंजाबी, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया. (अमृतसर के पुतलीघर अनाथालय से)
2. लन्दन में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया.

विदेशी प्रवास – (i) दक्षिण अफ्रीका
(ii) अमरीका
(iii) इंग्लैण्ड (1923 ई. में)
(iv) जर्मनी
(v) बर्लिन
(vi) लन्दन

सहयोगी – भगतसिंह

जेल – सन् 1928 ई. में आयुध अधिनियम के उल्लंघन में 4 वर्ष की सजा

छद्म नाम – उदयसिंह, शेरसिंह, फ्रेंक बारजिक, राम मोहम्मद सिंह आजाद

अतिवादी आचरण – 31 मार्च, सन् 1940 ई. को जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड के प्रमुख आरोपी माइकेल-ओ डायर को कैक्सटन-हॉल में मार दिया.

प्रसिद्ध कथन – 'मेरा नाम ऊधमसिंह नहीं है, मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है. राम हिन्दू, मोहम्मद मुसलमान, सिंह सिख और आजाद का अर्थ है–भारत की आजादी.

मृत्यु – 31 जुलाई, 1940 ई. को फाँसी दे दी गई (लन्दन में)

मदनलाल धींगरा
(Madan Lal Dhingra)

(1887 – 1909)

वास्तविक नाम – मदनलाल धींगरा

जन्म स्थल – अमृतसर (पंजाब)

परिवार – सम्पन्न खत्री परिवार

जन्म – 1887 ई. में

शिक्षा – 1. बी. ए. (पंजाब विश्वविद्यालय से)
2. उच्च शिक्षा (इंग्लैण्ड से)

सहयोगी – वीर सावरकर

गुरु – वीर सावरकर

अतिवादी कृत्य – 1 जुलाई, 1909 ई. को लॉर्ड मार्ले के राजनीतिक अंगरक्षक सर कर्जन वायली को एवं कावसजी लालम्का नामक भारतीय पारसी युवक को रिवाल्वर से मार दिया.

प्रसिद्ध वक्तव्य – ''हिन्दू होने के नाते मैं यह विश्वास करता हूँ कि मेरे देश के प्रति किया गया अपराध ईश्वर का अपमान है. मेरी

मातृभूमि का कार्य ही भगवान राम का कार्य है. मातृभूमि की सेवा ही भगवान श्रीकृष्ण की सेवा है. मुझ जैसे धनहीन और बुद्धिहीन व्यक्ति के पास अपने रक्त के अतिरिक्त मातृभूमि को समर्पित करने हेतु और क्या था? इसी कारण मैं मातृभूमि पर अपनी रक्तांजलि अर्पित कर रहा हूँ."

मृत्यु – 17 अगस्त, 1909 ई. को फाँसी की सजा दी गई.

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
(Surendra Nath Benarji)

(1848 – 1925)

वास्तविक नाम – सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

जन्म – 10 नवम्बर, 1848 ई. में

जन्म स्थान – कलकत्ता

शिक्षा –
1. स्नातक (कलकत्ता विश्वविद्यालय) से 1868 ई. में
2. भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा लन्दन से 1869 में उत्तीर्ण की.

सार्वजनिक जीवन –
1. उम्राधिक्य के कारण सिविल सेवा से निकाला गया, लेकिन कोर्ट के निर्णय से 1871 में सिलहट के सहायक मजिस्ट्रेट बने.
2. ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दोषारोपण कर जून 1875 ई. में सेवा से पदच्युत कर दिया गया.
3. मेट्रोपोलिटेन इन्स्टीट्यूट, फ्री चर्च कॉलेज एवं रिपन कॉलेज में अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में कार्य किया.

स्थापित संस्थाएं –
1. रिपन कॉलेज 1882 ई. में (वर्तमान में सुरेन्द्रनाथ कॉलेज)
2. इण्डियन एसोसिएशन (26 जुलाई, 1876 ई. को)

उपनाम – 'भारत के ग्लेडस्टन'

राजनीतिक जीवन –
1. 1876 से 1899 ई. तक कलकत्ता नगर निगम के सदस्य रहे.
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूना अधिवेशन (1895 ई.) एवं अहमदाबाद (1902 ई.) अधिवेशन के अध्यक्ष रहे.
3. 1894, 1896, 1898 एवं 1900 ई. में बंगाल की व्यवस्थापिका परिषद् के सदस्य रहे.
4. 1918 ई. में लिबरल पार्टी की स्थापना की.

राष्ट्रीय योगदान – स्वदेशी आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया.

समाचार-पत्र – बंगाली

विचारधारा –
1. ब्रिटिश शासन को दैवीय सत्ता मानते थे.
2. अंग्रेजों द्वारा सम्पादित कार्य एवं अंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान स्वीकार करते थे.
3. 'उदारवादी विचारधारा के स्तम्भ' के नाम से जाने जाते थे.

अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान –
1. नाईट की उपाधि प्रदान की गई.
2. 1919 में बंगाल सरकार के ब्रिटिश सत्ता के अधीन मंत्री बनाये गये.

मृत्यु – 4 अगस्त, 1925 ई. को निधन.

10

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन : सिंहावलोकन

(1885 से 1964 तक)

स्थापना वर्ष एवं प्रथम अधिवेशन

ए. ओ. ह्यूम

स्थापना	–	28 दिसम्बर, 1885 ई. में
संस्थापक	–	ए. ओ. ह्यूम (भारत सरकार के अवकाश प्राप्त सचिव)
स्थापना स्थल	–	गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, बम्बई
प्रथम अध्यक्ष	–	(उमेश) व्योमेश चन्द्र बनर्जी

उमेश (व्योमेश) चन्द्र बनर्जी

प्रथम अधिवेशन के प्रमुख सदस्य गण	–	(1) फीरोजशाह मेहता, (2) दादा भाई नौरोजी, (3) दीनशा एदलची वाचा, (4) वी. राघवाचारी, (5) काशीना तैलंग (6) एन. जी. चन्द्रावरकर (7) एस. सुब्रह्मण्यम
शब्द 'कांग्रेस' का चयन	–	उत्तरी अमरीका के इतिहास से कांग्रेस शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ 'लोगों का समूह' होता है.
स्थापना के प्रारम्भ के दौरान वायसराय–		लॉर्ड डफरिन
स्थापना के लिए प्रेरक	–	डब्ल्यू वेडरबर्न
प्रमुख सहयोगी	–	दादा भाई नौरोजी, एम. जी. रानाडे, फीरोजशाह मेहता एवं विलियम वेडरबर्न
स्थापना की प्रथम घोषणा	–	'हिन्दू' पत्रिका में 5 दिसम्बर, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की घोषणा.
कुल प्रतिनिधि	–	72
कांग्रेस के उद्देश्य (प्रथम अधिवेशन में उल्लिखित)	–	(1) देश के हित एवं उन्नति में लगे सभी व्यक्तियों के मध्य व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं मैत्री भाव को विकसित करना. (2) जाति, धर्म एवं क्षेत्रीयता से परे समस्त विभेदों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना. (3) सामाजिक एवं राजनीतिक मसलों पर शिक्षित वर्ग के मतों को प्रकट करना. (4) आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना.
प्रथम माँग (ब्रिटिश सरकार से)	–	विधान परिषदों में सुधार कर उनमें भारतीय जनता को अधिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाए
प्रमुख नारा	–	बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं (No Taxation without representation)
प्रस्ताव पारित कर ब्रिटिश सरकार से की गई माँगे	–	(1) भारतीय शासन की जाँच के लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए. (2) इंग्लैण्ड में कार्य कर रही 'इण्डिया कॉउन्सिल' को समाप्त किया जाए. (3) केन्द्रीय एवं प्रान्तीय व्यवस्थापिका में विस्तार किया जाए. परिषद् में मनोनीत सदस्यों की जगह पर निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल किए जाएं.

(4) आई. सी. एस. की परीक्षा भारत एवं इंग्लैण्ड दोनों स्थानों पर की जाए एवं अधिकतम उम्र सीमा 19 से 23 वर्ष की जाए.

(5) सैन्य व्यय में कमी की जाए.

(6) इंग्लैण्ड से आयात किए गए कपड़ों पर आयात कर लगाया जाए.

(7) बर्मा को अलग किया जाए.

(8) इन सभी प्रस्तावों को सभी प्रदेशों की राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए.

इण्डियन नेशनल कांग्रेस

नाम रखने के परामर्शी – दादा भाई नौरोजी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : द्वितीय अधिवेशन

दादा भाई नौरोजी

आयोजना – कलकत्ता में

आयोजन वर्ष – 1886 ई.

अधिवेशन के अध्यक्ष – दादा भाई नौरोजी.

स्वागताध्यक्ष – डॉ. राजेन्द्र मित्र

महामन्त्री – ए. ओ. ह्यूम

उपस्थित प्रतिनिधि – 406

उल्लेखनीय तथ्य – (1) कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 28 दिसम्बर, 1886 में कलकत्ता में प्रारम्भ हुआ.

(2) इस अधिवेशन के प्रतिनिधि संस्थाओं और सार्वजनिक सभाओं द्वारा चुने गए थे.

(3) इस अधिवेशन में कुल 15 प्रस्ताव हुए थे.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : तृतीय अधिवेशन

आयोजना – मद्रास में

आयोजन वर्ष – 1887 ई.

अधिवेशन के अध्यक्ष – सैय्यद बदरुद्दीन तैयवजी

स्वागताध्यक्ष – राजा सर टी. माधवराव

महामन्त्री – ए. ओ. ह्यूम

बदरुद्दीन तैयबजी

उपस्थित प्रतिनिधि – 607

उल्लेखनीय तथ्य – इस अधिवेशन में कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिनमें प्रमुख थे–

(1) प्रथम प्रस्ताव के तहत कांग्रेस की कार्य-प्रणाली एवं पद्धति सम्बन्धी नियमों की रचना के लिए समिति का गठन किया गया.

(2) 9वें प्रस्ताव के तहत प्रस्तावित कमेटी का निर्वाचन हुआ.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : चतुर्थ अधिवेशन

जॉर्ज यूल

आयोजना – इलाहाबाद में

आयोजन वर्ष – 1888 ई.

अधिवेशन के अध्यक्ष – जॉर्ज यूल

स्वागताध्यक्ष – पण्डित अयोध्यानाथ

महामन्त्री – ए. ओ. ह्यूम

उपस्थित प्रतिनिधि – 1248

उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन में 30 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया.

(2) इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे, इस आशय का फरमान शेख रजा हुसैन खाँ ने जारी किया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : पाँचवाँ अधिवेशन

आयोजना – बम्बई में

आयोजन वर्ष – 1889 ई.

अधिवेशन के अध्यक्ष – सर विलियम वेडरबर्न

सर विलियम वेडरबर्न

स्वागताध्यक्ष – सर फीरोजशाह मेहता

महामन्त्री – ए. ओ. ह्यूम

उपस्थित प्रतिनिधि – 1889

उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन में इंग्लैण्ड की पार्लियामेन्ट के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला ने भाग लिया.

(2) इस अधिवेशन में 15 प्रस्ताव पारित हुए, जिनमें अधिकांश कॉउन्सिल के सुधार, न्याय और प्रशासन के पृथक्करण, उच्च सरकारी नौकरियों की परीक्षा भारत में आयोजित करने से सम्बन्धित थे.

(3) एक प्रस्ताव के अनुसार मालगुजारी का स्थायी बन्दोबस्त करने के लिए सरकार से कहा गया.

(4) प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर निश्चित किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी में 5 प्रतिनिधि चुने जाएं.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : छठा अधिवेशन

सर फीरोजशाह मेहता

आयोजना – कलकत्ता में

आयोजन वर्ष – 1890 ई.

अधिवेशन के अध्यक्ष – सर फीरोजशाह मेहता

स्वागताध्यक्ष – मनमोहन घोष

महामन्त्री – पं. अयोध्यानाथ, ए. ओ. ह्यूम

उपस्थित प्रतिनिधि – 677

उल्लेखनीय तथ्य – इस अधिवेशन में 15 प्रस्ताव पारित किए गए.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : सातवाँ अधिवेशन

पी. आनन्द चार्लू

आयोजना – नागपुर में

आयोजन वर्ष – 1891 ई.

अधिवेशन के अध्यक्ष – पी. आनन्द चार्लू

स्वागताध्यक्ष – सी. नारायण स्वामी नायडू

महामन्त्री – ए. ओ. ह्यूम, पं. अयोध्यानाथ

उपस्थित प्रतिनिधि – 812

उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन में 18 प्रस्ताव पारित किए गए.

(2) इस अधिवेशन में ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी के लिए 40 हजार और कांग्रेस महामन्त्री के लिए 6 हजार रुपए खर्च की व्यवस्था की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : आठवाँ अधिवेशन

आयोजना – इलाहाबाद में

आयोजन वर्ष – 1892 ई.

अधिवेशन के अध्यक्ष – उमेश (व्योमेश) चन्द्र बनर्जी

स्वागताध्यक्ष – पं. विश्वम्भर नाथ

महामन्त्री – ए. ओ. ह्यूम, पं. आनन्द चार्लू

उपस्थित प्रतिनिधि – 625

उल्लेखनीय तथ्य – (1) आठवें अधिवेशन में 22 प्रस्ताव पारित किए गए.

(2) पं. आनन्द चार्लू को पं. अयोध्यानाथ की मृत्यु हो जाने के कारण महामन्त्री नियुक्त किया गया.

(3) पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर कांग्रेस ने हाउस ऑफ कॉमन्स को विरोध-पत्र भेजा.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : नवाँ अधिवेशन

आयोजना – लाहौर में

आयोजन वर्ष – 1893 ई.

अधिवेशन के अध्यक्ष – दादा भाई नौरोजी

स्वागताध्यक्ष – सरदार दयाल सिंह मजीठिया
महामन्त्री – ए. ओ. ह्यूम
उपस्थित प्रतिनिधि – 625
उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन में 23 प्रस्ताव पारित किए गए.
(2) इस अधिवेशन में 'प्रतिवाद' शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ.
(3) एक प्रस्ताव में पंजाब में हाईकोर्ट की माँग की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : दसवाँ अधिवेशन

अल्फ्रेड वेब

आयोजना – मद्रास में
आयोजन वर्ष – 1894 ई.
अधिवेशन के अध्यक्ष – अल्फ्रेड वेब (ब्रिटिश संसद का आयरिश सदस्य)
स्वागताध्यक्ष – पी. रंगैया नायडू
महामन्त्री – ए. ओ. ह्यूम
उपस्थित प्रतिनिधि – 1163
उल्लेखनीय तथ्य – कुल 27 प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किए गए.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : ग्यारहवाँ अधिवेशन

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

आयोजना – पूना में
आयोजन वर्ष – 1895 ई.
अधिवेशन के अध्यक्ष – सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
स्वागताध्यक्ष – वी. एम. भिण्डे
महामन्त्री – ए.ओ. ह्यूम, डी.ई. वाचा
उपस्थित प्रतिनिधि – 1584
उल्लेखनीय तथ्य – (1) ग्यारहवें अधिवेशन में कुल 26 प्रस्ताव पारित किए गए.
(2) एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें दक्षिण अफ्रीका स्थित प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा पर विरोध प्रकट किया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : बारहवाँ अधिवेशन

मोहम्मद रहीम तुल्ला सयानी

आयोजना – 1896 ई. में
आयोजन स्थल – कलकत्ता
अध्यक्ष – मोहम्मद रहीम तुल्ला सयानी
स्वागताध्यक्ष – सर रमेश चन्द्र मिश्र
महामन्त्री – ए. ओ. ह्यूम, डी. ई. वाचा
उपस्थित प्रतिनिधि – 784
उल्लेखनीय तथ्य – (1) पहली बार असम के चाय बागानों के कुलियों की दुरावस्था पर विचार किया गया.
(2) देशी राज्यों के सम्बन्ध में कांग्रेस ने अपना मत प्रकट किया.
(3) एक प्रस्ताव में यह कहा गया कि देशी नरेश को ब्रिटिश सरकार द्वारा खुली अदालत में अयोग्य प्रमाणित न होने तक गद्दी से न उतारा जाए.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : तेरहवाँ अधिवेशन

सी. शंकरन नायर

आयोजना – 1897 ई. में
आयोजन स्थल – अमरावती

अध्यक्ष	– सी. शंकरन नायर
स्वागताध्यक्ष	– गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे
महामन्त्री	– ए. ओ. ह्यूम, डी. ई. वाचा
उपस्थित प्रतिनिधि	– 692
उल्लेखनीय तथ्य	– (1) 13वें अधिवेशन में कुल 21 प्रस्ताव पारित हुए. (2) प्रथम प्रस्ताव में सरकार की पश्चिमोत्तर नीति की निन्दा करते हुए कहा गया कि सैनिक अभियानों का खर्च भारत पर न डाला जाए. (3) पूना में फैले प्लेग और प्रशासन के अत्याचारों का विरोध किया गया. (4) लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी पर सरकार द्वारा उन्हें छोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, जो पारित न हो सका.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : चौदहवाँ अधिवेशन

आनन्द मोहन बोस

आयोजना	– 1898 ई. में
आयोजन स्थल	– मद्रास
अध्यक्ष	– आनन्द मोहन बोस
स्वागताध्यक्ष	– एन. सुब्बाराव पंतुलु
महामन्त्री	– ए. ओ. ह्यूम, डी. ई. वाचा
उपस्थित प्रतिनिधि	– 614
उल्लेखनीय तथ्य	– (1) कांग्रेस के इस अधिवेशन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन बनकर आए थे. (2) दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के प्रति किए जा रहे दुर्व्यवहार और समाचार-पत्रों की स्वाधीनता तथा भाषणों के प्रतिबन्धक कानूनों के प्रति खेद प्रस्ताव रखे गए. (3) इस अधिवेशन में कांग्रेस महासभा ने अपनी प्रान्तिक स्थानीय कमेटियों से अपने-अपने सूबे में केन्द्रीय कमेटियाँ भी स्थापित करने को कहा.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : पन्द्रहवाँ अधिवेशन

रमेश चन्द्र दत्त

आयोजना	– 1899 ई. में
आयोजन स्थल	– लखनऊ में
अध्यक्ष	– रमेश चन्द्र दत्त
स्वागताध्यक्ष	– बंशीलाल सिंह
महामन्त्री	– ए. ओ. ह्यूम, डी. ई. वाचा
उपस्थित प्रतिनिधि	– 789
उल्लेखनीय तथ्य	– (1) पन्द्रहवें अधिवेशन में कुल 21 प्रस्ताव पारित किए गए. (2) एक नियमावली स्वीकृत की गई जिसका उद्देश्य वैध उपायों द्वारा भारतीय साम्राज्य के लोगों के हितों की वृद्धि करना निर्धारित किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : सोलहवाँ अधिवेशन

एन. जी. चन्द्रावरकर

आयोजना	– 1900 ई. में
आयोजन स्थल	– लाहौर
अध्यक्ष	– एन. जी. चन्द्रावरकर
स्वागताध्यक्ष	– राम काली प्रसन्नराय बहादुर
महामन्त्री	– ए. ओ. ह्यूम, डी. ई. वाचा
उपस्थित प्रतिनिधि	– 567
उल्लेखनीय तथ्य	– (1) कांग्रेस संविधान में नवीन संशोधन किए गए. (2) मुस्लिमों के अनुरोध पर पंजाब भूमि कानून पर विचार स्थगित किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : सत्रहवाँ अधिवेशन

दीनशा इदुलजी वाचा

आयोजना	–	1901 ई. में
आयोजन स्थल	–	कलकत्ता
अध्यक्ष	–	दीनशा इदुलजी वाचा
स्वागताध्यक्ष	–	बहादुर जोगेन्द्रनाथ राय (नेटोर के महाराजा)
महामन्त्री	–	ए. ओ. ह्यूम
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) भारत में ब्रिटिश सरकार के खाते में लाखों रुपए डालने की आलोचना की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : अठारहवाँ अधिवेशन

आयोजना	–	1902 ई. में
आयोजन स्थल	–	अहमदाबाद
अध्यक्ष	–	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
स्वागताध्यक्ष	–	दीवान बहादुर अम्बालाल शंकर लाल देसाई
महामन्त्री	–	ए. ओ. ह्यूम
उपस्थित प्रतिनिधि	–	461
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) इस अधिवेशन के दौरान रानी विक्टोरिया के स्थान पर एडवर्ड सप्तम ने गद्दी सँभाली. (2) निर्धनता, अकाल और आर्थिक परिस्थिति की जाँच विषयक सामान्य प्रस्ताव स्वीकृत किए गए. (3) इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत में ब्रिटिश फौजों के खाते में 7 लाख, 86 हजार पौण्ड के स्थायी बोझ के नए प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया गया. (4) विश्वविद्यालय कमीशन की प्रतिक्रियावादी सिफारिशों की निन्दा की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : उन्नीसवाँ अधिवेशन

लाल मोहन घोष

आयोजना	–	1903 ई. में
आयोजन स्थल	–	मद्रास
अध्यक्ष	–	लाल मोहन घोष
स्वागताध्यक्ष	–	नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर
महामन्त्री	–	ए. ओ. ह्यूम
उपस्थित प्रतिनिधि	–	538
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) भारत में ब्रिटिश सैनिक नीति और भारतीय करदाताओं पर फौजी छावनियों के खर्चे के बारे में एक विशेष प्रस्ताव रखा गया. (2) इस अधिवेशन के दौरान लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी विश्वविद्यालय कानून प्रकाशित हुआ, जिसका कांग्रेस महासभा ने विरोध किया. (3) ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को व्यक्तिगत स्वाधीनता के लिए खतरनाक घोषित कर विरोध प्रकट किया गया.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : बीसवाँ अधिवेशन

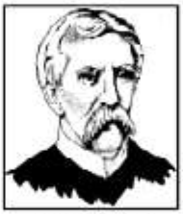

सर हैनरी काटन

आयोजना	–	1904 ई. में
आयोजन स्थल	–	बम्बई
अध्यक्ष	–	सर हैनरी काटन
स्वागताध्यक्ष	–	सर फीरोजशाह मेहता
महामन्त्री	–	ए. ओ. ह्यूम, डी. ई. वाचा एवं गोपाल कृष्ण गोखले
उपस्थित प्रतिनिधि	–	1010
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) कांग्रेस ने लॉर्ड कर्जन के तिब्बत अभियान एवं भारतीय राजस्व पर उसके भार का तीव्र विरोध किया. (2) बंग-भंग के प्रस्ताव के विरुद्ध कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शित किया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : इक्कीसवाँ अधिवेशन

आयोजना	–	1905 ई. में
आयोजन स्थल	–	बनारस
अध्यक्ष	–	गोपाल कृष्ण गोखले
स्वागताध्यक्ष	–	मुंशी माधव लाल
महामन्त्री	–	ए. ओ. ह्यूम, डी. ई. वाचा एवं जी. के. गोखले
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) इस अधिवेशन के दौरान अत्यधिक विरोधों के फलस्वरूप बंगाल का विभाजन किया गया. (2) लॉर्ड कर्जन की नीति का सामूहिक स्तर पर विरोध किया गया. (3) पहली बार राजनीतिक हथियार के रूप में स्वदेशी आन्दोलन तथा विदेशी माल के बहिष्कार का विचार रखा गया. (4) ब्रिटिश अधिकारियों के सामने कांग्रेस के प्रस्ताव रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले को इंग्लैण्ड भेजने का निर्णय लिया गया. (5) कांग्रेस के प्रस्तावों को वर्ष में क्रियान्वित करने के लिए पन्द्रह सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : बाईसवाँ अधिवेशन

आयोजना	–	1906 ई. में
आयोजन स्थल	–	कलकत्ता
अध्यक्ष	–	दादाभाई नौरोजी
स्वागताध्यक्ष	–	डॉ. रासबिहारी घोष
महामन्त्री	–	ए. ओ. ह्यूम, डी. ई. वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले
उपस्थित प्रतिनिधि	–	1663
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के उदारवादी एवं राष्ट्रवादी तत्वों में मतभेद सामने आने लगा. (2) कांग्रेस में अलगाव को रोकने के लिए दादाभाई नौरोजी को इंग्लैण्ड से लाया गया. (3) इस अधिवेशन के दौरान 20,000 व्यक्तियों के लिए उपयुक्त एक पाण्डाल का निर्माण किया गया.
प्रमुख स्वीकृत प्रस्ताव	–	(1) बंगाल का विभाजन रद्द किया जाए. (2) स्वदेश आन्दोलन को समर्थन दिया जाए. (3) स्वतन्त्र शासन की माँग की गई. (4) बंगाल में बहिष्कार के आन्दोलन को समर्थन दिया जाए. (5) सरकार की शिक्षा नीति की निन्दा की गई.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : तेईसवाँ अधिवेशन

रास बिहारी घोष

आयोजना	–	1907 ई. में (स्थगित हो गया था)
आयोजन स्थल	–	सूरत
अध्यक्ष	–	डॉ. रास बिहारी घोष
स्वागताध्यक्ष	–	त्रिभुवनदास एन. माल्वी
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) अधिवेशन नागपुर में होना था और स्वागत समिति चाहती थी कि लोकमान्य तिलक सम्मेलन की अध्यक्षता करे, लेकिन उदारवादी नेता इस पक्ष में नहीं थे. परिणामस्वरूप अधिवेशन सूरत में हुआ. (2) रास बिहारी घोष को अध्यक्ष उदारवादियों की इच्छा के अनुसार बनाया गया. (3) इस अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ. (4) इस अधिवेशन का लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने विरोध किया जिसके कारण हंगामा हो गया और सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा. इसी दौरान कांग्रेस उदारवादी और राष्ट्रवादी दो खेमों में बँट गई. **नोट**–यह अधिवेशन बीच में ही समाप्त हो गया था और इसमें कोई निर्णय न हो सका था अतः अगले वर्ष तेईसवें अधिवेशन की कार्यवाही मद्रास में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में चौबीसवें अधिवेशन में हुई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : चौबीसवाँ अधिवेशन

आयोजना – 1908 ई. में
आयोजन स्थल – मद्रास
अध्यक्ष – डॉ. रास बिहारी
स्वागताध्यक्ष – वी. कृष्णास्वामी अय्यर
महामन्त्री – डी. ई. वाचा, डी. ए. खरे
उपस्थित प्रतिनिधि – 617
उल्लेखनीय तथ्य – (1) यह अधिवेशन मात्र उदारवादियों का अधिवेशन था.
(2) इस दौरान उदारवादियों ने कांग्रेस का नया संविधान निर्मित कर राष्ट्रवादियों को निष्कासित कर दिया.
(3) मार्ले-मिण्टो सुधार को स्वीकार किया गया था.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : पच्चीसवाँ अधिवेशन

आयोजना – 1909 ई. में
आयोजन स्थल – लाहौर
अध्यक्ष – पं. मदनमोहन मालवीय
महामन्त्री – डी. ई. वाचा, डी ए. खरे
उपस्थित प्रतिनिधि – 243
उल्लेखनीय तथ्य – (i) गांधीजी के असहयोग आन्दोलन की मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : छब्बीसवाँ अधिवेशन

आयोजना – 1910 ई. में
आयोजन स्थल – इलाहाबाद
अध्यक्ष – विलियम वेडरवर्न
महामन्त्री – डी. ई. वाचा, डी. ए. खरे
उपस्थित प्रतिनिधि – 636
उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन के दौरान एडवर्ड सप्तम की मृत्यु हो जाने एवं जॉर्ज पंचम के उत्तराधिकारी बनने के कारण साम्प्रदायिक तनाव बढ़ गया था.
(2) साम्प्रदायिक तनाव से निपटा जा सके इसके लिए सहयोग बोर्ड बनाने का सुझाव दिया गया.
(3) दक्षिण अफ्रीका में हो रहे संघर्ष की इस अधिवेशन में सराहना की गई.
(4) पृथक् निर्वाचन को विस्तार देने का अत्यधिक विरोध किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : सत्ताइसवाँ अधिवेशन

पं. बिशन नारायणधर

आयोजना – 1911 ई. में
आयोजन स्थल – कलकत्ता
अध्यक्ष – पण्डित बिशन नारायणधर
महामन्त्री – डी. ई. वाचा, डी. के धर
उपस्थित प्रतिनिधि – 446
उल्लेखनीय तथ्य – (1) दिल्ली को राजधानी इसी अधिवेशन के समय बनाया गया था.
(2) बंग-भंग रद्द हो गया था और बिहार नाम का एक नये प्रान्त का आविर्भाव हुआ था.
(3) इस अधिवेशन के दौरान तिलक मांडले जेल में भर्ती थे.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : अट्ठाइसवाँ अधिवेशन

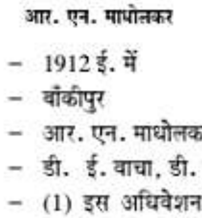

आर. एन. माधोलकर

आयोजना – 1912 ई. में
आयोजन स्थल – बाँकीपुर
अध्यक्ष – आर. एन. माधोलकर
महामन्त्री – डी. ई. वाचा, डी. ए. खरे
उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन में इम्पीरियल और प्रान्तीय परिषद् में चुने हुए प्रतिनिधियों की माँग की.
(2) अधिवेशन में पंजाब में 'कार्यकारी परिषद्' की माँग की गई.
(3) स्थानीय संस्थाओं में पृथक् निर्वाचन की भर्त्सना की गई.
(4) प्रादेशिक स्वतन्त्रता प्रदान करने के सरकार के प्रस्ताव पर संतोष व्यक्त किया गया.

(5) अंग्रेजी भाषा जानने वालों को ही स्थानीय निकायों में शामिल करने की इच्छा व्यक्त की गई.

(6) यह आशा व्यक्त की गई कि भविष्य में कांग्रेस ही मुसलमानों का नेतृत्व करेगी.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : उनतीसवाँ अधिवेशन

नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर

आयोजना – 1913 ई. में

आयोजन स्थल – कराची

अध्यक्ष – नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर

महामन्त्री – डी. ई. वाचा, डी. ए. खरे

उपस्थित प्रतिनिधि – 349

उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन के दौरान हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों में सुधार एवं दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर विशेष चर्चा की गई.

(2) गांधीजी के आन्दोलनों की प्रशंसा की गई एवं देश के लोगों से मदद करने के लिए आह्वान किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : तीसवाँ अधिवेशन

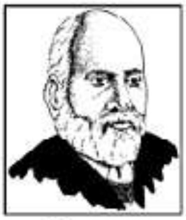

भूपेन्द्रनाथ बसु

आयोजना – 1914 ई. में

आयोजन स्थल – मद्रास

अध्यक्ष – भूपेन्द्रनाथ बसु

महामन्त्री – एन. सुब्बाराव एवं नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर

उपस्थित प्रतिनिधि – 366

उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन में स्वराज्य की माँग की गई.

(2) कांग्रेस द्वारा विश्वयुद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने का वायदा किया, लेकिन शर्त रखी गई कि भारतीयों को सेना में उच्च पद दिए जाएं और आर्म्स एक्ट खत्म किया जाए.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : इकतीसवाँ अधिवेशन

सर सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा

आयोजना – सन् 1915 में

आयोजन स्थल – बम्बई (अब मुम्बई) में

अध्यक्ष – सर सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा

स्वागताध्यक्ष – डी. ई. वाचा

उपस्थित प्रतिनिधि – 2259

उल्लेखनीय तथ्य – (1) तत्कालीन संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के लिए एक्जीक्यूटिव काउंसिल की माँग इस अधिवेशन में की गई.

(2) इकतीसवें अधिवेशन के दौरान सेन्ट्रल प्रोविसेंस (मध्य प्रदेश) एवं पंजाब तथा बर्मा (म्यांमार) के लिए हाईकोर्ट स्थापित करने की माँग की गई.

(3) राष्ट्रवाद की वापसी के लिए कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया.

(4) महात्मा गांधी को सब्जेक्ट कमेटी में नहीं चुना गया.

(5) इस अधिवेशन में पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता, आयात-निर्यात और राजस्व की माँग की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : बत्तीसवाँ अधिवेशन

अम्बिकाचरण मजूमदार

आयोजना – सन् 1916 में

आयोजन स्थल – लखनऊ

अध्यक्ष – अम्बिकाचरण मजूमदार

स्वागताध्यक्ष – पण्डित जगतनारायण

उपस्थित प्रतिनिधि – 2301

विशिष्ट तथ्य – (1) यह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, जिसमें अनेक प्रख्यात नेता शामिल हुए थे.

(2) इसी दौरान मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था.

उल्लेखनीय तथ्य – (1) कांग्रेस के बत्तीसवें अधिवेशन में स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया गया.

(2) इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस-लीग योजना वायसराय के समक्ष पेश की गई.

(3) डिफेंस ऑफ इण्डिया एक्ट तथा 1818 के रेग्यूलेशन III के विरुद्ध प्रस्ताव रखा गया.

(4) इस अधिवेशन में हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे की वकालत की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : तैंतीसवाँ अधिवेशन

आयोजना – सन् 1917 में

आयोजन स्थल – कलकत्ता (कोलकाता) में

अध्यक्ष – श्रीमती एनी बैसेन्ट

स्वागताध्यक्ष – पी. बी. बैकुण्ठनाथ सेन

महामन्त्री – सी. पी. रामास्वामी अय्यर, थुरग्री, पी. केशव पिल्लै

उपस्थित प्रतिनिधि – 4967

श्रीमती एनी बेसेन्ट

विशिष्ट तथ्य – (1) सर्वप्रथम तिरंगे झण्डे को कांग्रेस ने अपनाया.

(2) कांग्रेस लीग योजना को तत्काल लागू करने की माँग की गई.

उल्लेखनीय तथ्य – (1) स्वराज्य पर मुख्य प्रस्ताव पारित हुआ.

(2) अली बन्धुओं की रिहाई की माँग इस अधिवेशन में की गई.

(3) आर्म्स एक्ट की एकजुट होकर निन्दा की गई.

(4) उत्तरदायी स्वशासन की स्थापना के लिए निश्चित समय की माँग की गई.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : विशेष अधिवेशन

आयोजना – सन् 1918 में

आयोजन स्थल – बम्बई (अब मुम्बई)

अध्यक्ष – सैय्यद हसन इमाम

स्वागताध्यक्ष – वल्लभ भाई जे. पटेल

महामन्त्री – सी. पी. रामास्वामी अय्यर, पी. केशव पिल्लै, भुरग्री

उपस्थित प्रतिनिधि – 3500

उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस विशेषाधिवेशन में मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया गया.

(2) इसी दौरान इंगलैण्ड में एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने पर विचार किया गया.

(3) मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में संशोधन की माँग की गई.

राष्ट्रीय कांग्रेस : चौतीसवाँ अधिवेशन

पं. मदनमोहन मालवीय

आयोजना – सन् 1918 में

आयोजन स्थल – दिल्ली

अध्यक्ष – पं. मदनमोहन मालवीय

स्वागताध्यक्ष – हकीम अजमल खाँ

महामन्त्री – वी. जे. पटेल, फजलुल हक, गोकरणनाथ मिश्र

उपस्थित प्रतिनिधि – 4861

उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन के दौरान हिन्दी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया.

(2) कांग्रेस के एकमात्र इसी अधिवेशन में हजारों किसानों ने भाग लिया.

(3) दमनकारी कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया.

(4) भारत को युद्ध चन्दे के रूप में 4 करोड़ 50 लाख राशि के भुगतान से मुक्ति की माँग की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : पैंतीसवाँ अधिवेशन

पं. मोतीलाल नेहरू

आयोजना	– सन् 1919 में
आयोजन स्थल	– अमृतसर
अध्यक्ष	– पं. मोतीलाल नेहरू
महासचिव	– एम. ए. अन्सारी, वी. जे. पटेल, पण्डित गोकरणनाथ मिश्र
स्वागताध्यक्ष	– स्वामी श्रद्धानन्द
उपस्थित प्रतिनिधि	– 7031
विशिष्ट तथ्य	– (1) इस अधिवेशन के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का घोषणा-पत्र जारी किया. (2) प्रेस एक्ट और रोलेट एक्ट को समाप्त करने की दलीलें पेश की गईं. (3) वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड पर महाभियोग लगाने एवं वापस बुला लेने की माँग की गई.
उल्लेखनीय तथ्य	– (1) जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के बाद बड़े उत्साह एवं जोश के साथ बैठक आयोजित की गई. (2) इस अधिवेशन के दौरान हण्टर कमीशन के बहिष्कार का अनुमोदन किया गया. (3) स्वदेशी, दुधारू गायों तथा साँड़ों और प्रान्तों की आबकारी नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : छत्तीसवाँ अधिवेशन

सी. विजयाराघवाचारीयर

आयोजना	– सन् 1920 में
आयोजन स्थल	– नागपुर
अध्यक्ष	– सी. विजयाराघवाचारीयर
स्वागताध्यक्ष	– सेठ जमनालाल बजाज
महासचिव	– मोतीलाल नेहरू, सी. राजगोपालाचारी, एम. ए. अन्सारी
उपस्थित प्रतिनिधि	– 14,583
विशिष्ट तथ्य	– (1) छत्तीसवें अधिवेशन के दौरान कनाट के ड्यूक का बहिष्कार किया गया. (2) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सदस्य संख्या इस अधिवेशन में 350 कर दी गई. (3) कलकत्ता के असहयोग प्रस्ताव की पुनः पुष्टि की गई.
उल्लेखनीय तथ्य	– (1) इस अधिवेशन में 15 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति नियुक्त की गई. (2) भाषायी आधार पर प्रान्तों का फिर से ग्रुप बनाया गया. (3) आयरलैण्ड के अनशनकारी शहीद मैक स्वीनी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. (4) शान्तिपूर्ण एवं वैध उपायों द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने इस अधिवेशन में संकल्प लिया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : विशेष अधिवेशन

लाला लाजपत राय

आयोजना	– सन् 1920 में
आयोजन स्थल	– कलकत्ता (अब कोलकाता में)
अध्यक्ष	– लाला लाजपत राय
स्वागताध्यक्ष	– बी. चक्रवर्ती
महासचिव	– बी. जे. पटेल, एम. ए. अन्सारी, पण्डित गोकरणनाथ मिश्र
विशिष्ट तथ्य	– (1) कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और डॉ. महेन्द्रनाथ के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई. (2) महात्मा गांधी इस अधिवेशन से राष्ट्र नेतृत्व के रूप में उतरे.
उल्लेखनीय तथ्य	– (1) इस विशेष अधिवेशन में पंजाब जाँच समिति की जाँच पर सहमति व्यक्त की गई.

(2) हण्टर समिति की बहुसंख्यक रिपोर्ट को इस अधिवेशन में अस्वीकृत कर दिया गया.

(3) विपिनचन्द्र पाल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास एक शिष्टमण्डल भेजने सम्बन्धी संशोधन पेश किया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : सैंतीसवाँ अधिवेशन

हकीम अजमल खाँ

आयोजना	– सन् 1921 में
आयोजन स्थल	– अहमदाबाद
अध्यक्ष	– हकीम अजमल खाँ[1]
स्वागताध्यक्ष	– वल्लभ भाई पटेल
महासचिव	– सी. राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, वी. जे. पटेल, ए. रंगास्वामी आयंगर
उपस्थित प्रतिनिधि	– 4726
विशिष्ट तथ्य	– (1) इस अधिवेशन में साम्प्रदायिक एकता, पूर्ण मद्य निषेध एवं अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जन समर्थन देने के लिए अनुरोध किया गया. (2) मौलाना हसरत मौहानी की स्वराज्य की परिभाषा–पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव का महात्मा गांधी ने विरोध किया. (3) इस अधिवेशन में मोहनदास करमचन्द गांधी को कांग्रेस का एकमात्र अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया गया.
उल्लेखनीय तथ्य	– (1) इस अधिवेशन से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की समस्त शक्तियाँ एवं उत्तराधिकारी मनोनीत करने के लिए समस्त अधिकार महात्मा गांधी को सौंप दिए गए. (2) अहमदाबाद में आयोजित इस अधिवेशन में कामागाटामारू के बाबा गुरंजीत सिंह को बधाई दी गई.

1 इस अधिवेशन के निर्वाचित अध्यक्ष सी. आर. दास थे. जेल में होने के कारण हकीम अजमल खाँ ने अध्यक्षता का भार ग्रहण किया था.

(3) इस अधिवेशन में यह भी घोषणा की गई कि असहयोग आन्दोलन या खिलाफत आन्दोलन का मोपला (मोपिला) विद्रोह से कोई सम्बन्ध नहीं है.

(4) पौडानूर रेल दुर्घटना पर इस अधिवेशन में चिन्ता व्यक्त की गई.

(5) यूनानियों पर कमाल पाशा की जीत के लिए बधाई दी गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : अड़तीसवाँ अधिवेशन

देशबन्धु चितरंजनदास

आयोजना	– सन् 1922 में
आयोजन स्थल	– गया
अध्यक्ष	– देशबन्धु चितरंजनदास
स्वागताध्यक्ष	– ब्रजकिशोर प्रसाद
महासचिव	– मोअज्जम अली, वल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद
उपस्थित प्रतिनिधि	– 3248
अधिवेशन का मुख्य विषय	– कौंसिल में प्रवेश के लिए प्रस्ताव
विशिष्ट तथ्य	– (1) इस अधिवेशन में अपरिवर्तनवादियों का नेतृत्व राजगोपालाचारी ने तथा स्वराजवादियों का नेतृत्व सी. आर. दास ने किया था. (2) देशबन्धु चितरंजनदास ने अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया. (3) इस अधिवेशन में सरकार को चेतावनी दी गई कि सरकार अब और राष्ट्रीय ऋण न ले. (4) सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिए धन और कार्यकर्ता तैयार करने का आह्वान किया गया. (5) अकाल पीड़ित लोगों को उनकी उत्कृष्ट बहादुरी एवं अहिंसा की भावना के लिए बधाई दी गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : उनतालीसवाँ अधिवेशन

मौलाना मोहम्मद अली

आयोजना	– सन् 1923 में
आयोजन स्थल	– काकोनाडा
अध्यक्ष	– मौलाना मोहम्मद अली
स्वागताध्यक्ष	– देशभक्त कोण्डा वेंकटापैय्या
महासचिव	– डॉ. एस.डी. किचलू, गंगाधर राव देशपाण्डे, जवाहर लाल नेहरू, डी. गोपालकृष्णैया
उपस्थित प्रतिनिधि	– 6188
विशिष्ट तथ्य	– (1) सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह समितियों का कार्यकारिणी समिति में विलय इसी अधिवेशन के दौरान हुआ. (2) उनतालीसवें अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय स्वयंसेवक संगठन का निर्माण किया गया. (3) कीनियाई भारतीय कांग्रेस के लिए जॉर्ज जोसफ एवं सरोजिनी नायडू की नियुक्ति की गई.
उल्लेखनीय तथ्य	– (1) इस अधिवेशन के दौरान सिलोन में भारतीय श्रमिकों की दशाओं की जाँच के लिए समिति गठित की गई. (2) सावरकर के लगातार उत्पीड़ित करने की निन्दा की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : विशेष अधिवेशन

मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद

आयोजना	– सन् 1923 में
आयोजन स्थल	– दिल्ली
अध्यक्ष	– मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद
स्वागताध्यक्ष	– डॉ. एम. ए. अन्सारी
महासचिव	– मुअज्जम अली, वल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद
विशिष्ट तथ्य	– (1) विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का अनुरोध इसी अधिवेशन में किया गया. (2) संविधान में संशोधन के लिए समिति गठित की गई. (3) नागपुर झण्डा सत्याग्रह को उसकी सफलता पर बधाई दी गई.
उल्लेखनीय तथ्य	– (1) लाला लाजपतराय और मौलाना मुहम्मद अली की रिहाई का स्वागत किया गया. (2) राष्ट्रीय समझौते का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठित की गई. (3) जापान के भूकम्प पीड़ितों एवं बिहार, कनाडा तथा बर्मा (म्यांमार) में बाढ़ पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई. (4) महाराजा नाभा के जबर्दस्ती पद से त्यागपत्र देने की निन्दा की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : चालीसवाँ अधिवेशन

आयोजना	– सन् 1924 में
आयोजन स्थल	– बेलगाम
अध्यक्ष	– महात्मा गांधी
स्वागताध्यक्ष	– गंगाधर राव देशपाण्डे

महात्मा गांधी

महासचिव	– साहिब कुरैशी, बी. एफ. भरूच, जवाहर लाल नेहरू
उपस्थित प्रतिनिधि	– 1844
विशिष्ट तथ्य	– (1) इस अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गांधी-दास-नेहरू समझौते की पुष्टि की गई. (2) निज़ाम के राज्य में गुलबर्गा में दुःखी लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई.

(3) अस्पृश्यता और बायकोम सत्याग्रह पर प्रस्ताव पारित किया गया.

उल्लेखनीय तथ्य – (1) शराब एवं अफीम के चोरी-छिपे आने पर विचार किया गया.

(2) गांधी-दास-नेहरू समझौते के अनुरूप कांग्रेस मताधिकार में परिवर्तन.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : इकतालीसवाँ अधिवेशन

श्रीमती सरोजिनी नायडू

आयोजना – सन् 1925 में

आयोजन स्थल – कानपुर

अध्यक्ष – श्रीमती सरोजिनी नायडू

स्वागताध्यक्ष – डॉ. मुरली लाल

महासचिव – एम. ए. अन्सारी, ए. रंगास्वामी आयंगर एवं पण्डित सन्तानम्

उपस्थित प्रतिनिधि – 2688

उल्लेखनीय तथ्य – (1) भारत में आए दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत किया गया.

(2) गांधी-स्मट्स समझौते का उल्लंघन किया गया.

(3) गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से बातचीत का सुझाव दिया गया.

(4) बंगाल अध्यादेश की निन्दा की गई.

(5) गैर-बर्मी अपराध विधेयक को समाप्त किया गया.

(6) सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रति आस्था व्यक्त की गई.

(7) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का विदेश विभाग खोलने का प्रस्ताव रखा गया.

वर्ष की प्रमुख घटनाएं – (1) मुद्रा तथा विनिमय के सन्दर्भ में हिल्टन यंग रिपोर्ट प्रकाशित की गई.

(2) अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा साबरमती समझौता अस्वीकृत किया गया.

(3) असेम्बली के उद्घाटन के दौरान लॉर्ड रीडिंग का समन्वयवादी भाषण घोषित किया.

(4) सेवा दल एवं विदेशी प्रचार के लिए धनराशि स्वीकृत की गई.

(5) पण्डित मोतीलाल और लाला लाजपत राय के बीच एसेम्बली में बहस.

(6) बम्बई (अब मुम्बई) में इण्डियन नेशनल पार्टी का गठन किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : बयालीसवाँ अधिवेशन

एस. श्रीनिवास आयंगर

आयोजना – सन् 1926 में

आयोजन स्थल – गोहाटी

अध्यक्ष – एस. श्रीनिवास आयंगर

स्वागताध्यक्ष – टी. आर. फूकन

महासचिव – डॉ. एम. ए. अन्सारी, ए. रंगास्वामी आयंगर, पण्डित सन्तानम्, वी. जी. पटेल

उपस्थित प्रतिनिधि – 3000

उल्लेखनीय तथ्य – (1) परिषदों में कार्य के बारे में मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया.

(2) इस अधिवेशन के दौरान गांधीजी और मौलाना मुहम्मद अली द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द को श्रद्धांजलि दी गई.

(3) इस अधिवेशन में कीनिया में भारतीय मूल के बसे हुए लोगों के विरुद्ध भेदभाव की निन्दा की गई.

(4) इस अधिवेशन में हिन्दू-मुस्लिम एकता, गुरुद्वारा बन्दियों एवं बंगाल नजरबन्दों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया.

वर्ष की प्रमुख घटनाएँ – (1) अधिवेशन के इस वर्ष में स्वराजवादियों एवं राष्ट्रवादियों का एसेम्बली में मेल हुआ.

(2) सुभाष चन्द्र बोस चार साल के जेल में रहने के बाद अधिवेशन के इस वर्ष में रिहा किए गए.

(3) बम्बई में कांग्रेस द्वारा एकता सम्मेलन आयोजित किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : तेतालीसवाँ अधिवेशन

डॉ. एम. ए. अन्सारी

आयोजना	– सन् 1927 में
आयोजन स्थल	– मद्रास (अब चेन्नई)
अध्यक्ष	– डॉ. एम. ए. अन्सारी
स्वागताध्यक्ष	– सी. एम. मुत्युरंगा मुदालियार
महासचिव	– शैब कुरेशी, जवाहर लाल नेहरू एवं सुभाष चन्द्र बोस
उपस्थित प्रतिनिधि	– 2604
उल्लेखनीय तथ्य	– (1) हर स्तर तथा हर रूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए मुख्य प्रस्ताव पारित.

(2) 'भारतीय लोगों का अध्यक्ष–राष्ट्रीय स्वाधीनता' एक प्रस्ताव में कांग्रेस का मूलमंत्र परिभाषित किया गया.

(3) इस अधिवेशन के एक प्रस्ताव द्वारा युद्ध के खतरे की चेतावनी दी गई.

(4) जनरल अवारी को सत्याग्रह और अनशन के लिए बधाई दी गई.

(5) भारत से बर्मा को अलग करने के प्रस्ताव का विरोध किया गया.

(6) नजरबन्दों की रिहाई की माँग की गई.

(7) हिन्दू-मुस्लिम एकता, अफ्रीका में भारतीय तथा अराजक कानून के विरुद्ध लीग पर प्रस्ताव.

अधिवेशन के वर्ष की प्रमुख घटनाएँ – (1) इस अधिवेशन के वर्ष में साइमन कमीशन 3 फरवरी को बम्बई (मुम्बई) आया.

(2) असेम्बली में लाला लाजपत राय द्वारा साइमन बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया.

(3) 'नाइट' की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा बम्बई (मुम्बई) में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया.

(4) दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई.

(5) इस अधिवेशन के वर्ष में बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह का प्रारम्भ हुआ. बारदोली सत्याग्रह सफलता-पूर्ण रहा.

(6) इस अधिवेशन के वर्ष के दौरान भगतसिंह ने सेन्ट्रल एसेम्बली में बम फेंका.

(7) इस अधिवेशन के वर्ष के दौरान श्रीनिवास आयंगर द्वारा 'इण्डिपेन्डेन्स ऑफ इण्डिया लीग' की शुरूआत की.

(8) लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज एवं चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई.

(9) लाहौर में पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट साण्डर्स की गोली मार कर हत्या कर दी गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : चौवालीसवाँ अधिवेशन

पण्डित मोतीलाल नेहरू

आयोजना	– सन् 1928 में
आयोजन स्थल	– कलकत्ता (अब कोलकाता)
अध्यक्ष	– पण्डित मोतीलाल नेहरू
स्वागताध्यक्ष	– जे. एम. सेन गुहा
महासचिव	– एम. ए. अन्सारी तथा जवाहर लाल नेहरू

उपस्थित प्रतिनिधि – 5221

उल्लेखनीय तथ्य – (1) नेहरू रिपोर्ट पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया.

(2) समझौता फार्मूला तैयार किया गया.

(3) बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर बल्लभ भाई पटेल को बधाई दी गई.

(4) कांग्रेस के पण्डाल में 50,000 श्रमिकों-मजदूरों की रैली निकाली गई तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया गया.

(5) भारतीय रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की माँग की गई.

(6) पैन-एशियाई फेडरेशन की स्थापना करने पर विचार किया गया.

अधिवेशन के वर्ष की प्रमुख घटनाएँ – (1) कांग्रेस के कार्यक्रम को प्रभावी रूप देने के लिए उप-समिति नियुक्त की गई.

(2) गांधीजी को कलकत्ता (अब कोलकाता) में गिरफ्तार कर लिया गया और विदेशी कपड़े जलाने के आरोप में एक रु. का जुर्माना लगाया गया.

(3) इस अधिवेशन के वर्ष के दौरान गांधीजी ने बर्मा और आन्ध्रप्रदेश की यात्रा की.

(4) इस अधिवेशन के वर्ष के दौरान मेरठ-षड्यन्त्र काण्ड घटित हुआ

(5) इस वर्ष के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई (मुम्बई) में बैठक आयोजित की गई.

(6) भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को सजा दी गई.

(7) लाहौर षड्यन्त्र मामले का अध्यादेश पारित किया गया.

(8) जतीन्द्रनाथ और फोंगी विजया की शहादत हुई.

(9) कांग्रेस के नेताओं के साथ लॉर्ड इर्विन की बातचीत हुई.

(10) साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग के कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिवप्रसाद गुप्त नियुक्त किए गए.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : पैंतालीसवाँ अधिवेशन

पण्डित जवाहरलाल नेहरू

आयोजना – सन् 1929 में

आयोजन स्थल – लाहौर

अध्यक्ष – पं. जवाहरलाल नेहरू

महासचिव – सैयद महमूद, श्री प्रकाश, जयरामदास दौलतराम

उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन में स्वाधीनता के बारे में मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया.

(2) पैंतालीसवें अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की समस्त योजनाओं को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी.

(3) कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से विधान-मण्डलों से त्यागपत्र देने का अनुरोध किया गया था.

(4) इस अधिवेशन के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया.

(5) जतीन्द्रनाथ दास और फांगी विजया के सर्वोच्च स्तर के आत्म-त्याग की प्रशंसा इस अधिवेशन में की गई.

अधिवेशन वर्ष की प्रमुख घटनाएँ – (1) अधिवेशन वर्ष में भगतसिंह और उनके सहयोगियों को फाँसी की सजा दी गई.

(2) शोलापुर में मार्शल लॉ की घोषणा की गई.

(3) सुभाषचन्द्र बोस को एक वर्ष की सजा हुई.

(4) सम्पूर्ण राष्ट्र में स्वाधीनता दिवस मनाया गया.

(5) नमक कानून भंग हुआ.

(6) देश में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ.

(7) फरवरी मास में साबरमती में कार्यकारिणी समिति ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने के लिए गांधीजी को अधिकार दिया.

(8) मोतीलाल नेहरू की मृत्यु.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : छियालीसवाँ अधिवेशन

सरदार बल्लभ भाई पटेल

आयोजना	–	सन् 1931 ई. में
आयोजन स्थल	–	कराची (वर्तमान पाकिस्तान में)
अध्यक्ष	–	सरदार बल्लभ भाई पटेल
स्वागत समिति के अध्यक्ष	–	डॉ. चोइत राम गिदवानी
महासचिव	–	सैय्यद महमूद एवं जवाहर लाल नेहरू
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) इस अधिवेशन में भगत सिंह एवं उनके सहयोगियों की वीरता एवं त्याग की प्रशंसा की गई. (2) भगत सिंह एवं उनके सहयोगियों को फाँसी दिए जाने को तुच्छ बदले की भावना कहकर निंदा की गई. (3) गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की प्रशंसा की गई. (4) दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधीजी का नाम स्वीकृत किया गया.
प्रमुख पारित प्रस्ताव	–	(1) छियालीसवें अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया. (2) साम्प्रदायिक दंगों, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के पीड़ितों, शान्तिपूर्ण धरनों, सीमान्त लोगों तथा पश्चिमोत्तर प्रान्त एवं दक्षिणी-पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों के सम्बन्ध में कई प्रस्ताव पारित किए गए.
महत्त्वपूर्ण घटनाएं	–	(1) इस अधिवेशन की महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें सीमान्त क्षेत्र से भारी संख्या में खुदा-ए- खिदमतगार के लोगों ने भाग लिया था. (2) दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि यह अधिवेशन बिना किसी पाण्डाल या शामियाने के खुले आसमान के नीचे हुआ था.
अधिवेशन वर्ष की प्रमुख घटनाएं	–	(1) चरखे से युक्त केसरिया, सफेद और हरे रंगों के नए ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया गया. (2) गांधी-इमर्सन समझौता हुआ. (3) सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं भूला भाई बारदोली जाँच से हटे.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : सैंतालीसवाँ अधिवेशन

नेल्ली सेन गुप्ता

आयोजना	–	सन् 1933 ई. में
आयोजन स्थल	–	कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता)
अध्यक्ष	–	नेल्ली सेन गुप्ता
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) सन् 1932 में एवं सन् 1933 में कांग्रेस के अधिवेशनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया. (2) सन् 1932 में गैर-कानूनी रूप से दिल्ली में अप्रैल माह में अधिवेशन किया गया. (i) इस अधिवेशन में पुलिस की निगरानी के बावजूद 500 प्रतिनिधि उपस्थित. (ii) पण्डित मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया. परिणामस्वरूप नेल्ली सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की. (iii) कांग्रेस का लक्ष्य–स्वाधीनता, सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः शुरू करने का अनुमोदन, गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास एवं अंहिसा में गहरी आस्था से सम्बन्धित चार प्रस्ताव पारित किए गए.
वर्ष की प्रमुख घटनाएँ	–	(1) दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हुआ. (2) साम्प्रदायिक निर्णय के बारे में रैमजे-मैकडोनाल्ड की घोषणा 17 अगस्त को की गई. (3) हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया एवं हरिजन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया. (4) इस अधिवेशन वर्ष के दौरान तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ. (5) अनेक मन्दिरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर हरिजनों का प्रवेश प्रारम्भ कर दिया गया.

(6) गुरुवायूर मन्दिर हरिजनों के लिए खोला गया.

(7) 'यरवदा समझौते' पर हरिजनों, हिन्दू नेताओं एवं कांग्रेसी नेताओं ने हस्ताक्षर किए.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : अड़तालीसवाँ अधिवेशन

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

आयोजना	–	सन् 1934 ई. में
आयोजन स्थल	–	मम्बई (वर्तमान मुम्बई)
अध्यक्ष	–	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
स्वागत समिति के अध्यक्ष	–	के. पी. जरिमन
महासचिव	–	जे.बी. कृपलानी, सैय्यद महमूद, जयराम दास, दौलतराम
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती अधिवेशन के रूप में मनाया गया. (2) कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक-से-अधिक 2000 रखने का फैसला किया. (3) निर्वाचित सदस्यों के लिए सर्व-मताधिकार एवं खद्दर पहनना आवश्यक कर दिया गया. (4) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की संख्या आधी कर दी गई. (5) इस अधिवेशन में गांधीजी ने अपनी प्राचीन सदस्यता से त्यागपत्र देकर कांग्रेस से संन्यास ले लिया.
अधिवेशन वर्ष की प्रमुख घटनाएं	–	(1) इस अधिवेशन वर्ष में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ का 26 अक्टूबर को गठन हुआ. (2) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राहत कार्य आरम्भ किये गये. (3) केन्द्रीय विधान परिषद् के लिए आम चुनाव हुए. (4) कांग्रेस केन्द्रीय विधान परिषद् में बहुमत से जीती.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : उनचासवाँ अधिवेशन

पण्डित जवाहरलाल नेहरू

आयोजना	–	सन् 1936 ई. में
आयोजन स्थल	–	लखनऊ
अध्यक्ष	–	पं. जवाहर लाल नेहरू
महासचिव	–	जे. बी. कृपलानी, जयराम दास दौलतराम
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) मृत देशभक्तों की स्मृति में श्रद्धांजलि दी गई. (2) इस अधिवेशन में सुभाषचन्द्र बोस की गिरफ्तारी की निन्दा की गई. (3) युद्ध एवं फासिष्टवाद के खिलाफ रोम्याँ रोला द्वारा विश्व कांग्रेस को निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया गया. (4) अबीसीनिया के लिए सहानुभूति व्यक्त की गई.
अधिवेशन वर्ष की प्रमुख घटनाएं	–	(1) इस अधिवेशन वर्ष में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम में रहने की घोषणा की. (2) इस अधिवेशन वर्ष में कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया गया. (3) कांग्रेस संसदीय बोर्ड द्वारा कार्य संचालन प्रारम्भ किया. (4) इस अधिवेशन वर्ष के दौरान महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य बातचीत हुई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : पचासवाँ अधिवेशन

पं. जवाहर लाल नेहरू

आयोजना	–	सन् 1937 ई. में
आयोजन स्थल	–	फैजपुर

अध्यक्ष – पं. जवाहर लाल नेहरू

स्वागत समिति

अध्यक्ष – शंकर राव देव

महासचिव – जयराम दास दौलतराम, जे.बी. कृपलानी

उल्लेखनीय तथ्य – (1) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने अखिल भारतीय सम्मेलन के आयोजन का फैसला किया.

(2) स्पेनिश-संघर्ष में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप की निन्दा की गई.

(3) ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों को ध्यान में रखते हुए बर्मा को अलग रखने की घोषणा की गई.

(4) विशेष क्षेत्रों के लिए स्वशासित संस्थाओं के विस्तार का फैसला किया गया.

(5) साम्राज्यवाद को समाप्त करने की घोषणा की गई.

अधिवेशन वर्ष की प्रमुख घटनाएं – (1) गांधीजी की त्रावणकोर यात्रा इस अधिवेशन वर्ष के दौरान सम्पन्न हुई.

(2) इस अधिवेशन-वर्ष के दौरान आम चुनावों में ग्यारह में से आठ प्रान्तों में कांग्रेस की जीत हुई.

(3) इस अधिवेशन वर्ष के दौरान छः प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का गठन हुआ.

(4) मुस्लिम लीग द्वारा इस अधिवेशन वर्ष के दौरान स्वतन्त्रता का लक्ष्य घोषित किया गया.

(5) इस अधिवेशन-वर्ष के दौरान बम्बई विधान सभा द्वारा मन्दिर प्रवेश अधिनियम पारित किया गया.

(6) राजनीतिक बन्दियों की रिहाई के मामले में राज्यपालों के हस्तक्षेप के कारण यू.पी. और बिहार में मन्त्रिमण्डलीय संकट उत्पन्न हुआ जिसका बाद में समाधान भी हो गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : इक्यावनवाँ अधिवेशन

आयोजना – सन् 1938 ई. में

आयोजन स्थल – हरिपुरा

अध्यक्ष – सुभाषचन्द्र बोस

स्वागत समिति अध्यक्ष – दरबार गोपाल दास देसाई

महासचिव – जे. बी. कृपलानी

सुभाषचन्द्र बोस

उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा तथा बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा के लिए अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड नियुक्त किया गया.

(2) असम के गिदालों की रिहाई की माँग की गई.

(3) इक्यावनवें अधिवेशन के दौरान संविधान समिति की स्थापना की गई.

(4) श्रीलंका, चीन तथा फिलिस्तीन के भारतीयों के बारे में प्रस्ताव पारित किए गए.

(5) अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अधिक-से-अधिक सम्भावनाओं का आश्वासन दिया गया.

(6) मिदनापुर में कांग्रेस संगठनों पर लगाए गए प्रतिबन्ध की निन्दा की गई.

अधिवेशन वर्ष की प्रमुख घटनाएं – (1) इस अधिवेशन वर्ष के दौरान गांधीजी ने पश्चिमोत्तर सीमान्त क्षेत्र का दौरा किया.

(2) इस वर्ष में दिल्ली में प्रान्तीय मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ.

(3) राजकोट में सविनय अवज्ञा आन्दोलन हुआ एवं स्थगन हुआ.

(4) राष्ट्रीय योजना समिति के विचार-विमर्श जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में प्राप्त हुए.

(5) गांधीजी शान्ति मिशन पर राजकोट के लिए रवाना हुए.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : बावनवाँ अधिवेशन

आयोजना – सन् 1939 ई. में

आयोजन स्थल – त्रिपुरी

अध्यक्ष – (1) सुभाष चन्द्र बोस

(2) बाबू राजेन्द्र प्रसाद (सुभाष चन्द्र बोस के इस्तीफा देने पर)

स्वागत समिति अध्यक्ष – सेठ गोविन्द दास

महासचिव – जे. बी. कृपलानी

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

उल्लेखनीय तथ्य (1) इस अधिवेशन में सुभाष चन्द्र बोस ने महात्मा गांधी के समर्थक प्रतिनिधि डॉ. पट्टाभिसीतारमैया को हराकर जीत हासिल की थी.

(2) डॉ. पट्टाभिसीतारमैया की हार से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने इसे 'अपनी हार' बतलाया था.

(3) सुभाष चन्द्र बोस इस अधिवेशन में स्ट्रेचर पर चढ़कर भाग लेने आए थे.

(4) बावनवें अधिवेशन में गांधीजी एवं सुभाष चन्द्र बोस के मध्य अत्यधिक विवाद गहरा गया था. गांधीजी की मानसिकता को समझते हुए सुभाष चन्द्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.

(5) इस अधिवेशन में गोविन्द वल्लभ पन्त ने प्रस्ताव पेश किए थे.

(6) फिलिस्तीन की घटनाओं एवं विदेशों में भारतीयों की दशा पर प्रस्ताव पारित किए गए.

(7) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को संविधान में संशोधन करने के अधिकार प्रदान किए गए.

(8) सुभाष चन्द्र बोस द्वारा गांधीजी एवं पुरानी कार्यकारिणी समिति के प्रति पूर्ण निष्ठा की घोषणा की गई.

अधिवेशन वर्ष की प्रमुख घटनाएं – (1) इस वर्ष राजकोट में हुई तोड़फोड़ के लिए गांधीजी ने क्षमा याचना की.

(2) सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 21 मई को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की.

(3) सुभाष चन्द्र बोस पर तीन वर्ष के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई.

(4) केन्द्रीय विधान परिषद् में भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : तिरेपनवाँ अधिवेशन

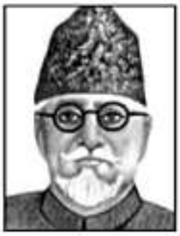

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद

आयोजना – सन् 1940 ई. में

आयोजन स्थल – रामगढ़

अध्यक्ष – मौलाना अब्दुल कलाम आजाद

महासचिव – आचार्य जे.बी. कृपलानी

उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन में भारत और युद्ध संकट के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया. जो केवल एकमात्र प्रस्ताव था.

(2) इस अधिवेशन के दौरान भारी वर्षा हुई थी जिसके कारण अधिवेशन थोड़े समय ही चला था.

(3) युद्ध छिड़ने के बाद होने वाला यह पहला और एकमात्र अधिवेशन था.

मार्च 1940 में आयोजित रामगढ़ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप भारत पर आने वाले संकट के सन्दर्भ में प्रस्ताव पारित किया था. इस खुले अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं—

'भारत और युद्ध संकट के बारे में प्रस्ताव'[1]
(रामगढ़ अधिवेशन 1940)

यूरोप में युद्ध से उत्पन्न गम्भीर और नाजुक स्थिति तथा इस सम्बन्ध में ब्रिटिश नीति को ध्यान में रखते हुए यह कांग्रेस अखिल भारतीय समिति और कार्यकारिणी समिति द्वारा युद्ध की स्थिति के बारे में पारित प्रस्तावों तथा कार्यवाहियों का अनुमोदन और समर्थन करती है. कांग्रेस का विचार है कि भारत की ब्रिटिश सरकार इस देश को उपेक्षित समझती है और यहाँ के लोगों से बिना कुछ पूछे युद्ध में भारत के संसाधनों का शोषण करती है जिसे कोई भी आत्मसम्मानी तथा स्वतन्त्रता प्रिय व्यक्ति न तो स्वीकार कर सकता है और न ही सहन कर सकता है. भारत के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की ओर से हाल में जो घोषणाएं की गई उनसे पता चलता है कि ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्यवादी उद्देश्यों तथा अपने साम्राज्यों को बनाए रखने तथा उसे मजबूत करने के लिए युद्ध जारी किए हुए है जो भारत तथा अन्य एशियाई और अफ्रीकी

1. काग्रेस वर्णिका-शती स्मृति अंक-दिसम्बर 1985, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी (इ.) का मासिक मुख-पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष 1885-1985, Page no. 141.

देशों के लोगों के शोषण पर आधारित है. इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में युद्ध में भाग नहीं ले सकती है, क्योंकि इसका तात्पर्य इस शोषण को जारी रखना और बनाए रखना होगा. इसलिए कांग्रेस ग्रेट ब्रिटेन के लिए युद्ध करने और युद्ध के उद्देश्यों के लिए भारत के जवानों और सामग्री का दुरुपयोग किए जाने पर विरोध प्रकट करती है. भारत में भरती और युद्ध के लिए धन जमा करने को भारत की ओर से स्वैच्छिक अंशदान नहीं समझा जाना चाहिए. कांग्रेसी लोग और कांग्रेस के प्रभाव में रहने वाले लोग धन-जन या सामग्री के साथ युद्ध के अभियोजन में सहायता नहीं कर सकते. यहाँ कांग्रेस पुनः घोषणा करती है कि भारत के लोग पूर्ण स्वतन्त्रता से कम किसी भी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते. भारतीय स्वतन्त्रता साम्राज्यवाद की सीमा या डोमिनियन या साम्राज्यवादी ढाँचे के अन्तर्गत किसी भी अन्य दर्जे में नहीं रह सकती, जोकि भारत के लिए पूरी तरह व्यवहार्य नहीं है और जो महान् राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख सकती तथा जो अनेक प्रकार से ब्रिटिश नीतियों तथा आर्थिक ढाँचे से भारत को बाँधे रहेगी. केवल भारत के लोग ही अपने संविधान को ठीक से तैयार कर सकते हैं और वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के जरिए वह यह निर्धारण करेगा कि विश्व के अन्य देशों के साथ उसका क्या सम्बन्ध होगा? कांग्रेस का यह विचार है कि वह साम्प्रदायिक सद्‌भाव बनाए रखने के लिए हर प्रयास के लिए हमेशा तैयार रहेगा जैसा कि हमेशा तैयार रहा है, संविधान सभा के माध्यम के बिना कोई स्थायी समाधान सम्भव नहीं है. जहाँ मान्यता प्राप्त सभी अल्पसंख्यकों के सभी अधिकारों की एक ऐसे समझौते द्वारा रक्षा की जाएगी जो विभिन्न बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक ग्रुपों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच किया जाएगा या किसी मुद्दे पर सहमति नहीं हुई, तो पंच फैसले द्वारा किया जाएगा. कोई भी विकल्प होने पर उसे अन्तिम नहीं माना जाएगा. भारत का संविधान स्वतन्त्र लोकतन्त्र और राष्ट्रीय एकता पर आधारित होगा और कांग्रेस भारत को विभाजित करने तथा अपनी राष्ट्रीयता के विभाजन के प्रयासों को अस्वीकार करता है. कांग्रेस का लक्ष्य हमेशा ऐसे संविधान तैयार करने का है जिसमें सभी ग्रुपों और सभी व्यक्तियों को भाग लेने की पूरी स्वतन्त्रता हो और विकास के अवसर हों और सामाजिक अन्याय के स्थान पर न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था लागू हो.

कांग्रेस विदेशी निहित स्वार्थों के आधार पर देशी रियासतों के उन अधिकारों को स्वीकार नहीं कर सकती जो भारतीय स्वतन्त्रता के रास्ते में रोड़े अटकाते हों. भारत में प्रभुसत्ता चाहे राज्यों में हो अथवा प्रान्तों में हो, लोगों में रहेगी और उनके अन्य हित प्रमुख हितों के अधीन रहेंगे. कांग्रेस का विचार है कि राज्यों के सम्बन्ध में जो कठिनाई हुई है वह ब्रिटिश लोगों की ही पैदा की हुई है और जब तक विदेशी शासन से भारत की स्वतन्त्रता की स्पष्ट घोषणा न कर दी जाए यह सन्तोषजनक ढंग से हल नहीं हो पाएगी. वे विदेशी हित, जो भारत के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं, उनकी रक्षा की जाएगी.

जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों में बहुमत था, वहाँ से उन्हें हटा लिया गया है, ताकि युद्ध से भारत के सम्बन्ध को समाप्त किया जा सके और विदेशी प्रभुत्व से भारत को स्वतन्त्र कराने की कांग्रेस की दृढ़ता को लागू किया जा सके. इस प्रारम्भिक कदम के बाद स्वाभाविक रूप से सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया जाएगा. कांग्रेस संगठन जब भी स्थिति अनुकूल देखेगा या उस पर संकट की घड़ी थोपी जाएगी, बिना हिचकिचाहट के सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ देगा. कांग्रेस गांधीजी की उस घोषणा की ओर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है कि वह सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने की केवल तभी घोषणा करेंगें जब वे इस बात से सन्तुष्ट होंगे कि वे स्वतन्त्रता की शपथ में निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रम को चला रहे हैं और अनुशासन का पालन कड़ाई से कर रहे हैं.

कांग्रेस जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी वर्गों तथा समुदायों की सेवा करेगी तथा उनका प्रतिनिधित्व करेगी और भारतीय स्वतन्त्रता समग्र राष्ट्र की आजादी के लिए है. इसलिए कांग्रेस की आकांक्षा है कि सभी वर्ग एवं समुदाय इसमें भाग लें. सविनय अवज्ञा आन्दोलन का उद्देश्य सम्पूर्ण राष्ट्र में बलिदान की भावना भर देना है.

अतः कांग्रेस जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को और यदि अत्यावश्यक हो, तो कार्यकारिणी समिति को अधिकृत करती है कि सभी प्रस्तावों पर अमल करने के लिए कदम उठाए अथवा सम्बद्ध समिति जो भी आवश्यक समझे, कार्य करे.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : चौवनवाँ अधिवेशन

आचार्य जे.बी. कृपलानी

आयोजना	– सन् 1946 ई. में
आयोजन स्थल	– मेरठ
अध्यक्ष	– आचार्य जे.बी. कृपलानी
स्वागताध्यक्ष	– चौधरी रघुवीर नारायण सिंह
महामन्त्री	– मृदुला साराभाई, डॉ. वी.वी. केसकर
उपस्थिति प्रतिनिधि	– 2950
उल्लेखनीय तथ्य	(1) कांग्रेस का यह अधिवेशन छः साल बाद हुआ, अतः यह हीरक जयन्ती अधिवेशन के रूप में अत्यधिक उत्साह-पूर्वक मनाया गया.
	(2) इस अधिवेशन के दौरान मेरठ में दंगे भड़क जाने के कारण उपस्थिति कम रही.
	(3) अव्यवस्थित माहौल के कारण स्वागत समिति के प्रबन्ध नहीं किए गए.

(4) इस अधिवेशन में फिजी, मलाया, सिंगापुर, ब्रिटिश गुमान तथा लन्दन में इण्डिया लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

(5) चौवनवें अधिवेशन में आजाद हिन्द फौज के संगीत एवं वाद्यवृन्दों ने लोगों को मन्त्रमुग्ध कर दिया.

(6) पण्डित मदन मोहन मालवीय, विजय राघवाचार्य, श्रीनिवास आयंगर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज, भूला भाई देसाई, सत्यमूर्ति, शिव-प्रसाद गुप्त एवं आर.एस. पण्डित के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किए गए.

(7) इस अधिवेशन के दौरान साढ़े छः वर्षों में हुई घटनाओं की समीक्षा की गई.

(8) स्वराज्य सम्बन्धी 'अगस्त प्रस्ताव' इसी अधिवेशन में पारित किया गया.

(9) बंगाल, बिहार और मेरठ के भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगों पर प्रस्ताव पारित किए गए.

(10) आजाद हिन्द फौज के कैप्टन रामसिंह एवं जनरल शाहनवाज खाँ ने इस अधिवेशन में उत्कृष्टतम प्रदर्शन किया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : पचपनवाँ अधिवेशन

बी. पट्टाभिसीतारमैया

आयोजना	–	सन् 1948 ई. में
आयोजन स्थल	–	जयपुर
अध्यक्ष	–	बी. पट्टाभिसीतारमैया
सभापति	–	गोकुल भाई भट्ट
स्वागत समिति		
महासचिव	–	शंकर राव देव, आचार्य जुगल किशोर
कोषाध्यक्ष	–	कमलनयन बजाज
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) पचपनवें अधिवेशन की कार्यवाही वन्देमातरम् एवं राष्ट्रगान के साथ प्रारम्भ हुई.

(2) इस अधिवेशन में अभिभाषण गोकुल भाई भट्ट द्वारा पढ़ा गया.

(3) पचपनवें अधिवेशन में महात्मा गांधी की हत्या पर गहरा दु:ख व्यक्त किया गया.

(4) महात्मा गांधी की स्मृति में राष्ट्रीय यादगार कोष एवं राष्ट्रीय यादगार स्थापित करने की कांग्रेस ने स्वीकृति दी.

(5) राष्ट्रीय यादगार कोष का उद्देश्य ऐसे सकारात्मक शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदर्शों तथा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था जिसके लिए महात्मा गांधी ने कार्य किया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : छप्पनवाँ अधिवेशन

आयोजना	–	नासिक (महाराष्ट्र) में
आयोजन	–	सन् 1950 में
अध्यक्ष	–	पुरुषोत्तम दास टंडन
स्वागताध्यक्ष	–	बी. ए. हिरे
महासचिव	–	मोहन लाल गौतम और कला वैंकटाराव
कोषाध्यक्ष	–	वल्लभ भाई पटेल
उल्लेखनीय तथ्य		(1) अधिवेशन की कार्यवाही 'वन्दे-मातरम्' के गान से प्रारम्भ हुई.

(2) इस अधिवेशन में आम शोक, प्राकृतिक विनाश आर्थिक कार्यक्रम, विस्थापित लोगों पर सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गए.

(3) अधिवेशन में साम्प्रदायिकता सम्बन्धी एक संकल्प पारित किया गया.

(4) कांग्रेस ने निर्णय किया कि विदेशी अधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को भारतीय गणराज्य में शामिल किया जाना चाहिए.

(5) अधिवेशन राष्ट्रगीत 'जन गण मन' के गायन के साथ सम्पन्न हुआ.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : सत्तावनवाँ अधिवेशन

पण्डित जवाहरलाल नेहरू

आयोजना	–	नई दिल्ली में

आयोजन – सन् 1951 में
अध्यक्ष – पं. जवाहरलाल नेहरू
स्वागताध्यक्ष – ब्रह्म प्रकाश
महासचिव – लाल बहादुर शास्त्री, यू.एन. माल्लिया
कोषाध्यक्ष – डी. डी. मिश्र
उल्लेखनीय तथ्य (1) 'वन्देमातरम्' के गान से अधिवेशन प्रारम्भ हुआ.
(2) इस अधिवेशन में लियाकत अली की हत्या के बारे में शोकसंकल्प पारित किया गया.
(3) कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य के संकल्प को दोहराया गया.
(4) योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए पंचवर्षीय योजना के मसौदे का स्वागत किया गया.
(5) सैनफ्रांसिस्को में जापानी शांति संधि में भाग न लेने का अनुमोदन किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : अट्ठावनवाँ अधिवेशन

आयोजना – हैदराबाद में
आयोजन – सन् 1953 में
अध्यक्ष – पं. जवाहरलाल नेहरू
स्वागताध्यक्ष – रामानन्द तीर्थ
महामन्त्री – बलवन्त राय मेहता, एस. एन. अग्रवाल, यू. एस. माल्लिया
उल्लेखनीय तथ्य (1) आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए 'भूदान यज्ञ' कार्यक्रम के बारे में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया.
(2) संयुक्त राष्ट्रसंघ की उपलब्धियों के लिए सराहना की गई.
(3) भारत सरकार की गुटनिरपेक्ष नीति, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सराहना की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : उनसठवाँ अधिवेशन

आयोजना – कल्याणी में
आयोजन – सन् 1954 में
अध्यक्ष – पं. जवाहरलाल नेहरू
स्वागताध्यक्ष – अतुल्य घोष
महासचिव – एस. एन. अग्रवाल और बलवन्त राय मेहता
कोषाध्यक्ष – मोरारजी देसाई
उल्लेखनीय तथ्य (1) कांग्रेस के इस अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधियों एवं अभिरक्षक सेनाओं द्वारा कोरिया में किए गए कार्यों की सराहना की गई.
(2) अफ्रीका तथा नाइजीरिया द्वारा अपनी सरकार बनाने की सराहना की गई.
(3) सूडान की नई सरकार की सराहना करते हुए कांग्रेस द्वारा सूडान के नागरिकों को शुभकामनाएँ प्रेषित की गईं.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : साठवाँ अधिवेशन

आयोजना – आवड़ी में
आयोजन – सन् 1955 में
अध्यक्ष – यू. एन. ढेबर
स्वागताध्यक्ष – श्रीमति एस. अम्बुजामल
महासचिव – एस. एन. अग्रवाल और के. पी. माधवन नायर
कोषाध्यक्ष – मोरारजी देसाई
उल्लेखनीय तथ्य (1) कांग्रेस के इस अधिवेशन में समाजवादी ढाँचे के संकल्प को पारित किया गया.
(2) राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में 'पंचशील' के पाँच सिद्धान्तों का स्वागत किया गया.
(3) अधिवेशन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा स्त्रियों एवं बच्चों के कल्याण सम्बन्धी प्रयासों की सराहना की गई और इस तरह के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया.
(4) शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्चतम शिक्षा के पुनर्गठन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का स्वागत किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : इकसठवाँ अधिवेशन

आयोजना – अमृतसर में
आयोजन – सन् 1956 में
अध्यक्ष – यू. एन. ढेबर
स्वागताध्यक्ष – गुरुमुख सिंह मुसाफिर
महासचिव – श्रीमन् नारायण और के. पी. माधवन नायर
कोषाध्यक्ष – मोरारजी देसाई
उल्लेखनीय तथ्य (1) 16 देशों को संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य बनाने पर इस अधिवेशन में प्रसन्नता व्यक्त की गई.

(2) चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व नहीं देने पर खेद व्यक्त किया गया.

(3) उपनिवेशी पुर्तगाली शासन में रहने वाले लोगों की स्थिति पर गहरा शोक व्यक्त किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : बासठवाँ अधिवेशन

यू. एन. ढेबर

आयोजना – इन्दौर में

आयोजन – सन् 1957 ई. में

अध्यक्ष – यू. एन. ढेबर

स्वागताध्यक्ष – कन्हैयालाल खादीवाला

महासचिव – श्रीमन नारायण, के. पी. माधवन नायर, एम. एम. चौधरी

कोषाध्यक्ष – मोरारजी देसाई

उल्लेखनीय तथ्य (1) इस अधिवेशन में 1857 की शताब्दी के बारे में पारित संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया.

(2) श्री जवाहर लाल नेहरू ने चुनाव घोषणा-पत्र स्वीकृत करने के लिए प्रस्तावित किया.

(3) भारतीय विदेश नीति के सन्दर्भ में नेहरूजी ने कहा कि "गृह नीति के सन्दर्भ में ही विदेश नीति पर विचार किया जा सकता है और यह जरूरी है कि दोनों एक दूसरी से जुड़ी हों.[1]"

(4) अधिवेशन में मिस्र की भूमि से आंग्ल-फ्रांसीसी सेनाओं के हटाए जाने का स्वागत किया गया एवं हंगरी से विदेशी सेना हटाने का अनुरोध किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : तिरेसठवाँ अधिवेशन

आयोजना – गुवाहाटी में

आयोजन – सन् 1958 में

अध्यक्ष – यू. एन. ढेबर

स्वागताध्यक्ष – महेन्द्र मोहन चौधरी

महासचिव – श्रीमन नारायण, के. पी. माधवन नायर, एम. एम. चौधरी

कोषाध्यक्ष – मोरारजी देसाई

उल्लेखनीय तथ्य (1) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी संकल्प में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व जनमत की भूमिका एवं हस्तक्षेप की सराहना की गई.

(2) विश्व के सभी देशों से निरस्त्रीकरण के अनुबन्ध के लिए विश्व जनमत के आह्वान को स्वीकार करने की अपील की गई.

(3) शैक्षिक पुनर्गठन एवं प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था को परिवर्तित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया.

(4) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किए गए निर्णयों का स्वागत किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : चौसठवाँ अधिवेशन

आयोजना – नागपुर में

आयोजन – सन् 1959 में

अध्यक्ष – यू. एन. ढेबर

स्वागताध्यक्ष – गोपिका भाई काननवार

महासचिव – सादिक अली, सुचेता कृपलानी, ए. एस. राजू, टिक्कामल

कोषाध्यक्ष – वाई. बी. चव्हाण

उल्लेखनीय तथ्य – (1) इस अधिवेशन में अल्जीरिया तथा साइप्रस के लोगों के द्वारा गणराज्य प्राप्त करने की माँग का समर्थन किया गया.

(2) गोआ के लोगों को पुर्तगाली शासन से मुक्ति दिलाने पर विचार किया गया.

(3) अफ्रीका में स्वतंत्रता बढ़ाने एवं गिनिया के स्वतन्त्र प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य के रूप में उभरने का स्वागत किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : पैंसठवाँ अधिवेशन

आयोजना – बंगलौर में

आयोजन – सन् 1960 ई. में

अध्यक्ष – एन. संजीव रेड्डी

स्वागताध्यक्ष – एच. के. वर्मा गौडा

महासचिव – जी. राजगोपालन, सादिक अली, आभा मैयती

1. कांग्रेस वर्णिका–शती स्मृति अंक–दिसम्बर–1985

एन. संजीव रेड्डी

कोषाध्यक्ष	–	वाई. बी. चव्हाण
उल्लेखनीय तथ्य		(1) योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा पंचायती राज की स्थापना के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया.
		(2) आण्विक परीक्षणों, निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की उम्मीद प्रस्ताव में की गई थी.
		(3) पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य हुए समझौते का स्वागत किया गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : छियासठवाँ अधिवेशन

आयोजना	–	भुवनेश्वर में
आयोजन	–	सन् 1961 में
अध्यक्ष	–	एन. संजीव रेड्डी
स्वागताध्यक्ष	–	ठाकुर भाई देसाई
महासचिव	–	जी. राजगोपालन, सादिक अली
कोषाध्यक्ष	–	वाई. बी. चव्हाण
उल्लेखनीय तथ्य		(1) 'पंचायती राज' से सम्बन्धित प्रस्ताव में उन राज्यों को बधाई दी गई जो पंचायती राज को पहले से ही स्वीकार कर चुके हैं.
		(2) इस अधिवेशन में तीसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन किया गया.
		(3) राष्ट्रीय अखण्डता सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें साम्प्रदायिकता, जातिवाद एवं प्रान्तीयता का मुकाबला करने का आह्वान किया गया.
		(4) अल्जीरिया सम्बन्धी प्रस्तावों में कांग्रेस ने फ्रांस के द्वारा किए जा रहे आक्रमणों की निन्दा की.
		(5) चीन द्वारा पारस्परिक सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का उल्लंघन करने की निन्दा की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : सड़सठवाँ अधिवेशन

आयोजना	–	पटना में
आयोजन	–	सन् 1962 में
अध्यक्ष	–	नीलम संजीव रेड्डी
स्वागताध्यक्ष	–	जगजीवन राम
महासचिव	–	के. के. शाह, जगन्नाथ राव, चौंद सादिक अली
कोषाध्यक्ष	–	एस. के. पाटिल
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस अधिवेशन में चुनाव घोषणा-पत्र तैयार किया तथा उसका समर्थन किया.
		(2) निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित वार्तालाप में गतिरोध समाप्त होने पर स्वागत किया गया.
		(3) गोआ में समाप्त हुए पुर्तगाली उपनिवेशवाद का स्वागत किया गया.
		(4) गोआ के भविष्य के बारे में प्रधानमंत्री की नीति की सराहना की गई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : अड़सठवाँ अधिवेशन

के. कामराज

आयोजना	–	भुवनेश्वर में
आयोजन	–	सन् 1964 ई. में
अध्यक्ष	–	के. कामराज
स्वागताध्यक्ष	–	बीजू पटनायक
कोषाध्यक्ष	–	एस. के. पाटिल
उल्लेखनीय तथ्य	–	(1) इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो भू.पू. अध्यक्षों–डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एवं पुरुषोत्तम दास टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया गया.
		(2) अमरीका के राष्ट्रपति श्री जानसन की नीति के अनुसरण करने के विचार का स्वागत किया गया.
		(3) केन्या और जंजीबार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का स्वागत किया गया.
		(4) सोवियत रूस की सशस्त्र सेनाओं में कमी की घोषणाओं की सराहना की गई.

प्रश्न कोश
(QUESTION BANK)

1. सन् 1908 ई. में बाल गंगाधर तिलक को बन्दी बनाकर भेज दिया गया था–
   (A) सिंगापुर की जेल में
   (B) मांडले की जेल में
   (C) दिल्ली की जेल में
   (D) अण्डमान एवं निकोबार की जेल में
2. भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया–
   (A) 23 नवम्बर, 1950 ई. को
   (B) 26 जनवरी, 1950 ई. को
   (C) 26 नवम्बर, 1949 ई. को
   (D) 26 जनवरी, 1948 ई. को
3. स्वराज पार्टी के संस्थापक थे–
   (A) मोतीलाल नेहरू (B) बाल गंगाधर तिलक
   (C) महात्मा गांधी (D) सरदार पटेल
4. महारानी विक्टोरिया ने 'भारत की महारानी' की उपाधि धारण की थी–
   (A) सन् 1877 ई. में (B) सन् 1875 ई. में
   (C) सन् 1865 ई. में (D) सन् 1850 ई. में
5. गांधी-इरविन समझौता हुआ था–
   (A) सन् 1925 ई. में (B) सन् 1923 ई. में
   (C) सन् 1931 ई. में (D) सन् 1926 ई. में
6. कौनसे नेता 'बिस्मार्क' के नाम से जाने जाते थे?
   (A) महात्मा गांधी
   (B) सुभाष चन्द्र बोस
   (C) सरदार पटेल
   (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
7. आम सहमति से चुने गये राष्ट्रपति थे–
   (A) श्री शंकर दयाल शर्मा
   (B) डॉ. जाकिर हुसैन
   (C) नीलम संजीव रेड्डी
   (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
8. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था–
   (A) कानपुर में (B) दिल्ली में
   (C) पटना में (D) मुम्बई में
9. वह स्वतन्त्रता सेनानी जिसे सन् 1908 ई. में अलीपुर सेंट्रल जेल में फाँसी दी गई–
   (A) भगत सिंह (B) सुखदेव
   (C) चन्द्रशेखर आजाद (D) खुदीराम बोस को
10. नरमपंथियों ने गरमपंथियों से अलग होने का फैसला किया–
   (A) सन् 1908 ई. में (B) सन् 1914 ई. में
   (C) सन् 1919 ई. में (D) सन् 1907 ई. में
11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कार्य करना प्रारम्भ किया–
   (A) 1971 ई. में (B) 1950 ई. में
   (C) 1975 ई. में (D) 1956 ई. में
12. भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ–
   (A) 24 अप्रैल, 1993 को
   (B) 25 अप्रैल, 1996 को
   (C) 1 मई, 1994 को
   (D) 4 मई, 1994 को
13. भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध हुआ–
   (A) 1850 ई. में (B) 1908 ई. में
   (C) 1857 ई. में (D) 1848 ई. में
14. भारतीय गणतन्त्र की उद्घोषणा हुई–
   (A) 26 जनवरी, 1950 को
   (B) 15 अगस्त, 1947 को
   (C) 10 जनवरी, 1951 को
   (D) 20 अगस्त, 1948 को
15. महात्मा गांधी की हत्या हुई–
   (A) 30 जनवरी, सन् 1948 को
   (B) 29 जून, सन् 1950 को
   (C) 17 जुलाई, सन् 1940 को
   (D) 13 मई, सन् 1964 को
16. पाकिस्तान ने पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया–
   (A) 2 दिसम्बर, 1971 को
   (B) 4 मई, 1972 को
   (C) 5 जून, 1972 को
   (D) 14 मई, 1971 को

17. चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया–
    (A) सन् 1962 ई. में (B) सन् 1964 ई. में
    (C) सन् 1970 ई. में (D) सन् 1961 ई. में

18. पं. जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु हुई–
    (A) 27 मई, 1964 ई. में
    (B) 20 मई, 1963 ई. में
    (C) 10 मई, 1960 ई. में
    (D) 10 जून, 1964 ई. में

19. "भारत को ईश्वर के सहारे छोड़ दो." कहा था–
    (A) नेहरू जी ने (B) लाला लाजपतराय ने
    (C) देसाई जी ने (D) महात्मा गांधी ने

20. सत्याग्रह की स्थापना की गई–
    (A) 1916 ई. में (B) 1920 ई. में
    (C) 1915 ई. में (D) 1914 ई. में

21. महात्मा गांधी के हत्यारे को फाँसी की सजा दी गई–
    (A) अम्वाला जेल में
    (B) सिंगापुर की जेल में
    (C) अण्डमान निकोबार की जेल में
    (D) दिल्ली की जेल में

22. हॉकी के जादूगर ध्यानचन्द्र का जन्म हुआ?
    (A) कानपुर में (B) बनारस में
    (C) कलकत्ता में (D) इलाहाबाद में

23. गदर पार्टी के संस्थापक थे–
    (A) सरदार भगत सिंह (B) चन्द्रशेखर आजाद
    (C) लाला हरदयाल (D) सुभाषचन्द्र बोस

24. देशबन्धु के नाम से जाने जाते हैं–
    (A) मोती लाल नेहरू
    (B) लाला लाजपतराय
    (C) सी. आर. दास
    (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

25. कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस पार्टी के जन्मदाता थे–
    (A) अब्दुल्ला शेख मुहम्मद
    (B) अब्दुल गफ्फार खाँ
    (C) आजाद मौलाना अब्दुल कलाम
    (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

26. एम. ए. ओ. कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की–
    (A) अहमद सर सैय्यद खान
    (B) अब्दुल नासिर
    (C) विनोबा भावे
    (D) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

27. 'नौजवान सभा' के संस्थापक थे–
    (A) सरदार भगत सिंह
    (B) ऊधम सिंह
    (C) चन्द्रशेखर आजाद
    (D) अशफाक उल्ला खान

28. "करो या मरो" का नारा दिया–
    (A) सुभाष चन्द्र बोस ने (B) मो. इकबाल ने
    (C) बाल गंगाधर तिलक ने (D) महात्मा गांधी ने

29. बंगाल का विभाजन हुआ–
    (A) सन् 1905 ई. में (B) सन् 1930 ई. में
    (C) सन् 1909 ई. में (D) सन् 1904 ई. में

30. मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग की गई–
    (A) सन् 1930 ई. में (B) सन् 1940 ई. में
    (C) सन् 1908 ई. में (D) सन् 1941 ई. में

31. स्वामी दयानन्द सरस्वती का प्रमुख नारा था–
    (A) वेदों की ओर लौटो (B) दिल्ली चलो
    (C) भारत छोड़ो (D) आराम हराम है

32. कारगिल का युद्ध हुआ था–
    (A) सन् 1998 ई. में (B) सन् 1999 ई. में
    (C) सन् 1997 ई. में (D) सन् 2000 ई. में

33. प्रथम गवर्नर जनरल थे–
    (A) राजगोपालाचारी (B) रामकृष्ण मिशन
    (C) जाकिर हुसैन (D) जवाहर लाल नेहरू

34. सन् 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे–
    (A) लॉर्ड केनिंग (B) चेम्स फोर्ड
    (C) मिंटो (D) वेवल

35. कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला–
    (A) श्रीमती सरोजनी नायडू थी
    (B) श्रीमती इन्दिरा गांधी थी
    (C) श्रीमती नलिनीसेन गुप्ता थी
    (D) श्रीमती कादम्बिनी गांगुली थी

36. 'शान्ति पुरुष' के नाम से जाना जाता था–
    (A) महात्मा गांधी को
    (B) वल्लभ भाई पटेल को
    (C) जवाहर लाल नेहरू को
    (D) लाल बहादुर शास्त्री को

37. बंगाल का नील आंदोलन हुआ–
    (A) 1858-59 में (B) 1957-58 में
    (C) 1959-60 में (D) 1960-61 में

38. नील आंदोलन का कारण था–
    (A) किसानों से कर लेना
    (B) किसानों को नील उत्पादन के लिए मजबूर करना
    (C) लगान अधिक लेना
    (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

39. 'हिन्दू पैट्रियट' के सम्पादक थे–
    (A) हरीश चन्द्र मुखर्जी (B) मदन मोहन मालवीय
    (C) महात्मा गांधी (D) इनमें से कोई नहीं

40. किस व्यक्ति ने सन् 1857 ई. के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई–
    (A) बहादुर शाह 'जफर' (B) बेगम हजरत महल
    (C) बालाजी बाजीराव (D) महारानी लक्ष्मीबाई

41. महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई–
    (A) 17 जून, 1858 को (B) 17 मई, 1957 को
    (C) 17 जुलाई, 1958 को (D) इनमें से कोई नहीं

42. कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी–
    (A) आचार्य नरेन्द्र देव ने
    (B) पं. जवाहर लाल नेहरू ने
    (C) मदन मोहन मालवीय ने
    (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

43. 1930 के दशक में वहाबी आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र था–
    (A) पटना (B) बनारस
    (C) दिल्ली (D) कानपुर

44. वहाबियों की लड़ाई में शामिल नहीं थे–
    (A) अंग्रेज (B) राजपूत
    (C) सिख (D) मुसलमान

45. रुहेलखण्ड में 1857 के विद्रोह का नेता था–
    (A) फिरोज खाँ (B) अमर सिंह
    (C) कुँवर सिंह (D) खान बहादुर

46. सन् 1935 ई. में आल इण्डिया मिशन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ–
    (A) इलाहाबाद में (B) कानपुर में
    (C) दिल्ली में (D) लखनऊ में

47. ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किस स्थान पर किया ?
    (A) झाँसी में (B) अलीगढ़ में
    (C) वेल्लोर में (D) कोटा में

48. हिन्दुओं को किस सामाजिक विधेयक ने अंग्रेजों के खिलाफ किया ?
    (A) सती प्रथा का अन्त (B) दास प्रथा का अन्त
    (C) विधवा विवाह (D) (A) व (C) दोनों

49. सन् 1929 ई. में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे–
    (A) जवाहर लाल नेहरू (B) सरदार पटेल
    (C) सर्वपल्ली राधा कृष्णन (D) राजेन्द्र प्रसाद

50. "भारत छोड़ो आन्दोलन" के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में नजरबन्द किया गया ?
    (A) दिल्ली की जेल में
    (B) हजारी बाग की जेल में
    (C) आगा खाँ के महल में
    (D) कानपुर की जेल में

51. बहादुर शाह जफर की सेना का सेनानायक कौन था ?
    (A) अहमदुल्ला (B) अजमल खाँ
    (C) बख्त खाँ (D) खान बहादुर

52. इण्डियन काउन्सिल एक्ट की स्थापना हुई थी–
    (A) 1905 ई. में (B) 1909 ई. में
    (C) 1904 ई. में (D) 1910 ई. में

53. सती प्रथा निषेध कानून पारित हुआ–
    (A) 1829 ई. में (B) 1850 ई. में
    (C) 1859 ई. में (D) 1840 ई. में

54. किस क्रांतिकारी ने बंग भंग-विरोध में आन्दोलन किया ?
    (A) सुभाष चन्द्र बोस ने (B) भगत सिंह ने
    (C) राजगुरु ने (D) खुदीराम बोस ने

55. 'प्रिन्स ऑफ वेल्स' का बहिष्कार किया था–
    (A) सोहन लाल पाठक ने (B) सुखदेव ने
    (C) सुभाष चन्द्र बोस ने (D) इनमें से कोई नहीं

56. 11 अगस्त, 1908 को किस क्रान्तिकारी को फाँसी दी गई ?
    (A) भगत सिंह को
    (B) खुदीराम बोस को
    (C) विष्णु गणेश पिंगले को
    (D) सोहन लाल पाठक को

57. निम्नलिखित में से किस क्रान्तिकारी को फाँसी नहीं दी गई ?
    (A) खुदीराम बोस को
    (B) बलवन्त वसुदेव को
    (C) विष्णु गणेश पिंगले को
    (D) भगत सिंह को

58. भगत सिंह क्रान्तिकारी दल में शामिल हुआ–
    (A) सन् 1925 में (B) सन् 1926 में
    (C) सन् 1924 में (D) सन् 1930 में

59. किस क्रान्तिकारी ने 8 अप्रैल, 1929 को केन्द्रीय विधान सभा में बम विस्फोट किया था ?
(A) चन्द्रशेखर आजाद ने (B) खुदी राम बोस ने
(C) असित भट्टाचार्य ने (D) भगत सिंह ने

60. अंग्रेजों ने पहला व्यापारिक केन्द्र खोला था–
(A) बनारस में (B) दिल्ली में
(C) सूरत में (D) मद्रास में

61. मुस्लिम लीग से सम्बन्धित नहीं थे–
(A) अबुल कलाम आजाद (B) सली मुल्ला खाँ
(C) आगा खाँ (D) फजलुल हक

62. रैयतवाड़ी प्रथा सम्बन्धित थी–
(A) कृषकों से (B) जमींदारों से
(C) भारतीय गुमाश्तो से (D) ग्रामीण समुदाय से

63. अंग्रेजों के राजनीतिक समर्थक थे–
(A) जमींदार
(B) भू-स्वामी
(C) संरक्षित राज्यों के राजकुमार
(D) उपर्युक्त सभी

64. वह जनजातीय नेता जो अपने को ईश्वर का अवतार मानता था–
(A) बिरसा मुण्डा (B) जात्रा भगत
(C) सिद्दो (सिद्धु) (D) भगत जवाहरमल

65. 19वीं सदी में नील आन्दोलन किसके विरुद्ध हुआ ?
(A) विदेशी उद्योगपतिओं
(B) भारतीय जमींदारों के
(C) ब्रिटिश सरकार के
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

66. खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था–
(A) जोमधर कुँवर ने
(B) तीरत सिंह ने
(C) करमशाह ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

67. सन् 1857 ई. के विद्रोह में कौन विद्रोहकारी नेता नेपाल भाग गया था ?
(A) नाना साहब (B) खान बहादुर
(C) हजरत महल (D) मौलवी अहमदुल्ला

68. किस क्रान्तिकारी की गिरफ्तारी के बाद सन् 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ?
(A) कुँवर सिंह (B) तात्यां टोपे

69. 1857 के प्रमुख नायक थे–
(A) सिपाही (सैनिक) (B) किसान
(C) जमींदार (D) लक्ष्मीबाई

70. पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ ?
(A) 1849 ई. में (B) 1853 ई. में
(C) 1858 ई. में (D) 1854 ई. में

71. वहाबी संस्थापक के अनुसार भारत की स्वतन्त्रता का सबसे प्रबल खतरा किसे था ?
(A) जाट सरदारों को (B) अंग्रेज व्यापारियों को
(C) सिख सरदारों को (D) हिन्दू राजाओं को

72. कौनसा जनजातीय आन्दोलन महाजनों तथा उनके संरक्षक अंग्रेजों के खिलाफ था ?
(A) कील विद्रोह (B) किसान विद्रोह
(C) कक्ष विद्रोह (D) संथाल विद्रोह

73. सुरक्षा कपाट सिद्धान्त सम्बन्धित है–
(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से
(B) लैण्ड होल्डर्स सोसाइटी से
(C) आल इण्डिया एसोसिएशन से
(D) भारतीय जनता पार्टी से

74. 'India Wins Freedom' पुस्तक के लेखक थे–
(A) अरविन्द घोष
(B) बाणभट्ट
(C) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
(D) बंकिम चन्द्र चटर्जी

75. सन् 1857 की क्रान्ति से कौनसा स्थान अछूता रहा ?
(A) बंगाल (B) मद्रास
(C) मुम्बई (D) झाँसी

76. किसने कहा था–"भारत पर स्थायी कब्जा रखने के लिए ईसाईकरण आवश्यक है" ?
(A) लॉर्ड डलहौजी (B) लॉर्ड कैनिंग
(C) मेजर एडवर्डस (D) लॉर्ड डफरिन

77. सन् 1885 ई. में बम्बई में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे–
(A) एनीबेसेंट (B) डॉ. होमी जहाँगीर
(C) महात्मा गांधी (D) व्योमेश चन्द्र बनर्जी

78. वह भारतीय नेता, जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामंस के सदस्य चुने गए–
(A) महात्मा गांधी (B) गोपाल कृष्ण गोखले

59. किस क्रान्तिकारी ने 8 अप्रैल, 1929 को केन्द्रीय विधान सभा में बम विस्फोट किया था ?
    (A) चन्द्रशेखर आजाद ने (B) खुदी राम बोस ने
    (C) असित भट्टाचार्य ने (D) भगत सिंह ने

60. अंग्रेजों ने पहला व्यापारिक केन्द्र खोला था–
    (A) बनारस में (B) दिल्ली में
    (C) सूरत में (D) मद्रास में

61. मुस्लिम लीग से सम्बन्धित नहीं थे–
    (A) अबुल कलाम आजाद (B) सली मुल्ला खाँ
    (C) आगा खाँ (D) फजलुल हक

62. रैयतवाड़ी प्रथा सम्बन्धित थी–
    (A) कृषकों से (B) जमींदारों से
    (C) भारतीय गुमाश्तो से (D) ग्रामीण समुदाय से

63. अंग्रेजों के राजनीतिक समर्थक थे–
    (A) जमींदार
    (B) भू-स्वामी
    (C) संरक्षित राज्यों के राजकुमार
    (D) उपर्युक्त सभी

64. वह जनजातीय नेता जो अपने को ईश्वर का अवतार मानता था–
    (A) विरसा मुण्डा (B) जात्रा भगत
    (C) सिद्दो (सिद्धु) (D) भगत जवाहरमल

65. 19वीं सदी में नील आन्दोलन किसके विरुद्ध हुआ ?
    (A) विदेशी उद्योगपतिओं
    (B) भारतीय जमींदारों के
    (C) ब्रिटिश सरकार के
    (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

66. खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था–
    (A) जोमधर कुँवर ने
    (B) तीरत सिंह ने
    (C) करमशाह ने
    (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

67. सन् 1857 ई. के विद्रोह में कौन विद्रोहकारी नेता नेपाल भाग गया था ?
    (A) नाना साहब (B) खान बहादुर
    (C) हजरत महल (D) मौलवी अहमदुल्ला

68. किस क्रान्तिकारी की गिरफ्तारी के बाद सन् 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ?
    (A) कुँवर सिंह (B) तात्यां टोपे

69. 1857 के प्रमुख नायक थे–
    (A) सिपाही (सैनिक) (B) किसान
    (C) जमींदार (D) लक्ष्मीबाई

70. पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ ?
    (A) 1849 ई. में (B) 1853 ई. में
    (C) 1858 ई. में (D) 1854 ई. में

71. वहाबी संस्थापक के अनुसार भारत की स्वतन्त्रता का सबसे प्रबल खतरा किसे था ?
    (A) जाट सरदारों को (B) अंग्रेज व्यापारियों को
    (C) सिख सरदारों को (D) हिन्दू राजाओं को

72. कौनसा जनजातीय आन्दोलन महाजनों तथा उनके संरक्षक अंग्रेजों के खिलाफ था ?
    (A) कील विद्रोह (B) किसान विद्रोह
    (C) कक्ष विद्रोह (D) संथाल विद्रोह

73. सुरक्षा कपाट सिद्धान्त सम्बन्धित है–
    (A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से
    (B) लैण्ड होल्डर्स सोसाइटी से
    (C) आल इण्डिया एसोसिएशन से
    (D) भारतीय जनता पार्टी से

74. 'India Wins Freedom' पुस्तक के लेखक थे–
    (A) अरविन्द घोष
    (B) बाणभट्ट
    (C) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
    (D) बंकिम चन्द्र चटर्जी

75. सन् 1857 की क्रान्ति से कौनसा स्थान अछूता रहा ?
    (A) बंगाल (B) मद्रास
    (C) मुम्बई (D) झाँसी

76. किसने कहा था–"भारत पर स्थायी कब्जा रखने के लिए ईसाईकरण आवश्यक है" ?
    (A) लॉर्ड डलहौजी (B) लॉर्ड कैनिंग
    (C) मेजर एडवर्डस (D) लॉर्ड डफरिन

77. सन् 1885 ई. में बम्बई में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे–
    (A) एनीबेसेंट (B) डॉ. होमी जहाँगीर
    (C) महात्मा गांधी (D) व्योमेश चन्द्र बनर्जी

78. वह भारतीय नेता, जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामंस के सदस्य चुने गए–
    (A) महात्मा गांधी (B) गोपाल कृष्ण गोखले

79. समुद्र का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रन्थ में किया गया है ?
    (A) ब्राह्मण ग्रन्थ (B) उपनिषद्
    (C) स्मृति ग्रन्थ (D) ऐतरेय
80. गड़करी विद्रोह कब हुआ ?
    (A) 1845 ई. में (B) 1830 ई. में
    (C) 1844 ई. में (D) 1846 ई. में
81. महाराष्ट्र में अकाल के कारण अनाज की दुकानों को कब लूटा गया ?
    (A) 1896-97 ई. में (B) 1899 ई. में
    (C) 1890 ई. में (D) 1895 ई. में
82. पावना जिला विख्यात है–
    (A) मुस्लिम-लीग की स्थापना के लिए
    (B) कांग्रेस की स्थापना के लिए
    (C) किसान-लीग की स्थापना के लिए
    (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
83. अंग्रेजों ने औद्योगिक आयोग का गठन किया–
    (A) सन् 1905 ई. में (B) सन् 1908 ई. में
    (C) सन् 1915 ई. में (D) सन् 1916 ई. में
84. सन् 1930 के दशक में बिहार में कृषक आन्दोलन के नेता थे–
    (A) सी. आर. दास (B) स्वामी सहजानन्द
    (C) मुजफ्फर अहमद (D) राजेन्द्र प्रसाद
85. "भारत भारतीयों के लिए है," कहा था–
    (A) हिन्दू समाज ने (B) आर्य समाज ने
    (C) मुस्लिम समाज ने (D) सिख समाज ने
86. कम आयु की बालिकाओं को विवाह से रोकने के लिए सर्वप्रथम किसने कदम उठाया ?
    (A) राजा राममोहन राय ने (B) केशवचन्द्र सेन ने
    (C) बेहरामजी मालवारी ने (D) पण्डित गुरुदत्त ने
87. राजा राममोहन राय के विचारों का प्रसार किसने किया ?
    (A) केशवचन्द्र सेन ने (B) देवेन्द्रनाथ टैगोर ने
    (C) अरविन्द घोष ने (D) इनमें से कोई नहीं
88. कमाण्डर ह्यूगेज रोज ने 1857 के संग्राम के किस विद्रोही को सबसे बहादुर नेता कहा था ?
    (A) रानी लक्ष्मीबाई को (B) बहादुर शाह जफर को
    (C) कुँवर सिंह को (D) तात्यां टोपे को
89. वह देश जिसने भारतीय अफीम के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया था–
    (A) चीन (B) इटली
    (C) पाकिस्तान (D) (A) व (B) दोनों
90. सन् 1857 ई. में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गम्भीर घटना हुई–
    (A) राजस्थान में (B) कानपुर में
    (C) दिल्ली में (D) बैरकपुर की छावनी में
91. जलियाँवाला हत्याकाण्ड से जुड़े जनरल डायर को मारा था–
    (A) भगत सिंह ने (B) ऊधमसिंह ने
    (C) खुदी राम बोस ने (D) सुभाष चन्द्र बोस ने
92. बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को "उच्च जातीय भाड़े के सैनिक" कहा था–
    (A) सर चार्ल्स नेपियर ने (B) हेनरी लॉरेन्स ने
    (C) हार्डिंग ने (D) ऑकलैण्ड ने
93. नौकरी से निष्कासित मराठा सिपाहियों ने विद्रोह किया था–
    (A) सतारा में (B) नागपुर में
    (C) पूना में (D) कानपुर में
94. राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ई. के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी–
    (A) सरदार पटेल ने
    (B) सुभाष चन्द्र बोस ने
    (C) मोती लाल नेहरू ने
    (D) पं. जवाहर लाल नेहरू ने
95. नमक मूल्य बढ़ाने के विरुद्ध आन्दोलन हुआ था–
    (A) 1844 ई. में (B) 1862 ई. में
    (C) 1863 ई. में (D) 1856 ई. में
96. 'इण्डियन मुस्लिम' पुस्तक के लेखक थे–
    (A) थियोडर बेक (B) सर विलियम हंटर
    (C) सर सैय्यद अहमद खाँ (D) चमन लाल
97. राजी किसान आन्दोलन हुआ था–
    (A) कानपुर में (B) झाँसी में
    (C) बंगाल में (D) बिहार में
98. ह्विटले कमीशन का सम्बन्ध था–
    (A) शिक्षा से (B) श्रम से
    (C) वेटन से (D) जनता से
99. सिविल सेवा में सफल होने वाला प्रथम भारतीय था–
    (A) सत्येन्द्रनाथ टैगोर (B) सुभाष चन्द्र बोस
    (C) आनन्द मोहन बोस (D) सुरेन्द्र नाथ बनर्जी
100. कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति थी–
    (A) इसे सहयोग देना
    (B) इसे नष्ट करना
    (C) गैर-कानूनी घोषित करना
    (D) सहयोग प्राप्त करना

101. कूका आन्दोलन से सम्बन्धित किस नेता को बर्मा म्यांमार भेजा गया ?
(A) राम सिंह को (B) भगत सिंह को
(C) सुखदेव को (D) चन्द्रशेखर आजाद को

102. भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखी थी–
(A) रमेश चन्द्र दत्त ने (B) एनीबेसेन्ट ने
(C) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने (D) रबीन्द्रनाथ टैगोर ने

103. महात्मा गांधी को 'महात्मा' की उपाधि प्रदान की थी–
(A) मो. जिन्ना ने
(B) मदनमोहन मालवीय ने
(C) रवीन्द्रनाथ टैगोर ने
(D) एनीबेसेन्ट ने

104. सन् 1857 के विद्रोह के पश्चात् अधिकांश सैनिकों की भर्ती कहाँ से की जाती थी ?
(A) मद्रास से (B) कानपुर से
(C) बंगाल तथा विहार से (D) पंजाब तथा नेपाल से

105. आल इण्डिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे–
(A) लाला लाजपतराय (B) बाल गंगाधर तिलक
(C) मदन मोहन मालवीय (D) महात्मा गांधी

106. दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था–
(A) सन् 1805 ई. में (B) सन् 1802 ई. में
(C) सन् 1804 ई. में (D) सन् 1825 ई. में

107. अखिल भारतीय ट्रेड की स्थापना हुई थी–
(A) सन् 1918 ई. में (B) सन् 1920 ई. में
(C) सन् 1930 ई. में (D) सन् 1940 ई. में

108. अंग्रेजों का 'फोर्ट विलियम' स्थित है–
(A) कानपुर में (B) लखनऊ में
(C) कोलकाता में (D) चेन्नई में

109. डण्डा फौज का गठन हुआ था–
(A) मेरठ में (B) बिहार में
(C) पंजाब में (D) बंगाल में

110. मुण्डा विद्रोह का नेतृत्व किया था–
(A) महात्मा गांधी ने (B) भगत सिंह ने
(C) ऊधम सिंह ने (D) बिरसा मुण्डा ने

111. अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई–
(A) 1905 ई. में (B) 1926 ई. में
(C) 1936 ई. में (D) 1920 ई. में

112. मुण्डा आदिवासियों का विद्रोह हुआ–
(A) 1901-1902 ई. तक (B) 1899-1900 ई. तक

113. बिहार प्रान्तीय किसान सभा के संस्थापक थे–
(A) गोपाल कृष्ण गोखले
(B) मदन मोहन मालवीय
(C) स्वामी सहजानन्द सरस्वती
(D) महात्मा गांधी

114. 1857 ई. के विद्रोह में अंग्रेजों के पक्ष में थे–
(A) राजपूत (B) मुस्लिम
(C) सिख (D) इनमें से कोई नहीं

115. आदिवासियों ने 'जंगल कानून' के खिलाफ विद्रोह किया–
(A) 1870 ई. में (B) 1871 ई. में
(C) 1879 ई. में (D) 1870 ई. में

116. बिरसा मुण्डा का जन्म हुआ था–
(A) 1874 ई. (B) 1870 ई.
(C) 1879 ई. (D) 1890 ई.

117. वह गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी–
(A) लॉर्ड कार्नवालिस की (B) लॉर्ड मैकाले की
(C) वारेन हेस्टिंग्स की (D) लॉर्ड हार्डिग्ज की

118. पहला ब्रिटिश विरोधी संघर्ष किया था–
(A) मुण्डाओं ने (B) संथालों ने
(C) उराँवों ने (D) संन्यासियों ने

119. आदिवासी नेता बिरसा को गिरफ्तार किया गया–
(A) 1905 ई. (B) 1906 ई.
(C) 1900 ई. (D) 1890 ई.

120. 'भारत सेवक समाज' के संस्थापक थे–
(A) महात्मा गांधी (B) भीमराव अम्बेडकर
(C) दादाभाई नौरोजी (D) गोपाल कृष्ण गोखले

121. नील आन्दोलन की सफलता का कारण था–
(A) सरकारी सहयोग
(B) जमींदारों का सहयोग
(C) रैयतों की एकजुटता व संगठन
(D) पुलिस का सहयोग

122. "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा." किसने कहा था?
(A) सुभाष चन्द्र बोस ने (B) भगतसिंह ने
(C) चन्द्रशेखर आजाद ने (D) महात्मा गांधी ने

123. किस विद्रोह का सम्बन्ध पश्चिमी भारत से नहीं था ?
(A) फरैजी विद्रोह (B) भल विद्रोह
(C) रामोसी विद्रोह (D) बघेरा विद्रोह

124. "बंगाल को अपने किसानों पर गर्व है." कहा था–

(B) गोपाल कृष्ण गोखले ने
(C) मोती लाल नेहरू ने
(D) हरीशचन्द्र मुखर्जी ने

125. "करो या मरो" नारा दिया गया–
(A) सन् 1940 ई. (B) सन् 1945 ई.
(C) सन् 1950 ई. (D) सन् 1942 ई.

126. "किसान संघ" की स्थापना की गई–
(A) 1873 ई. में (B) 1880 ई. में
(C) 1870 ई. में (D) 1871 ई. में

127. कच्छ नागा जनजातियों ने 1882 ई. में किस पर आक्रमण किया था–
(A) जमींदारों पर (B) महाजनों पर
(C) व्यापारियों पर (D) अंग्रेजों पर

128. 'नील उत्पादकों' में सबसे अधिक थे–
(A) भारतीय (B) यूरोपीय
(C) आदिवासी (D) जमींदार

129. सत्यशोधक मण्डल की स्थापना की थी–
(A) ज्योतिबा फुले ने
(B) महात्मा गांधी ने
(C) भीमराव अम्बेडकर ने
(D) पं. जवाहर लाल नेहरू ने

130. कोडाडोरा विद्रोह हुआ था–
(A) बिहार में (B) महाराष्ट्र में
(C) बंगाल में (D) आंध्र प्रदेश में

131. "जो रक्षक वही भक्षक" सूक्ति का जन्म हुआ–
(A) 1857 ई. में (B) 1854 ई. में
(C) 1860 ई. में (D) 1870 ई. में

132. 'गुलामगीरी' पुस्तक की रचना की–
(A) महात्मा गांधी ने (B) भीमराव अम्बेडकर ने
(C) ज्योतिबा फुले ने (D) ई. विद्यासागर ने

133. किसानों को उनके अपनी मर्जी से फसल उगाने की अनुमति मिली–
(A) सन् 1957 ई. में (B) सन् 1890 ई. में
(C) सन् 1860 ई. में (D) सन् 1959 ई. में

134. सविनय अवज्ञा आन्दोलन का स्थगन किस समझौते के तहत हुआ था ?
(A) शिमला समझौता
(B) गांधी-इरविन समझौता
(C) चीन समझौता
(D) पाकिस्तान समझौता

135. बंगाल में नील उत्पादन का अन्त हुआ–
(A) सन् 1860 ई. (B) सन् 1862 ई.
(C) सन् 1870 ई. (D) सन् 1874 ई.

136. ईश्वरचन्द्र विद्या सागर ने अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया–
(A) गरीबों के प्रति (B) स्वतन्त्रता के प्रति
(C) विधवा विवाह के प्रति (D) हरिजनों के प्रति

137. 'बंगाल काश्तकारी कानून' बना–
(A) 1885 ई. में (B) 1830 ई. में
(C) 1880 ई. में (D) 1884 ई. में

138. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड की जाँच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समित की अध्यक्षता की थी–
(A) महात्मा गांधी ने
(B) मोती लाल नेहरू ने
(C) मदन मोहन मालवीय ने
(D) पं. जवाहर लाल नेहरू ने

139. 'गांधी **बनाम** लेनिन' के लेखक थे–
(A) एम. एन. राय (B) मुजफ्फर अहमद
(C) एस. ए. डांगे (D) मदन मोहन मालवीय

140. दक्कन उपद्रव हुआ था–
(A) 1874 ई. में (B) 1875 ई. में
(C) 1880 ई. में (D) 1890 ई. में

141. सुभाष चन्द्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था–
(A) 1938 ई. में (B) 1924 ई. में
(C) 1937 ई. में (D) 1942 ई. में

142. 'रम्पा' आन्दोलन का नेतृत्व किया था–
(A) विजयसिंह पथिक ने (B) पी. सी. जोशी ने
(C) सीताराम राजू ने (D) माणिक्य लाल वर्मा ने

143. 'दक्कन कृषक राहत अधिनियम' कब पारित हुआ ?
(A) 1879 ई. में (B) 1880 ई. में
(C) 1888 ई. में (D) 1872 ई. में

144. 1893-94 ई. में "कर नहीं देंगे" का आन्दोलन कहाँ हुआ ?
(A) गुजरात में (B) असम में
(C) उड़ीसा में (D) बंगाल में

145. भू-राजस्व समझौता अधिनियम कब पारित हुआ ?
(A) 1867 ई. में (B) 1870 ई. में
(C) 1869 ई. में (D) 1840 ई. में

146. असहयोग आन्दोलन के समय भारत के वायसराय थे–
(A) लॉर्ड चेम्सफोर्ड (B) लॉर्ड इरविन
(C) लॉर्ड मिन्टो (D) लॉर्ड मैकाले

147. पालिगार थे–
(A) दक्षिण भारत के भू-घाटी सैनिक सरदार
(B) अपदस्थ राजा
(C) विजय भारतीय राज्यों के अधिकारी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

148. भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ कब हुई थी ?
(A) सन् 1840 ई. में (B) सन् 1853 ई. में
(C) सन् 1855 ई. में (D) सन् 1854 ई. में

149. सन् 1859 ई. में किसने कहा था "पुलिस जनता की भक्षक है" ?
(A) कैनिंग ने (B) विलियम ने
(C) लॉर्ड मेयो ने (D) कार्नवालिस

150. कांग्रेस की नींव में कितने लोगों ने भाग लिया ?
(A) 40 लोगों ने (B) 20 लोगों ने
(C) 80 लोगों ने (D) 72 लोगों ने

151. क्रिप्स मिशन को किसने 'उत्तरदिनांकित चैक' (Post dated cheque) की संज्ञा दी ?
(A) महात्मा गांधी ने (B) राजेन्द्र प्रसाद ने
(C) मोती लाल नेहरू ने (D) पं. जवाहरलाल नेहरू

152. किसने कहा था, "कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है" ?
(A) मोती लाल नेहरू ने
(B) महात्मा गांधी ने
(C) लाला लाजपतराय ने
(D) पं. जवाहरलाल नेहरू ने

153. मंगल पाण्डे को फाँसी कब दी गई ?
(A) 8 अप्रैल, 1857 को (B) 28 मार्च, 1858 को
(C) 29 मार्च, 1829 को (D) 30 मार्च, 1830 को

154. एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी–
(A) विलियम जोन्स ने (B) मैक्समूल ने
(C) वी. ए. स्मिथ ने (D) विलिकिन्स ने

155. निम्नलिखित में से किसका सम्बन्ध वेद समाज से था ?
(A) सुब्बुरायल चेट्टी (B) श्री धरालु नायडू
(C) श्रीकृष्णन् आयंगर (D) इनमें से कोई नहीं

156. मोपला विद्रोह के मूल कारण थे–
(A) आर्थिक (B) धार्मिक
(C) कृषिगत (D) सामाजिक-धार्मिक

157. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक थे–
(A) एम. एस. गोललकर (B) महात्मा गांधी

158. भारत के अन्तिम गवर्नर जनरल कौन थे ?
(A) लॉर्ड माउन्टबेटन (B) सी. राजगोपालाचारी
(C) लॉर्ड विलिंगटन (D) लॉर्ड मिन्टो

159. मंगल पाण्डे ने अंग्रेज सैन्य अधिकारी की हत्या की थी–
(A) 25 मार्च, 1858 को (B) 26 मार्च, 1857 को
(C) 29 मार्च, 1857 को (D) 21 जून, 1850 को

160. कांग्रेस के संस्थापक ए. ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी–
(A) मो. अली जिन्ना ने
(B) पं. जवाहर लाल नेहरू ने
(C) महात्मा गांधी ने
(D) वेडरबर्न ने

161. 1836 से 1854 तक कौनसा विद्रोह 22 बार हुआ ?
(A) रामौसी विद्रोह (B) कुकी विद्रोह
(C) मोपला विद्रोह (D) फरैजी विद्रोह

162. बुन्देला भू-स्वामियों ने सागर (म. प्र.) में विद्रोह किया था–
(A) 1842 ई. में (B) 1852 ई. में
(C) 1854 ई. में (D) 1850 ई. में

163. "ए. ओ. ह्यूम आजादी के प्रेमी थे." किसने कहा ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) पं. जवाहर लाल नेहरू ने
(C) मो. अली जिन्ना ने
(D) लाला लाजपतराय ने

164. असम में 1829 ई. में विद्रोह हुआ–
(A) संथाल विद्रोह (B) चुनार विद्रोह
(C) कोल विद्रोह (D) खासी विद्रोह

165. अंग्रेज सरकार के द्वारा महालवाड़ी प्रथा लागू की गई–
(A) अवध एवं पंजाब में (B) असम में
(C) बिहार में (D) उत्तर प्रदेश में

166. किस प्रथा के तहत भूमिदार को भूमि का स्वामी घोषित किया गया ?
(A) महलवाड़ी प्रथा (B) रैयतवाड़ी प्रथा
(C) जमींदारी प्रथा (D) पट्टेदारी प्रथा

167. लाला लाजपतराय थे–
(A) गरम पंथी नेता (B) नरम पंथी नेता
(C) क्रान्तिकारी नेता (D) इनमें से कोई नहीं

168. वासुदेव बलवन्त फड़के का आन्दोलन हुआ था–
(A) बिहार में (B) पंजाब में

169. 1764 ई. में सिपाहियों ने विद्रोह किया था–
(A) बंगाल में (B) पंजाब में
(C) हरियाणा में (D) उत्तर प्रदेश में

170. किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपना सर्वप्रथम व्यापारिक कारखाना लगाया ?
(A) सूरत में (B) कानपुर में
(C) लखनऊ में (D) मद्रास में

171. थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) मेडम एच. वी. ब्लावेदस्की
(C) मोतीलाल नेहरू
(D) मो. जिन्ना

172. ग्वालियर के 20,000 सैनिकों ने समर्पण किया–
(A) महात्मा गांधी को
(B) लाला लाजपतराय को
(C) रानी लक्ष्मीबाई को
(D) उपर्युक्त में से किसी को नहीं

173. मंगल पाण्डे निम्नलिखित में किस कम्पनी का सिपाही था ?
(A) 24 वीं नेटिव इन्फैन्ट्री का
(B) 20 वीं नेटिव इन्फैन्ट्री का
(C) 34 वीं नेटिव इन्फैन्ट्री का
(D) 10 वीं नेटिव इन्फैन्ट्री का

174. सन् 1878 ई. में कृषि एवं वाणिज्य विभाग के सचिव थे–
(A) महात्मा गांधी (B) मोतीलाल नेहरू
(C) लाला लाजपतराय (D) ए. ओ. ह्यूम

175. मदनलाल धींगरा को फाँसी की सजा दी गई–
(A) 17 अगस्त, 1909 ई. को
(B) 19 अगस्त, 1909 ई. को
(C) 17 अगस्त, 1910 ई. को
(D) 15 अगस्त, 1909 ई. को

176. वह स्थान जहाँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सर्वप्रथम स्वतन्त्र व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ–
(A) बिहार (B) बंगाल
(C) उड़ीसा (D) पंजाब

177. "कांग्रेस का गठन एवं उसकी कार्यशैली डफरन की ही देन है." किसने कहा ?
(A) सरदार भगतसिंह ने (B) लाला लाजपतराय ने
(C) मोतीलाल नेहरू ने (D) सुभाषचन्द्र बोस ने

178. इण्डिया हाउस की स्थापना की गई–
(A) अमरीका में (B) जापान में
(C) रूस में (D) लन्दन में

179. भारत के स्वतन्त्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री थे–
(A) लॉर्ड कैनिन (B) लॉर्ड डफरिन
(C) क्लीमेंट एटली (D) इनमें से कोई नहीं

180. चम्पारण आन्दोलन का महात्मा गांधी से सम्बन्ध था–
(A) जेल भेजे गए
(B) राजनीति में प्रवेश किया
(C) अंग्रेजों ने यातनाएँ दीं
(D) इनमें से कोई नहीं

181. तात्यां टोपे व महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा पराजित अंग्रेज जनरल था–
(A) नील (B) हैवलाक
(C) जॉन सीले (D) ह्यूगरोज

182. 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक किस वर्ग के नेताओं ने भाग लिया ?
(A) व्यापारी (B) भूपति
(C) किसान (D) राजकुमार

183. 'कांग्रेस समाजवादी पार्टी' की स्थापना की गई–
(A) 1905 ई. में (B) 1930 ई. में
(C) 1945 ई. में (D) 1950 ई. में

184. बालाजी बाजीराव ने किस विद्रोह में भूमिका नहीं निभाई ?
(A) 1857 के विद्रोह में (B) खासी विद्रोह में
(C) किसान विद्रोह में (D) इनमें से कोई नहीं

185. ए. ओ. ह्यूम ने भारतीय राजनीति में भाग लेने की अपील की थी–
(A) 1865 ई. में (B) 1880 ई. में
(C) 1882 ई. में (D) 1890 ई. में

186. 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था–
(A) किसानों ने
(B) कारीगरों ने
(C) जमींदारों ने
(D) नये मध्यम वर्ग के लोगों ने

187. धन निष्क्रमण सिद्धान्त का सम्बन्ध है–
(A) धन को बाहर ले जाने से
(B) धन को उपयोग न करने से
(C) धन को निष्क्रिय रखने से
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

188. सन् 1857 ई. में फैजाबाद में किसने आन्दोलन का नेतृत्व किया ?
(A) मंगल पाण्डे ने
(B) पं. जवाहर लाल ने
(C) पं. मदन मोहन मालवीय
(D) मौलवी अहमदुल्ला

189. "हम कांग्रेस को साबूत नहीं रहने देंगे," कहा था–
(A) डफरिन ने (B) ए. ओ. ह्यूम
(C) रे (D) इनमें से कोई नहीं

190. तेभागा आन्दोलन से सम्बन्धित थे–
(A) जमींदार (B) किसान
(C) मजदूर (D) बुनकर

191. ए. ओ. ह्यूम व डफरिन के मध्य मतभेद हुआ था–
(A) 1820 ई. में (B) 1880 ई. में
(C) 1882 ई. में (D) 1885 ई. में

192. उमाजी नाइक से सम्बन्धित विद्रोह था–
(A) चुनार विद्रोह (B) रामौसी विद्रोह
(C) कोल विद्रोह (D) गड़करी विद्रोह

193. सभी इतिहासकारों की नजर में 1857 का विद्रोह था–
(A) भारतीय स्वतन्त्रता का युद्ध
(B) अंग्रेज विरोधी आन्दोलन
(C) कृपक विद्रोह
(D) सिपाही विद्रोह

194. सबसे अधिक विद्रोह किसके विरुद्ध किए ?
(A) व्यापारियों के
(B) जमींदारों के
(C) सरकारी कर्मचारियों के
(D) बागान मालिकों के

195. इण्डियन एसोसिएशन का गठन किया–
(A) महात्मा गांधी ने (B) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने
(C) आनन्द मोहन बोस ने (D) (B) व (C) दोनों ने

196. मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ था–
(A) 1884 ई. में (B) 1880 ई. में
(C) 1870 ई. में (D) 1890 ई. में

197. मंगल पाण्डे ने किन दो अंग्रेज जनरलों की हत्या की थी ?
(A) बाग, फिनिस की (B) मिचेल, बाग की
(C) हियरसे, मिचेल (D) बाग, हियरसे

198. 1893-94 ई. में 'कर नहीं' आन्दोलन चलाया गया–
(A) असम में (B) उड़ीसा में

199. बाम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया–
(A) 1885 ई. में (B) 1889 ई. में
(C) 1890 ई. में (D) 1884 ई. में

200. भारत में प्रथम स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया–
(A) 26 जनवरी, 1930 ई. को
(B) 26 जनवरी, 1940 ई. को
(C) 26 जनवरी, 1926 ई. को
(D) 26 जनवरी, 1950 ई. को

201. राष्ट्रीय सोशल कान्फ्रेन्स की स्थापना की थी–
(A) सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने (B) तिलक ने
(C) एम. जी. रानाडे ने (D) महात्मा गांधी ने

202. राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खाँ को फाँसी दी गई–
(A) 1925 ई. में (B) 1930 ई. में
(C) 1926 ई. में (D) 1924 ई. में

203. 1857 की क्रान्ति के बाद विद्रोह हुआ था–
(A) मुण्डा विद्रोह (B) संभाल विद्रोह
(C) खोंद विद्रोह (D) कृपक विद्रोह

204. वस्त्र आयात शुल्क को लेकर कब विद्रोह हुआ ?
(A) 1875 ई. में (B) 1840 ई. में
(C) 1877 ई. में (D) 1890 ई. में

205. भारतीयों से 'आर्म एक्ट' का सम्बन्ध है–
(A) फाँसी की सजा
(B) हथियार न रखना
(C) चोरी न करना
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

206. कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे–
(A) पं. जवाहर लाल नेहरू (B) मो. जिन्ना
(C) गोपाल कृष्ण गोखले (D) डब्ल्यू. सी. बनर्जी

207. ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ–
(A) मेरठ में (B) कानपुर में
(C) झाँसी में (D) वेल्लोर में

208. गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ?
(A) 1935 ई. में (B) 1940 ई. में
(C) 1931 ई. में (D) 1925 ई. में

209. "राजा जनता के लिए बने हैं जनता राजा के लिए नहीं," किसने कहा था ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) राजा राममोहन राय ने
(C) दादा भाई नौरोजी ने

210. 'हम' नामक पत्र के प्रकाशक थे–
(A) मोती लाल नेहरू (B) आनन्द मोहन बोस
(C) एम. एस. गोवलकर (D) हरिश चन्द्र मुखर्जी

211. बिहार में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया–
(A) सुभाष चन्द्र बोस ने
(B) भगत सिंह ने
(C) सिद्धू, कान्हू ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

212. अजीमुल्लाह किसके भक्त थे ?
(A) हजरत महल के (B) नाना साहब के
(C) खान बहादुर के (D) तात्यां तोपे के

213. कांग्रेस शब्द लिया गया–
(A) जापान के इतिहास से
(B) उत्तरी अमरीका के इतिहास से
(C) रूस के इतिहास से
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

214. तेलंगाना विद्रोह हुआ–
(A) शोषण के विरुद्ध (B) धर्म के विरुद्ध
(C) शिक्षा के विरुद्ध (D) आजादी के विरुद्ध

215. 1857 की क्रान्ति के प्रचारक थे–
(A) मौलवी कुदरत अली (B) मौलवी बरकत अली
(C) मौलवी अहमद उल्ला (D) इनमें से कोई नहीं

216. विधवा पुनर्विवाह संगठन के संस्थापक थे–
(A) भीका जी कामां (B) ज्योतिबा फूले
(C) विष्णु शास्त्री पंडित (D) महात्मा गांधी

217. बंगाल में ब्रह्मसमाज की स्थापना की थी–
(A) फीरोजशाह मेहता ने
(B) दादा भाई नौरोजी ने
(C) लाला लाजपत राय ने
(D) राजा राममोहन राय ने

218. आर्य समाज की स्थापना हुई–
(A) 1875 ई. में (B) 1890 ई. में
(C) 1870 ई. में (D) 1880 ई. में

219. 1857 के विद्रोह के समय फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय को सहायता के लिए पत्र भेजा था–
(A) नाना साहब ने
(B) महात्मा गांधी ने
(C) पं. जवाहर लाल ने

220. प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई–
(A) कानपुर में (B) बनारस में
(C) बम्बई में (D) दिल्ली में

221. फकीरों का नेता था–
(A) फकीर हाजी मस्तान (B) टीटू मीर
(C) चिराग अली (D) मजनून शाह

222. सत्याग्रह समिति की स्थापना की थी–
(A) महात्मा गांधी ने
(B) पं. जवाहर लाल नेहरू ने
(C) सुचेता कृपलानी ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

223. झाँसी के सिपाहियों को हिंसा के लिए उत्तेजित किया था–
(A) रानी लक्ष्मीबाई ने (B) प्रभाकर राव ने
(C) तात्यां टोपे ने (D) लक्ष्मणराव ने

224. आजाद हिन्द फौज के जवानों को 'गुमराह देशभक्त' कहा था–
(A) मदन मोहन मालवीय ने (B) महात्मा गांधी ने
(C) गोपालकृष्ण गोखले ने (D) पं. जवाहरलाल ने

225. बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे–
(A) राजा राममोहन राय (B) दादाभाई नौरोजी
(C) डी. के. कर्वे (D) इनमें से कोई नहीं

226. सन् 1857 के विद्रोह का सबसे पहले संकेत मिला–
(A) मेरठ में (B) झाँसी में
(C) कानपुर में (D) बंगाल में

227. "स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर ही रहूँगा" किस आन्दोलन के दौरान नारा दिया गया ?
(A) सत्याग्रह आन्दोलन में
(B) स्वतन्त्रता आन्दोलन में
(C) होमरूल लीग आन्दोलन में
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

228. भारत के बड़े व्यापारियों ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था–
(A) उन्हें भारतीय सैनिकों पर भरोसा नहीं था
(B) उनका लाभ ब्रिटिश शासकों से था
(C) विद्रोहियों के द्वारा सताए गए थे
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

229. "तुम्हारी भक्ति व मुक्ति की परवाह किसे है." किसने कहा था ?
(A) महात्मा गांधी ने (B) विनोबा भावे ने

230. सन् 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे ?
(A) सुभाष चन्द्र बोस व भगतसिंह
(B) चन्द्रशेखर व राजगुरू
(C) दादाभाई नौरोजी व महात्मा गांधी
(D) बहादुरशाह जफर व नाना साहब

231. हिन्दू धर्म को 'जादू, अन्धविश्वास, अध्यात्मवाद की खिचड़ी' किसने कहा था ?
(A) मो. अली जिन्ना ने
(B) गोपाल कृष्ण गोखले ने
(C) नाना साहब ने
(D) मैक्स वेबर ने

232. महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा कब प्रारम्भ की थी ?
(A) 12 मार्च, 1930 को (B) 12 मार्च, 1929 को
(C) 12 मार्च, 1931 को (D) 12 मार्च, 1926 को

233. भारतीय ग्लेडस्टोन की उपाधि दी गई–
(A) नाना साहब को (B) स्वामी विवेकानन्द को
(C) महात्मा गांधी को (D) दादाभाई नौरोजी को

234. धन निकासी सिद्धान्त किसने दिया था ?
(A) महात्मा गांधी ने (B) दादाभाई नौरोजी ने
(C) एनीबेसेन्ट ने (D) एम. जी. रानाडे ने

235. सर सैय्यद अहमद खाँ की दिली-तमन्ना क्या थी ?
(A) समाज सुधार (B) गरीबों की सेवा
(C) धर्म सुधार (D) शिक्षा का सुधार

236. 'हिन्द स्वराज्य' पुस्तक के लेखक थे–
(A) महात्मा गांधी (B) मोतीलाल नेहरू
(C) पं. जवाहरलाल नेहरू (D) राजा राममोहन राय

237. किस भारतीय ने जलियाँवाला बाग के काण्ड के विरोध में वायसराय की कार्य परिषद् से त्यागपत्र दिया था ?
(A) सर शंकरराय ने (B) मोतीलाल नेहरू ने
(C) सुभाष चन्द्र बोस ने (D) इनमें से कोई नहीं

238. सूरमा घाटी किसान आन्दोलन का सम्बन्ध है–
(A) पंजाब से (B) म. प्र. से
(C) मेघालय से (D) असम से

239. प्रथम ऐतिहासिक सम्राट् कहा जाता है–
(A) अकबर को (B) बाबर को
(C) सिकन्दर को (D) चन्द्रगुप्त मौर्य को

240. सैनिकों की किस वर्ष निःशुल्क डाक सेवा समाप्त की गई ?
(A) 1850 ई. में (B) 1854 ई. में
(C) 1809 ई. में (D) 1835 ई. में

241. सती प्रथा "किसी भी शास्त्र के अनुसार यह हत्या है." किसने कहा था ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) राजा राममोहन राय ने
(C) पं. मदन मोहन मालवीय ने
(D) मोतीलाल नेहरू ने

242. माउण्टबेटन योजना कब बनी थी ?
(A) 2 जून, 1947 को (B) 4 जून, 1948 को
(C) 10 जून, 1950 को (D) 3 जून, 1947 को

243. दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय है–
(A) लॉर्ड डफरिन को (B) लॉर्ड एलन बरो को
(C) राजा राममोहन राय को (D) महात्मा गांधी को

244. वासुदेव बलवन्त फड़के ने महाराष्ट्र में कब बड़े पैमाने पर डाइबाजी की थी ?
(A) 1879 ई. में (B) 1880 ई. में
(C) 1870 ई. में (D) 1890 ई. में

245. जाति व्यवस्था के आलोचक कौन थे ?
(A) ज्योतिबा फुले (B) पं. मोती लाल नेहरू
(C) मो. अली जिन्ना (D) इनमें से कोई नहीं

246. "हिन्दू वकीलों के मुकाबले मुसलमान वकील ज्यादा ईमानदार होते हैं." किसका मानना है ?
(A) महात्मा गांधी का
(B) मोतीलाल नेहरू का
(C) जवाहरलाल नेहरू का
(D) राजा राममोहन राय का

247. भील सेवा मण्डल की स्थापना कब हुई ?
(A) 1922 ई. में (B) 1920 ई. में
(C) 1919 ई. में (D) 1930 ई. में

248. 1765 से 1772 के मध्य की सरकार को "डाकुओं की सरकार" किसने कहा ?
(A) के. एम. पणिक्कर ने (B) स्मिथ ने
(C) आर. सी. मजूमदार (D) के. के. दत्त

249. भारत में महिला आन्दोलन की मुख्य प्रेरणा स्रोत थीं–
(A) रानी लक्ष्मीबाई (B) विजय लक्ष्मी पंडित
(C) रमाबाई (D) एनीबेसेन्ट

250. बक्सर का युद्ध कब हुआ ?
(A) 1764 ई. में (B) 1790 ई. में
(C) 1768 ई. में (D) 1780 ई. में

251. राममोहन राय को 'राजा' की उपाधि प्रदान की थी–
(A) अकबर द्वितीय ने (B) औरंगजेब ने
(C) बहादुर शाह जफर ने (D) इनमें से कोई नहीं

252. किसके शासनकाल में रेल बम्बई से थाणे (ठाणे) तक चली ?
(A) लॉर्ड डलहौजी (B) मीर कासिम
(C) शाह आलम (D) लॉर्ड मैकाले

253. भारतीय ट्रैड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे–
(A) राजा राममोहन राय
(B) महात्मा गांधी
(C) पं. मदनमोहन मालवीय
(D) एम. एन. जोशी

254. मद्रास में हिन्दू संगठन की स्थापना कब हुई ?
(A) सन् 1904 ई. में (B) सन् 1906 ई. में
(C) सन् 1908 ई. में (D) सन् 1910 ई. में

255. सबसे पहले 'सहायक सन्धि' स्वीकार की–
(A) सिंधिया ने (B) निजाम ने
(C) अवध ने (D) तंजौर ने

256. स्वामी विवेकानन्द ने विश्वधर्म सम्मेलन सम्बोधित किया था–
(A) 1883 ई. में (B) 1895 ई. में
(C) 1899 ई. में (D) 1893 ई. में

257. दादाभाई नौरोजी का जन्म हुआ था–
(A) 1825 ई. में (B) 1824 ई. में
(C) 1826 ई. में (D) इनमें से कोई नहीं

258. 1781 ई. में कलकत्ता मदरसा की नींव डाली थी–
(A) विलियम जोंस ने (B) जोनाथन टंकन ने
(C) वारेन हेस्टिंग्स ने (D) इनमें से किसी ने नहीं

259. 'बंगाली' नामक अखबार के सम्पादक थे–
(A) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (B) प्रकाश नारायण
(C) महावीर प्रसाद द्विवेदी (D) इनमें से कोई नहीं

260. भारतीय भाषाओं में समाचार-पत्रों को प्रकाशित करने से रोकने के लिए कब एक्ट पारित किया गया था ?
(A) 1878 ई. में (B) 1880 ई. में
(C) 1890 ई. में (D) 1870 ई. में

261. 'मिरात उल' अखबार के लेखक थे–
(A) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (B) राजा राममोहन राय
(C) देवेन्द्रनाथ टैगोर (D) दयानन्द सरस्वती

262. गांधीजी के राजनीतिक गुरु कौन थे ?
(A) गोपाल कृष्ण गोखले (B) लोकमान्य तिलक
(C) महादेव गोविन्द रानाडे (D) इनमें से कोई नहीं

263. 1899 ई. में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की ?
(A) राजा राममोहन राय ने
(B) प्रो. डी. के. कर्वे ने
(C) महात्मा गांधी ने
(D) लाल बहादुर शास्त्री ने

264. विलियम जोन्स ने किस स्थान पर एशियाटिक सोसायटी की स्थापना की ?
(A) कानपुर में (B) लाहौर में
(C) मद्रास में (D) कलकत्ता में

265. महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई ?
(A) सन् 1906 ई. में (B) सन् 1910 ई. में
(C) सन् 1940 ई. में (D) सन् 1908 ई. में

266. गोपाल कृष्ण गोखले किसके अनुयायी थे ?
(A) दादाभाई नौरोजी के (B) तिलकजी के
(C) गोविन्द रानाडे के (D) इनमें से कोई नहीं

267. जनता के बीच 'लाल कुटी वाले के रूप में' जाने जाते थे–
(A) महात्मा गांधी (B) गोपाल कृष्ण गोखले
(C) राजा राममोहन राय (D) अब्दुल गफ्फार खाँ

268. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना कब की थी ?
(A) 1875 ई. में (B) 1870 ई. में
(C) 1880 ई. में (D) 1878 ई. में

269. "वेदों की ओर लौटो." किसने कहा था ?
(A) राजा राममोहन राय ने (B) दयानन्द सरस्वती ने
(C) विवेकानन्द ने (D) रामकृष्ण परमहंस

270. दादाभाई नौरोजी का व्यवसाय था–
(A) व्यापारी थे (B) किसान थे
(C) डॉक्टर थे (D) इन्जीनियर थे

271. "दुनिया के सभी स्थापित धर्म सच हैं." किसने कहा ?
(A) केशवचन्द्र सेन ने (B) महात्मा गांधी ने
(C) मोतीलाल नेहरू ने (D) इनमें से कोई नहीं

272. 1890 ई. में बम्बई में मिल हैण्ड एसोसिएशन की स्थापना किसने की ?
(A) टाटा ने (B) मानवेन्द्र राय ने
(C) पी. सी. जोशी ने (D) एम. एन. लोखाण्डी

273. आगरा में 1861 ई. में राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे–
(A) माधो प्रसाद जी
(B) स्वामी शिवदयाल सिंह
(C) पं. ब्रह्म शंकर मिश्र
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

274. ब्रिटिश साम्राज्य ने किस वर्ष गुलामी को समाप्त कर दिया था ?
(A) 1833 ई. में (B) 1840 ई. में
(C) 1834 ई. में (D) 1835 ई. में

275. विश्व बैंक की स्थापना कब हुई ?
(A) 1950 ई. में (B) 1945 ई. में
(C) 1948 ई. में (D) 1940 ई. में

276. पारसी समाज सुधारक कौन थे ?
(A) जमशेद जी (B) दादा भाई नौरोजी
(C) वहराम जी मालाबारी (D) इनमें से कोई नहीं

277. "उद्योगीकरण एक बेहतर व ऊँचे दर्जे की सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है." किसने कहा था ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) मदन मोहन मालवीय ने
(C) जी. वी. जोशी ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

278. लखनऊ समझौता हुआ था–
(A) 1916 ई. में (B) 1920 ई. में
(C) 1904 ई. में (D) 1908 ई. में

279. किसको 'नवराष्ट्रवादी' कहा जाता है ?
(A) उग्रवादियों को (B) समाजवादियों को
(C) उदारवादियों को (D) साम्यवादियों को

280. असहयोग आन्दोलन का विरोध किया था–
(A) लाला लाजपत राय ने (B) महात्मा गांधी ने
(C) मोतीलाल नेहरू ने (D) सी. आर. दास ने

281. भारत की गरीबी की समस्या को गम्भीरता से समझा था–
(A) महात्मा गांधी ने
(B) राजा राममोहन राय ने
(C) दादाभाई नौरोजी ने
(D) नाना साहब ने

282. "भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूँजी एक अनिवार्य शर्त है." किसने कहा था ?
(A) लॉर्ड कर्जन ने
(B) गोपाल कृष्ण गोखले ने
(C) अल्फ्रेड मासिल ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

283. अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम महिला अध्यक्षा थीं–
(A) सरोजनी नायडू
(B) कमलादेवी चट्टोपाध्याय
(C) एनीबेसेन्ट
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

284. द्वितीय कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ ?
(A) 1881 ई. में (B) 1885 ई. में
(C) 1891 ई. में (D) 1810 ई. में

285. "ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है." किसने कहा था ?
(A) लाला लाजपतराय ने (B) मोतीलाल नेहरू ने
(C) सुभाष चन्द्र बोस ने (D) दादाभाई नौरोजी ने

286. महाराष्ट्र में 'सत्यशोधक पार्टी' की स्थापना कब हुई ?
(A) 1873 ई. में (B) 1840 ई. में
(C) 1850 ई. में (D) 1833 ई. में

287. "भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान स्वशासन है." कब कहा गया ?
(A) सन् 1905 ई. में (B) सन् 1910 ई. में
(C) सन् 1909 ई. में (D) सन् 1904 ई. में

288. प्रजा मित्र मण्डली की स्थापना की थी–
(A) सी. आर. रेड्डी ने (B) एम. वी. नायडू ने
(C) सीता राम राजू ने (D) महात्मा गांधी ने

289. होमरूल शब्द कहाँ के आन्दोलन से लिया गया ?
(A) आयरलैण्ड से (B) अमरीका से
(C) रूस से (D) फ्रांस से

290. भारतीय पूँजी के निकास की बात सबसे पहले कही थी–
(A) महात्मा गांधी ने
(B) दादाभाई नौरोजी ने
(C) मोतीलाल नेहरू ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

291. सिंह सभा आन्दोलन का प्रारम्भ कहाँ से हुआ ?
(A) बनारस से (B) कानपुर से
(C) अमृतसर से (D) आगरा से

292. 1824 ई. में प्रेस पर अंकुश लगाने वाले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को किसने ज्ञापन भेजा था ?
(A) मोतीलाल नेहरू ने
(B) महात्मा गांधी ने
(C) राजा राममोहन राय ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

293. निम्नलिखित में से कौन महानतम सन्त थे ?
(A) तुकाराम (B) नामदेव
(C) गोवर्धन (D) नारायण पंडित

294. खान बहादुर खान की गतिविधियों का केन्द्र था–
(A) मेरठ (B) कानपुर
(C) दिल्ली (D) बरेली

295. निरंकारी आन्दोलन के प्रवर्तक थे–
(A) दयाल दास (B) सन्त निरंकारी
(C) बन्दा वैरागी (D) महात्मा गांधी

296. 'हिन्दुस्तानी' अखबार (News Paper) के सम्पादक थे–
(A) बाल गंगाधर तिलक (B) मोतीलाल घोष
(C) गोपाल कृष्ण गोखले (D) दादाभाई नौरोजी

297. ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया–
(A) 1884 ई. में (B) 1870 ई. में
(C) 1890 ई. में (D) 1880 ई. में

298. ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में 124 ए को कब जोड़ा ?
(A) 1870 ई. में (B) 1875 ई. में
(C) 1890 ई. में (D) 1880 ई. में

299. ताना भगत आन्दोलन का सम्बन्ध है–
(A) बंगाल से (B) बिहार से
(C) उड़ीसा से (D) मध्य प्रदेश से

300. लॉर्ड डफरिन ने ब्रिटिश भारत के अधीन नेपाल को कब किया ?
(A) 1818 ई. में (B) 1820 ई. में
(C) 1830 ई. में (D) 1815 ई. में

301. 'वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट' कब वापस लिया गया ?
(A) 1882 ई. में (B) 1880 ई. में
(C) 1881 ई. में (D) 1890 ई. में

302. 'मुस्लिम लीग' के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) अब्दुल कलाम आजाद ने
(C) मदन मोहन मालवीय ने
(D) सर सैय्यद अहमद खाँ ने

303. निम्नलिखित में से 'एण्डिया ए नेशन-1934' नामक पुस्तक की लेखिका कौन थी ?
(A) एनीबेसेन्ट
(B) सुचेता कृपलानी
(C) सरोजनी नायडू
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

304. लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कब भाषण दिया ?
(A) सन् 1905 ई. में (B) सन् 1906 ई. में
(C) सन् 1910 ई. में (D) सन् 1908 ई. में

305. 'वन्दे मातरम्' पत्रिका के सम्पादक थे–
(A) विपिन चन्द्र पाल (B) बाल गंगाधर तिलक
(C) अरविन्दो घोष (D) राजा राममोहन राय

306. पत्रकारिता के कारण किस भारतीय को सजा दी गई ?
(A) बाल गंगाधर तिलक को
(B) मोती लाल घोष को
(C) गोपाल कृष्ण गोखले
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

307. हरिजन संघ के संस्थापक थे–
(A) महात्मा गांधी (B) भीमराव अम्बेडकर
(C) रामा स्वामी नय्यर (D) इनमें से कोई नहीं

308. विदेशी 'वस्त्र बहिष्कार' आन्दोलन चलाया–
(A) महात्मा गांधी ने
(B) बाल गंगाधर तिलक ने
(C) मोती लाल नेहरू ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

309. महाराष्ट्र में जाति विरोधी व ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन चलाया–
(A) ज्योतिबा फुले ने (B) देशमुख ने
(C) महात्मा गांधी ने (D) भीमराव अम्बेडकर ने

310. 'कोई टेक्स नहीं' अभियान कब चलाया गया ?
(A) 1896-97 ई. में (B) 1893-94 ई. में
(C) 1897-98 ई. में (D) 1899-1900 ई. में

311. 'सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डियन सोसाइटी' की स्थापना की थी–
(A) गोपाल कृष्ण गोखले ने (B) महात्मा गांधी ने
(C) दादा भाई नौरोजी ने (D) रानाडे ने

312. शारदा एक्ट के तहत निर्धारित किया गया–
(A) महिलाओं की नौकरी
(B) विधवा विवाह
(C) लड़की व लड़के के विवाह की आयु
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

313. राजद्रोह के अभियोग में तिलक को गिरफ्तार किया गया–
(A) 1897 को (B) 1899 को
(C) 1870 को (D) 1890 को

314. डी. के. कर्वे का महाराष्ट्र में योगदान है–
(A) शिक्षा के क्षेत्र में
(B) संगीत के क्षेत्र में
(C) विधवाओं की स्थिति के सुधार के लिए
(D) सामाजिक उत्थान के लिए

315. 'पादशाहनामा' के लेखक थे–
(A) अबुल फजल (B) अब्दुल हमीद लाहोरी
(C) अब्दुल कादर (D) इनमें से कोई नहीं

316. अंग्रेजों ने सबसे अधिक लूटपाट की थी–
(A) अवध में (B) मैसूर में
(C) हैदराबाद में (D) जोधपुर में

317. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान का क्षेत्र है–
(A) बाल विवाह की समाप्ति
(B) सती प्रथा उन्मूलन
(C) दास प्रथा का अन्त
(D) विधवा पुनर्विवाह

318. 'बहिष्कार आन्दोलन' की अगवानी की–
(A) बाल गंगाधर तिलक ने
(B) महात्मा गांधी ने
(C) भगत सिंह ने
(D) राजा राममोहन राय ने

319. राजा राममोहन राय के प्रथम शिष्य थे–
(A) केशवचन्द्र सेन (B) देवेन्द्रनाथ टैगोर
(C) ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (D) रामचन्द्र विद्या वागीश

320. बाल गंगाधर तिलक को पुनः कब गिरफ्तार किया गया ?
(A) 24 जून, 1908 को (B) 28 जून, 1909 को
(C) 10 जून, 1904 को (D) 10 जून, 1905 को

321. 1828 ई. में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित वृद्ध समाज को आध्यात्मिक रूप दिया–
(A) देवेन्द्रनाथ टैगोर ने
(B) केशवचन्द्र सेन ने
(C) महादेव गोविन्द रानाडे ने
(D) ईश्वरचन्द्र विद्या सागर ने

322. गांधीजी को छः साल की सजा सुनाई गई–
(A) 1922 ई. में (B) 1925 ई. में
(C) 1926 ई. में (D) 1930 ई. में

323. स्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई ?
(A) सम्पूर्ण भारत में
(B) उत्तर भारत में
(C) उत्तर प्रदेश में
(D) बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में

324. बम्बई में सामाजिक सेवा संघ की स्थापना की थी–
(A) एम. एन. राय ने
(B) एम. एन. जोशी ने
(C) पी. सी. जोशी ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

325. "विधान परिषदों का दायरा बढ़ाया जाए." कब कहा गया ?
(A) 1892 ई. में (B) 1890 ई. में
(C) 1870 ई. में (D) 1899 ई. में

326. हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की–
(A) लाला लाजपत राय ने (B) लाला हंसराज ने
(C) गुरुदत्त ने (D) स्वामी दयानन्द ने

327. फीरोजशाह मेहता का जन्म कब हुआ था ?
(A) 1845 ई. में (B) 1850 ई. में
(C) 1856 ई. में (D) 1849 ई. में

328. "मानव सेवा ही भगवान की सेवा है." किसने कहा ?
(A) स्वामी विवेकानन्द ने (B) महात्मा गांधी ने
(C) स्वामी दयानन्द ने (D) रामकृष्ण परमहंस ने

329. फीरोज शाह मेहता ने विधान परिषद् में कब हस्तक्षेप किया ?
(A) 1895 ई. में (B) 1890 ई. में
(C) 1891 ई. में (D) 1899 ई. में

330. गोपाल कृष्ण गोखले को कब विधान परिषद् का सदस्य चुना गया ?
(A) 1901 ई. में (B) 1904 ई. में
(C) 1908 ई. में (D) 1909 ई. में

331. यंग बंगाल का मुख्य पत्र कौनसा था, जो आन्दोलन का कारण बना ?
(A) बंगाल डाइजेस्ट (B) बंगाल स्पेक्टर
(C) नील दर्पण (D) बंगाल क्रोनिकल

332. गोखले का मुख्य भाषण का केन्द्र था–
(A) भारत में अराजकता
(B) भारत की गरीबी
(C) ब्रिटिश उत्पीड़न
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

333. बंगाल जूट श्रमिकों की पहली हड़ताल हुई–
(A) 1919 ई. में (B) 1939 ई. में
(C) 1942 ई. में (D) 1922 ई. में

334. सन् 1905 ई. में निम्नलिखित में से किसका विभाजन हुआ ?
(A) असम (B) बंगाल
(C) बर्मा (D) पाकिस्तान

335. स्वदेशी आन्दोलन की घोषणा की गई–
(A) कलकत्ता में (B) असम में
(C) मद्रास में (D) कानपुर में

336. कूका आन्दोलन को आरम्भ किसने कराया था ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) भगत जवाहरमल ने
(C) दादू मियां ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

337. स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे ?
(A) आचार्य जे. वी. कृपलानी
(B) मोती लाल नेहरू
(C) महात्मा गांधी
(D) विनोबा भावे

338. महात्मा गांधी भारत वापस आए थे–
(A) सन् 1920 ई. में (B) सन् 1930 ई. में
(C) सन् 1915 ई. में (D) सन् 1913 ई. में

339. महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन चलाया था–
(A) 1921 ई. में (B) 1925 ई. में
(C) 1926 ई. में (D) 1928 ई. में

340. 1921 ई. में मोपला विद्रोह हुआ था–
(A) कानपुर में (B) केरल में
(C) मद्रास में (D) पंजाब में

341. चौरी-चौरा काण्ड का प्रभाव किस आन्दोलन पर पड़ा ?
(A) असहयोग आन्दोलन (B) कूका आन्दोलन
(C) स्वतन्त्रता आन्दोलन (D) इनमें से कोई नहीं

342 कस्तूरबा की मृत्यु कब हुई ?
(A) 1944 ई. में (B) 1945 ई. में
(C) 1949 ई. में (D) 1948 ई. में

343. भारत-पाक सीमा रेखा को निर्धारित किया था–
(A) सर रेड क्लिफ ने
(B) महात्मा गांधी ने
(C) मो. जिन्ना ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

344. मुस्लिम साहित्यिक की स्थापना कहाँ की गई ?
(A) पंजाब में (B) मद्रास में
(C) सूरत में (D) कलकत्ता में

345. भारतीय समाजवादी दल की स्थापना हुई थी–
(A) 1955 ई. में (B) 1960 ई. में
(C) 1966 ई. में (D) 1957 ई. में

346. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे–
(A) जय प्रकाश नारायण ने
(B) डॉ. राम मनोहर लोहिया ने
(C) आचार्य नरेन्द्र देव ने
(D) उपर्युक्त सभी ने

347. 'भारत में समाजवाद' पुस्तक के लेखक थे–
(A) जय प्रकाश नारायण (B) महात्मा गांधी
(C) सरोजनी नायडू (D) इनमें से कोई नहीं

348. सत्याग्रह का उद्घाटन किया था–
(A) महात्मा गांधी ने (B) कस्तूरबा ने
(C) विनोबा भावे ने (D) मोती लाल नेहरू ने

349. वेदान्त विद्यालय के संस्थापक थे–
(A) राजा राममोहन राय (B) केशवचन्द्र सेन
(C) देवेन्द्रनाथ टैगोर (D) एनीबेसेन्ट

350. मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष थे–
(A) मो. अली जिन्ना (B) आगा खाँ
(C) जाकिर हुसैन (D) इनमें से कोई नहीं

351. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया–
(A) 1857 ई. में (B) 1867 ई. में
(C) 1856 ई. में (D) 1840 ई. में

352. 26 जनवरी, 1950 से 12 जनवरी, 1952 के मध्य के भारत के राष्ट्रपति थे–
(A) डॉ. जाकिर हुसैन (B) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(C) डॉ. शंकर दयाल शर्मा (D) इनमें से कोई नहीं

353. "केवल धर्म से भूख शान्त नहीं हो सकती." किसने कहा था ?
(A) स्वामी विवेकानन्द ने (B) रवीन्द्र नाथ टैगोर ने
(C) महात्मा गांधी ने (D) रामकृष्ण परमहंस ने

354. 23 मार्च को किसका शहादत दिवस है ?
(A) आजाद का
(B) भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव का
(C) लाला लाजपतराय का
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

355. हरिद्वार के निकट गुरुकुल की स्थापना कब हुई ?
(A) सन् 1910 ई. में (B) सन् 1930 ई. में
(C) सन् 1902 ई. में (D) सन् 1905 ई. में

356. 'दर्पण' साप्ताहिक की शुरूआत कब हुई थी ?
(A) 1930 ई. में (B) 1932 ई. में
(C) 1940 ई. में (D) 1950 ई. में

357. "हिन्दू मुसलमान भारत के दो नेत्र हैं." किसने कहा था ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) मोतीलाल ने
(C) सर सैय्यद अहमद खाँ ने
(D) मो. अली जिन्ना ने

358. राजा राममोहन राय के घनिष्ठतम मित्र थे–
(A) केशव चन्द्र से (B) द्वारका नाथ टैगोर
(C) चन्द्रशेखर देव (D) इनमें से कोई नहीं

359. वह अंग्रेज जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी–
(A) जॉर्ज यूल ने
(B) लॉर्ड कर्जन ने
(C) लॉर्ड एलनवरी ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

360. 'औरत' नामक फिल्म कब बनी थी ?
(A) सन् 1940 ई. में (B) सन् 1948 ई. में
(C) सन् 1950 ई. में (D) सन् 1960 ई. में

361. 'आमार सोनार बाँगला' किस देश का राष्ट्रगान है ?
(A) भारत (B) पाकिस्तान
(C) अफगानिस्तान (D) बांग्लादेश

362. किस वर्ष को महान् विभाजक का वर्ष माना जाता है ?
(A) 1921 ई. में (B) 1925 ई. में
(C) 1930 ई. में (D) 1947 ई. में

363. भारत की वह महान् विभूति, जो लोकसभा अध्यक्ष व राष्ट्रपति रहे–
(A) ज्ञानी जैल सिंह
(B) डॉ. शंकर दयाल शर्मा
(C) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(D) नीलम संजीव रेड्डी

364. 'पार्वती परियोजना' का निर्माण हुआ था–
(A) 1959 ई. में (B) 1960 ई. में
(C) 1940 ई. में (D) 1945 ई. में

365. किसने कहा था–"वैदिक ग्रन्थ कभी गलत नहीं हो सकते" ?
(A) दादा भाई नौरोजी ने
(B) राजा राममोहन राय ने
(C) देवेन्द्रनाथ टैगोर ने
(D) महात्मा गांधी ने

366. आधुनिक राजनीति की शुरूआत किस आन्दोलन से हुई ?
(A) सत्याग्रह से
(B) भूमि आन्दोलन से
(C) स्वदेशी आन्दोलन से
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

367. 'नव दिन का प्रातः का तारा' (Morning star) किसे कहा जाता है ?
(A) महात्मा गांधी को
(B) राजा राममोहन राय को
(C) लाला लाजपतराय को
(D) मदन मोहन मालवीय को

368. ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक केन्द्र था–
(A) कानपुर में (B) बनारस में
(C) ग्वालियर में (D) देहरादून में

369. स्वदेशी आन्दोलन के विरोधी थे–
(A) पं. मोतीलाल (B) भगतसिंह
(C) सलीमुल्लाह (D) इनमें से कोई नहीं

370. आधुनिक भारत के 'अग्रदूत' के रूप में जाने जाते थे–
(A) स्वामी दयानन्द (B) मदन मोहन मालवीय
(C) राजा राममोहन राय (D) सुभाष चन्द्र बोस

371. "भारत भारतीयों के लिए है." किसने कहा ?
(A) मोती लाल नेहरू ने
(B) गोपाल कृष्ण गोखले ने
(C) लाला लाजपत राय ने
(D) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने

372. भारत में हिन्दू-मुस्लिम दंगे कब हुए ?
(A) 1907 ई. में (B) 1910 ई. में
(C) 1914 ई. में (D) 1908 ई. में

373. कांग्रेस का विभाजन हुआ था–
(A) 1907 ई. में (B) 1909 ई. में
(C) 1904 ई. में (D) 1910 ई. में

374. फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया था–
(A) महिला मजदूरों पर
(B) बाल मजदूरों पर
(C) शिप कारखानों पर
(D) सभी मजदूरों पर

375. नरमपंथियों ने किस प्रान्त में स्वदेशी आन्दोलन में भाग लिया ?
(A) असम में (B) बंगाल में
(C) तमिलनाडु में (D) पंजाब में

376. राजा राममोहन राय ने विरोध किया था–
(A) मूर्ति पूजा का
(B) धार्मिक कर्मकाण्ड का
(C) जातिवाद का
(D) उपर्युक्त सभी का

377. अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस को कहा–
(A) राजद्रोह का कारखाना (B) लड़ाकू संगठन
(C) सशक्त पार्टी (D) दुर्बल पार्टी

378. स्वामी दयानन्द सरस्वती किसकी सत्यता में विश्वास नहीं करते थे ?
(A) पुराण (B) वेद
(C) उपनिषद् (D) उपर्युक्त सभी

379. सन् 1900 ई. में किसने कहा था– "कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है" ?
(A) जॉर्ज हैमिल्टन (B) लॉर्ड मिंटो
(C) लॉर्ड रिपिन (D) इनमें से कोई नहीं

380. किस वर्ष देवेन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का गठन किया ?
(A) 1940 ई. में (B) 1950 ई. में
(C) 1970 ई. में (D) 1843 ई. में

381. डाण्डी यात्रा में कितने गांधीजी के सहयोगियों ने भाग लिया ?
(A) 80 (B) 70
(C) 78 (D) 100

382. माण्डले की जेल स्थित है–
(A) पंजाब में (B) बर्मा में
(C) गुजरात में (D) कानपुर में

383. गांधीजी ने किसके सन्दर्भ में कहा था–"मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया" ?
(A) शौकत अली के
(B) मोहम्मद अली के
(C) लाला लाजपत राय के
(D) बाल गंगाधर तिलक के

384. सन् 1819 ई. में "मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी" की स्थापना की थी–
(A) अमीर अली ने
(B) नवाब अब्दुल लतीफ खाँ ने
(C) मोहम्मद अली जिन्ना ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

385. राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी ?
(A) ब्रिस्टल (B) बाम्बे
(C) कानपुर (D) मद्रास

386. नामसूद्र किसान का सम्बन्ध किस स्थान से था ?
(A) पटना से (B) बंगाल से
(C) बिहार से (D) कानपुर से

387. भारत के प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई ?
(A) कानपुर में (B) मुम्बई में
(C) चेन्नई में (D) कोलकाता में

388. अंग्रेजी हुकूमत ने राजद्रोह का कारखाना किसे कहा था ?
(A) जनता दल को
(B) समाजवाद को
(C) कांग्रेस को
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

389. परमहंस मण्डली की स्थापना कहाँ हुई थी ?
(A) कानपुर में (B) महाराष्ट्र में
(C) बिहार में (D) दिल्ली में

390. भारत में वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रथम कानून बना–
(A) 1879 ई. में (B) 1890 ई. में
(C) 1840 ई. में (D) 1845 ई. में

391. लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब से सिंहासन छोड़ने के लिए कब कहा था ?
(A) 1856 ई. को (B) 1850 ई. को
(C) 1870 ई. को (D) 1850 ई. को

392. भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया ?
(A) 1927 ई. में (B) 1930 ई. में
(C) 1940 ई. में (D) 1935 ई. में

393. लन्दन में कर्जन वाइली की हत्या की थी–
(A) सुभाष चन्द्र बोस ने (B) मदन लाल धींगरा ने
(C) भगत सिंह ने (D) इनमें से कोई नहीं

394. किसके नेतृत्व में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के लिए क्रान्तिकारियों ने असफल प्रयास किया था ?
(A) सुभाष चन्द्र बोस
(B) खुदीराम बोस
(C) रास बिहारी बोस व सचिन सान्याल
(D) इनमें से कोई नहीं

395. शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन के समय स्वामी विवेकानन्द की आयु थी–
(A) 25 वर्ष (B) 30 वर्ष
(C) 40 वर्ष (D) 50 वर्ष

396. रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था–
(A) 1836 ई. में (B) 1840 ई. में
(C) 1830 ई. में (D) 1850 ई. में

397. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर किस वर्ष संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य बने ?
(A) 1850 ई. में (B) 1851 ई. में
(C) 1860 ई. में (D) 1840 ई. में

398. वारदौली में 'कर नहीं' आन्दोलन किसने चलाया था ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) पं. मोतीलाल नेहरू ने
(C) मदन मोहन मालवीय ने
(D) सरदार वल्लभ भाई पटेल ने

399. रामकृष्ण मिशन का ईष्टदेव था–
(A) काली माँ (B) हनुमान जी
(C) शंकर जी (D) इनमें से कोई नहीं

400. 'हण्टर कमीशन की स्थापना' किस क्षेत्र में सुधार के लिए की गयी थी ?
(A) शिक्षा के क्षेत्र में
(B) कृषि के क्षेत्र में
(C) क्रान्ति के क्षेत्र में
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

401. स्वामी विवेकानन्द का प्रारम्भिक नाम था–
(A) नरेन्द्र (B) महेन्द्र
(C) जितेन्द्र (D) गजेन्द्र

402. स्वदेशी आन्दोलन कब समाप्त हुआ ?
(A) सन् 1908 ई. में
(B) सन् 1905 ई. में
(C) सन् 1909 ई. में
(D) सन् 1904 ई. में

403. स्वामी विवेकानन्द का जन्म कहाँ हुआ था ?
(A) कलकत्ता में (B) बनारस में
(C) कानपुर में (D) पटना में

404. "विभाजन का मतलब विनाश होता है." किसने कहा था ?
(A) महात्मा गांधी ने (B) मोतीलाल ने
(C) गोखले ने (D) पं. नेहरू ने

405. विधवा विवाह की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी ?
(A) महादेव गोविन्द रानाडे ने
(B) महात्मा गांधी ने
(C) राजा राममोहन राय ने
(D) डेविड हेयर ने

406. तामलूक जातीय सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी ?
(A) पश्चिमी बंगाल में (B) बिहार में
(C) कर्नाटक में (D) तमिलनाडु में

407. भारतीयों को कनाडा में घुसने से रोका गया–
(A) 1908 ई. में (B) 1910 ई. में
(C) 1919 ई. में (D) 1915 ई. में

408. रैण्ड की हत्या किसने की थी ?
(A) भगत सिंह ने (B) प्रफुल्ल चाकी ने
(C) खुदीराम बोस ने (D) दामोदर चापेकर ने

409. 'अखिल भारतीय खादी समिति' की स्थापना कब हुई ?
(A) 1922 ई. में (B) 1925 ई. में
(C) 1929 ई. में (D) 1930 ई. में

410. ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई ?
(A) अमरीका में (B) जर्मनी में
(C) लन्दन में (D) भारत में

411. बंगाल के विभाजक थे–
(A) लॉर्ड कर्जन (B) जॉर्ज यूले
(C) विलियम जोन्स (D) करमशाह

412. पागल पंथ नामक अर्द्ध धार्मिक सम्प्रदाय को किसने चलाया ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) मदन मोहन मालवीय ने
(C) टीटू मीर ने
(D) करमशाह ने

413. डांडी यात्रा के तहत कितने किमी की दूरी पैदल तय की थी ?
(A) 500 किमी (B) 800 किमी
(C) 400 किमी (D) 300 किमी

414. 1857 ई. में रुहेलखण्ड में विद्रोह का नेता कौन था ?
(A) हसन खाँ
(B) खाँ बहादुर खाँ
(C) पीर अली
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

415. 'काला कानून' की उपाधि किसे दी गई ?
(A) रॉलैक्ट एक्ट को (B) शारदा एक्ट को
(C) बंगाल एक्ट (D) इनमें से कोई नहीं

416. 'गौरक्षा संघ' की स्थापना की थी–
(A) मदन मोहन मालवीय ने
(B) बाल गंगाधर तिलक ने
(C) महात्मा गांधी ने
(D) इनमें से कोई नहीं

417. असहयोग आन्दोलन कब वापस लिया गया ?
(A) 1922 ई. में (B) 1940 ई. में
(C) 1930 ई. में (D) 1924 ई. में

418. 'ऐलान-ए-जंग' की घोषणा किसने की थी ?
(A) कांग्रेस पार्टी ने (B) गदर पार्टी ने
(C) जनता पार्टी ने (D) इनमें से कोई नहीं

419. 'शोर कमेटी' (तृतीय समिति) का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था ?
(A) बलवन्त सिंह के (B) महात्मा गांधी के
(C) मोती लाल के (D) भगत सिंह के

420. हरदयाल को कब गिरफ्तार किया गया ?
(A) 1914 को (B) 1920 को
(C) 1930 को (D) 1910 को

421. गदर षड्यन्त्र में शामिल होने के आरोप में किसको फाँसी दी गई ?
(A) हरदयाल को
(B) रामचन्द्र को
(C) भगवान सिंह को
(D) करतार सिंह सराबा को

422. आर्य समाज संस्था ने किस आन्दोलन को जन्म दिया ?
(A) नील आन्दोलन (B) गदर आन्दोलन
(C) भारत छोड़ो आन्दोलन (D) शुद्धि आन्दोलन

423. आन्दोलनकारियों ने रास बिहारी बोस को अपना नेता कब चुना ?
(A) 1915 को (B) 1914 को
(C) 1919 को (D) 1926 को

424. कांग्रेस समाजवादी दल का गठन कब हुआ ?
(A) 1940 ई. में (B) 1937 ई. में
(C) 1938 ई. में (D) 1934 ई. में

425. पंजाब में किसान आन्दोलन की नींव किसने डाली ?
(A) जनता पार्टी ने
(B) गदर पार्टी ने
(C) कांग्रेस पार्टी ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

426. महान् पितामह के नाम से जाना जाता है–
(A) महात्मा गांधी को (B) मोती लाल नेहरू को
(C) दादा भाई नौरोजी (D) इनमें से कोई नहीं

427. वहावी आन्दोलन कहाँ शुरू हुआ था ?
(A) अरब में (B) भारत में
(C) पाकिस्तान में (D) नेपाल में

428. बाल गंगाधर तिलक की कैद का अधिकांश समय किस जेल में बीता था ?
(A) मांडले जेल में
(B) दिल्ली की जेल में
(C) अण्डमान निकोवार की जेल में
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

429. वामपंथी पक्ष का नेतृत्व किया था–
(A) महात्मा गांधी ने (B) एस. आयंगर ने
(C) भगत सिंह ने (D) सुभाष चन्द्र बोस ने

430. एनीबेसेंट भारत कब आई थीं ?
(A) 1905 ई. में (B) 1893 ई. में
(C) 1890 ई. में (D) 1891 ई. में

431. बम्बई में नौसेना विद्रोहियों का समर्थन किसकी अपील के पक्ष में था ?
(A) महात्मा गांधी (B) जवाहर लाल नेहरू
(C) वल्लभ भाई पटेल (D) राजेन्द्र प्रसाद

432. एनीबेसेंट ने 'न्यू इंडिया व कामन वील' अखबारों को कब प्रकाशित किया था ?
(A) सन् 1915 ई. में (B) सन् 1914 ई. में
(C) सन् 1910 ई. में (D) सन् 1920 ई. में

433. आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन 1929 ई. में कहाँ हुआ था ?
(A) नागपुर में (B) पटना में
(C) पंजाब में (D) कानपुर में

434. लोकमान्य तिलक ने अपने समर्थकों का सम्मेलन 1929 ई. में सर्वप्रथम कहाँ किया था ?
(A) पूना में (B) मणिपुर में
(C) बनारस में (D) कानपुर में

435. राष्ट्रीय कांग्रेस ने आम चुनाव में सात प्रान्तों में कब सरकार बनाई थी ?
(A) 1929 ई. में (B) 1937 ई. में
(C) 1940 ई. में (D) 1920 ई. में

436. होमरूल लीग के गठन की घोषणा कब की गई ?
(A) 1916 ई. में (B) 1920 ई. में
(C) 1914 ई. में (D) 1910 ई. में

437. 1944 ई. में कौनसा आन्दोलन वापस लिया गया ?
(A) वहावी आन्दोलन
(B) नील आन्दोलन
(C) भारत छोड़ो आन्दोलन
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

438. लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है–
(A) कांग्रेस-लीग समझौता
(B) शिमला समझौता
(C) बर्मा समझौता
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

439. जलियाँवाला काण्ड के विरोध में किसने अपनी ब्रिटिश सरकार को 'नाइट हुड' पदवी वापस कर दी थी ?
(A) महात्मा गांधी ने (B) रवीन्द्रनाथ टैगोर ने
(C) तिलक ने (D) मोतीलाल नेहरू ने

440. महात्मा गांधी ने कांग्रेस संविधान कब संशोधित किया ?
(A) 1920 ई. में (B) 1941 ई. में
(C) 1930 ई. में (D) 1915 ई. में

441. एनीबेसेन्ट को कब गिरफ्तार किया गया ?
(A) सन् 1917 ई. में (B) सन् 1910 ई. में
(C) सन् 1920 ई. में (D) सन् 1930 ई. में

442. 'वन्दी जीवन' पुस्तक के लेखक कौन थे ?
(A) खुदी राम वोस (B) महात्मा गांधी
(C) सचीन्द्रनाथ सन्याल (D) राम प्रसाद विस्मिल

443. एनीबेसेन्ट को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कब चुना गया ?
(A) 1917 को (B) 1920 को
(C) 1930 को (D) 1915 को

444. महात्मा गांधी ने किस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की ?
(A) रौलट एक्ट (B) रॉलेक्ट एक्ट
(C) शारदा एक्ट (D) इनमें से कोई नहीं

445. विवेकानन्द को आधुनिक राष्ट्रीय आन्दोलन का अध्यात्मिक पिता कहा था–
(A) महात्मा गांधी ने (B) मोतीलाल ने
(C) लाजपत राय ने (D) सुभाष चन्द्र वोस ने

446. चम्पारण और खेड़ा आन्दोलन था–
(A) किसानों का
(B) अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन
(C) उद्योगपतियों का आन्दोलन
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

447. किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) मदन मोहन मालवीय ने
(C) भीमराव अम्बेडकर ने
(D) मोतीलाल नेहरू ने

448. जलियाँवाला काण्ड में सरकारी आँकड़ों के अनुसार कुल कितने लोगों की जानें गई ?
(A) 379 (B) 410
(C) 415 (D) 420

449. स्वास्थ्य के आधार पर गांधीजी को जेल से कब रिहा किया गया ?
(A) सन् 1923 ई. में (B) सन् 1911 ई. में
(C) सन् 1901 ई. में (D) सन् 1924 ई. में

450. बम्बई में निम्नलिखित में से कौनसा आन्दोलन प्रस्ताव पारित हुआ था ?
(A) भारत छोड़ो आन्दोलन (B) नील आन्दोलन
(C) स्वराज्य आन्दोलन (D) इनमें से कोई नहीं

451. भारत के मुसलमान सन् 1920 ई. में अपना धर्म गुरु किसे मानते थे था ?
(A) तुर्की के खलीफा को
(B) मुहम्मद साहब को
(C) मौलाना साहब को
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

452. गदर पार्टी ने पंजाब में सशस्त्र विद्रोह की योजना कब बनाई थी ?
(A) सन् 1915 ई. में (B) सन् 1910 ई. में
(C) सन् 1904 ई. में (D) सन् 1901 ई. में

453. 'तरुण स्त्री' सभा की स्थापना कहाँ हुई ?
(A) दिल्ली में (B) सूरत में
(C) कानपुर में (D) कलकत्ता में

454. असहयोग आन्दोलन के विरोधी थे–
(A) मोतीलाल नेहरू (B) सुभाष चन्द्र वोस
(C) लाला लाजपत राय (D) सी. आर. दास

455. वहिष्कार आन्दोलन में सबसे सफल आन्दोलन था–
(A) विदेशी कपड़ों का वहिष्कार
(B) विदेशी शिक्षा का वहिष्कार
(C) (A) व (B) दोनों
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

456. अमरीका में गदर पार्टी का गठन किया था–
(A) तारक दास नाथ ने
(B) लाला हरदयाल ने
(C) सोहन सिंह ने
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

457. सन् 1921 ई. में कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था ?
(A) अहमदाबाद में (B) कानपुर में
(C) मेरठ में (D) सूरत में

458. चौरी-चौरा काण्ड के दौरान कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे ?
(A) 25 (B) 20
(C) 22 (D) 40

459. बारदौली प्रस्ताव कब पारित हुआ था ?
(A) 1922 ई. में (B) 1910 ई. में
(C) 1920 ई. में (D) 1930 ई. में

460. मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया–
(A) सन् 1939 ई. में (B) सन् 1940 ई. में
(C) सन् 1935 ई. में (D) सन् 1933 ई. में

461. सन् 1939 ई. में किस महान् व्यक्ति ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था ?
(A) महात्मा गांधी ने
(B) मोतीलाल ने
(C) सुभाष चन्द्र बोस ने
(D) उपर्युक्त में से किसी ने नहीं

462. माण्डले की जेल में निम्नलिखित में से किसने अपना बंदी जीवन व्यतीत नहीं किया ?
(A) सुभाष चन्द्र बोस ने
(B) महात्मा गांधी ने
(C) लोकमान्य तिलक
(D) उपर्युक्त में से किसी ने नहीं

463. भारत विभाजन के सिद्धान्त को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था ?
(A) मोतीलाल ने
(B) जवाहरलाल नेहरू ने
(C) चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने
(D) सभी ने

464. कांग्रेस के किस अधिवेशन में किसानों ने अधिक संख्या में भाग लिया ?
(A) कलकत्ता अधिवेशन में
(B) दिल्ली अधिवेशन में
(C) बनारस अधिवेशन में
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

465. रामविलास विस्मिल व अशफाक उल्ला खाँ को किस मामले में सजा दी गई ?
(A) काकोरी काण्ड (B) मेरठ काण्ड
(C) कानपुर काण्ड (D) लाहौर काण्ड

466. "भारत के बालू में से मैं एक आन्दोलन उत्पन्न करूँगा, जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा," किसने कहा था ?
(A) मोतीलाल ने (B) महात्मा गांधी ने
(C) सुभाष चन्द्र बोस ने (D) चन्द्रशेखर ने

467. खिलाफत आन्दोलन का समर्थन नहीं किया–
(A) मोहम्मद अली जिन्ना ने
(B) महात्मा गांधी ने
(C) मोतीलाल नेहरू ने
(D) मदन मोहन मालवीयजी ने

468. किसान नेता के रूप में सबसे अधिक भूमिका निभाई–
(A) महात्मा गांधी ने (B) नाना साहब ने
(C) राम प्रसाद विस्मिल ने (D) बाबा रामचन्द्र ने

469. आत्मसम्मान आन्दोलन के जनक थे–
(A) रामास्वामी नायकर (B) भीमराव अम्बेडकर
(C) ज्योतिबा फुले (D) सुभाष चन्द्र बोस

470. 'अवध किसान सभा' का गठन कब किया ?
(A) 1920 ई. में (B) 1925 ई. में
(C) 1913 ई. में (D) 1914 ई. में

471. स्वामी विवेकानन्द ने विश्वधर्म सम्मेलन सम्बोधित किया था–
(A) शिकागो में (B) लन्दन में
(C) न्यूयार्क में (D) श्रीलंका में

472. देशद्रोही बैठक अधिनियम किसके विरुद्ध लागू किया गया ?
(A) जमींदारों के विरुद्ध
(B) किसानों के विरुद्ध
(C) क्रान्तिकारियों के विरुद्ध
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

473. सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया–
(A) महात्मा गांधी ने (B) मोतीलाल नेहरू ने
(C) स्वामी विवेकानन्द ने (D) श्री नारायण गुरु ने

474. खिलाफत आन्दोलन के प्रमुख नेता थे–
(A) मोहम्मद अली जिन्ना (B) अली मुदलियार
(C) महात्मा गांधी (D) नारायण गुरु

475. सविनय अवज्ञा आन्दोलन के स्थगन का कारण था–
(A) पूना समझौता
(B) गांधी-इरविन समझौता
(C) गोलमेज सम्मेलन
(D) शिमला समझौता

476. महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था–
(A) एम. जी. रानाडे (B) के. टी. तेलंग
(C) महात्मा गांधी (D) बी. एम. मालावार्रा

477. बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस जेल में हुई ?
(A) दिल्ली की जेल में
(B) अण्डमान निकोबार की जेल में
(C) रंगून की जेल में
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

478. पुणे में होमरूल लीग की स्थापना किसने की ?
(A) महात्मा गांधी ने (B) जवाहरलाल नेहरू ने
(C) एनीबेसेंट ने (D) मोतीलाल नेहरू ने

479. वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई–
(A) खेड़ा सत्याग्रह के दौरान
(B) बारदौली सत्याग्रह के दौरान
(C) बलसाड सत्याग्रह के दौरान
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

480. भारत में विद्युत दूरसंचार का जनक किसे कहा जाता है ?
(A) लॉर्ड डलहौजी को (B) लॉर्ड कैनिंग को
(C) लॉर्ड कर्जन को (D) लॉर्ड लिटिल को

481. टी. एल. ए. की स्थापना अहमदाबाद में किसने की थी ?
(A) महात्मा गांधी ने (B) मोतीलाल नेहरू ने
(C) लाला लाजपतराय ने (D) लोकमान्य तिलक ने

482. "मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ-पाँव हैं." यह नारा कहाँ दिया गया था ?
(A) मद्रास में (B) कानपुर में
(C) बम्बई में (D) दिल्ली में

483. मजदूरों ने किस आन्दोलन में भाग नहीं लिया ?
(A) सविनय अवज्ञा आन्दोलन में
(B) नील आन्दोलन में
(C) किसान आन्दोलन में
(D) उपर्युक्त में से किसी में नहीं

484. अकाली आन्दोलन का मकसद था–
(A) गुरुद्वारों को बनवाना
(B) गुरुद्वारों को नष्ट करना
(C) भ्रष्ट महन्तों को निकालना
(D) उपर्युक्त सभी

485. अकाली आन्दोलन के दौरान सिखों के नायक थे–
(A) महात्मा गांधी
(B) मोती लाल नेहरू
(C) नाना साहब
(D) महाराजा रणजीत सिंह

486. फकीर आन्दोलन कहाँ हुआ था ?
(A) बंगाल में (B) कानपुर में
(C) मद्रास में (D) दिल्ली में

उत्तरमाला

1. (B)	2. (C)	3. (A)	4. (A)	5. (C)
6. (C)	7. (C)	8. (D)	9. (D)	10. (D)
11. (C)	12. (A)	13. (C)	14. (A)	15. (A)
16. (A)	17. (A)	18. (A)	19. (D)	20. (C)
21. (A)	22. (D)	23. (C)	24. (C)	25. (A)
26. (A)	27. (A)	28. (D)	29. (A)	30. (B)
31. (A)	32. (B)	33. (A)	34. (A)	35. (D)
36. (D)	37. (C)	38. (B)	39. (A)	40. (C)
41. (A)	42. (A)	43. (A)	44. (B)	45. (D)
46. (D)	47. (C)	48. (D)	49. (A)	50. (C)
51. (C)	52. (B)	53. (A)	54. (D)	55. (C)
56. (B)	57. (B)	58. (C)	59. (D)	60. (C)
61. (A)	62. (A)	63. (D)	64. (A)	65. (B)
66. (C)	67. (A)	68. (B)	69. (A)	70. (D)
71. (B)	72. (D)	73. (A)	74. (C)	75. (B)
76. (C)	77. (D)	78. (D)	79. (D)	80. (C)
81. (A)	82. (C)	83. (D)	84. (B)	85. (B)
86. (C)	87. (B)	88. (D)	89. (D)	90. (D)
91. (B)	92. (A)	93. (C)	94. (D)	95. (A)
96. (B)	97. (C)	98. (B)	99. (D)	100. (B)
101. (A)	102. (A)	103. (C)	104. (D)	105. (A)
106. (C)	107. (B)	108. (C)	109. (C)	110. (D)
111. (C)	112. (B)	113. (C)	114. (C)	115. (C)
116. (A)	117. (A)	118. (D)	119. (C)	120. (D)
121. (C)	122. (A)	123. (A)	124. (D)	125. (D)
126. (A)	127. (D)	128. (B)	129. (A)	130. (D)
131. (A)	132. (C)	133. (D)	134. (B)	135. (A)
136. (C)	137. (A)	138. (B)	139. (C)	140. (B)

474. खिलाफत आन्दोलन के प्रमुख नेता थे–
(A) मोहम्मद अली जिन्ना (B) अली मुदलियार
(C) महात्मा गांधी (D) नारायण गुरु

475. सविनय अवज्ञा आन्दोलन के स्थगन का कारण था–
(A) पूना समझौता
(B) गांधी-इरविन समझौता
(C) गोलमेज सम्मेलन
(D) शिमला समझौता

476. महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था–
(A) एम. जी. रानाडे (B) के. टी. तेलंग
(C) महात्मा गांधी (D) बी. एम. मालावार्रा

477. बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस जेल में हुई ?
(A) दिल्ली की जेल में
(B) अण्डमान निकोबार की जेल में
(C) रंगून की जेल में
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

478. पुणे में होमरूल लीग की स्थापना किसने की ?
(A) महात्मा गांधी ने (B) जवाहरलाल नेहरू ने
(C) एनीबेसेंट ने (D) मोतीलाल नेहरू ने

479. बल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई–
(A) खेड़ा सत्याग्रह के दौरान
(B) बारदौली सत्याग्रह के दौरान
(C) बलसाड सत्याग्रह के दौरान
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

480. भारत में विद्युत दूरसंचार का जनक किसे कहा जाता है ?
(A) लॉर्ड डलहौजी को (B) लॉर्ड कैनिंग को
(C) लॉर्ड कर्जन को (D) लॉर्ड लिटिल को

481. टी. एल. ए. की स्थापना अहमदाबाद में किसने की थी ?
(A) महात्मा गांधी ने (B) मोतीलाल नेहरू ने
(C) लाला लाजपतराय ने (D) लोकमान्य तिलक ने

482. "मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ-पाँव हैं." यह नारा कहाँ दिया गया था ?
(A) मद्रास में (B) कानपुर में
(C) बम्बई में (D) दिल्ली में

483. मजदूरों ने किस आन्दोलन में भाग नहीं लिया ?
(A) सविनय अवज्ञा आन्दोलन में
(B) नील आन्दोलन में
(C) किसान आन्दोलन में
(D) उपर्युक्त में से किसी में नहीं

484. अकाली आन्दोलन का मकसद था–
(A) गुरुद्वारों को बनवाना
(B) गुरुद्वारों को नष्ट करना
(C) भ्रष्ट महन्तों को निकालना
(D) उपर्युक्त सभी

485. अकाली आन्दोलन के दौरान सिखों के नायक थे–
(A) महात्मा गांधी
(B) मोती लाल नेहरू
(C) नाना साहब
(D) महाराजा रणजीत सिंह

486. फकीर आन्दोलन कहाँ हुआ था ?
(A) बंगाल में (B) कानपुर में
(C) मद्रास में (D) दिल्ली में

उत्तरमाला

1. (B)	2. (C)	3. (A)	4. (A)	5. (C)
6. (C)	7. (C)	8. (D)	9. (D)	10. (D)
11. (C)	12. (A)	13. (C)	14. (A)	15. (A)
16. (A)	17. (A)	18. (A)	19. (D)	20. (C)
21. (A)	22. (D)	23. (C)	24. (C)	25. (A)
26. (A)	27. (A)	28. (D)	29. (A)	30. (B)
31. (A)	32. (B)	33. (A)	34. (A)	35. (D)
36. (D)	37. (C)	38. (B)	39. (A)	40. (C)
41. (A)	42. (A)	43. (A)	44. (B)	45. (D)
46. (D)	47. (C)	48. (D)	49. (A)	50. (C)
51. (C)	52. (B)	53. (A)	54. (D)	55. (C)
56. (B)	57. (B)	58. (C)	59. (D)	60. (C)
61. (A)	62. (A)	63. (D)	64. (A)	65. (B)
66. (C)	67. (A)	68. (B)	69. (A)	70. (D)
71. (B)	72. (D)	73. (A)	74. (C)	75. (B)
76. (C)	77. (D)	78. (D)	79. (D)	80. (C)
81. (A)	82. (C)	83. (D)	84. (B)	85. (B)
86. (C)	87. (B)	88. (D)	89. (D)	90. (D)
91. (B)	92. (A)	93. (C)	94. (D)	95. (A)
96. (B)	97. (C)	98. (B)	99. (D)	100. (B)
101. (A)	102. (A)	103. (C)	104. (D)	105. (A)
106. (C)	107. (B)	108. (C)	109. (C)	110. (D)
111. (C)	112. (B)	113. (C)	114. (C)	115. (C)
116. (A)	117. (A)	118. (D)	119. (C)	120. (D)
121. (C)	122. (A)	123. (A)	124. (D)	125. (D)
126. (A)	127. (D)	128. (B)	129. (A)	130. (D)
131. (A)	132. (C)	133. (D)	134. (B)	135. (A)
136. (C)	137. (A)	138. (B)	139. (C)	140. (B)

141. (A) 142. (D) 143. (A) 144. (B) 145. (A)
146. (A) 147. (A) 148. (B) 149. (B) 150. (D)
151. (A) 152. (C) 153. (A) 154. (A) 155. (B)
156. (C) 157. (A) 158. (B) 159. (C) 160. (D)
161. (C) 162. (A) 163. (D) 164. (D) 165. (A)
166. (B) 167. (A) 168. (D) 169. (A) 170. (A)
171. (B) 172. (C) 173. (C) 174. (D) 175. (A)
176. (C) 177. (B) 178. (D) 179. (C) 180. (B)
181. (D) 182. (B) 183. (C) 184. (D) 185. (C)
186. (D) 187. (A) 188. (D) 189. (A) 190. (B)
191. (D) 192. (B) 193. (B) 194. (B) 195. (D)
196. (A) 197. (D) 198. (A) 199. (A) 200. (A)
201. (C) 202. (A) 203. (D) 204. (C) 205. (B)
206. (D) 207. (D) 208. (C) 209. (C) 210. (C)
211. (C) 212. (B) 213. (B) 214. (A) 215. (C)
216. (C) 217. (D) 218. (A) 219. (A) 220. (C)
221. (D) 222. (C) 223. (D) 224. (D) 225. (C)
226. (A) 227. (C) 228. (B) 229. (C) 230. (D)
231. (D) 232. (A) 233. (D) 234. (B) 235. (D)
236. (A) 237. (A) 238. (D) 239. (D) 240. (B)
241. (B) 242. (D) 243. (B) 244. (A) 245. (A)
246. (D) 247. (A) 248. (A) 249. (C) 250. (A)
251. (C) 252. (A) 253. (D) 254. (A) 255. (B)
256. (D) 257. (A) 258. (C) 259. (C) 260. (A)
261. (B) 262. (A) 263. (B) 264. (D) 265. (A)
266. (C) 267. (D) 268. (A) 269. (B) 270. (A)
271. (A) 272. (D) 273. (B) 274. (A) 275. (B)
276. (C) 277. (C) 278. (A) 279. (A) 280. (D)
281. (C) 282. (A) 283. (C) 284. (C) 285. (D)
286. (A) 287. (A) 288. (A) 289. (A) 290. (B)
291. (C) 292. (C) 293. (A) 294. (D) 295. (A)
296. (D) 297. (A) 298. (A) 299. (B) 300. (A)
301. (C) 302. (D) 303. (A) 304. (A) 305. (A)
306. (B) 307. (A) 308. (B) 309. (A) 310. (A)
311. (A) 312. (C) 313. (A) 314. (C) 315. (D)
316. (A) 317. (D) 318. (A) 319. (D) 320. (A)
321. (A) 322. (A) 323. (D) 324. (B) 325. (A)
326. (B) 327. (A) 328. (D) 329. (A) 330. (A)
331. (B) 332. (B) 333. (A) 334. (A) 335. (A)
336. (B) 337. (A) 338. (C) 339. (A) 340. (B)
341. (A) 342. (A) 343. (A) 344. (D) 345. (A)
346. (D) 347. (D) 348. (C) 349. (A) 350. (B)
351. (C) 352. (B) 353. (A) 354. (B) 355. (C)
356. (B) 357. (C) 358. (B) 359. (A) 360. (A)
361. (D) 362. (A) 363. (D) 364. (A) 365. (C)
366. (C) 367. (B) 368. (C) 369. (C) 370. (C)
371. (D) 372. (A) 373. (A) 374. (C) 375. (B)
376. (D) 377. (A) 378. (A) 379. (A) 380. (D)
381. (C) 382. (B) 383. (D) 384. (B) 385. (A)
386. (B) 387. (D) 388. (C) 389. (C) 390. (A)
391. (A) 392. (A) 393. (B) 394. (C) 395. (B)
396. (A) 397. (B) 398. (D) 399. (A) 400. (A)
401. (A) 402. (A) 403. (A) 404. (C) 405. (A)
406. (A) 407. (A) 408. (D) 409. (D) 410. (C)
411. (A) 412. (D) 413. (D) 414. (B) 415. (A)
416. (C) 417. (A) 418. (B) 419. (A) 420. (A)
421. (D) 422. (D) 423. (A) 424. (D) 425. (B)
426. (C) 427. (A) 428. (A) 429. (B) 430. (B)
431. (C) 432. (A) 433. (A) 434. (A) 435. (B)
436. (A) 437. (C) 438. (A) 439. (B) 440. (A)
441. (A) 442. (C) 443. (A) 444. (A) 445. (D)
446. (A) 447. (C) 448. (A) 449. (D) 450. (A)
451. (A) 452. (A) 453. (D) 454. (B) 455. (A)
456. (B) 457. (A) 458. (C) 459. (A) 460. (A)
461. (C) 462. (D) 463. (C) 464. (B) 465. (A)
466. (B) 467. (A) 468. (D) 469. (A) 470. (A)
471. (A) 472. (B) 473. (D) 474. (B) 475. (B)
476. (A) 477. (C) 478. (C) 479. (B) 480. (A)
481. (A) 482. (C) 483. (A) 484. (C) 485. (D)
486. (A)

संकेत

153. मंगल पाण्डे को 18 अप्रैल, 1857 को फाँसी दिया जाना निश्चित हुआ था, लेकिन 10 दिन पूर्व ही फाँसी दे दी गई थी.

परिशिष्ट
(Appendices)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रमुख घटनाएँ

1857 अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह, कलकत्ता, मुम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना (प्रेस एक्ट पारित).

1858 अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का दमन, ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन समाप्त. भारत में ब्रिटिश ताज का शासन.

1859 बंगाल में नील विद्रोह.

1860 जयंतिया विद्रोह.

1861 भारतीय परिषद् अधिनियम, फौजदारी तथा दीवानी प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम पारित. सिक्किम तथा अंग्रेजों में समझौता.

1862 सुप्रीम तथा सदर अदालतों का उच्च न्यायालयों के रूप में एकीकरण. सी. पुरुषोत्तम मुदालियर द्वारा लन्दन में लन्दन इंडिया कमेटी की स्थापना.

1863 अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद की मृत्यु.

1864 भूटान युद्ध.

1865 उड़ीसा में भीषण दुर्भिक्ष. लन्दन में लन्दन इंडिया सोसायटी की स्थापना.

1866 लन्दन में ईस्ट इंडिया एसोसियेशन की स्थापना.

1867 केशवचन्द्र सेन द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना.

1868 पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित.

1869 शेर अली के साथ अम्बाला सम्मेलन.

1870 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना.

1871 फिरोजपुर में 'रामसिंह की उपस्थिति' में कूकाओं का सम्मेलन.

1872 स्पेशल मैरिज एक्ट पारित. अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या.

1873 उत्तर विहार में भीषण दुर्भिक्ष.

1874 विहार में भीषण अकाल.

1875 प्रिन्स ऑफ वेल्स का भारत आगमन. आर्य समाज की स्थापना, कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष की हत्या.

1876 रायल टाइटिल्स एक्ट. इंडियन एसोसियेशन की स्थापना.

1877 लॉर्ड लिटन द्वारा–दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन.

1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं आर्म्स एक्ट पारित. द्वितीय अंग्रेज अफगान युद्ध.

1879 अकाल आयोग की नियुक्ति पूना में वासुदेव फड़के के नेतृत्व में विद्रोह.

1880 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी (मराठी) तथा मराठा (अंग्रेजी) पत्रों का प्रकाशन.

1881 प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू. बाल श्रमिकों को सीमित राहत.

1882 स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति. सूरत में प्रजाहितवर्धिनी सभा की स्थापना. लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द. मद्रास में थियोसोफिकल सोसायटी का मुख्यालय स्थापित.

1883 इलबर्ट बिल को लेकर विवाद. स्वामी दयानन्द सरस्वती का निधन. कराची में सिंध सभा की स्थापना.

1884 मद्रास महाजन सभा की स्थापना.

1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (28 दिसम्बर). कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में. तृतीय आंग्ल बर्मा (म्यांमार) युद्ध. बंगाल एजेन्सी एक्ट पारित.

1886 ब्रिटिश साम्राज्य में ऊपरी बर्मा का (म्यांमार) का विलय. चार्ल्स ऐचिसन की अध्यक्षता में सार्वजनिक सेवा आयोग की नियुक्ति.

1887 इंग्लैण्ड में दादा भाई नौरोजी के प्रयास में इंडियन रिफार्म एसोसियेशन की स्थापना.

1888 लाला लाजपतराय कांग्रेस में शामिल.

1889 प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी बार भारत यात्रा.

1890 इंडियन सेंसर एक्ट पारित. कलकत्ता में अंग्रेज, चीन, तिब्बत में संधि.

1891 द्वितीय फैक्ट्री एक्ट लागू, मणिपुर में विद्रोह.

1892 भारतीय परिषद् अधिनियम पारित. एज ऑफ कन्सेन्ट एक्ट पारित.

1893 एनीबेसेन्ट का भारत आगमन. तिलक द्वारा गणपति उत्सव का प्रारम्भ.

1894 भारतीय जेल अधिनियम पारित.

1895 तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव का आरम्भ. देशद्रोह के आरोप में तिलक गिरफ्तार.

1896 पूना में चापेकर बंधुओं द्वारा व्यायाम मंडली की स्थापना.

1897 चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में दो अंग्रेजों की हत्या. रामकृष्ण मिशन की स्थापना.

1898 सर सैय्यद अहमद खाँ का निधन.

1899 लॉर्ड कर्जन की भारत में वायसराय के रूप में नियुक्ति.

1900 भारत में भीषण अकाल.

1901 महारानी विक्टोरिया का निधन (25 जनवरी).

1902 स्वामी विवेकानन्द का निधन. कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति. शिक्षा पर रैले कमीशन की रिपोर्ट.

1903 बंगाल में प्रथम क्रान्तिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना.

1904 इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित.

1905 बंगाल का विभाजन (16 अक्टूबर). लन्दन में क्रान्तिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया होमरूल सोसायटी की स्थापना.

1906 मुस्लिम लीग की स्थापना (31 अगस्त). कलकत्ता में क्रान्तिकारी पत्र 'युगान्तर' का प्रकाशन प्रारम्भ.

1907 अंग्रेज रूस संधि. लाला लाजपत राय और अजीतसिंह का निर्वासन. सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजित. राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम पारित.

1908 खुदीराम बोस को फाँसी. लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष का कारावास. भारत में विकेन्द्रीकरण पर रायल कमीशन की नियुक्ति.

1909 लंदन में मदनलाल धींगरा द्वारा एक अंग्रेज की हत्या. गणेश दामोदर विनायक सावरकर को आजीवन निर्वासन की सजा. मार्ले-मिन्टो सुधार अधिनियम.

1910 इण्डिया प्रेस एक्ट पारित.

1911 बंगाल विभाजन समाप्त. राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरण. सम्राट् जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा. दिल्ली दरबार.

1912 मौलाना अब्बुल कलाम द्वारा 'अलहिलाल' तथा मोहम्मद अली द्वारा 'कामरेड' (अंग्रेजी) तथा 'हमदर्द' (उर्दू) पत्र का प्रकाशन.

1913 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन मुम्बई में. सान फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना.

1914 6 वर्ष की सजा के बाद तिलक रिहा. प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ. जापानी जहाज 'कामागाटामार' भारतीय क्रान्तिकारियों को लेकर भारत आया. एनी बेसेंट द्वारा 'कामनवील' पत्रिका तथा 'न्यू इंडिया' पत्र का प्रकाशन.

1915 गोपालकृष्ण गोखले तथा फीरोजशाह मेहता का निधन. लाहौर तथा बनारस षड्यन्त्र कांड में क्रान्तिकारियों को लम्बी सजाएँ. भारत सुरक्षा अधिनियम पारित. महात्मा गांधी का अफ्रीका से भारत आगमन.

1916 पूना में तिलक द्वारा होमरूल लीग की स्थापना. लखनऊ में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन कांग्रेस के उदार तथा उग्र गुट में मेल.

1917 चम्पारन में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह. उत्तरदायी शासन के बारे में मांन्टेग्यू की घोषणा. एनीबेसेंट जेल से रिहा.

1918 मद्रास में पहले ट्रेड यूनियन संगठन की स्थापना. कांग्रेस में फूट पड़ना और लिबरल फेडरेशन की स्थापना.

1919 रोलट एक्ट पारित (13 अप्रैल). जलियाँवाला बाग हत्याकांड मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम.

1920 जलियाँवाला कांड पर हंटर कमीशन नियुक्त. असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ. तिलक का निधन. खिलाफत आन्दोलन प्रारम्भ.

1921 ताशकंद में एम. एन. राय द्वारा भारतीय साम्यवादी दल का गठन. प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन.

1922 मोपला विद्रोह. चौरी-चोरा कांड 5 फरवरी. असहयोग आन्दोलन की समाप्ति. महात्मा गांधी की गिरफ्तारी. यू. पी. किसानों का एकी आन्दोलन. अकाली अन्दोलन (पंजाब).

1923 स्वराज पार्टी की स्थापना.

1924 हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए गांधीजी द्वारा 21 दिनों का उपवास. कानपुर षड्यंत्र काण्ड.

1925 सी. आर. दास निधन. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का निधन. कांकोरी कांड (9 अगस्त).

1926 भगतसिंह तथा उसके साथियों द्वारा 'नौजवान सभा' की स्थापना. स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या.

1927 साइमन कमीशन का भारत आगमन एवं उसका सभी दलों द्वारा बहिष्कार (8 नवम्बर).

1928 सर्वदलीय सम्मेलन (28 फरवरी) नेहरू रिपोर्ट. कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित. लाला लाजपत राय का निधन.

1929 दिल्ली में जिन्ना की राजनीतिक समझौते के लिए 14 माँगें. मेरठ कम्युनिस्ट षड्यन्त्र कांड. भगतसिंह, बटुकेश्वरदत्त के हाथों असेंबली में बम फेंका गया (8 अगस्त).

1930 सविनय अवज्ञा आन्दोलन (12 मार्च). लन्दन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन. गांधीजी की डांडी यात्रा (12 मार्च). अब्दुल गफ्फार खान द्वारा 'खुदाई खिदमतगार' संस्था की स्थापना (26 जनवरी, 1936). पूर्ण स्वाधीनता लक्ष्य की घोषणा.

1931 गांधी-इर्विन समझौता (5 मार्च). लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन. भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह को फाँसी (23 मार्च). इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए चन्द्रशेखर आजाद वीरगति को प्राप्त (26 जनवरी).

1932 लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन. कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, विपिन चन्द्र पाल का निधन. गांधीजी द्वारा भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना.

1933 गांधीजी द्वारा 21 दिनों का उपवास (8 मई) प्रस्तावित संवैधानिक शासन सुधार पर श्वेत-पत्र.

1934 सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त. भारतीय फैक्ट्री कानून. बिहार में भीषण भूकम्प.

1935 भारतीय शासन अधिनियम पारित.

1936 सम्राट् जॉर्ज पंचम का निधन. जॉर्ज षष्टम का सिंहासनारोहण. अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना.

1937 नये चुनाव प्रांतीय मन्त्रिमण्डलों का गठन. मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में सिकन्दर हयात-जिन्ना समझौता. प्रान्तीय स्वायत्तता का सूत्रपात.

1938 हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चन्द्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित.

1939 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ (3 दिसम्बर), कांग्रेस मंत्रीमण्डलों का त्यागपत्र, मुस्लिम-लीग द्वारा 'मुक्ति दिवस' का आयोजन 22 दिसम्बर. फारवर्ड ब्लाक की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुभाषचन्द्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित. अध्यक्ष पद से इस्तीफा.

1940 लॉर्ड लिनिलिथिगो का 8 अगस्त का प्रस्ताव. व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन. मुस्लिम-लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की माँग. भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत सुभाष चन्द्र बोस गिरफ्तार.

1941 गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का निधन.

1942 क्रिप्स मिशन भारत आया (22 मार्च). भारत छोड़ो आन्दोलन (8 अगस्त) और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी (9 अगस्त).

1943 सुभाष चन्द्र बोस द्वारा विदेश में स्वतन्त्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेवा का गठन.

1944 गांधीजी जेल से रिहा (6 मई).

1945 वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति.

1946 मुम्बई में नौसेना विद्रोह (23 फरवरी), कैबिनेट मिशन भारत में (24 मार्च), संविधान सभा का उद्‌घाटन (9 दिसम्बर), जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार (2 सितम्बर). मुस्लिम-लीग की सीधी कार्यवाही (16 अगस्त).

1947 लॉर्ड एटली द्वारा जून 1948 के पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने की घोषणा. लॉर्ड माउण्टबेटन योजना (3 जून). भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम (4 जुलाई). 15 अगस्त, 1947 को भारत विभाजन, 14 अगस्त को नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में. भारत स्वतन्त्र (15 अगस्त, 1947).

सन् 1857 का विद्रोह, प्रमुख केन्द्र व नेतृत्व

क्र.सं.	केन्द्र	भारतीय नेता	अंग्रेजी जनरल
1.	दिल्ली	बहादुर शाह जफर (प्रमुख नेता) बख्त खाँ (सैनिक नेता)	कैप्टन हड़सन
2.	कानपुर	नाना साहब	जनरल हैवलाक
3.	फतेहपुर	अमीमुल्ला	जनरल सरकैम्पवैल एवं जनरल हैवलाक
4.	लखनऊ	बेगम हजरत महल	जनरल हैवलाक एवं जनरल आउट्रम
5.	इलाहाबाद	लियाकत अली	जनरल नील
6.	झाँसी	रानी लक्ष्मीबाई	जनरल ह्यूरोज
7.	ग्वालियर	तात्याँ टोपे	जनरल ह्यूरोज
8.	जगदीशपुर (बिहार)	कुँवरसिंह	जनरल बेनविल, हेमिलअन एवं जनरल ली ग्रांट

सन् 1857 के बाद हुए किसान आन्दोलन और किसान विद्रोह

सन्	आन्दोलन/विद्रोह	क्षेत्र/केन्द्र
1859-60	नील आन्दोलन	गोविन्दपुर (बंगाल)
1873-76	पाबना विद्रोह	युसुफ परगना (बंगाल)
1875	दक्खन उपद्रव	करड़ाह गाँव, पूना, अहमद नगर (तत्कालीन महाराष्ट्र में)
1873-77	भू-राजस्व समझौता अधिनियम 1867 विद्रोह	पूना
1920	एका आन्दोलन	हरदोई, बहराइच (उ.प्र.)
1920	मोपिला (मोपला) विद्रोह	मालाबार (केरल)
1928	बारदोली सत्याग्रह	बारदोली (सूरत)
1930	जंगल सत्याग्रह	बिहार

प्रमुख आन्दोलन और उनके प्रवर्तक

	आन्दोलन	प्रवर्तक
1.	चम्पारन (नील विद्रोह) सत्याग्रह, खेडा, रौलट, सत्याग्रह, पूना पैक्ट, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन दाण्डीमार्च, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आन्दोलन	महात्मा गांधी
2.	खिलाफत आन्दोलन	अलीबन्धु-मुहम्मद अली व शौकत अली
3.	खुदाई खिदमतगार, लालकुर्ती आन्दोलन	फ्रन्टिअर गांधी–खान अब्दुल गफ्फार खाँ

4.	अहमदिया आन्दोलन	मिर्जा गुलाम अहमद (पंजाब)
5.	बहावी आन्दोलन	सैय्यद अहमद (भारत) मौलाना अब्दुल बहाव (अरब)
6.	अलीगढ़ आन्दोलन	सर सैय्यद अहमद खाँ
7.	भारतीय नौ सेना विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह	सरदार वल्लभ भाई पटेल
8.	वायकोम सत्याग्रह	के. पी. केशव मेनन
9.	गुरुवायूर सत्याग्रह	पीत सुब्रह्मण्यम् तिरचमाम्बु (केरल)
10.	चिटगाँव शस्त्रागार लूटकाण्ड	सूर्यसेन
11.	काँकोरी बम केस	रामप्रसाद बिस्मिल
12.	शुद्धि आन्दोलन	स्वामी दयानन्द सरस्वती
13.	पार्लियामेन्ट ऑफ रिलिजन (विश्वधर्म महासभा)	स्वामी विवेकानन्द (शिकागो)
14.	भूदान आन्दोलन	आचार्य विनोबा भावे
15.	कूका आन्दोलन	रामसिंह कूका
16.	अहरार आन्दोलन	अली बन्धु (मुहम्मद अली, जफर अली, अफजल खाँ

भारत के प्रमुख वायसराय एवं उल्लेखनीय घटनाएँ

सन्	वायसराय	उल्लेखनीय घटनाएँ
1858–62	लॉर्ड कैनिंग	सन् 1857 का सैनिक विद्रोह, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना, इण्डियन कौंसिल एक्ट (1861) पारित, भारतीय दण्ड संहिता, सिविल दण्ड प्रक्रिया संहिता अधिनियम पारित,.
1862-63	लॉर्ड एल्गिन	बहावी आन्दोलन
1864-69	सर जॉन लॉर्ड लॉरेन्स	तटस्थ सीमा नीति एवं भूटान युद्ध
1872–76	लॉर्ड मेयो	राजस्व विकेन्द्रीकरण, मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना
1876–80	लॉर्ड लिटन	अफगान युद्ध, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट-1878, आई. सी. एस. प्रवेश परीक्षा उम्र 19 वर्ष न्यूनतम
1880–84	लॉर्ड रिपन	वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाप्त, शिक्षा सुधार के लिए–हन्टर आयोग की स्थापना, फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित, स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित
1884–88	लॉर्ड डफरिन	कांग्रेस की स्थापना
1888–94	लॉर्ड लैन्सडाउन	भारत पाकिस्तान के मध्य डूरंड सीमा रेखा बनी.
1894–99	लॉर्ड एल्गिन-II	चितराल विद्रोह
1899–1905	लॉर्ड कर्जन	बंगाल विभाजन
1905–1910	लॉर्ड मिण्टो	मुस्लिम-लीग की स्थापना, स्वदेशी आन्दोलन, कांग्रेस का सूरत विभाजन, आंग्ल-रूस सम्मेलन, मिण्टो-मार्ले सुधार (मुसलमानों की पृथक् चुनाव व्यवस्था)
1910-1916	लॉर्ड हार्डिंग्स	जॉर्ज पंचम का भारत आगमन, बंगाल विभाजन रद्द, दिल्ली राजधानी बनी. वायसराय बमकांड, रवीन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार.
1916–1921	लॉर्ड चेम्सफोर्ड	कांग्रेस का लखनऊ एकीकरण, लखनऊ पैक्ट-1916, मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919) जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड, हंटर समिति, खिलाफत आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन.
1921–26	लॉर्ड रीडिंग	प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, भारतीयों का बहिष्कार आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन का चरमोत्कर्ष, चौरी-चोरा काण्ड स्वराज पार्टी की स्थापना.
1926–31	लॉर्ड इर्विन	साइमन कमीशन की नियुक्ति एवं बहिष्कार, स्वतन्त्रता दिवस समारोह की घोषणा, महात्मा गांधी-इर्विन समझौता, सरदार पटेल का बारदोली सत्याग्रह.
1931–36	लॉर्ड विलिंगटन	द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन (लन्दन में), साम्प्रदायिक पंचाट की घोषणा, रैम्जे मैक्डोनाल्ड द्वारा पूना समझौता, भारत सरकार अधिनियम, 1935 पारित.
1936–43	लॉर्ड लिनलिथगो	द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ, प्रान्तीय चुनाव, कांग्रेस का इस्तीफा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की माँग, भारत में क्रिप्स-मिशन का आगमन, भारत छोड़ो आन्दोलन.
1943–47	लॉर्ड वेवल	वेवल योजना, शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन प्रकाशित, अन्तरिम सरकार का गठन, द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त. संविधान सभा का प्रथम सम्मेलन, जून 1946 तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार की घोषणा.
1947-48	लॉर्ड माउण्टबेटन	स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 'माउण्टबेटन योजना' का क्रियान्वयन, इण्डियन इंडिपेन्डेन्स एक्ट, 1947 पारित, स्वतन्त्र भारत एवं पाकिस्तान स्थापित.

ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेस की स्वतन्त्रता के दमन की गिरफ्त में समाचार-पत्र पत्रिकाएँ

इमरजेंसी पॉवर्स एक्ट, 1931 के अन्तर्गत नवम्बर-1934-दिसम्बर 1934 तक पत्र-पत्रिकाओं से माँगी गई जमानतों का विवरण–

क्र.सं.	पत्र/पत्रिकाएँ	प्रकाशन स्थान	तिथि	जमानती राशि (रु. में)
1.	ब्राह्मण सरस्वती	इटावा	19 नव., 1931	100/-
2.	साहस	झाँसी	20 नव., 1931	500/-
3.	सैनिक	आगरा	8 जन., 1932	1000/-
4.	रंगेश्वर	इलाहाबाद	12 जन., 1932	500/-
5.	स्वदेशी	इलाहाबाद	20 अप्रैल, 1932	1500/-
6.	अग्रवाल सेवा	इलाहाबाद	27 मई, 1932	500/-
7.	भयंकर	कानपुर	अक्टूबर 1932	500/-
8.	लोधी क्षत्रिय	कानपुर	अक्टूबर 1932	200/-
9.	चाँद	इलाहाबाद	7 दिस., 1932	500/-
10.	मजदूर संसार	लखनऊ	15 जन., 1933	1500/-
11.	गुंजा-ए-इतिहाद	कानपुर	3 अप्रैल, 1933	500/-
12.	यू.पी. लोकल बॉडीज मैगजीन	मैनपुरी	26 अप्रैल, 1933	500/-
13.	चन्द्रहास	कानपुर	9 मई, 1933	500/-
14.	उत्तर भारत	गढ़वाल	5 जून, 1933	500/-
15.	आहूत सेवक	कानपुर	27 जून, 1933	200/-
16.	जरीफ	सहारनपुर	21 जुलाई, 1933	1000/-
17.	युवक	कानपुर	1 अगस्त, 1933	250/-
18.	अमल	कानपुर	21 दिस. 1933	500/-
19.	चित्रकूट आश्रम	कानपुर	25 दिस. 1933	500/-
20.	लाल झण्डा	कानपुर	3 फरवरी, 1934	500/-
21.	वनस्पति विज्ञान	कानपुर	16 जून, 1934	750/-
22.	मजदूर	कानपुर	3 अक्टू., 1934	500/-
23.	नायक	इटावा	20 अक्टू., 1934	500/-
इमरजेंसी पॉवर्स अधिनियम, 1931 धारा 3 (3) द्वारा प्रांतीय सरकार द्वारा माँगी जमानतें				
24.	तूफान	लखनऊ	10 फर., 1932	1500/-
25.	स्वाधीन प्रजा	अल्मोड़ा	19 फर., 1932	1500/-
26.	लेबर हेराल्ड	लखनऊ	5 अप्रैल, 1932	1500/-
27.	हंस	बनारस	11 मई, 1932	1000/-
28.	आज	बनारस	16 जून, 1932	1000/-
29.	देशभक्त	मेरठ	21 नव., 1932	500/-
30.	जागरण	बनारस	25 नव., 1932	1000/-
31.	डिस्ट्रिक्ट गजट	आजमगढ़	6 दिस., 1933	500/-
32.	वर्तमान	कानपुर	21 फर., 1934	500/-
33.	मदीना	बिजनौर	1934	1000/-
34.	अलनजाम	लखनऊ	1934	1500/-
35.	सदा-ए-मुस्लिम	कानपुर	1934	1000/-
36.	हिन्द-राजस्थान	झाँसी	22 अगस्त, 1934	500/-
37.	अल नकीद	आगरा	5 सित., 1934	500/-
38.	सैनिक	आगरा	5 सित., 1934	1500/-
39.	सुधारक	इटावा	5 अक्टू., 1934	1500/-

स्वतन्त्रता आन्दोलन की प्रमुख संस्थाएँ एवं उनके संस्थापक

संस्था/संगठन/समिति	संस्थापक	स्थापना वर्ष
कलकत्ता मदरसा	वारेन हेस्टिंग्स	1781
एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल	सर विलियम जोंस	1781
जैकोबिन क्लब	टीपू सुल्तान	
दल खालसा	गुरुगोबिन्द सिंह	1799
आत्मीय सभा	राजा राममोहन राय	1814
हिन्दू कॉलेज (कलकत्ता)	डेविड डेयर	1828
ब्रह्म समाज	राजा राममोहन राय	1828
यूनिटेरियन मिशन	राजा राममोहन राय	1825
तत्वबोधिनी सभा	देवेन्द्रनाथ टैगोर	1839
यंग बंगाल आन्दोलन	विवियन डेरोजियो	1826
ब्रिटिश सार्वजनिक सभा	दादाभाई नौरोजी	1843
बेथुन स्कूल	ड्रिंक वाटर बेथुन	1849
बालिका विद्यालय (पुणे)	ज्योतिबा फूले	1851
सत्यसेवक समाज	ज्योतिबा फूले	1851
सत्यप्रकाश (गुजरात)	कर्सनदास मूल जी	1852
पारसी लॉ एसोसिएशन	दादाभाई नौरोजी	
लैण्डहोल्डर्स सोसाइटी	प्रमुख जमींदार	1837
प्रार्थना समाज	आत्मा पांडुरंग/एम.जी. रानाडे	1867
आर्य समाज	स्वामी दयानन्द	1875
ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन (लन्दन)	दादाभाई नौरोजी	1866
रहनुमाई माजदयासन	दादाभाई नौरोजी	1851
इण्डियन एसोसिएशन	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी	1876
पूना सार्वजनिक सभा	जस्टिस एम. जी. रानाडे	
विधवा पुनर्विवाह	विष्णु शास्त्री पण्डित	1860
मोहम्मद एंग्लो ओरियंटल कॉलेज	सर सैय्यद अहमद खाँ	1875
देव समाज	सत्यानन्द अग्निहोत्री	1885

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	ए. ओ. ह्यूम	1885
वेद समाज (दक्षिण में)	के. के. श्रीधरालु नायडू	1872
रामकृष्ण मठ	स्वामी विवेकानन्द	1897
मुस्लिम लीग	आगाखाँ, सलीमउल्ला	1906
गदर पार्टी	लाला हरदयाल, परमानन्द	1913
अभिनव भारत	वी. डी. सावरकर	1904
होमरूल लीग I (महाराष्ट्र)	बी. जी. तिलक	1916
होमरूल लीग II	एनीबेसेन्ट	1916
सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी	गोपालकृष्ण गोखले	1905
विश्वभारती, शान्तिनिकेतन	रवीन्द्रनाथ टैगोर	1918
साबरमती आश्रम	महात्मा गांधी	1916
थियोसोफिकल सोसायटी	मैडम ब्लावट्स्की, कर्नल आकांट (न्यूयार्क)	1875
थियोसोफिकल सोसायटी	भारत में अड्यार में केन्द्र स्थापित	1886
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	एम. एन. जोशी	1920
हरिजन संघ	महात्मा गांधी	1932
वीमेन्स इण्डियन एसोसिएशन	लेडी सदाशिव	1927
बहिष्कृत हितकारिणी सभा	बी. आर. अम्बेडकर	1924
स्वराज्य दल	मोतीलाल नेहरू एवं सी. आर. दास	1922
अहमदिया आन्दोलन	मिर्जा गुलाम अहमद	1899
आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस	अल्ला बख्स	NA
साइंटिफिक सोसायटी	अब्दुल लतीफ	NA
रहनुमाई माजदयासान	दादाभाई नौरोजी	NA
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (ताशकंद में)	एम. एन. राय	1920
अनुशीलन समिति	पुलिन बिहारीदास	1902
देवबन्द स्कूल	मौलाना अबुल कलाम आजाद	
भील सेवा मण्डल	अमृत लाल विट्ठल दास	1922
फारवर्ड ब्लॉक	सुभाष चन्द्र बोस	1939
आजाद हिन्द फौज	रासबिहारी बोस (नेतृत्व मोहनसिंह)	1942
संगत सभा, आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म प्रतिनिधि	केशव चन्द सेन	1860
धार्मिक सुधार परिषद्	एस. एस. बंगाली	1908
रानाडे इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक्स	एम. जी. रानाडे	NA
साधारण ब्रह्म समाज	शिवशास्त्री आनन्द	1877
सोशल सर्विस लीग	नारायण मल्हार जोशी	NA

कांग्रेस अधिवेशन की महत्वपूर्ण घटनाएँ

सन्	अध्यक्ष	स्थान/सदस्य	घटना
1888	जॉर्ज यूल	इलाहाबाद 1248	कांग्रेस का संविधान नमक कर में कमी, शिक्षा बजट में वृद्धि
1889	सर विलियम वेडरबर्न	बम्बई 1889 महिलाएँ	मताधिकार का प्रस्ताव, 21 वर्ष उम्र निर्धारित
1891	पी आनन्द चार्लू	नागपुर	राष्ट्रीयता नामकरण
1893	दादाभाई नौरोजी	लाहौर	आई. सी. एस. भारत में करवाने की माँग
1895	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी	पूना	कांग्रेस अधिवेशन पर निर्णय
1896	रहमतुल्ला सयानी	कलकत्ता	वंदेमातरम् का गायन
1916	अम्बिका चरण मजूमदार	लखनऊ	कांग्रेस-लखनऊ लीग समझौता
1918	पं. मदनमोहन मालवीय	दिल्ली	गरम दल के अध्यक्ष निर्वाचित, आत्मनिर्णायक अधिकार की माँग
1919	पं. मोती लाल नेहरू	अमृतसर	भारतीय स्वशासन की माँग
1920	विजय राघवा चार्य	नागपुर	भाषायी आधार पर प्रान्तीय विभाजन, 21 वर्ष संविधान नियमानुसार कांग्रेस के लिए सदस्यता प्राप्ति की उम्र, तिलक स्वराज्य की स्थापना.
1921	चितरंजन दास	अहमदाबाद	पूर्ण स्वराज्य की घोषणा
1924	महात्मा गांधी	बेलगाम	मुस्लिम लीग का पृथक्की-करण, नरम दल कांग्रेस में समाहित
1925	सरोजिनी नायडू	कानपुर	पहली महिला अध्यक्ष (भारतीय), रिवोल्यूशनरी पत्रिका का प्रारम्भ

राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्ध प्रमुख समाचार-पत्र

क्र.सं.	नाम पत्र	सम्पादक/प्रणेता
1.	अलहिलाल	मौलाना अबुल कलाम आजाद
2.	मार्डन रिव्यू	रामानन्द चटर्जी
3.	कामरेड	मुहम्मद अली जिन्ना
4.	काल	पराजंपे
5.	लीडर, हिन्दुस्तान, अभ्युदय	मदनमोहन मालवीय
6.	यंग इण्डिया, हरिजन	महात्मा गांधी
7.	नेशन	गोपालकृष्ण गोखले
8.	इण्डिया मिरर	केशवचन्द्र सेन
9.	केसरी, मराठा	बाल गंगाधर तिलक

10.	बंगाली	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
11.	सोमप्रकाश	ईश्वरचन्द्र विद्यासागर
12.	संवाद कौमुदी	राजा राममोहन राय
13.	युगातंर, कर्मयोगी	अरविन्द घोष
14.	कॉमनवील, नया भारत	एनीबेसेन्ट
15.	इन्डिपेन्डेन्ट	मोतीलाल नेहरू
16.	रस्ट गुफ्तूर, द वॉयस ऑफ इण्डिया	दादाभाई नौरोजी
17.	हमदर्द	मुहम्मद अली जिन्ना
18.	अमृत बाजार पत्रिका	शिशिर कुमार घोष
19.	फ्री हिन्दुस्तान	तारकनाथ दास
20.	द रिवोल्युश्नरी	शचीन्द्रनाथ सान्याल
21.	मीरा तुल अखबार	राजा राममोहन राय

स्वाधीनता सेनानियों के प्रमुख नारे

1.	वन्दे मातरम् (आनन्द मठ से)	बंकिम चन्द्र चटर्जी
2.	सत्य और अहिंसा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है	महात्मा गांधी
3.	करो या मरो	महात्मा गांधी
4.	स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है	लोकमान्य तिलक
5.	वी हैड मैड ए ट्रायस्ट विद डेस्टिनी	जवाहर लाल नेहरू
6.	हू लिव्ज इफ इण्डिया हैज डाईज	जवाहर लाल नेहरू
7.	आराम हराम है	जवाहर लाल नेहरू
8.	जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता	रवीन्द्र नाथ टैगोर
9.	तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा	सुभाष चन्द्र बोस
10.	दिल्ली चालो	सुभाष चन्द्र बोस
11.	जयहिन्द	सुभाष चन्द्र बोस
12.	एकला चालो रे	रवीन्द्रनाथ टैगोर
13.	आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम पूरे राजभक्त हैं.	दादा भाई नौरोजी
14.	सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा	सर मुहम्मद इकबाल
15.	राष्ट्रीयता एक धर्म है जो भगवान के यहाँ से आता है.	अरविन्द घोष
16.	दीन दुःखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है	स्वामी विवेकानन्द
17.	इंकलाब जिंदाबाद	सरदार भगतसिंह
18.	हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तान	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
19.	वेदों की ओर लौटो	स्वामी दयानन्द सरस्वती
20.	पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ वेस ऑफ नेशन	अरविन्द घोष
21.	विजयी विश्व तिरंगा प्यारा	श्यामलाल गुप्ता
22.	सत्य और अहिंसा मेरा भगवान है	महात्मा गांधी
23.	सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है	रामप्रसाद बिस्मिल
24.	अंग्रेजो भारत छोड़ो	महात्मा गांधी
25.	वन्दे मातरम्	अरविन्द घोष

स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान लिखा साहित्य

1.	माई एक्सपेरिमेन्ट विद ट्रुथ	मोहनदास करमचन्द गांधी
2.	इण्डियन होमरूल	मोहनदास करमचन्द गांधी
3.	माई अर्ली लाइफ	मोहनदास करमचन्द गांधी
4.	मेरी आत्मकथा	मोहनदास करमचन्द गांधी
5.	माई चाइल्डहुड	मोहनदास करमचन्द गांधी
6.	हिन्दू स्वराज	मोहनदास करमचन्द गांधी
7.	वेदान्त सूत्र, तुहफत-उल मुजाहीद्दीन	राजा राममोहन राय
8.	डिस्कवरी ऑफ इण्डिया	जवाहर लाल नेहरू
9.	ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री	जवाहर लाल नेहरू
10.	ए बन्च ऑफ ओल्ड लेटर्स	जवाहर लाल नेहरू
11.	मेरी आत्मकथा	जवाहर लाल नेहरू
12.	हिज फादर टू हिज डॉटर	जवाहर लाल नेहरू
13.	इण्डिया डिवाइडेड	राजेन्द्र प्रसाद
14.	अनहैप्पी इण्डिया	लाला लाजपत राय
15.	वार ऑफ इण्डियन इण्डिपेन्डेन्स	वी. डी. सावरकर
16.	हिन्ट्स फॉर सेल्फ कल्चर	लाला हरदयाल
17.	इण्डिया विन्स फ्रीडम	अबुल कलाम आजाद
18.	नील दर्पण	दीनबन्धु मित्र
19.	गीता रहस्य	बाल गंगाधर तिलक
20.	आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन्स	बाल गंगाधर तिलक
21.	तराना ए-हिन्द	इकबाल
22.	सत्यार्थ प्रकाश	स्वामी दयानन्द सरस्वती
23.	आनन्द मठ	बंकिम चन्द्र चटर्जी
24.	कपाल कुण्डला	बंकिम चन्द्र चटर्जी
25.	मृणालिनी	बंकिम चन्द्र चटर्जी
26.	चन्द्रशेखर	बंकिम चन्द्र चटर्जी
27.	दुर्गेश नन्दिनी	बंकिम चन्द्र चटर्जी
28.	पॉवर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया	दादा भाई नौरोजी
29.	इण्डियन स्ट्रगल	सुभाष चन्द्र बोस
30.	एन इण्डियन पिलिग्रम	सुभाष चन्द्र बोस

32.	हाऊ इण्डिया फॉट फॉर फ्रीडम	एनीबेसेन्ट
33.	आत्मकथा	एनीबेसेन्ट
34.	ए फेज ऑफ द इण्डियन स्ट्रगल	श्यामा प्रसाद मुखर्जी
35.	इण्डिया फ्रोम कर्जन टू नेहरू एण्ड आफ्टर	दुर्गादास
36.	गीताञ्जलि	रवीन्द्रनाथ टैगोर
37.	चित्रा	रवीन्द्रनाथ टैगोर
38.	गोरा	रवीन्द्रनाथ टैगोर
39.	हंगरी स्टोन्स	रवीन्द्रनाथ टैगोर
40.	क्रीसेन्ट मून	रवीन्द्रनाथ टैगोर
41.	कोर्ट डांसर	रवीन्द्रनाथ टैगोर
42.	गार्डनर	रवीन्द्रनाथ टैगोर
43.	लाइफ डिवाइन	अरविन्द घोष
44.	सांग ऑफ इण्डिया	सरोजनी नायडू
45.	वीकनविंग	सरोजनी नायडू
46.	एसेज ऑन गीता, सावित्री	अरविन्द घोष
47.	गोल्डन थ्रेस वर्ल्ड ऑफ टाइम	सी. राजगोपालाचारी
48.	नेशन्स वायरस	सी. राजगोपालाचारी
49.	रिलिजन ऑफ कल्चर	सी. राजगोपालाचारी
50.	रिकान्सिलियेशन	सी. राजगोपालाचारी
51.	हिन्दू व्यू ऑफ लाइफ	डॉ. राधाकृष्णन्
52.	रिलिजन एण्ड सोसाइटी	डॉ. राधाकृष्णन्
53.	रिलिजन ऑफ कल्चर	डॉ. राधाकृष्णन्
54.	इण्डियन फिलोसोफी	डॉ. राधाकृष्णन्
55.	ईस्ट एण्ड वेस्ट इन रिलिजन	डॉ. राधाकृष्णन्
56.	आइडियलोजिस्ट व्यू ऑफ लाइफ	डॉ. राधाकृष्णन्
57.	द स्टोरी ऑफ माई लाइफ	डॉ. राधाकृष्णन्
58.	द स्कोप ऑफ हैप्पीनैस	विजय लक्ष्मी पण्डित
59.	वायसराय जनरल (लॉर्ड वेवल)	विस्टन चर्चिल
60.	गेदरिंग स्टार्म्स	लैरिकोलिन्स, डोमिनिक
61.	हिस्ट्री ऑफ द सेकण्ड वर्ल्डवार	लैरिकोलिन्स, डोमिनिक
62.	माउण्ट वेटन एण्ड पार्टिशन ऑफ इण्डिया	लैरिकोलिन्स, डोमिनिक
63.	फ्रीडम एट मिडनाइट	लैपियरे
64.	फिफ्थ होर्समैन	लैपियरे
65.	भारत विभाजन के गुनाहगार	डॉ. राम मनोहर लोहिया
66.	इण्डिया टुडे	रजनी पामदत्त
67.	इण्डियाज पास्ट	आर्थर ए मैक्डोनिल
68.	इण्डियन रेनेंसा	सी. एफ. एन्ड्रूज
69.	इण्डियन इस्लाम	टाईटस
70.	इन्फैन्ट मैरिज एण्ड एनफोर्सड विडोहुड इन इण्डिया	बी. एम. मालाबारी
71.	अहमदिया आन्दोलन	एच. ए. वाटर
72.	ब्रह्म समाज	मणीलाल सी. पारेख
73.	क्रिश्चियनियटी इन इण्डिया	सर जान. के.
74.	कानफेशन ऑफ ए ठग	मीडोज टायलर
75.	एजूकेशन इन इण्डिया	आर्थर गेहाऊ
76.	एसेज ऑन इण्डियन आडियलिज्म	ए. के. कुमार स्वामी
77.	हिस्ट्री ऑफ द हिन्दूज	वार्ड
78.	हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर	एम. विन्टरनिन्ज
79.	इण्डिया अण्डर कर्जन एण्ड आफ्टर	लोवट फ्रेजर
80.	इण्डिया एण्ड इण्डियन मिशन	अलेक्जेन्डर डफ
81.	लॉर्ड कर्जन इन इण्डिया	सर टी. रैले
82.	मॉर्डन इण्डियन एण्ड द इण्डियन्स	मोनियर विलियन्स
83.	रिलिजन एण्ड सोशियल रिफार्म्स	एम. जी. रानाडे
84.	मॉर्डन वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान	जॉर्ज ग्रियर्सन
85.	मिसेज बेसेन्ट एण्ड साइकोलोजिकल स्टडी	विपिन चन्द पाल
86.	एलन आक्टोपियन ह्यूम	सर विलियम वेडरवर्न
87.	इण्डिया	सर वेलेन्टाइन शिरोल
88.	इण्डियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम	हरेन्द्रनाथ मुखर्जी
89.	इण्डियन डायरी	इ. एस. माण्टेग्यु
90.	पाकिस्तान एण्ड द पार्टिशन ऑफ इण्डिया	बी. आर. अम्बेडकर
91.	द रीडल्स ऑफ हिन्दूइज्म	बी. आर. अम्बेडकर
92.	नेशन इन मेकिंग	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
93.	इण्डिया अण्डर रिपन	डब्ल्यू. एस. बलन्ट
94.	इण्डिया ए नेशन 1934	एनीबेसेन्ट
95.	आत्मकथा	दामोदर हरि चापेकर
96.	आत्मकथा	रामप्रसाद बिस्मिल
97.	आई. एन.एस. एण्ड इट्स नेताजी	शाहनवाज खाँ
98.	असवाव बगावत ए हिन्द-1858	अहमद खाँ
99.	अ पोलिटिकल बॉयोग्राफी	जे. एल. नेहरू
100.	इण्डियन अनरेस्ट	सर वेलेन्टाइन शिरोल
101.	इण्डिया फॉट फॉर फ्रीडम	एनीबेसेन्ट
102.	इण्डिया बाउण्ड आर फ्री-1926	एनीबेसेन्ट
103.	इण्डिया एण्ड द एम्पायर	एनीबेसेन्ट
104.	इन्ट्रोडक्शन टू इण्डियन पॉलिटिक्स	डब्ल्यू. सी. बनर्जी
105.	इण्डिया इन ट्रांजिशन	आगा खाँ
106.	इण्डिया एज आई सॉइट	माइकेल ओ. डायर
107.	इण्डिया फॉर फ्रीडम	सी. आर. दास
108.	कर्म भूमि	मुंशी प्रेमचन्द
109.	कांग्रेस का इतिहास	डॉ. पट्टाभि सीतारमैया
110.	कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एट वर्क	आचार्य जुगल किशोर
111.	गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया	सी. पी. इलबर्ट
112.	गुबारे-खातिर	अबुल कलाम आजाद
113.	गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया	[illegible]

114	न्यू इण्डिया	सर हेनरी कॉटन
115	न्यू इण्डिया	एनीबेसेन्ट
116	नेशनलिज्म	आर. एन. टैगोर
117	टूवार्ड्स होमरूल	रामानन्द चटर्जी
118	तराए-ए-हिन्द	मुहम्मद इकबाल
119	तसरीहात-ए-आजाद	अबुल-कलाम आजाद
120	थोट्स ऑफ पाकिस्तान	बी. आर. अम्बेडकर
121	द अवेकनिंग ऑफ इण्डिया	रेम्जे मैकडोनाल्ड
122	द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इण्डिया	लाला लाजपत राय
123	द वॉयस ऑफ फ्रीडम	मोतीलाल नेहरू
124	द इण्डियन्स रिवोल्ट ऑफ 1942	डॉ. अम्बा प्रसाद
125	पेशावर टू मास्को	शौकत उस्मानी
126	पीजेन्ट स्ट्रगल इन इण्डिया	ए. आर. देसाई
127	फ्रीडम इन मिडनाइट	कालिन्स एण्ड लॉपियर
128	ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इण्डिया	लॉर्ड कर्जन
129	बंदी जीवन	शचीन्द्र नाथ सान्याल
130	बांगे दारा	मुहम्मद इकबाल
131	भारत दुर्दशा	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
132	भारत-भारती	मैथिलीशरण गुप्त
133	भारत में अंग्रेजी राज्य	सुन्दर लाल
134	मेमोरीज ऑफ माई लाइफ टाइम	विपिन चन्द्र पाल
135	मिशन विद माउण्टवेटन	जनसन ए केम्पबेल
136	रिबेल इण्डिया	बेल्सफोर्ड
137	वामबोधिनी	केशवचन्द्र सेन
138	वार ऑफ इण्डियन इंडिपेन्डेन्स	वीर सावरकर
139	सावित्री	अरविन्द घोष
140	सोजे वतन	मुंशी प्रेमचन्द
141	होम एण्ड द वर्ल्ड	रवीन्द्रनाथ टैगोर
142	हिन्दू स्वराज	एम. के. गांधी

आधुनिक भारत के शिक्षा सम्बन्धी विकास एवं अधिनियम

चार्ल्स ग्रांट	1792
मैकाले मिनट	1835
चार्ल्स वुड डिस्पैच	1854
हन्टर शिक्षा आयोग	1882
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम	1904
सैंडलर आयोग	1917-19
हार्टोग समिति	1929
वर्धा योजना	1937
सार्जेंट योजना	1944
राधाकृष्णन आयोग	1948-49
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	1953
कोठारी शिक्षा आयोग	1964
राष्ट्रीय शिक्षा नीति	1968
नई शिक्षा नीति	1986

बंगाल के गवर्नर जनरल
(1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के अनुसार)

	नाम गवर्नर जनरल	अवधि (सन्)
1.	वॉरेन हेस्टिंग्ज	1774-1785 ई.
2.	कार्नवालिस	1786-1793 ई.
3.	सर जॉन-शोर	1793-1798 ई.
4.	रिचर्ड वेलेजली	1798-1805 ई.
5.	कार्नवालिस	1805-1807 ई.
6.	अर्ल ऑफ मिन्टो	1807-1813 ई.
7.	हेस्टिंग्ज	1813-1823 ई.
8.	लॉर्ड एमहर्स्ट	1823-1828 ई.
9.	विलियम वटरबर्थ बेली	1828 ई.
10.	लॉर्ड विलियम बैंटिंक	1828-1833 ई.

बंगाल के गवर्नर

1.	लॉर्ड क्लाइव	1757-1760 ई.
2.	लॉर्ड होलवेल	1760 ई.
3.	लॉर्ड वेन्सिटार्ट	1760-1765 ई.
4.	लॉर्ड क्लाइव	1765-1767 ई.
5.	लॉर्ड वेरेलस्ट	1767-1769 ई.
6.	लॉर्ड कार्टियर	1769-1772 ई.
7.	लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्ज	1772-1774 ई.

विदेशों में भारतीय क्रान्तिकारी संगठन

संगठन	संस्थापक	देश	स्थापना वर्ष
इण्डिया हाऊस	श्यामजी कृष्ण वर्मा	लन्दन (इंग्लैण्ड)	1904 ई.
अभिनव भारत	वी.डी. सावरकर	लन्दन (इंग्लैण्ड)	1906 ई.
इण्डियन इंडिपेन्डेन्स लीग	तारकनाथ दास	अमरीका	1907 ई.
गदर पार्टी	लाला हरदयाल, रामचन्द्र, बरकत उल्ला खाँ	सेनफ्रांसिस्को	1913 ई.
इण्डियन इंडिपेन्डेन्स लीग	लाला हरदयाल, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय	वर्लिन (जर्मनी)	1914 ई.
इण्डियन इण्डिपेन्डेन्स लीग एवं गवर्नमेन्ट	राजा महेन्द्रप्रताप	काबुल (अफगानिस्तान)	1915 ई.
इण्डियन इण्डिपेन्डेन्स लीग	रासबिहारी बोस	टोकियो (जापान)	1942 ई.
आजाद हिन्द फौज	रासबिहारी बोस	टोकियो	1942 ई.

भारत के गवर्नर जनरल
(1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार)

1.	लॉर्ड विलियम बैंटिंक	1833-1835 ई.
2.	सर चार्ल्स मैटकाफ	1835-1836 ई.
3.	अर्ल ऑफ ऑकलैण्ड	1836-1842 ई.
4.	अल एलनबरो	1842-1844 ई.
5.	विलियम विसूफोर्स बर्ड	1844 ई.
6.	सर हेनरी हॉर्डिग्स	1844-1848 ई.
7.	अर्ल ऑफ डलहौजी	1848-1856 ई.
8.	लॉर्ड कैनिंग	1856-1858 ई.

गवर्नर जनरल एवं क्राउन के प्रतिनिधि
(1935 के अधिनियम के अधीन)

1.	लिनलिथगो	1936-1937 ई.
2.	लिनलिथगो	1938-1944 ई.
3.	लॉर्ड वेवल	1944-1947 ई.
4.	लॉर्ड माउन्टबैटन	1947-1948 ई.
5.	चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	1948-1950 ई.

ब्रिटिशकालीन प्रमुख आयोग एवं समतियाँ

	आयोग/समिति	अध्यक्ष	वर्ष	गवर्नर/जनरल (वायसराय)
1.	इनाम आयोग	इनाम	1852ई.	लॉर्ड डलहौजी
2.	दुर्भिक्ष आयोग	रिचर्ड स्ट्रेची	1880ई.	लॉर्ड लिटन
3.	हण्टर आयोग	विलियम हण्टर	1882ई.	लॉर्ड विलियम हण्टर
4.	एटकिन्सन आयोग	चार्ल्स एटकिन्सन	1886ई.	लॉर्ड डफरिन
5.	अफीम आयोग	–	1893ई.	लॉर्ड लैंसडाउन
6.	हरशेल समिति	हरशेल	1893ई.	लॉर्ड लैंसडाउन
7.	दुर्भिक्ष आयोग	एंथनी मेकडोनाल्ड	1901ई.	लॉर्ड कर्जन
8.	दुर्भिक्ष आयोग	जेम्स लायल	1818ई.	लॉर्ड एल्गिन
9.	सिंचाई आयोग	वोल्विन स्कॉट	1901ई.	लॉर्ड कर्जन
10.	विश्वविद्यालय आयोग	थॉमस रैले	1902ई.	लॉर्ड कर्जन
11.	फ्रेजर आयोग	फ्रेजर	1902ई.	लॉर्ड कर्जन
12.	शाही आयोग	इसलिंग्टन	1912ई.	लॉर्ड हार्डिंग्ज
13.	मेक्लेगन समिति	मेक्लेगन	1914ई.	लॉर्ड हार्डिंग्ज
14.	सैंडलर आयोग	माइकल सैंडलर	1917ई.	लॉर्ड चेम्सफोर्ड
15.	शाही आयोग	लॉर्ड ली	1923ई.	लॉर्ड रीडिंग
16.	भारतीय छँटनी समिति	लॉर्ड इंचकैप	1923ई.	लॉर्ड रीडिंग
17.	भारतीय सेण्ड-हर्स्ट समिति	इण्ड्रयू स्कोन	1925ई.	लॉर्ड रीडिंग
18.	बटलर समिति	हरकोर्ट बटलर	1927ई.	लॉर्ड इरविन
19.	साइमन आयोग	जॉन साइमन	1927ई.	लॉर्ड इरविन
20.	लिनलिथगो आयोग	लिनलिथगो	1928ई.	लॉर्ड इरविन
21.	लिण्डसे आयोग	लिण्डसे	1929ई.	लॉर्ड इरविन
22.	भारतीय वैधानिक आयोग	फिलिप हर्येग	1929ई.	लॉर्ड इरविन
23.	व्हाइट ले आयोग	जे.एच.व्हाइटले	1929ई.	लॉर्ड इरविन
24.	सप्रू समिति	तेज बहादुर सप्रू	1934ई.	लॉर्ड विलिंगटन
25.	भारतीय परि-सीमन समिति	लॉरी हेमण्ड	1935ई.	लॉर्ड विलिंगटन
26.	राष्ट्रीय योजना समिति	जवाहरलालनेहरू	1938ई.	लॉर्ड लिनलिथगो
27.	क्रिप्स आयोग	स्टेफर्ड क्रिप्स	1942ई.	लॉर्ड लिनलिथगो
28.	कैबिनेट आयोग	पैथिक लारेन्स	1946ई.	लॉर्ड वेवल
29.	सार्जेण्ट योजना	जॉन सार्जेण्ट	1944ई.	लॉर्ड वेवल

स्वाधीनता संघर्ष से सम्बन्धित प्रमुख क्रान्तिकारी घटनाएँ एवं क्रान्तिकारी

	क्रान्तिकारी घटना	वर्ष	स्थान	क्रान्तिकारी
1.	कमिश्नर रैंड व आर्यस्ट हत्याकाण्ड	1897 ई.	पुणे	चापेकर बन्धु
2.	अलीपुर षड्यन्त्र काण्ड	1908 ई.	मुजफ्फरपुर	खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी
3.	जैक्सन हत्याकाण्ड	1909 ई.	नासिक	अनन्त कन्हेरे
4.	कर्नल नाइली हत्याकाण्ड	1909 ई.	लन्दन	मदनलाल धींगरा
5.	दिल्ली बमकाण्ड	1912 ई.	दिल्ली	रासबिहारी बोस व बसन्त कुमार
6.	काँकोरी काण्ड	1927 ई.	काँकोरी	रामप्रसादबिस्मिल, अशफाक उल्ला
7.	साण्डर्स हत्याकाण्ड	1928 ई.	लाहौर	सरदार भगतसिंह
8.	शस्त्रागार डकैती काण्ड	1930 ई.	चटगाँव	सूर्यसेन
9.	जनरल डायर हत्याकाण्ड	1940 ई.	लन्दन	ऊधमसिंह

स्वतन्त्रता संग्राम के प्रमुख आदिवासी आन्दोलन

	आन्दोलन	नेतृत्वकर्त्ता	सन्
1.	संथाल संघर्ष	सिद्धु, कान्हु	1855-57 ई.
2.	भील संघर्ष	सेवरम	1825 ई.
3.	रामोशी व डॉगर विद्रोह	वासुदेव फड़के	1879 ई.
4.	नागा संघर्ष	साबदान	1882 ई.

5.	रामोशी संघर्ष	दौलता रामोशी	1883 ई.
6.	रम्पा संघर्ष	राजन अनन्तय्या	1884 ई.
7.	मुण्डा उत्गुलन	बिरसा मुण्डा	1889-1900 ई.
8.	कोडा डोरा संघर्ष	कोरा मल्लया	1900 ई.
9.	भील जागृति संघर्ष	गोविन्द गुरु	1913 ई.
10.	उँराव उभार	जात्रा भगत	1914 ई.
11.	खासी संघर्ष	उत्तरीत सिंह	1917 ई.
12.	सम्भलपुर ब्रिटिश विरोधी संघर्ष	सुरेन्द्र सई	1919 ई.
13.	मेवाड़ भील संघर्ष	मोतीलाल तेजावत	1922 ई.

सन् 1857 ई. से पूर्व अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए प्रमुख आन्दोलन

	आन्दोलन	मुख्य नेतृत्वकर्ता	सन्	क्षेत्र
1.	कट्टबोम्मन का आन्दोलन	वीरपांड्य कट्टबोम्मन	1722-199 ई.	तिरून्नेवेलि (तमिलनाडु)
2.	पायकों का विद्रोह	जगबन्धु	1804-1806 ई.	उड़ीसा
3.	वेलूथम्पी का विद्रोह	वेलूथम्पी	1808-1809 ई.	त्रावणकोर
4.	राव भारमल का विद्रोह	राव भारमल	1816 ई.	कच्छ, काठियावाड़
5.	रमोसी विद्रोह	उमाजी, चित्तरसिंह	1822-1827 ई.	पूना
6.	कित्तुर विद्रोह	रायप्पा, चेनम्मा	1824-1829 ई.	कित्कुर
7.	सम्भलपुर विद्रोह	सुरेन्द्र सांई	1827-1840 ई.	सम्भलपुर
8.	सताराविप्लव	नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर, धरराव पवार	1840-1841 ई.	सतारा
9.	बुन्देला विद्रोह	जवाहरसिंह, मधुकर सिंह	1842 ई.	सागर, दमोह
10.	गाडकारी विद्रोह	गाडकारी	1844-1845 ई.	कोल्हापुर
11.	सतवन्दी विद्रोह	फोंड सतवन्त	1839-1845 ई.	सतवन्दी
12.	कूका आन्दोलन	भगत जवाहरमल	1845-1872 ई.	पंजाब
13.	बहावी आन्दोलन	सैय्यद अहमद	1820-1870 ई.	उत्तरी भारत
14.	पागलपंथी आन्दोलन	टीपू, करीमशाह	1825-1833 ई.	शेरपुर

स्वतन्त्र भारत का प्रथम मन्त्रिमण्डल

	नाम		विभाग
1.	जवाहर लाल नेहरू	—	विदेशी मामले, राष्ट्रमण्डल कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री
2.	वल्लभ भाई पटेल	—	गृह एवं सूचना प्रसारण
3.	बल्देव सिंह	—	रक्षा
4.	सी. राजगोपालाचारी	—	शिक्षा
5.	जगजीवनराम	—	श्रम
6.	लियाकत अली खान	—	वित्त
7.	सी. एच. भाभा	—	खान एवं बन्दरगाह
8.	डॉ. जॉन मथाई	—	उद्योग एवं आपूर्ति
9.	अब्दुल रब निश्तर	—	संचार
10.	आसफ अली	—	रेलवे
11.	गजान्तर अली खाँ	—	स्वास्थ्य
12.	आई. आई. चुन्दीगर	—	वाणिज्य
13.	जोगेन्द्रनाथ मण्डल	—	विधि
14.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	—	खाद्य एवं कृषि

अंग्रेज काल में भारत आने वाले विदेशी यात्री

भ्रमण काल	विदेशी यात्री	किसके समय में
1715 से 1717 ई.	जॉन सरमन (अंग्रेज व्यापारिक दूत)	फर्रुखसियर के समय में
1732 से 1739 ई.	स्टेवोरिनस (डच यात्री)	बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन खाँ के समय में
1763 से 1765 ई.	ल्यूक सेराफ्टन (अंग्रेज यात्री)	बंगाल के गवर्नर वेंसिटार्ट के समय में
1767 से 1772 ई.	विलियम बोल्ट्स (अंग्रेज यात्री)	बंगाल एवं बिहार में
1770 ई.	डो (अंग्रेज यात्री)	बंगाल के गवर्नर कर्टियन के समय में
1824 से 1826 ई.	बिशप हैनरी (अंग्रेज पादरी)	बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में
1830 से 1840 ई.	विक्टर जाकमा (फ्रेंच यात्री)	महाराज रणजीत सिंह के समय में

बंगाल के स्वतन्त्र नवाब

शासनावधि	नवाब
1713 से 1727 ई.	मुर्शिद कुली खाँ
1727 से 1739 ई.	शुजाउद्दीन खाँ
1739 से 1740 ई.	सरफराज खाँ
1740 से 1756 ई.	अलीवर्दी खाँ
1756 से 1757 ई.	सिराजुद्दौला
1757 से 1760 ई.	मीर जाफर
1760 से 1764 ई.	मीर कासिम
1764 से 1765 ई.	मीर जाफर (दुबारा)
1765 से 1767 ई.	नजीमुद्दौला

अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह

वर्ष	विद्रोह	प्रमुख क्षेत्र	नेतृत्वकर्त्ता
1760 से 1800 ई.	संन्यासी विद्रोह	बंगाल, बिहार	द्विजनारायण, केना सरकार
1766 से 1772 ई.	चुआर विद्रोह	मिदनापुर, बाकुंडा	दुर्जन सिंह
1782 से 1783 ई.	लगान बन्दी (कृषक) विद्रोह	रंगपुर (पू. बंगाल)	धीरज नारायण
1799 से 1801 ई.	पालिगार विद्रोह	तमिलनाडु	वी. पी. कट्टालाम्मान
1805 ई.	थम्पी विद्रोह	त्रावनकोर	दीवान वेलुथम्पी
1812 से 1819 ई.	भील विद्रोह	खानदेश	चिन्नावा
1817 ई.	पाइक विद्रोह	खुर्द क्षेत्र (उड़ीसा)	बख्शी जगबन्धु
1818 से 1820 ई.	बघेरा विद्रोह	ओखा मंडल	बघेरा सरदार
1819 से 1831 ई.	कच्छ विद्रोह	कच्छ	राजा भारमल
1822 से 1829 ई.	रमोसी विद्रोह	सतारा	चित्तर सिंह
1824 ई.	रानी चेनम्मा का विद्रोह	कित्तूर	रानी चेनम्मा
1825 से 1850 ई.	पागलपन्थी विद्रोह	शेरपुर (बंगाल)	टीपू गारो
1825 ई.	भील विद्रोह	महाराष्ट्र	सेवरम
1828 से 1830 ई.	अहोम विद्रोह	असम	गोमधर कुँवर
1831 ई.	बारसाल या हाथीखेड़ा विद्रोह	बारसाल (बंगाल)	टीटूमीर
1831 से 1832 ई.	कोल विद्रोह	छोटा नागपुर	विंदराय मानकी
1832 से 1833 ई.	खासी विद्रोह	जयन्तिया व गारो पहाड़ी	राजा तीरत सिंह
1838 से 1857 ई.	फरैजी विद्रोह	फरीदपुर (बंगाल)	दादू मियाँ
1840 से 1841 ई.	कूका विद्रोह-1	पंजाब	भगत जवाहरमल
1855 से 1856 ई.	संथाल विद्रोह	राजमहल क्षेत्र (बिहार)	सिद्धु (सीदो) व कान्हू
1859 से 1860 ई.	नील विद्रोह	बंगाल	दिगम्बर व विष्णु विश्वास
1872 ई.	कूका विद्रोह-2	पंजाब	रामसिंह कूका
1873 से 1876 ई.	पावना विद्रोह	पावना	ईशान चन्द्र राय
1879 ई.	रंपा विद्रोह	आन्ध्र प्रदेश	–
1879 ई.	कृषक विद्रोह	पुणे	वासुदेव बलवंत फड़के
1899 ई.	मुंडा विद्रोह	रांची	बिरसा मुंडा
1917 ई.	चम्पारन नील आन्दोलन	चम्पारन	महात्मा गांधी
1918 ई.	खेड़ा कृषक आन्दोलन	खेड़ा	महात्मा गांधी
1919 ई.	नाई-धोबी बन्द आन्दोलन	प्रतापगढ़	बाबा रामचन्द्र
1920 ई.	अवध किसान आन्दोलन	प्रतापगढ़	बाबा रामचन्द्र
1921 ई.	मोपला कृषक विद्रोह	मालाबार (केरल)	अली मुसीलियर
1921 ई.	एका कृषक आन्दोलन	अवध	–
1921 ई.	चिराला-विराला आन्दोलन	गुंटूर	दग्गिराजा गोपाल कृष्णय्या
1924 ई.	कोल बायकोम आन्दोलन	केरल	कैप्टन पी. के. मेनन
1930 ई.	चटगाँव शस्त्रागार विद्रोह	चटगाँव	सूर्यसेन
1930 ई.	मणिपुर विद्रोह	मणिपुर	रानी गैडिनल्यू
1931 से 1932 ई.	मन्दिर प्रवेश गुरुवायूर आन्दोलन	केरल	सुब्रह्मण्यम तिरूभावु
1942 ई.	बलिया नागरिक विद्रोह	बलिया (उ. प्र.)	चित्तू पान्डे
1941 ई.	सतारा नागरिक विद्रोह	सतारा (महाराष्ट्र)	वाई. वी. चव्हाण, अच्युत पटवर्धन
1946 ई.	नौसेना विद्रोह	बम्बई	–
1946 ई.	तेभागा कृषक आन्दोलन	तेभागा (बंगाल)	कृषक
1946 ई.	बेहरामपुर नागरिक विद्रोह	बेहरामपुर (असम)	भोगेश्वरी देवी फुकन

आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध

वर्ष	युद्ध	पक्ष-विपक्ष	परिणाम (विजयी)
1707 ई.	खेड़ा का युद्ध	मराठा छत्रपति शाहू एवं चाची ताराबाई	शाहू
1724 ई.	शंकर खेड़ा का युद्ध	निजामुलमुल्क एवं मुगल वायसराय मुबारिज खाँ	निजाम
1737 ई.	भोपाल का युद्ध	बाजीराव I एवं मुगलों के मध्य	बाजीराव I
1739 ई.	करनाल का युद्ध	नादिरशाह एवं मुगल सम्राट् मुहम्मद शाह	नादिरशाह
1740 ई.	गिरिया का युद्ध	बंगाल नवाब सरफराज खाँ एवं बिहार के उपगवर्नर अलीवर्दी खाँ	अलीवर्दी खाँ
1744 से 1748 ई.	प्रथम कर्नाटक युद्ध	फ्रांसीसी (डूप्ले) एवं अंग्रेज	फ्रांसीसी
1750 से 1754 ई.	द्वितीय कर्नाटक युद्ध	फ्रांसीसी (डूप्ले) एवं अंग्रेज (क्लाइव)	अंग्रेज
1757 से 1763 ई.	तृतीय कर्नाटक युद्ध	फ्रांसीसी (लैली) एवं अंग्रेज	अंग्रेज
1757 ई.	प्लासी का युद्ध	अंग्रेज (क्लाइव) एवं बंगाल नवाब सिराजुद्दौला	अंग्रेज
1759 ई.	बेदारा का युद्ध	अंग्रेज एवं डच	अंग्रेज
1760 ई.	वांडीवाश का युद्ध	अंग्रेज (आयरकूट) एवं फ्रांसीसी (लैली)	अंग्रेज
1761 ई.	पानीपत का तृतीय युद्ध	अफगान अहमदशाह अब्दाली एवं मराठे	अब्दाली
1764 ई.	बक्सर का युद्ध	अंग्रेज (हैक्टर मुनरो) एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाहआलम की संयुक्त सेना	अंग्रेज
1766 से 1769 ई.	प्रथम मैसूर युद्ध	अंग्रेज एवं हैदरअली	हैदरअली
1774 ई.	रूहेला युद्ध	लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं रूहेला शासक हाफिज खाँ	अंग्रेज
1775 ई.	सिंदखेड़ा का युद्ध	निजाम एवं मराठे	मराठे
1775 से 1782 ई.	प्रथम मराठा युद्ध	अंग्रेज (वारेन हेस्टिंग्स) एवं मराठे (नाना फड़नवीस)	अनिर्णीत
1780 से 1784 ई.	द्वितीय मैसूर युद्ध	लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स एवं हैदर व टीपू सुल्तान	अनिर्णीत
1790 से 1792 ई.	तृतीय मैसूर युद्ध	लॉर्ड कार्नवालिस एवं टीपू सुल्तान	अंग्रेज
1799 ई.	चतुर्थ मैसूर युद्ध	लॉर्ड वेलेजली एवं टीपू सुल्तान	अंग्रेज
1803 से 1806 ई.	द्वितीय मराठा युद्ध	लॉर्ड वेलेजली एवं मराठा राज्य	अंग्रेज
1814 से 1816 ई.	नेपाल युद्ध	लॉर्ड हेस्टिंग्स (सेनापति आक्टरलोनी) एवं गोरखे	अंग्रेज
1817 से 1819 ई.	तृतीय मराठा युद्ध	लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं मराठे राज्य	अंग्रेज
1817 से 1818 ई.	पिंडारी युद्ध	कर्नल स्लीमेन एवं पिंडारी लुटेरे	अंग्रेज
1817 ई.	किर्की का युद्ध	अंग्रेज एवं पेशवा बाजीराव द्वितीय	अंग्रेज
1817 ई.	सीता बर्डी का युद्ध	अंग्रेज एवं भोंसले अप्पा जी	अंग्रेज
1818 ई.	अष्टी का युद्ध	अंग्रेज एवं पेशवा बाजीराव द्वितीय	अंग्रेज
1824 से 1826 ई.	प्रथम बर्मा युद्ध	अंग्रेज (एमहर्स्ट) एवं बर्मा	अंग्रेज
1839 से 1842 ई.	प्रथम अफगान युद्ध	अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैण्ड एवं अफगान	अंग्रेज
1843 ई.	मियानी (सिंध) का युद्ध	अंग्रेज (ऐलनबरो) व सिंधी अमीर	अंग्रेज
1845 से 1846 ई.	प्रथम सिख युद्ध	अंग्रेज (हार्डिंग) व सिख	अंग्रेज
1848 से 1849 ई.	द्वितीय सिख युद्ध	अंग्रेज (डलहौजी) व सिख	अंग्रेज
1849 ई.	चिलियाँवाला का युद्ध	अंग्रेज सेनापति ह्यूगफ व सिख सेनापति शेरसिंह	सिख
1852 ई.	द्वितीय बर्मा युद्ध	अंग्रेज (डलहौजी) व बर्मी सेना	अंग्रेज
1878 से 1880 ई.	द्वितीय अफगान युद्ध	अंग्रेज (लिटन) व अफगान	अंग्रेज (विशेष लाभ नहीं)
1885 ई.	तृतीय बर्मा युद्ध	अंग्रेज (डफरिन) व बर्मी सेना	अंग्रेज
1919 ई.	तृतीय अफगान युद्ध	अंग्रेज (चेम्सफोर्ड) व अफगान	अंग्रेज
1962 ई.	भारत-चीन युद्ध	चीन द्वारा भारत पर आक्रमण	चीन
1965 ई.	भारत-पाक युद्ध	पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण	भारत
1971 ई.	भारत-पाक-युद्ध	युद्ध का कारण बांग्लादेश (पू. पाकिस्तान) की स्वतन्त्रता था	भारत

ब्रिटिशकाल में विदेशों में भेजे गये शिष्टमण्डल

वर्ष	शिष्टमण्डल	देश	गवर्नर जनरल/वायसराय
1787 ई	किर्क पैट्रिक शिष्टमण्डल	नेपाल	लॉर्ड कार्नवालिस
1797 ई.	मेलकम शिष्टमण्डल (1)	ईरान	लॉर्ड वेलेजली
1808 ई.	एलफिंस्टन शिष्टमण्डल	काबुल	लॉर्ड मिंटो
1808 ई.	मैलकम शिष्टमण्डल (2)	ईरान	लॉर्ड मिंटो
1809 ई.	डेविड सेटान शिष्टमण्डल	सिंध	लॉर्ड मिंटो
1892 ई.	रॉबर्ट्स शिष्टमण्डल	काबुल	लॉर्ड लेंसडाउन
1893 ई.	हेनरी डूरंड शिष्टमण्डल	काबुल	लॉर्ड लेंसडाउन
1903 ई.	यंग हस्बैंड शिष्टमण्डल	तिब्बत	लॉर्ड कर्जन
1904 ई.	डेन शिष्टमण्डल	काबुल	लॉर्ड कर्जन
1912 ई.	डॉ. अन्सारी मिशन (चिकित्सा)	तुर्की	लॉर्ड हार्डिंग
1938 ई.	डॉ. अटल मिशन (चिकित्सा)	चीन	लॉर्ड लिनलिथगो

विदेशों में भारतीय क्रान्तिकारी संगठन

स्थापना वर्ष	संगठन	संस्थापक	देश
1904 ई.	इंडिया हाउस	श्यामजी कृष्ण वर्मा	लन्दन (इंग्लैण्ड)
1906 ई.	अभिनव भारत	वी. डी. सावरकर	लन्दन (इंग्लैण्ड)
1907 ई.	इंडियन इंडिपेंडेंस लीग	तारक नाथ दास	अमरीका
1913 ई.	गदर पार्टी	लाला हरदयाल, रामचन्द्र व बरकतुल्ला	सेन फ्रांसिस्को (अमरीका)
1914 ई.	इंडियन इंडिपेंडेंस लीग	लाला हरदयाल व वीरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय	बर्लिन (जर्मनी)
1915 ई.	इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट	राजा महेन्द्र प्रताप	काबुल (अफगानिस्तान)
1942 ई.	इंडियन इंडिपेंडेंस लीग	रास बिहारी बोस	टोकियो (जापान)
1942 ई.	आजाद हिन्द फौज	रास बिहारी बोस (1943 में आजाद हिन्द फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने किया)	टोकियो (जापान)

भारतीय क्रान्तिकारी संगठन

स्थापना वर्ष	संगठन	संस्थापक	स्थान
1901 ई.	मित्र मेला	सावरकर बन्धु	पूना
1902 ई.	अनुशीलन समिति	ज्ञानेन्द्र नाथ बोस	मिदनापुर
1904 ई.	अभिनव भारत	वी. डी. सावरकर	पूना
1905 ई.	स्वदेश बांधव समिति	अश्विनी कुमार दत्त	बारिसाल
1907 ई.	अनुशीलन समिति	बारीन्द्र कुमार घोष व भूपेन्द्र दत्त	ढाका
1907 ई.	भारत माता सोसायटी	अजीतसिंह व अम्बा प्रसाद	पंजाब
1924 ई.	हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन	शचीन्द्र नाथ सान्याल	कानपुर
1926 ई.	नौजवान सभा	भगत सिंह	लाहौर
1928 ई.	हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन	चन्द्रशेखर आजाद	दिल्ली

आधुनिक भारत की राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संस्थाएँ

वर्ष	संस्था	संस्थापक	स्थान
1838 ई.	लैंडहोल्डर्स सोसाइटी	द्वारिका नाथ टैगोर	कलकत्ता
1839 ई.	ब्रिटिश इंडिया सोसायटी	विलियम एडम	लन्दन
1843 ई.	ब्रिटिश इंडिया सोसायटी	–	कलकत्ता
1851 ई.	ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन	देवेन्द्रनाथ टैगोर	कलकत्ता
1852 ई.	मद्रास नेटिव एसोसिएशन	–	मद्रास
1852 ई.	बॉम्बे एसोसिएशन	जगन्नाथ शंकर	बम्बई
1862 ई.	लन्दन इंडिया कमेटी	सी. पुरुषोत्तम मुदालियर	लन्दन
1866 ई.	ईस्ट इंडिया एसोसिएशन	दादा भाई नौरोजी	लन्दन
1867 ई.	नेशनल इंडिया एसोसिएशन	मेरी कारपेंटर	लन्दन
1872 ई.	इंडियन सोसायटी	आनन्द मोहन बोस	लन्दन
1876 ई.	इंडियन एसोसिएशन	आनन्द मोहन बोस व एस. एन. बनर्जी	कलकत्ता
1883 ई.	इंडियन नेशनल सोसाइटी	श्रीशचन्द्र बोस	कलकत्ता
1883 ई.	भारतीय राष्ट्रीय कान्फ्रेंस	एस. एन. बनर्जी	कलकत्ता
1884 ई.	मद्रास महाजन सभा	वीर राघवाचारी व एस. अय्यर	मद्रास
1885 ई.	बम्बई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन	फीरोजशाह मेहता व तेलंग	बम्बई
1885 ई.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	ए. ओ. ह्यूम	बम्बई
1888 ई.	यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन	सर सैय्यद अहमद खाँ	अलीगढ़
1905 ई.	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी	गोपाल कृष्ण गोखले	बम्बई
1915 ई.	होमरूल लीग	एनीबेसेंट व बाल गंगाधर तिलक	पुणे
1918 ई.	उ. प्र. किसान सभा	मालवीय, इन्द्र नारायण व गौरीशंकर	लखनऊ
1918 ई.	अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन	महात्मा गांधी	अहमदाबाद
1918 ई.	नेशनल लिबरल फेडरेशन	एस. एन. बनर्जी	कलकत्ता
1920 ई.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	एम. एन. राय	ताशकन्द
1920 ई.	सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी	लाला लाजपतराय	लाहौर
1920 ई.	अवध किसान सभा	नेहरू, रामचन्द्र गौरीशंकर	प्रतापगढ़
1920 ई.	भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	एन. एम. जोशी (संस्थापक) लाला लाजपतराय (अध्यक्ष)	लखनऊ
1921 ई.	कम्यूनिस्ट ग्रुप आफ इंडिया	नलिनी गुप्ता	कलकत्ता
1923 ई.	स्वराज्य पार्टी	मोतीलाल नेहरू व सी. आर. दास	दिल्ली
1924 ई.	अखिल भारतीय साम्यवादी दल	सत्यभक्त	कानपुर
1925 ई.	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ	के. बी. हेडगेवार	–
1927 ई.	आल इंडिया वीमेंस कांफ्रेंस	लेडी सदाशिव अय्यर	मद्रास
1928 ई.	श्रमिक स्वराज पार्टी	काजी नसरूल इस्लाम	–
1929 ई.	खुदाई खिदमतगार	खान अब्दुल गफ्फार खाँ	पेशावर
1934 ई.	कांग्रेस समाजवादी पार्टी	आचार्य नरेन्द्रदेव एवं जयप्रकाश नारायण	–
1936 ई.	प्रगतिशील लेखक संघ	मुन्शी प्रेमचन्द	लखनऊ
1936 ई.	अखिल भारतीय किसान सभा	एन. जी. रंगा व सहजानन्द	लखनऊ
1936 ई.	अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्	मीनू मसानी, अशोक मेहता व डॉ. अशरफ	–
1939 ई.	फारवर्ड ब्लाक	सुभाष चन्द्र बोस	कलकत्ता
1939 ई.	भारतीय बोल्शेविक दल	एन. डी. मजूमदार	कलकत्ता
1940 ई.	रेडिकल डेमोक्रेटिक दल	एम. एन. राय	कलकत्ता
1941 ई.	भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल	अजीत राय व इन्द्र सेन	कलकत्ता
1942 ई.	क्रान्तिकारी समाजवादी दल	सौम्येन्द्र नाथ टैगोर	कलकत्ता

अंग्रेजकालीन महत्वपूर्ण कानून एवं एक्ट			
वर्ष	कानून / एक्ट	गवर्नर जनरल / वायसराय	मुख्य प्रावधान
1773 ई.	रेग्यूलेटिंग एक्ट	वारेन हेस्टिंग्ज	भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियन्त्रण
1784 ई.	पिट का इंडिया एक्ट	वारेन हेस्टिंग्ज	बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना
1813 ई.	चार्टर एक्ट	लॉर्ड मिंटो	कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म
1829 ई.	सती प्रथा निषेध कानून	विलियम बैंटिंक	सती प्रथा पर रोक
1833 ई.	चार्टर एक्ट	विलियम बैंटिंक	बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना
1853 ई.	चार्टर एक्ट	लॉर्ड डलहौजी	कम्पनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियन्त्रक
1856 ई.	हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम	लॉर्ड डलहौजी	विधवा विवाह को मान्यता
1858 ई.	अच्छे शासन के लिए अधिनियम	लॉर्ड केनिंग	भारत पर सीधे ब्रिटेन का शासन
1861 ई.	भारतीय परिषद् अधिनियम	लॉर्ड केनिंग	कौंसिल में भारतीयों का प्रवेश
1891 ई.	सम्मति आयु अधिनियम	लेंसडाउन	बाल विवाह (12 वर्ष से कम) पर रोक
1892 ई.	भारतीय परिषद् अधिनियम	लेंसडाउन	निर्वाचन पद्धति की शुरूआत
1909 ई.	मिंटो-मार्ले अधिनियम	लॉर्ड मिंटो	पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था
1919 ई.	मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम	लॉर्ड चेम्सफोर्ड	प्रान्तों में द्वैध शासन
1927 ई.	साइमन कमीशन	लॉर्ड इरविन	संविधान निर्माण योजना
1930 ई.	शारदा एक्ट	लॉर्ड इरविन	विवाह आयु 18 वर्ष एवं 14 वर्ष हुई
1935 ई.	भारत सरकार अधिनियम	लॉर्ड वेलिंगटन	प्रान्तीय स्वायत्तता
1940 ई.	अगस्त घोषणा	लिनलिथगो	प्रादेशिक स्वशासन
1942 ई.	क्रिप्स मिशन प्रस्ताव	लिनलिथगो	संविधान सभा की योजना
1945 ई.	वेवल योजना	लॉर्ड वेवल	सभी दलों को मिलाकर कौंसिल निर्माण
1946 ई.	केबिनेट मिशन योजना	लॉर्ड वेवल	संघ निर्माण व प्रान्तों को स्वायत्तता
1947 ई.	माउंटबेटन योजना	लॉर्ड माउंटबेटन	भारत विभाजन

आंग्ल मैसूर युद्ध

प्रथम युद्ध (1766-69 ई.)

कारण–हैदरअली अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहता था और अंग्रेज उसे अपना कट्टर शत्रु मानते थे. अंग्रेजों ने निजाम और मराठा के साथ मिलकर हैदर के विरुद्ध त्रिपक्षीय संघ बनाया, जो हैदर ने तोड़ दिया.

युद्ध–मद्रास के निकट मार्च 1769 ई. में हैदर ने निर्णायक युद्ध में हराया.

सन्धि–अप्रैल 1769 ई. में सन्धि हुई और दोनों ने जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए और युद्ध के समय एक-दूसरे की सैन्य मदद करने का वादा किया.

द्वितीय युद्ध (1780-84 ई.)

कारण–(1) सन् 1771 ई. में अंग्रेजों ने हैदरअली की मराठों के विरुद्ध मदद नहीं की.

(2) अंग्रेजों ने हैदर के अधिकार क्षेत्र में स्थित माही (फ्रांसीसियों कोठी) पर अधिकार कर लिया था.

युद्ध–कर्नल बेली को हराया और अर्काट पर सन् 1780 में अधिकार कर लिया.

हैदरअली की पोर्ट नोवो (1781) में सर आयरकूट द्वारा पराजय, कर्नल ब्रेथवेट की हैदर द्वारा पराजय (1782), टीपू ने ब्रिग्रेडियर मेथ्यू और उसके आदमियों को कैद किया (1783).

सन्धि–टीपू और मैककार्टनी के बीच मंगलौर की सन्धि (1784) में दोनों ने एक-दूसरे के प्रदेश लौटा दिए.

तृतीय युद्ध (1790-92 ई.)

कारण–टीपू का फ्रांस और टर्की की ओर झुकाव, 1789 में त्रावणकोर के राजा पर टीपू का आक्रमण.

युद्ध–मेजर जनरल मेड्यू की टीपू द्वारा पराजय (1790) फरवरी 1792 में टीपू की श्रीरंगपट्टम में कार्नवालिस के हाथों पराजय.

सन्धि–मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टम की सन्धि.

चतुर्थ युद्ध (1799 ई.)

कारण–टीपू की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियाँ और वेलेजली का टीपू को पूरी तरह कुचलने का दृढ़ संकल्प.

युद्ध–टीपू की स्टुआर्ट और हेरिस द्वारा क्रमशः सदासीर और मालवेली में पराजय, टीपू की 4 मई, 1799 को श्रीरंगपट्टम के दरवाजे पर मृत्यु.

परिणाम–मैसूर में वादियार वंश की पुनः स्थापना.

आदिवासी संघर्षों के प्रमुख नेता

- **सीदो (सिद्धु) तथा कान्हू**–संथाल संघर्ष का नेतृत्व करने वाले दो भाई.
- **सेवरम**–1825 के भील संघर्ष (महाराष्ट्र) का नेता.
- **चित्तर सिंह**–1822 के रामोसी विद्रोह का नेता.
- **साम्बुदान**–1882 के नागा संघर्ष का नेतृत्व किया.
- **कोरा मल्लया**–1900 में विशाखापट्टनम एजेन्सी को कोडा डोरा संघर्ष का नेता.
- **राजन अनंतय्या**–1884 के रम्पा संघर्ष का नेता.
- **बिरसा मुण्डा**–1899-1900 के मुण्डा उन्मूलन (महा विद्रोह) का नायक.
- **वासुदेव बलवन्त फडके**–रामोसी व डांगर के गुप्त डाकू संगठन का नेता.
- **दौलता रामोसी**– एक तरह से फड़के के कार्य को आगे बढ़ाने वाला रामोसी डाकू दल का नेता (1883).
- **अल्लूरी सीताराम राजू**–1922-24 के रम्पा संघर्ष का नायक.
- **जात्रा भगत**–1914 के उराव उभार का नेता.
- **गोबिन्द गुरु**–राजस्थान में भील जागृति के नायक.
- **मोतीलाल तेजावत**–'मेवाड़ भील' संघर्ष (1922) के नेता.
- **भुन्दु भगत**–1831-32 के कोल संघर्ष का नायक.
- **उत्तरौत सिंह**–मेघालय के खासी संघर्ष का नेता.
- **सुरेन्द्र सई**–सम्भलपुर (उड़ीसा) में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष का नायक.
- **गोमधन कुँवर**–1828 के अहोम संघर्ष का नायक.

किसान आन्दोलनों से जुड़े प्रमुख नेता

- वासुदेव फड़के (1879 का आन्दोलन).
- लाला लाजपतराय, अजीतसिंह (1907, पंजाब).
- **महात्मा गांधी, जे. बी. कृपलानी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला**–चम्पारण आन्दोलन.
- **गांधी, मोहनलाल पांड्या**–खेड़ा आन्दोलन (1918)
- विजयसिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण, बाबा सीताराम दास, हरिभाऊ उपाध्याय (मेवाड़), मोतीलाल तेजावत (भील), जयनारायण (मारवाड़)
- **स्वामी विद्यानन्द**–दरभंगा (बिहार, 1919-20)
- **जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचन्द्र दास, इन्द्रनारायण द्विवेदी**–अवध 1921-23
- मदारी पासी–एका आन्दोलन (1922)
- अल्लूरी सीताराम राजू-रम्पा आन्दोलन (1922-24) आन्ध्र प्रदेश
- **एन. जी. रंगा, पी. सुन्दरैया**–आन्ध्र प्रदेश
- **वल्लभभाई पटेल, कुँवरजी मेहता, कल्याणजी मेहता**–बारदोली सत्याग्रह (1927-28)
- **सोहनसिंह माकना**–पंजाब (1937-39)
- **सहजानन्द, राहुल सांकृत्यायन, कृपानंद शर्मा**–बिहार (1937-39)
- **रविनारायण रेड्डी**–तेलंगाना (1946-51)
- भवानी सेन, सुनील सेन, मोनीसिंह तेभागा (1946)

1919 ई. के सुधार कानून के अन्तर्गत प्रान्तों में विधायिकाओं की सदस्य संख्या

(साइमन रिपोर्ट के अनुसार)

	कानून द्वारा तय संख्या	निर्वाचित सदस्य	नामजद सरकारी	गवर्नर की परिषद् के सदस्य	नामजद गैर सरकारी	कुल
मद्रास	118	98	7	4	23	132
बम्बई	111	86	15	4	9	114
बंगाल	125	114	15	4	10	143
सं. प्रान्त	118	100	15	2	6	123
पंजाब	83	71	23	2	8	104
बिहार-उड़ीसा	98	76	13	2	12	103
मध्य प्रान्त	70	55	8	2	8	73
असम	53	39	5	2	7	53

भारतीय संविधान

(उद्देशिका, नागरिकता, मूल-अधिकार, नीति-निदेशक तत्त्वों का मूल पाठ)[1]

भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के** लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को–

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, **धर्म**
और उपासना की **स्वतन्त्रता**,
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं.**

THE CONSTITUTION OF INDIA
PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMO-CRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief,
faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

---

1 भारत का संविधान : भारत, सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय.

भाग-1

संघ और उसका कार्य क्षेत्र

(1) **संघ का नाम और राज्यक्षेत्र**–(1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा.

(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं.

(3) भारत के राज्य क्षेत्र में–

(क) राज्यों के राज्य क्षेत्र

(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और

(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे.

2. **नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना**–संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी.

2 क. (सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना.) संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) निरसित.

3. **नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन–संसद, विधि द्वारा–**

(क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों में मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नये राज्य का निर्माण कर सकेगी.

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी.

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी.

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी.

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी.

परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहाँ जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा.

स्पष्टीकरण 1. इस अनुच्छेद के खण्ड (क) से खण्ड (ङ) में 'राज्य' के अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र है, किन्तु परंतुक में 'राज्य' के अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र नहीं है.

स्पष्टीकरण 2. खण्ड (क) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत किसी राज्य या संघ राज्य के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर नये राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है.

4. **पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुवंशिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ**–(1) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी (जिनके अन्तर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे.

(2) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा.

भाग-2

नागरिकता

5. **संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता**–इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और–

(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या

(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या

(ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले या कम-से-कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा.

6. **पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार**–अनुच्छेद 5 में से किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अन्तर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा–

(क) यदि वह या उसके माता-पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था; और

(ख) (i) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है; या

(ii) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 को या उसके पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब

यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पहले ऐसे अधिकारों को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है.

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम-से-कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा.

7. **पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार**–अनुच्छेद-5 और अनुच्छेद-6 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च, 1947 के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अन्तर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा.

परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को, इस समय पाकिस्तान के अन्तर्गत है, प्रव्रजन के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है, जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद-6 के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्यक्षेत्र को 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् प्रव्रजन किया है.

8. **भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार**–अनुच्छेद-5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह नागरिक प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में, जहाँ वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारम्भ से पहले या उसके पश्चात् आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है.

9. **विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना**–यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह अनुच्छेद-5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद-6 या अनुच्छेद-8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा.

10. **नागरिकता के अधिकारों का बना रहना**–प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा.

11. **संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना**–इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी.

भाग-3

साधारण

12. **परिभाषा**–इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं.

13. **मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ**–(1) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं.

(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खण्ड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी.

(3) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "विधि" के अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है.

(ख) "प्रवृत्त विधि" के अन्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पहले पारित या बनाई गई विधि है, जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है.

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी.

समता का अधिकार

14. **विधि के समक्ष समता**–राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा.

15. **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद का प्रतिषेध**–(1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा–

(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी आधार पर (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा.

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी.

(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी.

16. **लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता**–(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी.

(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जायेगा.

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के सम्बन्ध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है.

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी.

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि से प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो यह उपबन्ध करती है कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय या कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट सम्प्रदाय का ही हो.

17. **अस्पृश्यता का अंत**–'अस्पृश्यता' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है. 'अस्पृश्यता' से अपनी उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा.

18. **उपाधियों का अंत**–(1) राज्य, सेना या विद्या सम्बन्धी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा.

(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा.

(3) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा.

(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा.

स्वातंत्र्य अधिकार

19. **वाक्-स्वातन्त्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण**–(1) सभी नागरिकों को–

(क) वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का,

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

(ग) संगम या संघ बनाने का,

(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का

(ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, और

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा.

(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की

प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के सम्बन्ध में युक्ति-युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी.

(3) उक्त खण्ड के उपखण्ड (ख) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी.

(4) उक्त खण्ड के उपखण्ड (ग) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी.

(5) उक्त खण्ड के उपखण्ड (घ) और उपखण्ड (ङ) की कोई बात उक्त उपखण्डों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी.

(6) उक्त खण्ड के उपखण्ड (छ) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टतया उक्त उपखण्ड की कोई बात–

(i) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक तकनीकी अर्हताओं से, या

(ii) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारबार, उद्योग या सेवा, नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाए जाने से.

जहाँ तक कोई विद्यमान विधि सम्बन्ध रखती है, वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार सम्बन्ध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित करेगी.

20. **अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण**– (1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी.

(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा.

(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा.

21. **प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण**–किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं.

22. **कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण**– (1) किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा.

(2) प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा.

(3) खण्ड (1) और खण्ड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो–

(क) तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है; या

(ख) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है.

(4) निवारक निरोध या उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का तीन मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि–

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने तीन मास की उक्त

अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है;

परन्तु इस उपखण्ड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खण्ड (7) के उपखण्ड (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को खण्ड (7) के उपखण्ड (क) और उपखण्ड (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है.

(5) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गये आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा.

(6) खण्ड (5) की किसी बात से ऐसा आदेश, जो उस खण्ड में निर्दिष्ट है, करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा, जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है.

(7) संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि–

(क) किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिए खण्ड (4) के उपखण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा;

(ख) किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा; और

(ग) खण्ड (4) के उपखण्ड (क) के अधीन की जाने वाली जाँच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी.

शोषण के विरुद्ध अधिकार

23. **मानव के दुर्व्यापार और बलात्‌श्रम का प्रतिषेध**–(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्‌श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा.

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी. ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा.

24. **कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध**– चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा.

धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार

25. **अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता**–(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की वतन्त्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा.

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो–

(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है.

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है.

स्पष्टीकरण 1. कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिक्ख धर्म के मानने का अंग समझा जायेगा.

स्पष्टीकरण 2. खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि उसके अन्तर्गत सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा.

26. **धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता**–लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग को–

(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,

(ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का,

(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और

(घ) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा.

27. **किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतन्त्रता**–किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का

संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं.

28. **कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतन्त्रता**–(1) राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी.

(2) खण्ड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किन्तु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है.

(3) राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या वह अवयस्क है, तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है.

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

29. **अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण**–(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा.

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा.

30. **शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार**–(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा.

(1 क) खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खण्ड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए.

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है.

31. **[सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन.]**–संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 6 द्वारा (20-06-1979 से) निरसित.

कुछ विधियों की व्यावृत्ति

31 क. सम्पदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति–(1) अनुच्छेद-13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

(क) किसी सम्पदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या

(ख) किसी सम्पत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिये जाने के लिए,

या

(ग) दो या अधिक निगमों का लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए, या

(घ) निगमों के प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशकों, निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयर धारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या

(ङ) किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए,

उपबन्ध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद-14 या अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है;

परन्तु जहाँ ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गयी है;

परन्तु यह और कि जहाँ किसी विधि में किसी सम्पदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहाँ उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है वहाँ राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को,

जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से सम्बन्धित विधि उस दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है जो बाजार-मूल्य से कम नहीं होगी.

(2) **इस अनुच्छेद में–**

(क) "सम्पदा" पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू-धृतियों से सम्बन्धित विधमान विधि में है और इसके अन्तर्गत–

(i) कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान और तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्मम् अधिकार भी होगा.

(ii) रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी;

(iii) कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी, जिसके अन्तर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चरागाह या भूमि के कृषकों के कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं;

(ख) "अधिकार" पद के अन्तर्गत, किसी सम्पदा के सम्बन्ध में, किसी स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भू-धृतिधारक, रैयत, अवर रैयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू-राजस्व के सम्बन्ध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे.

31 ख. **कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण**–अनुच्छेद 31क में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक, उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त बना रहेगा.

31. ग. **कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति**–अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी, कोई विधि, जो (भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्वों) को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जायेगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है [और कोई विधि, जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है] :

परन्तु जहाँ ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्रदान नहीं हो गई है.

31. घ. **[राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के सम्बन्ध में विधियों की व्यावृत्ति.]**–संविधान (तैंतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 2 द्वारा (13-4-1978 से) निरसित.

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

32. **इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार**–(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है.

(2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम नयायालय को ऐसे निदेश या आदेश या रिट, जिनके अन्तर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट है, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी.

(3) उच्चतम न्यायालय को खण्ड (1) और खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद, उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्ड (2) के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी.

(4) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिक निलंबित नहीं किया जायेगा.

32. क. (**राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना.**)–संविधान (तैतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 3 द्वारा (13-4-1978 से) निरसित.

33. **इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपान्तरण करने की संसद की शक्ति**–संसद, विधि द्वारा, अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई–

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को, या

(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखने का भारसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को, या

(ग) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को, या

(घ) खण्ड (क) से (खण्ड) ग में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में, किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे.

34. **जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन**–इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहाँ सेना विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था के बनाए रखने या पुनःस्थापन के सम्बन्ध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दण्डादेश, दिए गए दण्ड, आदिष्ट समपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी.

35. **इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान**–इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी–

(क) संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह–

(i) जिन विषयों के लिए अनुच्छेद—16 के खण्ड (3), अनुच्छेद 32 के खण्ड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें से किसी के लिए, और

(ii) ऐसे कार्यों के लिए, जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दण्ड विहित करने के लिए, विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए, जो उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट हैं, दण्डविहित करने के लिए विधि बनाएगी;

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से सम्बन्धित या उस खण्ड के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दण्ड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि, जो भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निर्बंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवत्त रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है.

स्पष्टीकरण–इस अनुच्छेद में, "प्रवृत्त विधि" पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है.

भाग 4

राज्य के नीति-निदेशक तत्व

36. **परिभाषा**–इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग 3 में है.

37. **इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना**–इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा.

38 **राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा**–(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृत्ति का प्रयास करेगा.

(2) राज्य, विशिष्टतया, आपकी असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा.

39. **राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व**–राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार का संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से.

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बाँटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(च) बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए.

39 क. **समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता**–राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक-तन्त्र इस प्रकार काम करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा.

40. **ग्राम पंचायतों का संगठन**–राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों.

41. **कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार**–राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा.

42. **काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध**–राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं की सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा.

43. **कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि**–राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएँ तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा.

43. क. **उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मकारों का भाग लेना**–राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबन्ध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठायेगा.

44. **नागरिकों के लिए एकसमान सिविल संहिता**–राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एकसमान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा.

45. **बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध**–राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा.

46 **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि**–राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा.

47. **पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य कर्त्तव्य**–राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा.

48. **कृषि और पशुपालन का संगठन**–राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उसके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठायेगा.

48. क. **पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा**–राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा.

49. **राष्ट्रीय महत्त्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण**–संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गये कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी.

50. **कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण**–राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य कदम उठायेगा.

51. **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि**–राज्य–

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,

(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का,

(ग) संगठित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, प्रयास करेगा.

उपकार

सामान्य अध्ययन

आधुनिक भारत का इतिहास

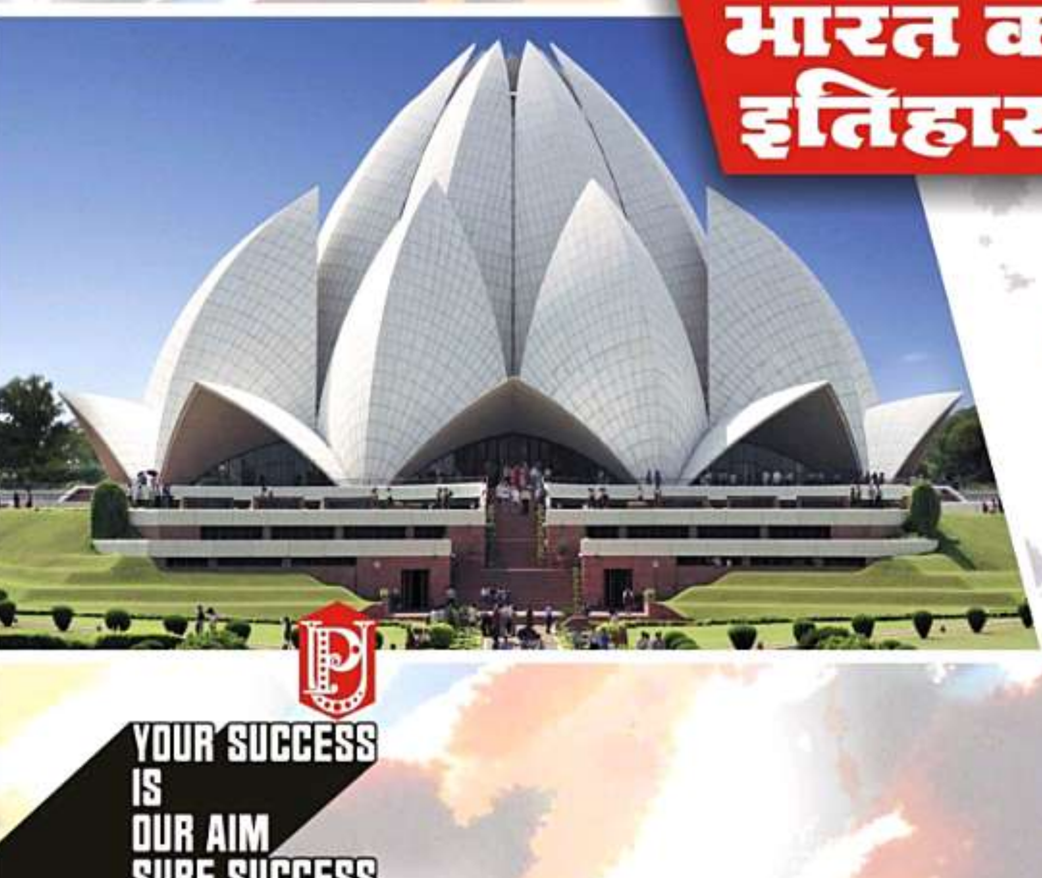

YOUR SUCCESS
IS
OUR AIM
SURE SUCCESS
WITH
OUR NAME
THAT IS
UPKAR

ISBN 978-93-5013-614-0
9 789350 136140

उपकार प्रकाशन, आगरा-2